

**DUE DATE SLIP****GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj )

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DTATE	SIGNATURE

# नयोजन तथा आर्थिक विकास

(Planning and Economic Development)

(भारत, सोवियत रूस व जापान के विशेष सन्दर्भ में)

(राजस्थान विश्व-विद्यालय के बी. ए. पाइनेल के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रमानुसार)

लेखक

बी० एल० ओज़ा

एम० ए०, एम० काम, आर० ई० एम०

अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
कोटा

पंचम संस्करण

1981

आदर्श प्रकाशन

चौड़ा रास्ता, जयपुर-3

प्रकाशक

आनन्द भित्तल

आदर्श प्रकाशन

चौडा रास्ता, जयपुर-3

© सर्वाधिकार लेखकाधीन सुरक्षित

प्रथम संस्करण, 1975

द्वितीय संस्करण 1976

तृतीय संस्करण, 1977-78

चतुर्थ संस्करण, 1979

पंचम संस्करण

1981

मुल्य - तीस रुपये

मुद्रक

नवल प्रिन्टिंग प्रेस जयपुर

जयपुर मान प्रिन्टस, जयपुर

आदित्य प्रेस, जयपुर

पजावी प्रेस, मेरठ

## पंचम संस्करण की भूमिका

चार संस्करणों का छात्र एवं प्राध्यापक वर्ग ने जो अपार स्वागत किया उससे प्रेरित होकर यह संशोधित एवं परिमार्जित संस्करण आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे हर्ष है।

राजस्थान विश्व-विद्यालय के टी. डी. सी. अन्तिम वर्ष वाणिज्य (T. D. C. Final Year Commerce) के नवीन पाठ्यक्रमानुसार इस कृति का सृजन किया गया है। इसके अन्तर्गत आर्थिक नियोजन के सिद्धान्तों का विवेचन भारत, रूस व जापान के आर्थिक विकास के सन्दर्भ में किया गया है। चूंकि आर्थिक विकास एक सतत प्रयत्न निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और आर्थिक नियोजन विकास में सुनिश्चितता, विवेक व साधनों के समुचित प्रयोग द्वारा आर्थिक विकास की दर में तीव्रता लाता है। भारत के सन्दर्भ में नियोजित प्रत्यक्षव्यवस्था वाले राष्ट्र रूस तथा पूँजीवादी परिवेश में औद्योगिक दृष्टि से सम्पन्न राष्ट्र जापान के आर्थिक विकास के क्रांतिकारी घटकों का शृंखलाबद्ध, तार्किक एवं विशद विवेचन इस प्रकार किया गया है कि आर्थिक नियोजन के द्वारा विकासशील राष्ट्र भारत के तीव्र आर्थिक विकास के लिए मार्ग-दर्शन मिल सके ताकि आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक समानता व पर्याप्त रोजगार का स्वप्न साकार हो सके। इस कृति को अनावश्यक विषय-सामग्री से मुक्त रखा गया है ताकि बढ़ते हुए कागज मूल्यों का अधिक भार छात्रों पर न पड़े। आशा है यह कृति भी मेरी अन्य कृतियों की भांति लोकप्रिय होकर छात्र वर्ग व पाठकों को लाभान्वित करेगी।

मैं अपने सभी मित्रों व सहकर्मियों का हार्दिक आभारी हूँ जिन्होंने मुझे शैक्षणिक कार्यानुकूल वातावरण उपलब्ध करके इस कृति के सृजन में सहयोग व प्रोत्साहन दिया है। मैं अपने प्रकाशक मैसर्स आदर्श-प्रकाशन के श्री धानन्द मित्तल का भी विशेष आभारी हूँ जिनके सौजन्य से यह संस्करण ठीक समय पर आपके हाथों में पहुँच पाया है।

मेरी सभी विद्वजनों व शुभचिन्तकों से नम्र निवेदन है कि वे अपने प्रमूल्य सुझाव देकर आगामी संस्करणों को अधिक उपयोगी बनाने में लेखक को सहयोग कर अनुग्रहीत करें।

बी० एल० श्रीवा

“बसुन्धरा”

38-A, प्रतापनगर,

चित्तौड़गढ़ (राज०)



# SYLLABUS-UNIVERSITY OF RAJASTHAN

T D C Final Year Commerce

Paper I—Planning and Economic Development

## SECTION—A

I Theory of Planning—Meaning and Importance of Planning Types of Planning Objectives, Techniques, Plan formulation, Execution and Evaluation

II Economic Development in India—Since Independence The State of Indian Economy on the eve of Independence, Objectives and achievements of Planning in India

Important developments since 1947 in the following sectors of the economy

- (a) Agriculture Significance Land reforms Green revolution, Agricultural Marketing, Community development and new Agricultural strategy
- (b) Industry Industrial policy Role of State Capital and Labour, Intensive Industries in India, Growth of the Public Sector with special reference to steel, petroleum and fertilisers
- (c) Trade Commercial policy and balance of payments
- (d) Transport A general review of the growth of transport with special references to rail road and air services

## SECTION—B

III Lessons from Economic developments of U S S R and Japan with special reference to Agriculture, Industry, Trade and Transport

- (a) Economic Development of U S S R (Since 1917) Soviet Economy on the eve of revolution War Communism, New Economic Policy Main objectives and achievements of the Plans in the field of Agriculture, Industry Trade and Transport, Lessons to be drawn from the Economic development of U S S R for developing Economies, with special reference to India and
- (b) Economic Development of Japan (General background since 1868 with particular emphasis on developments after 1945) Significance of Meiji Restoration, Developments of Agriculture Industry trade and transport factors responsible for the rapid growth of Japanese economy after the Second World war Lessons to be drawn from the economic development of Japan for developing economies with special reference to India

# विषय-सूची

क्रम सं०	विषय	पृष्ठ सं०
	भाग 1-नियोजन के सिद्धान्त एवं भारत में आर्थिक नियोजन (Principles of Planning and Planning in India)	
1	आर्थिक विकास में नियोजन का महत्व <u>५४०-४१</u>	
1	<u>Significance of Planning for Economic Development</u>	3
2	आर्थिक नियोजन के प्रकार या विभिन्न रूप <u>५४१</u>	
2	<u>Types of various Forms of Economic Planning</u>	25
3	अर्द्ध-विकसित राष्ट्र एवं उनकी आधारभूत समस्याएँ	
3	<u>Under-developed Countries &amp; Their Basic Problems</u>	38
4	आर्थिक विकास, निर्धारक तत्व एवं आधारभूत आवश्यकताएँ	
4	<u>Economic Development, Its Determinants and Basic Requisites</u>	59
5	आर्थिक नियोजन की तकनीक एवं विधि	
5	<u>Techniques and Methodology of Economic Planning</u>	79
6	आर्थिक नियोजन के उद्देश्य <u>५४१</u>	
6	<u>Objectives of Planning</u>	94
7	भारत में योजना निर्माण व योजना-तन्त्र	
7	<u>Plan Formulation and Planning Machinery in India</u>	116
8	1951 से भारत में पञ्चवर्षीय योजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन	
8	<u>Execution and Evaluation of Plans in India Since 1951</u>	133
9	चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना	
9	<u>Fourth Five Year Plan</u>	150
10	पाँचवी पञ्चवर्षीय योजना (1974-79)	
10	<u>Fifth Five Year Plan (1974-79)</u>	160
11	भारत में योजनाबद्ध विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ (1951-52 से 1978-79) <u>५४१</u>	
11	<u>Important Achievements of Planned Development in India (Since 1951-52 to 1978-79)</u>	167

क्रम सं०	विषय	पृष्ठ सं०
12.	छठी पंचवर्षीय योजना (1978-83) L 980 Draft of Sixth five Year Plan (1978-83)	182
13.	परिशिष्ट—आवर्ती योजना अथवा अनवरत योजना Rolling Plan	189
	भाग 2—स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में आर्थिक विकास (Economic Development in India Since Independence)	
1.	स्वतन्त्रता प्राप्ति की पूर्व संध्या को भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा ✓ State of Indian Economy on the Eve of Independence	3
2.	भारत में कृषि नीति एवं विकास Agricultural Policy and Development in India	10
3.	कृषि विकास की नवीन व्यूह-रचना बनाम हरित क्रान्ति + 1980-81 New Agricultural Strategy and Green Revolution	27
4.	भारत में भूमि सुधार ✓ Land Reforms in India	42
5.	भारत में कृषि विपणन अथवा कृषि उपज का विक्रय L 980 Agricultural Marketing in India	61
6.	सामुदायिक विकास ✓ Community Development	72
7.	भारत में औद्योगिक नीति एवं लाइसेंस नीति 1980 Industrial Policy & Licensing Policy in India	84
8.	भारत में औद्योगीकरण एवं औद्योगिक विकास की प्रवृत्तियाँ ✓ Industrialisation & Trends in Industrial Growth of India	106
9.	उद्योगों में राज्य अथवा सरकार की भूमिका ✓ Role of the State in Industries	119
10.	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विकास 1980-81 Growth of Industries in Public Sector	126
11.	भारत में पूँजी गहन अथवा वृहत् उद्योग Capital Intensive In India	149
12.	श्रम प्रधान लघु एवं कुटीर उद्योग ✓ Labour Intensive Small Scale Industries	170
13.	भारतीय विदेशी व्यापार की संरचना एवं दिशा तथा व्यापारिक नीति की प्रवृत्तियाँ 1981 Trends in Composition and Direction of Foreign Trade and Commercial Policy	187

क्रम सं०	विषय	पृष्ठ सं०
14	भारत का भुगतान सन्तुलन अथवा भुगतान शेष Balance of Payments of India	212
15	1947 से रेल यातायात का विकास 1980 Growth of Rail Transport since 1947	224
16	1947 से सड़क यातायात का विकास Growth of Road Transport Since 1947	234
17	1947 से वायु तथा भ्रान्तरिक जल यातायात का विकास 1981 Growth of Air, Shipping & Inland Water Transport	249
भाग 3-रूस का आर्थिक विकास (Economic Development of U.S.S.R.)		
1	क्रान्ति से पूर्व रूस की अर्थव्यवस्था ✓ Economy of Russia Before Revolution	3
2	रूस में यौद्धिक साम्यवाद 1981 War Communism in U.S.S.R.	15
3	सोवियत रूस में नवीन आर्थिक नीति (1921-28) 1980 New Economic Policy in U.S.S.R.	28
	परिशिष्ट (Appendix) कैंची सकट	46
4	रूसी योजनाओं के मूल उद्देश्य एवं उपलब्धियाँ Main Objectives & Achievements of Plans of U.S.S.R.	51
5	क्रान्ति के बाद सोवियत रूस के आर्थिक विकास के 61 वर्ष (1917-1978) Economic Development of U.S.S.R. Since 1917 to 1978	81
6	क्रान्ति के बाद रूस में कृषि विकास 1980 Agricultural Development in U.S.S.R. Since Revolution	90
7	1917 से रूस में औद्योगिक विकास अथवा औद्योगिकीकरण Industrial Development of Industrialisation in U.S.S.R. Since 1917	111
8	रूस में व्यापार विकास 1981 Development of Trade in U.S.S.R.	121
9	सोवियत रूस में यातायात विकास Development of Transport in U.S.S.R.	126
10	विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को रूसी आर्थिक विकास से शिक्षाएँ 1981 Lessons from Economic Development of U.S.S.R. for Developing Economies with Special Reference to India	131

क्रम सं०	विषय	पृष्ठ सं०
	<b>भाग 4-जापान का आर्थिक विकास</b> (Economic Development of Japan)	
1	जापान में मेजी पुनर्स्थापन का महत्व ✓ Significance of Meiji Restoration	1
2.	जापान में कृषि विकास 1981 Agricultural Development in Japan	16
3	जापान में औद्योगिक विकास 1981 Industrial Development in Japan	30
4	जापान के प्रमुख उद्योगों का उभरना Growth of Principal Industries	45
5.	जापान में लघु उद्योगों की भूमिका Role of Small Scale Industries in Japan	66
6.	जापान के विदेशी व्यापार का विकास एवं मुख्य विशेषताएँ 1982 Development of Foreign Trade of Japan	82
7	द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद जापानी अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास के कारण ✓ Factors Responsible for Rapid Growth of Japanese Economy after Second World War	99
8	जापान में परिवहन (यातायात) साधनों का विकास Development of Transport in Japan	117
9	जापान के आर्थिक विकास भ्रष्ट विकसित देशों को शिक्षाएँ Lessons from Economic Development of Japan for Under-developed or Developing Economies	128

भाग 1  
(PART ONE)

नियोजन के सिद्धान्त एवं  
भारत में आर्थिक नियोजन  
(PRINCIPLES OF PLANNING & PLANNING IN INDIA)

---

- 1 आर्थिक विकास में नियोजन का महत्व  
(Significance of Planning for Economic Development)
  - 2 आर्थिक नियोजन के प्रकार अथवा विभिन्न रूप  
(Types of Planning)
  - 3 अर्द्ध-विकसित राष्ट्र एवं उनकी समस्याएँ  
(Under-Developed Countries & Their Basic Problems)
  - 4 आर्थिक विकास, निर्धारक तत्व एवं आधारभूत आवश्यकताएँ  
(Economic Development, its Determinants & Basic Requisites)
  - 5 आर्थिक नियोजन की तकनीकी एवं विधि  
(Techniques & Methodology of Economic Planning)
  - 6 आर्थिक नियोजन के उद्देश्य  
(Objectives of Planning)
  - 7 योजना निर्माण व भारत में योजना तन्त्र  
(Plan Formulation & Planning Machinery in India)
  - 8 1951 से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन  
(Execution & Evaluation of Plans in India Since 1951)
  - 9 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना  
(Fourth Five Year Plan)
  - 10 पाचवी पंचवर्षीय योजना 1974-79  
(Fifth Five Year Plan)
  - 11 भारत में योजनाबद्ध विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ (1951-52 से 1977-78)  
(Important Achievement of Planned Development in India Since 1951-52 to 1977-78)
  - 12 छठी पंचवर्षीय योजना (1978-83)  
(Sixth Five Year Plan)
- परिशिष्ट—आदर्श योजना एवं खन्योद्घय

## आर्थिक विकास में नियोजन का महत्व

(SIGNIFICANCE OF PLANNING IN  
ECONOMIC DEVELOPMENT)

### आर्थिक नियोजन—एक परिचय

आज सम्पूर्ण विश्व में नियोजन का बोलचाल है। चाहे विकसित राष्ट्र हो और चाहे विकासशील राष्ट्र, सभी आर्थिक नियोजन के द्वारा अपनी आर्थिक समस्याओं के निराकरण के लिये प्रयत्नशील हैं। सभी भौतिक समृद्धि, आर्थिक स्थायित्व एवं विकास के लिये नियोजन को अपना रहे हैं। इसी कारण प्रो० रोबिन्स ने ठीक ही कहा है। “आर्थिक नियोजन हमारे युग की समस्त आर्थिक समस्याओं के निराकरण की एक अच्छी रामबाण औषधि है—कल्याणकारी राज्य के आदर्श की प्राप्ति का एकमात्र साधन आर्थिक नियोजन ही है।”<sup>1</sup>

विकसित राष्ट्र आर्थिक स्थायित्व व भावी विकास के लिये नियोजन का सहारा लेते हैं और विकासशील तथा अर्द्ध विकसित राष्ट्र अपने उपलब्ध साधनों के नियोजित विद्योहन से आर्थिक विकास व समृद्धि के लक्ष्य से प्रेरित हैं ताकि निर्धनता, शोषण व बेकारी से मुक्ति मिले। ‘विश्व के किसी भी भाग में गरीबी, विश्व शान्ति एवं समृद्धि की खतरा है’ यही कारण है कि विकसित राष्ट्र व्यक्तिगत रूप में तथा सामूहिक रूप में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से विकासशील एवं अर्द्ध विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिये आर्थिक, तकनीकी एवं अन्य सहायता देने के लिये जागरूक एवं सतत् प्रयत्नशील हैं।

साधनों की सीमितता और आवश्यकताओं की अनन्तता के कारण नियोजन राष्ट्र-धर्म बन गया है। अपने महत्व के कारण यह केवल सिद्धान्त ही नहीं बरन् व्यावहारिक नीतियों का अविभाज्य अङ्ग बन गया है। आज नियोजन के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद नहीं है, विवाद है तो केवल उसके स्वरूप पर। इसी कारण

1 Economic Planning is a grand panacea of our age      Economic  
Planning is the only means of realising the ideal of a Welfare State  
—L. Robbins

प्रो० लेविंस ने लिखा है 'नियोजन के सम्बन्ध में केन्द्रीय बात यह नहीं कि नियोजन होना चाहिये या नहीं—वरन् यह है कि नियोजन का स्वरूप क्या हो। अब निरपेक्षता की नीति (Policy of Laissez) की कल्पना पाल ही कर सकते हैं।'

### आयोजन या नियोजन का अर्थ एवं परिभाषायें (Meaning and Definitions)

आर्थिक शब्दावली में समाजवाद की भांति नियोजन शब्द का अर्थ भी विभिन्नताओं के भ्रम में उसझा हुआ है अतः कोई सुनिश्चित एवं सर्वमान्य धारणा सम्भव नहीं। सामान्यतः आर्थिक नियोजन का अभिप्राय राष्ट्र की उस नियमित एवं विवेकपूर्ण व्यवस्था से लिया जाता है जिसमें आर्थिक क्रियाओं का संचालन पूर्वं निश्चित उद्देश्यों के अनुरूप अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिये किया जाता है। साहित्यिक दृष्टि से "किमी विशिष्ट आर्थिक उद्देश्य से किया गया राजनीय कार्य आर्थिक नियोजन कहलाता है पर यह बहुत ही सखीण है। स्वर्गीय प० जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में 'नियोजन का अर्थ केवल कार्य-सूची बना लेने से नहीं और न यह कोई राजनैतिक आदर्शवाद है। आयोजन एक बुद्धिमत्तापूर्ण, विवेकपूर्ण तथा वैज्ञानिक पद्धति है जिसके अनुसार हम अपने आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्य निर्धारित करते हैं और प्राप्त करते हैं।' नियोजन के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है—

प्रो० रॉबिन्स (L Robbins) के अनुसार "सच्चे मायन में सम्पूर्ण आर्थिक जीवन नियोजन में भरा है। आयोजन करने का अभिप्राय वायदे के साथ कार्य करना है चयन करना और चयन ही आर्थिक क्रियाओं का सार है।" जन्मन उन्होंने लिखा है कि आधुनिक शब्दावली में 'नियोजन का अभिप्राय राज्य द्वारा उत्पादन के साधनों पर किसी न किसी प्रकार का नियन्त्रण है।'

ये दोनो ही परिभाषायें अपूर्ण हैं क्योंकि रॉबिन्स ने नियोजन का अर्थ बहुत ही सखीण दृष्टिकोण से लिया है जिसमें राज्य के नियन्त्रण को ही नियोजन मान लिया है। केवल चयन करना ही पर्याप्त नहीं सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था के व्यापक सर्वेक्षण के बाद एक निश्चित अर्थ में पूरा निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिये उत्पादन, वितरण व उपभोग सब पर नियन्त्रण ही आयोजन कहलाता है।

प्रो० हैक (Hayek) के शब्दों में "आर्थिक नियोजन का अर्थ एक केंद्रीय मता द्वारा उत्पादन क्रियाओं का निर्देशन है।" प्रो० हैक की परिभाषा भी अपर्याप्त है किन्तु यह नियोजन के अर्थ को उल्टा कर केवल निर्देशन तत्त्व पर ही ध्यान देती है।



श्रीमती बारबरा वूटन (Mrs Barbara Wootton) के मतानुसार "जिसी सार्वजनिक सत्ता द्वारा विचारपूर्वक एवं जान-बूझकर आर्थिक प्राथमिकताओं के चयन करने की क्रिया को आर्थिक नियोजन कहते हैं।" इस परिभाषा में भी केवल प्राथमिकताओं के निर्धारण पक्ष पर जोर दिया गया है तथा स्वतन्त्र बाजार तन्त्र में जान बूझकर हस्तक्षेप से एक अलग व्यवस्था वायम बनाने की बात नहीं। पर इन दोनों तत्वों के अनिवार्य आर्थिक नियोजन के अधिक महत्वपूर्ण तत्वों की अवहेलना अनुपयुक्त है।

प्रो० एच० डी० डिकिन्सन (H D Dickinson) के अनुसार "आर्थिक नियोजन प्रमुख आर्थिक निर्णय करने की वह क्रिया है जिसमें समस्त अर्थ-व्यवस्था के व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर एक निर्धारक सत्ता द्वारा विचारपूर्वक निर्णय लिये जाते हैं कि क्या और कितना उत्पादन किया जाय, कैसे, कब और कहाँ उत्पादन किया जाये और इसका वितरण किनमें हो?"

प्रो० डिकिन्सन की यह परिभाषा बहुत ही उपयुक्त मानी जा सकती है क्योंकि इसमें आर्थिक नियोजन के प्रायः सभी तत्वों का समवेश है। इसमें केवल पूर्व निर्धारित उद्देश्यों व निश्चित अवधि के तत्वों को भुला दिया गया है।

प्रो० लुईस लार्विन (Lewis Larwin) के शब्दों में 'नियोजित अर्थ व्यवस्था आर्थिक संगठन की एक ऐसी पद्धति है जिसके अन्तर्गत एक निश्चित अवधि में जनता की आवश्यकताओं की अधिकतम सन्तुष्टि के लिये समस्त उपलब्ध साधनों का प्रयोग के उद्देश्य से सभी व्यक्तिगत एवं भिन्न-भिन्न कारखानों, उपकरणों व उद्योगों को एक ही व्यवस्था की समन्वित हवाइयाँ माना जाता है।"

लुईस लार्विन की इस परिभाषा में भी नियोजन के प्रायः सभी तत्व सम्मिलित

- 1 "Planning may be defined as the conscious and deliberate choice of economic priorities by some public authorities"

—Mrs Barbara Wootton *Plan or no Plan*,

- 2 *Economic Planning is the making of major economic decision What and how much is to be produced how, when and where is to be produced and to whom it is to be allocated by the conscious decision of a determinate authority on the basis of a comprehensive survey of the economic system as a whole.*

—H D Dickinson *Economic of Socialism* p 14

- 3 "Planned economy is a scheme of economic organisation in which individual and separate plants, enterprises and industries are treated as co-ordinated units of a single system for the purpose of utilising available resources to achieve the maximum satisfaction of the peoples' needs within a given time"

—Lewis Larwin

(2) केन्द्रीय नियोजन सत्ता—आर्थिक नियोजन में अर्थ-व्यवस्था का संचालन स्वतः बाजार-प्रक्रिया (Market Mechanism) द्वारा न होकर सरकार या राज्य की केन्द्रीय मत्ता द्वारा किया जाता है जो देश के उपलब्ध साधनों का सर्वेक्षण करती है, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप उनके प्रयोग का चयन व समन्वय करती है। विकास की योजनाओं का निर्माण, कार्यान्वित व मूल्यांकन व आवश्यक समन्वय बैठाने का कार्य भी केन्द्रीय नियोजन सत्ता द्वारा किया जाता है।

(3) पूर्व निर्धारण उद्देश्य—देश की वार्षिक, राजनैतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये आर्थिक नियोजन के उद्देश्य सुविचारित एवं पूर्व निर्धारित होते हैं और केन्द्रीय सत्ता इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करती है।

(4) प्राथमिकताओं का निर्धारण—आवश्यकताओं की अत्यन्तता और साधनों की सीमितता के कारण केन्द्रीय नियोजन सत्ता पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के बीच प्राथमिकताओं का निर्धारण करती है।

(5) साधनों का आवंटन एवं प्रयोग—आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत उत्पादन के सभी साधनों—चाहे वे निजी स्वामित्व में हों और चाहे सार्वजनिक स्वामित्व में—पर सरकार या नियोजन सत्ता सत्ता का प्रभावी नियन्त्रण रहता है। सरकार इन साधनों का आवंटन एवं प्रयोग पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्राथमिकताओं (Priorities) के आधार पर करती है।

(6) निर्धारित समय—आर्थिक नियोजन की एक महत्वपूर्ण विशेषता समयबद्ध निर्दिष्ट करना है। पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति इस अवधि विशेष में किये जान का प्रावधान होता है। निर्दिष्ट समय में उद्देश्यों की पूर्ति ही योजना की सफलता का द्योतक है।

(7) नियोजन एक निरंतर एवं दीर्घकालीन प्रक्रिया है—नियोजन एक आकस्मिक एवं अल्पकालीन प्रयास न होकर निरन्तर एवं दीर्घकालीन प्रक्रिया (Continuous and long period process) होती है। अल्पकालीन योजनाओं को दीर्घकालीन योजनाओं से समन्वित किया जाता है।

(8) राज्य का हस्तक्षेप एवं साझेदारी—आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप या राज्य की साझेदारी का तत्त्व विद्यमान होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग राज्य द्वारा संचालित होते हैं। संयुक्त क्षेत्र में राज्य व निजी उद्यमकर्त्ताओं के बीच साझेदारी व सहयोग होता है और निजी क्षेत्र के उद्योगों के संचालन पर राज्य का प्रभावी नियन्त्रण व हस्तक्षेप रहता है।

(9) आर्थिक नियोजन का व्यापक दृष्टिकोण—आर्थिक नियोजन सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को समष्टि दृष्टिकोण के आधार पर देखता है और सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर लागू किया जाता है। आंशिक नियोजन जो किसी क्षेत्र विशेष के लिये होता है उसकी सफलता सन्दिग्ध रहती है।

(10) संरचनात्मक परिवर्तन—विनासमान आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय व एकीकरण के परिणामस्वरूप संरचनात्मक परिवर्तनों (Structural changes) का प्रादुर्भाव होता है। अर्थ-व्यवस्था का रूढ़िवादी ढांचा धाराशाधी होकर नवीन प्रगतिशील संस्थाओं को जन्म देता है।

(11) जन-सहयोग—आर्थिक नियोजन की कल्पना जन सहयोग पर आधारित है और यही नियोजन की सफलता का आधार स्तम्भ है। जन-सहयोग के अभाव में योजनाओं की सफलता मन्दिग्ध ही रहनी है।

(12) अन्तिम उद्देश्य—आर्थिक नियोजन का अन्तिम उद्देश्य देश के उपलब्ध एवं सम्भावित साधनों के समुचित प्रयोग से अधिकतम सामाजिक कल्याण के लक्ष्य की प्राप्ति करना है।

**आर्थिक नियोजन की आवश्यकता व लोकप्रियता के कारण**

**(Need of Economic Planning & Causes of its Popularity)**

अवास्तविक मांगताओं पर आधारित जे० बी० से० का पूर्ति नियम (Supply creates its own Demand) और एडम स्मिथ के आर्थिक निरपेक्षता (Laissez Faire) एवं स्वहित के षोथ सिद्धान्त 20वीं शताब्दी की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं में जटिलताओं में धाराशाधी हो गये तो आर्थिक जीवन में नियोजन की आवश्यकता पड़ी। अर्थ व्यवस्था में स्थायित्व एवं विकास के लिये आर्थिक नियोजन की आवश्यकता महसूस हुई है। प्रो० रोबिन्स ने तो 'आर्थिक नियोजन को हमारे युग की समस्त आर्थिक समस्याओं के निराकरण की अचूक रामरान औपधि' माना है। अतः नियोजन अब केवल सिद्धान्त ही नहीं बल्कि यह सम्पूर्ण आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन का अविभाज्य अंग बनता जा रहा है। "आर्थिक नियोजन एक राक्षस नहीं बल्कि साधन मान है। इसकी आवश्यकता योजना निर्माण में ही नहीं बल्कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में निहित है ताकि राष्ट्रीय आय, उत्पादन रोजगार व जीवन-स्तर में वृद्धि हो। अर्थ-व्यवस्था में स्थायित्व, सुरक्षा व विकास का मार्ग प्रशस्त हो। आधुनिक युग में नियोजन की आवश्यकता व बढ़ती हुई लोक-प्रियता के निम्न कारण हैं—

(1) पूँजीवादी एवं स्वतन्त्र उपह्म व्यवस्था के दोषों का निवारण—नियोजन की लोकप्रियता का प्रमुख कारण उसमें पूँजीवाद के दोषों के निराकरण की क्षमता है। पूँजीवाद में व्याप्त आर्थिक असमानता, शोषण, व्यापार क्षेत्रों के दुष्प्रभाव, बेकारी, सम्पन्नता में विषमता, साधनों का अपव्यय आदि दोषों का निराकरण आर्थिक नियोजन में ही निहित है। यही कारण है कि लार्ड केन्स (J M Keynes) ने पूँजीवाद की युराइयो के समापन के लिये राज्य-हस्तक्षेप का समर्थन किया। समाजवादी डर्बिन (E F M Durbin) के शब्दों में "केवल नियोजन ही पूँजीवाद की युराइयो को दूर करने का एक मात्र साधन और आशा प्रदान करता है।"

(2) सोवियत रूस व नازی जर्मनी में नियोजन की अप्रत्याशित सफलताएँ—विश्व के विकासशील व विकसित राष्ट्रों में आर्थिक नियोजन की लोकप्रियता का दूसरा कारण रूस व जर्मनी में इसकी अभूतपूर्व सफलता थी। 1917 की क्रांति के बाद रूस ने आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाकर अपनी पिछड़ी अर्थ-व्यवस्था को बहुत ही समृद्ध एवं शक्तिशाली बनाकर सम्पूर्ण विश्व को आश्चर्य चकित कर दिया। इसी प्रकार 1933 में जर्मनी में व्याप्त बेरोजगारी के निवारण के लिये बनाई गई चार-वर्षीय योजना पर्याप्त सफल रही। अतः सभी राष्ट्रों में आर्थिक नियोजन के प्रति आकर्षण निरन्तर बढ़ता गया।

(3) युद्ध में विजयध्वी व पुनर्निर्माण का अनुभव—विश्व युद्ध में सलग्न इन राष्ट्रों ने युद्ध जीतने के लिये अपने सीमित साधनों के विवेकपूर्ण ढंग से सैनिक तथा नागरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आर्थिक आयोजन की अनिवार्यता महसूस की। और प्रभावी नियन्त्रण लागू किये जो युद्धों की समाप्ति के बाद भी किसी न किसी रूप में चालू रहे। ताकि युद्ध-जर्जरित अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण किया जा सके।

द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से जर्जरित यूरोपीय देशों की अर्थ-व्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण व पुनर्विकास के लिये मार्शल योजना (Marshall Plan) लागू की गई तथा उनकी सफलता के परिणामस्वरूप आर्थिक नियोजन की लोकप्रियता और बढ़ी।

(4) व्यापार चक्रों से मुक्ति—1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी ने सम्पूर्ण विश्व अर्थ-व्यवस्थाओं को पकथोर दिया और मन्दी से उत्पन्न बेकारी, भुख-मरी व ग़ातनाओं से मुक्ति पाने के लिये राज्य हस्तक्षेप की दुहाई दी जाने लगी। अमेरिका में न्यू डील (New Deal) व ब्रिटेन में आर्थिक स्थिरीकरण की नीनियाँ इसकी परिचायक हैं अतः व्यापार चक्रों से मुक्ति पाने के लिये आर्थिक नियोजन की आवश्यकता व लोकप्रियता बढ़ी।

(5) अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में विकास के प्रति जागरूकता—द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त जब अफ्रीका व एशिया के बहुत से अर्द्ध-विकसित राष्ट्र औपनिवेशिक दासता से मुक्त हुये तो उनकी स्वतन्त्र जनता में विकास की प्रबल भावना जागृत हुई। अर्द्ध-विकसित देशों की जनता में तीव्र आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय व समानता, आर्थिक शोषण से मुक्ति व समृद्ध आर्थिक जीवन के लिये आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाया। अतः आर्थिक नियोजन की आवश्यकता अर्द्ध-विकसित व विकासशील राष्ट्रों के तीव्र गति से आर्थिक विकास माग प्रशस्त करने के लिये है और इसी कारण इसकी लोकप्रियता बढ़ता स्वाभाविक है।

(6) आर्थिक नियोजन की विचारधारा (Ideology) का प्रसार—आर्थिक नियोजन की आवश्यकता महसूस कराने तथा उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय उन

प्रो० रोबिन्स ने कहा है कि "आर्थिक नियोजन हमारे युग की आर्थिक समस्याओं के निराकरण की अचूक रामबाण औषधि है।" इसी परिप्रेक्ष्य में आर्थिक नियोजन के निम्न लाभ उसके पक्ष के प्रबल तर्क हैं—

(1) साधनों का सर्वोत्तम उपयोग एवं तीव्र आर्थिक विकास (Optimum Utilisation of Resources & Rapid Economic Development)—आर्थिक नियोजन के द्वारा देश में उपलब्ध साधनों व सम्भावित साधना का प्रयोग प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। उनके अपव्यय को रोका जाता है। प्रयोग में द्विगुणन (Duplication) को रोक उचित समन्वय बँटाया जाता है। उपयोग पर प्रभावी नियन्त्रण होने से उनका सर्वोत्तम उपयोग तीव्र आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है।

(2) अधिकतम सामाजिक कल्याण (Maximum Social Welfare)—नियोजित अर्थ-व्यवस्था व्यक्तिगत लाभ व स्वहित की भावना से प्रेरित न होकर अधिकतम सामाजिक कल्याण (Maximum good of Maximum Number) के लक्ष्य से प्रेरित होती है। शोषण, कृत्रिम बर्मी व पराधितता को समाप्त कर आर्थिक एवं सामाजिक न्याय की व्यवस्था की जाती है। आर्थिक विकास के साथ ही समाज के अधिकतम हित में वितरण होता है जिससे अधिकतम सामाजिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है।

(3) साधनों का अनुकूलतम वितरण व अपव्यय पर रोक (Optimum Distribution of Resources & Control over Wastage)—पूँजीवाद की अनियोजित अर्थ व्यवस्था में साधनों का निजी लाभ के लिए निर्दयतापूर्ण दुरुपयोग होता है। साधनों का प्रयोग धनिकों की विरासतियों में कर निर्धनों की अनिवार्यताओं की उपेक्षा की जाती है। अमेरिका में शिक्षा व सामाजिक सुरक्षा पर 5 अरब डॉलर के खर्च के मुकाबले सराव पर 7 अरब डॉलर खर्च को नियोजित अर्थ व्यवस्था बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि नियोजित अर्थ-व्यवस्था में समस्त प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों का उत्पादन व उपभोग में वितरण अनुकूलतम करने का भरसक प्रयास होता है। सरकार साधनों के वितरण पर प्रभावी नियन्त्रण रखती है।

(4) आर्थिक विषमताओं की कमी (Reduction in Economic Inequality)—आर्थिक नियोजन के अभाव में स्वतन्त्र मूल्य यन्त्र प्रणाली साधनों का वितरण धनिकों के पक्ष में करती है जिसमें धनिक और अधिक धनी तथा गरीब अधिक गरीब होते जाते हैं। जबकि आर्थिक नियोजन के द्वारा प्रगतिशील करारोपण व सामाजिक ध्येय से आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयास रहता है।

(5) निर्णयों व कार्यों में समन्वय (Co-ordination in Actions & Decisions)—एक अनियोजित पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में असरय उत्पादकों व्यापारियों व उपभोक्ताओं के असंग-अलग कार्यों व निर्णयों में परस्पर समन्वय न होने से व्यापार-चक्रों का जन्म होना है। प्रो ए. के लर्नर (A K Lerner) व शब्दों में,

“अनियोजित पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना एक चातक बिहीन मोटर से की जा सकती है जिसमें सभी यात्री इसके स्टियरिंग व्हील को अपनी इच्छानुसार घुमाने का प्रयास करते हैं।” परिणामस्वरूप परस्पर मर्घर्ष व सवट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जबकि नियोजित अर्थव्यवस्था अधिवादा कार्यों व निर्णयों में केन्द्रीय नियोजन गता द्वारा यथामुम्भव समन्वय स्थापित कर साधनों का आदर्शतम उपयोग व वितरण किया जाता है।

(6) दूरदर्शितापूर्ण निर्णय (Far Sighted Decisions)—एक नियोजित अर्थव्यवस्था अनियोजित स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था की अपेक्षा बड़ी अधिक दूरदर्शी होती है। इसी कारण नियोजित अर्थव्यवस्था को एक खुले नेत्र वाली अर्थव्यवस्था (An Economy with open Eyes) कहा जाता है। अनियोजित पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में असम्य उत्पादन, व्यापारी व उपभोक्ता अपने-अपने अल्पकालीन लाभ के लिये भावी भविष्य को भूल जात हैं जबकि नियोजित अर्थव्यवस्था में केन्द्रीय नियोजन सत्ता प्रत्यक्ष आर्थिक निर्णय को भावी भविष्य के परिप्रेक्ष्य में परखती है। प्रो डब्लिन ने केन्द्रीय नियोजन सत्ता की तुलना सेनापति और असम्य स्वतन्त्र उत्पादकों, व्यापारियों व उपभोक्ताओं की तुलना सैनिकों से करते हुए लिखा है, ‘एक पहाड़ी पर खड़ा सेनापति युद्ध कबित में लड़े सैनिकों की अपेक्षा अधिक देखने योग्य होता है’ अतः स्पष्ट है कि नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय दूरदर्शी होते हैं।

(7) व्यापार चक्रों से मुक्ति एवं आर्थिक स्थायित्व (Freedom from Trade Cycles & Establishment of Economic Stability)—एक अनियोजित पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में असम्य मनमाने एवं अदूरदर्शिता निर्णयों में परस्पर समन्वय के अभाव में अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों का प्रादुर्भाव होता है और अर्थव्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न होती है जबकि नियोजित अर्थव्यवस्था में विवेकपूर्ण एवं दूरदर्शी निर्णयों, कार्यों व निर्णयों में समन्वय तथा प्रभावी नियन्त्रण होने से आर्थिक तेजी-मन्दी के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है और अर्थव्यवस्थाओं में स्थायित्व आता है।

(8) कटु प्रतिस्पर्धा के दोषों व सामाजिक लागतों का समापन (Abolition of Cut Throat Competition & Social Costs)—एक नियोजित अर्थव्यवस्था में गला घोट प्रतियोगिता साधनों के दुष्प्रयोग व अपव्यय को बढ़ाती है। विज्ञापन, चित्रण कला पर भारी व्यय होता है। प्रो डब्लिन के शब्दों में “कटु प्रतिस्पर्धा की संस्था आर्थिक जीवन को बुद्धिमत्तापूर्ण दिशा में नहीं ले जाती” अतः नियोजित अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा को अत्यन्त सीमित कर देने में जगने दृष्टप्रभावों में सुक्ति मिल जाती है। इसी प्रकार अनियोजित पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में समाज को अनेक हानिकारक परिणामों का मार उठाना पड़ता है जो औद्योगिक बीमारियों, चण्डीय बेकारी, औद्योगिक मन्दी दस्तियों का निर्माण, धूर्तदार अस्वस्थ नताकरण व दण्डनाओं के रूप में होने हैं। प्रो पीगू ने दृढ़ पूँजीवाद का दिवानियापन कहा है।

(9) शोषण से मुक्ति व सामाजिक पर आर्थिकों का समापन (Abolition of

**Exploitation & Social Parasites)**—अनियोजित पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी लाभ की भावना से श्रमिकों, उपभोक्ताओं व निर्बल वर्गों का शोषण होता है। कृत्रिम अभावों का सृजन कर ऊँचे मूल्यों में काला बाजारी की जाती है। धनी गरीबों का शोषण करते हैं और कई व्यक्ति उत्तराधिकार में प्राप्त अपार सम्पत्ति के कारण भारी मात्रा में लगान, व्याज, लाभ बिना किसी परिश्रम के ही अर्जित करते हैं। इस अनाजित आय (Unearned Income) के द्वारा जीवन निर्वाह करने वाले समाज के खटमल हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था में निजी सम्पत्ति के स्वामित्व को सीमित कर देने से सामाजिक पराधिनो (Social Parasites) का समापन कर दिया जाता है। वितरण पर सरकार का प्रभावी नियन्त्रण होने से कृत्रिम अभावों का भय समाप्त होता है। निजी लाभ के स्थान पर अधिकतम सामाजिक लाभ की प्रधानता के कारण शोषण नहीं हो पाना। स्पष्ट है कि नियोजित अर्थव्यवस्था में शोषण से मुक्ति मिलती है और सामाजिक पराधिनो का समापन होता है।

**(10) सामाजिक न्याय और आर्थिक सुरक्षा (Social Justice & Economic Security)**—नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता, उचित मजदूरी लाभ का न्यायोचित वितरण, और रोजगार की पर्याप्त व्यवस्था के साथ साथ समाज के पाँच महान शत्रुओं—बेकारी, बीमारी, वृद्धावस्था, मृत्यु व दुर्घटनाओं पर विजय के लिये सरकार सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था भी करती है। इस प्रकार सामाजिक न्याय आर्थिक सुरक्षा व औद्योगिक शान्ति आर्थिक नियोजन में ही निहित है। अनियोजित अर्थव्यवस्था में असमान वितरण, शोषण, व्यापार चक्रों और सुरक्षा के अभाव में सामाजिक न्याय की कल्पना है।

**(11) पूँजी निर्माण की ऊँची दर (High Rate of Capital Formation)**—नियोजित अर्थव्यवस्था में अनियोजित अर्थव्यवस्था की अपेक्षा पूँजी निर्माण की गति तेज होती है क्योंकि साधनों के अनुबलतम उपयोग से उत्पादन व विनियोग बढ़ते हैं और आय-वचत व विनियोग बढ़ते ही जाते हैं। उपभोग को नियन्त्रित कर पूँजी निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाता है। रूस में तोत्र गति से पूँजी निर्माण इसका परिचायक है।

**(12) नवीन परिवर्तनों से शीघ्र सामंजस्य व अधिकतम तकनीकी कुशलता (Speedy Adjustment with New changes & Maximum Technical Efficiency)**—नियोजित अर्थव्यवस्था में वैज्ञानिक आविष्कार एवं अनुसंधानों से उत्पादन तकनीकी में होने वाले परिवर्तनों के साथ शीघ्र सामंजस्य बैठाया जाता है ताकि उत्पादन तकनीक से अधिकतम लाभ सम्भव हो सके। अर्थव्यवस्था में विवेकीकरण (Rationalisation), विशिष्टीकरण (Specialisation) तथा वैज्ञानिक प्रबन्ध (Scientific Management) के लिये आर्थिक नियोजन द्वारा ही सत्यागत संरचना में तीव्रगामी परिवर्तनों से नवीन परिवर्तनों के अनुरूप शीघ्र एवं सुगम सामंजस्य बैठाया जाता है। अनियोजित पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में नवीन परिवर्तनों

के साथ शीघ्र सामन्जस्य बैठाने तथा अधिकतम तकनीकी बुद्धलता प्राप्त करने की प्रक्रिया धीमी होती है।

(13) युद्ध व राष्ट्रीय संकट के समय नियोजित अर्थव्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त व्यवस्था (Planned Economy is most efficient system in War & National Emergency)—युद्ध काल में शत्रु पर विजय पाने की दृष्टि से उपराष्ट्र साधना का नियोजन द्वारा समुचित उपयोग किया जाता है तथा आर्थिक नियोजन से युद्ध-जर्जरित अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण व पुनर्स्थापन भी तीव्र गति से हो सकता है। राष्ट्रीय संकटों का मुकाबला करने की क्षमता नियोजित अर्थव्यवस्था में अनियोजित अर्थव्यवस्था की अपेक्षा अधिक रहती है। 1930 की विश्व व्यापी आर्थिक मंदी में जब समूचा विश्व बरागी व भुखमरी से ग्रस्त था तब की नियोजित अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार व आर्थिक समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर थी। पूँजीवादी राष्ट्र अमेरिका की भी न्यूडील, (New Deal) की नीति आर्थिक नियोजन का प्रतीक थी।

(14) अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में तीव्र आर्थिक विकास (Rapid Economic growth in Under-Developed or developing Countries)—आज विश्व के अनेक राष्ट्र गरीबी, भुखमरी, बेकारी, जनसंख्या समस्या तथा सम्पन्नता में विपन्नता के कुचक्र में फँसे हुए हैं। उनकी इन समस्याओं का निराकरण व तेजी से आर्थिक विकास के लिये आर्थिक नियोजन ही एक मान्य उपयुक्त मार्ग है। हम जो 1917 की शान्ति के समय पिछड़ा कृषि-प्रधान राष्ट्र था आर्थिक नियोजन के द्वारा आज विश्व की एक महान शक्ति के रूप में उभर आया है। अनेक विकसित राष्ट्र भी आर्थिक नियोजन व राज्य हस्तक्षेप के कारण रूढ़िवादी सामाजिक जड़ताओं को तोड़कर सम्पन्न जीवन की प्रेरणा व उत्साह से आर्थिक विकास की ओर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं।

(15) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा—आज विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच वैमनस्यता व अज्ञात भय का कारण राजनैतिक नहीं बरन् आर्थिक है विश्व के किसी भी भाग में गरीबी अन्तर्राष्ट्रीय समृद्धि, शान्ति एवं सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा के लिये नियोजन द्वारा समूचे विश्व में समृद्धि व सम्पन्नता का प्रयास प्रबल है।

(16) नैतिक उत्थान (Moral Uplift)—समाज में चोरी, झूठ, भ्रष्टाचार, वैश्यावृत्ति, उत्पान एवं दंगों के प्रमुख कारण निर्धनता, बेकारी, भुखमरी व व्यापक आर्थिक विपन्नता है। आर्थिक नियोजन इन समस्याओं का निराकरण कर अर्थव्यवस्था को आर्थिक समृद्धि व विकास की ओर अग्रसर करता है जिससे मानव के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास व नैतिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त होता है।

उपयुक्त तर्कों से स्वयं मिथि हो जाता है कि नियोजित अर्थव्यवस्था पूँजीवादी दोषों से दूर समाज के अधिकतम कल्याण की सर्वोत्तम व्यवस्था है। प्रो० मुन्वारराव के अनुसार "नियोजित अर्थव्यवस्था में नई प्रणाली तथा नई कला से जो बुद्धि प्राप्त



करने के लिये प्रयत्न किए जाते हैं वे उत्पादन कुशलता, आर्थिक स्थिरता और विवरण में न्याय के परिचायक हैं।" आज सम्पूर्ण आर्थिक जीवन आयोजन से ओत-प्रोत है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रो० लुईस का यह कथन उपयुक्त लगता है "अब निरपेक्षता की नीति (Laissez Faire Policy) में विश्वास करने वाले पागलों के अतिरिक्त कोई नहीं है।"¹ नियोजन आज प्रत्येक राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था के संचालन का प्रमुख धर्म है। नियोजन का उपहाम उठाने वाले पूँजीवादी राष्ट्र भी जब स्वयं उसके पुजारी बन गए हैं। अमेरिका में स्टीडी, इंग्लैंड में स्थिरीकरण व पूर्ण रोजगार व लिंग नियोजन, युद्धोत्तर काल में युद्ध जर्जरित अर्थ-प्रवस्थाओं व पुनर्निर्माण के लिये मांगल योजना इस प्रवृत्ति के स्पष्ट परिचायक हैं।

### आर्थिक नियोजन के सम्भावित दोष-हानियाँ—नियोजित अर्थ-व्यवस्था के विपक्ष में तर्क अथवा अनियोजित अर्थ-व्यवस्था के तत्पाकयित लाभ-गुण (Probable Demerits of Economic Planning or Arguments against Planned Economy)

यद्यपि नियोजित अर्थ-व्यवस्था आर्थिक विकास, स्थायित्व व सामाजिक न्याय के लिये सर्वोत्तम व्यवस्था है फिर भी उसमें दोष सम्भावित हैं और इन दोषों के द्वारा पूँजीवाद के समर्थक आर्थिक नियोजन की कटू आलोचना करते हैं। प्रो० हेयक (Hayek) ने अपनी प्रसिद्ध कृति 'Road to Serfdom' में आर्थिक नियोजन को दासता का मार्ग कहा है जिसमें व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हनन होता है, अधिकारी तन्त्र, लालफीताशाही, भ्रष्टाचार व आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण होता है मूल्य तन्त्र के अभाव में आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इस प्रकार नियोजित अर्थ-व्यवस्था के विपक्ष में निम्न तर्क दिये जाते हैं—

(1) नियोजन से व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हनन—नियोजित अर्थ-व्यवस्था में सब प्रमुख आर्थिक निर्णय केन्द्रीय नियोजन सत्ता द्वारा लिये जाते हैं। निजी व्यक्तियों की उपभोग, उत्पादन व व्यवसाय की सार्वभौमिकता समाप्त हो जाती है। इसी कारण प्रो० हेयक (Hayek) ने 'आर्थिक नियोजन को दासता का मार्ग कहा है (Planning is a Road to Serfdom)।'

यह आरोप पूर्णतः सत्य नहीं है। नियोजित अर्थ-व्यवस्थाओं में उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता सामाजिक हित में नियन्त्रित होती है। स्वयं जैसी साम्यवादी नियोजन व्यवस्था में भी अब लोगों की उपभोग व व्यावसायिक अभिव्यक्तियों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिये जाते हैं। प्रजातन्त्रीय नियोजन में तो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता काफी होती है जैसे भारत में उद्दिष्टोच्चर होती है। श्रीमती बारबरा वूटन के शब्दों में "जहाँ तक स्वाधीनता का सम्बन्ध है आर्थिक नियोजन का अभाव यही है कि

1 There are no longer any believers in Laissez Faire except in the lunatic fringe

आर्थिक प्राथमिकताओं के सामूहिक एवं जानबूझकर लिये गये निर्णयों द्वारा हमारी निराशाएँ कम होती हैं, स्वाधीनता बढ़ती है और जो हम करना चाहते हैं उसके लिये पर्याप्त अवसर बढ़ते हैं।" पूँजीवाद की तथ्यांकिक स्वतन्त्रता एवं प्रभुसत्ता आर्थिक असमानता की दशा में केवल सुखद स्वप्न है क्योंकि काम चुनने की स्वतन्त्रता होती है पर काम नहीं मिलता और उपभोग की स्वतन्त्रता होती है पर निर्धनों के पास क्रय शक्ति नहीं होती। अतः स्वतन्त्रता का सीमित हनन पूँजीवाद के बेरोजगारी भुलमरी आर्थिक शोषण व निधनता से कहीं अच्छा है।

(2) नियोजित अर्थ व्यवस्था एक अस्तव्यस्त अर्थ व्यवस्था (Muddled Economy) होती है—आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली (Free Price Mechanism) के स्थान पर कृत्रिम मूल्य प्रणाली मनमाने ढंग से निर्दिष्ट की जाती है अतः स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली के अभाव में वितरण व उत्पादन सम्बन्धी निर्णय अविश्वेकपूर्ण होते हैं जिससे साधनों व उत्पादन की वितरण व्यवस्था अस्तव्यस्त हो जाती है और समूची अर्थव्यवस्था अस्तव्यस्तता के दलदल में फँस जाती है।

यह आलोचना भी व्यावहारिक सत्यता से काफी परे है। नियोजित अर्थव्यवस्था में सामाजिक हितों के अनुरूप कृत्रिम मूल्य प्रणाली साधनों का उत्पादन व उपभोग में समुचित वितरण व व्यापार चक्रों से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाती है और एसी अर्थव्यवस्था गड़बड़ियों से मुक्त हो जाती है।

(3) तानाशाही प्रवृत्ति का विस्तार—नियोजित अर्थ व्यवस्था में समस्त प्रमुख आर्थिक निर्णय केंद्रीय नियोजन सत्ता द्वारा लिये जाते हैं अतः सरकार के पास राजनैतिक सत्ता के साथ साथ आर्थिक सत्ता का भी कन्द्रापकरण हो जाता है और इससे सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। नियोजन के अन्तर्गत देश में सरकार ही सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान हो जाती है। जैसा चीन, रूस व अन्य साम्यवादी देशों में दृष्टिगोचर होता है।

यह आरोप प्रजातान्त्रिक नियोजन प्रणाली में सही नहीं उतरता क्योंकि वहाँ नियोजन जनता के द्वारा जनता के लिये जनता की इच्छानुरूप होता है।

(4) अधिकारी तन्त्र और लान चोताशाही का भय (Dangers of Bureaucracy & Red T. -ism)—नियोजित अर्थ व्यवस्था में अर्थ व्यवस्था का संचालन एवं नियंत्रण केंद्रीय नियोजन सत्ता के सरकारी कर्मचारियों की इच्छा और आदेशों के अनुसार होता है अतः सरकारी अधिकारियों व बाहुल्य में अधिकारी तन्त्र पनपना है और निष्ठा में विश्वास से लान चोताशाही का धोलबाला बढ़ता है। यह नियोजित भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्यक्ष क्षय में स्पष्ट है। वैसे यह दोष नियोजन का नहीं बल्कि प्रशासनिक कुशासन एवं सरकार की दीनी ढाली नीति का दुष्परिणाम है। अतः इस में आपात स्थिति की घोषणा के बाद प्रशासन में बुदबुदाई बढ़ी है।

(5) भ्रष्टाचार एवं अकुशलता को बढ़ावा—नियोजित अर्थ-व्यवस्था में सरकारें आर्थिक एवं राजनैतिक सत्ता का केन्द्रीकरण कर लेती हैं उससे सरकारी एवं कर्मचारी स्तर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। “सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है और पूर्ण सत्ता उसे पूर्ण भ्रष्ट बना देती है” (Power corrupts the man and Absolute power corrupts the man absolutely) की कहावत सत्ता के केन्द्रीकरण पर, शासकों, अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी चरितार्थ होती है जैसा हम भारत में हर क्षेत्र में अनुभव कर रहे हैं। भ्रष्टाचार व सत्ता केन्द्रीकरण में अकुशलता को भी प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि लाल फीताशाही और अधिकारी तन्त्र में अनावश्यक विलम्ब, अकुशलता व भ्रष्टाचार पनपता है।

सही मायने में यह आर्थिक नियोजन के दोष नहीं बरन् शासन पद्धति व प्रशासनिक व्यवस्था के दोष हैं।

(6) भावश्यक उत्प्रेरणाओं (Incentives) का अभाव—पूँजीवादी स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था में “निजी लाभ” का जादू निजी साइस का प्रेरणा स्रोत होता है पर नियोजित अर्थ-व्यवस्था में “निजी लाभ” के तत्त्व का नितान्त अभाव होने से वेतन भोगी सरकारी कर्मचारियों व श्रमिकों में नये साहस की प्रेरणा नहीं होती। परिणाम-स्वरूप नियोजित अर्थ-व्यवस्था में अधिक परिश्रम, साहसी भावना व आविष्कार की योग्यताओं में शून्य शून्य ह्रास होता है। पर इस सभी को दृष्टिगत रखते हुए आजकल नियोजित अर्थ-व्यवस्थाओं में पारितोषिक, पदोन्नति व राष्ट्रीय सम्मान तथा अन्य मौद्रिक एवं अमौद्रिक उत्प्रेरणाओं द्वारा श्रमिकों की कार्यक्षमता, योग्यता व साहसी भावना को बढ़ावा दिया जाता है।

(7) विशाल जन शक्ति का अपव्यय—प्रो० सुईस के अनुसार योजना बनाने, उसके लिये विस्तृत विवरण तैयार करने, योजना को कार्यान्वित करने तथा उसके मूल्यांकन के लिये केन्द्रीय नियोजन सत्ता को विशाल सग्या में विशेषज्ञों, अधिकारियों, कर्मचारियों व अन्य लोगों की आवश्यकता पड़ती है। कार्यकर्ताओं की यह विशाल सग्या प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में योगदान नहीं करती। अतः अर्थ-व्यवस्था में विशाल जन-शक्ति का अपव्यय है जबकि अनियोजित अर्थ व्यवस्था में स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली समूची अर्थ-व्यवस्था को स्वयं संचालित बनाकर इस अपव्यय को रोकती है।

यह तर्क भी भ्रमात्मक है क्योंकि नियोजन में सलग्न कार्यकर्ताओं की विशाल सग्या साधनों के दूरदर्शनापूर्ण व विवेकशील उपयोग व वितरण से वही अधिक अपव्यय को बचा देती है जो पूँजीवादी स्वचालित अर्थ व्यवस्था में व्यापार चक्रों, वेकारी, भुजमरी व साधनों के दुरुपयोग से उत्पन्न होता है।

(8) दीर्घकालीन नियोजन खतरनाक हो सकता है—आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया में दीर्घकालीन योजनाओं में अल्पकालीन योजनाओं का समावेश कर विकास

का मार्ग निर्दिष्ट किया जाता है पर भविष्य की अनिश्चितताओं और तीव्र गति से बदलती परिस्थितियों के कारण उद्देश्यों व तरीकों में अन्तर आ सकता है अतः दीर्घ-कालीन नियोजन निरर्थक एवं हानिकारक हो सकता है। यह आलोचना भी निरर्थक है क्योंकि नियोजन में पर्याप्त लोचता व संशोधनों की व्यवस्था से इस खतरे से मुक्ति मिल जाती है।

(9) अन्तर्राष्ट्रीय सघर्ष की सम्भावना—प्रो० रोबिन्स के अनुसार विश्व के अनेक देशों द्वारा राष्ट्रीय नियोजन अपनाने से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में संकुचन, विदेशी विनिमय पर नियन्त्रण, पूँजी तथा श्रम की गतिशीलता में बाधा तथा आर्थिक क्षेत्र में शक्ति परीक्षण से अन्तर्राष्ट्रीय वैमनस्य एवं सघर्ष का जन्म होता है जो कितनी भी समय युद्ध की चिंगारी भड़का कर विश्व शांति एवं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर सकता है। यहाँ यह बताना उल्लेखनीय है कि अन्तर्राष्ट्रीय सघर्ष आर्थिक नियोजन से नहीं बरन् उग्र राष्ट्रवाद से उत्पन्न होता है, यह अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में भी सम्भव है।

(10) राजनैतिक अस्थिरता का भय—आर्थिक नियोजन प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था में राजनैतिक सत्ता के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप होता है और राजनैतिक सत्ता में परिवर्तन के साथ ही आधारभूत नीतियों में भी परिवर्तन होने से अनेक पुराने कार्यक्रमों को बन्द कर अनेक नवीन आधारभूत नीतियों को क्रियान्वित किया जाता है। अतः नियोजन में अस्थिरता का भय व्याप्त रहता है। प्रो० जैक्स (Jewkes) के अनुसार राजनैतिक अस्थिरता के वातावरण में दीर्घकालीन औद्योगिक परियोजनाएँ नहीं बन सकती। इस दोष का निराकरण सभी राजनैतिक दलों में नियोजन के प्रति सामूहिक महामाँव व सदभावना में निहित है।

(11) संक्रमण काल में अर्थव्यवस्था व जनता का असन्तोष—आर्थिक नियोजन मुख्य मांगताओं पर आधारित होता है पर दुर्भाग्य से प्राकृतिक विपदा, युद्ध अथवा प्राकृतिक अन्तर्राष्ट्रीय सन्तुलन व कारण नियोजन के लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते जबकि जनता शांति एवं सुख के लक्ष्यों को अर्थव्यवस्था में प्राप्त हो जाती है। जापान में व असन्तोष रहता है जैसे 1974-75 के आँकड़ों में भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता के लक्ष्य मुख्यतः मध्यम वर्ग की जिंजा-आन्दोलनों का तात्कालिक लक्ष्य था। इसका समापन आपात स्थिति की घोषणा में ही सम्भव हो पाया था।

नियोजन के पक्ष एवं विपक्ष में दिये गये उपयुक्त तर्कों के निवेदन से यह निष्पक्ष विचार निकाला जा सकता है कि आर्थिक नियोजन आधुनिक युग की समस्याओं के निराकरण तथा तीव्र आर्थिक विकास के लिए अचूक रामबाण औपचारिक है। आज पूँजीवादी राष्ट्र भी आर्थिक नियोजन के द्वारा अपनी आर्थिक समस्याओं के हल में प्रयत्नशील हैं। आर्थिक नियोजन के सम्भावित दोषों का

निराकरण नियन्त्रित व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, नियोजन की लोचता, कुशल संचालन व राजनैतिक स्थिरता में निहित है। अब नियोजन सभी अर्थ-व्यवस्थाओं में राष्ट्र धर्म बन गया है। आर्थिक नियोजन के लिए कोई विवाद नहीं, विवाद है केवल उसके स्वरूप पर। इसी कारण पीपू ने लिखा है 'यदि समाजवादी केन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली को प्रभावपूर्ण ढंग से सगठित किया जाय तो यह हमारी वर्तमान पूँजीवादी प्रणाली से कई बातों में श्रेष्ठ होगी।' अतः नियोजित अर्थ-व्यवस्था की श्रेष्ठता स्पष्ट है।

### आर्थिक नियोजन की सफलता के मूल तत्व या आवश्यक शर्तें (Essential Elements or Essential Conditions for Planning Success of Economic)

आर्थिक नियोजन एक स्वचालित व्यवस्था न होकर राज्य की एक सुसंगठित एवं सुसम्बद्ध प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य निश्चित अवधि में पूर्व निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करना होता है। नियोजन की सफलता से आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समानता व राजनैतिक सुदृढ़ता बढ़ने के कारण भावी नियोजन की प्रेरणा मिलती है और नियोजन की विफलता में निराशा, निर्वनता और सामाजिक उत्पीड़न होने से नियोजन की प्रक्रिया का हतोत्साहन होता है। अतः आर्थिक नियोजन की सफलता एक अनिवार्य आवश्यकता है और यह निम्न तत्वों या शर्तों पर निर्भर करती है—

(1) सशक्त एवं स्थिर शासन (Strong & Stable Government)—आर्थिक नियोजन में केन्द्रीय नियन्त्रण को प्रभावी एवं कुशल बनाने के लिए सशक्त एवं स्थिर सरकार एक अनिवार्य घटक है। आन्तरिक शान्ति एवं बाह्य सुरक्षा के वातावरण में ही नियोजन की सफलता निहित है जबकि ढीली एवं अस्थिर शासन व्यवस्था में प्रभावी एवं कुशल नियन्त्रण के अभाव, आन्तरिक दंगों व अर्थव्यवस्था और बाह्य आक्रमणों के भय से नियोजन की सफलता सन्दिग्ध रहती है। यही कारण है कि तानाशाही शासन पद्धति से नियोजन प्रजातान्त्रिक प्रणाली की अपेक्षा अधिक कुशल, प्रभावी एवं सफल होता है। इस और भारत इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। भारत में राज्यों में शासन की अस्थिरता से शासक कुर्सी की सुरक्षा के लिये आर्थिक नियोजन को उपेक्षा करत थे और अपने निजी राजनैतिक हितों की पूर्ति के लिए आर्थिक नियोजन के हितों की चर्चा दे देते थे। अतः नियोजन की सफलता की प्रमुख शर्त देश में सुदृढ़, स्थिर एवं ईमानदार सरकार होना है।

(2) यथार्थवादी उद्देश्य, प्राथमिकताएँ एवं लक्ष्य (Realistic Objectives, Priorities & Targets)—आर्थिक नियोजन की सफलता की दूसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि योजना के उद्देश्य, प्राथमिकताएँ एवं लक्ष्य स्पष्ट एवं यथार्थवादी होने चाहिए। उनका निर्धारण अर्थ-व्यवस्था के साधनों व आवश्यकताओं के अनुरूप विवेक

पूर्ण ढंग से करना चाहिए। योजना बहुत अधिक महत्वाकांक्षी व वास्तविकता से परे होने अथवा उद्देश्यों व लक्ष्यों के बहुत नीचा निर्धारित करने में नियोजन की विफलता इसके प्रति निराशा का वातावरण फैलाती है। अतः नियोजन की सफलता के लिये योजना व उद्देश्य, प्राथमिकता व लक्ष्यों को यथार्थवादी बनाना चाहिये।

(3) साधनों का उचित मूल्यांकन तथा पर्याप्त विश्वसनीय सांख्यिकी आँकड़े (Proper Evaluation of Resource & Adequate Correct Statistical Data)—नियोजन के अन्तर्गत साधनों के विदोहन, विभिन्न क्षेत्रों में वितरण तथा अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामंजस्य बैठाने की समस्या का समाधान समस्त साधनों के गजेंक्षण एवं मूल्यांकन तथा तत्-सम्बन्धी पर्याप्त विश्वसनीय आँकड़ों पर निर्भर करता है। अतः राष्ट्रीय आय, बचत, उपयोग, वच्चे माल, जनसंख्या, खनिज सम्पत्ति, प्राकृतिक साधनों व पूंजीगत साधनों के बारे में पर्याप्त विश्वसनीय आँकड़े होने पर योजना का निर्माण, त्रियान्वयन व प्राथमिकताओं का निर्धारण सही-सही करने में सहायता मिलती है और इनके अभाव में अन्धकार में कदम रखने के समान है। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में कुशल सार्वजनिक संगठनों के अभाव में विश्वसनीय आँकड़ों का अभाव योजनाओं की सफलता में सदिग्धता का एक प्रमुख कारण रहा है। अब भारत में केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (C.S.O.) तथा राज्य स्तर पर राज्य सांख्यिकी विभाग कार्यरत हैं। अन्य विभागीय संस्थाएँ भी इस भाग में रत हैं।

(4) भौतिक तथा वित्तीय स्रोतों की निश्चितता व पर्याप्तता (Certainty & Adequacy of physical & Financial Resources)—योजना में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न कार्यक्रमों व परियोजनाओं की वार्यान्वित करने के लिये पर्याप्त माना में भौतिक एवं वित्तीय साधनों की आवश्यकता पड़ती है। भौतिक साधनों (Physical Resources) के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की भौतिक वस्तुओं जैसे मशीनें, यन्त्र औजार, सभी प्रकार का वच्चा माल, इस्पात, सीमेन्ट, रसायन श्रमिक, प्रबन्धक साहसी तथा तकनीकी एवं वित्तीय विद्यमानताओं आदि का समावेश होता है जिनकी पूर्ति आन्तरिक साधनों व विदेशी आयातों पर निर्भर करती है जबकि वित्तीय साधनों (Financial Resources) के अन्तर्गत योजनाओं के लिये उपलब्ध आन्तरिक एवं बाह्य भौतिक साधन आते हैं जिनकी पूर्ति राष्ट्रीय आय, बचत व विनियोग दर, करदान क्षमता, जन सहयोग, वित्तीय संस्थाओं के योग व बाह्य गणना में विदेशी भुगतान सन्तुलन पर निर्भर करती हैं। भौतिक एवं वित्तीय साधन दोनों परस्पर पूरक एवं सहायक साधन हैं, एक व अभाव में दूसरे की पर्याप्त पूर्ति ज्ञान पर भी लक्ष्य की पूर्ति सम्भव नहीं होती। अतः नियोजन की सफलता के लिये भौतिक एवं वित्तीय साधनों की पर्याप्त एवं निश्चित पूर्ति होना आवश्यक घटक है। भारत में दोनों प्रकार के साधनों अपर्याप्त एवं अनिश्चित पूर्ति के कारण योजना की सफलता में सदिग्धता व सागर में गोते लगानी है।

(5) आर्थिक संगठन का उपयुक्त स्वरूप (Suitable Structure of Economic Organisation)—यह सत्यागत संरचना जिसमें विभिन्न आर्थिक क्रियाओं—उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग एवं राजस्व का सम्पादन होता है आर्थिक संगठन कहा जाता है अतः नियोजन की सफलता के लिए आर्थिक संगठन का उपयुक्त स्वरूप भी एक अनिवार्य शर्त है। समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में नियोजन की सफलता सुनिश्चित होती है जबकि पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था में नियोजन की सफलता सदिग्ध रहती है क्योंकि प्रभावी नियन्त्रण का अभाव होता है। मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के साथ साथ काम करने से नियोजन की सफलता बहुत कुछ सरकार के प्रभावी नियन्त्रण व निजी क्षेत्र के सहयोग पर निर्भर करती है अगर प्रभावी नियन्त्रण न हो और निजी क्षेत्र निजी लाभ के पीछे सामाजिक हितों की उपेक्षा करे तो नियोजन विफल रहता है जैसा कि भारत की मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में नियोजन आंशिक रूप से ही सफल रहा है। जबकि रूस व साम्यवादी राष्ट्रों में समाजवादी अर्थ व्यवस्था के कारण नियोजन सर्वाधिक सफल रहा है। अतः भारत में नियोजन की सफलता के लिए आर्थिक संगठन को समाजवाद की ओर अग्रसर करना एक उपयुक्त कदम है। प्रो डब्लिन के शब्दों में 'आर्थिक नियोजन की समस्या मुख्यतः वित्तीय समस्या नहीं बल्कि यह तो आर्थिक संगठन अथवा व्यवस्था की समस्या है।'

(6) योजना निर्माण क्रियान्वयन व मूल्यांकन की उचित व्यवस्था (Proper Machinery for plan Formation Implementation & Evaluation)—योजना की सफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि उनके निर्माण क्रियान्वयन व मूल्यांकन के लिए उपयुक्त मशीनरी हो, क्योंकि आर्थिक नियोजन व विभिन्न कार्यक्रमों परियोजनाओं के निर्धारण, साधना के उपयोग में प्राथमिकताओं का निश्चित करना तथा विभिन्न क्षेत्रों में सामन्तस्य व सन्तुलन बैठाना तथा इन योजनाओं को मूर्तरूप देने में एक कुशल व उपयुक्त व्यवस्था आवश्यक होती है। यही नहीं योजना के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों व वास्तविक प्राप्ति के मूल्यांकन की भी आवश्यकता पड़ती है ताकि आवश्यक संशोधन व सुधार किया जा सके। भारत में योजना निर्माण कार्य के द्वितीय स्तर पर योजना आयोग (Planning Commission) तथा राज्य स्तर पर राज्य योजना बोर्डों (State Planning Boards) को सौंपा गया है। योजना आयोग देश की सर्वोच्च नियोजन संस्था है। मूल्यांकन का कार्य करने के लिये विशिष्ट विभाग है। क्रियान्वयन का कार्य विभागा पचायतों आदि में विवेन्द्रित है।

(7) कुशल योग्य व ईमानदार प्रशासन (Efficient Competent & Honest Administration)—आर्थिक नियोजन का सफल क्रियान्वयन कुशल योग्य एवं ईमानदार प्रशासन से ही सम्भव होता है। योजना निर्माण पक्ष प्रवृत्त हान पर भी अगर क्रियान्वयन पक्ष दुर्बल अकुशल आयोग्य व द्रष्टृ हुआ तो योजना की विफलता

निर्दिष्ट है। आ बद्ध-विवर्जित व विवातशील राष्ट्रों में कुशल, योग्य व ईमान-दार प्रशासन के अभाव में अच्छी योजनाएँ भी सफल नहीं हो पा रही हैं। भारत उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब प्रा लुईस (W. A. Lewis) के शब्दों में 'नियोजन में सर्वप्रथम मुद्दा, योग्य एवं ईमानदार प्रशासन की आवश्यकता होती है।'<sup>1</sup>

(8) विपक्षी राजनैतिक दलों में नियोजन के प्रति सामान्य सहमति (General Acceptance of Planning by all Opposition Political Parties)—नियोजन की सफलता के लिए विभिन्न राजनैतिक दलों में आर्थिक नियोजन की आधारभूत नीतियों, उद्देश्यों व लक्ष्यों के प्रति एकमत एवं सामान्य स्वीकृति आवश्यक है अन्यथा विपक्षी राजनैतिक दलों द्वारा सत्ताधारी दल की नियोजन नीति की कटु आलोचना जनता में भ्रम फैलाकर जन सहयोग व भावना को ठेन पहुँचा कर नियोजन को विफल बनाने में योग देगी। जैसे भारत में विभिन्न दलों में नियोजन की आधारभूत नीतियों उद्देश्यों लक्ष्यों व प्राथमिकताओं के बारे में काफी मतभेद नियोजन की सफलता में बाधा बनता है।

(9) उच्च राष्ट्रीय चरित्र व जनता में त्याग की तत्परता (High National Character & Preparedness for Sacrifices)—जनता की त्याग की तत्परता व उच्च राष्ट्रीय चरित्र सभी अममभावनाओं को सम्भव बना सकता है। अगर देश के लोग परिश्रमी, कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार सत्योन्मी व राष्ट्रभक्त होंगे तो नियोजन की सफलता निश्चित है पर अगर अपनी भ्रष्ट देशद्रोही व कामचोर हुए तो अच्छी से अच्छी योजना भी विफल हो जायेगी। आज जापान के लोगों में उच्च राष्ट्रीय चरित्र उनकी आर्थिक समृद्धि का राज है। हमारी योजनाओं में विफलता का एक प्रमुख कारण हमारे में उच्च राष्ट्रीय चरित्र व त्याग की तत्परता की भावना का अभाव है। हम निजी लाभ व हिन्ने के लिए राष्ट्रीय लाभ व हिन्ने की बलि देने को उत्तन हैं। "बिना आँसू नियोजन की सफलता सम्भव नहीं।"<sup>2</sup> उन त्याग की तत्परता भी आवश्यक होती है।

(10) नियोजन में व्यापक, लोचपूर्ण व दीर्घकालीन दृष्टिकोण—आर्थिक नियोजन एक अल्पकालीन प्रयत्न न होकर निम्नतर चलने वाली दीर्घकालीन प्रक्रिया है अब: नियोजन की सफलता के लिये नियोजन आंशिक न होकर व्यापक तथा कठोर न होकर लोचपूर्ण तथा अल्पकालीन न होकर दीर्घकालीन दृष्टिकोण से प्रेरित होना चाहिए। अल्पकालीन याज्ञानों दीर्घकालीन दृष्टिकोण में समाविष्ट होनी चाहिये। हमें 20 वर्षों योजना (1960-80) पंचवर्षीय योजनाओं के लिये दीर्घकालीन

1. In first place, Planning requires a strong, competent and incorrupt administration —W. A. Lewis

2. "Planning without tears" is not successful

—W. A. Lewis



दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। भारत में भी योजना आयोग के अन्तर्गत एक दीर्घवालीन आयोजन विभाग (Perspective Planning Department) खोला गया है यह सही दिशा में एक कदम है।

(11) जन सहयोग (Public Co-operation)—आर्थिक नियोजन ऐसी प्रक्रिया है जिसे दूसरों पर थोपा नहीं जा सकता। उसकी सफलता जनता की इच्छा, उत्साह व उसके सहयोग पर निर्भर करती है। प्रजातान्त्रिक मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रो० लुईस (W A Lewis) के शब्दों में 'जन-उत्साह नियोजन के लिए चिकना तेल (Lubricating Oil) तथा आर्थिक विकास का पेट्रोल दोनों हैं—यह एक ऐसी प्रारम्भिक शक्ति है जो प्रायः सब चीजों को सम्भव बनाती है।'<sup>1</sup> भारत में जन-सहयोग की कमी के कारण प्रजातान्त्रिक विभेदनीकरण की व्यवस्था लागू की गई ताकि योजना का निर्माण व कार्यान्वयन ऊपर व नीचे दोनों स्तर से सम्भव हो। योजना का व्यापक प्रचार, उनमें नियोजन के प्रति रुचि, जागृति एवं उत्साह बढ़ाकर नियोजन को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

(12) विविध शर्तें (Miscellaneous Conditions)—आर्थिक नियोजन की सफलता उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त कुछ अन्य तत्वों पर भी निर्भर करती है जैसे—  
(1) अनुकूल प्राकृतिक दशावस्थाएँ—ताकि लक्ष्यों की पूर्ति सम्भव हो सके पर अगर बाढ़, अकाल, आँधी, सूफान, शीत लहर आदि का प्रकोप हो तो नियोजन असफल हो जाता है जैसे भारत में समय-समय पर हुआ है। (2) अन्तरिक शांति एवं सुरक्षा—अगर देश में दंगे, झूटपाट, हड़तालें, ताकतबन्दी, आगजनी, हत्याएँ आदि का वातावरण हो तो योजना की सफलता सन्दिग्ध है पर अगर देश में शान्ति व व्यवस्था बनी रहे तो नियोजन सफलता की ओर अग्रसर होता है। (3) बाह्य आक्रमणों की सुरक्षा—अगर देश को बाह्य आक्रमणों का भय रहता है तो सीमित साधनों का प्रयोग युद्ध की तैयारी के लिये व युद्ध पर भारी व्यय में सगाना पड़ता है तथा विकास कार्यों की उपेक्षा भी करनी पड़ती है जबकि सुरक्षा की अवस्था में देश अविरल गति से प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होता जाता है। भारत को चीनी आक्रमण, पाकिस्तानी आक्रमण व बंगला देश की रक्षार्थ काफी क्षति उठानी पड़ी और योजना के लक्ष्य पूरे न हो सके। (4) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग—देश के आर्थीकरण व अन्य विकास कार्यों के लिये विदेशी सहायता व सहयोग की भी आवश्यकता होती है। अगर विकासशील राष्ट्र को विदेशी साधनों की पर्याप्त पूर्ति होती रहे तो नियोज-

1 Popular enthusiasm is both the lubricating oil of planning and the petrol of Economic Development a Dynamic force that almost makes all things possible W A Lewis -The Principles of Eco Planning p-182,

जन की सफलता सुगम हो जाती है (5) उपयुक्त समन्वय व सन्तुलन—अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर समन्वय व उपयोग में सन्तुलन बँठाना भी नियोजन की सफलता का आवश्यक तत्व है। इस प्रकार इन सब तत्वों से सामूहिक प्रभाव पर ही नियोजन की सफलता निर्भर करती है।

### परीक्षोपयोगी प्रश्नमय संकेत

1. आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं ? आधुनिक युग में इसके महत्व को समझाइये।

(Raj. III yr. Com 1979)

(संकेत:—नियोजन का अर्थ एवं परिभाषायें देकर पुस्तक में शीर्षकानुसार महत्व देना है।)

## आर्थिक नियोजन के प्रकार या विभिन्न रूप (TYPES OF VARIOUS FORMS OF ECONOMIC PLANING)

जि का युग आर्थिक नियोजन का युग है और यह आधुनिक युग के समस्त गो को झूक रामबाण औषधि मानी जाती है इसी कारण प्रायः सभी गालियो में विकास, स्थापित्व अनुरक्षण अथवा पुनरुत्थान आदि के लिये योजना का न्यूनाधिक रूप में बोलबासा है। इसकी इस लोकप्रियता व के कारण ही प्रो० रोबिन्स ने लिखा है “आज वाद-विवाद नियोजन के होने होने के बीच न होकर इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में है।” अतः आर्थिक अपने विभिन्न रूपों में प्रस्तुतित हुआ है जिसका वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर है। (देखें पृष्ठ 26)

आर्थिक नियोजन का यह वर्गीकरण पूर्ण अथवा अंतिम नहीं है। यह तो इसके स्वरूप की मोटी रूपरेखा निश्चित करता है। इन स्वरूपों का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

### I सामान्य एवं आंशिक नियोजन (General & Partial Planning)

सामान्य नियोजन (General Planning)—इसके अन्तर्गत समूची अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिये सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था का नियोजन किया जाता है इसको व्यापक नियोजन या सम्पूर्ण नियोजन भी कहा जाता है। इसके अन्तर्गत देश के सर्वांगीण विकास के लिये तथा सम्पूर्ण आर्थिक बुराइयों व निराकरण व लिये आर्थिक ढाँचे में यथोचित तात्त्विक बैठकाया जाता है। सब अल्प-विचसित राष्ट्रीय तथा रुच द्वारा अपनाया गया नियोजन सामान्य नियोजन का ज्वलन उदाहरण है। यह अधिक कष्टप्रद होता है।

आंशिक नियोजन—(Partial Planning)—इसमें अर्थ-व्यवस्था के सम्पूर्ण ढाँचे के विकास की योजना न होकर केवल किसी क्षेत्र या एक भाग विशेष के विकास व उसकी बुराइयों के निराकरण की योजना होती है। जैसे केवल कृषि विकास की योजना, या केवल परिवहन विकास की योजना। यह कम व्ययमाध्य तथा कम कष्टप्रद होता है, यह एक प्रकार से सखिप्त नियोजन है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय नहीं बैठाया जाता। इसी कारण प्रो० रोबिन्स ने कहा है “आंशिक नियोजन तो नियोजन

आर्थिक नियोजन के प्रकार का रूप (Types of Planning)

A	B	C	D	E	F
सर्व-क्षेत्र के आधार पर	आय का आधार पर	निर्णय के आधार पर	अवधि के आधार पर	प्रवृत्ति के आधार पर	व्यय आधार
1 सामान्य एवं आदिता नियोजन	1 पूँजीवादो नियोजन	1 आज्ञा मूलक एवं प्रो महान मूलन नियोजन	1 बल्पमालीन अथवा दीघकालीन नियोजन	1 भोतिव नियोजन एवं प्रतीय नियोजन	1 गार्वजनन क्षय एवं निजी क्षेत्र नियोजन
2 सरचनात्मक एवं क्रियात्मक नियोजन	2 समाख्यादी नियोजन	2 नेम्डिल तथा विरेन्द्रा नियोजन	2 स्याई अस्याई एवं आपात्-रालीन नियोजन	2 गतिशील एवं स्थिर नियोजन	2 समुचित तथा अमनुजित नियोजन
3 सुधारवादी एवं विनासवादी नियोजन	3 प्रजातान्त्रिक नियोजन	3 ऊपर से नियोजन तथा नीचे से नियोजन			3 रचनात्मक एवं विस्थापन नियोजन
4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय नियोजन	4 पामिस्ट नियोजन				4 उद्धार अथवा अनुद्धार नियोजन
	5 माधोवादी नियोजन				5 दृष्टि प्रधान या उद्योग प्रधान नियोजन
	6 साम्यवादी नियोजन				6 हीनार्थ या मोहित नियोजन
					7 पूँजी प्रधान या श्रम प्रधान नियोजन

न होने की स्थिति से भी खराब है" "Where there is partial planning the position is worse than it would be with no planning at all" पूंजीवादी राष्ट्रों में यह पद्धति अपनाई जाती है।

## (2) संरचनात्मक एवं क्रियात्मक नियोजन (Structural and Functional Planning)

संरचनात्मक नियोजन (Structural Planning) के अन्तर्गत समाज के आर्थिक एवं सामाजिक ढाँचे में आमूल मूल परिवर्तन कर नये आर्थिक एवं सामाजिक ढाँचे का निर्माण किया जाता है। यह पुरातन और रुढ़िवादी अवस्थाओं को समाप्त कर वैज्ञानिक तथा प्रगतिशील ढाँचे का निर्माण करती है जिससे वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति अल्पकाल में हो सके। इसे क्रान्तिकारी नियोजन भी कहा जाता है। रूस में 1928 में आर्थिक नियोजन का सूत्रपात इसका ज्वलन्त उदाहरण है। दूसरा उदाहरण साम्यवादी चीन का है।

क्रियात्मक नियोजन (Functional Planning) में विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक ढाँचे को विकासोन्मुख बनाये जाने के प्रयत्न किये जाते हैं। इसके अन्तर्गत सुधार के प्रयत्न किये जाते हैं पर इस प्रक्रिया में वांछित लक्ष्यों की पूर्ति में विलम्ब रहता है। यह पद्धति नियोजन का प्रभावपूर्ण उद्योग नहीं है। इसलिये डा० लुडविग वान भाईसेस ने कहा है कि "पूँजीवाद और नियोजन पूर्णतः असंगत है। नियोजन तो स्वतन्त्र उपनम, निजी पहल, उत्पत्ति के साधनों का निजी स्वामित्व, बाजार अर्थ-व्यवस्था और मूल्य प्रणाली का प्रतिवाद है।"

अतः विकासशील राष्ट्रों के तीव्र विकास के लिये संरचनात्मक नियोजन ही महत्वपूर्ण है और इसी से निर्धनता के कुचक्र को तोड़ना सम्भव है। यद्यपि संरचनात्मक नियोजन बाद में क्रियात्मक नियोजन का रूप धारण कर लेता है पर क्रियात्मक नियोजन को संरचनात्मक बनाने में काफी समय लगता है इसी बीच में असफलताओं से निराशा का बातावरण हो सकता है। संरचनात्मक नियोजन एक दीर्घवालीन नियोजन है। एक ही राष्ट्र में दोनों प्रकार की पद्धतियों का सम्मिश्रण किया जा सकता है जैसे भारतीय अर्थ-व्यवस्था में ऐसा किया गया है।

## (3) सुधारवादी एवं विकासवादी नियोजन (Corrective and Development Planning)

सुधारवादी नियोजन (Corrective Planning) आर्थिक नियोजन की वह पद्धति है जो अर्थ-व्यवस्था में उत्पन्न असन्तुलन अथवा प्रतिकूल प्रवृत्तियों के सुधार के लिये अपनाई जाती है ताकि अर्थ-व्यवस्था को उसके दुष्प्रभावों से मुक्ति मिल सके। विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में व्यापार चक्रों से उत्पन्न बकायों, भुखमरी आदि के निराकरण के लिये जो नियोजन होता है वह सुधारवादी कहा जाता है जैसे अमेरिका में 1930 की विदवध्यापी मंदी के समय अपनाया गया न्यू डील (New Deal) तथा 1946 में पारित रोजगार अधिनियम (Employment Act) तथा फ्रांस में

अपनाया गया न्यून प्रयोग मुखारवादी नियोजन के बहिष्कृत उदाहरण है। मुखारवादी नियोजन की अन्य विशेषता यह होती है कि सरकार समाज के सामान्य जीवन में हस्तक्षेप न कर मूल्य निर्धारण कर, सहायता देकर या प्रलोभन देकर मार्ग-दर्शन करती है।

विकासवादी नियोजन (Development Planning) में अर्थ-व्यवस्था के सर्वांगीण विकास के लिये सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था का सत्यागत पश्चिर्तनो के साथ-साथ नियोजन किया जाता है। अर्थ-निश्चित व विकासशील राष्ट्रों द्वारा आर्थिक विकास के लिये जो आयोजन पद्धति अपनाई जा रही है वह विकासवादी नियोजन का परिचायक है। रूस, चीन, भारत तथा अन्य विकासशील राष्ट्रों में इसी पद्धति का नियोजन है।

#### (4) क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन (Regional, National & International Planning)

क्षेत्रीय नियोजन (Regional Planning) का अन्विष्ट उस नियोजन से है जिसमें देश के किसी क्षेत्र प्रदेश व भाग का विकास, विस्तार व पुनर्निर्माण के लिये निश्चित योजना बनाया उसे कार्यान्वित किया जाता है। क्षेत्रीय नियोजन सामान्यतः तब अपनाया जाता है जब क्षेत्रीय विषमता को समाप्त कर समतुलित विकास करना हो, अलग-अलग क्षेत्रों की परिस्थितियों में भिन्नता के कारण उनके लिये विशेष योजनाएँ बनानी हों या किसी क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों का पूर्ण विकास करना हो या उस क्षेत्र का सामूहिक महत्व हो। नियोजन की यह अवस्था कभी-कभी राजनैतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है। यह नियोजन अलग-अलग अलग होते हुए भी राष्ट्रीय नियोजन का एक अविभाज्य अंग होता है। अर्थात् वैसे ही वैसे ही वैसे ही भारत में दण्डवाण्य योजना, आदिवासी क्षेत्र योजना इनके बहिष्कृत उदाहरण हैं।

राष्ट्रीय नियोजन (National Planning) वह है जो सम्पूर्ण देश के सर्वांगीण एवं समुचित विकास के लिये सारा देश में लागू होता है अर्थात् नियोजन की परिधि सारे देश की अर्थ-व्यवस्था पर लागू होती है। राष्ट्रीय नियोजन में देश की श्रम, पूँजी प्रवण्य प्रसारण, मूल्य आदि सभी नीतियों का समावेश होता है। भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ राष्ट्रीय नियोजन का प्रतीक हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन (International Planning) नियोजन की वह पद्धति है जिसमें दो या दो से अधिक राष्ट्र मिलकर सामूहिक साधनों एवं सम्पत्ति का विद्वेष्टन, प्रयोग व विकास सामूहिक आर्थिक शक्तों के लिये किया जाता है पर यह अभी सम्भव होना है जब एक बड़ी शक्ति व अधिकार में अनेक छोटे-छोटे राष्ट्र आ जायें और वे अपनी भावभूमिगतता को सामूहिक शक्ति में त्याग दें पर आपुनिक युग में यह प्राप्त कठिन है इसी कारण अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन को दूसरे अर्थ में परिभाषित किया जाता है जिसमें अनेक राष्ट्र अपने कुछ चुने हुये उद्देश्यों की

पूँति के लिये परस्पर आर्थिक सहयोग की सामूहिक नीति अपनाते हैं और उसका संचालन प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता के प्रभावी नियन्त्रण में होता है। इस पद्धति में प्रत्येक राष्ट्र का अलग-अलग अस्तित्व होता है पर स्वैच्छापूर्ण समझौते से वे कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिये समान नीति अपनाते हैं जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) विदेशी विनिमय नियन्त्रण व व्यापार वृद्धि का अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन है। प्रयुक्त दर व व्यापार का सामान्य समझौता (G.A.T.T.) व्यापार व शुल्क दरों का अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन है। यूरोपीय साझा बाजार (European Common Market or E. C. M.) यूरोप के सात देशों फ्रान्स, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम-लक्जमबर्ग, पुर्तगाल तथा ब्रिटेन के बीच आर्थिक नियोजन का सम्मिलित प्रयास है। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक, बोलम्बो योजना आदि अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन के कनिष्ठ उदाहरण हैं। अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन सभी सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है जबकि (i) उद्देश्य सीमित एवं सामूहिक महत्व के हों। (ii) सम्बन्धित देशों में परस्पर सहयोग हो, (iii) केन्द्रीय सत्ता उत्तम संचालन करे और। (iv) केन्द्रीय सत्ता का आन्तरिक व्यवस्था में हस्तक्षेप केवल निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति तक सीमित रहे।

इनका उद्देश्य आर्थिक सघर्षों को रोकना, विश्व शान्ति को बढ़ावा देना तथा अविच्छिन्न राष्ट्रों के विकास में तकनीकी तथा आर्थिक सहायता देना होता है। संयुक्त राष्ट्र सघ के द्वारा आधिकारिक रूप से आर्थिक नियोजन के प्रयत्न किये जाते हैं पर विश्व सरकार के अभाव में सफलता मुश्किल है।

### (5) पूँजीवादी नियोजन (Capitalistic Planning)

“पूँजीवादी आर्थिक संरचना में आर्थिक क्रियात्मक तथा सुधारवादी नियोजन के सम्मिश्रण को पूँजीवादी नियोजन कहते हैं।” यह नियोजन आदेशमूलक न होकर प्रोत्साहन मूलक होता है। इसमें विकास कार्यक्रमों का भी समावेश होता है। ग्रेट ब्रिटेन में 1965-70 की योजना, अमेरिका में न्यूडील इसका उदाहरण है। इसमें सफलता आदेशों पर नहीं बल्कि बाजार तन्त्र तथा प्रोत्साहन पर निर्भर करती है।

### (6) समाजवादी नियोजन (Socialistic Planning)

यह समाजवादी सिद्धान्तों पर आधारित आर्थिक प्रणाली में अपनाई गई सामान्य आज्ञा मूलक, विकासवादी एवं संरचनात्मक नियोजन की सम्बन्धित पद्धति है। इसमें केन्द्रीय नियोजन सत्ता सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रभावी नियन्त्रण एवं कार्यान्वयन करती है। उद्यमों का प्रबन्ध मार्गदर्शक नियमों द्वारा जनता की प्रतिनिधि सत्ताओं तथा मजदूरों द्वारा होता है। पूँजीगत उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है। यह नियोजन पहले वृष्टप्रद होता है। कभी-कभी इसकी भागी कीमन चुकानो पड़ती है। सोवियत रूस में समाजवादी नियोजन है। इस नियोजन में

आधारभूत एवं मूल उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। विदेशी व्यापार पर भी सरकार का पूर्ण नियन्त्रण होता है। कुछ सीमा तक निजी उपक्रमों को सीमित स्वतन्त्रता होता है। इसे कभी-कभी अधिनायकवादी नियोजन (Totalitarian Planning) भी कहा जाता है।

### (7) साम्यवादी नियोजन

#### (Communist Planning)

साम्यवादी नियोजन समाजवादी नियोजन का ही कठोर रूप है जिसमें समूची अर्थ-व्यवस्था पर सरकार का बख़ोर नियन्त्रण होता है। निजी स्वामित्व एवं साहस समाप्त कर दिये जाते हैं। निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में निजी हितों की बलि दे दी जाती है जनता के आर्थिक जीवन के साथ-साथ उसके सामाजिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक जीवन को भी नियन्त्रित किया जाता है। 'Each according to capacity and each according to need'—No work—No food आदि सिद्धान्तों का पालन किया जाता है। इसमें नियोजन की सफलता द्रुतगति से होती है। प्रारम्भ में रूस का आर्थिक नियोजन इसका ज्वलन्त उदाहरण है। चीन (साम्यवादी) इसका दूसरा उदाहरण है। यही कारण है कि इन देशों ने अल्पकाल में जो प्रगति की है उस स्तर पर पहुँचने के लिये पूँजीवादी राष्ट्रों को 200-300 वर्ष लगे।

### (8) प्रजातान्त्रिक नियोजन

#### (Democratic Planning)

प्रजातन्त्रात्मक नियोजन जनता के द्वारा, जनता के लिये जनता का नियोजन है (Democratic planning is planning by the people, for the people and of the people) इस पद्धति में जनता के प्रतिनिधि देश की नियोजन सत्ता के द्वारा निर्मित योजना को जनता की स्वीकृति से कार्यान्विष्ट करती है। इसमें सामान्य, आदेशात्मक तथा प्रोत्साहनमूलक विकासोन्मुख कार्यक्रम जनता की सामान्य स्वीकृति व सहयोग से चलाये जाते हैं। बस यह धारणा पहले यह थी कि नियोजन तथा प्रजातन्त्र एक दूसरे के विरोधभास है पर भारत के प्रजातन्त्रात्मक नियोजन ने यह सिद्ध कर दिया है कि इस पद्धति में आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ मानवीय स्वतन्त्रता तथा संस्कृति समग्रता का अवसर मिलता है। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों को राष्ट्रहित में विनियमित करने की मिश्रित नीति का अनुसरण किया जाता है। निर्णय घोपे नहीं जाते पर सामान्य स्वीकृति से लागू किए जाते हैं।

### (9) तानाशाही नियोजन

#### (Fascist Planning)

तानाशाही नियोजन में सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाओं का संचालन केन्द्रीय शक्ति या तानाशाही द्वारा किया जाता है। अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है पर प्रशासकीय अंगुली व निर्देशों से आर्थिक तथा राजनैतिक सकेन्द्रीकरण को रोका जाता है। माधनों के उपयोग एवं विवरण के सम्बन्ध में राज्य



द्वारा सिद्धान्त तथा नियम निर्धारित कर दिये जाते हैं और आर्थिक क्रियाओं पर राज्य का कठोर नियन्त्रण रहता है। क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है। कितना उपभोग करना है आदि पूर्ण निर्धारित होते हैं। जर्मनी में हिटलर के समय में आर्थिक नियोजन इसी प्रकार का था जिसमें भय, अकुश व कठोरता का बाहुल्य रहता है। यह पद्धति युद्ध, बंदी आदि सकटों के समय अधिक उपयुक्त है।

### (10) गांधीवादी नियोजन अथवा सर्वोदय नियोजन

(Gandhian Planning or Sarvodaya Planning)

गांधीजी के आर्थिक सिद्धान्तों—अहिंसा, सादगी, सद्भावना, सहयोग, धर्म के महत्व तथा सत्य पर आधारित यह नियोजन नागरिकों के आर्थिक एवं आध्यात्मिक विकास से सम्बन्धित है। इसका मुख्य उद्देश्य शोषण रहित, आत्म निर्भर तथा विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना होता है जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सर्वांगीण विकास मानव व आध्यात्मिक विकास को प्रेरित करे। भारतीय नियोजन में इसके प्रमुख तत्वों का समावेश किया गया है पर परिस्थितियाँ अनुकूल न होने से उद्देश्यों की पूर्ति केवल स्वप्न और मल्पना बनकर रह गई है।

### (11) आज्ञामूलक एवं प्रोत्साहनमूलक नियोजन

(Planning by Direction and Planning by Inducement)

आज्ञामूलक नियोजन (Planning by Direction) में जिसे निर्देशात्मक अथवा आदेशात्मक नियोजन भी करते हैं, केन्द्रीय नियोजन सत्ता द्वारा प्रत्यक्ष आदेशों द्वारा नियोजित कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाता है। इसमें कभी-कभी आदेश कठोर होते हैं तो जनता को बच्य उठाना पड़ता है। अतः इसे आसुओं का आयोजन (Planning With Tears) कहा जाता है और चूँकि यह आदेशों से जनता पर लादा है इसलिये इसे 'ऊपर से आयोजन' (Planning from Above) तथा अधिकारात्मक आयोजन (Authoritative Planning) की भी संज्ञा दी जाती है। यह नियोजन अनेक प्रकार की कठिनाइयों से पूर्ण तथा जटिल है। उत्पादन के क्षेत्र में लागू करना उपयुक्त रहता है पर उपभोग में प्रभावी कम होता है। साम्यवादी एवं समाजवादी आयोजन आज्ञामूलक नियोजन की श्रेणी में आता है।

प्रोत्साहनमूलक नियोजन (Planning by Inducement) को प्रेरणामूलक तथा प्रेरणात्मक नियोजन भी कहा जाता है। इस पद्धति में सरकार आदेशों को न कर आर्थिक क्षेत्र में निजी ग्राहकों को अनेक प्रकार की सुविधायें तथा प्रलोभन देकर लक्ष्यों की पूर्ति को प्रोत्साहित करती है। इसके अन्तर्गत मौद्रिक एवं अमौद्रिक प्रलोभनों से, मौद्रिक तथा राजस्वोपेय नीतियों से अप्रत्यक्ष नियन्त्रण किया जाता है। इसे नीचे से आयोजन (Planning from Below) भी कहा जाता है। इसकी सफलता बहुत कुछ जन सत्याग पर निर्भर करती है।

भारतीय नियोजन में दोनों पद्धतियों का सन्तुलित मिश्रण करने की नीति का अनुसरण किया गया है। सावजनिक क्षेत्र में आज्ञामूलक तथा निजी एवं सहकारी क्षेत्र में प्रेरणामूलक नीतियाँ अपनाई गई हैं।

## (12) केन्द्रित नियोजन एवं विकेन्द्रित नियोजन

अथवा

ऊपर से नियोजन एवं नीचे से नियोजन

(Centralised Planning and Decentralised Planning)

Or

(Planning from above and Planning from below)

केन्द्रित नियोजन व अन्तर्गत योजनाओं का निर्माण स्वीकृति क्रियान्वयन, निरीक्षण तथा मूल्यांकन का वायव्य केंद्रीय मंत्रालय में होता है। इसमें जहाँ एक ओर निगमित मे एकरूपता तथा सामंजस्य बैठता है वहाँ दूसरी ओर इस पद्धति में जनता व सहयोग का अभाव क्षीण विकास कार्यों की प्राथमिकता में नुति तथा सरा व केन्द्रीयकरण व दोष पाये जाते हैं। समाजवादी देशों में सामान्यतः यह पद्धति अपनाई जाती है। इस ही ऊपर से नियोजन (Planning from above) भी कहा जाता है।

विकेन्द्रित अथवा नीचे से नियोजन आर्थिक नियोजन की वह पद्धति है जिसमें जन के अधिष्ठित सहयोग क लिये योजना का निर्माण, स्वीकृति क्रियान्वयन, निरीक्षण तथा मूल्यांकन आदि कार्यों को विभिन्न क्षेत्रीय स्थानीय या प्रादेशिक संस्थाओं को सौंप दिया जाता है। फ्रांस तथा इंग्लैंड में नियोजन का यही स्वरूप अपनाया गया है। इसमें योजनाओं का निर्माण यथार्थवादी तथा क्रियान्वयन व्यावहारिक होने की श्रवृत्ति पाई जाती है।

आजकल इन प्रणालियों में भेद करना कठिन हो गया है और प्रजातान्त्रिक देशों तथा समाजवादी देशों में इन पद्धतियों का सम्मिश्रण कर दिया गया है। योजना का प्रेम जब केंद्रित नियोजन में है और उसका वाद स्थानीय संस्थाओं की योजनाओं उसी प्रेम धर्म में प्रमुख अंग होती है।

## (13) भौतिक नियोजन

(Physical Planning)

भौतिक नियोजन में योजनाओं की आवश्यकताओं तथा लक्ष्यों का वास्तविक वस्तुओं और तत्वों के रूप में व्यक्त किया जाता है। योजना आयोग व अनुसार भौतिक नियोजन वह प्रयत्न है जिसके द्वारा विकास सम्बन्धी प्रयत्नों को साधनों के विवरण एवं वस्तुओं की उपनिधि का रूप में प्रकट किया जाता है जिससे आप व रोजगार में पूर्णता हाव। भौतिक नियोजन में उत्पादित व विभिन्न साधनों की स्थिति एवं उपनिधि के बार में जानकारी प्राप्त कर योजना की आवश्यकताओं को भौतिक साधनों में मूल्यांकन करत है जम 3 महाविद्यालयों के लिये किता पत्थर, किता सीमेंट, चूना मजदूर लोहा पानी, रेत इत्यादि। फिर विभिन्न उत्पादन ताल—जैसे 12 करोड़ टन गन्ना 300 मीन रेलवे लाइनें, 1500 मीन पक्की सड़कें, 40 लाख टन सीमेंट 90 लाख टन दूध आदि। जैसे तृतीय योजना

मे भौतिक योजना 8600 करोड़ रुपये की थी। पर वित्तीय योजना 7500 करोड़ रुपये की थी। अतः भौतिक योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वित्तीय साधन जुटाने की वित्तीय योजना बनाई जाती है। समाजवादी राष्ट्रों में भौतिक नियोजन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रो० डोब तथा प्रो० महासन्तोविस देश में उपलब्ध साधनों के विदोहन के लिये भौतिक आयोजन पर जोर देते हैं। सोवियत रूस की प्रगति का मूलमंत्र भौतिक नियोजन की प्रधानता है।

#### (14) वित्तीय नियोजन (Financial-Planning)

वित्तीय नियोजन का अर्थ-आर्थिक योजनाओं की आवश्यकताओं तथा लक्ष्यों आदि को द्रव्य के रूप में व्यक्त करना है। इसमें लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये वित्तीय साधनों का निर्धारण एवं प्रबंध की व्यवस्था की जाती है। जैसे प्रत्येक भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति पर कितना कितना द्रव्य व्यय होगा और यह द्रव्य कैसे जुटाया जायेगा। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, अध्यापकों पर क्रमशः 100 करोड़ रु०, 200 करोड़ रु० तथा 50 करोड़ रु० व्यय होगा। उसमें से 200 करोड़ रु० करो से, 100 करोड़ रु० श्रृणो तथा 50 करोड़ रु० घाटे की वित्त व्यवस्था इसके सक्षिप्त उदाहरण हैं। इस प्रकार इस पद्धति में लक्ष्यों की भौतिक गणना के बाद उसे मुद्रा में मूल्यांकित किया जाता है तथा विभिन्न स्रोतों से मौद्रिक आय का अनुमान लगाया जाता है। डा० बी० आर० शिनाय ने भौतिक नियोजन से अधिक महत्व वित्तीय नियोजन को दिया है और उनका यह मत है कि वित्तीय नियोजन बचत कोष पर निर्भर करता है। बचत पर ही विनियोग सम्भव है अतः विनियोग बचत से अधिक होने पर मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है जो विकास में बाधक बनती है।

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में वित्तीय नियोजन परमावश्यक है क्योंकि भौतिक साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है और सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये व्यय करना पड़ता है। वित्तीय साधनों के अभाव में लक्ष्यों की पूर्ति करना कठिन हो जाता है।

भौतिक नियोजन और वित्तीय नियोजन के उपर्युक्त विवरण से यह निष्कर्ष निकालना श्रुतिपूर्ण होगा कि दोनों एक दूसरे से पृथक् व असम्बन्धित हैं। वास्तव में ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं प्रो० जे० के० मेहता के अनुसार भौतिक व वित्तीय नियोजन दोनों एक अविभाज्य प्रक्रिया के ही दो अंग हैं।

डा० बालकृष्ण के अनुसार "भौतिक तथा वित्तीय नियोजन के बारे में वाद-विवाद निरर्थक है क्योंकि दोनों में वास्तव में परस्पर विरोध नहीं है। भौतिक आयोजन प्रयासों को सूर्तरूप देने के लिये नितान्त आवश्यक है लेकिन भौतिक नियोजन को गतिमान करने के लिये वित्त आवश्यक है। दोनों में परस्पर मेल के अभाव

में न तो वित्तीय और न भौतिक नियोजन ही लाभप्रद हो सकता है।”

साधनों की कमी से कभी-कभी लक्ष्यों में परिवर्तन करना पड़ता है और अगर लक्ष्यों को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय किया गया है तो उन्हें प्राप्त करने के लिये अतिरिक्त साधन जुटाने पड़ते हैं। विकासशील राष्ट्रों में साधनों का अभाव है और उनके विकास के निम्न स्तर को देखते हुए आर्थिक सम्पन्नता के लिये महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाने पर वित्तीय साधन न होने पर लक्ष्यों की पूर्ति कठिन हो जाती है। पर डा० शिनाय के अनुसार बिना बचत विनियोग बढ़ाना वास्तविक साधनों में वृद्धि के बजाय मुद्रास्फीति के दुष्प्रभावों को आमंत्रित करना है। मैं इस कथन से पूर्णतया सहमत नहीं हूँ क्योंकि मुद्रा स्फीति का जन्म तभी होता है जबकि मौद्रिक आय में तो वृद्धि हो जाती है पर विनियोग का प्रतिफल दीर्घकाल तक नहीं मिलता। अगर होनाय प्रबन्ध से साधन जुटाकर उनका उपयोग दीर्घ फलदायिनी योजनाओं में व्यय किया जाता है तो मौद्रिक आय के साथ साथ भौतिक साधनों की भी वृद्धि होनी है। अल्पकालीन स्थिति पर नियन्त्रण के लिये उपभोग वस्तुओं की पूर्ति विवेकपूर्ण कर पद्धति व बचत योजनाओं से उन पर काबू पाया जा सकता है जैसे प्रथम योजना में प्रावधान से अधिक अर्थात् 420 करोड़ रुपये होनाय प्रबंध से जुटाया गया फिर भी सामान्य मूल्य स्तर में गिरावट आई यद्यपि 1955 के अन्त में पुन तेजी का दौर प्रारम्भ हो गया था। चौथी योजना के भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिये आवार बढ़ा दिया गया है। तीसरी योजना में वित्तीय साधनों की योजना सावजनिक क्षेत्र के लिये केवल 7500 करोड़ रु० की थी पर वास्तविक व्यवस्था 85/7 करोड़ रु० की गई अर्थात् इसके अन्तर्गत देश में नियोजन को सुरक्षात्मक तथा विकासोन्मुख (Defence cum Development oriented) बनाने के लिये अतिरिक्त साधन जुटाने ही पड़े। जबकि द्वितीय योजना में व्यय को खर्च के अभाव में प्रावधान से कम ही करना पड़ा और भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी।

### (15) अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन आयोजन (Short Period Planning and Long Period Planning)

अथवा

### निकट भविष्य आयोजन एवं सुदूर भविष्य आयोजन (Prospective Planning and Perspective Planning)

अल्पकालीन आयोजन को निकट भविष्य आयोजन भी कहते हैं। इस पद्धति में प्राय 3 से 7 वर्ष की अवधि के लिये कार्यक्रम बनाये जाते हैं जो दीर्घकालीन आयोजन से सम्बद्ध होते हैं। इस अवधि के कार्यक्रम को भी प्राय वार्षिक योजना के रूप में बांटा जाना है ताकि प्रतिवर्ष का प्रगति की समीक्षा से अगले वर्ष का कार्यक्रम

1. *The controversy between Financial and Physical Planning is needless as the two are not really contradictory. Physical Planning is absolutely essential for giving concreteness to effort, but Financial is the mobiliser of Physical Planning. Neither Financial nor Physical Planning can set things going without an integration between them.* Dr. Bal Krishan

संशोधित किया जा सके, तथा उसमें यथार्थ तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जा सके।

दीर्घकालीन आयोजन (Perspective or Long period Planning) को सुदूर भविष्य आयोजन भी कहा जाता है। इसके अन्तर्गत अर्थव्यवस्था के भावी विकास की 15-20 साल की अवधि की प्रगति की मोटी रूपरेखा निर्धारित की जाती है और अल्पकालीन योजनाएँ उन दीर्घकालीन उद्देश्यों के अनुकूल ढाली जाती हैं।

आर्थिक नियोजन की यह पद्धति भी अल्पकाल की योजनाओं को प्रभावित करती है। ये दोनों परस्पर सम्बद्ध हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति को 30 मील की यात्रा करनी है। उसे पहले घण्टे में कितना चलना है—दूसरे में कितना—जबकि उसे पहुँचने के लिये 10 घण्टे दिए हों। अतः वह अपनी यात्रा को इन दस घण्टों में समायोजन करेगा। ठीक उसी प्रकार से दीर्घकालीन योजना 15-20 साल की होती है उसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं (या जैसा चाहे) में विभाजन करेगा, फिर इनको वार्षिक योजनाओं में भारत में जो दोनो प्रकार की योजनाओं का सम्मिश्रण है। रूस में भी 20 वर्षीय योजना (1960-80) सप्तम, अष्टम, नवम् तथा दसवीं—इन चार योजनाओं की सम्मिलित दीर्घकालीन योजना है।

#### (16) स्थायी नियोजन तथा आकस्मिक या आपातकालीन नियोजन (Permanent Planning & Emergency Planning)

स्थायी नियोजन—दीर्घकालीन दृष्टिकोण पर आधारित वह नियोजन प्रक्रिया होती है जो अर्थ-व्यवस्था में निरन्तर चलती रहती है तथा आर्थिक जीवन का सामान्य एवं अविभाज्य अङ्ग बन जाती है जैसे रूस में 1928 से प्रारम्भ किया गया नियोजन निरन्तर चल रहा है और आगे भी अवाध गति से चलता रहेगा। भारत में भी 1951 से स्थायी नियोजन का मार्ग अपनाया गया है।

अस्थायी आकस्मिक या आपातकालीन नियोजन (Emergency Planning)—आयोजन की वह पद्धति है जो अर्थ व्यवस्था में तात्कालिक संकट या अल्पकालीन आर्थिक असन्तुलन के निराकरण के लिये अपनाई जाती है और उस संकट के बाद अर्थ-व्यवस्था का संचालन अपने सामान्य ढंग से होना है। उदाहरण के तौर पर 1933 में अमेरिका का न्यू-डील, युद्ध जर्जरित अर्थ व्यवस्था के पुनः निर्माण की मार्शल योजना युद्ध व संकट का मुकाबला करने के लिये अपनाया गया आयोजन इसी श्रेणी में आते हैं।

#### (17) गतिशील व स्थिर नियोजन (Dynamic or Static Planning)

गतिशील या प्राबलिक नियोजन (Dynamic Planning) के अन्तर्गत नियोजन में पर्याप्त लोचता एवं परिवर्तन क्षमता होती है जिससे कि परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन सम्भव होता है। यह बहुत ही व्यावहारिक एवं समायोजक होता है।

स्थिर नियोजन (Static Planning)—नियोजन की वह कठोर पद्धति होती है जिसमें समय, स्थान एवं परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन की क्षमता नहीं होती। इसका परिणाम यह होता है कि नियोजन की कठोरता में व्यावहारिकता की बलि दे दी जाती है।

### (18) सार्वजनिक क्षेत्र नियोजन तथा निजी क्षेत्र का नियोजन

सार्वजनिक क्षेत्र नियोजन (Public sector Planning) का अभिप्राय सरकार द्वारा देश की) सार्वजनिक उद्योगों तथा व कार्यालयों में सम्बन्धी योजनाओं का निर्माण व प्रशासन से है। इसके अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के विचारों एवं नियुक्त व्यक्ति व उद्योग यान्त्रिक एवं परिवहन, समाज कल्याण, शिक्षा, परिवार नियोजन आदि के कार्यक्रमों का है। भारत जैसे मिश्रित अर्थ व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र नियोजन आर्थिक विकास का प्रमुख अंग है।

निजी क्षेत्र नियोजन (Private Sector Planning)—अर्थ-व्यवस्था के निजी क्षेत्र के उत्पादन विनिर्माण, वस्त्र उपभोग, वितरण आदि के नियोजन से सम्बन्धित होता है। यह सम्पूर्ण नियोजन का महत्वपूर्ण भाग होता है।

### (19) उदार एवं अनुदार नियोजन (Liberal & Conservative Planning)

उदार नियोजन (Liberal Planning) व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित बाह्य एवं आन्तरिक साधनों, ऋणों तथा विदेशी सहयोग व ऋणों के द्वारा आर्थिक विकास के लिये आयोजित होता है अतः विकास की दर अधिक तथा विकास के लिये आर्थिक तकनीकी सहायता सन्तुष्ट हो जाती है। विश्व के सभी विकासशील राष्ट्र व भारत ने उदार नियोजन अपनाया है। अनुदार नियोजन (Conservative Planning) संकुचित दृष्टिकोण पर आधारित स्वयं के आन्तरिक साधनों से विकास के लिये नियोजन अपनाया जाता है। विदेशी सहायता व ऋणों का सहारा नहीं लिया जाता परिणामस्वरूप विकास की दर नीची और आत्म-निर्भरता में समय लगता है।

### (20) कृषि प्रधान या उद्योग प्रधान नियोजन

आर्थिक नियोजन को जिस योजना में कृषि कार्यक्रमों की प्रधानता व कृषि की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है, उसे कृषि प्रधान नियोजन (Agricultural Planning) कहा जाता है पर जहाँ उद्योगों के विकास तथा तत्सम्बन्धी कार्यक्रमों की प्रधानता व उनका सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है उसे उद्योग प्रधान नियोजन (Industrial Planning) कहते हैं।

### 21 पूँजी प्रधान या श्रम प्रधान नियोजन

जब नियोजन प्रक्रिया में पूँजी विनियोग व पूँजी प्रयोग की प्रधानता होती है। तो ऐसी योजना को पूँजी प्रधान नियोजन (Capital Oriented Planning) कहते हैं पर जब नियोजन में श्रम के उपयोग व श्रम के भोग्यताओं के वृद्धि को प्राथमिकता दी जाती है तो उसे श्रम प्रधान नियोजन (Labour Oriented Planning) कहते हैं। भारत में दोनों का उपयोग सम्मिश्रित किया गया है।

## (22) सन्तुलित बनाम असन्तुलित नियोजन (Balanced V/S Unbalanced Planning)

जब आर्थिक नियोजन के द्वारा अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों उत्पादन-उद्योगों व उपभोग-उद्योगों का साथ-साथ विकास किया जाता है तो उसे सन्तुलित नियोजन (Balanced Planning) कहा जाता है पर जब नियोजन में पूंजीगत एवं उत्पादक उद्योगों के तोड़ विकास में उपभोग व वितरण की उपेक्षा की जाती है तो उसे असन्तुलित नियोजन कहा जाता है। विकासशील राष्ट्रों में सीमित साधनों के द्वारा असन्तुलित नियोजन की व्यवस्था ऊँची विकास दर के लिए उपयुक्त मानी जाती है पर प्रारम्भिक व्यवस्था में कष्ट उठाना पड़ता है।

## (23) रचनात्मक एवं विस्थापन नियोजन

जब अर्थ-व्यवस्था में नियोजन के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिये रचनात्मक कार्यों—नये आविष्कारों, नवीन उद्योगों, नयी उत्पादन पद्धतियों, नवीन बाजारों व नये कच्चे माल की खोज आदि का सहारा लिया जाता है तो उसे रचनात्मक नियोजन (Constructive Planning) कहा जाता है। पर अगर पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिये अर्थव्यवस्था में बिघटन, तोड़-फोड़ व नीतियों में आमूल-भूत परिवर्तनों का रास्ता अपनाया जाता है तो उसे विस्थापन के द्वारा नियोजन (Planning Through Dislocation) कहते हैं।

## (24) हीनार्थ एवं सीमित नियोजन (Deficit & Restricted Planning)

जब नियोजन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये वित्तीय व्यवस्था में हीनार्थ प्रवृत्ति (घाट की वित्त व्यवस्था) का उदारता से प्रयोग किया जाता है तो उसे हीनार्थ नियोजन कहा जाता है पर जब योजना के भीतिक लक्ष्यों को देश में उपलब्ध साधनों से सीमित किया जाता है तब घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा नहीं लिया जाता है। उपलब्ध साधनों की कमी होने पर कार्यक्रमों को भी कम कर दिया जाता है। इसी कारण ऐसे नियोजन को सीमित नियोजन (Restricted Planning) कहा जाता है।

विभिन्न आधारों पर नियोजन के वर्गीकरण के उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि आर्थिक नियोजन का यह वर्गीकरण सपेक्षिक एवं परस्पर निर्भर है इसी कारण किसी भी देश के नियोजन में उसके अनेक रूपों का सम्मिलित एवं समन्वित रूप अपनाया जाता है। जैसे भारत में प्रजातान्त्रिक नियोजन सामान्य, सरचनात्मक, विकासवादी, प्राथमिक उदार नियोजन है जो श्रम प्रधान, हीनार्थ, प्रवृत्त और मिश्रित है।

जनसंख्या वाले देश में जिसमें प्राकृतिक साधनों का अभाव हो अथ व्यवस्था के पूर्ण विकास के बावजूद भी उन देश की प्रति व्यक्ति आय का स्तर नीचा हो सकता है। अगर अमेरिका या अन्य देशों की तुलना में अन्य अथ व्यवस्थाओं को हमेशा ही देखा जाय तो सम्भव है कि एक देश विकसित हो जाने पर भी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम होने से अर्द्ध विकसित श्रेणी में ही मानना उपयुक्त नहीं है।

प्रो० जेकब वानर (Jacob Viner) के शब्दों में 'एक अर्द्ध विकसित देश वह है जिसमें अधिक धर्म अधिक पूँजी या अधिक प्राकृतिक साधनों या इन सभी साधनों के उपयोग की पर्याप्त सम्भावनाएँ हैं जिससे वर्तमान जनसंख्या का रहन सहन का स्तर ऊँचा उठाया जा सकता है और यदि उसकी प्रति व्यक्ति आय पहले से ही काफी ऊँची है तो जीवन स्तर को गिराये बिना अधिक जनसंख्या का निर्वाह किया जा सकता है' यह परिभाषा अर्द्ध विकसित अथ व्यवस्था को साधनों के सम्बन्ध और जीवन स्तर के परिप्रस्थ में देखती है पर यह नहीं बताती कि विकास के लिये क्या बाधाएँ और अर्द्ध विकसित अथ व्यवस्था की क्या क्या मुख्य विशेषताएँ हैं अतः यह परिभाषा भी अपूर्ण है।

भारतीय योजना आयोग ने अर्द्ध विकसित अथ व्यवस्था को इस प्रकार परिभाषित किया है 'एक अर्द्ध विकसित राष्ट्र वह है जहाँ एक ओर अप्रयुक्त अथवा अल्पप्रयोगित मानव शक्ति तथा दूसरी ओर अशोषित प्राकृतिक साधनों का गूना-धिक मात्रा में सह अस्तित्व पाया जाता है।' इस परिभाषा में यह तो स्पष्ट है कि ऐसे राष्ट्रों में एक ओर अप्रयुक्त मानव शक्ति तथा दूसरी ओर विरोध के लिये पर्याप्त प्राकृतिक साधनों का सह अस्तित्व होता है पर ऐसा क्यों है इसका स्पष्टीकरण नहीं है।

रॉबर्ट नर्कसे (Nurkse) तथा आस्कर लॉग आदि अर्थशास्त्रियों ने अर्द्ध विकसित राष्ट्रों में पूँजी का अभाव का आधार माना है जैसे आस्कर लॉग (Oskar Lange) के अनुसार अर्द्ध विकसित देश वह है कि जिसमें पूँजी की मात्रा इतनी नहीं है कि 'ह वर्तमान धर्म शक्ति का उपलब्ध तकनीकी स्तर पर प्रयोग कर सके।' इसी प्रकार का विचार नर्कसे (Robert Nurkse) ने व्यक्त किया है। उनके मतानुसार अर्द्ध विकसित देश वह है जिसमें प्राकृतिक साधनों व जनशक्ति का उपयोग यदि पूँजी का अभाव हो। परन्तु पूँजी विकास के लिये आवश्यक होने हुए भी उत्पन्न होता ही पर्याप्त नहीं है। ये दोनों परिभाषाएँ भी अपूर्ण हैं केवल पूँजी

1. Jakob Viner *International Trade & Economic Department* p. 123

2. An under developed country is that which is characterized by the co-existence of greater or less degree of unutilized manpower on the one hand of unexploited natural resources on the other — *Indians Five Year Plan*



के अभाव को अर्द्ध-विकसितता का कारण मानती है जबकि अर्द्ध-विकसित होने के दूसरे भी कई महत्वपूर्ण कारण होते हैं। प्रो० जे० के० मेहता ने लिखा है 'एक अर्द्ध-विकसित देश एक बच्चे की भाँति है जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है परन्तु विकासशील है।' इससे अलावा प्रो० जे० आर० हिक्स (J R Hicks) ने अर्द्ध-विकसित राष्ट्र की परिभाषा देते हुए उसके प्रौद्योगिक एवं तकनीकी ज्ञान के निम्न स्तर की ओर संकेत दिया है। उसके अनुसार "एक अर्द्ध-विकसित देश वह है जिसमें प्रौद्योगिक (Technological) तथा मौद्रिक साधनों (Monetary Resources) की सीमा भी उत्पादन व वृद्धि के वास्तविक स्तर के समान ही नीची है। फलस्वरूप प्रति इकाई भूमिक पुरस्कार उस स्तर के मुकाबले बहुत कम है जो देश व साधनों पर प्रौद्योगिक ज्ञान के प्रयोग की पूर्णतया में सम्भव हो पाता है।" इस परिभाषा में मौद्रिक तथा प्रौद्योगिक ज्ञान पर विशेष बल दिया गया है जबकि विकास में प्राकृतिक साधनों, सामाजिक संगठन व राजनैतिक व्यवस्था के महत्व की अपेक्षा की गई है।

इन सब परिभाषाओं के सलिप्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी परिभाषा सर्वमान्य, सन्तोषजनक एवं अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था की सभी विशेषताओं का समावेश करने में समक्ष नहीं है फिर भी अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था की अधिक उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं एक अर्द्ध विकसित देश वह है जिसमें एक ओर अप्रयुक्त या अर्द्ध प्रयोगित मानव शक्ति तथा अक्षोपित प्राकृतिक साधनों का सह-अस्तित्व हो और दूसरी ओर भौद्रिक, प्रौद्योगिक व गैर-आर्थिक सीमाओं के कारण विकसित राष्ट्रों की तुलना में आय उपभोग वृद्धि तथा पूँजी निर्माण का स्तर बहुत नीचा होने से निधनता का कुचक्र होने के बावजूद जनता आर्थिक विकास व सभाष्य समृद्धि के लिये सतत् प्रयत्नशील हो। इस परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में देखने पर भारत, लका पाकिस्तान, एशिया के अन्य देश, अफ्रीका के अनेक देश और केन्द्रीय तथा दक्षिणी अमेरिका के अनेक देश अर्द्ध विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं जबकि अमेरिका, ब्रिटन, रूस जापान व पश्चिमी यूरोप के प्रायः सभी राष्ट्र विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। अर्द्ध-विकसित देशों में भी आर्थिक विकास का स्तर समान न होने से कुछ अर्द्ध विकसित दूसरों की अपेक्षा अधिक विकसित अर्द्ध विकसित हैं। सामान्यतः अर्द्ध-विकासित राष्ट्रों में निम्न विशेषताएँ दृष्टि-गोचर होती हैं।

### अर्द्ध विकसित या अल्प विकसित राष्ट्रों की प्रमुख विशेषताएँ

(Main Characteristics of an Under-developed Country)

विश्व के अनेक अर्द्ध विकसित राष्ट्रों में प्रत्येक की अपनी अलग अलग विशेषताएँ होने के कारण यद्यपि उनकी समुक्त रूप से एक प्रकार की विशेषता बताना कठिन है फिर भी मोटे रूप में उनमें सामान्यतः अग्र विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं—

## (A) आर्थिक विशेषतायें (Economic Characteristics)

(1) प्राथमिक उद्योगों की प्रधानता (Predominance of Primary Industries)—अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों की सर्व प्रथम विशेषता उनमें प्राथमिक उद्योगों की प्रधानता का होना है जिसके अन्तर्गत कृषि, पशु-पालन, मत्स्य पालन व खनिज उद्योग तथा वनों से आय प्राप्त करना आदि का समावेश होता है। देश की जनसंख्या का 50 से 75% भाग कृषि से अपना जीविकोपार्जन करता है और कृषि से प्रायः राष्ट्रीय आय का 40 से 60 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है जैसे भारत में 70% कोलम्बिया की 72% ब्राजील की 64% तथा लूसा की 53% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। कृषि से भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग 45% से 50% भाग प्राप्त होता है। यही नहीं इन प्राथमिक उद्योगों में उत्पादकता का स्तर बहुत नीचा होने से आश्रित जनसंख्या दरिद्र है। जैसे भारतीय कृषि की दशा अब भी पिछड़ी है। दोषपूर्ण भूमि वितरण, कृषि जोतों का छोटा आकार उप-खेती एवं उप विभाजन, उत्पादन की परम्परागत पद्धतियाँ व यन्त्रीकरण का अभाव आदि से ऋण प्रसूता और कृषि उत्पादकता का निम्न स्तर है। भारत में प्रायः सभी फसलों में प्रति एकड़ उपज विकसित राष्ट्रों के मुकाबले बहुत कम है।

(2) औद्योगिक पिछड़ापन (Industrial Backwardness)—अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में आधुनिक ढंग के बड़े पैमाने के आधारभूत एवं मूलभूत उद्योगों का नितान्त अभाव होता है। उपभोग उद्योग भी पिछड़ी अवस्था में होते हैं। जहाँ विकसित राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय आय का लगभग 30 से 40% भाग औद्योगिक क्षेत्र से प्राप्त करते हैं वहाँ अर्द्ध विकसित राष्ट्रों में उद्योगों से राष्ट्रीय आय का केवल 8 से 12% भाग प्राप्त होता है। यही नहीं उद्योगों में केवल 10 से 20 प्रतिशत जनसंख्या आजीविका कमाती है जबकि विकसित राष्ट्रों में उद्योगों पर देश की कुल जनसंख्या का 30 से 40% भाग आश्रित होता है। भारत में कुल जनसंख्या का केवल 20% भाग उद्योगों पर आश्रित है और औद्योगिक क्षेत्र से राष्ट्रीय आय का लगभग 11 से 14% भाग प्राप्त होता है।

(3) अर्द्ध-विकसित प्राकृतिक संपन (Under-developed Natural Resources)—अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में प्रायः यह विशेषता विद्यमान है कि देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का पूरा पूरा विदोहन एवं विकास नहीं होने से उनका प्रयोग सम्भव नहीं हो पाया है जैसे अनेक अफीका में विश्व की सम्भावित जलशक्ति का 40% भाग है पर वहाँ केवल 0.1% का उपयोग हो रहा है। इसी प्रकार भारत में प्राकृतिक साधनों का प्राचुर्य है खनिज सम्पदा की सम्पन्नता है पर पर्याप्त विदोहन के अभाव में देश पिछड़ा है। जहाँ भारत में विश्व लोह भण्डार का 25% भाग अर्थात् 2160 करोड़ टन का अनुमान है वहाँ लोहे का वार्षिक खनन 19.3-74 में 5 करोड़ टन होने का अनुमान है। इसी प्रकार हम अपने उपलब्ध जल स्रोतों में केवल 33% का उपयोग सिंचाई में कर पा रहे हैं।

(4) सामान्य दरिद्रता एवं निम्न प्रति व्यक्ति आय (General Poverty & Low Per Capital Income)—अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में औद्योगिक पिछड़ापन, अर्द्ध-विकसित प्राकृतिक साधन, पिछड़ी कृषि की प्रधानता, अप्रयुक्त विशाल मानव शक्ति आदि कारणों से सामान्य निर्धनता का साम्राज्य है तथा प्रति व्यक्ति आय का स्तर विकसित राष्ट्रों के मुकाबले बहुत कम है। जहाँ अमेरिका में 1970 में प्रति व्यक्ति आय 4760 डॉलर, कनाडा में 3700 डॉलर, फ्रान्स में 3100 डॉलर, जापान में 1920 डॉलर तथा रूस में 1790 डॉलर थी वहाँ अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में प्रति व्यक्ति आय भारत में 110 डॉलर, चीन में 160 डॉलर, सजा में 150 डॉलर तथा पाकिस्तान में 120 डॉलर ही थी। मोटे रूप में यह कहा जा सकता है कि विश्व की आधी जनसंख्या की प्रति व्यक्ति आय 100 डॉलर से कम तथा दो-तिहाई जनसंख्या की आय 300 डॉलर से कम है और ये सब राष्ट्र अर्द्ध-विकसित की श्रेणी में आते हैं।

(5) निम्न जीवन स्तर (Low Standard of Living)—अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में दरिद्रता व प्रति व्यक्ति आय के नीचे स्तर के कारण लोगों का जीवन-स्तर भी बहुत नीचा है। स्वास्थ्यप्रद भोजन की तो बात दूर रही अधिकांश लोगों को भर पेट भोजन भी उपलब्ध नहीं होना। जहाँ भोजन में न्यूनतम 3000 कैलोरीज प्रति व्यक्ति आवश्यक माना जाता है, अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में औसतन 2000 कैलोरी से भी कम होता है। वस्त्र, मकान, शिक्षा एवं चिकित्सा जैसी आधारभूत आवश्यकताओं का भी नितान्त अभाव श्रष्टिपोचर होता है। न तन ढकने की कपड़ा, न रहने की मकान और न पेट भरने की भोजन की समस्या। संक्षेप में रोटी, कपड़ा, मकान की समस्या प्रायः सभी अर्द्ध विकसित राष्ट्रों में न्यूनाधिक रूप में विद्यमान है, शिक्षा सुविधायें कम होने से शिक्षा का भी अभाव होता है। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में बीस वर्षों के योजनाबद्ध विकास के बावजूद भी 1971 में साक्षरता का प्रतिशत 29.35 था जबकि जापान, ब्रिटेन, अमेरिका आदि राष्ट्रों में लगभग 90 से 99% जनसंख्या साक्षर होती है। चिकित्सा सुविधायें भी अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में न्यूनतम स्तर पर होती हैं। अतः लोगों का जीवन-स्तर विकसित देशों के मुकाबले बहुत नीचा होता है।

(6) व्यापक बेरोजगारी, अर्द्ध-बेकारी तथा छिपी बेरोजगारी (Large Scale Unemployment, Under-employment and Disguised Unemployment)—बायर एवं यामे के अनुसार “अकुशल श्रमिकों की व्यापक बेकारी पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्थाओं की एक प्रमुख विशेषता है। कई व्यक्ति अनियोजित या अर्द्ध-नियोजित केवल इसलिए नहीं होते कि वे काम करना पसन्द न करते हो बल्कि इसलिए होते हैं कि उन्हें काम में लगाने के लिये सहयोगी उत्पादन साधन अपर्याप्त होते हैं।” कृषि की प्रधानता व औद्योगिक पिछड़ापन के कारण केवल कृषि ही उनके रोजगार का

खोन है और कृषि पर आवश्यकता में अधिक भाग होने से अल्प अथवा छिपी हुई बेकारी भी होती है। अल्प बेकारी का अभिप्राय उन लोगों से है जो प्रत्यक्ष रूप से तो काम पर लगे हुए लगते हैं पर अगर उनको उस काम से हटा दिया जाये तो भी उत्पादन में कमी नहीं होगी। संयुक्त राष्ट्र सघ के एक अध्ययन के अनुसार भारत, पाकिस्तान, फिलीपाइन्स तथा इन्डोनेशिया के कुछ भागों में छिपी हुई बेकारी 20 से 25% है। भारत जैसे राष्ट्र में चूर्ण तथा सफरिन न बेकारी तथा अर्द्ध बेकारी की समस्या को इस प्रकार व्यक्त किया है—“भारत में प्रनिवर्ण बेकारी व अर्द्ध-बेरोजगारी के कारण उतने श्रम घण्टों का अपव्यय होता है जितने संयुक्त राज्य अमेरिका में समस्त श्रम शक्ति द्वारा किये जाते।” यही दशा प्रायः सभी अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में है। भारत में बेरोजगारी की संख्या 1955 में 53 लाख थी और 1978 तक 45 करोड़ होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त इन देशों में मौसमी बेरोजगारी, घातीय बेकारी तथा सघर्षात्मक बेकारी भी दृष्टिगोचर होती है।

(7) पूँजी निर्माण तथा विनियोग का निम्न स्तर (Low level of Capital Formation & Investment)—अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में आर्थिक निर्धनता के कारण प्रति व्यक्ति आय एवं बचत का स्तर बहुत नीचा होता है जबकि उपभोग क्षमता की दर ऊँची रहती है। जो कुछ थोड़ी बहुत बचत होती है वे भी सामाजिक एवं परम्परागत रूढ़िवादों के कारण अनुप्यादक कार्यों—विवाह, मृत्यु-भोज, गहनो आदि पर व्यय कर दी जाती है। परिणामस्वरूप बचत व विनियोग के अभाव में पूँजी निर्माण की दर विकसित राष्ट्रों के मुकाबले नगण्य है। संयुक्त राष्ट्र सघ के एक सर्वेक्षण के अनुसार 1960 में जहाँ पूँजी निर्माण की दर विकसित राष्ट्रों-अमेरिका में 18%, पश्चिमी जर्मनी में 24% व जापान में 28.5% थी वहाँ अर्द्ध-विकसित देशों में पूँजी निर्माण की दर भारत में 8%, लक्सा व घाना में 11% तथा तुर्की व ईराक में लगभग 15% थी। यह उल्लेखनीय है कि भारत में 1951 में पूँजी निर्माण की दर राष्ट्रीय आय का 5½% ही थी अब यह बढ़कर लगभग 22% हो गई है। यही नहीं, अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में आय के असमान वितरण के कारण जो धनी लोग बचाने में सक्षम हैं वे भी बचतों को प्रदर्शनात्मक प्रभाव के कारण उत्कृष्ट उपभोग (Conspicuous Consumption) पर अपव्यय करते हैं।

(8) विदेशी व्यापार पर आधारित अर्थ-व्यवस्था (Foreign Trade Oriented Economies)—वर्तमान से अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों की अर्थ-व्यवस्था विदेशी व्यापार पर बहुत अधिक आश्रित होती है। इन राष्ट्रों में प्रायः राष्ट्रीय आय का 20 से 30% भाग परम्परागत वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त होता है। एक अनुमान के अनुसार लक्सा, मलाया व दक्षिणी अमेरिका के देशों में निर्यातों से राष्ट्रीय आय का 30% भाग प्राप्त होता है। इसी प्रकार ईरान, दक्षिणी अफ्रीका व कुवैत अपने तेल निर्यात से 90% भाग प्राप्त करते हैं। वयला देश भी जूट से अपनी निर्यात आय का 70%

भाग तथा भारत भी 1951 में परम्परागत वस्तुओं से 60% निर्यात आय प्राप्त करता था। 1971 में यह लगभग 35% था और 1976-77 में घटकर 16% हो गया है।

अन्तराष्ट्रीय बाजारों में इन वस्तुओं व भावों में अत्यधिक उतार चढ़ावों से अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों की अर्थ-व्यवस्था आर्थिक संकटों में फँसती रहती है। व्यापार की शर्तें भी विकसित देशों के अनुकूल तथा अर्द्ध-विकसित देशों के प्रतिकूल हो रहती हैं।

(9) बाजार की अपूर्णताएँ (Market Imperfections)—प्रो० मेयर एव बाल्डविन (Meir & Baldwin) के अनुसार अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में उत्पादन मापनों में गतिशीलता का अभाव, मूल्यों की वोलैयता, अज्ञानता, सामाजिक एवं धार्मिक रुढ़िवादिता, विशिष्टीकरण का अभाव, परम्परा से वोलैय आर्थिक ढाँचा, आय, वस्तु एवं विनियोग का निम्न स्तर तथा एक ओर सकीर्ण मौद्रिक क्षेत्र और दूसरी ओर अमौद्रिक क्षेत्र आदि अनेक अपूर्णताओं के कारण अर्थव्यवस्था निर्धनता व गरीबी के फँसी हुई है जिससे विकास प्रक्रिया ही अवरुद्ध हो गई है। साहसियों तथा सरकार की सक्रियता के अभाव में विकास की उत्पत्ति और भी कठिन हो जाती है।

(10) तकनीकी ज्ञान एवं प्रौद्योगिक पिछड़ापन (Backwardness of Technical know-how & Technology)—अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में तकनीकी ज्ञान एवं प्राविधिक उत्पादन पद्धतियों का नितान्त अभाव होता है उनमें उत्पादन की परम्परागत रुढ़िवादी पद्धतियाँ निम्न उत्पादन स्तर का कारण एवं परिणाम हैं। अल्प-विकसित देशों में प्रौद्योगिक ज्ञान एवं वैज्ञानिक शिक्षा की बात दूर रही, साक्षरता प्रतिशत भी 20 से 30 होता है। वैज्ञानिक शोध एवं अनुसंधान की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। जहाँ विकसित राष्ट्रों में नवीन उत्पादन पद्धतियों, शोध एवं अनुसंधान पर अमेरिका में 154 द० प्रति व्यक्ति, रूस में 110 द० प्रति व्यक्ति वार्षिक व्यय किया जाता है वहीं भारत जैसे विकासशील देश में यह व्यय नाम मात्र 15 पैसे प्रति व्यक्ति वार्षिक है। यही नहीं, अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में श्रम प्रधान अकुशल उत्पादन पद्धतियों के कारण उत्पादन लागत भी अधिक रहती है।

(11) आर्थिक विषमता की चौड़ी खाई (Extreme Economic Disparities) अर्द्ध-विकसित अर्थ व्यवस्था में राष्ट्रीय आय व सम्पत्ति के वितरण में काफी विषमता पाई जाती है। एक ओर थोड़े से धनिकों को अपार सम्पत्ति व राष्ट्रीय आय का सापेक्षतया बड़ा भाग जबकि दूसरी ओर असह्य साधन व आयहीन निर्धन जनता। प्रो० महलनोबीस के प्रतिवेदन के अनुसार 1955-56 में भारत में 5% लोगों को राष्ट्रीय आय का 23% प्राप्त हो रहा था जबकि इनसे ऊपर के 1% लोगों को राष्ट्रीय आय का 11% तथा सबसे नीचे के 25% लोगों को राष्ट्रीय आय का केवल

10% भाग ही मिल रहा था। इसी प्रकार के विचार की पुष्टि साइमन कुजनेत्स ने भी की है। उसके अनुसार जहाँ भारत और लक्सा में देश की 20% घनिक जन-संख्या राष्ट्रीय आय का क्रमशः 55% तथा 50% भाग हड़प जाती है वहाँ देश की 70% गरीब जनता क्रमशः 28% तथा 30% ही प्राप्त करती है जबकि विकसित राष्ट्रों में यह विषमता की खाई कम चौड़ी है।

(12) उचित राजकोषीय एवं मौद्रिक संगठन का अभाव (Lack of Proper Fiscal & Monetary Organisation)—अर्द्ध-विकसित देशों में न तो एक सन्तुलित एवं प्रगतिशील राजकोषीय नीति होती है और न एक उपयुक्त मौद्रिक व्यवस्था ही। अप्रत्यक्ष करों की प्रधानता होती है जो प्रगतिशील होने हैं और करवचना की प्रवृत्ति प्रबल होने से सरकार के आय स्रोत सीमित होते हैं ऐसे देशों का मुद्रा बाजार असंगठित होता है और संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में समन्वय का अभाव होता है अतः केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीति अशुभ होती है। बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं के अभाव में पूँजी-निर्माण व बचत को प्रोत्साहन नहीं मिलता।

(13) आर्थिक निर्धनता के कुचक्रों का जोर (Vicious Circle of Economic Poverty) — अर्द्ध-विकसित राष्ट्र निर्धनता के कुचक्रों में फँसे होते हैं। माँग और पूर्ति पक्षों में ये कुचक्र अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास में सबसे प्रमुख बाधा है। ये कुचक्र उनकी निर्धनता के कारण एवं परिणाम दोनों ही होते हैं। प्रो० नर्से के अनुसार "एक देश निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है" (A Country is poor because it is poor) इन देशों में अविकसित साधनों, पिछड़ेपन व पूँजी की कमी के कारण निम्न उत्पादकता होती है जिससे वास्तविक आय नीची होती है परिणामस्वरूप उपभोग व बचत का स्तर भी नीचा रहता है और विनियोग भी कम रहता है इससे पूँजी निर्माण कम होता है और अर्थव्यवस्था पिछड़ी ही रह जाती है। इन दुष्चक्रों को तोड़ें बिना अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में आर्थिक पिछड़ापन, निर्धनता व बेकारी दूर करना कठिन कार्य है।

(14) अन्य आर्थिक विशेषताएँ (Other Economic Characteristics)—अर्द्ध विकसित राष्ट्रों में उपर्युक्त आर्थिक विशेषताओं के अनिरीकृत उद्यमी प्रवृत्ति (Entrepreneurial Spirit) का भी नितान्त अभाव पाया जाता है क्योंकि बाजारों की सीमितता, पूँजी एवं प्रौद्योगिक ज्ञान का अभाव तथा आवश्यक उत्प्रेरणाओं की अनुपस्थिति में सात्त्विक जोखिम उठाने से बचते हैं। सरकार भी आगे नहीं आती। अर्थ-व्यवस्था में जीवन-निर्वाह के लिये लघु एवं कुटीर उद्योगों का अधिक सहारा लिया जाता है। अर्थ-व्यवस्था का एक बड़ा भाग अमौद्रिक क्षेत्र होता है जिसमें वस्तु-विनिमय एवं जीवन-निर्वाह की आर्थिक गति-विधियाँ ही चलती हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण का अभाव रहता है।

### (B) जनसंख्या सम्बन्धी विशेषताएँ (Demographic Characteristics)

अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में आर्थिक विशेषताओं के समान जनसंख्या सम्बन्धी विशेषताएँ भी बड़ी रोचक हैं—

(1) जनाधिक्य की समस्या (Problem of Over-population)—अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में जनाधिक्य की समस्या बड़ी जटिल है। जहाँ अमेरिका, रूस व जापान की जनसंख्या क्रमशः 20 करोड़, 24 करोड़ तथा 10 करोड़ है वहाँ अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में भारत की अकेले की जनसंख्या उन 68 करोड़ अर्थात् उपर्युक्त तीनों देशों की सम्मिश्रित जनसंख्या से भी अधिक है। चीन की जनसंख्या भी लगभग 80 करोड़ है। विश्व की दो तिहाई जनसंख्या अर्द्ध-विकसित देशों में बसती है और उन्हें विश्व की कुल आय का केवल 15% भाग प्राप्त होता है। जबकि विकसित राष्ट्रों में विश्व की केवल 18% जनसंख्या निवास करती है पर उन्हें विश्व आय का लगभग 67% भाग मिलता है। अमेरिका में विश्व-जनसंख्या का केवल 6% भाग है पर वह विश्व उत्पादन का लगभग 35% भाग उत्पादित करती है।

(2) उच्च जन्म एवं मृत्यु दर व विस्फोटक वृद्धि (High Birth and Death Rate and Rapid Growth)—अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में जनाधिक्य होने के साथ-साथ जन्म दरें एवं मृत्यु दरें भी विकसित राष्ट्रों के मुकाबले काफी ऊँची हैं। इनमें जन्म एवं मृत्यु दरें क्रमशः 35 से 50 प्रति हजार तथा 30 से 45 प्रति हजार हैं। जनसंख्या में विकास की दर भी 2% से 3% है जबकि विकसित राष्ट्रों में जन्म दरें 10 से 25 प्रति हजार तथा मृत्यु दरें भी 9 से 20 प्रति हजार हैं और उनमें जनसंख्या वृद्धि की दर 0.5% से 2% है। भारत में जन्म दर 33 प्रति हजार तथा मृत्यु दर 15 प्रति हजार होने के कारण जनसंख्या में 2.5% की दर से विस्फोटक वृद्धि हुई है।

(3) कम औसत आयु (Low Expectation of Life)—अर्द्ध विकसित राष्ट्रों में आर्थिक दरिद्रता, अज्ञानता तथा स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में औसत आयु विकसित राष्ट्रों की तुलना में बहुत कम है। जहाँ विकसित राष्ट्र अमेरिका, रूस, ब्रिटेन व स्वीडन में औसत आयु क्रमशः 70 वर्ष, 72 वर्ष है वहाँ अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में औसत आयु 32 से 50 वर्ष के मध्य है। भारत में औसत आयु 1951 में 32 थी जबकि 1971 में बढ़कर 52 वर्ष होने का अनुमान है फिर भी विकसित देशों की तुलना में अब भी नीचे है।

(4) अन्य (Miscellaneous)—(i) अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात लगभग 40 से 50% होता है क्योंकि वहाँ की जनसंख्या में बालको (15 वर्ष की आयु से कम) की संख्या कुल जनसंख्या के 40% के बराबर होती है जबकि इंग्लैंड व अमेरिका आदि में यह अनुपात 20 से 25% ही है।  
(ii) अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में ग्रामीण जनसंख्या की प्रधानता होती है जहाँ विकसित

देशों में लगभग 80% जनसंख्या गहरा में और 20% जनसंख्या गाँवों में रहती है, वन्य जन्तु निपटारा अर्द्ध विकसित देशों का 80% जनसंख्या गाँवों में तथा लगभग 20% ही गहरा में रहती है। (iii) इसी प्रकार अर्द्ध विकसित देशों में 70% से 90% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है जबकि उद्योगों व व्यवसायों में यह अनुपात 10 से 30% है जबकि विकसित देशों में इसके विपरीत स्थिति होती है।

### (C) सामाजिक एवं राजनैतिक विशेषताएँ

#### (Social and Political Characteristics)

अर्द्ध विकसित देशों की समस्याओं में सामाजिक जटिलता एवं धार्मिक दृष्टिकोणों का कारण जनता अंध विश्वासों, भाव्यवादी एवं अज्ञानता से ग्रस्त होती है। अज्ञानता एवं अंधविश्वास का कारण लोगों का दृष्टिकोण संकुचित तथा उन्नत भविष्य के लिए उदात्त मान हो जाता है। सामाजिक कुर्याज, मृग्य भोज, विवाह उत्सवों व पाएण्डा कार्यों पर भारी व्यय किया जाता है। भारत इनका अनुपम उदाहरण है।

अर्द्ध विकसित देशों में जनता में राजनैतिक चेतना का अभाव होता है अतः व राजनैतिक अधिकारों व दायित्वों का प्रति जागरूक नहीं होते। राजनैतिक अस्थिरता पाई जाती है। योग्य व क्षम्य पराजय एवं साहसी राजनेताओं के अभाव में राजनैतिक भ्रष्टाचार का शासन बाला होता है। कुशल योग्य एवं ईमानदार प्रशासन के अभाव में विकास कार्यों का नियोजन सफल होना कठिन रहता है।

### अर्द्ध विकसित देशों के पिछड़ेपन के कारण

#### (Causes of Backwardness of Under Developed Countries)

अथवा

### अर्द्ध विकसित देशों के विकास में बाधाएँ, समस्याएँ या कठिनाइयाँ

#### (Obstacles Problems or Difficulties in Development of Under Developed Countries)

विश्व के प्रायः सभी अर्द्ध विकसित देशों में विकास की दो तिहाई जनसंख्या आर्थिक दृष्टिकोण से गरीब में फँसकर बसा हुआ है यद्यपि निम्नता की स्थिति में मुक्त श्रम श्रमिकों की भूख नगी जनता की विविधतापूर्ण गुणों, जीवन स्तर, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए समस्त प्रयत्नशील है परन्तु उनका पिछड़ेपन व कारण हैं व हाँ उनका आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएँ या समस्याएँ हैं। यद्यपि प्रत्येक अर्द्ध विकसित देशों का राजनैतिक, सामाजिक, भौगोलिक एवं आर्थिक संरचना में भिन्नता के कारण उनका समस्याओं व विकास की समस्याओं में अंतर हो सकता है फिर भी सद्भावना दृष्टि में ये समस्याएँ लगभग एक ही होती हैं। उन अध्ययनों की दृष्टि से अर्द्ध विकसित देशों के पिछड़ेपन के कारणों तथा उत्तरी समस्याओं का वर्गीकरण, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक आधारों पर जय प्रकार है—



## अर्द्ध-विकसित देशों के पिछड़ेपन के कारण व विकास में बाधाएँ

↓			
↓	↓	↓	↓
(A) आर्थिक बाधाएँ	(B) सामाजिक बाधाएँ	(C) राजनैतिक बाधाएँ	(D) सांस्कृतिक बाधाएँ
(1) बाजार की अपूर्णताएँ	(1) जनसंख्या की समस्या का	(1) राजनैतिक पराधीनता	(1) धार्मिक अन्धविश्वास
(2) निर्धनता के दुष्प्रभाव	(2) सामाजिक संगठन	(2) राजनैतिक स्थिरता अभाव	(2) आध्यात्मिक दृष्टिकोण
(3) पूँजी विनि-योग का अभाव	(3) सामाजिक बन्धन एवं रुढ़िवादिता	(3) कुशल प्रशासन का अभाव	
(4) प्रौद्योगिक व तकनीकी ज्ञान का अभाव	(4) जन सहयोग एवं जागृति का अभाव	( ) योग्य नेतृत्व का अभाव	
(5) अन्तर्राष्ट्रीय शोषण			
(6) विदेशी विनिमय संकट			
(7) बेकारी व अर्द्ध-बेकारी			
(8) उत्कृष्ट उपभोग			

### (A) आर्थिक बाधाएँ (Economic Obstacles)

(1) बाजार की अपूर्णताएँ (Market Imperfections)—अर्द्ध विकसित देशों के पिछड़ेपन का कारण तथा आर्थिक विकास की बाधा उनके बाजार की अपूर्णताओं में निहित है। उनमें उत्पादन साधनों की गतिशीलता का अभाव, मूल्यों में लोचता की कमी, बाजार दबावों की असमानता, विस्तृत अमौद्रिक क्षेत्र की प्रधानता और विशिष्टीकरण के अभाव के कारण उत्पादन साधनों का सर्वोत्तम वितरण एवं समन्वय न होने से प्राकृतिक साधनों का पूरा-पूरा प्रयोग नहीं हो पाता और वास्तविक उत्पादन सम्भावित उत्पादन के मुकाबले बहुत ही निम्न स्तर पर रहता है। सहयोगी उत्पादन साधनों के अभाव में अत्यधिक धन शक्ति का सदुपयोग नहीं हो पाता जिससे कई उद्योगों में धन की सीमान्त उत्पादन शून्य होती है। अतः विकास मार्ग अवरुद्ध हो जाता है।

(4) औद्योगिक एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव (Lack of Technology & Technical Know how)—अर्द्ध-विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिये बड़े पैमाने के आधारभूत उद्योगों की स्थापना करने तथा उत्पादन की नवीन पद्धतियों के प्रयोग व खोज के लिये शोध, अनुसंधान करना पड़ता है और ये सब कार्य करने के लिये तकनीकी विशेषज्ञों व प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इनका विद्युद्देशे राष्ट्रों में नितान्त अभाव है अतः अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास में इनका अभाव बाधा उपस्थित करता है।

(5) अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों द्वारा शोषण (Exploitation by International Forces)—विकसित राष्ट्र अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों को अपनी निर्मित वस्तुओं का बाजार तथा कच्चे माल के उत्पादक बना कर उनका शोषण करने पर उतारू हैं। व अपने विनियोगों से भी निर्धन देशों पर आर्थिक प्रभुत्व जमाकर उनका शोषण करने का प्रयास करते हैं। विदेशी व्यापार में भी व्यापारिक शर्तें प्रतिकूल ही होती हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का शोषण इसका परिचायक है। अभी भी विकसित राष्ट्रों में मगठित होकर अर्द्ध विकसित राष्ट्रों पर हावी होने की प्रवृत्ति प्रबल है अतः यह प्रवृत्ति उनका आर्थिक विकास में बाधा बनती है।

(6) विदेशी विनिमय संकट (Foreign Exchange Problems)—अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों को अपने विकास की प्राग्भिय अवस्था में मशीना औद्योगिक कच्चा माल, तकनीकी एवं औद्योगिक ज्ञान तथा पूँजी आदि के लिये, विदेशों पर बहुत अधिक आश्रित रहना पड़ता है जिससे आयात निर्यातों की अपेक्षा बढ़ जाते हैं और विदेशी भुगतानों में असन्तुलन विदेशी विनिमय संकट को जन्म देता है जैसा भारत में 1957 से ही विनिमय संकट न्यूनाधिक रूप से आर्थिक विकास में बाधा बना है। 1966 में हमें बाध्य होकर रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा।

(7) बेकारी एवं अर्द्ध-बेकारी (Unemployment and under employment)—अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में एक बड़ी समस्या यह है कि एक ओर विशाल मानव शक्ति होती है तो दूसरी ओर अक्षोपित प्राकृतिक साधनों का बाहुल्य। पर औद्योगिक एवं तकनीकी ज्ञान के अभाव तथा पूँजी व माह्रम की कमी के कारण रोजगार के अवसर सीमित होते हैं अतः बड़ी मात्रा में बेकारी और अर्द्ध-बेकारी की समस्या सामने रहती है। परिणामस्वरूप उन्हें आर्थिक विकास में ध्रुम-प्रधान योजनाओं को महत्व देना पड़ता है जिससे विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है।

(8) उत्कृष्ट उपभोग की समस्या (Problem of Conspicuous Consumption)—अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में वैसे भी असह्य निर्धनों की आय नीची होने के कारण बचत नहीं होती और जो कुछ धनी लोग होते हैं तथा जिनमें बचाने की बुद्धि क्षमता है वे भी अपनी आय को प्रदर्शनात्मक प्रभाव के कारण पाश्चात्य लोगों के जीवन-स्तर को प्राप्त करने की इच्छा से उत्कृष्ट उपभोग पर व्यय कर देते हैं इससे

दोहरे दुःप्रभाव पड़ना है न तो पूँजी निर्माण के लिए बचते होती हैं और विदेशी उपभोग वस्तुओं के आयात करने से विदेशी विनिमय सरट सामने आता है। यही नहीं बल्कि अपनी आर्थिक बहिष्करण गहनों, विनाशिताओं व आसीशान भवनों के निर्माण में जगजग कर देते हैं। अतः विनियोग एवं पूँजी निर्माण नहीं हो पाता जो आर्थिक विकास का आधार स्तम्भ है।

### (B) सामाजिक बाधाएँ (Social Obstacles)

अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के आर्थिक पिछड़ेपन व आर्थिक विकास में बाधाएँ केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक बाधाएँ भी होती हैं। इन देशों में (1) जन-अधिकार का समस्या (Population Problem) प्रमुख है, यह न केवल मात्रात्मक समस्या है बल्कि गुणात्मक भी है। इन देशों में विद्यालय जनसंख्या होती है पर उनका प्रयोग नहीं होता अतः उनका भरण-पोषण व रोजगार की समस्या रहती है। उनका जीवन-स्तर नीचा व पर्याप्त चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जनसंख्या कमजोर बीमार व दौढ़िक दृष्टि से निम्न स्तर की होती है। जैसे भारत में जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि की वजह से आर्थिक विकास की उपलब्धियों को ही नहीं बल्कि जानी बूझी भाव-भाव में खाद्यान्न अभाव, वकरी, आवश्यक वस्तुओं का अभाव जैसे मूल्यों तथा अज्ञानता को भी जन्म देता है। (2) दोषपूर्ण सामाजिक संगठन (Defective Social Organisation) भी आर्थिक विकास में बाधा है क्योंकि जाति प्रथा, मनुक परिचार-प्रणाली, पदों प्रथा, उत्तराधिकार नियम आदि व कठोर परिधानन में माहम का अभाव, बच्चों का हतोत्साहन व श्रम की अनिर्णीयता में कमी, आर्थिक विकास में अटकते उत्पन्न करती हैं। (3) सामाजिक बंधन एवं रूढ़िवादों के कारण लोग अपने खून पसीने की कमाई को मृत्यु-भोगों, विवाहान्तरों व रूढ़ियों का पूरा करने में व्यर्थ व्यर्थ कर देते हैं जिससे न तो पूँजी निर्माण हो पाता है और न व रूढ़िवादी प्रवृत्तियों व चणुल में ही निराल पाते हैं। (4) जन, भरण-भोग एवं जन-जागृति का अभाव अर्द्ध-विकसित देशों में शिक्षा एवं अज्ञानता के कारण न तो जनता में आर्थिक चेतना होती है और न वे आर्थिक विकास कायप्रथा में रुचि ही लेते हैं परिणामस्वरूप जन सहयोग जो कि आर्थिक विकास की मजबूत एवं गतिदायक शक्ति होती है, नितान्त अभाव होता है अतः आर्थिक विकास के लिये आवश्यक पृष्ठभूमि नहीं बन पाती।

### (C) राजनैतिक बाधाएँ (Political Obstacles)

अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में राजनीतिक बाधाएँ भी महत्वपूर्ण हैं। बहुत से अर्द्ध-विकसित राष्ट्र विकसित राष्ट्रों के पराधीन रहते हैं उनके स्थानीय शासकों ने विदेशी साम्राज्यों के साथ मिलकर अर्थ व्यवस्थाओं के शोषण की कोई कसर नहीं छोड़ी। विदेशी शासकों ने अपने आर्थिक हितों के लिये इन पिछड़े राष्ट्रों के आर्थिक हितों की रक्षा नहीं की और उन्हें ऐसा अलग बना दिया कि वे अपने आर्थिक विकास की बात भी न सोच सकें। इन देशों ने राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद

प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालियों का सहारा लिया है पर अज्ञानता व शिक्षा के अभाव में स्वार्थी, भ्रष्ट एवं अयोग्य राजनेताओं द्वारा आर्थिक विकास की आड़ में अपना उल्लू सीधा करने की प्रवृत्ति प्रबल है। योग्य नेतृत्व का अभाव रहता है।

राजनैतिक अस्थिरता, घरेलू अशान्ति एवं बाह्य आक्रमणों के कारण भी अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में आर्थिक विकास बाधित गति से नहीं हो पाता। जैसे भारत के राज्यों में राजनैतिक अस्थिरता, उपल-पुथल, हड़तालों, आगजनी, लूट-पाट, तोड़-फोड़ तथा चीनी एवं पाकिस्तानी आक्रमणों से आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई है।

योग्य, कुशलत तथा ईमानदार प्रशासन आर्थिक विकास की आधारभूत आवश्यकता मानी जाती है पर अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में इसका भी नितान्त अभाव है। प्रो० लेविस ने लिखा है कि “आर्थिक नियोजन के लिये सर्वप्रथम एक सक्षम, योग्य व ईमानदार प्रशासन चाहिये जो उपायों को इच्छापूर्वक लागू कर सके।”

#### (D) सांस्कृतिक बाधाएँ (Cultural Obstacles)

अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में धार्मिक अन्ध-विश्वास व रूढ़ियों के कारण व्यक्ति भाग्यवादी व अकर्मण्य हो जाते हैं। भौतिक उत्थान के बदले जब वे आध्यात्मिकता को महत्व देने लग जाते हैं तो आर्थिक विकास की सम्भावनाएँ घूमिल हो जाती हैं। अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में “सादा जीवन एवं उच्च विचार” (Simple Living & High Thinking) की धारणा के कारण वे जो कुछ मिलता है उसी में ही संतुष्ट हैं। अतः उनमें भौतिकवादी प्रवृत्ति उत्पन्न करने में समय लगता है। अब प्रायः सभी अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में शिक्षा के प्रसार व पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण भौतिकवादी दृष्टिकोण तेजी से बढ़ रहा है और धार्मिक अन्ध विश्वास व रूढ़ियाँ घरासायी हो रही हैं। पर भौतिक दृष्टिकोण में परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत धीमी ही है।

अतः निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि अर्द्ध-विकसित देशों में अनेक प्रकार की बाधाएँ आर्थिक विकास के मार्ग को अवरोध करती हैं इस सन्दर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ समिति का यह कथन ठीक है “उपयुक्त वातावरण के अभाव में आर्थिक विकास असम्भव है। आर्थिक विकास के लिये आवश्यक है कि लोगों में विकास की इच्छा हो और उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं वैधानिक संस्थाएँ इस इच्छा को कार्यान्वित करने व मूर्त रूप देने में सहायक हों।”

अर्द्ध-विकसित देशों में आर्थिक-विकास के सामान्य उपाय व आवश्यकताएँ  
(General Measures, Requisites or Requirements for Economic Development of Underdeveloped Countries)

यद्यपि अर्द्ध विकसित देशों के आर्थिक-विकास में अनेक अड़चने हैं फिर भी विश्व शान्ति एवं मानवीय कारणों से उनके आर्थिक विकास की उपेक्षा करना उपयुक्त

नहीं इन देशों में निर्धनता के कुचक्र में फँसी असरण जनसंख्या अब अधिक द्रुतगति से बढ़ रही है। इन देशों में निर्धनता के कुचक्र में फँसी असरण जनसंख्या अब अधिक द्रुतगति से बढ़ रही है। इन देशों में निर्धनता के कुचक्र में फँसी असरण जनसंख्या अब अधिक द्रुतगति से बढ़ रही है।

(1) स्वदेशी शक्तियों का सुदृढ़ आधार तैयार करना (Strong Base of Indegenous Forces)—अर्द्ध विकसित राष्ट्रों को अपने आर्थिक विकास के कार्यक्रमों में स्वदेशी शक्तियों के लिए स्वदेशी शक्तियों का एक सुदृढ़ आधार तैयार करना चाहिये क्योंकि बाह्य शक्तियाँ तो स्वदेशी शक्तियों के लिए पूरक एवं प्रेरक के रूप में काम कर सकती हैं वे विभाग प्रतिष्ठा के लिये प्रतिस्थापन (Substitute) नहीं बन सकती। विदेशी सहायता पर आश्रित विकास राजनितिक सम्बन्धों के साथ-साथ डबाडोल होता है और मजदूरी के समय गम्भीर स्थिति उत्पन्न कर देता है। अल्पकाल में विदेशी शक्तियों का सहारा उपयोगी हो सकता है अन्तिम रूप में तो स्वदेशी शक्तियों पर ही निर्भर होना चाहिये। इस मन्दन में मेयर और बाल्डविन का कथन 'यदि विकास की प्रक्रिया सही और दीर्घकालीन है तो विकास की शक्तियाँ देश के अन्तर्गत ही होती हैं वे उपयुक्त रहती हैं।'

(2) बाजार अपूर्णताओं का समापन (Removal of Market Imperfections)—अर्द्ध विकसित देशों में आर्थिक विकास की दूसरी आवश्यकता बाजार अपूर्णताओं को दूर करना है जो कि उनके विकास में महत्वपूर्ण बाधा है। इसके लिये सामाजिक एवं आर्थिक संरचनाओं में क्रान्तिकारी परिवर्तनों से उन्ने प्रक्रियाओं के अनुसार बनाना होगा। शिक्षा व तकनीकी ज्ञान की अभिवृद्धि से साधनों की गतिशीलता उत्पादकता तथा उत्पादक पद्धतियों में आधुनिकीकरण करना पड़ेगा। प्राकृतिक साधनों के विशेष-ज्ञान के लिये अर्थात् सीमांत क्षेत्रों का सहारा देना होगा। पूँजी व साधन का विस्तार, एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण बाजार का विस्तार अर्थ-व्यवस्था का संतुलित विकास करने के लिये उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने की आवश्यकता है। प्रो० मेयर व बाल्डविन के अनुसार 'देश की राष्ट्रीय आय में तीव्र गति से वृद्धि के लिये नवीन आवश्यकताओं नवीन विचारधाराओं उत्पादन के नये तरीकों तथा नवीन संस्थाओं के निर्माण की आवश्यकता होती है।'

(3) पूँजी-निर्माण व विनियोग दर में वृद्धि (Increase in Rate of Capital Formation & Investment)—अर्द्ध विकसित राष्ट्रों में आय के नीचे स्तर एवं कम बचतों के कारण पूँजी निर्माण की दर नीची है जबकि इन देशों में विकास में भारी मात्रा में विनियोगों के लिये पूँजी निर्माण दर में वृद्धि करना आवश्यक है। प्रो० रॉस्टो (W Rostow) के अनुसार किसी देश को आर्थिक विकास की स्वयं-संपूर्ण अवस्था (Self generating Stage) में पहुँचाने के लिये बचत व विनियोग दर की राष्ट्रीय आय के 10 से 15% बढ़ाना आवश्यक होता है। विकास की प्रारम्भिक अवस्था में आन्तरिक पूँजी निर्माण की गति धीमी होने पर विदेशी बचतों व सहायता का प्रयोग विनियोगों में किया जाना चाहिये।

अर्द्ध विकसित देशों में पूँजी निर्माण की गति तेज करने के लिये अल्प-वचनों को प्रोत्साहन, सघटित साधनों की उत्पादक उपयोगिता में बढावा, वचनों की गतिशील बनाने के लिये सात सुविधाओं व वित्तीय संस्थाओं का विस्तार तथा वचनों की उत्पादक कार्यों में प्रयोग की आवश्यकता होती है। सरकार भी प्रगतिशील करारोपण, सार्वजनिक ऋणों तथा हीनाथ प्रवन्ध से पूँजी निर्माण व उत्पादक विनियोगों की दर बढ़ा सकती है। पूँजी निर्माण की दर बढ़ाने के लिये विदेशी प्रत्यक्ष विनियोगों, ऋणों तथा अनुदान का सहारा भी ले लिया जा सकता है इसमें दोहरा लाभ मिलता है। एक ओर विदेशी विनियोग सफट हल करने में सहायता मिलती है तो दूसरी ओर विदेशी साहसी जोखिम उठाकर प्रौद्योगिक स्तर में वृद्धि करते हैं। नर्कसे के अनुसार "अर्द्ध विकसित देश अपनी छिपी बेकारी का प्रयोग पूँजी निर्माण में कर सकते हैं।"

(4) पूँजी सोखने की क्षमता में वृद्धि (Increase in Capital Absorption Capacity)—अर्द्ध-विकसित देशों में बाजार अपूर्णताओं, निम्न प्राविधिक स्तर तथा कुशल प्रशासन के अभाव में पूँजी होने पर भी उसके उपयोग की समस्या आती है। इसलिये प्रशासनिक कुशलता में सुधार, तन्त्रोंकी एवं प्रौद्योगिक ज्ञान में वृद्धि तथा बाजार अपूर्णताओं के समापन द्वारा, अर्थ व्यवस्था की पूँजी सोखने की शक्ति में वृद्धि करना चाहिये ताकि मुद्रा-स्फीति और भ्रुपतान असन्तुलन की समस्याएँ उत्पन्न न हों।

(5) आर्थिक नियोजन द्वारा विकास (Development through Economic Planning)—अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों को अपने आर्थिक विकास के लिये आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाना अधिक हितकर है क्योंकि आर्थिक नियोजन हमारे युग की आर्थिक समस्याओं के निराकरण की एक अच्छी रामबाण औपधि माना जाता है। अर्द्ध-विकसित दस पादशास्य देशों के समान आर्थिक विकास के लिये स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली की लम्बी अवधि की जोखिम नहीं उठा सकते अतः उनके लिये अपने तीव्र आर्थिक विकास के लिये आर्थिक नियोजन की प्रणाली अपनाना ही ध्येष्ट है।

(6) उपयुक्त विनियोग मापदण्ड (Suitable Investment Criterion)—अर्द्ध विकसित देशों में साधन सीमित है जबकि आवश्यकताएँ अनेक हैं। अतः तीव्र आर्थिक विकास के लिये उचित प्राथमिकताओं के आधार पर विनियोग का आवंटन विभिन्न क्षेत्रों व उपयोगों में विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिये। इसके लिए (i) साधनों का विनियोग इस प्रकार किया जाय कि प्रत्येक उपयोग में सीमान्त उत्पादकता समान हो तथा सामाजिक सीमान्त उत्पादकता अधिकतम हो। (ii) ऐसी परियोजनाओं में विनियोग को प्राथमिकता देना चाहिये जिसमें पूँजी उत्पाद-अनुपात (Capital Output Ratio) कम हो अर्थात् कम से कम पूँजी से अधिक उत्पादन किया जा सके। (iii) आर्थिक विकास के लिए सुदृढ आधार के लिए सामाजिक ऊपरी-व्यय पूँजी (Social Overhead Capital) जैसे सड़कों रेलों, संचार साधनों, विद्युत व सिंचाई परियोजनाओं, शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार पर

विनियोग को प्रोत्साहन देना चाहिये। (iv) विनियोग ऐसे किया जाय कि अधिकतम रोजगार सम्भव हो सके तथा श्रमिकों की कार्य-क्षमता में अधिकतम वृद्धि सम्भव हो सके।

(7) असन्तुलित विकास पद्धति का अनुकरण (Adoption of Un-Balanced Growth Technique)—अर्द्ध विकसित राष्ट्रों को अपने निर्धनता के कुचक्रों को तोड़ने तथा आर्थिक विकास की गति तेज करने के लिए विकास की प्रारम्भिक अवस्था में असन्तुलित विकास पद्धति को अपनाना चाहिये ताकि आधारभूत उद्योगों के विकास से वर्तमान में त्याग करके भावी विकास का सुदृढ़ आधार तैयार हो सके। एड्रिट नेहरू के अनुसार 'सन्तुलित विकास पद्धति जिसमें सभी उद्योगों व क्षेत्रों का एक साथ विकास करने का प्रयास होता है आधुनिक युग में पूर्णतः अलोकप्रिय सिद्धान्त (A Completely Discredited Theory) है।

(8) प्रौद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा का विकास (Development of Technology and Technical Education)—विकास प्रक्रिया के हर क्षेत्र में तकनीकी एवं प्रौद्योगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। अब देश में तकनीकी एवं प्राविधिक शिक्षा का विकास एवं विस्तार अर्द्ध विकसित राष्ट्रों में विकास की आधार-भूत आवश्यकता है। यही नहीं देश में अनुसंधान एवं शोध कार्यों को प्रोत्साहन देना चाहिये ताकि देश में उपलब्ध साधनों व विदेशी पूँजी का विकास में समुचित उपयोग हो सके।

(9) सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ (Social Cultural & Psychological Requirements)—विकास प्रक्रिया पर सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक विचारों व मनोवैज्ञानिक धारणाओं का भी काफी प्रभाव पड़ता है अतः (i) सामाजिक संरचना को विकास के अनुकूल बनाने के लिए सयुक्त परिवार प्रथा, जातिवाद उत्तराधिकार नियमों, पर्दा-प्रथा आदि में आवश्यक परिवर्तन किया जाना चाहिए (ii) जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि पर नियन्त्रण करना चाहिए अन्यथा जनसंख्या की बाढ़ विराम उपलब्धियों को वहाँ से जाती है और प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं होती (iii) धार्मिक व सामाजिक रुढ़ियों को समाप्त कर प्रगतिशील दृष्टिकोण विकसित करना चाहिये इसके लिये शिक्षा का प्रसार व अज्ञानता का समापन जरूरी होता है, (iv) लोगों में भौतिकवादी दृष्टिकोण से समृद्धि व उच्च जीवन स्तर की खानसा उत्पन्न करनी चाहिये। (v) धनिकों के उष्कृष्ट उपभोग (Conspicuous Consumption) जैसे पादचर्य विलासिता पूर्ण जीवन का अनुसरण बहुभूत्य गृहनों, प्रदर्शनात्मक अपभ्रंश, जालसाज कोटियों व भवनों के निर्माण पर नियन्त्रण लगाना चाहिये (vi) आर्थिक विकास के प्रति रुचि एवं प्रेरणा उत्पन्न करने की भी आवश्यकता है।

(10) मजबूत एवं स्थिर राष्ट्रीय सरकार (Strong & Stable National Government)—अर्द्ध-विकसित राष्ट्र सार्वजनिक पारधीनता में आदिम विनाश

करने में असमर्थ रहते हैं क्योंकि विदेशी सरकार अपने हितों के लिए परतन्त्र देश के विकास की बलि देना व उनका शोषण करने में भी नहीं हिचकिचाती। अतः ऐसे देशों में लोकप्रिय राष्ट्रीय सरकारों की स्थापना विकास के लिए आवश्यक है। देश की सरकार बाह्य आन्दोलनों व आन्तरिक शान्ति एवं सुशासन बनाए रखने में काफी सुदृढ़ व सशक्त होनी चाहिये। सुदृढ़ता के साथ साथ सरकार की स्थिरता भी उतनी ही आवश्यक है। राजनैतिक स्थिरता व शांतिपूर्ण विकास की कल्पना निरर्थक है। आज विश्व के प्रायः सभी अर्द्ध-विकसित राष्ट्र अपनी विदेशी दासता की बड़ियों से मुक्त होकर अपनी राष्ट्रीय सरकारों के अन्तर्गत विकास की ओर अग्रसर हैं।

(11) प्रशासनिक आवश्यकता (Administrative Requirement)—अर्द्ध-विकसित देशों में आर्थिक विकास कायम करने के लिए एक सशक्त, कुशल, योग्य एवं ईमानदार प्रशासन होना एक अविहार्य आवश्यकता है क्योंकि इसके अभाव में आर्थिक विकास की अच्छी से अच्छी योजनाएँ भी विफल हो सकती हैं। यह प्रशासन अपने निष्पक्षों को लागू करने में पूर्णतः समर्थ होना चाहिये।

(12) आर्थिक विकास में जन सहयोग एवं रविव (Public Co-operation & Enthusiasm)—प्रगति के प्रति उदासीन जनता का आर्थिक विकास करना कठिन कार्य है जबकि अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में जनता भाग्यवादी, अकर्मण्य तथा विकास के प्रति उदासीन रहती है। अतः अर्द्ध-विकसित देशों में आर्थिक विकास के लिए जनता में उत्प्रेरण, रविव एवं सहयोग की भावना जागृत करनी चाहिये। इसके लिए लोगों को विकास योजनाओं के निर्माण व कार्यान्वयन के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में सम्मिलित करना चाहिये क्योंकि जन सहयोग आर्थिक विकास का पेट्रोल तथा नियोजन व्यवस्था का चिकना तेल है। यह वह शक्ति है जो सब बातों को सम्भव बनाती है।

(13) विदेशी सहायता एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (Foreign Aid and International Co-operation)—अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों का तीव्र आर्थिक विकास करने में प्रारम्भिक अवस्था में बहुत अधिक विदेशी सहायता और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की आधारभूत आवश्यकता है क्योंकि अर्द्ध-विकसित देशों में निधनता के कुछ तोड़ने के लिए विदेशी पूँजी औद्योगिक एवं तकनीकी ज्ञान आधुनिक मशीनों व यन्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। यह न केवल पिछड़े राष्ट्रों के विकास के लिए जरूरी है बल्कि स्थायी विश्व शान्ति एवं आत्म-निर्भरता के लिए भी जरूरी है। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर न होकर मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिये, शोषण पर आधारित न होकर सहयोग से प्रेरित होना चाहिये। राजनैतिक और आर्थिक बन्धन से मुक्त अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I M F) विश्व बैंक (World Bank), अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (I F C) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (I D A), एशियन विकास बैंक, भारत सहायता ऋण आदि के माध्यम से वित्तीय सहायता से बन्धनों व शोषण के भय का निराकरण होता है।



(14) विविध (Miscellaneous)—इसके अतिरिक्त अर्द्ध-विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिये देश में निजी साहसियों को प्रोत्साहन देना चाहिये तथा सरकार का स्वयं एक साहसी के रूप में आधारभूत उद्योगों की स्थापना करनी चाहिये और विकास के लिये आधारभूत अन्तर-संरचना (Basic Infrastructure) तैयार करना चाहिये, कर्त्तव्यनिष्ठा एवं राष्ट्रीयता की भावना की प्रेरणा राजनैतिक जागृति आदि भी विकास में योगदान करते हैं। विकास की प्रारम्भिक अवस्था में मूल्य वृद्धि पर प्रभावी नियन्त्रण के लिए आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिये और मूल्य नीति ऐसी हो जो उत्पादकों को प्रेरणा दे तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुएँ उपलब्ध हो।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के विकास में अनेक बाधाओं के बावजूद उनके विकास की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। आज विश्व के प्रायः सभी अर्द्ध-विकसित राष्ट्र अपनी राजनैतिक पराधीनता से मुक्त होकर आर्थिक नियोजन के द्वारा अपने आर्थिक विकास के लिए सतत् प्रयत्नशील हैं। विकसित राष्ट्र व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता, पूँजी औद्योगिक ज्ञान व भौतिक व राजकीय नीतियों में मार्गदर्शन कर स्थायी विश्व शान्ति एवं विश्व समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, भारत में विछले 20-25 वर्षों में विकास इसका परिचायक है। □

## आर्थिक विकास, निर्धारक तत्व एवं आधारभूत आवश्यकताएँ (ECONOMIC DEVELOPMENTS, ITS DETERMINANTS & BASIC REQUISITES)

आज विश्व के विकसित एवं अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में आर्थिक विकास की होड़ लगी है। मानवीय कारणों से नहीं बरन् अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की दृष्टि से अर्द्ध विकसित राष्ट्रों में व्याप्त निर्धनता व आर्थिक असमानता को समाप्त करने के लिये भी आर्थिक विकास आवश्यक है। विश्व की तीन चौथाई जनसंख्या घोर निर्धनता व भय का जीवनयापन करे यह मानव सभ्यता पर सबसे बड़ा कलह तो है ही पर साथ ही विश्व के किसी भी भाग में निर्धनता अन्यत्र आर्थिक समृद्धि का महान् खतरा है। एक ओर अमेरिका, इंग्लैण्ड, जापान, रूस तथा अन्य पाश्चात्य विकसित राष्ट्र आर्थिक समृद्धि में मदहोश हैं दूसरी ओर अफ्रीका व लेटिन अमेरिका के पिछड़े देश, भारत, लका, पाकिस्तान व एशिया के अन्य देश निर्धनता के कुचक्र में नारकीय जीवन बिता रहे हैं। विश्व के विकसित राष्ट्रों की कुल संख्या 18% जनसंख्या विश्व आय का 67% भाग प्राप्त करती है। जबकि अर्द्ध विकसित राष्ट्रों में विश्व जनसंख्या का लगभग 67% विश्व आय का केवल 15% भाग प्राप्त करता है। 1970 में जहाँ अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय 4760 डालर, कनाडा में 3700 डालर, पश्चिमी जर्मनी में 3000 डालर, ब्रिटेन में 2 70 डालर, जापान में 1920 डालर, तथा रूस में 1790 डालर थी वहाँ भारत में प्रति व्यक्ति आय 110 डालर, लका में 150 डालर चीन में 160 डालर को न्यूनतम सीमा विकसित राष्ट्रों व अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों की आर्थिक विषमता की गहरी खाई का संकेत देती है। "आर्थिक विकास व विषमता की इस गहरी खाई को पाटना विश्व आय को सभी विकसित एवं अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में पुनर्वितरण से सम्भव नहीं बरन् अल्प विकसित राष्ट्रों के तीव्र विकास में ही निहित है। अतः अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों को अपने तीव्र आर्थिक विकास का दृढ़ संकल्प करके उसे मूर्त रूप देना है जबकि विकसित राष्ट्रों को इन निधन राष्ट्रों के आर्थिक विकास में तन, मन और धन से हर सम्भव सहयोग देना है ताकि समूचे विश्व की समृद्धि से स्थायी विश्व शान्ति एवं सहयोग की कल्पना को साकार किया जा सके।" इन सबको समझने के लिये आर्थिक विकास का अर्थ, उसके निर्धारक तत्वों एवं विकास की आधारभूत आवश्यकताओं का अध्ययन आवश्यक है।

## आर्थिक विकास का अर्थ एवं परिभाषायें

### (Meaning & Definitions of Economic Development)

सामान्यतः आर्थिक विकास का अभिप्राय आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन की उस प्रक्रिया से लगाया जाता है जिसके द्वारा उत्पादन शक्ति, राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में स्थायी वृद्धि होती है। आर्थिक संरचना व देशवासियों के दृष्टिकोण में परिवर्तनों से जनता के जीवन स्तर में सुधार, वितरण व्यवस्था में न्याय व मानव के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होता है और अन्ततः आर्थिक समृद्धि एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास के अर्थ के सम्बन्ध में विद्वानों के मतों में एकरूपता नहीं है। कुछ अर्थशास्त्री प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को ही आर्थिक विकास कहते हैं जबकि कुछ इसे एक प्रक्रिया मानते हैं जिसके द्वारा किसी अर्थ-व्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। इन दोनों दृष्टिकोणों में वितरण की अवहेलना की है अतः कुछ लोग आर्थिक विकास को व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं। यह निम्न परिभाषाओं से स्पष्ट होता है—

### (A) आर्थिक विकास का अर्थ “वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि है”

प्रो० मेयर एच बाल्डविन के अनुसार, “आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है।”<sup>1</sup> इस परिभाषा में आर्थिक विकास की तीन विशेषतायें मानी हैं पहली, आर्थिक विकास परिवर्तनों की एक प्रक्रिया है। जिसमें अनेक आर्थिक चल राशियों (Variables) में परिवर्तनों का दौर चलता है और इनमें परिवर्तन विकास के कारण और परिणाम होते हैं। दूसरी, आर्थिक विकास का सम्बन्ध वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है। वास्तविक राष्ट्रीय आय का आशय आधार वर्ष की तुलना में मूल्य-स्तर में हुये परिवर्तनों के समायोजन के बाद शुरू राष्ट्रीय उत्पाद से है, तीसरी, अर्थ-व्यवस्था की वास्तविक ‘राष्ट्रीय आय में वृद्धि दीर्घकालीन होती है। अल्पकाल में राष्ट्रीय आय में अस्थायी वृद्धि को आर्थिक विकास नहीं कहा जाता क्योंकि आर्थिक विकास का सम्बन्ध वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन स्थायी वृद्धि से होता है जो प्रायः 10 से 20 वर्ष होती है।

यह परिभाषा एक पक्षीय एवं अपूर्ण है क्योंकि इस परिभाषा में न तो देश के ‘आकार व जनसंख्या की मात्रा’ पर ध्यान दिया गया है और न वितरण पक्ष पर ध्यान दिया है जबकि आर्थिक विकास का सम्बन्ध केवल अधिक उत्पादन से ही नहीं चरन अधिक उत्पादन के न्यायोचित वितरण से भी सम्बन्धित होता है।

<sup>1</sup> Economic Development is a process whereby an economy's real national income increases over a long period of time "

(B) आर्थिक विकास का अर्थ “प्रति व्यक्ति आय या उत्पादन में वृद्धि है”

इस मत के अनुयायी अर्थशास्त्री आर्थिक विकास को कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। यह दृष्टिकोण जनसंख्या के आधार को भी ध्यान में रखकर चलता है जो अधिक व्यवहारिक है। प्रो० डब्ल्यू० ए० लेविस (W A Lewis) के अनुसार “आर्थिक विकास का अभिप्राय प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि से है।” इसी प्रकार प्रो० बेरन के शब्दों में ‘आर्थिक विकास या वृद्धि को निश्चित समय में प्रति व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिये।”

प्रो० विलियमसन एवं बटरिक (Williamson & Buttrick) के अनुसार “आर्थिक विकास या वृद्धि का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी देश या क्षेत्र के लोग उपलब्ध साधनों का उपयोग प्रति व्यक्ति वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में स्थिर वृद्धि के लिये करते हैं।” इन सब परिभाषाओं में भी न्यायोचित वितरण की उपेक्षा की गई है।

(C) आर्थिक विकास का अर्थ “मानव के अधिकतम आर्थिक कल्याण व सर्वांगीण विकास है”

आधुनिक अर्थशास्त्री उपर्युक्त दोनों दृष्टिकोणों को सर्वांगीण बताते हैं और एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार “आर्थिक विकास का आशय केवल राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय के न्यायोचित वितरण, अर्थव्यवस्था की संरचना व देशवासियों की मान्यता व दृष्टिकोणों के अनुकूल परिवर्तनों की प्रक्रिया है ताकि जनता के जीवन स्तर में सुधार, अधिकतम सामाजिक कल्याण व मानव के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त हो। इस व्यापक दृष्टिकोण से प्रेरित संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिवेदन की परिभाषा उल्लेखनीय है ‘विकास मानव की भौतिक आवश्यकताओं से ही नहीं अपितु उसके जीवन की सामाजिक दशाओं के सुधार से भी सम्बन्धित है। अतः विकास न केवल आर्थिक वृद्धि ही है किन्तु आर्थिक वृद्धि और सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत तथा आर्थिक परिवर्तनों का योग है।”

यद्यपि व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित यह परिभाषा सैद्धान्तिक दृष्टि से बहुत उपयुक्त लगती है पर उपर्युक्त सामाजिक, सांस्कृतिक एवं संस्थागत परिवर्तनों का मापना कठिन है अतः विकास दर की व्याख्या में मूल्य निर्णय (Value Judgment) सम्भव नहीं हो पाता यही कारण है कि अधिकांश अर्थशास्त्री आर्थिक विकास को राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से व्यक्त करते हैं।

आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति और वृद्धि (उन्नति) में अन्तर

(Difference Between Economic Development,  
Economic Progress & Economic Growth)

यद्यपि सामान्यतः आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति एवं आर्थिक वृद्धि परस्पर एक-दूसरे के पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं पर कुछ विद्वानों ने इनमें भेद करने का

प्रयास किया है। श्रीमति उर्सला हिक्स (Mrs Ursula Hicks) के अनुसार आर्थिक वृद्धि या आर्थिक उन्नति (Economic Growth) शब्द का प्रयोग उन देशों के लिये किया जाता है जो आर्थिक दृष्टि से उन्नत हैं और अधिकांश साधन श्रुत एवं विकसित हैं जबकि आर्थिक विकास (Economic Development) शब्द का प्रयोग उन पिछड़े देशों के लिये किया जाता है जहाँ अधिवास प्रावृत्ति एवं मानवीय साधन अक्षोपित एवं अर्द्ध-विकसित हैं तथा जिनमें साधनों के उपयोग व विकास की काफी सम्भावनाएँ हैं।

प्रो० बोने (Bonne) के मतानुसार आर्थिक उन्नति (Economic Growth) की प्रगति स्वतः (Spontaneous) होती है जो प्रायः विकसित राष्ट्रों में सत्य उतरती है जबकि आर्थिक विकास (Economic Development) अर्थव्यवस्था में साधनों के विस्तार में निर्देशन नियमन व पथ-प्रदर्शन को मुख्य आधार मानता है जो अधिवास अर्द्ध-विकसित देशों में सम्बन्ध में सत्य है।

प्रो० शुम्पेटर (Schumpeter) के अनुसार "आर्थिक वृद्धि या उन्नति (Economic Growth) का अभिप्राय अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में होने वाले नमिष्ठ एवं स्थिर परिवर्तनों से है जो जनसंख्या व वचन दशों में परिवर्तन से उत्पन्न होता है जबकि आर्थिक विकास (Economic Development) का आशय स्थिर अर्थव्यवस्थाओं में असतत (रक-रक कर) एवं स्वाभाविक परिवर्तनों से है जिसमें नवीन उत्पादन पद्धतियों, नवीन उत्पादन साधनों के प्रयोग से नवीन वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन होता है।"

प्रो० बरेरी के अनुसार 'आर्थिक वृद्धि या उन्नति का आशय जनसंख्या व कुल वास्तविक आय (Total Real Income) दोनों में वृद्धि से है जब आर्थिक प्रगति (Economic Progress) का अभिप्राय प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) में वृद्धि से है।'

आधुनिक सभ्यताओं में "आर्थिक विकास (Economic Development) शब्द का प्रयोग अर्थव्यवस्था में मानव के सर्वाङ्गीण विकास के सम्बन्ध में किया जाता है जिसमें केवल मानव की आर्थिक उन्नति ही नहीं बल्कि मानव की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक सभी क्षेत्रों में प्रगति का समावेश होता है जबकि आर्थिक उन्नति (Economic Growth) शब्द का प्रयोग केवल मानव की आर्थिक उन्नति के सम्बन्ध में ही किया जाता है।

उपरोक्त सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण में विशेष महत्व नहीं है क्योंकि इन शब्दों का पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है।"

### आर्थिक विकास का माप-दण्ड

#### (Measurements of Economic Development)

जहाँ प्राचीन अर्थशास्त्रियों में वाणिज्यवादी सोना-चाँदी के रूप में वृद्धि को आर्थिक विकास का माप-दण्ड मानते थे वहीं एडम स्मिथ उत्पादन वृद्धि को आर्थिक

विकास मानना था। कार्ल मार्क्स ने सहकारिता की वृद्धि को विकास की सजा दी है जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री आर्थिक विकास को मापने में निम्न घटकों को आधार माप-दण्ड मानते हैं—

(1) राष्ट्रीय आय में वृद्धि (Increase in National Income)—बहुत से विद्वान राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि को आर्थिक विकास का माप-दण्ड मानते हैं पर केवल यही आधार अपूर्ण एवं भ्रमात्मक हो सकता है क्योंकि यदि जनसंख्या में वृद्धि की दर विकास दर से अधिक हो या राष्ट्रीय आय की गणना में आधार मूल्यों व वर्तमान प्रचलित मूल्यों में अन्तर हो तो सही-सही निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। जैसे जनसंख्या में 5% वृद्धि हो जबकि राष्ट्रीय आय में केवल 3% वृद्धि हो तो यह आर्थिक विकास न होकर आर्थिक विमन्दन का परिचायक है। इसलिये राष्ट्रीय आय में वृद्धि को जनसंख्या के परिप्रोक्ष्य में देखना तथा मूल्यों में परिवर्तनों के अनुरूप समायोजन से वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि (Increase in Real National Income) तथा राष्ट्रीय आय के न्यायोचित वितरण के आधार पर देखना अधिक उपयुक्त है। स्वयं यंगमैन ने इस मापदण्ड की पूर्णता का उल्लेख करते हुए लिखा है “मूल्य परिवर्तन के प्रभाव को सुधार लेने पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि को निरपक्ष रूप से आर्थिक प्रगति का सूचक मानना असम्भव है।” अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में तो कुछ वास्तविक राष्ट्रीय आय को मापने में कई कठिनाइयाँ होती हैं अतः उनसे इसे आर्थिक विकास का माप दण्ड मानना उपयुक्त नहीं कहा जा सकता।

(2) प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि (Increase in Per Capita Income)—कुछ विद्वान कुल वास्तविक आय की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को आर्थिक विकास का उचित मापदण्ड मानते हैं क्योंकि यह राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के सन्दर्भ में देखती है। पिछड़े राष्ट्रों में जहाँ जनसंख्या में तीव्रगति में वृद्धि होती है और वहाँ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से ही उन्हें निर्धनता से मुक्ति मिल सकती है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक विकास का सूचक है जबकि प्रति व्यक्ति आय में कमी आर्थिक पतन का संकेत है। पर यह आधार भी अपूर्ण, एक पक्षीय एवं भ्रमात्मक है क्योंकि—(i) यह केवल आर्थिक पहलू पर ध्यान देती है। (ii) इसमें आय की न्यायोचित वितरण व्यवस्था पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। (iii) राष्ट्रीय आय के आकड़े विश्वव्यापी न होने पर प्रति व्यक्ति आय की गणना भी त्रुटिपूर्ण होगी। (iv) अधिक विकास के अविभाज्य भाग मानव की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक प्रगति की इस गणना में उपेक्षा की जाती है।

(3) वास्तविक विकास दर का सामान्य दर से अधिक होना (Actual Growth Rate V/s General Growth Rate)—जब किसी देश में वास्तविक दर विश्व की सामान्य दरों से अधिक होती है तो उसमें आर्थिक विकास की गति अधिक मानी जाती है जबकि वास्तविक विकास दर से कम होती है तो अर्थ-व्यवस्था

को अर्द्ध-विकसित एवं स्थिर मानते हैं। यह माप-दण्ड भी अनुपयुक्त है क्योंकि सामान्य समय, स्थान एवं परिस्थितियों के अनुसार स्वयं परिवर्तनशील है अतः इसे आर्थिक विकास का सही माप दण्ड नहीं कहा जा सकता।

(4) राष्ट्रीय आय की वितरण व्यवस्था में सुधार (Reforms in distribution of National Income)—इसके अन्तर्गत विद्वानों की यह मान्यता है कि प्रति व्यक्ति आय तथा कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि को ही आर्थिक विकास का माप-दण्ड मानना उपयुक्त नहीं क्योंकि इसमें वितरण पक्ष पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यदि बड़े हुई कुल वास्तविक आय का एक बड़ा भाग केवल कतिपय धनवानों के हाथों में केन्द्रित हो जाये तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के बावजूद भी देश में दरिद्रता व्याप्त रहेगी जैसा भारत में पिछले 23-24 वर्षों में हुआ है। दरिद्र और अधिक दरिद्र हुये हैं जबकि कतिपय अमीरों की समृद्धि में अपार वृद्धि हुई है अतः अगर राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि के साथ-साथ उसके न्यायोचित वितरण में सबको पर्याप्त आय प्राप्त हो सके तो इसे आर्थिक विकास का सूचक कहा जा सकता है।

(5) मानव कल्याण में वृद्धि (Increase in Human Welfare)—यद्यपि आर्थिक विकास को मापने के लिये मानव कल्याण में वृद्धि का दृष्टिकोण अपनाया सैद्धान्तिक दृष्टि से उपयुक्त है क्योंकि आर्थिक विकास का लक्ष्य अन्ततः मानव कल्याण में वृद्धि करना ही है। मानव कल्याण के माप के लिये समाज में प्रति व्यक्ति उपभोग तथा जीवन स्तर की वृद्धि को आधार बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त जन्म के समय जीवन आशा अधिक ऊँची होना भी आर्थिक विकास का परिचायक है। पर यह माप-दण्ड अवैज्ञानिक एवं अस्पष्ट है न तो जीवन स्तरों और न प्रति व्यक्ति उपभोग की ठीक-ठीक ज्ञात करना सम्भव है और न जीवन आशा को आधार मानना ही विश्वसनीय है।

(6) व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन (Changes in Occupational Structure)—जब कृषि प्रधान देश औद्योगीकरण की ओर अग्रसर होता है तो यह आर्थिक विकास का परिचायक है। अर्द्ध विकसित राष्ट्र जिनमें प्राथमिक उद्योगों (Primary Industries) जिनके अन्तर्गत कृषि पशुपालन, मत्स्यपालन, खनिज, खनन, वनों से आय आदि को प्रधानता होती है। देश की 50 से 90% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अत्यक्ष रूप से इन उद्योगों से अपना जीविकोपार्जन करती है—मगर व्यावसायिक दृष्टि में अनुबून परिवर्तन के कारण उद्योगों, निर्माण कार्यों परित्यक्त, संचार एवं लोकोपयोगी सेवाओं के उद्योगों का बोलबाला होता है और जनसंख्या का वितरण इसके पक्ष में बढ़ता है तो यह आर्थिक विकास का मापदण्ड माना जाता है।

(6) विविध—उपयुक्त मापदण्डों के अतिरिक्त सखीण दृष्टिकोण पर आधारित आर्थिक विकास के मापदण्ड हैं—(1) औद्योगीकरण, (2) सावर्जनिक क्षेत्र

का विस्तार, (3) पूँजी निर्माण दर में वृद्धि, (4) आधारभूत एवं मूलभूत उद्योगों का विकास, (5) लोहे का प्रति व्यक्ति उपभोग, (6) शक्ति तथा ऊर्जा शक्ति का प्रति व्यक्ति उपभोग आदि-आदि। काल भावसं तथा एंजिल्स ने उत्पादन तथानीक में क्रान्तिकारी प्रगति को ही आर्थिक विकास की सज्ञा दी है।

### आर्थिक विकास की अवस्थाएँ

#### (Stages of Economic Development)

प्रायः किसी देश का आर्थिक विकास ऐतिहासिक क्रम में अलग-अलग अवस्थाओं से गुजर कर ही उच्चस्तरीय उपभोग अवस्था में पहुँचता है। जहाँ जर्मन अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट (F. List) ने अर्थव्यवस्था में व्यवसायों की प्रधानता के क्रम के आधार पर आर्थिक विकास की पाँच अवस्थाएँ—(i) आखेट अवस्था (ii) पशु पालन अवस्था (iii) कृषि अवस्था (iv) औद्योगिक अवस्था तथा (v) सामान्य अवस्था बताई है वहाँ प्रो० कोलिन क्लार्क ने आर्थिक विकास की तीन क्रमिक अवस्थाएँ बताई हैं। पहली प्राथमिक अवस्था (Primary Stage) जिसमें लोग पिछड़ी अवस्था में होते हैं और उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनिज खोदना, व वनों से जीविकोपार्जन करना होता है। जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग उन पर आश्रित होता है। दूसरी द्वितीयक अवस्था (Secondary Stage) होती है जिसमें निर्माणकारी उद्योगों खनिज प्रयोग उद्योगों आदि का पर्याप्त विकास हो जाता है। अर्थ व्यवस्था में पर्याप्त औद्योगीकरण के कारण कृषि व प्राथमिक उद्योगों में नियोजित जनसंख्या कम होती है तथा देश की अधिकांश जनसंख्या उद्योगों से जीविकोपार्जन करती है। तीसरी तृतीयक अवस्था (Tertiary Stage) यह आर्थिक विकास की वह अन्तिम अवस्था है जबकि देश का पर्याप्त विकास हो जाने से सेवा क्षेत्रों में परिवहन, संचार, बैंकिंग एवं लोकोपयोगी सेवाएँ उपलब्ध होती हैं। प्रो० रस्टोव (W. W. Rostow) ने अपने विवेक अध्ययन के आधार पर आर्थिक विकास की पाँच प्रमुख अवस्थाओं का उल्लेख किया है जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

#### (1) परम्परागत समाज की अवस्था (Stage of Traditional Society)—

यह आर्थिक विकास की वह प्रारम्भिक अवस्था है जिसमें रूढ़िवादी समाज सीमित प्राथमिक उद्योगों—कृषि, पशुपालन, मछली पालन और वनों आदि में परम्परागत उत्पादन पद्धतियों से कार्य करते हैं। आविष्कारों व नवीन विधियों के प्रयासों व पहल का अभाव होता है। उत्पादकता का नीचा स्तर होने से आय उपभोग व वचतो का स्तर भी बहुत नीचा होता है। अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक उद्योगों से ही जीविकोपार्जन करती है। उद्योग, व्यापार तथा सेवाओं का नितांत अभाव होता है। यद्यपि कुछ विकास के अतिरिक्त सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था दुर्बल और अविकसित अवस्था में होती है और लोग बहुत दरिद्र एवं उनका जीवनस्तर बहुत नीचा होता है। ऐसे समाज में भू-स्वामी राजनैतिक व आर्थिक सत्ता हथिया लेते हैं।



(2) स्वय-स्फूर्त या छूटांग लेने की पूर्व दशाओं की अवस्था (Stage of Pre-conditions of Take-off)—यह आर्थिक विकासक्रम की दूसरी ऐसी सक्रमण अवस्था है जिसमें स्वय स्फूर्त अवस्था के लिए आवश्यक दशाओं व आधार परिस्थितियों का निर्माण होता है। प्रो. रोस्टोव के अनुसार इस अवस्था में “गमाज के दृष्टिकोण में आगरभूत व प्रयोगिक विज्ञान के प्राद, उत्पादन-कला में परिवर्तन के प्रति, जोखिम उठाने, काय के तरीकों व दशाओं के प्रति क्रान्तिकारी परिवर्तन आवश्यक है।” इस अवस्था में कृषि में क्रान्ति से भावी औद्योगिक विकास का सुदृढ आधार तैयार होता है, विनियोग की दर 5% से बढ़कर 10% हो जाती है। सामाजिक ऊर्गों पूँजी के अन्वर्गण परिवर्द्धन, संचार, विद्युत, तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण तथा चिन्तितता मुविधाओं का विस्तार होना है। यह वह अवस्था है जिसमें सन्- सन्- ऋडिवादी एवं भाग्यवादी समाज में प्रगतिसौल दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव होता है और समाज स्वय स्फूर्त अवस्था के मार्ग पर अग्रसर होना है।

(3) स्वय स्फूर्त या छूटांग स्तर की अवस्था (Take off Stage)—प्रो. रोस्टोव के अनुसार यह आर्थिक विकास की एक ऐसी महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें विनाश स्वगनिमान एवं आत्म प्ररित होता है बिना बाह्य सहायता के भी अन्तरिक साधनों के प्रयोग से विनाश सामान्य एवं नियमित रूप से होने लगता है। प्रो. रोस्टोव के शब्दों में ‘यह एक ऐसा सक्रमणकाल है जिसमें विनियोग की दर इस प्रकार बढ़ती है कि प्रति व्यक्ति वास्तविक उत्पादन बढ़ जाता है और यह प्रारम्भिक वृद्धि उत्पादन-शला की क्रान्तिकारी विधियों को जन्म देती है, आय बढ़ती है और आय में वृद्धि से विनियोग के तय आगार की गुरआत होती है। परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति उत्पादन की वृद्धि की भी नवीन प्रवृत्तियों का सूत्रपात होता है।’ इस अवस्था में तीन सन्- पूरी होती है। (i) विनियोग की दर राष्ट्रीय आय की 10% या इससे अधिक होती है (ii) निर्माणकारी उद्योगों की विविधता तथा उच्च उत्पादकता का विकास होता है तथा (iii) अर्थ-व्यवस्था में एक ऐसा सम्थानत ढांचे का निर्माण होता है कि आन्तरिक साधनों से ही पूँजी निर्माण की उच्च क्षमता उत्पन्न हो जाये है।

ब्रिटेन में यह अवस्था 1783-1802 में प्राप्त की थी, अमेरिका में 1843-1860, जापान में 1878-1900, रूस में 1890-1914 में भारत व चीन में 1952 में प्राप्ता की गयी।

(4) परिपक्वता की दशा में कदम (Stage of Drive to Maturity)—स्वय-स्फूर्त अवस्था के बाद परिपक्वता की अवस्था आती है “जब अर्थ-व्यवस्था के विकास, विदाहन एवं सरक्षण के लिये आधुनिकतम तकनीकी एवं औद्योगिक-जानकारी का उच्च पैमाने पर प्रयोग होता है।” अर्थ-व्यवस्था में विनियोग की दर बढ़कर राष्ट्रीय आय का 20% या इससे अधिक हो जाता है। उद्योगों में विविधता आती है, उद्योग-निर्माण, साहाय्यक, रसायन, जहाज, विद्युत-यंत्र तथा अन्य आधारभूत

उद्योगों की प्रधानता के साथ-साथ उपभोग उद्योगों का विस्तृत आधार होता है। परिपक्वता की अवस्था में प्रायः तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं (i) जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग तकनीकी एवं कुशल श्रम के रूप में उद्योगों से आय अर्जित करता है। कृषि पर जनसंख्या का भार कम हो जाता है। (ii) देश प्रायः आत्म-निर्भर हो जाता है तथा (iii) अर्थव्यवस्था में आय, विनियोग, व बचत तथा उपभोग का स्तर ऊँचा हो जाने से आर्थिक सम्पन्नता व सुखदता का मार्ग प्रशस्त होता है।

(5) उच्चस्तरीय उपभोग की अवस्था (The Stage of High Mass Consumption)—यह आर्थिक विकास की उच्चतम अवस्था है जिसमें देश की उत्पादक गतिविधियाँ अपनी चरम सीमा पर होती हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति सामान्य उपभोग की वस्तुओं के अतिरिक्त उच्चतम एवं विशिष्ट वस्तुओं व सेवाओं के उपभोग का प्रयोजन करता है। विलासिता की वस्तुयें सामान्य आवश्यक वस्तुओं के रूप में उपभोग की जाने लगती हैं जैसे कारें, टेलीविजन, कपड़े धोने की मशीनें, रेफ्रिजरेटर, एयरकंडीशनर आदि महंगी वस्तुओं की माग धनी व्यक्तियों तक ही सीमित न होकर सामान्य जनता की माग में परिणत हो जाती है। औद्योगिक विकास इस स्तर पर पहुँच जाता है कि सुधार व नवीनता की गुंजाइश न रहते हुए भी अनुसंधान एवं परीक्षणों का क्रम चलता रहता है। प्रो० रोस्टोव के मतानुसार अमेरिका 1920 में, ब्रिटेन 1930 में तथा रूस, जापान व पश्चिमी यूरोप के देश 1950 के बाद इस अवस्था में पहुँच गये हैं।

**भारत आर्थिक विकास की किस अवस्था में ?**

प्रो० रोस्टोव द्वारा वर्णित आर्थिक विकास की पाँच अवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में देखने से पता लगता है कि विश्व के समृद्ध राष्ट्र अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस व जापान आर्थिक विकास की उच्चस्तरीय अवस्था में पहुँच चुके हैं जबकि विकासशील राष्ट्रों में कुछ परिपक्वता की अवस्था में पहुँच रहे हैं तो कुछ अभी स्वयं-स्फूर्त अवस्था में ही चल रहे हैं। इस सन्दर्भ में देखने से जहाँ प्रो० रोस्टोव के अनुसार भारत 1952 में ही स्वयं-स्फूर्त अवस्था में पहुँच चुका था वहाँ वास्तविक तथ्य उसे विवादास्पद बना देते हैं।

(1) परम्परागत रूढ़िवादी दृष्टिकोण—भारत में अभी भी जनसंख्या का लगभग 71% भाग अक्षित है, स्त्रियों में तो साक्षरता का प्रतिशत बहुत ही कम लगभग 19% है। तकनीकी ज्ञान का अभाव है, उत्पादन की परम्परागत विधियों की प्रधानता है। लोग साम्यवादी एवं रूढ़िवादी हैं। यह प्रत्यक्ष है प्रमाण की कोई आवश्यकता ही नहीं है।

(2) विनियम की दर कम—प्रो० रोस्टोव के अनुसार स्वयं-स्फूर्त अवस्था में विनियोग की दर राष्ट्रीय आय के 10 प्रतिशत से अधिक होती है। भारत में पञ्चवर्षीय योजना के अन्त तक विनियोग की दर 14% तक पहुँच गई है वर आन्तरिक

बचते राष्ट्रीय आय के करीबन 11-12 प्रतिशत ही हैं। पाचवी पंचवर्षीय योजना में भी लगभग 3 हजार करोड़ रुपये की विदेशी सहायता अनुभव की जा रही है। अतः हमारी अर्थव्यवस्था बिना विदेशी सहायता के अब भी तीव्र गति से आर्थिक विकास की क्षमता प्राप्त नहीं कर पाई है।

(3) कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक भार—स्वयं-स्फूर्त अवस्था में औद्योगिक क्षेत्र में विविधता तथा तीव्र विकास से कुशल एवं तकनीकी श्रमिकों की संख्या बढ़ती है। कृषि पर जनसंख्या का भार कम होता है और जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग उद्योगों से जीविका अर्जन करता है पर भारत में अब भी जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है, उद्योगों व निर्माणकारी उद्योगों में जनसंख्या का केवल 12 से 15 प्रतिशत भाग नियोजित है, अब भी देश की 81 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या है जबकि केवल 18 प्रतिशत जनसंख्या ही नगरों में रहती है।

(4) राजनैतिक अस्थिरता—भारत में योजनावद्ध विकास के 25 वर्षों के सतत प्रयत्नों के बावजूद भी अर्थव्यवस्था आर्थिक संकटों, खाद्यान्न के अभाव, प्राकृतिक प्रकोपों व विदेशी विनिमय के संकटों से ग्रस्त है। अकुशल प्रशासन, व्यापक भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद आदि के कारण न तो आर्थिक स्थिरता है और न राजनैतिक स्थायित्व हो।

(5) औद्योगीकरण की धीमी गति—योजनावद्ध विकास के 25 वर्षों में यद्यपि मूलभूत उद्योगों का सुदृढ़ व व्यापक आधार तैयार किया है। देश में उद्योगों में विविधता आई है पर फिर भी उद्योगों के विकास की दर अपेक्षाकृत धीमी है। जहाँ 1969-74 की चौथी योजना में औद्योगिक विकास की दर 8-10% का लक्ष्य था पर वास्तविक उपलब्धि 4.5% रही है। अनेक उपभोग उद्योगों में पुरातन घिसी-पिटी मशीनों का प्रयोग हो रहा है। आधुनिकतम मशीनों व उच्चतम औद्योगिक ज्ञान का नितान्त अभाव हमारे सामने महान संकट का कारण है।

(6) राष्ट्रीय विकास दर भी बहुत कम रही है—यद्यपि पाचवी योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय आय में 5% वृद्धि का था पर वास्तविक उपलब्धियाँ निराशाजनक रही हैं। 1972-73 में विकास की दर 1% थी जबकि 1977-78 में विकास की औसत दर 3.9% से अधिक नहीं थी। भारत में प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी बहुत नीचा है। जहाँ अमेरिका में 1970 में प्रति व्यक्ति आय 4760 डॉलर थी वहाँ भारत में यह 110 डॉलर थी। अर्थात् दोनों की प्रति व्यक्ति आय में लगभग 42 गुना अन्तर है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह बहना अनिश्चयोत्तिपूर्ण न होगा कि भारत अब तक स्वयं-स्फूर्त अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाया है यह प्रारम्भिक दो अवस्थाओं को पार कर चुका है पर तीसरी अवस्था में गिरने लगा रहा है। इसके लिये श्रम,

निष्ठा, प्रगतिशील दृष्टिकोण व सशक्त कुशल एवं ईमानदार प्रशासन के साथ साथ जन सहयोग एवं उत्प्रेरणाओं पर आर्थिक नियोजन की सफलता व तीव्र आर्थिक विकास को सम्भव बनाना है।

### आर्थिक विकास का महत्व

#### (Importance of Economic Development)

विश्व में निर्धनता के निराकरण व आर्थिक विषमताओं के समापन का एक मात्र विकल्प आर्थिक विकास ही है और इसके द्वारा ही मानव का सर्वांगीण विकास सम्भव होता है। आर्थिक विकास से न केवल मानव की आर्थिक समृद्धि व सम्पन्नता सम्भव होती है वरन् अर्थ-व्यवस्था में सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान, राजनैतिक स्थिरता और जनता के लिये विविधतापूर्ण जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है।

(1) प्राकृतिक साधनों का विदोहन—आर्थिक विकास के कारण देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का तेजी से विदोहन होने लगता है और उनके विदोहन से लोगों की आय, रोजगार तथा उत्पादकता में वृद्धि होती है। कृषि, उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों में भी विकास होता है।

(2) औद्योगीकरण—आर्थिक विकास के कारण देश में आधारभूत उद्योगों के साथ-साथ उपभोग उद्योगों का भी तेजी से विकास होता है। सन्तुलित विकास की दृष्टि से लघु एवं कुटीर उद्योगों को भी विकसित किया जाता है। इस प्रकार तीव्र औद्योगिक विकास के साथ-साथ उद्योगों में विविधता, विशिष्टीकरण, बड़े पैमाने की उत्पत्ति एवं श्रम विभाजन को प्रोत्साहन मिलता है।

(3) राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि—देश के प्राकृतिक साधनों के विदोहन, औद्योगीकरण, रोजगार अवसरों में वृद्धि तथा तीव्र पूँजी-निर्माण से राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है जो अन्ततः आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है।

(4) पूँजी निर्माण एवं विनियोग दर में वृद्धि—आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप बचत व पूँजी-निर्माण में वृद्धि होती है। नये-नये उद्योगों की स्थापना होती है, उत्पादन की नवीन विधियाँ अपनायी जाती हैं। उसके लिये अधिकाधिक विनियोग किया जाता है। लोगों की बढ़ी हुई भाग की पूर्ति के लिये उत्पादन वृद्धि भी अधिक विनियोग से सम्भव होती है।

(5) मानवीय साधनों का सदुपयोग—आर्थिक विकास से रोजगार अवसरों में वृद्धि होती है अतः न केवल बेरोजगारी व अर्द्ध-बेरोजगारी का समापन होता है वरन् नये रोजगार व रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार के चुनाव के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं। एवं के अनुसार कार्य के चुनाव से श्रम की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है तथा मानव शक्ति साधनों का यथासम्भव सदुपयोग होता है।

(6) संतुलित अर्थ-व्यवस्था—आर्थिक विकास देश में कृषि के साथ-साथ उद्योगों का विकास करता है। कृषि से जनसंख्या का भार उद्योगों की ओर स्वा-

नान्तरित होता है। अर्थ व्यवस्था का विकास एकाकी न रहकर विविधतापूर्ण होता है। अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों का सन्तुलित विकास होने से आर्थिक सकटों से मुक्ति मिलती है।

(7) सामाजिक सेवाओं का विस्तार—आर्थिक विकास का कारण अर्थव्यवस्था में शिक्षा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक सेवाओं का तेजी से विकास होता है। मनोरंजन के साधनों में वृद्धि होती है अतः अर्थव्यवस्था में विवेकशील, स्वस्थ जनसंख्या की वृद्धि होती है, उनकी औसत आयु बढ़ती है तथा मृत्यु दर घटती है।

(8) उच्च जीवन स्तर—अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास उत्पादन में विविधता तथा अधिकता वितरण में समानता व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के कारण जनता को उपभोग के लिये अधिकाधिक वस्तुएँ व सेवाएँ उपलब्ध होती हैं और उनका जीवन स्तर निरन्तर ऊँचा होता जाता है।

(9) शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा—आर्थिक विकास से देश की बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा क्षमता बढ़ती है तथा देश में पर्याप्त उत्पादन एवं उसके समुचित वितरण से आन्तरिक शांति बनी रहती है। यही नहीं सभी देशों में आर्थिक विकास के कारण अन्तर्राष्ट्रीय शांति का भी भाग प्रशस्त होता है क्योंकि विश्व के किसी भी भाग में गरीबी अग्र्यत्र समृद्धि को निरन्तर खतरा है।

(10) निर्धनता के कुचक्र को तोड़ना—निर्धनता के कुचक्र को तोड़ना भी आर्थिक विकास द्वारा सम्भव होता है क्योंकि प्राकृतिक साधनों के विदोहन औद्योगीकरण व रोजगार अवसरों में वृद्धि से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। उपभोग व वचन में वृद्धि से विनियोग, उत्पादन व पूँजी-निर्माण में वृद्धि होती है अतः निर्धनता के निराकरण की व्यवस्था उत्पन्न होती है।

(11) सामाजिक सुरक्षा एवं स्वतन्त्रता—आर्थिक विकास से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि व आर्थिक समानता समाज की बेरोजगारी, वृद्धावस्था बीमारी, दुर्घटना व मृत्यु आदि पाँच सनटों से मुक्ति प्रदान करती है। व्यक्तियों को आर्थिक समृद्धि में स्वतन्त्रता का आभास होता है। मशीनों के अधिकाधिक उपयोग से अधिक आराम मिलता है।

### आर्थिक विकास के सम्भावित दोष

आर्थिक विकास यद्यपि समृद्धि व सम्पन्नता का मार्ग प्रशस्त करता है परन्तु यह विकास अनियोजित व अत्यधिक भौतिकतावादी होने पर मानव के सर्वांगीण विकास में बाधा भी बन जाता है। (1) बड़े पैमाने की उत्पत्ति में व्यक्तिगत रुचियों की उपेक्षा की जाती है। (2) कुटीर एवं लघु उद्योगों के पतन पर बड़े उद्योग धनपने हैं। मनुष्य मशीनों का दास बन जाता है। (3) विशिष्टीकरण व श्रम विभाजन से कार्य में नीरसता बढ़ती है। (4) अत्यधिक औद्योगीकरण में उद्योगों के केन्द्रीकरण से गन्दी वास्तव्या का निर्माण। (5) पूँजी व श्रम में वैमनस्य और

(6) शोषण को बढ़ावा मिलता है। (7) धन का असमान वितरण होना है जिससे (8) वर्ग-सघर्ष का प्रादुर्भाव होता है। अत्यधिक आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण से प्रेरित होकर (9) एकाधिकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया जाता है और सर्वत्र भौतिकवादी दृष्टिकोण से [10] अनेक अनर्निव कार्यों को प्रोत्साहन मिलता है। आर्थिक उत्थान में नैतिक पतन की प्रवृत्तिता पनपती है। (11) आध्यात्मिकता की भावना को ठेक पहुँचती है और व्यक्ति नास्तिकता की ओर बढ़ता है।

### आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व, घटक या कारक (Determinants or Factors of Economic Growth)

आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों व सम्बन्ध में भी विद्वानों में मतभेद का अभाव है। जहाँ प्रो० नर्कसे तथा राइट ने आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों में गैर-आर्थिक तत्वों को प्रधानता दी है वहीं प्रो० रोस्टोव तथा स्पेंगलर आदि ने आर्थिक तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है। प्रो० नर्कसे (Nurkse) के अनुसार आर्थिक विकास बहुत कुछ सामाजिक भावनाओं, राजनैतिक दशाओं, मानवीय योग्यताओं व ऐतिहासिक घटनाओं पर निर्भर करता है। इसी प्रकार डेविड एम राइट (D M Wright) के अनुसार आर्थिक विकास के आधार तत्व अभौतिक एवं गैर आर्थिक हैं। इसके विपरीत प्रो० रोस्टोव (Rostow) के शब्दों में "आर्थिक विकास पूँजी व श्रम की मात्रा एवं स्वच्छ पर निर्भर करता है" और इन दो तत्वों पर छ. प्रवृत्तियों (Propensities) का प्रभाव पड़ता है—(i) आधारभूत विज्ञान के विकास की प्रवृत्ति, (ii) विज्ञान के आर्थिक कार्यों में प्रयोग की प्रवृत्ति, (iii) तकनीकी प्रवर्तनों की प्रवृत्ति, (iv) भौतिक उत्पादन की प्रवृत्ति, (v) उपभोग की प्रवृत्ति तथा (vi) सन्तानोत्पत्ति की प्रवृत्ति। इसी प्रकार प्रो० स्पेंगलर (Spengler) ने भी आर्थिक विकास के 19 तत्वों का इल्लेस किया है। विभिन्न विद्वानों के विचार मन्थन के बाद आर्थिक विकास के प्रमुख तत्वों का वर्गीकरण निम्न तालिका में दिया जा सकता है—

### आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व, घटक या कारक (Factors or Determinants)

आर्थिक तत्व					गैर-आर्थिक तत्व		
प्राकृतिक	श्रम	पूँजी	संगठन	साहस	तकनीकी	अन्तर्राष्ट्रीय	सामाजिक
साधन	शक्ति				एव	आर्थिक	वातावरण
					ज्ञान	वातावरण	वातावरण
					नव-प्रवर्तन	सहयोग	धार्मिक
							भावनाएँ

इन तत्वों का मक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

(1) प्राकृतिक साधन (Natural Resources)—प्राकृतिक साधन आर्थिक विकास का आधारभूत कारक हैं। प्रो० लेविंस का अनुमान “प्राकृतिक साधन विकास का माग एवं दिशा निर्धारित करते हैं।” प्राकृतिक साधनों से अभिप्राय उन सब प्राकृतिक मायना में है जो भूमि खनिज, वन, वर्षा, हवा, पानी व जलवायु आदि के रूप में मानव का उत्पादन के लिये प्रकृति की ओर से निशुल्क उपहार हैं। उर्वरा भूमि तथा जल व बिना कृषि विकास असम्भव होगा, वीयसा, सोहा एवं आधार खनिजों का अभाव में औद्योगीकरण की कल्पना साकार करना कठिन होगा तथा उपयुक्त भोगात्मक परिस्थितियों का वातावरण के अभाव से आर्थिक विकास में बाधाएँ होंगी।

विकसित राष्ट्रों—अमेरिका, जापान, इंग्लैंड व रूस आदि के आर्थिक विकास में वहाँ के प्राकृतिक साधनों की प्राचुर्यता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान ओर भावी प्राकृतिक साधनों की बहुलता ही आर्थिक विकास के लिये पर्याप्त नहीं वरन् उनके समुचित विदाहन, नवीन साधनों की खोज तथा उनके नय-नय उपयोगों का पना लगान से ही आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। भारत अपने प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से सम्पन्न होने हुए भी उनके पर्याप्त विदाहन के अभाव में आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ा है अतः प्राकृतिक साधनों के विकास, विदोहन एवं संरक्षण ओर उनके प्रयोगों में विविधता, समुचितता ओर नवीन प्रयोगों की खोज से आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योग रहना है।

(2) मानवीय साधन (Human Resources)—प्राकृतिक साधन उत्पादन का निष्पन्न घटक है अतः उनके उपयोग के लिये मानवीय साधन विकास का आधार, साधन एवं माध्य का रूप में अत्यन्त आवश्यक है। प्रो० रिचार्ड मिल के शब्दों में ‘आर्थिक विकास एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। यह एक मानवीय उपक्रम है और समस्त मानवीय उपक्रमों की भाँति इसकी सफलता अन्तिम रूप में इसके क्रियान्वित करने वाले मनुष्यों की कुशलता, गुणो, शक्ति, एवं प्रवृत्तियों पर निर्भर करेगी।’ मानवीय साधन का अभिप्राय देश की सम्पूर्ण जनसंख्या से है। यद्यपि उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने वाली जनसंख्या जिसे कार्यशील जनसंख्या (Working Population) कहते हैं आर्थिक विकास की मुख्य रूप से प्रभावित करती है परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास जनसंख्या के आकार, कार्य कुशलता, संरचना, व्यावसायिक वितरण तथा उनकी गुणात्मक प्रवृत्ति भी आर्थिक विकास के निर्धारक घटक हैं। मानवीय साधनों की आर्थिक विकास में दोहरी भूमिका होती है एक ओर वह उत्पादन का मन्त्रिय साधन है तो दूसरी ओर समस्त आर्थिक क्रियाओं का माध्य है वह उत्पादन और उपभोक्ता दोनों है। जहाँ एक ओर जनसंख्या में वृद्धि श्रम शक्ति और उत्पादन वस्तुओं का वातावरण की अभिवृद्धि करती है पर आदर्श विन्दु के बाद या

अर्द्ध-विकसित देशों में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का उनके आर्थिक विकास पर प्रतिबल प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ है। अतः संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि विकसित मानवीय साधन एवं श्रम-शक्ति आर्थिक विकास का एक प्रमुख सक्रिय एवं अत्याज्य घटक है। विकसित राष्ट्रों के तीव्र आर्थिक विकास का राज उनको कुशल, योग्य एवं विकसित श्रम शक्ति में छिपा है। अतः प्रो० राब के अनुसार "विकास प्रक्रिया में मानवीय साधनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिये मानव शक्ति के शारीरिक मानसिक, मनोवैज्ञानिक तथा संगठनात्मक विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिये।"

(3) पूँजी (Capital)—आर्थिक विकास का सीसरा महत्वपूर्ण घटक पूँजी है। पूँजी मनुष्य द्वारा उत्पादित धन का वह भाग है जो अधिक धनोत्पत्ति के लिये प्रयुक्त किया जाता है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत समाज एवं व्यक्ति अपने वर्तमान उपयोग को कम करके बचत करते हैं और इन बचतों को अधिक उत्पादन के लिये प्रयुक्त करते हैं तथा इन बचतों को पूँजीगत उत्पादक सम्पत्तियों में बदलते हैं। प्रो० रिचार्ड गिल ने आर्थिक विकास में पूँजी के महत्व को इन शब्दों में व्यक्त किया है 'पूँजी का सचय वर्तमान युग में निर्धन देशों को धनवान बनाने व औद्योगिक युग का प्रारम्भ करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है।' पूँजी के द्वारा ही आधारभूत उद्योगों की स्थापना परिवहन एवं सामाजिक ऊपरी पूँजी का निर्माण होता है जो आर्थिक विकास का आधार स्तम्भ हैं। जहाँ जापान, अमेरिका आदि देशों में बचत एवं पूँजी निर्माण की दर क्रमशः 30% एवं 25% है वहाँ भारत में पूँजी निर्माण की दर 22% ही है जिसमें आन्तरिक बचतों की दर राष्ट्रीय आय का 19.8% ही है तथा 2.5% विदेशी पूँजी का प्रयोग होता है।

अर्द्ध-विकसित देशों में पूँजी निर्माण की धीमी गति के कारण आर्थिक विकास की दर भी बहुत कम है अतः उनमें व्यक्तिगत, सत्यागत एवं राजकीय बचतों में वृद्धि तथा विनियोगों के लिये उपलब्ध पूँजी के समुचित उपयोग, उत्पादक कार्यों में प्रयोग, वित्तीय संस्थाओं के विकास, संग्रह प्रवृत्ति पर रोक आदि का प्रयोग करना चाहिये। प्रो० नर्से के अनुसार, "अर्द्ध-विकसित देशों में अप्रयुक्त मानव शक्ति का प्रयोग करके भी पूँजी निर्माण किया जा सकता है।"

यद्यपि पूँजी आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण घटक है किन्तु यही एक पर्याप्त घटक नहीं। पूँजी के अतिरिक्त आर्थिक विकास के लिये तकनीकी ज्ञान, आर्थिक संसाधन एवं समाज में विकास के प्रति उपयुक्त दृष्टिकोण भी आवश्यक है। अगर देश में उपलब्ध पूँजी के योजनाबद्ध उपयोग की समुचित दशाएँ नहीं हैं तो पर्याप्त पूँजी होने पर भी आर्थिक विकास सम्भव नहीं होगा।

(4) तकनीकी ज्ञान (Technical Know-How) तथा औद्योगिक ज्ञान (Technology)—यह भी आर्थिक विकास का आवश्यक घटक एवं परिणाम है। तकनीकी ज्ञान का अभिप्राय उत्पादन सम्बन्धी ज्ञान में विशिष्टता या वृद्धि से है।



प्रो० एटलिस के अनुसार 'तकनीकी ज्ञान की प्रगति को ऐसे नये ज्ञान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसके कारण या तो वर्तमान वस्तुएँ कम लागत पर उत्पन्न की जा सकें या जिसके कारण नवीन वस्तुओं का उत्पादन हो सके।' दूसरे शब्दों में तकनीकी ज्ञान में वृद्धि से उत्पादन लागत में कमी नवीन वस्तुओं का निर्माण, पदार्थों के नय-नये उपयोग, उत्पादन में वृद्धि तथा उत्पादन के नय नये साधनों का पता लगाया जाता है या उत्पादित वस्तुओं के गुणों में वृद्धि एवं विविधता आती है।

तकनीकी ज्ञान एवं प्राविधिकी की प्रगति आर्थिक विकास को सम्भव बनाने वाला महत्वपूर्ण घटक है। प्रो० लेविस के शब्दों में, 'आर्थिक विकास एक ओर वस्तुओं व जीवधारियों के विषय में प्रौद्योगिक ज्ञान पर निर्भर है और दूसरी ओर यह मनुष्य व उसने साधनों के आपसी सम्बन्धों के सामाजिक ज्ञान पर निर्भर करता है।' विकासशील राष्ट्रों में प्राविधिक ज्ञान की कमी के कारण न तो उनके प्राकृतिक साधनों का समुचित विद्योहन हो पाया है और न उनकी आर्थिक दरिद्रता का कुचक्र टूट पाया है। उत्पादन की नयी तकनीकी विधियों के विकास व परम्परागत विधियों में सुधरे प्रयोगों में ही अर्द्ध-विकसित देशों की कृषि, उद्योग, परिवहन, एवं मानवीय साधनों की प्रगति निहित है।

अतः विकासशील देशों में तकनीकी ज्ञान व प्रौद्योगिक ज्ञान की वृद्धि के लिये (i) आविष्कारों व अनुसंधानों को प्रोत्साहन, (ii) सर्वोच्च शिक्षा एवं प्रयोग प्रिय मस्तिष्क वाले व्यक्तियों के ज्ञान वृद्धि की उत्प्रेरणार्थ, (iii) शिक्षा एवं प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने के साथ-साथ, (iv) नवीन तकनीकी प्रयोगों को मूर्त रूप देने के लिये जनता की अभिरुचियों में वृद्धि करवा आवश्यक है। तकनीकी ज्ञान की उपलब्धि ही आर्थिक विकास के लिये पर्याप्त नहीं, उसके समुचित प्रयोजन व प्रयोग और अन्य सहायक घटकों का होना भी उतना ही आवश्यक है।

(5) संगठन (Organisation)—आधुनिक बड़े पैमाने की उत्पत्ति एवं वृद्धि उत्पादन प्रक्रिया में उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में अनुकूलतम संयोग बैठाना भी आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण घटक है। संगठन के अन्तर्गत उन सब क्रियाओं का समावेश होता है जो उत्पादन साधनों में आदर्श संयोग बैठाने के लिये कम से कम लागत पर अधिकाधिक उत्पादन करने का प्रयास करती है जैसे प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों के समुचित विद्योहन की व्यवस्था करना, उद्योगों का आदर्श आकार, विसिद्दीकरण, श्रम विभाजन, औद्योगिक संयोग आदि-आदि। प्रो० डोब (Dobb) ने आर्थिक संगठन के महत्व का उल्लेख करते हुये लिखा है 'आर्थिक विकास की समस्या मुख्यतः वित्तीय समस्या नहीं बल्कि यह तो आर्थिक संगठन एवं व्यवस्था की समस्या है।' संगठन व्यक्तित्व कुशलता, भौगोलिक परिस्थितियों की अनुकूलता, उत्पादन में यन्त्रीकरण व प्रमाणीकरण द्वारा आर्थिक विकास को शक्तिशाली योग देता है। अर्द्ध-विकसित देशों में कुशल एवं योग्य संगठन के अभाव के कारण आर्थिक विकास की गति धीमी

है अतः उनमें बड़े पैमाने की उत्पत्ति, भूमि व्यवस्था में सुधार, श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण, यन्त्रीकरण एवं उद्योगों के कुशल संगठन की आवश्यकता है।

(6) साहसी एवं नव प्रवर्तन (Entrepreneur & Innovations)—आर्थिक विकास में साहसी एवं नव प्रवर्तन कर्ताओं का भी विशेष स्थान होता है। साहसी वे व्यक्ति होते हैं जो नये आविष्कारों एवं तकनीकी ज्ञान को उत्पादन तथा आर्थिक साधनों के विद्योहन में प्रयुक्त करने का साहस करते हैं जोखिम उठाते हैं तथा नव-प्रवर्तनकर्ता वे साहसी होते हैं जो (i) उत्पादन की नवीन विधियों की खोज करते हैं, (ii) कच्चे माल के नवीन साधनों का प्रयोग, (iii) नये बाजारों की खोज (iv) साधनों के नवीन उपयोग आदि का प्रयोग करते हैं। आर्थिक विकास में साहसी एवं नवीन प्रवर्तनों के महत्व को स्पष्ट करते हुए प्रो० रिचर्ड गिस् ने लिखा है “तकनीकी ज्ञान आर्थिक दृष्टि से प्रभावपूर्ण तभी होता है जबकि इसका नव-प्रवर्तन के रूप में प्रयोग किया जावे।”

अर्द्ध विकसित देशों में साहस एवं नव प्रवर्तनों का अभाव होता है। सरकार स्वयं साहसी के रूप में भूमिका निभाती है जैसा कि भारत में विस्तृत सार्वजनिक क्षेत्र इसका परिचायक है।

(7) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग (International Economic Assistance)—आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय परस्पर निर्भरता के युग में आर्थिक विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग भी बहुत आवश्यक घटक है। अर्द्ध-विकसित राष्ट्र विकसित राष्ट्रों से तकनीकी ज्ञान, आधुनिक उपकरण एवं यन्त्रों औद्योगिक मशीनों तथा वित्तीय साधन प्राप्त करके अपना कृषि एवं औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। जापान में द्वितीय विश्व युद्धोत्तरकाल में तीव्र आर्थिक विकास एवं पुनर्निर्माण का बहुत कुछ श्रेय अमेरिका के आर्थिक सहयोग को जाता है। भारत को भी विदेशों से अत्यधिक सहायता उसके आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता के महत्वपूर्ण घटक रही है। इसके विपरीत अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के अभाव में विकास की गति मन्द हो जाती है।

(8) सामाजिक वातावरण (Social Environment)—विकास की प्रक्रिया केवल आर्थिक तत्वों से ही प्रभावित नहीं होती बल्कि वैयक्तिक तत्वों से भी प्रभावित होती है। अगर समाज रुढ़िवादी है, सामाजिक समस्याएँ विकास के अनुत्पन्न नहीं हैं तो विकास सम्भव नहीं होगा जैसे भारत में जाति प्रथा, सयुक्त परिवार प्रणाली, पर्दा प्रथा आदि आर्थिक विकास में बाधक रहे हैं। अगर समाज में धन प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता हो, लोगों का दृष्टिकोण भौतिकवादी हो और समाज में उच्च जीवन स्तर एवं आर्थिक विकास की तीव्र लालसा हो तो विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे विपरीत अगर समाज में विकास के प्रति रुचि न हो, शिक्षा एवं ज्ञान का अभाव हो सामाजिक अशान्ति हो और शोषण का बोलबाला हो तो आर्थिक विकास होने हुए भी विकास सम्भव नहीं होगा।

(9) सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ (Cultural Attitudes)—अगर समाज में आध्यात्मिक विचारधारा प्रबल हो, आवश्यकताओं की सीमितता के जीवन दर्शन का प्रभुत्व हो और लोगों में भौतिकता के प्रति अरुचि हो तो आर्थिक उतावरण के अनुकूल होत हुए भी आर्थिक विकास की कल्पना करना मिथ्या होगा पर अगर देश में भौतिकता, आर्थिक समृद्धि, उच्च जीवन स्तर आदि की विचारधारा प्रबल हो तो आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। पाश्चात्य राष्ट्रों में भौतिकवादों दृष्टिकोण ने उन्हें आज उच्च उपभोग स्तर पर पहुँचा दिया है जबकि भारत, सक्का, मुस्लिम राष्ट्र आदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण में सिप्य होने के कारण आर्थिक विकास नहीं कर पाये हैं।

(10) नैतिक मूल्य (Ethical Values)—आर्थिक विकास पर प्रभाव डालने वाला गैर-आर्थिक तत्व "नैतिक मूल्य" भी है। अगर समाज में उद्योग, व्यापार, सरकार, प्रशासन, शोध एवं साहस आदि का नेतृत्व योग्य, ईमानदार, राष्ट्र भक्त एवं समाज सभी व्यक्तियों के हाथ में हो तो आर्थिक विकास तीव्र गति से होगा। पर अगर समाज में व्यक्तियों का नैतिक पतन हो चुका हो, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, रिश्तेदारी, चोर-बाजारी एवं बेईमानी का बोलचाल हो तो आर्थिक विकास का मार्ग अवरोध हो जायेगा। आज भारत में नैतिक मूल्यों में अत्यधिक ह्रास हो जाने से आर्थिक विकास वांछित गति से नहीं हो पा रहा है। हर स्तर पर भ्रष्टाचार व अनैतिकता का व्यवहार न्यूनधिक रूप में विद्यमान है। अतः अच्छी योजनाओं की सफलता भी गलत हाथों में मन्दिम है।

(11) राजनैतिक एवं प्रशासनिक वातावरण (Political & Administrative Environment)—आर्थिक विकास के लिये न केवल सशक्त एवं स्थायी सरकार की आवश्यकता होती है बल्कि कुशल, योग्य एवं ईमानदार प्रशासन भी उतना ही आवश्यक है। प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली एक ढीली-ढाली शासन व्यवस्था होती है जिसमें जनता के प्रतिनिधि अपने राजनैतिक स्वार्थों के पीछे कभी कभी देश व आधारभूत आर्थिक हितों को भुला देते हैं जबकि शासन की तानाशाही प्रणाली में नियोजन व आर्थिक विकास अधिक निश्चित एवं प्रभावी होता है। सशक्त सरकार होने पर आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा एवं शान्ति आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होती है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक वातावरण भी आर्थिक विकास को प्रभावित करता है अगर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में युद्ध अशान्ति व शक्यों हो तो दूसरे शान्तिप्रिय राष्ट्रों के विकास पर भी दुःप्रभाव पड़ बिना नहीं रहता। बंगला देश में नर-संहार की पाकिस्तानी नीति भारत के आर्थिक विकास में बाधा पनी। उसके द्वारा छोड़े गये युद्ध से अमेरिका से सम्बन्ध विगड़े भारत के साधनों का प्रयोग युद्ध में हुआ। इनका विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रशासनिक अनुपयुक्तता, भ्रष्टाचार आदि विकास को अवरोध करते रहे हैं।

## आर्थिक विकास के विभिन्न तत्वों का सापेक्षिक महत्व

(Relative Importance of Various Factors of Economic Development)

आर्थिक विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले घटक अनेक हैं। इनमें अकेले एक घटक का कोई विशेष महत्व नहीं क्योंकि ये परस्पर एक दूसरे के पूरक एवं सहयोगी होते हैं। यदि देश में प्राकृतिक साधनों का तो बाहुन्य हो पर उनके विदोहन के लिये पर्याप्त पूँजी, तकनीकी ज्ञान, श्रम शक्ति तथा उनके विदोहन व विकास की इच्छा का अभाव हो तो प्राकृतिक साधन आर्थिक विकास में निरर्थक सिद्ध होंगे। हाँ, एक साधन दूसरे साधन का सहयोग करता है जैसे प्राकृतिक साधनों के प्रयोग के कारण उत्पादन क्षमता, आय, बचत, विनियोग, राजगार व उपभोग में वृद्धि का आधार उत्पन्न होगा। अमेरिका, इंग्लैंड और रूस में वहाँ के प्राकृतिक साधनों का विकास में अत्यधिक योग रहा है। उसके विपरीत जापान और स्विटजरलैंड के आर्थिक विकास में सरकार की नीति एवं मानवीय साधनों का विशेष महत्व रहा है। प्रो० लेबिन्स ने पूँजी को आर्थिक विकास का केन्द्र-बिन्दु माना है जबकि प्रो० नर्कसे के अनुसार "आर्थिक विकास बहुत कुछ सीमा तक मनुष्यों के गुणों, सामाजिक दृष्टिकोणों, राजनैतिक दृष्टांतों एवं ऐतिहासिक अनुभवों पर निर्भर करता है।" इसी प्रकार के विचार प्रो० रिचार्ड गिल ने व्यक्त किए हैं। "आर्थिक विकास एक मशीनी प्रक्रिया नहीं है और न ही वह साधनों के संग्रह की प्रक्रिया मात्र है। अन्ततः यह तो एक मानवीय उपक्रम है और मनुष्य मानवीय उपक्रम की भाँति इसका भी अन्तिम फल इसे संचालित करने वाले मनुष्यों के चातुर्य, गुण एवं दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।" अतः आर्थिक विकास के लिये गैर-आर्थिक तत्वों का भी उतना ही महत्वपूर्ण योग रहता है। इसी कारण तो समुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबद्धन में स्पष्ट है। "उपयुक्त वातावरण का अभाव में आर्थिक प्रगति असम्भव है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि लोगों में विकास की इच्छा हो उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं वैधानिक संस्थाएँ इस इच्छा को कार्यान्वित करने में सहायक हों।"

अतः मतभेदों के समूहों में पड़ते की अपेक्षा यह कहना उचित है कि आर्थिक विकास के प्रायः सभी घटक परस्पर पूरक एवं सहयोगी हैं उनका सापेक्षिक महत्व देश की परिस्थितियों विकास की अवस्था और विचारधाराओं के अनुकूल बदलता रहता है। प्रो० शोर्डन मध्यम भाग अपनाते हुए लिखा है कि 'किसी एक कारण से नहीं अपितु विभिन्न महत्वपूर्ण कारकों से उचित अनुपात के मिलाने से आर्थिक विकास होता है।'

निष्कर्ष में यही कहना युक्तिसंगत होगा कि आर्थिक विकास विभिन्न आर्थिक घटकों तथा गैर-आर्थिक घटकों का सम्मिलित परिणाम होता है। उनके सापेक्षिक महत्व को जोसेफ फिशर ने इस प्रकार व्यक्त किया है 'आर्थिक विकास के लिए किसी एक विशेष तत्व को अलग करना और इसे ऐसे आर्थिक विकास का प्रथम या प्राथमिक कारण बनाना न तो उपयुक्त है और न विशेष सहायक ही। प्राकृतिक

साधन, कुशल, धन, मशीनें एवं उपकरण, वैज्ञानिक एवं प्रबन्धात्मक साधन एवं आर्थिक स्थानीयकरण महत्वपूर्ण हैं। अगर आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना है तो इन कारकों को प्रभावपूर्ण ढंग से मिलना चाहिये।" यही नहीं आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त राजनैतिक सामाजिक एवं नैतिक तत्वों का विद्यमान होना भी उतना ही जरूरी है। प्रो० एलबर्ट ने इस मत की पुष्टि करते हुये लिखा है 'आर्थिक विकास के लिए एक बहुत बड़ी घनात्मक प्रेरणा एक ऐसी सम्मति है जो अपने मूल्यों में भौतिक समृद्धि को उच्च प्राथमिकता देती है।'

**आर्थिक विकास की आधारभूत आवश्यकताएँ, शर्तें अथवा उपाय<sup>1</sup>**  
(Fundamental Requisites, Conditions or Measures for Economic Development)

आर्थिक विकास एक जटिल एवं कठिनाइयों से परिपूर्ण प्रक्रिया है अतः आर्थिक विकास के लिये देश में कुछ आधारभूत आवश्यकताएँ अथवा शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है। इसके अन्तर्गत (1) देशवासियों में आर्थिक विकास की प्रेरणा एवं इच्छा होना जरूरी है (2) देश में विकास के लिए स्वदेशी आधार होना चाहिये। (3) पर्याप्त पूँजी निर्माण व विनियोग व्यवस्था होनी चाहिये। (4) अर्थ व्यवस्था में व्याप्त बाजार अपूर्णताओं व निर्धनता के कुचक्र को तोड़ने की आवश्यकता होती है। विकास के लिए (5) विवेकपूर्ण योजनाएँ तथा (6) उनका सफल कार्यान्वयन (7) सशक्त स्थिर सरकार तथा (8) कुशल प्रशासनिक ढाँचा होना भी जरूरी है अन्यथा सरकार की योजनाओं व आर्थिक नीति की सफलता सन्दिग्ध रहती है (9) विकास के लिये अर्थव्यवस्था में उपयुक्त सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिये। (10) यही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का सद्भावनापूर्ण वातावरण तथा विश्व शान्ति एवं सुरक्षा आर्थिक विकास की आधारभूत आवश्यकता मानी जाती है।

(1) (इस भाग के विस्तृत विवरण के लिए 'अर्द्ध-विकसित' राष्ट्र एवं उनके आधारभूत समस्याएँ" नामक अध्याय के अन्तिम भाग को पढ़िये) ●

## आर्थिक नियोजन की तकनीक एवं विधि

### (TECHNIQUES & METHODOLOGY OF ECONOMIC PLANNING)

आर्थिक नियोजन एक कठिन एवं जटिल प्रक्रिया है अतः आर्थिक योजनाओं के कारण, उनके सफल कार्यान्वयन तथा उचित मूल्यांकन के लिये आवश्यकतानुसार तकनीक एवं विधि का सहारा लेना पड़ता है। नियोजन की प्रारम्भिक शुरुआत, उसके कुशल संचालन एवं अन्तिम मूल्यांकन तथा अनुवर्तन तक की सम्बन्धी प्रक्रिया तथा उसके लिए अपनाई गई व्यवस्था को नियोजन की तकनीक एवं विधि की संज्ञा दी जाती है। नियोजन की तकनीक एवं प्रक्रिया की प्रमुख पांच अवस्थायें क्रमानुसार अग्र तालिका से स्पष्ट हैं—

तालिका से स्पष्ट है कि नियोजन की तकनीक एवं विधि की पांच प्रमुख अवस्थायें हैं—पहली केन्द्रीय नियोजन संगठन व उसके सहायक विभागों का निर्माण, दूसरी इस संगठन द्वारा आर्थिक योजनाओं का निर्माण करना तीसरी योजनाओं की जाच व स्वीकृति, चौथी योजनाओं का कार्यान्वयन व पांचवी योजनाओं का सामयिक मूल्यांकन व अनुवर्तन ताकि योजना के निर्धारित लक्ष्यों व उद्देश्यों की पूर्ति सम्भव हो सके। इन अवस्थाओं का क्रमबद्ध संपिन्त विवरण इस प्रकार है—

#### (A) नियोजन के लिये केन्द्रीय संगठन का निर्माण व सहायक विभाग (Creation of a Central Organisation & Allied Sections for Planning)

आर्थिक नियोजन की एक जटिल एवं निरन्तर प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुये यह आवश्यक है कि देश के सभी प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों का सर्वेक्षण करने, वर्तमान एवं भावी उपलब्धता का अनुमान लगाने, योजनायें बनाने, उन्हें कार्यान्वित करने तथा उनके अनुकूल आर्थिक नीतियाँ निर्धारित करने के साथ-साथ उनका सही-सही मूल्यांकन करने के लिये एक स्थाई केन्द्रीय नियोजन संगठन हो। इस संगठन का वैधानिक अस्तित्व हो ताकि वह 'राजनैतिक पार्टी' हिसो से ऊपर देश के सामूहिक आर्थिक हितों के लिये स्वतन्त्रतापूर्वक नियोजन कर सके। इस संगठन को अर्ध-व्यवस्था के सभी अंगों का व्यापक नियोजन करना पड़ता है। अतः प्रत्येक क्षेत्र के अलग-अलग सहायक विभाग हो और उनमें सम्बन्धित तकनीकी, वित्तीय तथा

## आर्थिक नियोजन की तकनीक एवं विधि की अवस्थाएँ

(A) नियोजन के लिये केन्द्रीय संगठन का निर्माण व सहायक विभाग	(B) योजना का निर्माण अथवा योजना निर्माण प्रक्रिया	(C) योजनाओं को जाँच व स्वीकृति	(D) योजनाओं का कार्यान्वयन	(E) योजनाओं का निरीक्षण एवं अनुवर्तन
(i) कृषि संगठन (ii) उद्योग व व्यापार संगठन (iii) परिवहन व संचार संगठन (iv) वित्तीय संगठन (v) सामाजिक सेवाएँ संगठन (vi) प्रशासकीय संगठन (vii) सांख्यिकीय एवं अनुसंधान संगठन (viii) सूचना एवं प्रसारण संगठन (ix) जन सहयोग विभाग	(i) उद्देश्य व निर्धारण (ii) प्राथमिकताओं व निर्धारण (iii) विनियोग माना निर्धारण (iv) भौतिक व वित्तीय साधन निर्धारण (v) विभिन्न गन्तुलन बंधना (vi) ऊपर व नीचे के नियोजन में समन्वय (vii) वार्षिक, अल्पकालीन व दीर्घकालीन नियोजन (viii) पूरक नियोजक (ix) नियोजन में तोचता	(i) उद्देश्य, प्राथमिकता- ओं विनियोग माना व वित्तीय साधनों से भौतिक तथ्यों के सम- न्वय की जाच (ii) सुधारों व संशोधनों की पूर्ति व योजनाओं की ससदीय स्वीकृति	(i) कार्यान्वयन की उचित संगठन व्यवस्था (ii) कुशल, योग्य ह्रमानदार व सशक्त प्रशासन (iii) सफलता के तत्त्वों का समावेश	(i) एक स्वतन्त्र योग्य, तथा निष्पक्ष विशेषज्ञों की संस्था (ii) अनुवर्तन की तत्परता

आर्थिक विशेषज्ञों का समावेश होने के साथ विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले जन प्रतिनिधि भी नियुक्त किये जा सकते हैं।

इसी कारण एक केन्द्रीय नियोजन सगठन के अन्तर्गत प्रायः ये सहायक विभाग होते हैं (i) कृषि सगठन जो कृषि विकास सम्बन्धी नियोजन का कार्य करता है (ii) उद्योग एवं व्यापार सगठन विभिन्न उद्योगों और व्यापार सम्बन्धी नियोजन का कार्य करता है उसमें उद्योगों व व्यापारिक विशेषज्ञों व रोजगार विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जाता है (iii) परिवहन एवं संचार सगठन यह सगठन देश में रेल, सड़क, जल एवं वायु यातायात के विकास व विस्तार सम्बन्धी योजनाएँ बनाता है तथा उनकी समस्याओं को ध्यान देता है। इस सगठन द्वारा संचार के विकास एवं विस्तार सम्बन्धी नियोजन पर भी ध्यान दिया जाता है। (iv) वित्तीय सगठन देश में योजना के कार्यान्वयन के लिये आवश्यक वित्तीय साधन जुटाने की योजना बनाते तथा उनके मार्ग में आने वाली समस्याओं के निराकरण के उपाय सुझाने का दायित्व उठता है (v) सांख्यिकीय एवं अनुसन्धान सगठन देश की अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में नियोजन के लिये विश्वसनीय आँकड़े सङ्कलन, सर्वेक्षण व मूल्यांकन करना का कार्य करता है तथा नियोजन के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कर नवीन उत्पादन विधियों, नवीन आर्थिक नीतियों आदि के साथ उनके प्रभाव का विश्लेषण करता है। (vi) सामाजिक सेवार्थ सगठन विभिन्न सामाजिक सेवाओं, शिक्षा, चिकित्सा, समाज कल्याण परिवार नियोजन, सामाजिक सुरक्षा आदि से सम्बन्धित योजनाएँ बनाता है तथा उनके कार्यान्वयन पर निगरान रखता है (vii) सूचना एवं प्रसारण विभाग का कार्य नियोजन में अधिकाधिक जनसहयोग प्राप्त करने के लिये नियोजन सम्बन्धी नीतियों, उनके कार्यान्वयन की प्रवृत्ति तथा प्रभाव से जनता को अवगत करना है। पिछड़े राष्ट्रों में एक अलग विभाग (viii) जन सहयोग विभाग भी खोला जाता है जो जन सहयोग प्राप्त करने के नये-नये तरीकों की खोज करता है तथा अधिकाधिक जनता को नियोजन में सहयोग के लिये आकर्षित एवं शिक्षित किया जाता है। (ix) प्रबन्ध सगठन अथवा प्रशासकीय सगठन यह सगठन नियोजन के सफल प्रशासन के लिये कुशल एवं उपयुक्त व्यक्तियों व विशेषज्ञों का चयन करता है, अच्छे तरीकों की खोज करता है, विभिन्न विभागों व उपविभागों के कार्यों में तालमेल बैठाता है व उनके प्रबन्ध में कुशलता का प्रयास करता है। कभी-कभी समन्वय विभाग अलग होता है। भारत में नियोजन सगठन का विवरण आगे अलग अध्याय में दिया गया है।

लुईस जे वाल्टर्सकी के मतानुसार एक नियोजन सगठन में (i) सामाजिक एवं आर्थिक नियोजन विभाग (ii) तकनीकी एवं भौतिक नियोजन विभाग (iii) सांख्यिकीय विभाग (iv) अनुसंधान विभाग तथा (v) अन्य विभागों में विधि विभाग, लोक प्रशासन विभाग तथा सूचना एवं सम्पर्क विभाग होने चाहिये।



## (B) योजना का निर्माण व योजना निर्माण प्रक्रिया (Formulation of Plans or Process of Planning)

नियोजन के लिये केन्द्रीय संगठन का स्वरूप निर्धारण के बाद वह नियोजन संगठन (भारत में योजना आयोग) देश के लोगों की आशा और आकांक्षाओं, राज-नैतिक सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में योजना निर्माण की प्रक्रिया निम्न क्रम में पूरी करता है—

### (1) योजना के उद्देश्यों का निर्धारण (Determination of Objectives)—

योजना निर्माण प्रक्रिया में सर्वप्रथम योजना के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। इन उद्देश्यों का निर्धारण देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों के साथ लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुये किया जाता है। उद्देश्यों का निर्धारण करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं होकर यथार्थता के अनुरूप स्पष्ट एवं समझानुकूल हों। विकासशील अर्थव्यवस्था में नियोजन के उद्देश्य मुख्यतः बहु-उद्देश्य व आधिक होते हैं पर उनमें सामाजिक एवं राजनैतिक उद्देश्य का भी यथा-सम्भव समायोजन किया जाता है क्योंकि आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक उद्देश्य एक-दूसरे से बिल्कुल पृथक् उद्देश्य न होकर परस्पर सम्बन्धी अन्तर्निर्भर व अविभाज्य होते हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उद्देश्यों का निर्धारण दीर्घकालीन दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिये और वार्षिक तथा अल्पकालीन योजनाओं में उन उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयास किया जाना चाहिये।

### (2) प्राथमिकता का निर्धारण (Determination of Priorities)—

आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया सीमित साधनों से अधिकारिक सामाजिक लाभ के उद्देश्य से प्रेरित होती है अतः आवश्यकता व साधनों की अनेकता तथा साधनों की सीमितता के कारण साधनों के वैकल्पिक प्रयोगों में प्राथमिकता का क्रम निर्धारण आवश्यक हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को सबसे पहले पूरा किया जाना चाहिये जबकि कम महत्वपूर्ण कार्यों की साधनों की उपलब्धता पर पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिये। दूसरे शब्दों में, सीमित साधनों द्वारा कौन-सा कार्य बच दिया जाय, किन कार्यों को पहले और किन कार्यों को बाद में किया जाय आदि सम्बन्धित निर्णयों की प्रक्रिया को ही प्राथमिकता निर्धारण कहते हैं। प्राथमिकताओं के निर्धारण की समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण हैं—(i) साधनों की सीमितता, (ii) साधनों की अनेकता (iii) साधनों के वैकल्पिक प्रयोग, (iv) विभिन्न कार्य-क्रमों की पारस्परिक निर्भरता तथा (v) कम से कम समय में अधिकतम सामाजिक उत्पन्न।

प्राथमिकताओं का निर्धारण करने में कोई कटोरा व निश्चित नियम नहीं है। इनका निर्माण योजना के उद्देश्यों, देश में वर्तमान सामाजिक एवं राजनैतिक

परिस्थितियों तथा जनता की दीर्घकालीन आशाओं व आकांक्षाओं के अनुरूप दिया जाता है। अतः उनमें समय, स्थान व परिस्थितियों के अनुसार भिन्नता हो सकती है जैसे भारत में प्रथम योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी पर द्वितीय योजना में उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता और उसमें भी आधारभूत उद्योगों को प्रथमिकता के क्रम में उच्च स्थान पर रखा गया। तृतीय योजना में निर्धारित प्राथमिकताओं में भी चीनो एवं पाकिस्तानी आक्रमणों के कारण परिवर्तन करना पड़ा। इस प्रकार स्पष्ट है योजनाओं की सफलता के लिये प्राथमिकताओं का निर्धारण करते समय (i) देश के विकास स्तर, (ii) योजना के उद्देश्यों, (iii) अर्थ-व्यवस्था का आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक ढांचा व पृष्ठ भूमि, (iv) उपलब्ध भौतिक एवं वित्तीय साधनों की मात्रा, (v) जनता की आशाएँ व आकांक्षाएँ, (vi) देश में उपलब्ध तकनीकी ज्ञान (vii) विदेशी सहायता की मात्रा व प्रकृति तथा (viii) भावी विकास की रूपरेखा को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है।

प्राथमिकताओं के निर्धारण की समस्या प्रायः निम्न रूपों में सामने आती है—

(i) कृषि विकास बनाम औद्योगिक विकास (Agricultural Development V/s Industrial Development)—अर्द्ध-विकसित व पिछड़े राष्ट्रों में कृषि की प्रधानता है और औद्योगीकरण का नितान्त अभाव है जबकि औद्योगिक विकास से ही राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में तीव्र गति से वृद्धि सम्भव होती है। अतः उस औद्योगिक विकास योजनाओं को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति पाई जाती है पर उनकी इस प्राथमिकता में बड़ी मात्रा में पूँजी, तकनीकी ज्ञान, विदेशी विनिमय आदि की बाधा आती है। इस कारण प्रारम्भिक विकास की अवस्था में पिछड़ी कृषि के विकास को प्राथमिकता देकर औद्योगिक कच्चा माल, खाद्यान्न की पूर्ति, कृषि में रोजगार से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, बचतों में वृद्धि, निर्यातों में वृद्धि से विदेशी विनिमय अजन आदि से भावी औद्योगीकरण का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है जैसे भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर दूसरी योजना में औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।

विकसित राष्ट्रों में औद्योगीकरण उनकी सम्पन्नता का प्रतीक होता है। जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग उनसे अपनी जीविका अर्जित करता है अतः उन राष्ट्रों में औद्योगीकरण को प्राथमिकता देने के साथ कृषि विकास का भी पर्याप्त प्राथमिकता दी जाती है ताकि सन्तुलित विकास सम्भव हो। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में तृतीय पंचवर्षीय योजना से ही दोनों के सन्तुलित विकास से आत्मनिर्भरता, गरीबी हटाओ व रोजगार बढ़ाओ के उद्देश्यों से प्रेरित होकर कृषि और औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

(ii) आधारभूत उद्योग बनाम उपभोग उद्योग (Producers Industries V/s Consumers Industries)—अगर कोई राष्ट्र अपने आर्थिक नियोजन में उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है तो भी यह समस्या आती है कि आधारभूत उद्योगों

को अधिक प्राथमिकता दी जाय अथवा उपभोग उद्योगों को। अगर देश पिछड़ा है तो उससे भावी औद्योगीकरण तथा तीव्र आर्थिक विकास के लिये आधारभूत उद्योगों के विकास को प्रधानता देने से एक सुदृढ़ आधार बनता है और तदुपरान्त उपभोग वृद्धि व रोजगार के अवसरों का मार्ग प्रशस्त होता है पर उसमें विदेशी विनिर्माण उपभोक्ता माल के अभाव तकनीकी ज्ञान की उपलब्धता की समस्याएँ आती हैं। अनेक राष्ट्रों में विकास के लिये यही उपयुक्त प्राथमिकता होती है जबकि विभिन्न राष्ट्रों में उपभाग उद्योगों को प्राथमिकता देना उपयुक्त रहता है क्योंकि विकास का अन्तिम उद्देश्य जन उपभोग व जीवन स्तर में वृद्धि कर उनके आर्थिक वर्धमान में वृद्धि करना है। भारत जैसी विकासशील अर्थ व्यवस्था जिसमें प्रजातांत्रिक नियोजन का रास्ता अपनाया गया है। आर्थिक विकास के लिये आधारभूत एवं उपभोग उद्योगों के बीच सामन्तस्य का रास्ता अपनाया उपयुक्त रहा है जिससे सुदृढ़ औद्योगिक आधार तैयार करने के लिये पूँजीगत उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर साथ साथ उपभोगों का भी पर्याप्त महत्व दिया गया है।

(iii) पूँजी-प्रधान बनाम श्रम प्रधान उद्योग (Capital Intensive V/s Labour Intensive Industries)—नियोजन में प्राथमिकता निर्धारण में प्रायः यह समस्या भा महत्वपूर्ण है कि पूँजी प्रधान उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी जाय अथवा श्रम प्रधान उद्योगों के विकास को। विकसित राष्ट्रों में पूँजी का आधिक्य होता है तथा सस्ती पूँजी की उत्पादकता अधिक होने के कारण पूँजी प्रधान उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है जबकि पिछड़े व अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में श्रम का बाहुल्य होता है पूँजी का नितान्त अभाव होता है। अतः प्रो० नकसे तथा किन्डलेबर्गर आदि अर्थशास्त्री अर्द्ध विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास में श्रम प्रधान उद्योगों की प्राथमिकता पर जोर देते हैं ताकि जहाँ एक ओर उन देशों में बेरोजगारी व अर्द्ध-बेकारी की समस्याएँ हल होंगी वहाँ दूसरी ओर पूँजी के अभाव में भी विकास सम्भव होगा। यह मानवीय दृष्टि से भी उपयुक्त है। इससे विपरीत कुछ आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत है तीव्रगति से आर्थिक विकास के लिये पूँजी प्रधान उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिये क्योंकि पूँजी प्रधान उद्योगों में पूँजी-उत्पाद अनुपात (Capital Output Ratio) अधिक होता है और अतीव्रता विकास पूँजीगत उद्योगों तथा तकनीकी ज्ञान के सुदृढ़ आधार से ही सम्भव होता है।

इन दोनों दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए अर्द्ध-विकसित व विकासशील राष्ट्र इन दोनों में उपयुक्त सम्बन्ध का रास्ता अपनाते हैं। आधारभूत उद्योगों में पूँजी को प्रधानता दी जाती है जबकि उपभोग उद्योगों में श्रम की प्रधानता होती है।

(iv) निवेशन बनाम उपभोग (Investment V/s Consumption)—आर्थिक नियोजन का प्राथमिकताएँ निर्धारित करते समय यह प्रश्न भी आता है कि निवेशन को प्राथमिकता दी जाय अथवा उपभोग को। विकसित राष्ट्रों में विकास

व व्यापार चनो मे मन्दी के समय उपभोग को प्राथमिकता दी जाती है जबकि विकासशील राष्ट्रों मे उत्पादन का स्तर नीचा होता है, आय कम होती है तथा बिना उत्पादन वृद्धि के उपभोग बढ़ाना असम्भव नहीं तो बठिन अवश्य है अतः पिछड़े राष्ट्रों मे विनियोग को प्राथमिकता देना उपयुक्त रहता है क्योंकि विनिमय बटने से रोजगार, आय व उत्पादन मे वृद्धि होती है जिससे भावी उपभोग वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है । प्रजातान्त्रिक नियोजन मे दोनों मे उचित समन्वय बँटाया जाता है ।

(v) उत्पादन बनाम वितरण को प्राथमिकता (Production V/s Distribution)—आर्थिक विकास की प्रक्रिया मे दो महत्वपूर्ण बातें होती हैं (i) उत्पादन वृद्धि तथा (ii) उसका न्यायोचित वितरण । अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों मे तो उत्पादन वृद्धि को प्राथमिकता दी जाती है ताकि बाद म उस उत्पत्ति वृद्धि मे न्यायोचित वितरण की व्यवस्था की जा सके जबकि विकसित राष्ट्रों मे उत्पादन तो पहले ही उच्च स्तर पर होता है अतः उन देशों मे वितरण को प्राथमिकता देना उपयुक्त रहता है । पिछड़े राष्ट्रों मे प्रारम्भ मे वितरण को प्राथमिकता देना तो गरीबों को बाटने के समान होगा ।

(vi) क्षेत्रीय प्राथमिकतायें (Regional Priorities)—आर्थिक नियोजन मे देश के सन्तुलित विकास व क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त करने का लक्ष्य निहित होता है और क्षेत्रीय समानता का महत्व तब और बढ़ जाता है जब देश विशाल हो और कुछ क्षेत्र दूसरों की अपेक्षा बहुत पिछड़े हो । उदाहरण के तौर पर भारत मे राजस्थान, आसाम, उड़ीसा व जम्मू कश्मीर राज्य, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि के मुकाबले काफी पिछड़े हैं । यही नहीं पिछड़े भागों मे भी कुछ क्षेत्र कहीं अधिक पिछड़े हैं अतः क्षेत्रीय विषमता के समापन व सन्तुलित आर्थिक विकास के लिये क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिये । भारत मे चतुर्थ व पंचवर्षीय योजनाओं मे क्षेत्रीय समानता के प्रयासों पर जोर दिये जाने की प्रवृत्ति रही है ।

(vii) आर्थिक विकास बनाम प्रतिरक्षा (Economic Development V/s Defence)—नियोजन मे प्राथमिकताओं का निर्धारण करते समय यह समस्या भी महत्वपूर्ण है कि आर्थिक विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाय अथवा प्रतिरक्षा को । यह देश की राजनैतिक स्थिति, पड़ोसी राष्ट्रों के सम्बन्धों व उनकी सैन्य शक्ति के साथ-साथ देश मे आर्थिक विकास के स्तर पर निर्भर करता है । यदि बाहरी से देखा जाय तो आर्थिक विकास एवं प्रतिरक्षा दोनों का परस्पर विरोधी चरित्र न होकर एक दूसरे के पूरक एवं अन्तर्निर्भर चरित्र हैं । जहाँ देश म आर्थिक विकास के लिये शान्ति एवं सुरक्षा आवश्यक है वहाँ सुदृढ प्रतिरक्षा क्षमता तभी सम्भव होती है जबकि अर्थ-व्यवस्था मे सुदृढ आर्थिक आधार हो । जितना ही देश आर्थिक दृष्टि से उन्नत होगा उतनी ही उसकी प्रतिरक्षा क्षमता भी अधिक होती है । रूस, अमेरिका व ब्रिटेन

की प्रतिरक्षा क्षमता पिछड़े राष्ट्रों से अधिक है। भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई पर 1962 में चीनी आक्रमण तथा 1965 में पाकिस्तानी आक्रमणों के कारण योजनाओं को प्रतिरक्षा एवं विकासोन्मुख (Defence Cum-Development Oriented) बनाया गया है। पिछले 10-12 वर्षों में देश प्रतिरक्षा की दृष्टि से काफी सक्षम एवं सुदृढ़ है। इसका श्रेय आर्थिक विकास को जाता है और आर्थिक विकास के सुचारु रूप से चलने के पीछे आन्तरिक शान्ति एवं बाह्य आक्रमणों से भय की मुक्ति है।

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि योजनाओं में प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिये विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्विरोधों को यथासम्भव कम कर सीमित साधनों से अधिकतम सामाजिक उत्पन्न करने की व्यवस्था रचना की जाती है। प्रो० टिन्बर्गेन (Tinbergen) ने प्राथमिकताओं के निर्धारण में तीन सिद्धान्तों (i) विनियोग कार्यक्रमों का चुनाव अन्य निर्णयों से परे नहीं होना चाहिये; (ii) विनियोग कार्यक्रम संपूर्ण उत्पादन कार्यक्रमों के अन्तर्गत होना चाहिये तथा (iii) उन योजनाओं को अपनाया जाना चाहिये जिससे देश के कल्याण में अधिकतम लाभ हो।

### 3 विनियोग का निर्धारण (Determination of Investment)

प्राथमिकताओं के निर्धारण के बाद योजना निर्माण की अगली अवस्था विनियोग माना निर्धारण की है। विभिन्न उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये कितना-कितना विनियोग उनमें किया जाना चाहिये इसका निर्धारण करने के लिये केन्द्रीय नियोजन सत्ता विभिन्न विकास मॉडलों (Growth Models) का सहारा लेती है जिनमें प्रायः (i) पूंजी-उत्पाद-अनुपात (Capital-Output-Ratio) (ii) श्रम-उत्पाद-अनुपात (Labour Output-Ratio) तथा (iii) बचत-आय-अनुपात आदि को आधार बनाया जाता है। इन विकास मॉडलों में हैरॉड (Harrod) मॉडल व डोमोर (Domar) मॉडल, कीन्स का विकास मॉडल (Keynes Growth Model) तथा महालनोबिस विकास मॉडल (Mahalanobis Model) अधिक लोकप्रिय हैं। प्रथम तीन मॉडल विकसित राष्ट्रों के लिये उपयुक्त हैं जबकि महालनोबिस मॉडल भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के लिये विनियोग निर्धारण का उपयुक्त उपकरण है। इन मॉडलों से आप को एक निश्चित वृद्धि के लिये विनियोग की दर मालूम की जाती है। यह दर पूंजी-उत्पाद-अनुपात (Capital Output Ratio) पर निर्भर करती है। भिन्न-भिन्न उद्योगों तथा अलग-अलग परिस्थितियों में पूंजी-उत्पाद-अनुपात में अन्तर पाया जाता है अतः एक सामान्य औसत अनुपात ज्ञात कर लिया जाता है। प्रो० वाल्मिस्की (Walmsky) के अनुसार "पूंजी-उत्पाद-अनुपात उत्पादन की वृद्धि के लक्ष्य का करीब निगुना होना चाहिए।" बद्ध-विकसित राष्ट्रों के पूंजी उत्पाद-अनुपात के बारे में मनैरथ का अभाव है जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) 21 से

आर्थिक नियोजन की तकनीक एवं विधि

5:1, सिगर कृषि क्षेत्र में 4:1 तथा अन्य क्षेत्रों में 6:1 तथा रोसेन्सटिन-रोडन ने 3:1 से 4:1 के पूँजी-उत्पाद-अनुपात का अनुमान लगाया है वहाँ कीनथ के कुरिहारा ने 5:1 का अनुमान लगाया है। यहाँ निम्न और उच्च पूँजी-उत्पाद-अनुपात के पक्ष व विपक्ष में निम्न तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं—

अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में निम्न पूँजी-उत्पाद-अनुपात (Low Capital Output Ratio) के पक्ष में तर्क—इस मत के मानने वाले विद्वानों की मान्यता है कि अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में निम्न विशेषताओं के कारण पूँजी उत्पाद अनुपात नीचा रहता है। अर्थात् कम पूँजी विनियोग से ही अधिक उत्पादन संभव होता है। (i) अशोषित एवं अर्द्ध-शोषित प्राकृतिक साधनों का प्राचुर्य होने से उनके विदोहन की पर्याप्त सम्भावनाएँ रहती हैं। (ii) जनाधिषय के कारण श्रम-प्रधान उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है (iii) पूँजी की बचत के प्रयास प्रबल होते हैं (iv) थोड़े पूँजी विनियोग में ही उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि होती है। (v) श्रम की उत्पादकता व कुशलता में भी तेजी से वृद्धि होती है। (vi) देश की समूची उत्पादन क्षमता के विकास व पूर्ण विदोहन से कम पूँजी से भी अधिक उत्पादन सम्भव होता है।

अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में उच्च पूँजी-उत्पाद-अनुपात (High Capital Output Ratio) के पक्ष में तर्क—जो विद्वान अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में उच्च पूँजी-उत्पाद-अनुपात के मत वाले हैं वे अपने मत के पक्ष में ये तर्क देते हैं (i) सामाजिक ऊपरी लागतों जैसे परिवहन, संचार, शिक्षा, आवास, शक्ति आदि में वृद्धि की आवश्यकता पूर्ति अधिक पूँजी के द्वारा ही संभव होती है क्योंकि इनका पिछड़े राष्ट्रों में नितांत अभाव होता है जबकि ये विकास के आधार स्तम्भ हैं (ii) परम्परागत उत्पादन पद्धतियों में पूँजी का अपव्यय होता है (iii) तकनीकी ज्ञान का अभाव होने से भी विकास की प्रारम्भिक अवस्था में पूँजी के अपव्यय व दुरुपयोग की सम्भावनाएँ अधिक होती हैं (iv) आधारभूत उद्योगों में अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है (v) कुछ पिछड़े राष्ट्रों में विकास का आधार प्राकृतिक साधनों के अभाव को दूर करने के लिये पूँजी का प्रतिस्थापन अधिक पूँजी की माग को जन्म देता है। (vi) पिछड़े राष्ट्रों में पूँजी का अनुत्पादक कार्यों में प्रयोग की प्रवृत्ति जैसे मृत्यु-भोज, विवाहाहृतसव एवं प्रदर्शनात्मक प्रभाव आदि में प्रबल होनी है।

उपर्युक्त तर्कों को व्यावहारिकता की कसौटी पर परखने से स्पष्ट होता है कि पिछड़े राष्ट्रों में विकास की प्रारम्भिक अवस्था में पूँजी-उत्पाद-अनुपात कम होता है और विकास प्रक्रिया में प्रगति के साथ-साथ बढ़ता जाता है जैसे भारत में प्रथम योजना में यह अनुपात 1:8.1 द्वितीय योजना में 2:3.1, तृतीय योजना में 2:5.1 तथा चौथी योजना में 3:4.1 रहता सामान्य प्रवृत्ति का परिचायक है क्योंकि आर्थिक प्रगति के साथ-साथ आधुनीकरण, स्वचालिता तथा पूँजी यन्त्र उद्योगों (Capital Intensive Industries) की प्रवृत्ति बढ़ती है।

#### (4) भौतिक साधन बनाम वित्तीय नियोजन

##### (Planning of Physical v s Financial Resources)

विनियोग की मात्रा निर्धारित करने के बाद योजना निर्माण का अगला कदम भौतिक तथा वित्तीय योजनाएँ तैयार करना है। भौतिक साधनों के नियोजन का अभिप्राय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक भौतिक साधनों की मात्रा खोना उनको विभिन्न वैकल्पित प्रयोगों में बांटने तथा योजना के लक्ष्यों को भौतिक इकाईयों को व्यक्त करने से है जैसे वित्तना कितना लोहा, सीमेंट, पथर, कितने कितने तकनीकी विशेषज्ञ शिक्षा डॉक्टर, प्रबन्धक, श्रमिक आदि चाहिये उनकी पूर्ति के स्रोत क्या क्या होंगे इनको किन किन क्षेत्रों में प्रयोग करना है तथा कितनी कितनी मात्रा में ताकि भौतिक लक्ष्य पूरे हो सके। जबकि वित्तीय साधनों के नियोजन का अभिप्राय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये भौतिक साधनों की आवश्यक मात्रा का निर्धारण, उनकी प्राप्ति के स्रोतों का निर्धारण तथा भौतिक साधनों के वैकल्पिक प्रयोगों की एक समतुलित योजना तैयार करना है। पूँजीवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय साधनों का आयोजन विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि भौतिक साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है और सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये भौतिक साधनों के क्रय के लिये सरकार को भौतिक व्यय करना पड़ता है। वित्तीय साधनों की पर्याप्त पूर्ति भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक रहती है। जहाँ एक ओर विनियोग भौतिक साधनों की पूर्ति व उनके उत्पादन प्रयोग पर निर्भर करता है वहाँ दूसरी ओर वित्तीय साधनों की पूर्ति विनियोग मात्रा को सीमित करती है अतः ये दोनों (भौतिक तथा वित्तीय साधन) परस्पर पूरक एवं अन्तर्निर्भर घटक हैं। यदि भौतिक साधनों की प्रचुर पूर्ति भी हो पर वित्तीय साधनों का अभाव हो तो विकास अवरुद्ध हो जाता है अथवा भौतिक साधन सीमित हो पर वित्तीय साधन खूब हो फिर भी विकास वांछित गति से सम्भव नहीं हो पाता अतः दोनों में उचित सामन्वय बँटाने की आवश्यकता पड़ती है। भारत में प्रथम योजना में वित्तीय नियोजन पर ही विशेष ध्यान दिया गया था पर अब योजनाओं में दोनों को समन्वित करने का प्रयास किया जाता है।

#### (5) योजना में विभिन्न समतुलनों की समस्या

##### (Problem of Various Balances in Planning)

भौतिक तथा वित्तीय साधनों की योजना तैयार करने के बाद योजना के विभिन्न क्षेत्रों में समतुलन बँटाने की समस्या सामने आती है ताकि योजना को सफलता पूर्वक कार्यान्वित किया जा सके। समतुलन के मुख्य तीन रूप हैं—

(अ) अधोगामी समतुलन (Backward Balances)—यह उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा तथा उनका उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं के बीच समतुलन को प्रकट करता है अर्थात् अधोगामी समतुलन के अन्तर्गत पड़त उत्पादन वितरण (Input Output Analysis) द्वारा अन्तिम उत्पादन लक्ष्यों के निर्धारण

की सरलता जानी जाती है उदाहरण के लिए एक लाख टन स्टील बनाने के लिये कितना-कितना लोहा, मैंगनीज, चूना, ईंधन तथा श्रम आदि की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार सभी भौतिक उत्पादन लक्ष्यों के बारे में निर्धारण होता है। इसके लिए प्रो० लियोन्टिएफ (Prof. Leontief) ने एक संयुक्त समीकरण दिया है जिसकी सहायता से यह गणना की जा सकती है कि उपलब्ध भौतिक साधनों से किन-किन वस्तुओं की कितनी-कितनी मात्रा उत्पादित करने से अर्थ-व्यवस्था में सन्तुलन व साधनों का अनुकूलतम प्रयोग सम्भव है। इस विश्लेषण पद्धति का प्रयोग उन्हीं अर्थ-व्यवस्थाओं में उपयोगी है जहाँ पर्याप्त एवं विश्वसनीय सांख्यिकी आंकड़े उपलब्ध हों।

(ब) संगमगामी सन्तुलन (Cross Balance)—इसके अन्तर्गत कुल उत्पादन लक्ष्यों व कुल उपलब्ध साधनों के बीच सन्तुलन व साम्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है जैसे उत्पादन लक्ष्यों व मानवीय तथा प्राकृतिक साधनों के बीच सन्तुलन होना चाहिये अन्यथा या तो ये साधन बेरोजगार होंगे या उनकी कमी महसूस होगी। नियोजन की सफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगी कि (i) उत्पादन लक्ष्यों व मानव शक्ति साधनों में सन्तुलन है (ii) भौतिक साधनों व वित्तीय साधनों में सन्तुलन है। क्योंकि भौतिक साधनों की तुलना में वित्तीय साधन कम होने पर कई साधन अक्षोपित रह जायेंगे व भौतिक लक्ष्य अपूर्ण रहेंगे। इसी प्रकार भौतिक लक्ष्य वित्तीय साधनों की तुलना में ऊँचे होने पर हीनाय-प्रबन्ध (Deficit Financing) के कारण मुद्रा-भ्रसार का भय रहता है तथा वित्तीय सकट उत्पन्न होना है। भारत की प्रथम योजना में भौतिक लक्ष्य नीचे थे तथा वाद की सब योजनायें वित्तीय सकट से गुजर रही हैं और हीनाय-प्रबन्ध का अत्यधिक प्रयोग होने से मूल्यों में अप्रदशित वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त संगमगामी सन्तुलन में तीसरे रूप उद्योग की आदर्श स्थिति (Optimum Location) पर भी ध्यान दिया जाता है कि उद्योग की स्थापना ऐसे स्थान पर की जानी चाहिये जहाँ उसके लिये पर्याप्त कच्चा माल, श्रम, पूँजी व बाजार मिल जाये तथा यह योजना के उद्देश्यों के अनुरूप क्षेत्रीय समानता स्थापित करने में सहायक हो।

(स) मौद्रिक सन्तुलन (Monetary Balance)—इसके अन्तर्गत देश में मौद्रिक आय, उपभोग, बचत, निजी विनियोग की राशि तथा विनियोगों के लिए उपलब्ध भौतिक साधन, विदेशी भुगतानों एवं प्राप्तियों के बीच सन्तुलन बँटाना पड़ता है। इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग तथा उसके लिये उपलब्ध वित्तीय साधनों के साथ-साथ उत्पादित एवं आयोजित वस्तुओं में सन्तुलन बँटाना भी महत्वपूर्ण होता है।

(6) ऊपर से तथा नीचे से आयोजन में सामन्जस्य

(Co ordination Between Planning From Above & From below)

विभिन्न सन्तुलनों की स्थापना के पश्चात् योजना निर्माणकर्ता सत्ता ऊपर से नियोजन तथा नीचे से नियोजन में सामन्जस्य बँटाती है क्योंकि जब ऊपर से नियोजन



राष्ट्रीय स्तर से राज्य-स्तर—फिर जिलास्तर व स्थानीय स्तर पर घोषा जाता है तो सामान्य जन सहयोग प्राप्त नहीं होता अतः नियोजन को नीचे स्तर जिला व स्थानीय स्तर से प्रारम्भ कर राज्य व केन्द्रीय स्तर पर समन्वित किया जाता है तो उसमें व्यावहारिकता आती है यही कारण है कि दोनों प्रकार के आयोजन में उपर्युक्त सामन्-जम्हा बँटाया जाता है।

(7) वार्षिक, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन योजनाओं में परस्पर समन्वय  
(Co-ordination Amongst Annual, Prospective & Perspective Planning)

आर्थिक नियोजन एक निरन्तर चलने वाली दीर्घकालीन प्रक्रिया है अतः सामान्यतः नियोजन की दीर्घकालीन विकास की मोटे रूप में रूप-रेखा 15-20 वर्ष की अवधि के लिये तैयार की जाती है। इसके बाद इस अवधि को सुविधा की दृष्टि से अल्पकालीन (5 से 7 वर्ष) की योजनाओं तथा वार्षिक योजनाओं में विभाजित किया जाता है। चूँकि अल्पकाल में विकास का स्वरूप वार्षिक योजनाओं के विकास कार्यों में उपलब्धियों पर निर्भर करता है अतः वार्षिक योजनाओं अल्पकालीन उद्देश्यों के अनुरूप बनाई जाती है और ठीक इसी प्रकार अल्पकालीन योजनाओं का स्वरूप दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति के अनुरूप ढाला जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मजिल की पहली व अन्तिम सीढ़ी के बीच की दूरी दीर्घकालीन नियोजन का सूचक है तो प्रत्येक सीढ़ी वार्षिक योजना का रूप है जबकि 4-5 सीढ़ियों के बाद भी मोड़ या चौड़ी सीढ़ी अल्पकालीन योजना का स्वरूप समझाती है।

(8) अनुपूरक नियोजन (Supplementary Planning)

इन अर्थव्यवस्थाओं में जहाँ वित्तीय साधनों की कमी का संकट बना रहता है, नियोजन में एक विशेष तकनीक का महारा लिया जाता है जिसके अन्तर्गत योजना को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है पहला आवश्यक या अनिवार्य भाग (Essential or Core projects) वह भाग होता है जिसके कार्यान्वयन के लिये हर प्रकार से साधन जुटाने की व्यवस्था की जाती है। दूसरा सम्भाव्य भाग (Contingent projects) इसके अन्तर्गत उन योजनाओं का समावेश होता है जिनकी कार्यान्वित वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है अगर अनिवार्य भाग के कार्यान्वित करने के अतिरिक्त साधन बचते हैं तो सम्भाव्य भाग को भी कार्यान्वित किया जाता है पर अगर वित्तीय साधन कम हो तो उनमें कटौती कर दी जाती है और केवल अनिवार्य भाग को पूरा किया जाता है। 1957 में विदेशी विनिमय संकट के कारण भारत की द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना को भी दो भागों—अनिवार्य भाग तथा सम्भाव्य भाग में बाँटा गया था।

(9) नियोजन में लोचता (Flexibility in Planning)

प्रो० डर्बिन (Durbin) की यह मान्यता है कि नियोजन में भविष्य के बारे में निश्चितता की रचना कठिन है क्योंकि भविष्य में होने वाले परिवर्तन, तकनीकी अनुसंधानों, लोगों के उपभोग, वृद्ध व जीवन स्तर में परिवर्तन की अनिश्चितता

रहती है अतः नियोजन में बदलती हुई परिस्थिति के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन की पर्याप्त सोच होना जरूरी है जैसे भारत की प्रथम योजना में बेकारी की विषम स्थिति से निपटने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र में 175 करोड़ रुपये व्यय के प्रावधान से ग्यारह सूत्रीय कार्यक्रम अपनाया गया। इसी प्रकार से सामयिक परिवर्तन भारत के अन्य योजनाओं में भी किये गये हैं। जनता सरकार ने आवृत्ति योजना (Rolling Plan) के द्वारा नियोजन में एक नई तकनीक का सूत्रपात किया है।

नियोजन में सोचता का अभिप्राय यह बतई नहीं है कि सरकार लोचना के नाम पर योजना की मुख्य संरचना को ही परिवर्तित कर दे। प्रो० मिडल (Myrdal) के मतानुसार योजना की आधारभूत संरचना की सुरक्षा के लिये संवैधानिक एव राजनैतिक व्यवस्था की जानी चाहिये और इसी आधारभूत संरचना के अन्तर्गत ही सोचता बनी रहे।

### (C) योजना का निरीक्षण (जांच) एवं स्वीकृति (Testing & Adoption of Plan)

जब योजना बनाकर तैयार कर ली जाती है तो अगला कदम उसकी जांच करना तथा आवश्यक संशोधन कर उसे स्वीकृति प्रदान करना होता है। योजना का निरीक्षण अलग विधिपरिपद् या उच्च सरकारी स्तर पर किया जाता है जिसमें देखा जाता है कि उद्देश्य, विनियोग की मात्रा, प्राथमिकताएँ तथा साधनों की व्यवस्था परिस्थितियों के अनुरूप है तथा उनमें परस्पर सन्तुलन एव सामन्जस्य है। अगर कहीं कोई कमी या असन्तुलन होता है तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है और आवश्यक संशोधनों के बाद योजना बनाकर तैयार हो जाने पर उसके प्रारूप को जनसाधारण के सूचनायंत्र प्रसारित किया जाता है तथा रचनात्मक सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं और सरकारी स्तर पर कैबिनेट तथा राष्ट्रीय विकास परिपद् (National Development Council) भी विचारविमर्श करती है।

राष्ट्रीय विकास परिपद् के अनुमोदन के पश्चात् योजना का अन्तिम प्रारूप प्रधान मंत्री द्वारा संसद की अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया जाता है ताकि योजना को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया जा सके। संसद में योजना के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाता है और आवश्यक संशोधनों के बाद संसद योजना के अन्तिम प्रतिवेदन पर अपनी स्वीकृति की छाप लगाती है। इस स्वीकृति के बाद योजना क्रियान्वयन के लिये प्रकाशित कर दी जाती है।

### (D) योजना का कार्यान्वयन

#### (Implementation or Execution of the Plan)

संसद की स्वीकृति के बाद योजना के कार्यान्वयन के कदम उठाये जाते हैं। योजना का निर्माण कर लेना ही पर्याप्त नहीं उसे कार्यान्वित कर मूर्तरूप सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि योजना की सफलता उसके सफल क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। योजना चाहे कितनी ही बढ़िया क्यों न हो पर अगर उसे जाये अथवा कार्यान्वयन अपूर्ण, अनुपयुक्त एव अकुशल हुआ तो न केवल

सम्भावनाएँ ही धूमिल होगी वरन् अर्थ-व्यवस्था में संकट, अस्त-व्यस्तता एवं पतन की समस्याएँ सामने आ सकती हैं अतः योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये एक कुशल एवं प्रभावी संगठन की आवश्यकता है।

योजनाओं को कार्यान्वित करने का दायित्व केन्द्र तथा राज्य सरकारों का है अतः केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें अपने विभिन्न मन्त्रालयों और उनके अधीनस्थ विभागों—कृषि, सिंचाई, सहकारिता, उद्योग, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा आदि—को उनसे सम्बन्धित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का आदेश देती हैं। निजी क्षेत्र के कार्यक्रमों को निजी संस्थाओं को कार्यान्वित करने के लिये सौंप दिया जाता है। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर व स्थानीय स्तर पर उपयुक्त, कुशल, सुदृढ़ एवं ईमानदार प्रशासन की व्यवस्था जानी चाहिये जिनमें परस्पर समन्वय एवं सहयोग बना रहे। योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी अधिकारियों में वर्तमान परायणता, कुशलता व तकनीकी योग्यता आवश्यक है।

योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये यह भी आवश्यक है कि (i) योजना के उद्देश्य यथार्थवादी हों, (ii) प्राथमिकताएँ उद्देश्यों के अनुरूप हों, (iii) विनियोग के लिये पर्याप्त वित्तीय साधन हों, (iv) विश्वसनीय सांख्यिकी आँकड़े हों, (v) ईमानदार, योग्य, सुदृढ़ एवं कुशल प्रशासक हों, (vi) एक उत्तरदायी राजनैतिक विपक्षी दल हो, (vii) एक सुदृढ़ सरकार हो जिसका नेतृत्व प्रगतिशील शासक के हाथ में हो, (viii) पर्याप्त-जन सहयोग हो तथा (ix) अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ व सहयोग अनुकूल बना रहे। यही नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में पूर्ण समन्वय एवं सहयोग बना रहे। जब ये तत्व विद्यमान होंगे तो योजना का क्रियान्वयन सुगम हो जाता है।

### (E) निरीक्षण, मूल्यांकन एवं अनुवर्तन

#### (Supervision, Evaluation & Follow-up Action)

आयोजन तकनीक एवं विधि की अन्तिम अवस्था योजना का निरीक्षण, मूल्यांकन तथा अनुवर्तन सम्बन्धी कार्य हैं। योजना के क्रियान्वयन का निरन्तर निरीक्षण तथा उसका सामयिक मूल्यांकन योजना की प्रगति की समीक्षा के लिये आवश्यक है ताकि योजना के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं का निराकरण किया जा सके, आवश्यक परिवर्तन किये जा सकें और योजना के सद्यों को प्राप्त करने के लिये प्रभावी कदम उठाये जा सकें। भारत में योजना बनाने तथा उसके क्रियान्वयन के निरीक्षण व मूल्यांकन का उत्तरदायित्व योजना आयोग पर है जबकि क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व केन्द्र तथा राज्य सरकारों पर है। भारतीय योजना आयोग का एक प्रमुख कार्य "योजना की प्रत्येक अवस्था के क्रियान्वयन द्वारा प्राप्त प्रगति का समय-समय पर लेखा जाया लेना तथा उसके अनुसार नीति में समायोजन व अन्य उपायों के लिए सिफारिशें करना है।" अतः जब योजना आयोग में योजना

क्रियान्वयन का विभिन्न क्षेत्रों व स्तरों पर पर्यवेक्षण व मूल्यांकन के लिये एक कार्यक्रम मूल्यांकन सगठन (Programme Evaluation Organisation) स्थापित किया गया है। इस सगठन द्वारा प्रदत्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुवर्तन का कार्य किया जाता है तथा उसमें बताई गई कमियों व तत्सम्बन्धी राय को विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

निष्कर्ष—इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि नियोजन की तकनीक एवं विधि एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सर्वप्रथम योजना निर्माण के लिए उपयुक्त सगठन की आवश्यकता होती है। यह सगठन योजनाएँ बनाना है, योजना की प्रक्रिया में सर्वप्रथम उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है तथा फिर प्राथमिकताएँ निर्धारित की जाती हैं। योजना निर्माण में विनियोग माना निर्धारण, भौतिक तथा वित्तीय साधनों का नियोजन, विभिन्न सन्तुलन बैठाना, ऊपर व नीचे से नियोजन में समन्वय स्थापित करना, पूरक योजना बनाना तथा उसमें आवश्यक लोचता प्रदान करना योजना प्रक्रिया की महत्वपूर्ण बातें हैं। योजना बनकर तैयार हो जाने पर उसकी जाँच की जाती है और जाँच के बाद आवश्यक सशोधनों पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृति के पश्चात् योजना को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय व राज्य सरकारों के मन्त्रालयों व विभागों पर डाला जाता है अतः कुशल सुदृढ़, योग्य एवं ईमानदार प्रशासनिक व्यवस्था योजना के सफल क्रियान्वयन की आवश्यक बात है। योजना के क्रियान्वयन का समय-समय पर निरीक्षण करने तथा प्रगति का मूल्यांकन करने के लिये एक निष्पक्ष स्वतन्त्र सगठन होना है जो विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन कर उसकी कमियों को बताता है, तथा उन्हें दूर करने के उपाय सुझाता है जिसको विभिन्न मन्त्रालय कार्यान्वित करते हैं। इस प्रकार नियोजन का कार्य निरन्तर चलते हुए सर्वांगीण सन्तुलित विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। भारत में नियोजन प्रक्रिया व योजना तन्त्र का विवरण आगे अलग अध्याय में दिया गया है। □

## आर्थिक नियोजन के उद्देश्य

(OBJECTIVES OF PLANNING)

(भारत के विशेष सम्दर्भ से)

### (आर्थिक नियोजन के उद्देश्य)

(Objectives of Economic Planning)

आर्थिक नियोजन राज्य द्वारा अर्थ-व्यवस्था के संचालन, नियन्त्रण व निर्देश की एक ऐसी सुसंगठित एवं समन्वित प्रक्रिया है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रेरित होती है अतः नियोजन सदा ही सोद्देश्य होता है। ईलियट के शब्दों में "नियोजन की क्रिया सोद्देश्य क्रिया है, बिना उद्देश्यों के नियोजन के विषय में सोच सम्भव नहीं है।" नियोजन के ये उद्देश्य आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक हो सकते हैं जिन्हें निम्न तालिका से दर्शाया जा सकता है।

### आर्थिक नियोजन के उद्देश्य

↓	↓	↓
(A) आर्थिक उद्देश्य	(B) सामाजिक उद्देश्य	(C) राजनैतिक उद्देश्य
(i) प्राकृतिक साधनों का विदोहन	(i) सामाजिक सुरक्षा	(i) बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा
(ii) उत्पादन वृद्धि	(ii) सामाजिक समानता	(ii) शक्ति व सत्ता प्रसार
(iii) पूर्ण रोजगार	(iii) वर्ग-संघर्ष का समापन	
(iv) कृषि का विकास	(iv) नैतिक एवं बौद्धिक उत्थान	(iii) शान्ति एवं व्यवस्था
(v) औद्योगीकरण		(iv) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग
(vi) आर्थिक समुलन		
(vii) आर्थिक विपन्नता का समापन		
(viii) युद्धोपरान्त पुनर्निर्माण		
(ix) आर्थिक स्थायित्व व व्यापार जघनो पर नियन्त्रण		
(x) राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि		
(xi) आर्थिक आत्म निर्भरता		

### (A) आर्थिक उद्देश्य (Economic Objectives)

नियोजन के आर्थिक उद्देश्य देश की परिस्थितियों के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। अर्द्ध-विकसित विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में नियोजन के आर्थिक उद्देश्य प्राकृतिक साधनों का विहोदन, पूर्ण रोजगार, उत्पादन वृद्धि, सन्तुलित विकास आदि होते हैं जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में नियोजन का उद्देश्य आर्थिक स्थायित्व, पूर्ण रोजगार व विकास होता है। नियोजन के उद्देश्य मुख्यतः आर्थिक ही होते हैं—जैसे

(i) प्राकृतिक साधनों का शोषण—अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्थाओं के नियोजन का उद्देश्य देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का आर्थिक विकास के लिये विहोदन करना होता है। इन साधनों का शोषण करने से अधिक रोजगार, अधिक आय और अधिक सन्तुलित विकास का मार्ग प्रशस्त होता है।

(ii) उत्पादन वृद्धि—आर्थिक नियोजन का उद्देश्य उत्पादन के सभी क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि करना होता है। इसके लिये उत्पादन साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाता है तथा उत्पादन व्यवस्था को इस प्रकार सगठित किया जाता है कि कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन कर सामाजिक समृद्धि में वृद्धि की जा सके।

(iii) पूर्ण रोजगार—आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य देश की उपलब्ध मानव-शक्ति का समुचित एवं लाभपूर्ण उपयोग करना होता है। इसके लिये बेरोजगारी का निराकरण, रोजगार अवसरों में वृद्धि तथा आर्थिक रोजगार वालों को पूर्ण रोजगार व्यवस्था की करना होता है। ग्रेब (Zweig) के शब्दों में "पूर्ण रोजगार या तो आर्थिक नियोजन का प्राथमिक उद्देश्य या किसी भी अन्य कारणों से अपनाये गये तो नियोजन अनिवार्य उप-उत्पत्ति (Necessary by-Product) होती है।" रूस में प्रथम योजना में ही बेरोजगारी की समस्या का समापन हो गया। अमेरिका ने भी न्यू डील (New Deal) से बेकारी को दूर करने की योजना क्रियान्वित की तथा 1946 में पूर्ण रोजगार नियोजन प्रारम्भ किया। भारत में भी आर्थिक नियोजन का एक प्रमुख उद्देश्य बेरोजगारी को दूर करना व रोजगार अवसरों में वृद्धि करना है।

(iv) कृषि का विकास—अर्द्ध-विकसित एवं पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक नियोजन का एक उद्देश्य वहाँ की कृषि का विकास करना है ताकि भावी विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। भारत में भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। अभी भी खाद्यान्नों की आपूर्ति व औद्योगिक वस्त्रों के लिये कृषि विकास एक प्रमुख उद्देश्य है। इसे प्राथमिक क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि, आर्थिक समृद्धि तथा सन्तुलित विकास के माध्यम से सम्बन्धित उद्देश्यों की पूर्ति होती है।

(१) औद्योगीकरण व आन्ध्रभूत उद्योगों का तीव्र विकास—विश्व भी अर्थ-व्यवस्था में नियोजन का एक मुख्य उद्देश्य आधारभूत उद्योगों व उपभोग उद्योगों का तेजी से विकास करना होता है क्योंकि औद्योगीकरण के बिना अर्थ-व्यवस्था का न तो सर्वाङ्गीण एवं सन्तुलित विकास सम्भव है और न पूर्ण रोजगार व साधनों का पूर्ण विद्योहन ही हो पाता है। यही कारण है कि आज सभी पिछड़े राष्ट्र औद्योगीकरण के लिये नियोजन अपना रहे हैं। भारत में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व पाँचवी योजनाओं में औद्योगीकरण का उद्देश्य प्रमुख रहा है।

(ii) सन्तुलित आर्थिक विकास—आर्थिक नियोजन का उद्देश्य यह होता है कि अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का सन्तुलित विकास हो। इसके लिये पिछड़े क्षेत्रों के विकास को अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रकार कृषि व उद्योगों में सन्तुलन, उपभोग व उत्पादन में सन्तुलन, बचत व विनियोग में सन्तुलन, सभी क्षेत्रों में सन्तुलित विकास का सर्वाङ्गीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है।

(iii) आर्थिक विषमता का समापन—आर्थिक नियोजन का उद्देश्य न केवल उत्पादन वृद्धि ही है बल्कि उत्पादन का न्यायोचित वितरण भी है जिससे समाज में सम्पत्ति, आय व अवसर की समानता स्थापित की जा सके और समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता को दूर किया जा सके। कभी-कभी आर्थिक नियोजन प्रक्रिया में न चाहते हुए भी आर्थिक विषमता बढ़ जाती है जैसा भारतीय योजनाओं में दृष्टि-गोचर हुआ है। अब आर्थिक विषमता के समापन के लिये प्रभावी कदम 20-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत उठाये जा रहे हैं।

(iv) युद्धोपरान्त पुनर्निर्माण—आर्थिक नियोजन का उद्देश्य कभी-कभी युद्ध जर्जरित अर्थ व्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण करना होता है ताकि वह देश पुन अपनी खोई हुई आर्थिक शक्ति साधन व उत्पादन क्षमता स्थापित कर विकास की ओर अग्रसर हो सके। यूरोप में मार्शल योजना व जापान में पुनर्निर्माण योजनाएँ इसके उदाहरण हैं।

(v) आर्थिक स्थायित्व व व्यापार चक्रों पर नियन्त्रण—पूँजीवादी देशों में स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली कभी-कभी व्यापार चक्रों को जन्म देती है जिससे समस्त अर्थ-व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। 1930 की विश्व व्यापी आर्थिक मंदी ने समूचे विश्व को मंदी के ऐसे दल दल में पसा दिया था कि बेकारी, भूखमरी व सम्पन्नता में विषमता का सबूत था। ऐसे समय में आर्थिक स्थायित्व के लिये अमेरिका ने न्यू डील (New Deal) की नीति अपनाई गई, ब्रिटेन में भी आर्थिक स्थिरीकरण की नीति अपनाई गई। अब आर्थिक नियोजन का एक मुख्य उद्देश्य व्यापार चक्रों के दृष्टान्तों से मुक्ति प्रदान करना तथा आर्थिक स्थायित्व स्थापित करना भी है।

(vi) राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि—आर्थिक विकास का माप-दण्ड राष्ट्रीय आय के स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि होता है अत आर्थिक नियोजन का उद्देश्य अतः राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना है ताकि

लोगों की आय व उपभोग में वृद्धि से उनकी आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक कल्याण का लक्ष्य पूरा हो। भारत की पाँचवी योजना में भी राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष 55% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।

(अ) आत्म निर्भरता—यद्यपि अर्द्ध-विकसित विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक नियोजन की प्रारम्भिक अवस्था में नियोजन का उद्देश्य आत्म-निर्भरता न होकर तीव्र आर्थिक विकास करना होता है पर एक निश्चित स्तर के बाद देश में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य अन्ततः आत्म-निर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना होता है ताकि वह राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं के लिये दूसरों पर आश्रित न हो। अपना विकास अपने ही सधनों से करने में सक्षम हो। आज भारत साधान् में आत्म-निर्भरता के उद्देश्य को प्राप्त करने में कृत-सक्षम है। अन्य क्षेत्रों में भी 1985-90 तक आत्म निर्भरता का लक्ष्य है।

## (B) सामाजिक उद्देश्य

### (Social Objectives)

आयोजन के आर्थिक उद्देश्यों में सामाजिक आकांक्षाओं ग्याय व सामाजिक सुरक्षा का प्रतिनिम्ब नजर आता है क्योंकि आर्थिक नियोजन का अन्तिम लक्ष्य अधिकतम सामाजिक कल्याण करना होता है अतः आर्थिक नियोजन के निम्न सामाजिक उद्देश्य होते हैं—

(i) सामाजिक सुरक्षा—आर्थिक नियोजन का एक सामाजिक उद्देश्य यह है कि समाज के प्रत्येक सदस्य की उसके पाँच महान् शत्रुओं—बेकारी, बीमारी, वृद्धावस्था, गरीबी व आकस्मिक आर्गत व दुर्घटना से सुरक्षा प्रदान करना है इसके लिये 'सामाजिक बीमा व सामाजिक सहायता की व्यवस्था की जाती है।

(ii) सामाजिक समानता—आर्थिक नियोजन का उद्देश्य आर्थिक समानता के द्वारा समाज के प्रत्येक सदस्य को समानता के अवसर प्रदान करना है ताकि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बिना वर्ग लिंग भेद के समानता का दर्जा मिले, इसके लिये निम्न एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता, नौकरियों में प्राथमिकता तथा राजनैतिक स्तर पर आरक्षण (Reservation) की व्यवस्था की जाती है। जैसा अब 20सूत्रीय कार्यक्रम में दलित एवं पिछड़े लोगों की आर्थिक समानता के प्रयास प्रबल हैं—

(iii) वर्ग सघर्ष का समापन—आर्थिक विषमता एवं सामाजिक असमानता शोषण को जन्म देती है और समाज दो वर्गों—पहला धनी वर्ग तथा दूसरा निचन वर्ग में बँट जाता है जिनके परस्पर वैमनस्य एवं भेदभाव वर्ग सघर्ष व खूनी भ्रान्ति के कारण बनते हैं अतः आर्थिक नियोजन द्वारा आर्थिक समानता, सामाजिक सुरक्षा व समानता स्थापित कर वर्ग सघर्ष को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है।

(iv) नैतिक एवं बौद्धिक उत्थान—नियोजन के आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति में नैतिक एवं बौद्धिक उत्थान का उद्देश्य पूरा होता है। सभी आर्थिक उद्देश्यों के साथ मानव का अपना सर्वांगीण विकास अन्तर्निहित है।



आर्थिक नियोजन के उद्देश्य

**नियोजन के उद्देश्य परस्पर सम्बन्धित व आत्मनिर्भर होते हैं**

यद्यपि आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों को अलग-अलग श्रेणियों—आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं अन्य में—विभाजित किया गया है। इसका अभिप्राय यह नहीं कि ये उद्देश्य एक दूसरे से पूर्णतः पृथक् एवं असम्बन्धित उद्देश्य हों। अल्पकाल में ये उद्देश्य परस्पर विरोधी, या प्रतियोगी हो सकते हैं पर दीर्घकाल में उनका यह भेद कम या समाप्त हो जाता है क्योंकि ये उद्देश्य अधिकतम उत्पादन, पूर्ण रोजगार, सामाजिक समानता तथा राजनैतिक सुरक्षा एक दूसरे से परस्पर सम्बन्धित एवम् आत्मनिर्भर उद्देश्य हैं क्योंकि बिना आर्थिक विकास व पूर्ण रोजगार के आर्थिक समानता व राजनैतिक सुदृढ़ता की कल्पना निरर्थक है और बिना राजनैतिक सुरक्षा के आर्थिक विकास में बाधा आती है। इसी प्रकार आर्थिक विषमता समाप्त किया बिना सामाजिक समानता, वर्ग संघर्ष का समापन तथा शान्ति स्थापित की आशा करना व्यर्थ है। यही नहीं विभिन्न श्रेणियों में रखे गये उद्देश्य भी परस्पर निर्भर हैं अतः प्रत्येक आर्थिक नियोजन व्यवस्था में इन तीनों प्रकार के उद्देश्यों का समावेश होता है पर समय, स्थिति एवं परिस्थितियों के अनुरूप उनके महत्व को निर्धारित किया जाता है। युद्ध व संकट काल में राजनैतिक व आर्थिक उद्देश्यों की प्रमुखता होती है जबकि शान्तिकाल में सामाजिक कल्याण की भावना से प्रेरित योजनाओं में आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की प्रधानता होती है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में इन उद्देश्यों का विवेकपूर्ण समायोजन किया गया है जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि, रोजगार अवसरों में वृद्धि एवं अवसर की समानता, औद्योगीकरण, कृषि का तेजी से विकास, आधार एवं मूलभूत उद्योगों का सुदृढ़ आधार नैयार करना, आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण पर रोक, आदि से सामाजिक न्याय व सुरक्षा प्रदान कर देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने तथा आन्तरिक शान्ति एवं व्यवस्था कायम करना है।

### भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य एवं व्यूह रचना (Objectives & Strategy of India's five Year Plans)

भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक तीनों प्रकार के परस्पर एक दूसरे से सम्बन्धित तथा आत्मनिर्भर उद्देश्यों का समावेश किया गया है। प्रत्येक योजना में समय, स्थिति तथा परिस्थितियों में एकस्यता न होने से उद्देश्यों में भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। योजनावार उद्देश्य निम्न विवरण से स्पष्ट हैं—

#### प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य—

प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत में सदियों की दासता और शोषण से पीड़ित निष्क्रिय अर्थव्यवस्था में जागृति का प्रथम तथा नया प्रयोग था। देश में विभाजन तथा युद्धोपरान्त समस्याएँ भी प्रबल थीं। अतः इस योजना के उद्देश्य दो थे—

(1) द्वितीय विश्व-युद्ध तथा देश में विभाजन से अर्थव्यवस्था में उत्पन्न असन्तुलन को दूर करना, तथा

(2) देश में सर्वांगीण तथा सन्तुलित विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारम्भ करना जिसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार तथा सविधान में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके।

इस योजना में पहला उद्देश्य अल्पकालिक तथा तत्कालीन आर्थिक असन्तुलन की समस्याओं के समाधान से सम्बन्धित है ता दूसरा उद्देश्य दीर्घकालिक तथा सामाजिक एवं आर्थिक ढाँचे में प्रजातांत्रिक ढंग से परिवर्तनों के लक्ष्य से ओत प्रोत है जिससे देश के मानवीय तथा भौतिक साधनों के विकास तथा समुचित उपयोग आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सके तथा समाज में धन की प्राप्ति, आ व्यवस्था तथा सम्पत्ति की अममानताओं को दूर कर सामाजिक सुरक्षा एवं न्याय सुलभ हो सके।

### प्रथम योजना की ब्यूह रचना (Strategy)<sup>1</sup>

सामान्य रूप में ब्यूह रचना (Strategy) शब्द का प्रयोग युद्ध में "मोर्चाबिंदों के लिये प्रयुक्त किया जाता है और यह युद्ध की योजना तकनीकी निश्चित क्रम तथा उपायों से सम्बन्धित है। आधुनिक युग में यह शब्द आर्थिक क्षेत्र में बहुत प्रचलित है जैसे उद्योग ब्यूह रचना, रोजगार ब्यूह रचना, कृषि ब्यूह रचना, योजना ब्यूह रचना निर्यात ब्यूह रचना आदि। जिस प्रकार युद्ध में विजय श्री प्राप्त की जाने के लिये सभी मोर्चों वामपंथी से जमाये जाते हैं ठीक उसी प्रकार आर्थिक नियोजन आर्थिक दुश्मनों-गरीबी, बेकारी, भुलमरी, आर्थिक पिछड़ापन पर विजय पाने तथा आर्थिक सुरक्षा आदि निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों की "मोर्चाबन्दी" की जाती है। इसी प्रकार आर्थिक शब्दावली में आर्थिक योजना के उद्देश्यों प्राथमिकताओं उपायों टैक्नीक आदि के निर्धारण की क्रिया को योजना की "ब्यूह रचना" कहा जाता है। प्रो० लोकनाथ के अनुसार 'ब्यूह रचना' का अर्थ उन उपायों व सामान्य रूप से प्राथमिकताओं के उस क्रम से है जो इच्छित लक्ष्यों व प्राप्त करने के लिये अपनाया जाता है।" "The term Strategy refers to the means and order of priorities in general that should be followed to achieve the desired ends इस प्रकार "योजना ब्यूह रचना" में तीन बातें का समावेश होता है—(i) लक्ष्य निर्धारण (ii) प्राथमिकताओं का क्रम निर्धारण तथा (iii) लक्ष्यों की पूर्ति के लिये उपायों का चयन। ब्यूह रचना में अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों (Crucial Sectors) को ध्यान में रखते हुए स्थिरता व विकास (Growth with Stability) का मार्ग चुनना पड़ता है।

उपयुक्त अर्थ के सन्दर्भ में भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में विकास का

1 Strategy शब्द के हिन्दी रूपान्तर में "ब्यूह रचना" मूलभूत नीति मोर्चाबन्दी, सैली आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

कोई स्पष्ट झूह रचना दृष्टिगोचर नहीं होती है। न तो आय के सम्बन्ध में कोई दीर्घकालीन अनुमान था और न कोई प्राथमिकता का उपयुक्त क्रम। यह तो पूर्व-चालित योजनाओं का एक समूह था और इसीलिये अनेक विद्वानों ने इसे सार्वजनिक व्यय की एक योजना की सजा दी है। योजना के विनियोग के प्रारम्भ में कृषि व सिंचाई विकास को प्राथमिकता दी गई, ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि से खाद्यान्न व कच्चे माल की पूर्ति बढ़ सके और औद्योगीकरण का मार्ग प्रशस्त हो। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आर्थिक समृद्धि तथा उच्च जीवन स्तर के लिये 1952 में सामुदायिक विकास योजना तथा 1953 में राष्ट्रीय सेवा विस्तार कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये। प्रथम योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल वास्तविक व्यय 1,960 करोड़ रुपये हुआ उसमें कृषि, सिंचाई तथा सामुदायिक विकास योजनाओं पर 601 करोड़ रुपये व्यय हुआ। इस प्रकार कुल व्यय का लगभग 33% व्यय हुआ। अगर शक्ति विकास पर व्यय जोड़ दिया जाय तो यह कुल व्यय का 44% भाग था। बेरोजगारी की समस्या के निराकरण के लिये योजना आयोग ने ग्यारह सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया जिसमें सड़क निर्माण, ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन, गृह निर्माण सहायता, सड़क निर्माण, भू-संरक्षण, सहकारिता तथा प्रशिक्षण आदि प्रमुख थे।

### प्रथम योजना में उद्देश्यों तथा झूह रचना का मूल्यांकन

प्रथम योजना, अर्थ-व्यवस्था में विभाजन तथा युद्धोत्तरकालीन असन्तुलन को समाप्त करने में सफल नहीं जा सकती है क्योंकि खाद्यान्न का उत्पादन लक्ष्य से भी अधिक रहा। मुद्रा-स्फीति पर काबू पा लिया। राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय में 11% वृद्धि होने का अनुमान है। पूँजी विनियोग 3 660 करोड़ रुपये हुआ। फिर भी ग्रहण उद्योगों एक खनिज विकास पर कुल योजना व्यय का केवल 4% भाग अद्वैतता को प्रदर्शित करता है। यद्यपि प्रथम योजना में 44 लाख लोगों को रोजगार दिया गया फिर भी योजना के अन्त में 53 लाख लोगों का बेरोजगार होना तथा आर्थिक समानता के स्थान पर आर्थिक विषमता और केन्द्रीकरण की प्रवृत्तियाँ दीर्घकालीन उद्देश्यों की असफलता स्पष्ट करती हैं। प्रथम योजना अनुभवों के अभाव में "TRIAL & ERROR" पर आधारित प्रयास था। संक्षेप में यही कहना न्यायसंगत है कि इस योजना ने हमें अधिक व्यावहारिक, महत्वाकांक्षी तथा दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाने को प्रेरित किया।

### द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य (Objectives)

प्रथम योजना के सफल क्रियान्वयन, देश में औद्योगीकरण की तीव्र लालसा तथा 1954 में कांग्रेस अधिवेशन में समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य से नीति में शान्तिकारी परिवर्तन का संकेत मिला। तदनुसार द्वितीय योजना में उद्देश्य अधिक महत्वाकांक्षी, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक दृष्टि से व्यापक तथा दीर्घकालीन लक्ष्यों से प्रेरित थे। इस योजना में निम्न उद्देश्य थे—

(1) राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि—राष्ट्रीय आय में पाँच वर्षों

में 25°, तथा प्रति व्यक्ति आय में 18°, वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया ताकि देश-वासियों का जीवन स्तर उच्च हो सके।

(2) द्रुत गति से औद्योगीकरण—इसके लिये आधारभूत एवं मूलभूत उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी जिनमें मावों औद्योगीकरण का मुह्य आधार तैयार हो सके।

(3) रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि—वृद्धती बेरोजगारी समाजवादी एवं कम्युनिस्ट अर्थ-व्यवस्था में कलक है और मानव शक्ति के दुरुपयोग का द्योतक है। अतः इस योजना में बेरोजगारी के समापन के लिये श्रम-प्रधान उद्योगों के विकास पर बल दिया गया और योजना काल में कृषि के अनिरिक्त अन्य क्षेत्रों में 80 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा।

(4) आर्थिक विषमताओं में कमी तथा केन्द्रीयकरण पर रोक—समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की स्थापना क सत्त्व को मूर्तरूप प्रदान करने के लिये इस योजना में आय तथा सम्पत्ति की असमानता को दूर करना, आर्थिक शक्तियों के समान वितरण की प्रोत्साहित करना तथा आर्थिक मता के केन्द्रीयकरण पर रोक लगाने के उद्देश्य रखे गए।

योजना आयोग के अनुसार “दूसरी योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत का पुनर्निर्माण करना, औद्योगीकरण की मुह्य नींव रखना, जनता के दक्षिणहीन एवं अधिकारहीन वर्ग को सम्पत्ति का जवमर प्रदान करना तथा देश के सभी भागों का सन्तुलित विकास करना है।” इसमें स्पष्ट है कि द्वितीय योजना के उद्देश्य व्यापक, दूरदर्शितापूर्ण तथा विवेकशील थे जिनमें आर्थिक समृद्धि के लिये आवश्यक पृष्ठभूमि तथा मुह्य आधार तैयार करने के साथ-साथ सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा तथा राजनैतिक स्वायत्त के तत्व निहित थे।

### द्वितीय योजना की व्यूह रचना

उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस योजना में व्यूह रचना अधिक उपयुक्त थी। औद्योगीकरण के लिए 1956 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा तथा औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत और मूलभूत उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई। जहाँ प्रथम योजना में लघु एवं कुटीर तथा बृहत् उद्योगों एवं मजिज विकास पर कुल योजना व्यय का केवल 2% तथा 4% भाग व्यय किया गया वहीं द्वितीय योजना में क्रमशः 4% तथा 20% भाग व्यय हुआ। संचालन क्षति पर कुल व्यय का लगभग 10 प्रतिशत भाग व्यय किया गया। उद्योगों के वित्तीय माधनों की पूर्ति के लिए वित्तीय निगमा की स्थापना की गई। औद्योगिक नीति में राष्ट्रीयकरण के भय का निराकरण कर विदेशी उद्योगपतियों का औद्योगीकरण में सक्रिय योगदान करने की व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय नीति क्षेत्रीय असमानता को दूर करने तथा केन्द्रीयकरण व असाधारण प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण के लिये उचित व्यवस्था की गई। रोजगार के माधनों में वृद्धि के लिये कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास पर बल दिया गया।

1957 में विदेशी विनिमय के संकट का सामना करने के लिये निर्यात सम्पन्न तथा आयात नियन्त्रण की नीति अपनाई गई।

दीर्घकाल में आर्थिक विकास की गति को तेज करने तथा आत्मनिर्भर विकास (Self Sustained Economic Growth or Self Generating Economy) के लिये उद्योगों में लोहा इस्पात, मशीन निर्माण, बिजली का भारी सामान, भारी रसायन आदि के उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और इनके विकास का अधिकाधिक दायित्व सार्वजनिक क्षेत्र पर रखा गया। कृषि एवं सिंचाई विकास को प्राथमिकता में तृतीय स्थान मिला। इन पर कुल व्यय का लगभग 20% भाग व्यय हुआ जबकि परिवहन एवं संचार विकास पर कुल व्यय का 28% भाग व्यय हुआ और उनका प्राथमिकता में द्वितीय स्थान रहा। सामाजिक सेवाओं पर इस योजना काल में प्रथम योजना के मुकाबले व्यय का प्रतिशत 23 से घटकर 18 प्रतिशत ही रह गया।

### द्वितीय योजना के उद्देश्यों तथा व्यूह रचना का मूल्यांकन

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि देश में विकास की गति तेज करने तथा दीर्घकाल में आत्म-निर्भर अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करने के लिए औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता तथा आधारभूत एवं मूलभूत उद्योगों के विकास पर विशेष बल की व्यवस्था तर्कसंगत, व्यावहारिक, उपयुक्त एवं औचित्यपूर्ण थी। उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार में समाजवाद का स्वप्न या तो आर्थिक विपन्नताओं का समापन व्याप्योचित था। मुद्रा स्फीति पर नियन्त्रण तथा रोजगार अवसरों में वृद्धि के लिये लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास का प्रयत्न लाभदायक था। इस योजना के उद्देश्यों में तीनों प्रकार के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों के सामन्तस्य की कोशिश की गई थी और व्यूह रचना का वास्तविक निर्धारण इसी से प्रारम्भ होता है। योजना में उद्देश्यों की पूर्ति आशानुकूल कही जा सकती है फिर भी विफलताओं को भुलाया नहीं जा सकता। ये विफलताएँ निम्न हैं—

(1) आर्थिक विपन्नताओं में वृद्धि—सरकार के प्रयत्नों के बावजूद घन के केन्द्रीयकरण को बढ़ावा मिला तथा एकाधिकारी प्रवृत्तियाँ प्रबल हुईं। प्रो० नकसे, प्रो० वकील, प्रो० ए० के० दास०, प्रो० महसानीबिस समिति आदि के अनुसार समाजवादी समाज की स्थापना कोरी कल्पना रही।

(2) विविध नीतियों के क्रियान्वयन के समन्वय का अभाव—योजना निर्माण कार्य तो प्रबल रहा पर परिपालन पक्ष कमजोर था। प्राथमिकता निर्धारण में विभिन्न मन्त्रालयों, विकास परिषदों और आयोगों में समायोजन का अभाव रहने से क्रियान्वयन में प्रत्याशित सफलता न मिल सकी। कृषि को कम महत्व देना श्रुतिपूर्ण सिद्ध हुआ।

(3) मुद्रा मूल्य नीति का अभाव—प्रथम योजना के अनुभवों को भुलाकर द्वितीय योजना में मूलभूत उद्योगों के विकास तथा हीनार्थ प्रबन्ध की व्यवस्था से

सम्भावित मूल्य वृद्धि के नियन्त्रण के लिये मुद्रा तथा सुनिश्चित नीति का अभाव सबूत का कारण बना।

(4) सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन में असन्तुलन—सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से विस्तार निजी क्षेत्र के लिये कुछ सीमा तक हताहताह का कारण बना। पूँजीगत उद्योगों के उत्पादन तथा उपभोग उद्योगों के उत्पादन में आवश्यकता से कम अंतर न बँट पाया। सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग अधिक हुआ पर हमनी की वृद्धि से चिन्ता बढ़ी।

(5) व्यूह रचना कमजोर रही—इस योजना में प्राथमिकताओं का निर्धारण तथा लक्ष्य का निर्धारण महत्वाकांक्षी सिद्ध हुआ। अपनाया गया Growth Model भी काल्पनिक रहा। जहाँ राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में क्रमशः 25% तथा 18% वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था वहाँ पाँच वर्षों में राष्ट्रीय आय में 20% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% ही वृद्धि हुई। वचन राष्ट्रीय आय के 10% के बजाय 8.5% ही बढ़ी। योजना के क्रियान्वयन में भी आवश्यक समन्वय न होने से प्रगति आशानुबूल न रही।

इस प्रकार द्वितीय योजना के उद्देश्य व्यापक, विवेकशील तथा समाजवाद की स्थापना की ओर महत्वपूर्ण कदम थे। व्यूह रचना में उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता भावी औद्योगीकरण का माग प्रस्तावित करने में आवश्यक थी जिससे अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भर विकास का मुद्रा आधार बन जाये पर लक्ष्यों की पूर्ति न हो पाना दुर्भाग्यपूर्ण था।

### तृतीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य (Objectives)

तृतीय पंचवर्षीय योजना भारत की योजनाओं में देश के सर्वांगीण विकास तथा स्वावलम्बी एक स्वयं सफूत अर्थव्यवस्था के निर्माण का एक लम्बा डग था। इस योजना के उद्देश्य भी समाजवादी अर्थव्यवस्था के निर्माण के तत्वों से प्रेरित थे। इस योजना में द्वितीय योजना के उद्देश्यों के साथ कृषि उपज में वृद्धि तथा खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता का उद्देश्य और जोड़ दिया गया। य उद्देश्य इस प्रकार थे—

(1) राष्ट्रीय आय में वृद्धि—अगले पाँच वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25 से 30 प्रतिशत वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय में 16.6% वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया। पूँजी विनियोग की संरचना को इस प्रकार व्यवस्थित करने का लक्ष्य था जिससे आगे योजनाओं में भी इस विकास दर को कायम रख सकें।

(2) खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता तथा कृषि उपज में वृद्धि—देश में खाद्यान्नों के मायात को कम करने तथा पर्याप्त खाद्यान्न की पूर्ति के लिये खाद्यान्नों के उत्पादन में 30% वृद्धि का लक्ष्य खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से प्रेरित था। कृषि उपज में वृद्धि का उद्देश्य उद्योगों के लिय पर्याप्त सस्ते माल उपलब्ध करने तथा विदेशी व्यापार के लिय अतिरिक्त बढ़ाने के लिये था।

(3) आधारभूत उद्योगों का विस्तार—अर्थव्यवस्था को स्वावलम्बी तथा आत्म-निर्भर बनाने के लिये बुनियादी उद्योग—लोहा, इस्पात, रसायन, बिजली का भारी सामान, मशीन निर्माण, भारी रसायन तथा तेल ईंधन उद्योगों में विकास से औद्योगिक उत्पादन में पाँच वर्षों में 69% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया।

(4) रोजगार के अवसरों में वृद्धि—मानव शक्ति के समुचित उपयोग तथा बेकारी के निराकरण के लिये थम प्रधान योजनाओं को इस प्रकार विकसित करना जिससे पांच वर्षों में 140 लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सके।

(5) श्रम तथा सम्पत्ति की असमानता को दूर करना—समाजवादी समाज की स्थापना के स्वप्न को साकार करने तथा वर्ग-सर्पर्ष की सम्भावनाओं के समापन के लिये एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक, केन्द्रीयकरण पर नियन्त्रण, आर्थिक विषमताओं की कमी तथा आर्थिक शक्ति के अधिक समान वितरण के लिये उचित प्रजातान्त्रिक व्यवस्था करना आदि उद्देश्य थे।

ये उद्देश्य आर्थिक सुदृढ़ता, सामाजिक समानता तथा राजनैतिक स्वतन्त्रता और सुरक्षा में उचित समन्वय के द्योतक तो हैं ही साथ ही व्यापक दूरदर्शितापूर्ण और महत्वाकांक्षी प्रतीत होते हैं। खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता का उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये पुनः प्राथमिकताओं में बरीयता की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

### तृतीय योजना की व्यूह रचना (Strategy)

तृतीय योजना में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये एक ऐसी व्यूह रचना की गई जिससे कृषि अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ आधार, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र का समतुल्य तथा विकास में तकनीकी तथा प्रावधिक विधियों का बढता उपयोग भारतीय अर्थव्यवस्था को स्वावलम्बन तथा आत्म-निर्भरता की ओर अग्रसर कर सके। इसीलिये कृषि को पुनः प्राथमिकता दी गई। साथ ही तीव्र औद्योगीकरण के लिये आधारभूत उद्योगों के विस्तार, विशालकाय तथा लघु उद्योगों में समायोजन, रोजगार अवसरों में वृद्धि तथा शीघ्र उत्पादकता के लिये लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर बल, उपभोग तथा उत्पादक उद्योगों में समन्वय और क्षेत्रीय असमत्तुल्य को दूर करने की नीतियाँ अपनाई गईं। कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का कारण सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि, रसायनिक खादों के उत्पादन तथा उपभोग में वृद्धि, वैज्ञानिक कृषि के लिये उत्तम बीज, सुधरे उपकरण तथा पौध संरक्षण को महत्व दिया गया। उद्योगों की प्राथमिकता में दूसरा तथा परिवहन एवं संचार विकास को तृतीय स्थान दिया गया।

1962 में चीनी आक्रमण तथा 1965 में पाकिस्तानी आक्रमण से योजना व्यूह रचना में सुरक्षा मय विकास (Defence-Cum-Development) का समावेश हुआ। योजना को युद्धोन्मुख (Defence-Oriented) तथा विकासोन्मुख (Development Oriented) बनाया गया। कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में तेजी लाने के साथ साथ प्रतिरक्षा क्षेत्र के उद्योगों में उत्पादन वृद्धि तथा अनुसन्धान एवं विकास की

नीति का अनुसरण किया गया। मूल्यों पर नियन्त्रण के लिये खाद्यान्नों के मूल्यों में स्थिरता, उत्पादन लागतों में कमी, उपयुक्त मजदूरी नीति तथा हीनार्य प्रबन्ध में कमी की व्यूह रचना अपनाई गई। तृतीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रस्तावित व्यय 7 500 करोड़ रुपया था पर वास्तविक व्यय 8,577 करोड़ रुपया हुआ। इसमें से 85% व्यय कृषि-सामुदायिक विकास, सिंचाई तथा विद्युत विकास पर था जबकि उद्योगों के विकास पर कुल व्यय का 23% भाग था।

### तृतीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों तथा व्यूह रचना का मूल्यांकन

तृतीय योजना के उद्देश्य और लक्ष्य जितने महत्वाकांक्षी थे उतने ही विफल तथा निराशाजनक रहे। राष्ट्रीय आय में 25% से 30% की वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त न हो सका। राष्ट्रीय आय में केवल 13% की वृद्धि हुई। कृषि के उत्पादन में वृद्धि बहुत कम थी। अतः खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता की बात तो दूर रही यहां तक कि योजना काल में 1,033 करोड़ रुपय मूल्य के खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा। 1965-66 का वर्ष कृषि उत्पादन की दृष्टि से असामान्य वर्ष था क्योंकि इस वर्ष अभूतपूर्व सूखा तथा पाकिस्तानी आक्रमण से अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई। कृषि उत्पादन में 15% की कमी हुई। खाद्यान्न का उत्पादन जो 1964-65 में 8.9 करोड़ टन था वह घटकर 1965-66 में 8.2 करोड़ टन रह गया। योजनाकाल में 140 लाख अंतरिक्ष लोगों को रोजगार प्रदान करने के बावजूद भी 120 से 160 लाख व्यक्ति बेकार थे।

हीनार्य प्रबन्ध से वित्त साधनों की प्राप्ति के कारण तथा उत्पादन लागतों में वृद्धि के साथ-साथ आक्रमणों के कारण सामान्य मूल्य स्तर में 36% की वृद्धि हुई। कर भार की वृद्धि ने तथा मूल्य स्तर की वृद्धि ने जनसाधारण के जीवन स्तर में वृद्धि एवं सुधार में रुकावट डाली और जीवन सखटपूर्ण हो गया।

देश में सन्तुलित विकास के लिये उद्योगों में विवेकीकरण की व्यूह रचना अपनाई गई थी पर योजना के कार्यान्वयन से क्षेत्रीय विषमताओं में आद्यानुकूल कमी न हो सकी।

सामाजिक उद्देश्य भी अधूरे रहे। धन के वितरण में असमानता की दूर करने के लिये कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। एकाधिकारी प्रवृत्तियाँ और प्रबल हुईं। डॉ० आर० के० हजारी की रिपोर्ट इसका प्रत्यक्ष प्रतीक है।

फिर भी दूसरी ओर दृष्टिपात करने से स्पष्ट होता है कि औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से योजना में सफलता मिली। 5 वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में 62% की वृद्धि हुई। आधारभूत उद्योगों के उत्पादन में 100 से 500 प्रतिशत की वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन में विविधता आई और सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार हुआ। भावी औद्योगिक विकास के लिये देश में आवश्यक मुरब्बा आधार तैयार हो गया जिससे विकास की गति तेज हो सके।



### तीन वार्षिक योजनाओं में उद्देश्य एवं व्यूह रचना (1966-1969)

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष 1965-66 में देश में अभूतपूर्व सूखा पड़ने, दो विदेशी आक्रांती से रक्षा पर व्यय में वृद्धि होने, मूल्य स्तर में निरन्तर वृद्धि, वित्तीय साधनों के अभाव अथवा विदेशी सहायता की अनिश्चितता से अर्थ-व्यवस्था में "कि वर्त्तव्य विमूढम्" की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। साथ ही तृतीय योजना में व्यापक असफलता और औद्योगिक क्षेत्र में शिथिलता ने योजना निर्माताओं को चतुर्थ योजना को सीधे शुरू करने में बाधा उपस्थित कर दी। मई 1966 में अवमूल्यन से स्थिति ओर बिगड़ी। अतः चतुर्थ योजना के स्थान पर वार्षिक योजनाओं का सिलसिला प्रारम्भ हुआ। ये तीन वार्षिक योजनाएँ (1966-67, 1967-68 तथा 1968-69) पंचवर्षीय योजनाओं के बीच अवकाश (Holiday in Planning) कहा जाता है।

इन वार्षिक योजनाओं के मूल में पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लक्ष्य होने व्यापक एवं महत्वपूर्ण नहीं थे जितने तत्कालीन समस्याओं का निराकरण कर चतुर्थ योजना के लिये उचित वातावरण तैयार करना। अतः कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये गहन कृषि को बढ़ावा, कम समय में अधिक उपज देने वाली फसलों को बढ़ावा, लघु सिंचाई योजनाएँ तथा पोष संरक्षण कार्य-क्रमों को प्रोत्साहन दिया गया। उद्योगों में और खास तौर से इन्जीनियरिंग एवं मशीन निर्माण उद्योगों में शिथिलता को समाप्त करने के लिये उपभोक्ता साख को प्रोत्साहन, भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन, निर्यात सम्बर्द्धन, कर्गों में छूट तथा आर्थिक सहायता की नीति अपनाई गई। नहीं चाहते हुए भी हीनार्थ प्रबन्ध में वृद्धि हुई।

सरकार के इन प्रायनों के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में पुनः आशा का संचार हुआ। 1 अप्रैल 1969 से फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को प्रारम्भ करने के लिए उपयुक्त वातावरण बना।

### चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य

योजना आयोग के अनुसार भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के व्यापक उद्देश्य तेजी से आर्थिक विकास के साथ-साथ स्थायित्व (Growth with Stability) तथा सामाजिक न्याय और सामाजिक व आर्थिक प्रजातन्त्र की स्थापना के रूप में निरूपित किये जा सकते हैं।<sup>1</sup>

इन्हीं व्यापक उद्देश्यों के सदर्भ में भारत की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भी स्थायित्व के साथ विकास पर बल तथा समाजवाद का उद्देश्य रखा गया। इन व्यापक उद्देश्यों में अग्र उद्देश्यों का समावेश था —

1 "The broad objectives of Planning could thus be defined as rapid economic development accompanied by continuous progress towards equality and social justice and the establishment of a social economic democracy."

(1) राष्ट्रीय आय में 5.5% वार्षिक वृद्धि—आर्थिक स्थिरता एवं प्रगतिशील आत्मनिर्भरता के लिये चतुर्थ योजना में राष्ट्रीय आय में 5.5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है और 1980-81 तक विकास की दर (Rate of Growth) 6% वार्षिक करने का दीर्घकालीन लक्ष्य था।

(2) स्वावलम्बन एवं स्वयं सफूर्तता—भारतीय अर्थ व्यवस्था को आगामी दस वर्षों में आत्म-निर्भर बनने के लिये कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के उन कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना जिनके क्रियान्वयन से भावी विकास बिना विदेशी सहायता के सम्भव हो सके।

(3) मूल्य स्थायित्व—मूल्य स्थायित्व आर्थिक क्षेत्र की अनिश्चितता व निराशा को समाप्त कर अधिक उत्पादन तथा सहयोग को प्रोत्साहन देता है। अतः जनता को योजनाओं से साभान्वित करने के लिये मूल्य स्थायित्व की नीति का उद्देश्य रखा गया है।

(4) खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता तथा कृषि उपज में वृद्धि—भारत में हरित क्रांति लाकर 1970-71 तक खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता का लक्ष्य रखा गया और कृषि क्षेत्र में उपज में 5% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य था।

(5) जीवन स्तर में वृद्धि तथा उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में द्रुत प्रगति—आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि से ही मूल्य स्थायित्व तथा जीवन-स्तर में सुधार की अपेक्षा की जा सकती है। अतः उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में द्रुत गति से वृद्धि करने का उद्देश्य था।

(6) आधारभूत उद्योगों का विस्तार—रासायनिक, धात्विक, खनिज तथा यातायात और मशीन निर्माण उद्योगों के विकास के लिये प्रचलित कार्यों में तेजी तथा नये कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना जिससे पाँचवी योजना के लिये मुरद आधार तैयार हो जाये।

(7) मानवीय साधनों का विकास एवं समुचित उपयोग—इसके लिये सामाजिक सेवाओं का विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण की वृद्धि तथा समुचित अर्थ-व्यवस्था में रोजगार अवसरों की वृद्धि।

(8) जनसंख्या नियन्त्रण—जनसंख्या पर मात्रात्मक नियन्त्रण के लिये परिवार नियोजन सुविधाओं का तेजी से विस्तार तथा गुणात्मक नियन्त्रण के लिये चिकित्सा सुविधाओं तथा पोष्टिक आहार की व्यवस्था।

(9) सामाजिक न्याय एवं समानता—इसके अन्तर्गत शरीरों की आर्थिक सहायता करने, पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा करने तथा आय एवं सम्पत्ति के केन्द्रीयकरण पर रोक आदि से सामाजिक एवं आर्थिक लोकतन्त्र को मुरद करना।

इस प्रकार चतुर्थ योजना के उद्देश्यों में समाजवाद का स्वप्न सम्मोया गया था जहाँ पहले तीन पंचवर्षीय योजनाओं में मूल्य स्थायित्व, जनसंख्या नियन्त्रण और

उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्यों का समावेश नहीं था, इस योजना में उनको उपयुक्त स्थान दिया गया। इसमें स्थायित्व के साथ विकास (Growth with Stability) को प्रधानता देते हुए सामाजिक एवं आर्थिक लोकतन्त्र की स्थापना के प्रयास का समावेश था।

### चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की व्यूह रचना

भारत में अब तक आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में आई बाधाओं की नई त्रुटियों और संकटों तथा उल्लंघनों के बीच अन्तर को मद्देनजर रखते हुए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विकास की व्यूह रचना अधिक रचनात्मक, विवेकशील और व्यापक थी। स्थायित्व के साथ विकास और सामाजिक समानता व न्याय पर आधारित सामाजिक, आर्थिक लोकतन्त्र का मार्ग प्रशस्त करने के लिये नवीन व्यूह रचना महत्वपूर्ण थी। इस व्यूह रचना की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं—

(1) कृषि उत्पादन में होने वाले उतार-चढ़ाव को रोकने के लिये कृषि में हरित-क्रान्ति की शुरुआत तथा सुरक्षात्मक कार्यों का समावेश था। इसके अन्तर्गत सघन कृषि कार्यक्रमों का तेजी से विस्तार, कम समय में अधिक उपज देने वाली फसलों की बुआई, पौध स लग, लघु सिंचाई साधनों का विकास, रासायनिक खादों का उपयोग, भूमि सुधारों में तेजी तथा उपयुक्त एवं प्राकृतिक प्रयोगों से सुरक्षित क्षेत्रों में कृषि विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना आदि थे। इसके साथ-साथ कृषि में पशुओं के उत्पादन उद्योगों को औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया जैसे खाद उद्योग, कीटनाशक औषधि उद्योग, कृषि उपकरण उद्योग आदि। कृषि एवं 'सिंचाई पर कुल 3815 करोड़ रुपया व्यय की व्यवस्था थी।

(2) खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता के लिये बफर स्टॉक का निर्माण।

(3) मूल्यों में स्थायित्व तथा मुद्रा स्फीति को न बढ़ाते हुए अतिरिक्त आन्तरिक साधन जुटाना।

(4) आत्म-निर्भरता तथा स्वावलम्बन के लिये उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और औद्योगिक विकास पर सार्वजनिक क्षेत्र में कुल व्यय 14,902 करोड़ के प्रस्तावित व्यय में से वृद्धत उद्योगों व खनिज विकास पर 3,338.7 करोड़ तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों पर 293 करोड़ रुपय व्यय का प्रावधान था। इस प्रकार उद्योगों पर कुल व्यय का 24.5 प्रतिशत भाग व्यय का प्रावधान था। धात्विक रासायनिक, धातुमय उद्योगों तथा मशीन निर्माण उद्योगों के विकास को प्रमुख स्थान दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के साथ-साथ निजी उद्योगपतियों व सहकारीता को पर्याप्त प्रोत्साहन देना था।

(5) राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर योजना निर्माण मशीनरी को अधिक सुदृढ करना।

(6) वैक्ति पर प्रभावी सामाजिक नियन्त्रण तंत्रि पूंजी निर्माण एवं पूंजी विनियोग की प्राथमिकताओं के अनुरूप हो सके।

(7) एकाधिकार सम्बन्धी अधिनियम तथा प्रशुभ नीति का उपयोग आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण की समस्या का हल करने के लिये करना ।

(8) सावर्जनिक प्रतिष्ठानों की पूष क्षमता का उपयोग तथा प्रशासन में कुशलता से हानि को कम करना तथा लाभ पर संचालन करना ।

(9) सावर्जनिक क्षेत्र का अधिवाश परिष्वय बल्गाण कार्यक्रमों पर खर्च न होकर अव्यवस्था के निवस अगो के आर्थिक आधार को सुदृढ करने पर खर्च करना था ।

(10) विदेशी सहायता की अनिश्चितता से सुरक्षा के लिये प्रति वर्ष निर्धारित 7 प्रतिशत वृद्धि तथा आयात में द्रुत गति से कमी की नीति भुगतान असन्तुलन को समाप्त कर आत्म निर्भरता की मूलभूत नीति थी ।

**मूल्यांकन**

उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि चतुर्थ योजना की व्यूह रचना अधिक व्यावहारिक तथा उद्देश्यो के निकट थी । इस व्यूह रचना में स्थिरता के साथ विकास (Growth with Stability) तथा राष्ट्रीय आत्म निर्भरता (National Self Reliance) को प्रधानता दी गई । इसमें क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के साथ-साथ समाज के निचले वर्गों को लाभान्वित कर सामाजिक समानता व न्याय का प्रयास निहित था । कृषि और औद्योगिक विकास को परस्पर सम्बद्ध कर विकास में तेजी लाने के प्रयत्नों का समावेश था ।

**पांचवी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य एवं व्यूह रचना** 4

**(Objectives & Strategy of Fifth Plan)**

पांचवी योजना के दो प्रमुख उद्देश्य थे—पहला गरीबी हटाओ तथा दूसरा आत्मनिर्भरता लाना । इन दो व्यापक उद्देश्यों का प्राप्ति के लिये योजना की व्यूह-रचना में निम्न तत्वों का समावेश किया गया ताकि भारत में व्याप्त निर्धनता व गरीबी का उन्मूलन करने तथा आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त किया जा सके ।

(1) कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 5.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि करना, संशोधित योजना में वार्षिक वृद्धि दर 4.37 प्रतिशत निर्धारित की गई किन्तु विकास दर 3.9 प्रतिशत ही रही ।

(2) उत्पादक रोजगार अवसरों का विस्तार,

(3) न्यूनतम आवश्यकताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू करना जिससे अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा, पोष्टिक आहार, गन्दी वस्तुओं का सुधार, देहाती इलाकों में पानी, बिजली आवास व परिवहन व्यवस्था तथा निम्न स्तर की 30 प्रतिशत निर्धन जनता के प्रति व्यक्ति उपभोग को 25 रु० प्रतिमाह से बढ़ाकर 29 रु० प्रति माह करना ।

(4) समाज बल्गाण का व्यापक कार्यक्रम अपनाना ।

(5) कृषि, आधारभूत उद्योगों तथा सामान्य उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों का तेजी से विकास एवं विस्तार।

(6) गरीबों को उचित मूल्यों पर अनिवार्य उपभोग वस्तुओं के सार्वजनिक वितरण एवं प्राप्ति की पर्याप्त व्यवस्था करना।

(7) निर्यात सम्बर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापन के प्रभावी कदम उठाना।

(8) अनावश्यक उपभोग पर प्रभावी नियन्त्रण लगाना।

(9) कीमतों, मजदूरी व बेतन दरो व आयों में समुलन बँटाना तथा।

(11) सामाजिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिये सहायक राजकोपीय एवं अन्य उपायों का सहारा लेना।

“गरीबी हटाओ” तथा “आत्मनिर्भरता लाओ” के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक नीतियों का निर्धारण एवं कार्यान्वयन इस प्रकार किया गया कि १। १५ के साथ विकास हो, निर्यातों से अधिकाधिक विदेशी मुद्रा कमाई जाय तथा आयात साइसेन्स पद्धति की योजना की प्राथमिकताओं के अनुषंग बनाया जाय ताकि विदेशी सहायता की न्यूनतम आवश्यकता के कारण आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त हो सके।

### छठी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य एवं कार्य-नीति

#### (Objectives & Strategy of Sixth Five year Plan)

जनता सरकार न जन आकांक्षाओं व आशाओं की पूर्ति हेतु छठी पंचवर्षीय योजना (1978-83) के प्राप्ति के चार प्रमुख उद्देश्य हैं—

(1) अगले दस वर्षों में बेकारी का निराकरण तथा अर्द्ध-बेकारी में महत्वपूर्ण कमी करना।

(2) जनसंख्या के सबसे गरीब वर्गों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार करना।

(3) इन आय समूहों के अन्तर्गत आने वाले लोगों के लिये राज्य द्वारा बुनियादी आवश्यकताओं—जैसे पीने का पानी, प्रौढ शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण सबके आवास आदि की व्यवस्था करना तथा।

(iv) अधिक समान समाज का निर्माण करना।

इन प्राथमिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सरकार की कार्य-नीति (Strategy) में निम्न बातें उल्लेखनीय हैं—

(क) पिछले समय की अपेक्षा अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास करना।

(ख) आय तथा सम्पत्ति की वर्तमान विषमताओं को पर्याप्त मात्रा में कम करने की दिशा में आगे बढ़ना।

(ग) आत्मनिर्भरता की दिशा में देश की सतत् प्रगति सुनिश्चन करना।

इसके लिये योजना में चार क्षेत्रों—कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योग, समन्वित ग्रामीण विकास के लिये क्षेत्रीय आयोजन तथा न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर देने के लिये कहा गया है।

## पंचवर्षीय योजनाओं में उद्देश्यों की पूर्ति का मूल्यांकन<sup>1</sup> (FULFILMENT OF OBJECTIVES DURING PLANS)

पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों के सकलन से स्पष्ट होता है कि हमारी योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, कृषि का सन्तुलित विकास, शक्ति एवं सिंचाई साधनों में वृद्धि, आधारभूत एवं मूल उद्योगों का विकास औद्योगीकरण में तेजी, रोजगार अवसरों में वृद्धि से बेकारी का निराकरण, छाछालन में आत्मा-निर्भरता, सामाजिक न्याय की दृष्टि से आर्थिक विषमताओं में कमी एवं आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण पर रोक आदि रहे हैं। योजनाबद्ध विकास के पिछले 28 वर्षों से इन उद्देश्यों की पूर्ति निम्न तथ्यों से स्पष्ट होती है।

(1) राष्ट्रीय आय — पिछले 27-28 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 150% तथा प्रति व्यक्ति आय में 50% वृद्धि हुई है जहाँ 1950-51 में राष्ट्रीय आय 9850 करोड़ ₹० तथा प्रति व्यक्ति आय 236 ₹० थी चालू मूल्यों पर 1977-78 में राष्ट्रीय आय 73157 करोड़ ₹० तथा प्रति व्यक्ति आय 1163 ₹० हो गई है।

(2) आर्थिक विकास की दर — जहाँ 1950-51 में आर्थिक विकास की दर 1 प्रतिशत वर्षिक थी वह अब बढ़कर 5% होने का अनुमान है। बचत एवं पूंजी निर्माण की दर भी क्रमशः 5% और 7% से बढ़कर अतः क्रमशः 22% तथा 23 5% होने की सम्भावना है।

(3) कृषि में तीव्र विकास — पिछले 28 वर्षों में कृषि उत्पादन में लगभग 121% की वृद्धि हुई है। खाद्यान्नों का उत्पादन 1950-51 में 55 करोड़ टन से बढ़कर अब 13 करोड़ टन हो गया है। व्यापारिक फसलों के उत्पादन में भी लगभग 170% की वृद्धि हुई है। कृषि विकास की दर 0.5% से बढ़कर अब 4% हो गई है।

(4) सिंचाई एवं विद्युत विकास — कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में सिंचाई के विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है। जहाँ 1950-51 में सिंचित क्षेत्र 208 करोड़ हेक्टर था अब बढ़कर 52 करोड़ हेक्टर हो गया है। इसी प्रकार उद्योगों एवं कृषि में विद्युत के महत्व की ध्यान में रखते हुए विद्युत क्षमता भी 23 किलो वाट से बढ़कर 178-74 मे 270 लाख किलो वाट कर दी गई है। 1982-83 तक सिंचाई क्षमता 684 करोड़ हेक्टर तथा विद्युत क्षमता 440 किलो वाट करने का लक्ष्य है।

(5) औद्योगिक विकास — भारत में योजना बद्ध विकास के 28 वर्षों में औद्योगीकरण का मुहूर्त आधार तैयार हो गया है। आधारभूत एवं मूल भूत उद्योगों के उत्पादन में 400% की वृद्धि तथा रसायनिक उद्योगों में 500% वृद्धि हुई है। औद्योगिक विकास की दर 1950-51 में 2.5% थी वह अब बढ़कर 8 से 10%.

1 अधिक विस्तृत विवरण के लिये जम्मो अग्रवाल "भारत में योजनाबद्ध विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ" शीर्षक में पढ़िये।

वर्षाधिक हो गई है। सार्वजनिक क्षेत्र में भी 155 उपक्रम हैं जिनमें लगभग 13500 करोड़ रु० की पूँजी लगाई। प्रमुख उद्योगों का उत्पादन निम्न तालिका से स्पष्ट है :—

**भारत में औद्योगिक विकास 1950-79**

विवरण	इकाई	1950-57	1978-79
			लक्ष
लोहा-इस्पात	लाख टन	10	88
मशीनरी—	मूल्य लाख रु०	30	13000
एल्युमिनियम	हजार टन	4	310
सीमेन्ट	लाख टन	27	208
पेट्रोलियम पदार्थ	लाख टन	2	270
कोयला	लाख टन	323	1240
सूती कपड़ा	करोड़ मी०	421	950
चीनी	लाख टन	11.3	54
विद्युत क्षमता	लाख kW	23	270

(6) परिवहन एवं संचार — अर्थव्यवस्था में तीव्र विकास के लिए परिवहन एवं संचार विकास का भी पूरा ध्यान रखा गया है और सभी प्रकार के परिवहन साधनों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं यह निम्न तथ्यों से स्वयं स्पष्ट है —

**परिवहन एवं संचार विकास (1950-79)**

विवरण	इकाई	1950-51	1978-79
रेलो की लम्बाई	हजार किलोमीटर	54	61.5
रेलो की माल ढोने की क्षमता	करोड़ टन	9.3	26
जहाजरानी क्षमता	लाख G R T	3.9	55
सतहदार सड़कें	लाख Kms	1.6	60
डाकघर	हजार रु०	36	150
तारघर	संख्या	8205	23000
टेली फोन	लाख	2	27

(7) रोजगार वृद्धि — यद्यपि पिछले 28 वर्षों में विकास प्रयत्नों में लगभग 6.5 करोड़ अनिर्दिष्ट लोगों को रोजगार दिया गया है किन्तु फिर भी देश में बेकारी द्रोपदी के चौर की भाँति बढ़ती जा रही है। छठी योजना में 10 वर्षों में बेकारी को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य है और योजना काल में 4.92 करोड़ मानव वर्ष का रोजगार प्रदान किया जायगा फिर भी 1982-83 के अन्त तक बेकारी 155 लाख मानव वर्ष रहेगी।

(8) आर्थिक समानता एवं सामाजिक न्याय — योजना काल में आर्थिक विषमता घटने के स्थान पर निरन्तर बढ़ी है और आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण हुआ है। अब गरीबों के उत्थान की प्राथमिकता दी जा रही है किन्तु उनसे भी विशेष प्रभाव की उम्मीद करना निरर्थक है।

(9) शिक्षा एवं सामाजिक सेवाओं का तेजी से विस्तार किया गया है — देश में औसत आयु 32 वर्ष से बढ़कर 55 वर्ष हो गई है। साक्षरता भी 16.5 से बढ़कर अब 33 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(10) उपभोग एवं जीवनस्तर — देश के आर्थिक विकास का अनुमान लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि से लगना है। पिछले 24 वर्षों में उपभोग स्तर बढ़ा है और लोगों में परम्परागत दृष्टिकोण के स्थान पर भौतिक समृद्धि की प्रवृत्ति प्रबल हुई है। उपभोग की सुलना के निम्न आंकड़ों जीवन स्तर में सुधार की दशति है —

#### प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुओं की उपलब्धता

विवरण		1950-51	1978-79
खाद्यान्न	(प्रति दिन ग्राम में)	395	460
खाने का तेल	(प्रतिवर्ष किलोग्राम में)	27	34
चीनी	" "	30	75
सूती कपड़ा	(प्रतिवर्ष मीटर में)	110	140
विद्युत-शक्ति	(प्रतिवर्ष किलोवाट)	16	80

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यद्यपि देश में तेजी से विकास हुआ है किन्तु जनसंख्या में तीव्र वृद्धि विकास का लाभ समृद्ध लोगों को ही मिलने तथा बढ़ते मूल्यों के साथ बढ़ती बेकारी के कारण लोगों को विकास के प्रति विशेष रुचि न होकर निराशा महसूस हुई है। यद्यपि देश में सुदृढ़ औद्योगिक आधार तैयार हुआ है, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुए हैं किन्तु क्षेत्रीय असमनता, बढ़ी है। गरीबों और समृद्धिवाज लोगों के बीच विषमता बढ़ी है। औद्योगिक एवं आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण बढ़ा है। अब सामाजिक न्याय नहीं मिल पाता है। आर्थिक समानता कौरी कल्पना रह गयी है। मानव शक्ति के उपयुक्त नियोजन के अभाव में लगभग 4.07 करोड़ मानव वर्षों की बेकारी का ताण्डव नृत्य हो रहा है। अब अधिक प्रभावी नियोजन एवं क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

#### परोक्षोपयोगी प्रश्न मध्य संकेत

1. आर्थिक नियोजन के क्या-क्या उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों की प्राप्ति किस प्रकार परस्पर निर्भर है?

(संकेत—प्रथम भाग में योजना के आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक उद्देश्यों की समताद्वय तथा दूसरे भाग में उनकी परस्पर निर्भरता अध्याय के शीर्षा-नुसार पढ़िये) —

2. भारत में पञ्चवर्षीय योजनाओं के क्या-क्या उद्देश्य रहे हैं तथा उनकी पूर्ति कदा तक सम्भव हुई है? विवेचना कीजिये।



## आर्थिक नियोजन के उद्देश्य

(संकेत—प्रथम भाग में योजनावार उद्देश्यों का उल्लेख कर द्वितीय भाग में मूल्यांकन देना है)

(3) “भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना है।” भारत की योजनाओं के उद्देश्य इस कथन से कहाँ तक मेल खाते हैं ?

(संकेत—प्रथम भाग में “समाजवादी समाज” का अभिप्राय स्पष्ट कर दूसरे भाग में प्रत्येक योजना के उद्देश्यों का विवेचन करना है तथा निष्कर्ष में बताना है कि उद्देश्य हैं तो अनुकूल पर उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाई है)

(4) नियोजन के उद्देश्य स्थायी प्रकृति के होते हैं किन्तु उनका रूप व सन्स्थाए जिनके द्वारा ये उद्देश्य अभिव्यक्ति पाते हैं बदलते रहते हैं” भारतीय नियोजन के उद्देश्यों के सन्दर्भ से इस कथन की पुष्टि कीजिये।

(संकेत—नियोजन के उद्देश्यों का उल्लेख कर दूसरे भाग में बताना है कि वे भारत में समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहे हैं और यही नहीं उनकी प्राथमिकता का क्रम भी बदला है)

(5) “आर्थिक शब्दावली में” व्यूह रचना (Strategy) शब्द का क्या अभिप्राय है ? भारतीय योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या व्यूह रचना अपनाई गई है ?

(संकेत—व्यूह रचना का अर्थ बताकर दूसरे भाग में योजनावार व्यूह रचना बतानी है तथा उनका मूल्यांकन करना है)

## भारत में योजना-निर्माण व योजना तंत्र (PLAN FORMULATION & PLANNING MACHINERY IN INDIA)

आर्थिक नियोजन की जटिल प्रक्रिया को शुरू से अन्त तक अनेक अवस्थाओं से ही नहीं गुजरना पड़ता बल्कि उनके मफल सम्पादन के लिए एक स्थायी नियोजन संगठन की भी आवश्यकता होती है। भारत में भी योजना निर्माण की प्रक्रिया अनेक अवस्थाओं से गुजरती है उसके निर्माण सम्पादन व मूल्यांकन के लिये एक स्थायी नियोजन संगठन के रूप में योजना-आयोग (Planning Commission) है। इनका संक्षिप्त विवरण इस अध्याय में दिया जा रहा है।

### भारत में योजना-निर्माण प्रक्रिया (Plan Formulation Process In India)

भारत में योजना निर्माण का कार्य मुख्यतः योजना आयोग द्वारा किया जाता है और उसकी प्रक्रिया अत्यन्त ही लोचपूर्ण व परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तनशील है। योजना की रूपरेखा तैयार करने से पूर्व राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में तकनीकी व गणितीय अध्ययनों के आधार पर एक दीर्घ-कालीन योजना (Perspective Plan) बनाई जाती है और इसी दीर्घकालीन योजना की पृष्ठभूमि में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण होता है। विकास के भिन्न-भिन्न मापदंडों के तैयार किए जाने हैं जिनमें विशेषज्ञों के कार्यकारी दल तथा उप दल तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक कारोबारों का विश्लेषण कर योजना को व्यावहारिकता प्रदान करने के अनेक परामर्श समितियाँ व समन्वय समितियाँ, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, आर्थिक विकास सस्थान व सावजनिक प्रशासन सस्थाएँ आदि की भी योजना निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। योजना आयोग व राज्यों के बीच समन्वय के लिये 1952 में ही राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Development Council, NDC) की स्थापना की गई। प्रांतीय-स्तर पर योजना निर्माण का कार्य राज्य योजना मण्डल (State Planning Board) अथवा राज्य योजना विभाग करता है।

भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया के अन्तर्गत निम्न अवस्थाएँ (Stages) से गुजरना पड़ता है और योजना का अन्तिम प्रारूप स्वीकृत होने

के बाद ही योजना आयोग उसे कार्यान्वित करने के लिये सरकार को सौंप देता है। वैसे व्यवहार में योजना की अन्तिम स्वीकृति व पूर्व ही उसका कार्यान्वयन प्रारम्भ हो जाता है जैसे भारत की सभी योजनाओं में दृष्टिगोचर होता है।

(1) सामान्य दृष्टिकोण व प्रतिवेदन के लिए विभिन्न अध्ययन दलों का संगठन—सर्वप्रथम योजना आयोग दीर्घकालीन योजना के सन्दर्भ में जायामी योजना के प्रारम्भ होने के दो-तीन वर्ष पूर्व ही अर्थव्यवस्था की तत्कालिक आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक परिस्थितियों के सामान्य अध्ययन के आधार पर आर्थिक विकास व उद्देश्यों सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करता है। इस समन्वित प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए आयोग द्वारा प्रमुख क्षेत्रों के लिए कार्यकारी दल (Working Groups) उप-कार्यकारी दल (Sub-Working Groups) अर्थात् दल उप समितियाँ, अर्थशास्त्रियों के पैनल और विशेषज्ञ दल नियुक्त किये जाते हैं। प्रत्येक दल अपने-अपने क्षेत्र का अध्ययन कर तत्सम्बन्धी क्षेत्र की कमियों व विकास की योजना का प्रतिवेदन तैयार करता है। इन सब समूहों, कार्यकारी दलों, समितियों आदि के प्रतिवेदनों को प्राप्त कर योजना आयोग एक समन्वित व सुनिश्चित प्रतिवेदन तैयार कर उसे राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Development Council) तथा मन्त्रि परिषद् (Cabinet) के निरीक्षण व विचार-विमर्श हेतु प्रस्तुत करता है।

(2) योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा (Draft Outline) तैयार करना—दीर्घकालीन योजना के सन्दर्भ में योजना आयोग विभिन्न अध्ययन दलों व विशेषज्ञ समितियों के समन्वित प्रतिवेदन पर राष्ट्रीय विकास परिषद् व केन्द्रीय मन्त्रि परिषद् द्वारा विचार-विमर्श होने के बाद योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा तैयार करता है। रूपरेखा तैयार करने का कार्य जटिल है। इसके लिये (i) आर्थिक विकास मॉडल (Economic Development Models) तथा विभिन्न सांख्यिकी रीतियों, बजटिंग पद्धति, रैखीय कार्यक्रम प्रणाली (Linear Programming), विभिन्न क्षेत्रों में समन्तुलन बँटाने के तरीकों (Methods of Balances) तथा अन्तर्-उद्योग तालिकाओं (Inter-Industry Tables) आदि का सहारा लिया जाता है। इस प्रकार योजना की प्रारम्भिक रूप रेखा में उसके उद्देश्य, भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है जिसमें राज्यो व केन्द्रीय योजनाओं में समन्वय बँटाकर सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिये एक एकीकृत, समन्वित व सुनिश्चित योजना तैयार हो जाती है।

(3) प्रारम्भिक रूपरेखा की स्वीकृति एवं प्रकाशन—योजना आयोग अपने द्वारा तैयार योजना की प्रारम्भिक रूप रेखा को विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रियों व राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को विचाराय भेजता है। फिर मन्त्रि-परिषद् (Cabinet) इस रूपरेखा पर विचार-विमर्श कर स्वीकृति देती है तत्पश्चात् इसे राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Development Council) की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद् (N D C) द्वारा स्वीकृति देने के बाद योजना आयोग

योजना की रूपरेखा को जनता के सूचनार्थ व विचारार्थ उनकी राय, प्रतिक्रिया व सुझावों के लिये प्रकाशित कर देता है।

(4) प्रारम्भिक रूपरेखा पर विस्तृत विचार-विमर्श—जनमत के लिए प्रकाशित योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा पर देश के प्रबुद्ध विचारक, राजनैतिक दल, व्यावसायिक संस्थान, विश्व-विद्यालय विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, सामाजिक संस्थाएँ तथा अन्य प्रतिनिधि संस्थायें व विचारक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तथा उपयोगी सुझाव योजना आयोग को भेजते हैं और इस योजना आयोग केन्द्रीय मन्त्रियों के सहयोग से राज्य-सरकारों से उसकी राज्य योजनाओं पर विस्तृत विचार-विमर्श करता है। प्रत्येक राज्य के विकास कार्यक्रमों तथा उसके भौतिक व वित्तीय साधना के सम्बन्ध में राजनैतिक एवं विशेषज्ञ स्तर पर विचार-विमर्श किया जाता है और राज्य के मुख्यमन्त्री की सलाह पर आवश्यक संशोधन किया जाता है। विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त उपयोगी व उचित सुझावों को योजना की नवीन रूपरेखा तैयार करते समय विशेष महत्व दिया जाता है।

(5) योजना की नवीन रूपरेखा तैयार करना—विभिन्न स्तरों पर विस्तृत विचार-विमर्श व दौरान प्राप्त उपयोगी सुझावों, प्रतिक्रियाओं तथा जनमत को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग फिर योजना का नवीन प्रारूप तैयार करता है जिसमें योजनाओं के उद्देश्यों, विभिन्न कार्यक्रमों व परियोजनाओं तथा विभिन्न भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के साथ पाथ योजना की व्यूह रचना तथा नीति आदि का विस्तृत उल्लेख होता है।

(6) नवीन प्रारूप पर राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्वीकृति—योजना आयोग योजना की नवीन रूपरेखा तैयार करने के बाद मन्त्रि परिषद् को प्रस्तुत करता है और मन्त्रि परिषद् की अनुमति के बाद उसे स्वीकृति के लिये राष्ट्रीय विकास परिषद् (N.D.C.) के सम्मुख प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद् योजना की इस नवीन रूपरेखा को पुन अध्ययन करती है। संशोधन का सुझाव भी दे सकती है और अन्ततः इस नवीन प्रारूप को स्वीकृति प्रदान कर देती है।

(7) योजना का अन्तिम प्रारूप संसद की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करना—योजना के नवीन प्रारूप पर राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्वीकृति होने के बाद देश का प्रधानमंत्री या योजना मंत्री इस योजना के अन्तिम प्रतिवेदन को संसद में प्रस्तुत करता है। संसद में इस अन्तिम प्रारूप पर कई दिनों तक बहस होती है तथा कुछ छोटे-मोटे संशोधन किये जा सकते हैं पर ऐसे संशोधन नहीं किये जाते कि योजना का सम्पूर्ण प्रारूप ही बदलना पड़े। आवश्यक संशोधनों के बाद संसद योजना को स्वीकृति प्रदान कर देती है। संसद की स्वीकृति के बाद योजना का यह प्रारूप बंधनान्वित रूप ग्रहण कर लेता है और योजना कार्यान्वयन के लिये मान्य हो जाती है। इसलिए संसद की स्वीकृति के बाद योजना का अन्तिम प्रारूप प्रकाशित कर दिया जाता है।

(8) योजना का कार्यान्वयन (Implementation of Plan)—जब योजना सदन की स्वीकृति के बाद वैधानिक रूप ग्रहण कर लेती है तो योजना आयोग उसे कार्यान्वयन के लिये केन्द्रीय व राज्य सरकारों को सौंप देता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि योजना आयोग एक सलाहकार संस्था (Advisory Body) है उसका कार्य योजना का निर्माण करना, समन्वय बैठाना व उसका मूल्यांकन करना है। योजना के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व केन्द्र व राज्य सरकारों का है। अतः केन्द्रीय व राज्य सरकारों के विभिन्न मन्त्रालय व विभाग योजना के क्रियान्वयन व उसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जुट जाते हैं। विभिन्न विभागों व योजना आयोग में योजना के क्रियान्वयन के समय निकट सम्पर्क रहता है ताकि नवीन परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक संशोधन हो सके।

(9) योजना क्रियान्वयन का निरीक्षण व मूल्यांकन (Supervision & Evaluation of Plan Implementation)—योजना की सफलता केवल उसके निर्माण में ही नहीं बल्कि उसके कुशल क्रियान्वयन पर भी निर्भर करती है। अच्छी से अच्छी योजना भी ठीक व कुशलतापूर्वक क्रियान्वित न होने पर असफल हो सकती है अतः योजना के कुशल क्रियान्वयन का समय-समय पर निरीक्षण व मूल्यांकन एक स्वतन्त्र व निष्पक्ष व दक्ष व्यक्तियों की संस्था द्वारा होना आवश्यक है। भारत में योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण व मूल्यांकन करने के लिये योजना आयोग के अन्तर्गत एक विशिष्ट संगठन के रूप में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (Programme Evaluation Organisation) की स्थापना 1952 में की गई है। प्रारम्भ में इस संगठन का कार्य क्षेत्र सामुदायिक विकास योजनाओं के मूल्यांकन तक ही सीमित था पर अब इसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, निरीक्षण व मूल्यांकन करना है तथा उसकी कमियों की ओर ध्यान दिलाना है जैसे तृतीय तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं का मध्यावधि मूल्यांकन इसी संस्था द्वारा किया गया था और उसी के प्रतिवेदनो के आधार पर योजनाओं में आवश्यक हरे-फेरे व संशोधन किये गये थे।

(10) योजना में अनुवर्तन (Follow-up Action)—योजना कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के निरीक्षण व मूल्यांकन प्रतिवेदनो के आधार पर ही योजनाओं में अनुवर्तन का कार्य किया जाता है। संगठन द्वारा निर्दिष्ट कमियों व खामियों को दूर करने का प्रयास तेज किया जाता है। समय व परिस्थितियों के अनुरूप योजना लक्ष्यो, नीति, प्राथमिकताओं व व्यूह-रचना में परिवर्तन कर योजना को कुशलतापूर्वक क्रियान्वित करने के प्रयास तेज किये जाते हैं। विभिन्न मन्त्रालय व विभाग इन संशोधनों व नवीन परिवर्तनों को मूर्त रूप देने में जुट जाते हैं।

भारत में नियोजन-तंत्र अथवा योजना मशीनरी

(Planning Machinery in India)

आर्थिक नियोजन एक निरन्तर चलने वाली जटिल प्रक्रिया है अतः योजनाओं

के निर्माण, क्रियान्वयन व मूल्यांकन करने के लिए दक्ष-विशेषज्ञों, कुशल प्रशासक एवं कर्मचारियों तथा स्वतंत्र व निष्पक्ष निरीक्षण संगठन आदि की आवश्यकता है। इसी कारण 1950 में भारत में योजना निर्माण के लिये आर्थिक नियोजन के एक प्रमुख केन्द्रीय संगठन के रूप में विशिष्ट सत्त्वा “योजना आयोग” (Planning Commission) की स्थापना की गई। इस सत्त्वा के सहयोग के लिये अन्य सत्त्वाएँ भी संगठित की गई हैं। राज्य स्तर पर भी नियोजन की प्रक्रिया का सम्पादन राज्य योजना विभाग अथवा राज्य योजना मण्डल द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय स्तर व राज्य स्तर पर नियोजन तन्त्र का संक्षिप्त विवेचन अलग-अलग इस प्रकार है—

**(A) केन्द्रीय-स्तर पर नियोजन-तन्त्र—भारतीय योजना आयोग (Planning Machinery at Central Level Indian Planning Commission)**

भारत में आर्थिक नियोजन का प्रमुख केन्द्रीय संगठन भारतीय योजना आयोग है जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई। भारत में योजनाओं के निर्माण, समन्वय व मूल्यांकन का कार्य इसी केन्द्रीय सत्त्वा के हाथ में है। इस सत्त्वा के कार्यों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि यह एक सलाहकार एवं समन्वयकर्ता संगठन है तथा योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों की है पर व्यवहार में योजना आयोग एक ऐसे शक्तिशाली संगठन के रूप में प्रकट हुआ है कि इसे विरोधियों द्वारा सुपर कैबिनेट (Super Cabinet) की संज्ञा दी जाती है।

**योजना आयोग के कार्य (Functions of Planning Commission)—** भारतीय योजना आयोग एक स्वतन्त्र केन्द्रीय नियोजन सत्त्वा के रूप में (i) आर्थिक योजनाएँ बनाती है। (ii) देश के समस्त भौतिक व वित्तीय साधनों के प्रभावी उपयोग का सम्बन्धित कार्यक्रम लागू करने का सुझाव देती है। (iii) प्राथमिकताओं का निर्धारण कर (iv) उनके अनुरूप साधनों का आवंटन करती है, (v) प्रगति का निरीक्षण व मूल्यांकन करती है व (vi) आवश्यक सुझाव देती है। इस प्रकार भारतीय योजना आयोग एक सलाहकार व समन्वयकारी सत्त्वा है। योजनाओं के क्रियान्वयन व उनसे सम्बन्धी अन्तिम निर्णय लेने का कार्य केन्द्रीय व राज्य सरकारों का है। योजना आयोग की प्रशासनिक अधिकार नहीं है। योजना आयोग के प्रमुख कार्य भारत सरकार के पारित प्रस्ताव के अनुसार निम्न हैं—

**(1) साधनों का अनुमान एवं सर्वेक्षण (Survey & Assessment of Resources)—**योजना आयोग का प्रथम कार्य देश के समस्त प्राकृतिक, भौतिक, पूँजीगत व मानवीय साधनों का अनुमान लगाना तथा राष्ट्रीय महत्व के अपर्याप्त साधनों की अभिवृद्धि की सम्भावनाओं का सर्वेक्षण करना आदि है। विकास की योजनाओं का निर्माण व उनका सफल कार्यान्वयन इस कार्य के अभाव में कठिन हो जाता है।

**(2) योजना निर्माण करना (Plan Formulation)—**योजना आयोग का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य देश के उपलब्ध साधनों के सर्वोत्तम व सन्तुलित उपयोग की

ऐसी योजनाएँ बनाना है जिससे देश का आर्थिक विकास उद्देश्यों के अनुरूप शीघ्रता से हो सके।

(3) प्राथमिकताओं का निर्धारण (Determination of Priorities)—साधनों की सीमितता व लक्ष्यों की अनन्तता, अनेकता व उनके वैकल्पिक प्रयोगों के कारण योजना आयोग का तीसरा प्रमुख कार्य योजनाओं में प्राथमिकताओं का निर्धारण करना है।

(4) साधनों का आवंटन (Allocation of Resources)—प्राथमिकताओं का निर्धारण करने के बाद वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों का आवंटन करने का कार्य भी योजना आयोग का कार्य है। आयोग साधनों का आवंटन इस प्रकार करने का प्रयास करता है कि कम से कम समय में अधिकाधिक प्रगति सम्भव हो, साधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो और निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करना सुगम हो जाय।

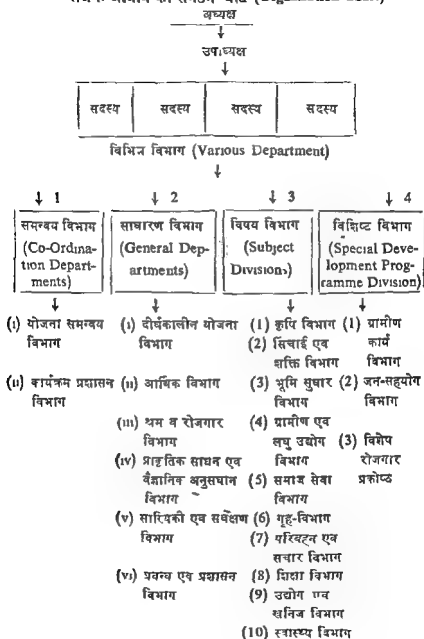
(5) साधक तत्वों का सकेत व विकास की अनुकूल परिस्थितियों का निर्धारण—योजना आयोग का पाँचवा कार्य उन तत्वों तथा घटकों की ओर सकेत देना है जो विकास में बाधक हैं तथा उन बाधक तत्वों के निराकरण की सलाह देने के साथ-साथ योजना की सफलता के लिये आवश्यक आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक परिस्थितियों के निर्धारण का सुझाव देना है।

(6) उपयुक्त योजना तन्त्र का निर्धारण (Determination of Suitable Planning Machinery)—योजना के विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन व क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त नियोजन तन्त्र का निर्धारण भी योजना का एक मुख्य कार्य है।

(7) योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन व समायोजन सम्बन्धी सिफारिशें करना (Plan Evaluation & Adjustment Recommendations)—योजना आयोग केवल योजनाओं का निर्माण ही नहीं करता बल्कि समय-समय पर योजनाओं के क्रियान्वयन की जांच व प्रगति का मूल्यांकन भी करता है और इस निरीक्षण व मूल्यांकन के आधार पर आर्थिक नीतियों, संचालन विधियों में आवश्यक समायोजन की सिफारिश करता है ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन की खामियों, विकास सम्बन्धी रुकावटों को दूर करने के लिये प्रभावी कदम उठाये जा सकें।

(8) कर्तव्य-पालन के लिये अन्य आवश्यक सिफारिशें करना—योजना आयोग उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त ऐसे आन्तरिक व उपयोगी सुझाव देता है जिसके क्रियान्वयन से आयोग को उसे सौंपे गये कार्यों की पूरा करने में सुविधा हो अथवा तत्कालिक परिस्थितियों में आयोग उन सुझावों को आवश्यक समझता हो या केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा सौंपी गयी विशेष समस्या के अध्ययन व तत्सम्बन्धी सिफारिश करनी हो।

## योजना आयोग का संगठन चार्ट (Organisation Chart)



उपपुंक्त विभागों के अतिरिक्त योजना आयोग के अन्तर्गत चार और प्रतिनिधि



विभाग है जो आयोग के आन्तरिक संगठन के भाग न होते हुए भी उसके सहायक के रूप में कार्य करते हैं। और वे नियोजन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं—

(i) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (Programme Evaluation Organisation)—यह सस्या योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का निरीक्षण व मूल्यांकन करती है तथा आवश्यकतानुसार समायोजन का सुझाव देती है यह उन कमियों व खामियों को बताती है जिनके कारण लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा आई है। पहले इस सठन का कार्य केवल सामुदायिक विकास योजनाओं का मूल्यांकन करना था पर अब इसको सभी योजनाओं के मूल्यांकन का काम सौंप दिया गया है।

(ii) परियोजना समिति (Committee on Plan Projects)—यह समिति राज्य सरकारों द्वारा आयोग को भेजी जाने वाली नयी-नयी परियोजनाओं की जांच करती है तथा विचार-विमर्श के बाद अपनी सिफारिस देती है।

(iii) राष्ट्रीय योजना परिषद् (National Planning Council)—यह परिषद् स्वतन्त्र तथा विशेषज्ञों की सस्या है जिनमें 15 से 20 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय योजनाओं में व्यावहारिकता, कुशलता तथा विशिष्टता लाने के लिए इस सस्या में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, तकनीकों व वित्तीय विशेषज्ञों का समावेश होता है। इस सस्या की स्थापना 1965 में की गई।

(iv) अनुसंधान कार्यक्रम समिति (Research Programme Committee)—यह समिति आयोग के कार्य में सहयोग देती है। यह समिति विभिन्न अनुसंधान कार्यों का आयोजन करती है। योजना आयोग का अध्यक्ष इसका भी अध्यक्ष होता है।

### भारत में आर्थिक नियोजन से सम्बन्धित अन्य संस्थाएं

भारत में योजना आयोग के अतिरिक्त कुछ अन्य संस्थाएं भी हैं जो नियोजन के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जिसमें प्रमुख निम्न हैं—

(1) राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Development Council)—यह नियोजन क्षेत्र में केंद्र तथा राज्यों के बीच समन्वय करने वाली संस्था है जिसमें प्रधान मंत्री, राज्यों के मुख्य मंत्री व योजना आयोग के सदस्य इसके सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद् के मुख्य कार्य ये हैं —

(i) आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाली आर्थिक व सामाजिक नीतियों पर विचार-विमर्श करना,

(ii) योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों व उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रभावी तरीकों का सुझाव देना,

(iii) प्रशासनिक कुशलता में वृद्धि के उपायों पर विचार करना तथा कार्य-न्वयन का सुझाव देना।

(iv) राष्ट्रीय योजनाओं के कार्यों का पर्यवेक्षण करना,

(iiiv) जन सहयोग प्राप्त करने के प्रयासों को लागू करने पर विचार करना तथा

(vi) क्षेत्रीय विषमताओं को मिटाकर सन्तुलित विकास का मार्ग प्रशस्त कराना आदि है।

योजना आयोग की प्रारम्भिक रूपरेखा तैयार करते समय भी राष्ट्रीय विकास परिषद् से विचार विमर्श करता है तथा जब नवीन रूपरेखा विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित हो जाती है तभी उसे संसद की स्वीकृत के लिये प्रस्तुत किया जाता है—

(2) सलाहकार संस्थाएँ अथवा पैनल (Advisory Bodies or Panels)—योजना आयोग को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सलाह देने के लिये कृषि, भूमि सुधार, वित्त उद्योग, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास आदि क्षेत्रों में सलाहकार समितियाँ बनाई गई हैं जिनमें 80 लोक सभा सदस्यों की एक सलाहकार समिति का नाम उल्लेखनीय है।

(3) सम्बद्ध संस्थाएँ (Associated Bodies)—योजना आयोग को योजना निर्माण में रिजर्व बैंक तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा आवश्यक सांख्यिकी रचना उपलब्ध हो जाती है।

### योजना आयोग की कार्य-विधि

#### (Working Procedure of Planning Commission).

योजना आयोग की कार्य-विधि बड़ी ही लोचपूर्ण है। पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करने में सर्वप्रथम उद्देश्यों के सन्दर्भ में तकनीकी व श्रेणीय अध्ययनों के आधार पर दीर्घकालीन योजना बनाई जाती है और इस दीर्घकालीन योजना की पृष्ठभूमि में ही आर्थिक मॉडल तैयार किये जाते हैं। देश में जनसंख्या, राष्ट्रीय आय वृद्धि, विनियोग, रोजगार आदि की ध्यान में रखते हुए आयोग विभिन्न क्षेत्रों की अस्थायी योजनाएँ बनाकर उसमें समन्वय एवं सन्तुलन बँठना है। रूपरेखा तैयार करने में अन्तर-उद्योग तालिकाओं बजट प्रणाली, क्षेत्रीय कार्यक्रम तथा तकनीकी बारीकियों का अध्ययन करने के लिये विशेषज्ञों के कार्यकारी दल तथा उप-दल नियुक्त किये जाते हैं। फिर विचार-विमर्श करने के बाद नवीन रूप-रेखा तैयार की जाती है। जिसमें उद्देश्य, लक्ष्य आदि का विस्तृत उल्लेख होता है। यद्यपि आयोग द्वारा किये जाने वाले कार्यों को विभिन्न विभागों में बांट दिया जाता है किन्तु महत्वपूर्ण कार्यों को आयोग सामूहिक रूप से करता है। महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श के लिये सब सम्बन्धित विभागों, प्रभारों व मन्त्रों से राय ली जाती है।

आयोग तथा राज्यों में समन्वय हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद् से नवीन रूप-रेखा पर विचार-विमर्श कर अनुमोदन करवाता है। इस परिषद् में प्रधान मन्त्री, योजना आयोग के सदस्य तथा राज्यों के मुख्य मंत्रियों का समावेश होता है। परिषद्

के अनुमोदन के बाद आयोग योजना के अन्तिम प्रतिवेदन को संसद में प्रस्तुत करता है तथा लम्बी बहस के बाद मामूली संशोधनों के उपरांत समद की स्वीकृति प्राप्त होने पर योजना वैधानिक प्रपत्र बन जाता है तथा उसके क्रियान्वयन के लिये सरकार को सौंप दिया जाता है। योजना के क्रियान्वयन का समय-समय पर मूल्यांकन व निरीक्षण तथा आवश्यक सुझाव का कार्य योजना आयोग का योजना मूल्यांकन संगठन करता है तथा उन सुझावों को लागू किया जाता है। इस प्रकार आयोग के द्वारा योजनायें बनाने की प्रक्रिया का विवरण अध्याय के प्रारम्भ में दिया जा चुका है।

### (B) राज्य-स्तर पर नियोजन-तन्त्र

#### (Planning Machinery at State Level)

भारत में नियोजन की दोहरी प्रक्रिया है। केन्द्रीय स्तर पर नियोजन ऊपर के नियोजन (Planning from Above) है पर राज्य स्तर पर नियोजन नीचे से नियोजन (Planning from Below) का सूचक है : योजना आयोग राज्यों तथा केन्द्रीय योजनाओं के बीच सतुलन बैठाता है और एकीकृत व समन्वित योजना प्रस्तुत करता है।

राज्य स्तर पर नियोजन का कार्य योजना आयोग की भांति राज्य योजना मण्डलों (State Planning Boards) द्वारा किया जाता है जिन राज्यों में योजना मण्डलों की स्थापना नहीं हुई है वहां राज्य का योजना विभाग (State Planning Department) ही इस कार्य को करता है। राज्य के विभिन्न विभागों की सहायता से योजना मण्डल राज्य की योजनायें तैयार करता है, राज्य की सांख्यिकी विभाग आवश्यक आंकड़ें उपलब्ध करता है। राज्यों में योजना मण्डलों के सहयोग के लिये विकास मण्डल (Development Board) तथा योजना सलाहकार समिति (Plan Advisory Committee) कार्य करते हैं। इन दोनों के द्वारा योजना का प्रारूप अनुमोदित हो जाने पर राज्य योजना मण्डल उसे राज्य-विधान सभा की अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता है।

योजना का अन्तिम प्रारूप स्वीकृत होने के बाद यह सरकार के विभिन्न विभागों को क्रियान्वयन के लिये सौंप दिया जाता है। राज्यों की योजना को जिला स्तर पर जिलाधीश अर्थात् जिला विकास अधिकारी (District Development Officers) तथा विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी (Block Development Officer) तथा पंचायत-स्तर विकास पंचायतें कार्यान्वित करती हैं।

### भारत में नियोजन-तन्त्र के दोष व आलोचनायें

#### Defects & Criticisms of planning Machinery in India)

यद्यपि भारत में पिछले 28 वर्षों में आर्थिक नियोजन द्वारा तीव्र आर्थिक प्रगति हुई है। योजना आयोग ने देश में छ. पंचवर्षीय योजनायें तथा तीन वार्षिक योजनाओं (1966-69) के निर्माण व समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है फिर

भी उनकी कार्यप्रणाली व संगठन में कुछ ऐसी कमियां रही हैं जिसके कारण भारतीय नियोजन तंत्र की आलोचना की जाती है। मुख्य आलोचना इस प्रकार है—

(1) नियोजन के लिये एक स्वतन्त्र एवं वैधानिक संस्था का अभाव—भारतीय योजना आयोग का कोई संवैधानिक अस्तित्व नहीं है जैसा कि लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग तथा चुनाव आयोग का है। योजना आयोग की स्थापना एक सरकारी प्रस्ताव के अन्तर्गत हुई है। इस संस्था में सत्ताधारी राजनैतिक पार्टियों का प्रभुत्व रहना है। यह एक सलाहकार व समन्वयकर्ता संस्था है। इसे अपने द्वारा निमित्त योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये राष्ट्रीय विकास परिषद तथा संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना मंत्री उसका सदस्य होता है अतः योजना आयोग को वे अपने मत से काफी प्रभावित कर सकते हैं अतः कभी कभी आर्थिक हितों की राजनैतिक हितों पर बलि चढ़ा देने का भय रहता है।

(2) योजना निर्माण व क्रियान्वयन में समन्वय का अभाव—आयोग एक सलाहकार संस्था है अतः वह केवल योजना का निर्माण करती है जबकि योजना का क्रियान्वयन केन्द्र तथा राज्य सरकारों के हाथ में होता है अलग-अलग कार्य विभाजन से योजना निर्माण व क्रियान्वयन में समन्वय नहीं हो पाता और लक्ष्यों व उपलब्धियों में काफी अन्तर हो जाता है। यही कारण है कि भारतीय योजनायें निर्माण की दृष्टि से कुशल पर क्रियान्वयन की दृष्टि से असफल रही हैं। लक्ष्यों व उपलब्धियों में अन्तराल इसका परिचायक है।

(3) विभिन्न विभागों में समन्वय व परस्पर सहयोग का अभाव—आयोग की स्थापना के बाद उसके विभागों व उप विभागों में इतनी तीव्र गति के वृद्धि हुई है कि उनमें सहयोग व समन्वय बैठना कठिन प्रक्रिया बन गई है। उनके परस्पर विरोधों निर्णय, निर्णयों में विलम्ब तथा समन्वय के अभाव में अकुशलता व पिजूलखर्चों को प्रोत्साहन करता है।

(4) राज्य स्तर पर उपयुक्त नियोजन-तंत्र का अभाव—राज्य-स्तर पर प्रारम्भ में उपयुक्त योजना तंत्र का अभाव होने से राज्यों में योजनाओं का निर्माण पक्ष ढीला रहा है। अब प्रायः सभी राज्यों में राज्य योजना मण्डल स्थापित किये गये हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद केन्द्रीय तथा राज्य योजनाओं में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है फिर भी राज्यों की नियोजन व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण नहीं है अतः विभिन्न राज्यों में काफी अन्तर व विषमताओं की समस्या उत्पन्न हुई है। राज्य सरकारें अपनी योजनाओं को कुशलतापूर्वक कार्यान्वित करने में भी असफल रहती हैं। जिला व ग्राम स्तर पर भी उचित नियोजन व क्रियान्वयन के संगठनों का अभाव है प्रशासनिक अधिकारी ही सर्वोत्तम होकर नियोजन व उसके कार्यान्वयन पथ की व्यवहालता करते हैं। आपातस्थिति की घोरता के बाद स्थिति में काफी सुधार आया है।

(5) भौतिक तथा वित्तीय साधनों में असन्तुलन की समस्या रही है योजना की सफलता भौतिक व वित्तीय साधनों के असन्तुलन में निहित है पर भारत में अब तक के अनुभव यह बताते हैं कि दोनों में काफी असन्तुलन पाया गया है। जिससे विकास की गति अवरुद्ध हुई है। एक दूसरे के सदर्थ में केवल भौतिक लक्ष्यों की परीक्षा करना ही पर्याप्त नहीं वरन् इससे भी अधिक महत्वपूर्ण समस्या उन वित्तीय साधनों की है जो भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं।

(6) विभागीय सम्मिश्रण की समस्या (Problem of over lapping)—योजना आयोग में अब इतने ज्यादा विभाग एवं उप विभाग हो गये हैं कि कार्यों का विभिन्न विभागों में वितरण ठीक-ठीक होना सम्भव नहीं होता। परिणामस्वरूप विभागीय सम्मिश्रण की समस्या उत्पन्न हो गई है यही नहीं राज्यों व केन्द्र व राज्य वित्तीय साधनों के वितरण का कार्य वित्त आयोग तथा योजना आयोग दोनों के हाथ में होने से सम्मिश्रण की समस्या रहती है। इससे उत्पन्न पैदा होती है। कार्यों के संचालन में देरी होती है। एक विभाग अपनी फाइल दूसरे विभाग को सौंपता है जिससे अनावश्यक विलम्ब बढ़ जाता है।

(7) नियोजन तन्त्र के गठन में गड़बड़ी—योजना आयोग का गठन करने में भी स्वार्थी व राजनैतिक हित प्रभावी होते हैं। सदस्यों के लिये कोई निश्चित योग्यता आदि न होने से आयोग के कभी-कभी ऐसे सदस्य भी हो सकते हैं जिन्हें किसी क्षेत्र विशेष का तकनीकी ज्ञान भी नहीं होता। सदस्यों में कार्यों का विभाजन भी कभी-कभी ठीक प्रकार से नहीं किया जाता। सदस्यों की नियुक्ति में भी विलम्ब होता है अतः सदस्यों की अनुपस्थिति में उसका विभागों में कार्य ठप्प हो जाता है। यही नहीं, समय समय पर सदस्यों की संख्या में भी मनमाने ढंग से परिवर्तन होता रहा है। इसके अलावा जब सदस्यों के विभागों में बार बार परिवर्तन किया जाता है तो उत्तरदायित्व निश्चित न होने से कार्य की अवहेलना होती है।

(8) योजना आयोग का बड़ता व्यय—योजना आयोग पर होने वाला व्यय निरन्तर बढ़ता जा रहा है क्योंकि योजना आयोग के आकार व कर्मचारियों की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। 1950-51 में आयोग का कुल व्यय 85.8 लाख रुपये था वह बढ़कर 1960-61 में 8.56 लाख रुपये 1965-66 में 139.6 लाख रुपये अब 3.5 करोड़ से भी अधिक होने का अनुमान है। कर्मचारियों की संख्या भी लगभग 10 गुना हो गई है। इससे फिजूलखर्चों, लालचीताशाही व समन्वय के अभाव की समस्या उत्पन्न हुई है।

(9) राजनैतिक प्रभाव के दुष्परिणाम—यद्यपि सैद्धान्तिक दृष्टि से योजना आयोग को राजनैतिक एवं दलगत भेदभावों से मुक्त रखने की व्यवस्था है पर योजना आयोग में राजनीतिज्ञ सदस्य विशेषज्ञों की बाबाज को दबा देते हैं। 1957 में योजना आयोग के प्रमुख सदस्य डा० मिन्हास का योजना में लक्ष्यों सम्बन्धी मतभेद पर इस्तीफा देना तथा उस इस्तीफा की राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में कोई

प्रतिक्रिया न होने से आशय होता है कि जहाँ विशेषज्ञ आर्थिक दृष्टि से निष्पक्ष व विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं वहाँ राजनीतिज्ञ अपनी सत्ताधारी पार्टी के हितों व राजनैतिक दृष्टिकोण से निर्णय लेते हैं इससे उनमें प्रायः मतभेद होने पर राजनीतिज्ञों के निर्णय विशेषज्ञों के निर्णयों को दबा देते हैं। परिणामस्वरूप योजना के निर्णय वास्तविकता से परे होते हैं।

(10) सालफीताशाही (Red-Tapism)—सरकार के अन्य विभागों की भाँति योजना आयोग के विशाल आकार, कार्य वितरण में सम्मिश्रण, सदस्यों की नियुक्ति में गडबडी आदि से योजना आयोग में भी सालफीताशाही तथा नीकरशाही का बोलबाला है। जहाँ एक ओर योजनाओं को जल्दी ही मूर्त रूप देने तथा उनमें परस्पर समन्वय की आवश्यकता है वहाँ अत्यधिक विलम्ब न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता।

(11) योजनाओं के कार्यान्वयन पहलू की अवहेलना—भारतीय नियोजन तन्त्र का एक सबसे बड़ा दोष यह है कि योजनाओं के निर्माण पक्ष पर तो पर्याप्त ध्यान दिया जाता है पर इन योजनाओं को शीघ्रताशीघ्र कुशलतापूर्वक क्रियान्वित करने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। परिणामस्वरूप लक्ष्यों व उपलब्धियों में काफी अन्तराल रहता है। श्रीमती वारबारा बार्ड के शब्दों में “भारतीय नियोजन योजना निर्माण की दृष्टि से मजबूत रहा है बनिस्पत क्रियान्वयन के। यहाँ के नियोजक चीजों को सोचने में अधिक रहे हैं। अपेक्षाकृत उन्हें किया हुआ देखने में।”

**भारत में नियोजन-तन्त्र के दोषों को दूर करने व सुधार के सुझाव**  
(Suggestions for Improvement & Removal of Defects of Planning Machinery in India)

जब हमने प्रजातान्त्रिक नियोजन प्रणाली को आर्थिक विकास व नियन्त्रण का आधार बनाया है तो योजनाओं के सफल संचालन व क्रियान्वयन के लिये ‘नियोजन तन्त्र’ के दोषों का निराकरण कर उसमें सुधार के निम्न सुझाव विचारणीय हैं—

(1) योजना आयोग को एक स्वतन्त्र सर्वपक्षीय संस्था का रूप प्रदान किया जाना चाहिये—ताकि उसमें राजनैतिक प्रभाव को कम किया जा सके तथा उसके निर्णयों को अन्तिम रूप से लागू करने में सुविधा हो जाये। आर्थिक, वित्तीय व तकनीकी विशेषज्ञों को आयोग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का अवसर मिलना चाहिये।

(2) योजना निर्माण व क्रियान्वयन की कुशलता के लिये आयोग व प्रशासन में निकटतम सम्बन्ध व समन्वय स्थापित करना चाहिये—ताकि लक्ष्यों व उपलब्धियों में तालमेल बैठाना सम्भव हो सके। परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन किये जा सकें।

(3) राज्य स्तर जिला स्तर व ग्राम स्तर पर नियोजन व उसकी क्रियान्वयन की उचित व्यवस्था की जानी चाहिये—यद्यपि अब प्रायः सभी राज्यों में राज्य स्तर पर नियोजन तन्त्र के रूप में राज्य योजना मण्डलों की स्थापना की है पर उनका

अस्तित्व भी योजना आयोग की भांति ही स्वतन्त्र नहीं है। राज्य स्तर पर भी योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिये एक स्वतन्त्र संगठन होना चाहिये। जनता सरकार जिला स्तरीय नियोजन पर जोर दे रही है।

(4) नियोजन-तन्त्र की कार्य-प्रणाली में कुशलता व सुधार किया जाना चाहिये—इसके लिये विभिन्न विभागों में समन्वय बैठायी जाए, भौतिक व वित्तीय साधनों में सन्तुलन बैठाया जाए। कार्य आवंटन में विवेक से काम लेकर दोहरीकरण को रोका जाए। वैकल्पिक योजना प्रस्तुत की जाए ताकि बदलती परिस्थितियों में उसे प्रतिस्थापित किया जा सके। इससे एक ओर सालफोताशाही व नौकरशाही के दुष्प्रभावों को दूर किया जा सकेगा तथा दूसरी ओर नियोजन की कुशलता बढ़ेगी। यही नहीं, सावजनिक क्षेत्र की भांति निजी क्षेत्र की योजनाओं का भी योजना में व्यापक व पर्याप्त महत्व दिया जाए।

(5) योजना-तन्त्र के गठन में व्यापक दृष्टिकोण—योजना आयोग तथा योजना-निर्माण में सलग्न संस्थाओं में सभी वर्गों को निष्पक्ष रूप में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। राजनीतिज्ञों की नियुक्ति मुख्यतः उनकी योग्यता व विशिष्टता पर आधारित होनी चाहिये। योजना आयोग व विभिन्न सदस्यों को विभागों का वितरण उनकी उस विभाग सम्बन्धी योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए तथा उनमें बार-बार जल्दी-जल्दी परिवर्तन न करके निश्चित दायित्व ढालना चाहिए। रिक्त स्थानों को अविलम्ब भरना चाहिये। योजना आयोग में आर्थिक व तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति को प्राथमिकता देनी चाहिये।

(6) राजनैतिक प्रभाव में कमी—योजना आयोग व अन्य सम्बन्धित संस्थाओं में यथा-सम्भव राजनैतिक प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि योजनाओं की वास्तविकता के नजदीक लाने में सुविधा हो। प्रशासनिक सुधार आयोग के मतानुसार तो आयोग में कोई मंत्री सदस्य नहीं होना चाहिये ताकि आयोग आर्थिक दृष्टि पर अधिक उपयुक्त स्वतन्त्र निर्णय ले सके।

(7) आयोग के व्यय में मितव्ययता—भारत जैसे राष्ट्र में वर्तमान परिस्थितियों में योजना आयोग के विस्तृत आकार व बढ़ते कमचारियों से बढ़ता व्यय एक भारी भार है अतः व्यय में मितव्ययता व आकार में यथासम्भव कमी करके विभागीय सम्मिश्रण को रोकना चाहिये। इससे अनावश्यक विलम्ब व सालफोताशाही का भी निराकरण सम्भव होगा।

(8) योजना निर्माण के साथ साथ उसके कार्यान्वयन पहलू को भी महत्वपूर्ण माना जाना चाहिये—क्योंकि योजना की सफलता अन्ततः उनके कुशल क्रियान्वयन पर ही निर्भर करती है। चाहे योजना कितनी ही अच्छी क्यों न हो पर अगर उस योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित न किया जा सके तो सारा उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है अतः कार्यान्वयन पक्ष को सुदृढ़, कुशल व तीव्रगामी बनाना चाहिये।

### परीक्षोपयोगी प्रश्न मय संकेत

(1) भारत में योजनाओं के निर्माण (Formulation of Plans) की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए ।

अथवा

भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कैसे तैयार की जाती हैं और योजना को लागू करने से पूर्व किन-किन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है ?

(संकेत—भारत में योजना निर्माण प्रक्रिया का विवरण अध्याय में दिये गये शीर्षकानुसार दीजिये) ।

(2) भारत में नियोजन-तन्त्र अथवा योजना आयोग का आलोचनात्मक विवरण दीजिये ।

अथवा

भारत में नियोजन-तन्त्र व उसकी कार्य प्रणाली देकर उसके दोषों का उल्लेख कीजिये ।

(संकेत—प्रथम भाग में केन्द्रीय-स्तर पर योजना आयोग तथा राज्य स्तर पर योजना मण्डलों आदि का विवरण, गठन, कार्य-प्रणाली आदि देकर उनके दोषों का उल्लेख करना है) ।

(3) भारत में नियोजन तन्त्र के दोषों की आलोचनात्मक विवेचना कर उसके सुधार के सुझाव दीजिये ।

अथवा

भारत में नियोजन तन्त्र के मुख्य-मुख्य दोष क्या हैं, इनके निराकरण व सुधार के सुझाव दीजिये ।

(संकेत—प्रथम भाग में संक्षेप में भारतीय नियोजन प्रणाली बताकर उसके दोष बताने हैं तथा दूसरे भाग में उनके निराकरण व सुधार के सुझाव अध्याय में शीर्षकानुसार देना है) ।





## 1951 से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन (EXECUTION & EVALUATION OF PLANS IN INDIA SINCE 1951)

भारत में योजनाबद्ध आर्थिक विकास की प्रक्रिया की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से हुई और तब से अब तक देश में चार पंचवर्षीय योजनाएँ तथा तीन वार्षिक योजनाएँ क्रियान्वित की जा चुकी हैं और पाचवी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की पूर्ति के लिये पूरे जोश से प्रयत्न किया जा रहा है। पिछले 27 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि उत्पादन में नास्तिकारी परिवर्तन, औद्योगीकरण का सुदृढ़ आधार और परिवहन साधनों में प्रगति से न केवल समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है बल्कि सामाजिक सेवाओं में विस्तार से कल्याणकारी राज्य एवं समाजवाद की स्थापना का स्वप्न साकार हो रहा है। योजनावार प्रगति का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

### प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-52 से 1955-56) (First Five Year Plan)

प्रथम योजना का निर्माण तत्कालीन आर्थिक असन्तुलन एवं युद्धोत्तरकालीन समस्याओं का समाधान तथा दीर्घकालीन विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिये किया गया। प्रारम्भ में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रस्तावित व्यय 2,069 करोड़ रुपये था पर 1953 में बेरोजगारी के निराकरण के लिए राशि बढ़ाकर 2,356 करोड़ रुपये तथा 1954 में बढ़ाकर 2,378 करोड़ रु० कर दी गई। जबकि वास्तविक व्यय केवल 1960 करोड़ रुपये रहा जो कि कुल प्रस्तावित व्यय का 1/3 प्रतिशत ही था।

उद्देश्य—(i) इस योजना का उद्देश्य विभाजन तथा युद्धोत्तरकालीन समस्याओं—खाद्यान्न तथा कच्चे माल के अभाव, क्षरणाधियों की समस्या को सुलझावा तथा अर्थव्यवस्था में असन्तुलन को दूर करना, तथा

(ii) पूर्ण चालित योजनाओं को पूरा करना तथा देश की अर्थव्यवस्था को इस प्रकार सबल बनाना जिससे भावी आर्थिक विकास द्रुतगति से सुगमतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सके।

**प्राथमिकताएँ—**इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इससे कृषि, सिंचाई एवं विद्युत कार्यक्रमों पर कुल योजना व्यय का 44% भाग निर्धारित किया गया। यातायात एवं सामाजिक सेवाओं को क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान मिला जबकि उद्योगों का प्राथमिकता में अन्तिम स्थान था।

**प्रथम योजना का परिचय—**यह योजना नियोजित विकास में भारत का पहला प्रयास था। अतः सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय 2069 करोड़ रुपये का प्रस्ताव था जबकि वास्तविक व्यय 1,960 करोड़ रुपया रहा जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है—

**प्रथम पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय**  
(करोड़ रुपये)

वर्ग	मूल प्रस्तावित व्यय	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय का प्रतिशत
कृषि एवं सामुदायिक विकास	360	291	15
सिंचाई एवं शक्ति	561	570	29
उद्योग एवं खनिज	174	117	6
परिवहन एवं संचार	497	523	27
सामाजिक सेवाएँ व अन्य	477	459	23
कुल योग	2069	1960	100

**योजना में वित्तीय व्यवस्था—**सार्वजनिक क्षेत्र में किये जाने वाले परिव्यय की वित्तीय व्यवस्था में बटो व रेलों से 752 करोड़ रुपये, अल्प बचत व अन्य श्रृणों से 304 करोड़ रुपये, बाजार श्रृण से 205 करोड़ रुपये, अन्य पूँजीगत प्राप्तियों से 91 करोड़ रुपये जुटाये गये। घाटे की अर्थव्यवस्था से 290 करोड़ रुपये जुटाने का प्रस्ताव था पर इस स्रोत से 420 करोड़ रुपये जुटाये गये। विदेशी सहायता से 188 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इस प्रकार आन्तरिक एवं बाह्य साधनों का अनुपात क्रमशः 90 : 10 रहा।

**प्रथम योजना के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ**  
(Plan Targets & Their Achievements)

प्रथम योजना में योजनाबद्ध विकास के अनुभव के अभाव में लक्ष्य नीचे रखे गये तथा भाग्य से व प्राकृतिक अनुकम्पा से उपलब्धियाँ लक्ष्यों से अधिक रही। पहला प्रयास काफी सन्तोषजनक रहा। यह निम्न तथ्यों से स्पष्ट है—

(1) राष्ट्रीय आय एवं वित्तियोग में वृद्धि—राष्ट्रीय आय में केवल 13% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था जबकि पाँच वर्षों में राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि हुई। उपभोग स्तर में 8 से 9% की वृद्धि

1951 से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन 135

हुई। इस योजना में विनियोग 3660 करोड़ रुपये हुआ। जहाँ 1950-51 में पूंजी निर्माण की दर 5 प्रतिशत थी वह बढ़कर 1955-56 में 7.3 प्रतिशत वार्षिक हो गई।

**कृषि, सिंचाई एवं विद्युत विकास**—योजना काल में कृषि उत्पादन में 1.1 प्रतिशत वृद्धि हुई। खाद्यान्न का उत्पादन जो योजना के प्रारम्भ में 5.5 करोड़ टन था, बढ़कर 1953-54 में 6.8 करोड़ टन हो गया जबकि लक्ष्य 6.5 करोड़ टन ही था। योजना के शुरू में सिंचित क्षेत्र 2.08 करोड़ हेक्टर था वह अन्त में बढ़कर 2.26 करोड़ हेक्टर हो गया। इसी प्रकार कृषि विकास की दर जो पहले 0.5 प्रतिशत वार्षिक थी वह बढ़कर 3.6 प्रतिशत वार्षिक हो गई। विद्युत उत्पादन 23 लाख किलोवाट से बढ़कर 34 लाख किलोवाट कर दिया गया।

(3) उद्योग—इस योजना में औद्योगिक उत्पादन में 40 प्रतिशत वृद्धि हुई। सार्वजनिक क्षेत्र में बड़ी औद्योगिक योजनाओं पर 57 करोड़ रुपये व्यय हुए तथा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, हिन्दुस्तान शिपयार्ड, इन्टीग्रल बोच फैक्टरी, टेलीफोन कारखाना, हिन्दुस्तान केबल्स तथा चित्तोजन लोकोमोटिव, सिन्दरी खाद कारखाना आदि स्थापित किये गए। सीमेन्ट का उत्पादन 27 लाख टन से बढ़कर 46 लाख टन, इस्पात का उत्पादन 9.8 लाख टन से बढ़कर 15.8 लाख टन, चीनी का उत्पादन 11.34 लाख टन से बढ़कर 18 लाख टन से अधिक हो गया। इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में सुदृढ़ आधार की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई।

(4) यातायात एवं संचार—अव्यवस्था के विकास में परिवहन एवं संचार साधनों का विकास आवश्यक है। इस योजना में रेलों की 380 लम्बी लाइनों का निर्माण किया गया। वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। जहाज निर्माण के लिये हिन्दुस्तान शिपयार्ड बनाया गया और जहाजरानी क्षमता 3.9 लाख G.R.T. से बढ़कर 4.8 लाख G.R.T. कर दी गई। 4000 मीटर लम्बी सड़कों को सुधारा गया तथा 636 मील लम्बी राष्ट्रीय महत्व की सड़कों का निर्माण किया गया। संचार व्यवस्था में काफी विस्तार और विकास हुआ।

(5) सामाजिक सेवाएँ—इस मद पर कुल वास्तविक व्यय का 23 प्रतिशत भाग व्यय हुआ। शिक्षा क्षेत्र में प्राथमिक शालाओं की संख्या 2 लाख से बढ़कर 2.8 लाख, मेडिकल कालेजों की संख्या 30 से बढ़ाकर 42, वुनियादी विद्यालयों की संख्या 1,751 से बढ़ाकर 15,800 कर दी गई। अस्पतालों व औपचारिकों की संख्या 8,600 से बढ़ाकर 10 हजार कर दी गई। गृह निर्माण कार्यों पर 135 करोड़ रुपये व्यय हुआ। इसी प्रकार शिशु कल्याण, अन्न प्रदाय तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के प्रयास किये गये।

(6) रोजगार—प्रारम्भ में रोजगार की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया था पर जब 1953 में समस्या विकट हुई तो योजना परिषद की राशि में 308 करोड़ रु० वृद्धि से 5.8 लाख अतिरिक्त लोगों के लिये रोजगार व्यवस्था का प्रावधान

किया गया। प्रारम्भ में 40 लाख लोगों के बेरोजगार होने का अनुमान था। योजना-काल में 75 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया फिर भी योजना के अन्त में 53 लाख लोग बेकार थे।

### प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन

उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में उपलब्धियाँ लक्ष्यों से अधिक रहीं और प्रगति ने भावी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तथा जनता में योजनाबद्ध विकास के प्रति श्रद्धा का सृजन किया फिर भी इसमें अनेक अपूर्णताएँ दृष्टिगोचर हुईं जिनकी कुछ विचारकों ने आलोचना की है—

(1) प्राकृतिक तथा मानवीय साधनों का उचित अनुमान नहीं लगाया गया और लक्ष्य बहुत नीचे निर्धारित किये गए।

(2) योजना राशि के व्यय में असमानता एवं अपूर्णता रही। कुल प्रस्तावित व्यय 7,378 करोड़ २० था पर वास्तविक व्यय, 1,9 0 करोड़ २० ही हुआ अर्थात् 17 प्रतिशत कम हुआ। प्रारम्भिक वर्षों में व्यय कम तथा अन्तिम वर्षों में अधिक व्यय असमानता का द्योतक है।

(3) विदेशी सहायता के लिए 300 करोड़ रुपये उपलब्ध थे पर केवल 188 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता का ही उपयोग हो पाया।

(4) हीनार्थ प्रबन्ध पर अत्यधिक निर्भरता से योजना के अन्तिम वर्षों में मूल्यों में वृद्धि का दौर चला।

(5) उद्योगों की उपेक्षा की गई क्योंकि इस योजना में उद्योगों पर योजना व्यय का केवल 6 प्रतिशत भाग व्यय हुआ और औद्योगीकरण के अभाव में बेरोजगारी की समस्या जटिल हुई।

(6) इस योजना में दीर्घकालीन विकास का जो आशावादी दृष्टिकोण अपनाया गया था वास्तविक तथ्यों पर आधारित न होकर काल्पनिक था। यह वर्तमान स्थिति से स्पष्ट है।

किन्तु इन सब आलोचनाओं के बावजूद प्रथम योजना में आश्चर्यजनक सफलता मिली और मृत प्रायः खर्चव्यवस्था में नये जीवन के संचार से भावी आर्थिक विकास के लिये उचित वातावरण तैयार हुआ।

### द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-57 से 1960-61)

(Second Five Year Plan)

प्रथम योजना की सफलता से देश में समाजवाद की स्थापना के लक्ष्य की पृष्ठभूमि में द्वितीय योजना अधिक बड़ी एवं औद्योगीकरण की प्रमुख योजना के रूप में लागू की गई। इसने उद्देश्य अपेक्षाकृत व्यापक और समाजवाद के अनुकूल थे।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य

(1) राष्ट्रीय आय में पाँच वर्षों में 25 प्रतिशत वृद्धि करना ताकि जनता का रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठ सके।

(2) द्रुतगति से औद्योगीकरण जिसमें आधारभूत उद्योगों के सुदृढ़ आधार पर बल दिया गया ।

(3) रोजगार अवसरों में व्यापक वृद्धि एवं विस्तार ।

(4) आय तथा धन की असमानता में कमी कर आर्थिक सत्ता के समान वितरण की व्यवस्था ।

इन एक दूसरे से परस्पर सम्बन्धित उद्देश्यों को सन्तुलित रूप से प्राप्त करने के प्रयासों की व्यवस्था पर जोर दिया गया ।

### द्वितीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का परिचय

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में 4 800 करोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र में 2,400 करोड़ रुपये परिचय निर्धारित किए गए पर वास्तविक व्यय क्रमशः 4672 करोड़ रुपये तथा 3,100 करोड़ रुपये हुआ । सार्वजनिक क्षेत्र में कुल विनियोग 3,650 करोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र में 3,100 करोड़ रुपये हुआ । यह कुल विनियोग 6,750 करोड़ रुपये प्रथम योजना के विनियोग से लगभग दुगुना था । विभिन्न मंचों पर व्यय का विवरण इस प्रकार है—

### द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का परिचय

(करोड़ रुपये)

मंच	प्रस्तावित	वास्तविक	कुल वास्तविक व्यय
कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	568	520	11
सिंचाई एवं शक्ति	9 3	865	19
उद्योग एवं खनिज	890	1075	24
परिवहन एवं संचार	1385	1300	28
सामाजिक सेवाएँ	945	830	18
विविध	99		
कुल योग	4800	4600	100

प्राथमिकताएँ—यह औद्योगीकरण की योजना थी अतः उद्योगों के विकास को प्राथमिकता में सर्वोच्च स्थान दिया गया । द्वितीय स्थान परिवहन एवं संचार तथा प्राथमिकता में तृतीय स्थान सिंचाई एवं विद्युत विकास को दिया गया । सामाजिक सेवाएँ प्राथमिकता के अन्तिम क्रम में थी । आधारभूत उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी जानी थी ताकि देश में तीव्र औद्योगीकरण के लिए सुदृढ़ आधार तैयार किया जा सके ।

वित्तीय व्यवस्था—द्वितीय योजना का आकार प्रथम योजना के आकार से लगभग दुगुना था । अतः अधिक आय के साधन जुटाने थे । वित्तीय व्यवस्था का ढांचा इस प्रकार रहा—

## द्वितीय योजना में वित्तीय व्यवस्था

विवरण	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय
राजस्व संचयन	800	1002
सार्वजनिक ऋण	1200	1180
अन्य वजेट साधन	400	380
घाट की वित्त व्यवस्था	1200	948
विदेशी सहायता	800	1090
अन्तर-वित्त साधन	400	—
<b>कुल</b>	<b>4800</b>	<b>4600</b>

इसमें 1062 करोड़ रुपये की न्यून करो से आय हुई जबकि चालू राजस्व में 50 करोड़ का घाटा रहा। विदेशी साधना में 190 करोड़ की वृद्धि के कारण हीनार्य प्रवर्ग से 252 करोड़ रु० कम जुटाये गये। आन्तरिक साधन तथा बाह्य साधनों का अनुपात क्रमशः 76 : 24 रहा। 1957-58 में विदेशी विनिमय संकट जटिल हो गया।

### द्वितीय योजना के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ (Plan Targets & Achievements)

द्वितीय योजना में ऊँचे लक्ष्य रखे गये तथा उपलब्धियाँ भी मन्तोपजनक बढ़ी जा सकती हैं। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति निम्न तथ्यों से स्पष्ट है—

(1) राष्ट्रीय आय एवं विनियोग—राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया पर वास्तविक वृद्धि 20% ही रही। प्रति व्यक्ति आय में 15% आय के मुकाबिल 11% वृद्धि रही। राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में विनियोग दर जो प्रारम्भ में 7.3% थी, बढ़कर 11% हो गई। योजनाकाल में कुल मिलाकर 6,750 करोड़ रुपये विनियोग हुआ। इस प्रकार जहाँ प्रथम योजना में विनियोग का वार्षिक औसत 850 करोड़ रुपये था 1960-61 में बढ़कर 1,609 करोड़ रुपये वार्षिक हो गया। राष्ट्रीय आय 10,800 करोड़ रुपये से बढ़कर 13,480 करोड़ रुपये तथा प्रति व्यक्ति आय, में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण केवल 11% ही वृद्धि हुई।

(2) कृषि, सिंचाई, एवं विद्युत विकास—पाँच वर्षों में कृषि उत्पादन में 21.7% की वृद्धि हुई। खाद्यान्न का उत्पादन 1955-56 में 6.5 करोड़ टन से बढ़कर 1960-61 में 8.2 करोड़ टन हो गया जबकि लक्ष्य 7.5 करोड़ टन ही था। भूमि सुधार कार्यक्रमों में तेजी रही। निश्चित क्षेत्र जहाँ पहले 2.26 करोड़ हेक्टर था वह योजना के अन्त में बढ़कर 2.8 करोड़ हेक्टर हो गया। विद्युत उत्पादन 34 किलोवाट से बढ़कर 56 लाख किलोवाट हुआ जबकि लक्ष्य 69 लाख किलोवाट था।

(3) उद्योगों का विकास—1956 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा तथा उद्योगों को विकास में प्राथमिकता देने से औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (1950-51 के आधार वर्ष) 1955-56 के 139 से बढ़कर 1960-61 में 194 हो गया। मशीन उत्पादन और रासायनिक उद्योगों में क्रमशः 400 प्रतिशत तथा 220% वृद्धि हुई। प्रमुख उद्योगों में लक्ष्य तथा प्राप्तियाँ इस प्रकार थी—

उद्योग	इकाई	उत्पादन 1955-56	लक्ष्य (संशोधित)	उपलब्धियाँ 1960-61
1 कोयला	लाख टन	384	600	546
2 इस्पात	"	17	43	35
3 शक्कर	"	17	23	30
4 सीमेंट	"	46	130	80
5 पेट्रोलियम पदार्थ	"	36	57	58
6 मशीन टूल्स	करोड़ रुपये	0.8	5.5	6

इस अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र में तीन स्लो इस्पात कारखाने दुर्गापुर, कर्कला तथा भिलाई में स्थापित किये। नागल व दुर्गापुर में रासायनिक खाद कारखाने खोले। लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास पर 180 करोड़ रुपये व्यय किया गया। नूनमती व बरीनी में तेल शोधक कारखाने तथा खनिज तेल गैस का पता लगाने के लिए प्राकृतिक तेल एवं गैस आयोग की स्थापना की गई।

(4) परिवहन एवं संचार—इस योजना में रेलों के विकास पर 1,044 करोड़ रुपये व्यय से 8 हजार मील रेल लाइनो में सुधार, 1,300 मील लाइनो का दोहरीकरण व 9,500 मील रेलों का विद्युतीकरण किया। सड़क विकास पर 224 करोड़ रुपये व्यय से कच्ची एवं पक्की सड़कों की लम्बाई में क्रमशः 37 हजार तथा 22 हजार मील की वृद्धि हुई। जहाजरानी क्षमता 4.8 लाख GRT से बढ़ाकर 8.6 लाख GRT कर दी गई। डाकघरों की संख्या 1955-56 में 55 हजार थी उसे 1960-61 में बढ़ाकर 77 हजार कर दी गई जबकि लक्ष्य 75 हजार था।

(5) सामाजिक सेवाओं का विस्तार—प्राथमिक एवं तकनीकी शिक्षा तथा उच्च स्तर शिक्षा सुविधाओं में वृद्धि की गई। प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या 1955-56 में 1.8 लाख थी वह 1960-61 में बढ़कर 3.42 लाख हो गई। सभी छात्रों की संख्या जो प्रारम्भ में 3.13 करोड़ थी बढ़कर योजना के अन्त में 4.35 करोड़ तक बढ़ी। अस्पतालों की संख्या 10 हजार से बढ़ाकर 12 हजार कर दी गई। मेडिकल कॉलेजों की संख्या पाँच वर्षों में 42 से बढ़कर 57, आवास गृहों की संख्या में 5 लाख की वृद्धि तथा पिछड़े वर्गों के 4,800 छात्रों को आर्थिक सहायता देना महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ थी।

(6) रोजगार—इस योजना में 80 लाख अतिरिक्त लोगों को गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करने का लक्ष्य था। योजना में कुल मिलाकर 95 लाख अतिरिक्त लोगों का रोजगार दिया गया फिर भी रोजगार के अन्त में 90 लाख व्यक्तियों के बेरोजगार होने का अनुमान था।

### द्वितीय योजना की समीक्षा

द्वितीय योजना में लक्ष्यो के ऊँचा होना पर भी बहुत से क्षेत्रों में अधिक उपलब्धियाँ नहीं पर सामान्य तौर पर प्रगति मन्तोषजनक नहीं रही। राष्ट्रीय आय में 25% के स्थान पर 20% वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय में 18% के बजाय 11% वृद्धि, बैंगरों की समस्या में वृद्धि तथा दोषपूर्ण निम्नीय व्यवस्था से योजना की आलोचना की गई है—

(1) बहुत महत्वाकांक्षी—प्रथम योजना के मुताबिके सार्वजनिक क्षेत्र में दुगुने से भी अधिक व्यय तथा ऊँचे लक्ष्यो का निर्धारण होने में विदेशी विनिमय सफट व ऊँचे मूल्य स्तर निराशा के कारण बने। योजना काल में मूल्य-स्तर में 24% की वृद्धि हुई।

(2) उपभोग उद्योगों की अक्षमता—आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विकास की प्राथमिकता में, उपभोग उद्योगों की अक्षमता हुई। उनके कारण उपभोग वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि में जीवा-न्तर में गुंथार सम्भव न हो सका।

(3) बेकारी की समस्या जटिल—प्रथम योजना में 1060 करोड़ रुपये व्यय में 75 लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार दिया गया जबकि द्वितीय योजना में दुगुनी राशि व्यय करने भी केवल 95 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। योजना के अन्त में 90 लाख लोगों की बेकारी की समस्या निराशा व्याप्त कर रही थी।

(4) दोषपूर्ण वितीय व्यवस्था—विदेशी सहायता तथा हीनार्थ प्रवृत्ति पर अत्यधिक आश्रितता में मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि तथा विदेशी विनिमय सफट उत्पन्न हुआ।

(5) संवैधानिक समाजवाद—द्वितीय योजना में आर्थिक असमानता में वृद्धि, आर्थिक गति व तेजस्वीकरण और सामाजिक नियमताओं में वृद्धि हुई। यह समाज-वादी सिद्धान्त के विरुद्ध रहा।

(6) यातायात एवं गन्तार व्यवस्था के अभाव में औद्योगिक प्रगति में बाधा रही।

(7) विनियोग एवं परिवर्धन लक्ष्य से कम—सार्वजनिक क्षेत्र में कुल वास्तविक व्यय लक्ष्य में 200 करोड़ रुपये कम रहा। इसी प्रकार निम्नीय का लक्ष्य 3,800 करोड़ रुपये था यही वास्तविक विनियोग 3,650 करोड़ रुपये ही रहा।

इस आलोचनाओं के बावजूद यह कहना न्यायसम्मत है कि इस योजना में औद्योगीकरण की प्रगति भावी विकास के लिये मूल्य आधार बनी। देश में विदेशी



1951 से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण, त्रिवान्वयन एवं मूल्यांकन 141

विनियम के सकट और मूल्य-स्तर में अप्रत्याशित वृद्धि से निपटाने के लिये व्यावहारिक एवं प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाया गया है।

### तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-62 से 1965-66)

(Third Five year plan)

भारत में योजनाबद्ध विकास की तीसरी कड़ी के रूप में तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 को लागू हुई। इस योजना का सक्षम भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वरूप-स्फूर्त-अर्थव्यवस्था की स्थापना तथा समाजवाद के स्वप्न को साकार बनाने में योगदान करना था। पिछले अनुभवों तथा दीर्घकालीन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न थे—

#### तृतीय योजना के उद्देश्य (Objectives)

(1) राष्ट्रीय आय में 5 के 6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि से पांच वर्षों में 30% की वृद्धि करना तथा विनियोग के स्वरूप को इस प्रकार बनाना जिससे विकास की दर में वृद्धि हो सके।

(2) छायाश्रम में आत्मा-निर्भरता तथा औद्योगिक कच्चे माल की पर्याप्त पूर्ति के लिये दृष्टि उत्पादन में वृद्धि।

(3) आधारभूत उद्योगों का विस्तार—जिससे भारत आगामी दस वर्षों में अपने साधनों में भावी औद्योगिकरण की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और विदेश : निर्भरता कम हो जाये।

(4) रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि—जिससे देश में उपलब्ध जन-शक्ति 'मयासम्भव पूर्ण' उपयोग हो सके।

(5) आय व सम्पत्ति की असमानता में कमी और केन्द्रीयकरण पर रोक।

इस योजना की एक विशेषता यह थी कि यह योजना दीर्घकालीन विकास कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में तैयार की गई थी। दीर्घकालीन विकास कार्यक्रम में अगली न पंचवर्षीय योजनाओं के लिये राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय और विनियोग दर अनुमान लगाये गये थे। तृतीय योजना इन दीर्घकालीन लक्ष्यों में पहली महत्वपूर्ण की थी।

#### तृतीय पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का परिचय

तृतीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में 7,500 करोड़ रु० तथा निजी क्षेत्र में 1,100 करोड़ रु० व्यय होने का प्रावधान था। इस प्रकार कुल योजना परिव्यय 1,600 करोड़ रु० था उसमें से 10,400 करोड़ रु० विनियोग का उद्देश्य था। तीसरी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक व्यय 8,577.4 करोड़ रु० होने का अनुमान है विवरण इस प्रकार रहा—

## तृतीय पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय

(करोड़ रुपये)

दर	कुल प्रस्तावि व्यय	वास्तविक व्यय	व्यय का प्रतिशत
कृषि एवं सम्बन्ध क्षेत्र	1,068	1089	12.7
सिंचाई एवं बिजली	1,662	1,916	22.4
ग्राम एवं लघु उद्योग	264	241	2.8
बृहत् उद्योग एवं खनिज	1,520	1,726	20.1
परिवहन एवं संचार	1,486	2,111	24.6
सामाजिक सेवाय व विविध	1,300	1,356	15.3
अवशिष्ट माल (Inventories)	200	138	1.6
कुल योग	7,500	8,577	170

उपर्युक्त तालिका के स्पष्ट होता है कि योजना का वास्तविक व्यय प्रस्तावित व्यय से काफी अधिक रहता है और फिर भी योजना में सदस्यों से उपलब्धियाँ बहुत कम थीं। क्योंकि ऊँचे मूल्य-स्तर, देश पर 1962 में चीनी आक्रमण तथा 1965 में पाकिस्तानी आक्रमणों से अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई। 1963-66 के अभूतपूर्व सूखा ने स्थिति को गम्भीर बनाने में योग दिया।

योजना में प्राथमिकताएँ—अर्थव्यवस्था को स्वयं-सफूर्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिये कृषि व सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। कृषि, सिंचाई व शक्ति साधन पर कुल व्यय का लगभग 35% भाग व्यय हुआ। द्वितीय स्थान उद्योगों एवं खनिजों विकास को मिला। प्राथमिकता में तृतीय स्थान परिवहन एवं संचार विकास तथा अन्तिम स्थान सामाजिक सेवाओं को दिया गया।

वित्तीय व्यवस्था—तृतीय योजना में प्रस्तावित व्यय पहली दो योजनाओं के सम्मानित व्यय के भी अधिक था। अतः आय से खर्चों में तीव्रता अपनायी गई। सार्वजनिक क्षेत्रों में वित्तीय व्यवस्था का स्वरूप अग्र तालिका से स्पष्ट है—

## तृतीय पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में वित्तीय व्यवस्था (करोड़ रुपये)

स्रोत	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय
(1) चालू राजस्व में वृद्धि	550	—419 (घाटा)
(2) रेलों का अन्वयान	100	6
(3) सार्वजनिक उपक्रमों में वृद्धि	50	373
(4) अनिश्चित करारोपण	1,710	2,892
(5) अल्प-वृद्धि	600	505
(6) जनता से ऋण (विशुद्ध)	800	823
(7) अन्य पूँजीगत प्राप्तियाँ	540	725
(8) विदेशी सहायता	2,200	2,423
(9) हीनार्थ प्रवृत्ति	550	1,133
योग	7,500	8,577

वित्तीय व्यवस्था का अन्वयान स्पष्ट करता है कि चालू राजस्व में ता 419 करोड़ रुपये का घाटा रहा पर अनिश्चित करारोपण से जहाँ केवल 1,710 करोड़ रु० जुटाना था वहाँ 2,892 करोड़ रुपये जुटाये गये। ठीक इसी प्रकार हीनार्थ प्रवृत्ति का भी अत्यधिक सहारा लेने से अर्थव्यवस्था बहुत मूल्यों के कुचक्र में फँस गई। विदेशी सहायता पर भी अधिक धन प्राप्त हुआ। इन सबका भार साधारण जनता के लिये असह्य हो गया था पर राष्ट्रीय भावना में त्याग किया गया।

### तृतीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

यद्यपि तृतीय योजना में लक्ष्य ऊँचे रखे गये पर योजना के क्रियान्वयन में बाधाएँ उपस्थित होने तथा विदेशी आक्रमणों का मुकाबला करने से उपलब्धियाँ बहुत कम रही जहाँ तक कि निराशा व्याप्त हो गई। विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य एवं उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण निम्न है—

(1) राष्ट्रीय आय विनियोग एवं प्रति व्यक्ति आय—तृतीय योजना में राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में क्रमशः 30% तथा 1 % वृद्धि का लक्ष्य था ताकि राष्ट्रीय आय (1960-61 के मूल्यों पर) 14,500 करोड़ रुपये से बढ़कर 19,000 करोड़ रुपये तथा प्रति व्यक्ति आय 330 रुपये से बढ़कर 385 रुपये हो जाये। पर योजना के अन्त में राष्ट्रीय आय 15,930 करोड़ रुपये तथा प्रति व्यक्ति आय 325 रुपये ही थी। राष्ट्रीय आय में जहाँ पाँच वर्षों में 3 % वृद्धि का लक्ष्य था वहाँ राष्ट्रीय आय में 5 सालों में 13.8% वृद्धि हुई जबकि प्रति व्यक्ति आय में 5.3% की वृद्धि हुई।

विनियोग में वृद्धि हुई। जहाँ 1960-61 में विनियोग का आर्थिक औसत 1,600 करोड़ रुपये था वह 1965-66 में बढ़कर 2,600 करोड़ रुपये वार्षिक हो गया। इस तरह विनियोग दर राष्ट्रीय आय के 11% से बढ़कर 14.15% हो गई। वचन दर भी 8.5% से बढ़कर 11.4% हो गई।

(2) कृषि सामुदायिक विकास एवं सिंचाई विकास—इस योजनाकाल में कृषि उत्पादन में 16% की वृद्धि हुई। खाद्यान्न का उत्पादन लक्ष्य 10 करोड़ टन था पर 1964-65 में खाद्यान्न का उत्पादन 8.9 करोड़ टन पहुँचकर 1965-66 में 7.2 करोड़ टन ही रह गया। 1965-66 में अभूतपूर्व सूखे के कारण कृषि उत्पादन सूचकांक (1964-65 में 158 से) घटकर 131 ही रह गया। कृषि उत्पादन गन्ने के अलावा सभी फसलों का लक्ष्य से कम उत्पादन रहा। सिंचाई योजनाओं में निश्चित क्षेत्र 2.8 करोड़ हेक्टर में बढ़कर 3.22 करोड़ हेक्टर हो गया।

(3) उद्योग एवं खनिज विकास—योजना में उद्योग एवं खनिज विकास पर 1520 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान था पर वास्तविक व्यय 1,726.3 करोड़ रुपये रहा। इसमें अलावा नष्ट एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर 240.8 करोड़ रु० व्यय हुआ। इस प्रकार कुल योजना व्यय का 24% भाग उद्योगों पर व्यय हुआ। योजनाकाल में औद्योगिक उत्पादन में 11% संचयी वृद्धि का लक्ष्य रखा गया जबकि वास्तविक वृद्धि 8% वार्षिक ही रही। 1960-61 के आधार वर्ष पर 1965-66 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 182 हो गया। आधारभूत उद्योगों में उत्पादन वृद्धि की दर 15 से 16% वार्षिक रही। प्रमुख उद्योगों में उत्पादन वृद्धि इस प्रकार से रही—

#### प्रमुख उद्योगों में उत्पादन

उद्योग	इकाई	1960-61 (वास्तविक)	1965-66 लक्ष्य	वास्तविक उत्पन्नियमा
लोहा स्पात	लाख टन	23	68	48
मीसट	लाख	80	130	108
मशीनरी	करोड़ रु०	7	30	20
विद्युत शक्ति	लाख k.w.	56	127	102
एल्यूमिनियम	हज़ार टन	18	80	62
खनिज तेल	लाख टन	58	102	99
कोयला	लाख टन	546	970	680

उपमूल्य तालिका से स्पष्ट है कि वास्तविक उत्पादन लक्ष्य से काफी नीचे रहे। इससे कारण विदेशी विनियम की कमी, कच्चे माल का अभाव, शक्ति की कमी, दो आयननों से बने पुर्जों व मशीनों के आयातों तथा विदेशी महापता का अवरोध हो जाता आदि हैं। फिर भी उत्पादन में वृद्धि सन्तोषजनक रही और आधार-

1951 से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन 145

भूत उद्योगों के विकास से भावी औद्योगीकरण के लिये मृद्व आधार तैयार हुआ। चीनी का उत्पादन लक्ष्य को पार कर गया। लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास की पर्याप्त सुविधाओं का विस्तार किया गया और उनके अलावा उपभोग वस्तुओं का भी उत्पादन बढ़ा।

(4) परिवहन एवं संचार विकास—इस योजना में परिवहन एवं संचार पर 2,110.7 करोड़ रुपये व्यय किया गया। परिणामस्वरूप प्रगति सतोपजनक रही। योजनाकाल में रेलों की माल ढोने की क्षमता 15.6 करोड़ मीट्रिक टन से बढ़कर 20.30 करोड़ मी० टन हो गई। सड़कों के विकास से पक्की सड़कों की लम्बाई 1.44 लाख मील से बढ़कर 1.69 लाख मील हो गई अर्थात् 25 हजार मील की वृद्धि हुई। जहाज रानी क्षमता 9 लाख GRT से बढ़कर 15 लाख GRT हो गई।

संचार साधनों में भी विकास हुआ। योजना के अन्त में देश में 98 हजार डाक घर, 8,800 तार-घर और 8,75 लाख टेलीफोन उपलब्ध थे।

(5) सामाजिक सेवार्थ—शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं सामाजिक सेवाओं पर 1,300 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान था पर वास्तविक व्यय 1,355 करोड़ रुपये हुआ। शिक्षा पर 600 करोड़ रुपये व्यय से स्कूलों की संख्या 4 लाख से बढ़कर 5 लाख तथा विद्यार्थियों की संख्या 4.5 करोड़ से बढ़कर 6.8 करोड़ हो गई। अस्पतालों की संख्या में 2000 की वृद्धि हुई। परिवार नियोजन केन्द्रों की संख्या 1649 से बढ़कर 1965-66 में 11,474 हो गई। तीन नये मेडिकल कालेज खोले गये। पिछड़ी जाति कल्याण पर 102 करोड़ रु० और गृह निर्माण योजनाओं पर 110 करोड़ रु० व्यय किया गया।

(6) रोजगार—तृतीय योजना के पाँच वर्षों में ग्रँर कृषि तथा कृषि क्षेत्र में क्रमशः 105 लाख तथा 35 लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य था। योजना काल में कुल 145 लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार दिया गया फिर भी योजना के अन्त में 140 लाख लोग बेकार थे।

### तृतीय पंचवर्षीय योजना की आलोचना एवं मूल्यांकन

तृतीय योजना के आकार, विनियोग एवं असफलता के कारण उसकी कुछ विचारकों ने आलोचना की है। उपयुक्त उपलब्धियों के तथ्यों के साथ-साथ आलोचना के आधार पर समीक्षा के लिये आलोचनाओं पर ध्यान देना आवश्यक है।

(1) समाजवाद के निश्चित आदर्शों का अभाव—योजना में समाजवाद के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट निर्देशों का अभाव तथा आय की असमानता की समाप्ति को उद्देश्यों में अन्तिम स्थान देना समाजवाद का कोरा ढोंग मात्र था।

(2) स्पष्ट मूल्य नीति का अभाव—मूल्यों में 7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि ने समूची अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया। अगर मूल्य नीति को सही रूप से क्रियान्वित किया जाता तो जन-साधारण को संकट न झेलना पड़ता।

## तीन वार्षिक योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र व्यय

(करोड़ रुपये)

विवरण	अनुमानित व्यय
(1) कृषि, सिंचाई एवं सम्बद्ध क्षेत्र	1481
(2) विद्युत शक्ति	1127
(3) उद्योग एवं खनिज	1722
(4) परिवहन एवं संचार	1302
(5) शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवाएँ	1160
कुल योग	6792

इन वार्षिक योजनाओं में कृषि व सिंचाई विकास को प्राथमिकता दी गई पर साथ ही उद्योगों के विकास को भी महत्व दिया गया। विदेशी सहायता पर आश्रितता घटने तथा भुगतान असंतुलन को देखते हुए 1966 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ा।

## तीन वार्षिक योजनाओं में उपलब्धियाँ

(Achievements)

तीन वार्षिक योजनाओं में अर्थव्यवस्था को इस प्रकार गतिशील किया गया कि प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर आर्थिक विकास को नियोजित ढंग से द्रुतगति से समाजवाद की ओर अग्रसर कर सके। तीन वर्षों में ही चतुर्थ योजना को चालू करने का आवश्यक एवं उचित वातावरण तैयार हो गया। विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति का संक्षिप्त विवरण यह है—

(1) कृषि, सिंचाई एवं सम्बद्ध क्षेत्र—1965-66 तथा 1966-67 के सूखे के बाद 1967-68 में कृषि उत्पादन में आश्चर्यजनक प्रगति हुई। 1968-69 में खाद्यान्न का उत्पादन 1965-66 के 72 करोड़ के मुकाबले बढ़कर 94 करोड़ टन हो गया। मिनचिन क्षेत्र इसी अवधि में 32 करोड़ हेक्टर से बढ़कर 36 करोड़ हेक्टर हो गया। कृषि में नवीन व्यूह रचना से वैज्ञानिक कृषि का अनुसरण कर रासायनिक उर्वरकों, उत्तम बीजों तथा पीथ संरक्षण कायों में तेजी गयी।

(2) औद्योगिक, खनिज एवं विद्युत विकास—1966 व 1967-68 में औद्योगिक शिपिंग को समाप्त करने के लिए सरकार ने रियायतें दी, आर्थिक सहयोग प्रदान किया। परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (1960-61 के आधार पर) 150 हो गया। विद्युत क्षमता 102 लाख Kw में बढ़कर 145 लाख Kw, गीमेट का उत्पादन 104 लाख टन से 125 लाख टन, इस्पात का उत्पादन 46 लाख टन से 65 लाख टन, मशीनों का मूल्य 20 करोड़ रुपये से बढ़कर 25 करोड़ रुपये तथा खनिज तेल का उत्पादन 97 लाख टन से बढ़कर 161 लाख टन हो गया। इस प्रकार उद्योगों में भी प्रगति अच्छी रही।

(3) यातायात एवं संचार—तीन वार्षिक योजनाओं से पक्की सड़कों की लम्बाई में 29 हजार किलोमीटर, जहाजरानी क्षमता में 6 लाख GRT की वृद्धि हुई। रेलों तथा संचार व्यवस्था का विकास मन्द रहा।

(4) सामाजिक सेवार्थ—शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति सन्तोषजनक रही। सामान्य शिक्षा में छात्रों की संख्या में तीनों वर्षों में एक करोड़ की वृद्धि हुई। स्वास्थ्य सेवकों का विस्तार हुआ। पिछड़ी जाति के कल्याण-कार्यों, जल-प्रदाय योजनाओं और पिछड़ी जाति के लोगों के कल्याण कार्य किये गये।

(5) राष्ट्रीय आय, बचत एवं रोजगार—इस अवधि में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि धीमी गति से होने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि न हो सकी। केवल 1967-68 में अच्छे मानसून से पहली बार राष्ट्रीय आय में 9% की वृद्धि हुई। विनियोग व बचत की दर में कमी हुई, जहाँ 1965-66 में बचत व विनियोग की दरें राष्ट्रीय आय का क्रमशः 10.4 तथा 13.8 प्रतिशत भाग था वह 1968-69 में घटकर क्रमशः 8.5 तथा 11.5 प्रतिशत ही रह गयी। रोजगार के अवसरों में वृद्धि असन्तोषजनक रही। नवभागान्तुकों के आगमन से 1968-69 के अन्त में बेकारी की संख्या 3.5 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया।

इन तीन वार्षिक योजनाओं में विकास की गति मन्द रही। सक्रिय नीतियों का अभाव रहा। वित्तीय साधनों के अभाव में नये कार्यक्रमों को हाथ में न लेकर पुरानी परियोजनाओं को समाप्त करने की चेष्टा की गई। 1966-67 तथा 1968-69 सूखा स्थिति, 1967-68 में उद्योगों में शिथिलता, मूल्यों में निरन्तर वृद्धि, बेकारी की समस्या में वृद्धि आदि कठिन परिस्थितियों से निपटारने में वार्षिक योजनाएँ महत्वपूर्ण थीं। □

## चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (FOURTH FIVE YEAR PLAN)

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तृतीय योजना की समाप्ति के तुरन्त बाद 1 अप्रैल, 1966 को प्रारम्भ होने वाली थी पर अर्थव्यवस्था में वित्तीय साधनों की अनिश्चितता, विदेशी सहायता की सदृग्धता, 1965-66 में अभूतपूर्व सूखा, मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि औद्योगिक क्षेत्र में स्थिरता (Recession) आदि अनेक कारणों से चतुर्थ योजना को स्थगित कर दिया गया और उसके स्थान पर तीन वार्षिक योजनाएँ (1966-69) कार्यान्वित की गईं। जब (1968-69) के अन्त तक अर्थ-व्यवस्था में चतुर्थ योजना के शुभारम्भ के लिये उपयुक्त वातावरण बना तो 1 अप्रैल 1969 से चतुर्थ योजना प्रारम्भ की गई। चतुर्थ योजना का मूल प्रस्तावित परिव्यय 24398 करोड़ रु० होने का प्रावधान था पर 18 मई 1969 को ससद में प्रस्तुत किये गये अन्तिम प्रलेख के अनुसार चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल में सशोधित परिव्यय 24882 करोड़ रुपये होने का प्रावधान था जिसमें से 15902 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र में तथा 8980 करोड़ रुपये निजी क्षेत्र में व्यय होने का अनुमान था।

### चतुर्थ योजना के प्रमुख उद्देश्य (Main Objectives)

चतुर्थ योजना के प्रमुख उद्देश्य—(1) स्थायित्व के साथ विकास, (2) सामाजिक न्याय एवं आर्थिक समानता की ओर निरन्तर अग्रसर होना, (3) क्षेत्रीय असन्तुलन का समापन, (4) रोजगार अवसरों में वृद्धि, (5) निर्यात सम्बर्द्धन तथा (6) आत्म-निर्भरता का मार्ग प्रशस्त करना था। इसके लिये अर्थव्यवस्था में आवश्यक सत्यागत परिवर्तन लाने पर भी जोर दिया गया था।

इन व्यापक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये योजना की व्यूह रचना में निम्न तत्वों का समावेश किया गया—

(i) राष्ट्रीय आय में 5.5% की दर से वार्षिक वृद्धि करना ताकि 1980-81 तक विकास की दर 6% वार्षिक हो जाय और देश आर्थिक स्थिरता के साथ प्रगति और आत्म निर्भरता की ओर अग्रसर हो सके।

(2) कृषि उत्पादन में 5.6% वार्षिक वृद्धि तथा 1970-71 तक खाद्यान्न में आत्म निर्भरता प्राप्त करना।

(3) जनसंख्या पर प्रभावी नियन्त्रण।



(4) उद्योगों के क्षेत्र में 8 से 10% वार्षिक वृद्धि तथा आधारभूत उद्योगों का तेजी से विकास ।

(5) प्रतिरक्षा एवं आर्थिक स्वावलम्बन हेतु घातुओं, मशीनों, रसायनों, मिजली आधारभूत उद्योगों का निरन्तर विकास ।

(6) मानवीय साधनों के विकास के लिये सामाजिक सेवाओं का विस्तार, रोजगार अवसरों में वृद्धि तथा सामाजिक न्याय प्राप्ति की दिशा में प्रगति ।

(7) आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण एवं उचित वितरण व्यवस्था ।

(8) ग्रामीण जनता तथा समाज के कमजोर वर्गों को विकास योजनाओं से अधिकारिक लाभ पहुंचाना ।

### चतुर्थ योजना का कुल परिव्यय (Total Outlay)

चतुर्थ योजना में कुल 24882 करोड़ रुपये व्यय होने का प्रावधान था जिसमें 15902 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र में तथा 8980 करोड़ रुपये निजी क्षेत्र में व्यय होने थे पर योजना के अन्तिम अनुमानों के अनुसार कुल परिव्यय 25754 करोड़ रुपये हुआ जिसमें 16774 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र तथा लगभग 10,000 करोड़ रुपये निजी क्षेत्र में व्यय हुए । चतुर्थ योजनाकाल में उत्पादक परिसम्पत्तियों के निर्माण पर 22635 करोड़ रुपये विनियोग करने का प्रावधान था । पर योजनाकाल में कुल विनियोग 22654 करोड़ रुपये होने का अनुमान था । चतुर्थ योजना के सार्वजनिक क्षेत्र का प्रस्तावित व्यय तथा वास्तविक व्यय को निम्न तालिका में दर्शाया गया है—

चतुर्थ योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रस्तावित एवं वास्तविक परिव्यय (Outlay)

विवरण	प्रस्तावित परिव्यय (करोड़ रुपये)	वास्तविक व्यय (करोड़ रुपये)	कुल का प्रतिशत
कृषि एवं सामुदायिक विकास	2728	3466	20.7
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	1087		
विद्युत	2448		
ग्रामाण एवं लघु उद्योग	293	3729	22.2
उद्योग एवं संचार	3338		
परिवहन एवं सैनिक	3237		
व्यापार एवं सप्लाइ (अभ्यन्तर)	2771	3887	2.2
आवास एवं भूमि		349	2.0
अन्य सामाजिक सेवाएँ-शिक्षा		251	1.5
वैज्ञानिक अनुसंधान, स्वास्थ्य		2644	15.8
कार्यक्रम, परिवार नियोजन			
पोषण, जल आदि आदि ।			
कुल योग	15,902	16774	100

**निजी क्षेत्र परिव्यय**—निजी क्षेत्र में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में 1600 करोड़ रु०, विद्युत विकास पर 75 करोड़ रुपये लघु एवं कुटीर उद्योगों पर 560 करोड़ रुपये, उद्योग एवं खनिज विकास पर 2000 करोड़ रुपये, परिवहन एवं संचार पर 920 करोड़ रुपये शिक्षा पर 50 करोड़ रुपये, आवास, क्षेत्रीय विकास पर 2175 करोड़ रुपये तथा खोज बायों पर 1600 करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था थी। वास्तविक व्यय 10000 करोड़ रु० होने का अनुमान है।

**प्राथमिकताएँ**—चौथी योजना में औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। उद्योगों के विकास पर कुल परिव्यय का 22.2 प्रतिशत व्यय हुआ। प्राथमिकताओं के क्रम में दूसरा स्थान कृषि विकास व तृतीय स्थान परिवहन एवं संचार विकास को दिया गया जिन पर योजना व्यय का क्रमशः 20.7 प्रतिशत तथा 23.2 प्रतिशत भाग व्यय हुआ। सामाजिक सेवाओं में परिवार नियोजन, शिक्षा व गिद्धे वर्गों के विकास पर बल दिया गया।

### चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की वित्त व्यवस्था

चतुर्थ योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में 15902 करोड़ रु० तथा निजी क्षेत्र में 8980 करोड़ रु० व्यय का प्रावधान था पर सार्वजनिक क्षेत्र में वास्तविक व्यय 16774 करोड़ रु० तथा निजी क्षेत्र का व्यय 10000 करोड़ रु० रहा। प्रस्तावित परिव्यय की व्यवस्था निम्न स्रोतों से किये जाने का प्रावधान था—

(करोड़ रुपये)		
		निजी क्षेत्र
1 घरेलू बजट साधन	8734	
2 अतिरिक्त करारोपण	3198	
3 जीवन बीमा निगम से ऋण		निजी क्षेत्र में बचतों से
व राजकीय उपक्रम	506	8950 करोड़ रु० तथा
4 घाटे की वित्त व्यवस्था	850	30 करोड़ रु० विदेशी
5 विदेशी सहायता	2614	धन की नेट बचतें।
कुल	15902	8980

### चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

#### (Targets & Achievements of Fourth Plan)

चौथी योजना एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना थी जिसमें स्थिरता के साथ विकास आत्मनिर्भरता व समाजवाद के स्वप्न को साकार करने की दिशा में विभिन्न क्षेत्रों में ऊँचे लक्ष्य निर्धारित किये पर योजना की समाप्ति तक उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। प्रमुख लक्ष्यों व उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

(1) राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय एवं विनियोग—इस योजना में राष्ट्रीय आय में 5.5% तथा प्रति व्यक्ति आय में 3% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा था। सार्वजनिक क्षेत्र में 13655 करोड़ रु तथा निजी क्षेत्र में 8980 करोड़ रु विनियोग का अनुमान था। विनियोग की औसत दर को 1968-69 की 11.8% की तुलना में 1973-74 तक बढ़ाकर 13.8% करने का लक्ष्य था। इसी प्रकार आन्तरिक बचत की दर को भी 9% से बढ़ाकर राष्ट्रीय आय के 12.6% करने का लक्ष्य था।

चतुर्थ योजनाकाल में विकास की दर में काफी उतार-चढ़ाव रहा। जहाँ 1969-70 में विकास दर 5.2% थी वह 1972-73 में केवल 0.6% ही रह गई। इस प्रकार लक्ष्य की प्राप्ति सम्भव नहीं हुई। विनियोग की मात्रा 1973-74 में 22635 करोड़ रु० के मुकाबले 22645 करोड़ रु० रही। वार्षिक विनियोग दर 11.3% से बढ़कर 13.7% रही जबकि लक्ष्य 13.8% वृद्धि का था बचत की दर भी राष्ट्रीय आय के 12.6% करने का लक्ष्य था पर वास्तविक बचत दर 12.2% रही। प्रति व्यक्ति आय चालू मूल्यों के आधार पर 1965-66 के 426 रु० से बढ़कर 1973-74 में 850 रु० हो गई।

(2) कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र—योजनाकाल में कृषि एवं सम्बद्ध विकास कार्यों पर सार्वजनिक क्षेत्र में 2728 करोड़ रु० तथा निजी क्षेत्र में 1600 करोड़ रु० व्यय का प्रावधान था और कृषि उत्पादन में 5.6% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य था। 1971-72 तक खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए खाद्यान्न का उत्पादन 1973-74 तक 12.9 करोड़ टन करने का लक्ष्य था तथा व्यापारिक फसलों में भी 29 से 30 प्रतिशत वृद्धि करना था। कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ निम्न तालिका से स्पष्ट है—

चतुर्थ योजना में कृषि के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

विवरण	इकाई	1973-74 का लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धियाँ
कृषि विकास दर	वार्षिक वृद्धि	5.6%	3.9%
खाद्यान्न उत्पादन	करोड़ टन	12.9	10.47
तिलहन	लाख टन	105	94
गन्ना	" "	150	140.8
कपास	" गाँठें	80	63
जूट	" "	74	77
सब उर्वरकों का उपभोग	लाख टन	46	28
अधिक उपज देने वाली फसलें	मिलियन हेक्टर	18.0	25.8
पौध संरक्षण	" "	80	80

हरित क्रान्ति के अन्तर्गत जहाँ 1970-71 में केवल 114 लाख हेक्टर क्षेत्र में उन्नत बीजों का प्रयोग होता था वह बढ़ कर 1973-74 में 258 लाख हेक्टर हो गया था। 41 लाख हेक्टर में बहुत कमल कार्यक्रम लागू किया गया। यन्त्रीकरण में भी तेजी से वृद्धि हुई। 1968-69 में विद्युत संचालित पम्प-सेटों की संख्या लगभग 15 लाख में बढ़कर 25 लाख तथा ट्रैक्टरों की संख्या 25 हजार से बढ़कर एक लाख होन का अनुमान था।

(3) सिंचाई एवं विद्युत विकास—इन दोनों मदों पर लगभग 1087 करोड़ रु तथा 2523 करोड़ रु व्यय का प्रावधान था। सिंचित क्षेत्र 360 लाख हेक्टर में बढ़ाकर 430 लाख हेक्टर करन का लक्ष्य था पर योजना के अन्त में सिंचित क्षेत्र 440 लाख हेक्टर होन का अनुमान है। इसी प्रकार विद्युत विकास पर किए गए व्यय में कुल विद्युत क्षमता 145 लाख किलोवाट से बढ़ाकर 220 लाख किलोवाट करन का लक्ष्य था पर 1973-74 के अन्त तक विद्युत उत्पादन क्षमता 184 लाख किलोवाट ही हो पाई थी। विद्युतीकृत घस्तियों की संख्या 1968-69 में लगभग 70 हजार थी वह बढ़कर 1973-74 में 140 लाख हो गई।

(4) उद्योग एवं खनिज—योजना काल में उद्योग एवं खनिज विकास पर सांख्यिक क्षेत्र में लघु एवं बुटीर उद्योगों के लिये 293 करोड़ रुपये तथा बृहत् उद्योगों व खनिजों के लिये 3338 करोड़ रु व्यय किए जाने का प्रावधान था तथा निजी क्षेत्र में भी कुल 2560 करोड़ रु अतिरिक्त व्यय का प्रावधान था। योजना काल में सांख्यिक क्षेत्र में इस मद पर 3729 करोड़ रुपये व्यय हुआ औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक 1970 में 180.8 था वह बढ़कर 210 हो गया। पूंजीगत उद्योगों में तेजी से विकास के साथ उपभोग उद्योगों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। औद्योगिक क्षेत्र में चौथी योजना के लक्ष्य तथा वास्तविक उपलब्धियाँ अग्र सारणी से स्पष्ट हैं—

## चतुर्थ योजना में खनिज एवं औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

विवरण	इकाई	वास्तविक उत्पादन 1968-69	चतुर्थ योजना का लक्ष्य (73-74)	वास्तविक उपलब्धियाँ 1973-74
साहा अयस्क	लाख टन	260	400	357
कोयला	" "	695	935	790
पेट्रोलियम पदार्थ	" "	116	260	197
इस्पात पिण्ड	" "	65	100	63.2
तैयार इस्पात	" "	46	82	48.3
मशीनरी मुख्य	करोड़ रुपया	25	65	67.9
अल्यूमिनियम	"	1.2	2.2	14.8
लाख टन	लाख टन	125	180	146.6
सीमेंट	करोड़ मीटर	460	570	794
कपड़ा	लाख टन	35.6	47	39.5
चीनी	लाख किलोवाट	145	220	202
विद्युत उत्पादन	लाख टन	15	25	18
नाइट्रोजन खाद				

इस प्रकार स्पष्ट है कि चतुर्थ योजना काल में जहाँ औद्योगिक उत्पादन में 8 से 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य था वहाँ वास्तव में औद्योगिक उत्पादन में 4 से 5% की वार्षिक वृद्धि हुई। जहाँ 1968-69 में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि 6.6% तथा 1969-70 में 6.9% रही वह घटकर 1970-71 में 3.5%, तथा 1971-72 में 1.5% से 2% रही। अन्तिम वर्ष में भी विकास दर नीची ही रही। क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियाँ लक्ष्य से काफी कम रही हैं जो उसकी असन्तोषजनक स्थिति का परिचायक है।

(5) परिवहन एवं संचार—चौथी योजना में परिवहन एवं संचार विकास पर सार्वजनिक क्षेत्र 3237 करोड़ रु० तथा निजी क्षेत्र में 920 करोड़ रु० (कुल 4157 करोड़ रु०) व्यय करने का प्रावधान था। रेलों के विकास पर एक हजार करोड़ रु० व्यय होने थे। इससे रेलों की माल ढोने की क्षमता 20.3 करोड़ टन से बढ़ाकर 1973-74 तक 26.5 करोड़ रु० करने का लक्ष्य था जबकि वास्तव में योजना के अन्त तक रेलों की माल ढोने की क्षमता 21.5 करोड़ टन ही हो पाई। सड़क विकास पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया। जहाँ 1968-69 में सतहदार सड़कों की कुल लम्बाई 3.17 लाख किलो मीटर थी और उसे बढ़ाकर 1973-74 तक 3.67 लाख किलो मीटर करना था पर वास्तव में सतहदार सड़कों की कुल लम्बाई 4.74 लाख किलो मीटर थी। जहाजरानी क्षमता 21 लाख जी आर टी से बढ़ाकर 35 लाख GRT का लक्ष्य था पर वास्तविक क्षमता 30.90 लाख GRT ही रही। संचार व्यवस्था के लिये 31 हजार नये डाकखाने, पाँच नये टेलीविजन केन्द्र तथा 7 लाख

नये टेलीफोन दिये जाने का लक्ष्य था। पर योजना के अन्त तक 23 हजार नए डाक खाने व 2450 तार घर खोले गए।

#### चतुर्थ योजना के अन्तर्गत परिवहन एवं संचार लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

विवरण	इकाई	1968-69	लक्ष्य 1973-74	वास्तविक उपलब्धियाँ 1973-74
रेलो की कुल लम्बाई	हजार किलोमीटर	60	61	61
रेलो की मास होने की क्षमता	करोड़ टन	20 3	26 5	21 5
सतहदार सड़कें	लाख किलोमीटर	3 17	3 67	4 90
जहाजरानी क्षमता	लाख GRT	21 4	35 0	30 00
डाक घर	हजार सख्या	107 0	133 3	117 00
तार घर	सख्या	14000	17000	17000

(6) सामाजिक सेवाएँ—सावजनिक क्षेत्र में सामाजिक सेवाओं पर 1818 करोड़ रु० व्यय होने का प्रावधान था जिसमें से शिक्षा पर 825 66 करोड़ रु० व्यय होना था प्राथमिक शिक्षा के विस्तार में पिछड़े वर्गों, क्षेत्रों व लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं पर 435 करोड़ रु० व्यय करने का प्रावधान था। परिवार नियोजन पर 315 करोड़ रु० व्यय किये जाने थे जिससे 2 8 करोड़ दम्पतियों को परिवार नियोजन की परिधि में लाये जाने थे। जन्म दर 39 प्रति हजार से घटाकर 25 प्रति हजार करने का लक्ष्य रखा गया।

इसी प्रकार सामाजिक कल्याण-कार्यों, गृह निर्माण, श्रम-कल्याण, जल-प्रदाय आदि कार्य-क्रमों पर भी विशेष ध्यान दिया गया।

इन सब प्रयत्नों के परस्पररूप योजना के अन्त में प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत 6-11 वर्ष की उम्र के 637 करोड़ छात्र-छात्रा, माध्यमिक शिक्षा में 1 50 करोड़ छात्र-छात्रा, हायर-सैण्डरी में 85 लाख छात्र छात्रा तथा विश्व विद्यालयों में 30 लाख छात्र छात्रा पंजीकृत थे। स्वास्थ्य कार्यक्रमों के विकास से मेडीकल कॉलेजों की संख्या 93 से बढ़ाकर 99 तथा रोगी संख्या की संख्या 2 56 लाख से बढ़ाकर 7 82 लाख तथा अस्पतालों में डाक्टरों व नर्सों की संख्या 1968-69 में क्रमशः 1 02 लाख तथा 61 हजार से बढ़ा कर 1 38 लाख व 88 हजार कर दी गई। वैज्ञानिक अनुसंधान पर 373 6 करोड़ रु० व्यय किया गया।

(7) रोजगार—यद्यपि योजना के अन्तर्गत रोजगार के सम्बन्ध में निश्चित धौकड़े प्रस्तुत नहीं किये गये थे पर विभिन्न क्षेत्रों में विकास के कारण रोजगार अवसरों में पर्याप्त वृद्धि का लक्ष्य था। कृषि क्षेत्र में तृतीय जन की तुलना में लोगो को रोजगार देने की व्यवस्था थी।

पर चतुर्थ योजना में भी रोजगार की स्थिति निरन्तर बिगड़ी है। शिक्षित बेरोजगारी की संख्या में व्यापक वृद्धि हुई। 1973-74 में बेरोजगारी की संख्या 3.5 करोड़ थी। शिक्षित बेरोजगारी की पंजीकृत संख्या 50 लाख से भी अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित रोजगार कार्यक्रम (Crash Employment Programme) के अन्तर्गत लगभग 2.5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। देश में बेरोजगार डाक्टरों व इंजीनियरों की संख्या क्रमशः 3 हजार तथा 46 हजार होने का अनुमान था।

### चतुर्थ योजना की आलोचनात्मक समीक्षा

चतुर्थ योजना के सम्बन्ध में लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया रही है। जहाँ कुछ इसे एक लोचपूर्ण एवं व्यवहारिक योजना मानते थे जबकि कुछ ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण, अत्यधिक महत्वाकांक्षी, भ्रमपूर्ण एवं अव्यावहारिक बताया। योजना अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त न कर सकी। मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। आवश्यकताओं की वस्तुओं के नितान्त अभाव में निर्धन जनता को काफी कष्ट उठाना पड़ा। कुछ आलोचकों द्वारा की गई मुख्य आलोचनाएँ इस प्रकार हैं—

(1) अत्यधिक महत्वाकांक्षी योजना थी—इस योजना में 24882 करोड़ ₹० व्यय से राष्ट्रीय आय में 5.5% कृषि उत्पादन में 5.6 तथा औद्योगिक उत्पादन में 8 से 10% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य था जबकि योजना के अन्त तक राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि की औसत दर 3.4 से 4% ही रही। कृषि उत्पादन में विकास की दर 3.9% तथा औद्योगिक उत्पादन में औसत दर 5% ही रही। वस्त्र एवं पूँजी विनियोग में भी उपलब्धियाँ लक्ष्य से काफी कम रही। खाद्यान्न का उत्पादन लक्ष्य 12.9 करोड़ टन था पर उत्पादन 10.47 करोड़ टन ही रहा। औद्योगिक क्षेत्र के लक्ष्य भी अधूरे रहे।

(2) योजना निर्माण में विलम्ब व कार्यान्वयन में शिथिलता—चतुर्थ योजना 1 अप्रैल 1969 में लागू की गई पर इसका अन्तिम प्रोत्सु लगभग डेढ़ वर्ष बाद संसद में प्रस्तुत किया गया था अतः इस अनिश्चितता व विलम्ब के वातावरण में कार्यान्वयन में अकुशलता व शिथिलता बनी रही। बंगला देश के क्षरणार्थियों ने चतुर्थ योजना में अनिश्चितता को और बढ़ा दिया।

(3) वित्तीय साधनों की अनिश्चितता—चतुर्थ योजना की प्रस्तावित रूपरेखा के लिये सांविजनिक क्षेत्र में 13902 करोड़ ₹० व्यय की व्यवस्था की गई थी जबकि योजना काल में सांविजनिक क्षेत्र में 16774 करोड़ ₹० व्यय हुए हैं। जहाँ पूर्ण योजनावृद्धि में हीनाथ प्रबन्ध से 850 करोड़ ₹० जुटाने का प्रावधान था जबकि योजनाकाल में हीनार्थ प्रबन्ध से कुल 2858 करोड़ ₹० जुटाया गया। नर करो में भी अत्यधिक वृद्धि की गई। विदेशों से सहायता में भी सन्दिग्धता बनी रही।

(4) भ्रमपूर्ण मान्यताओं पर आधारित थी—चतुर्थ योजना के लक्ष्यों का निर्धारण कुछ ऐसी मान्यताओं पर आधारित था जो असत्य सिद्ध हुईं। ये मान्यताएँ

थी कि मूल्य स्तर में स्थिरता रहेगी, निर्यात में 7% वार्षिक वृद्धि, कृषि से अतिरिक्त साधन तथा सामान्य अनुसूच वर्षों, सुरक्षा व्यय में स्थिरता रहेगी। योजना काल में अनुभव हुआ कि ये मान्यताएँ भ्रमपूर्ण थीं। मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई यहाँ तक कि 1972-73 में मूल्यों में 17% तथा 1973-74 में केवल 7-8 महीनों में ही मूल्यों में 21% वृद्धि हुई। सुरक्षा व्यय भी निरन्तर बढ़ता ही गया। जहाँ 1969-70 में प्रतिरक्षा व्यय 11 0 करोड़ रु० व्यय हुए वहाँ 1973-74 में व्यय 1600 करोड़ रु० पहुँच गया। राजनैतिक अस्थिरता, प्रतिकूल मौसम व भयंकर अतिवृष्टि व अकाल दोनों के कारण भी कृषि उत्पादन लक्ष्य से काफी नीचे रहे।

(५) बेकारी की समस्या के समाधान के लिये विशेष कार्यक्रम का अभाव रहा—1970 के दशक में बेरोजगारी की संख्या 3 5 करोड़ से बढ़कर 1980 तक 6 9 करोड़ हो जाने का अनुमान है। बेकारी को इस विषय समस्या के समाधान के लिये इस योजना में किसी विशेष व प्रभावी कदम का अभाव रहा। यद्यपि त्वरित रोजगार योजना के अन्तर्गत केवल 2 6 लाख लोगों को रोजगार दिया गया था जो कुल बेरोजगारों का एक नगण्य भाग है। यह योजना निर्माताओं की त्रुटि का परिणाम है।

(6) समाजवाद एक विरोधाभास—यद्यपि योजना में सामाजिक न्याय एवं समानता का सुखद स्वप्न सजोया गया था पर योजनाकाल में किसी ऐसे प्रान्तिकारी कदम का अभाव रहा। समाजवाद के आकर्षक नारे से राजनीतिज्ञ अपना उल्लू सीधा कर रहे तथा देश की भोली-भाली जनता को बुद्ध बनाते रहे। देश में काला-बाजारी, मुनाफाखोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार के कारण आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण होता गया। आर्थिक विषमता बड़ी। निर्धनों का शोषण हुआ। पाखण्डी मौज उड़ाते रहे। इन पाँच वर्षों में गरीबी हटाने के स्थान पर गरीबों को ही समाप्त करने के वातावरण में वृद्धि हुई। उनके सामान्य उपभोग की वस्तुओं का मूल्य आसमान छू रहा। था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 274 था।

(7) हीनार्थ प्रबन्ध का अत्यधिक सहारा व मूल्यों में वृद्धि—यद्यपि चतुर्थ योजना में स्वायत्त विकास की बात कही गई थी तथा हीनार्थ प्रबन्ध पर आश्रितता कम करने का आश्वासन था। इसी कारण हीनार्थ प्रबन्ध से 850 करोड़ रुपये ही जुटाने का प्रावधान था। पर योजनाकाल में मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। जहाँ 1969 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100) 175 था वह 1972 में 221 तथा मार्च 1974 में 274 हो गया था। 1972-73 में मूल्यों में 87% तथा 1973-74 में 21% की वृद्धि चौका देने वाली थी। जहाँ हीनार्थ प्रबन्ध से 850 करोड़ रुपये जुटाने का प्रावधान था वहाँ इस स्रोत से 2858 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई।

चतुर्थ योजना की उपलब्धियों के परिप्रेक्ष्य में आलोचनाओं का विदोषण करने से स्पष्ट होगा कि भारत की प्रायः सभी योजनाओं की भाँति चतुर्थ योजना



मे भी अवास्तविक मान्यताओं को आधार बनाया गया। योजना के त्रियान्वन मे अकुशलता एव दिथिलता रही। प्राकृतिक प्रकोपो, श्रमिक आन्दोलनो, हडतालो, तगलाबन्दी, तोड फोड आदि के कारण कृषि, उद्योग एव अन्य क्षेत्रो मे प्रगति धीमी रही। फिर भी अन्ततः यही कहा कहा जाना चाहिये कि यह योजना काफी हद तक असफल रहने के बावजूद भी खाद्यान्न मे आराम निमरता, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र मे उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि, योजनाबद्ध विकास को श्रुखला मे एक महत्वपूर्ण कडी थी। इससे पाँचवी योजना के लिये सुष्ठु आधार, तैयार हुआ। यही नहीं इसकी असफलताओ ने हमारे योजना निर्माताओ की विकास के प्रति ऊँची आशाओ एव आकांक्षाओ की निर्मूल घारणाओ को ठेस पहुचाकर उन्हें भावी योजना निर्माण एव कार्यान्वयन के लिये ठेस, व्यवहारिक एव विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के प्रति सजग किया।

## पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974-79)

(FIFTH FIVE YEAR PLAN 1974-79)

भारत के योजनाबद्ध विकास में पांचवी योजना एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। इस योजना के प्रारम्भ में सार्वजनिक क्षेत्र में 37250 करोड़ ₹० व्यय की व्यवस्था थी किन्तु मशोचित योजना का कुल परिध्यय 69303 करोड़ ₹० रखा गया जिसमें 42303 करोड़ ₹० सार्वजनिक क्षेत्र में तथा 27000 करोड़ ₹० निजी क्षेत्र में व्यय करने का प्रावधान था। इस परिध्यय में कुल विनियोग 63571 करोड़ ₹० होने से और आर्थिक विज्ञान की वार्षिक दर 4.37% करने का लक्ष्य था।

जनता सरकार के सत्तास्थ होने के साथ ही इसमें परिवर्तन का विचार था किन्तु फिर पांचवी योजना को अपनी निर्धारित अवधि के एक वर्ष पहले ही समाप्त कर जनता सरकार ने आर्वर्णी योजना (Rolling Plan) के अन्तर्गत छठी योजना (1978-83) का श्री गणेश कर दिया गया। इस प्रकार पांचवी योजना केवल चार वर्ष ही पूर कर पाई।

योजना के प्रमुख उद्देश्य (Objectives)—पांचवी योजना के दो प्रमुख उद्देश्य थे। (i) गरीबी हटाओ तथा (ii) आत्म निर्भरता की प्राप्ति इन दो मूल उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना में निम्न ध्युह-रचना अपनाई जानी थी।

योजना की ध्युह रचना अथवा कार्य नीति (Strategy)—योजना काल में प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य-नीति की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार थी—

- (i) राष्ट्रीय आय में 4.37% वार्षिक वृद्धि की दर प्राप्त करना,
- (ii) उत्पादक ग्रेजुआर का विस्तार
- (iii) समाज कल्याण के व्यापक कार्यक्रम अपनाना
- (iv) न्यूनतम आवश्यकताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू करना जिसके अन्तर्गत ग्राम प्राथमिक शिक्षा चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा, पोषिक आहार, गन्दी बर्तियों का मुद्धार, शुद्ध पेय जल की व्यवस्था आदि।
- (v) समाज कल्याण के व्यापक कार्यक्रम अपनाना।
- (vi) कौशल मजदूरी तथा आयो में न्यायोचित मन्तुलन बंटाना
- (vii) सामाजिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिये समायोजन, राजनीतीय एवं अन्य उपायों का सहारा लेना।
- (viii) निर्धन सम्बर्द्धन एवं आयान प्रतिस्थापन के लिये जोरदार कदम उठाना,

(ix) गरीबों को उचित मूल्यो पर अनिवार्य उपभोग वस्तुओं के सार्वजनिक वितरण एवं प्राप्ति की पर्याप्त व्यवस्था करना ।

(x) कृषि, आधार-भूत उद्योगो एवं व्यापक उपभोग वस्तुओं को उत्पादन करने वाले उद्योगो के विकास पर विशेष बल देना ।

आर्थिक नीतियो का निर्धारण इस प्रकार किया जाना था कि स्थायित्व के साथ विकास हो सके, निर्यातो से अधिकाधिक विदेशी विनिमय कमाया जा सके । आयात लाइसेन्स पद्धति योजना की प्राथमिकताओं के अनुरूप हो और विदेशी सहायता पर निर्भरता कम से कम हो ।

### पाँचवी योजना का परिचय एवं प्राथमिकताएँ (Outlay & Priorities of Fifth year Plan)

पाँचवी योजना का कुल प्रस्तावित परिव्यय 69303 करोड़ रु० था उसमे से 42303 करोड़ रु० सार्वजनिक क्षेत्र तथा 27000 करोड़ रु० निजी क्षेत्र में व्यय होने थे । सार्वजनिक क्षेत्र के कुल परिव्यय 42303 करोड़ रु० मे से 36703 करोड़ रु० का विनियोग, 2600 करोड़ रु० चालू परिव्यय तथा 3000 करोड़ रु० इन्वेस्टरी पर विनियोग होना था । निजी क्षेत्र का विनियोग 27048 करोड़ रु० रखा गया था । योजनाकाल में कुल विनियोग 63751 करोड़ रु० करने का प्रावधान था इसके लिये 58320 करोड़ रु० आन्तरिक बचतों से तथा 5431 करोड़ रु० विदेशी सहायता से जुटाये जाने थे । पाँचवी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रस्तावित परिव्यय निम्न तालिका से स्पष्ट है —

पाँचवी योजना के मध्यावधि परिणाम के कारण योजना के चार वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र में 29571 करोड़ रु० तथा निजी क्षेत्र में 12929 करोड़ रु० व्यय का अनुमान था इस प्रकार प्रथम चार वर्षों में योजना का कुल परिव्यय 69303 करोड़ रु० के बजाय केवल 42500 करोड़ रु० ही रहने का अनुमान था ।

### पाँचवी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रस्तावित एवं वास्तविक व्यय (करोड़ रु०)

वर्ग	प्रस्तावित व्यय 1974-79	वास्तविक व्यय 1974-78 <sup>1</sup>
(1) कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	4302	3400
(2) सिंचाई, विद्युत एवं बाढ़ नियंत्रण	14517	8316
(3) उद्योग एवं खनिज	7362	7820
(4) परिवहन एवं संचार	6917	5188
(5) सामाजिक सेवार्थे	6224	4847
कुल परिव्यय	39322	29571

1 वास्तविक व्यय 1974-78 रिजर्व बैंक बुलेटिन के दिसम्बर 1978 के सप्लीमेन्ट "Basic Statistics" से लिया गया है । जबकि प्रस्तावित व्यय छठी योजना के प्रारूप से ।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि पाचवी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का कुल परिव्यय चौथी योजना के परिव्यय का लगभग 2½ गुना तथा पिछली सभी योजनाओं के समग्र व्यय के बराबर था अकेली पाचवी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में 39322 करोड़ रु० व्यय की व्यवस्था उसके विशाल आकार और व्यापक उत्पादन क्षमता वृद्धि का परिचायक था।

**प्राथमिकताएँ (Priorities)**—इस योजना में औद्योगिक विकास की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई जिसके अन्तर्गत उपभोग उद्योगों में तेजी से उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य था। कृषि की प्राथमिकता के दूसरे क्रम पर तथा परिवहन एवं संचार का स्थान प्राथमिकता क्रम में तीसरा था।

### सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय साधन

पाचवी योजना के लिये विशाल धन राशि जुटाने की व्यापक व्यवस्था की गई। घरेलू बजट साधनों से 32115 करोड़ रु० (80.5 प्रतिशत) साधन जुटाये गये। केन्द्र तथा राज्यों को 14693 करोड़ रु० अनिश्चित करारोपण से जुटाना था जो कुल सार्वजनिक परिव्यय का 32 प्रतिशत भाग था जबकि बाह्य साधनों से 5834 करोड़ रु० (15 प्रतिशत) जुटाने की व्यवस्था थी। हीनार्थ प्रबन्ध से 1354 करोड़ रु० जुटाने का प्रावधान था। ससाधनों के स्रोत निम्न तालिका से स्पष्ट है—

### पांचवी योजना के प्रस्तावित ससाधन (Finances)

(A) घरेलू बजट साधन	रु० 32115 करोड़ रु०
(i) 1973-74 की आलू दरों पर बजट अतिरेक	4901
(ii) सार्वजनिक उपक्रमों से बचत	849
(iii) बाजार से उधार	5879
(iv) अल्प बचतें	2022
(v) राज्य भविष्य निधियाँ	1987
(vi) वित्तीय संस्थानों से प्राप्ति	628
(vii) अनिश्चित करारोपण	14693
(viii) विविध पूँजीगत प्रस्थियाँ	556
(ix) विदेशी विनिमय कोष से उपयोग	600
(B) हीनार्थ प्रबन्ध (Deficit Financing)	1354 करोड़ रु०
(C) विदेशी सहायता (Foreign Assistance)	5834 करोड़ रु०
<b>कुल योग</b>	<b>39303 करोड़ रु०</b>

### पांचवी योजना के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

#### (Main targets & Achievements of Fifth Plan)

पांचवी योजना के बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किये गये थे किन्तु कांग्रेस सत्ता को पतन कर जनता पार्टी ने जो दि दायन सत्ता सभान्तीने चुनावों

वायदो को पूरा करने तथा जन आशाओं और आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने के लिए पांचवी योजना का मध्यावधि परित्याग कर उसे 1977-78 में ही समाप्त कर दिया और नयी छठी योजना का श्री गणेश कर दिया है।

पांचवी योजना के 1974-79 के निर्धारित लक्ष्य तथा 1977-78 तक के चार वर्षों में उपलब्धियों का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है—

(1) राष्ट्रीय आय, बचत एवं विनियोग—योजनाकाल में वार्षिक विकास दर 4.37 प्रतिशत करने का लक्ष्य था किन्तु विकास दर 1977-78 तक 3.9 प्रतिशत रही जबकि 1977-78 में राष्ट्रीय आय में 3.9 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान था पूँजी निर्माण दर 18.3 प्रतिशत करने का लक्ष्य था जबकि बचतों को राष्ट्रीय आय के 15.9 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य था। ताजा अनुमानों के अनुसार देश में पूँजी निर्माण की दर 1978-79 में 23.5 प्रतिशत तथा बचतों की दर 22 प्रतिशत होने की आशा है।

(2) कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र—कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र पर 4302 करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था थी जिसके द्वारा कृषि विकास दर को 3.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.67 प्रतिशत करने का लक्ष्य था। खाद्यान्न का उत्पादन 12.5 करोड़ टन करने का लक्ष्य था। इसी प्रकार उर्वरकों का प्रयोग 50 लाख टन वार्षिक तथा पौध संरक्षण दवाओं का प्रयोग 75 हजार टन वार्षिक करने का प्रावधान था। कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए ट्रैक्टरों की संख्या 5 लाख की जानी थी। पांचवी योजना के लक्ष्य और 1977-78 की उपलब्धियाँ निम्न तालिका से स्पष्ट हैं—

### कृषि क्षेत्र के मुख्य लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

मद	इकाई	पांचवी योजना के लक्ष्य 1974-79	पांचवी योजना की उपलब्धियाँ 1974-78
खाद्यान्न	करोड़ टन	12.5	12.5
तिलहन	लाख टन	120	118
गुड़-गन्ना	" "	165	57
कपास			
जूट	लाख गांठें	80	64.3
घास	" "	77	60
	करोड़ किलो	56	50
	ग्राम		

(3) सिंचाई एवं शक्ति—पांचवी योजना से सार्वजनिक क्षेत्र में सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण पर 4226 करोड़ रु० तथा विद्युत विकास पर 7294 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान था। इस विकास व्यय से सिंचित क्षेत्र में 131 लाख हेक्टर क्षेत्र वृद्धि का लक्ष्य था जबकि योजना के चार वर्षों में सिंचित क्षेत्र में केवल 86 लाख हेक्टर की वृद्धि हुई। जहाँ योजना ने अन्ततः सिंचित क्षेत्र 584 लाख हेक्टर करने

का लक्ष्य था वहीं 1977-78 तक केवल 484 लाख हेक्टर ही सिंचाई सुविधा की परिधि में आया है।

विद्युत विकास को भी विशेष महत्व दिया गया था। योजनाकाल में विद्युत उत्पादन क्षमता में 12.5 मिलियन किलोवाट वृद्धि का लक्ष्य था किन्तु योजनाकाल में विद्युत उत्पादन क्षमता केवल 66 लाख किलोवाट ही बढ़ी। 1977-78 में विद्युत उत्पादन क्षमता 250 लाख किलोवाट होने का अनुमान है। योजना के चार वर्षों में 9 लाख पम्प सेटों और 80 हजार गावों को बिजली दी गई जबकि लक्ष्य 11.3 लाख पम्प सेटों और 81 हजार गावों का था। स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में प्रगति सन्तोष जनक रही।

(4) उद्योग एवं खनिज विकास—इस योजना में उद्योग एवं खनिज विकास पर 7362 करोड़ रु० व्यय का प्रावधान था जिससे उद्योगों में विकास दर 7 प्रतिशत तथा अन्तिम तीन वर्षों में 10 प्रतिशत करने का लक्ष्य था। यह लक्ष्य 1976-77 में ही पूरा हो गया जबकि इस दशक की सर्वाधिक विकास दर 10.4 प्रतिशत पहुँच गई जबकि 1977-78 में औद्योगिक विकास की दर 5 से 6 प्रतिशत ही रही। प्रमुख उद्योगों में योजना का लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ निम्न तालिका से स्पष्ट हैं—

**पाचवी योजना में औद्योगिक उत्पादन के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ**

विवरण	इकाई	पाचवी योजना के लक्ष्य 1974-79	उपलब्धियाँ 1974-78
लोहा अपस्क	लाख टन	560	430
कोयला	" "	1240	1032
कूड पेट्रोसियम	" "	141.8	107.7
इस्पात	" "	88	77.3
मशीनें एवं औजार	मूल्य करोड़ रु०	130	120
एल्युमिनियम	हजार टन	190	180
सीमेन्ट	लाख टन	208	192
बपडा (दोनों क्षेत्र)	करोड़ मीटर	950	960
उर्वरक (नाइट्रोजन एवं फास्फेट)	लाख टन	36.7	27.2

इसके अतिरिक्त लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर 535 करोड़ रु० व्यय कर 60 लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य था किन्तु योजना के चार वर्षों में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर 388 करोड़ रु० व्यय किये गये। खनिजों के उत्पादन मूल्य में भी तेजी से वृद्धि हुई यहाँ तक कि खनिजों का मूल्य 1977-78 में 1300 करोड़ रु० से भी अधिक पहुँच गया।

(5) परिवहन एवं संचार—योजनाकाल में 6917 करोड़ रु० व्यय करने का प्रावधान था। रेलों की माल ढोने की क्षमता 2526 करोड़ टन करने तथा ग्रामीण सड़कों के विकास पर अधिक बल दिया गया। 54 लाख नये टेलीफोन कनेक्शन देने तथा 31 हजार नये पोस्ट ऑफिस खोलने का लक्ष्य था। जहाजरानी क्षमता को बढ़ाकर 65 लाख GRT करने की आशा थी। योजनाकाल में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का पूरा-पूरा प्रयास किया गया है।

(6) सामाजिक सेवाएं—इसके अन्तर्गत शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाएं समाज कल्याण, आवास एवं परिवार कल्याण कार्य क्रम आते हैं। शिक्षा पर 1285 करोड़ रु० व्यय, प्राथमिक शिक्षा में छात्र प्रवेश सत्या 711 लाख, माध्यमिक शिक्षा में शालाख, उच्च माध्यमिक में 110 लाख, तथा विश्व विद्यालय शिक्षा में 45 लाख करने का लक्ष्य था। इसी प्रकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 5351 तक बढ़ाने का लक्ष्य था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर 1179 करोड़ रु० व्यय किये जाने थे। परिणामस्वरूप 59 लाख भ्रूण लगाने तथा 180 लाख, लोगों की नसबन्दी का लक्ष्य था यह लक्ष्य आपात स्थिति के समय ही सीमा पार कर गया है।

विधिवत :—बढ़ती बेरोजगारी के निराकरण के लिये कृषि क्षेत्र में अधिक रोजगार देने की व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार अवसर बढ़ाने का पूरा-पूरा प्रयास रहा। निर्यातों में वृद्धि लक्ष्य से अधिक रही और आयात प्रतिस्थापन को सफल बनाया गया।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा, शुद्ध पेय जल की व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास, भूमिहीनों को भूमि आवंटन, गन्दी वस्तियों का सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण का व्यापक कार्यक्रम अपनाया गया। 70 लाख भूमिहीन मजदूरों को भूमि आवंटन हुआ।

भारत के विदेशी विनिमय कोषों में भारी वृद्धि हुई है और विदेशी विनिमय सफ्ट का युग समाप्त हुआ है। अब भारत में विदेशी विनिमय कोष 4 हजार करोड़ रु० से भी अधिक है। निर्यातों में तेजी से वृद्धि और आयातों में कमी से विदेशी व्यापार का 1975-76 का 1222 करोड़ रु० का घाटा, 1976-77 में लगभग 69 करोड़ रु० बचत में बदल गया यह उल्लेखनीय है कि 1976-77 से निर्यातों में पिछले वर्ष के मुकाबले 27% की वृद्धि होने में निर्यातों का मूल्य 5143 करोड़ रु० था जबकि आयातों में 39% कमी से आयातों का मूल्य 5074 करोड़ रु० रहा और इस प्रकार विदेशी व्यापार 69 करोड़ रु० पक्ष में रहा।

### पांचवी योजना की आलोचनात्मक समीक्षा

यद्यपि योजनाकाल में “गरीबी हटाओ” एवं आत्म निर्भरता लाओ उद्देश्यों की पूर्ति के लिये योजना के अन्तर्गत भारी व्यय किया गया और व्यापक कार्यक्रम अपनाए गये किन्तु महत्वाकांक्षी लक्ष्यों, बढ़ते मूल्यों और साधनों की अनिश्चितता के कारण वांछित सफलता न मिल सकी। यही नहीं, जनता पार्टी के सत्तारूढ़ होने के

कारण नयी प्राथमिकताओं और बदलती परिस्थितियों में पाँचवी योजना का 1977-78 में ही मध्यावधि परित्याग कर छठी योजना का सूत्रपात कर दिया गया है। इसकी मुख्य आलोचनाओं की समीक्षा इस प्रकार है —

(1) अत्यधिक महत्वाकांक्षी योजना थी — चौथी योजना की भाँति पाँचवी योजना भी काफी महत्वाकांक्षी थी। आर्थिक विकास की दर 4.37% रखी गई जबकि 1977-78 तक विकास की वास्तविक दर 3.9% ही रही है। औद्योगिक विकास की वार्षिक दर भी 6.5% रही जबकि लक्ष्य 8 से 10% करने का था। साक्षात्त का उत्पादन अपने लक्ष्य पर पहुँच गया।

(2) घाटे की विलम्ब व्यवस्था से मूल्यों में वृद्धि हुई। आपात स्थिति होने के कारण मूल्यों पर नियन्त्रण संभव हो गया अन्यथा मूल्य बहुत बढ़ जाते।

(3) योजना निर्माण में अत्यधिक विलम्ब एवं कार्यान्वयन में शिथिलता — योजना का अन्तिम स्वरूप योजना लागू होने के लगभग 2 वर्ष बाद भी स्पष्ट नहीं था। अतः योजना निर्माण में विलम्ब से उसके कार्यान्वयन में शिथिलता रही।

(4) बेकारी की समस्या के निराकरण के लिये प्रभावी कार्यक्रम का अभाव रहा। यहाँ तक कि योजना के चार वर्षों बाद भी समस्या की जटिलता को देखते हुए जनता सरकार ने छठी योजना लागू की है।

(5) समाजवाद कीरी बल्बना रही — आर्थिक विषमताओं में नगण्य रही। यह कहना ठीक होगा कि यह एक राजनैतिक भार है जिसे जनता को भ्रम में डाल कर वोट घटोरने की व्यवस्था की जाती है।

इन सब आलोचनाओं के बावजूद पाँचवी योजना की उपलब्धियों को नजर-न्दाज नहीं किया जा सकता। योजना का न अत्यधिक विकास अधिक सुदृढ़ हुई है। सभी प्रकार के उत्पादन बढ़े हैं जैसा ऊपर उपलब्धियों के विवेचन से स्पष्ट है। यह योजना योजनावद्ध विकास प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध हुई है।

— — —



## भारत में योजनाबद्ध विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ (1951-52 से 1978-79)

(IMPORTANT ACHIVEMENTS OF PLANNED DEVELOPMENT IN INDIA SINCE 1951 TO 1978-79)

### भारत में पञ्चवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक प्रगति (Economic Progress in India During Five Year Plans)

भारत की निर्बल जनता को समृद्ध एवं विविधतापूर्ण जीवनयापन के नये अवसर प्रदान करने, उनके जीवन स्तर को उन्नत करने तथा रोजगार की अभिवृद्धि के साथ-साथ आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिये 1 अप्रैल 1951 से भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों पर आधारित वार्षिक नियोजन का सूत्रपात हुआ तब से 1978-79 तक योजनाबद्ध विकास के 28 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस अवधि में पांच पञ्चवर्षीय योजनायें तथा तीन वार्षिक योजनाओं (1966-1969) को कार्यान्वित किया गया। पहली पञ्चवर्षीय योजना में अल्पकालीन समस्याओं के समाधान पर ध्यान देकर भावी विकास के लिये सुदृढ़ आधार तैयार करने का लक्ष्य था, द्वितीय योजना मुख्यतः औद्योगिकरण की योजना थी, तृतीय योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को स्वयं स्फूर्त अवस्था की ओर अग्रसर करना था। विदेशी विनिमय संकट, वित्तीय साधनों की सदृग्धता तथा अनिश्चित वातावरण में तीन वार्षिक योजनायें (1966-69) कार्यान्वित की गईं। चतुर्थ योजना आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से प्रेरित योजना थी। इस योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया में यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था की सफलता-विफलताओं को कठिन परिस्थितियों के दौर से गुजरना पड़ा है फिर भी कठिनाइयों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्र गति से आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हुई है। देश में भावी विकास के लिये सुदृढ़ आधार तैयार हुआ है। निर्बलता व बेरोजगारी की समस्याओं से निबटने के लिये भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्षमता में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

भारत की प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में 1960 करोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र में 1800 करोड़ रु० व्यय किया गया। इसमें कृषि विकास को सर्वोच्च

प्राथमिकता दी गई थी। द्वितीय योजना मुख्यतः औद्योगीकरण की योजना थी जिसमें आधारभूत एवं मूलभूत उद्योगों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में 4672 करोड़ रु० तथा निजी क्षेत्र में 3100 करोड़ रु० व्यय किया गया। तृतीय योजना में कृषि व उद्योगों के समुत्थित विकास के लिये अर्थव्यवस्था को स्वयं-सुपूर्ण बनाने का लक्ष्य था और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये सार्वजनिक क्षेत्र में 8577 करोड़ रु० तथा निजी क्षेत्र में 4100 करोड़ रु० व्यय किए गए। तीन वार्षिक योजनाओं (1966-69) में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र पर क्रमशः 6676 करोड़ रु० तथा 3640 करोड़ रु० व्यय हुआ। चौथी योजना में स्वयं सिद्ध तथा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के स्वप्न को साकार करने के लिये पांच वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र में 15902 करोड़ रु० तथा निजी क्षेत्र में 8980 करोड़ रु० व्यय का प्रावधान था पर बड़ती कीमतों के कारण वास्तविक व्यय क्रमशः 16,774 करोड़ रु० तथा 10 हजार करोड़ रु० होने का अनुमान है। पांचवी योजना के प्रथम चार वर्षों (1974-78) सार्वजनिक क्षेत्र में 29571 करोड़ रु० तथा निजी क्षेत्र में 12900 करोड़ रु० व्यय हुआ।

इस प्रकार उपर्युक्त व्यय को तात्कालिक करने पर स्पष्ट होता है कि योजनावद्ध विकास के लिये पिछले 27 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल मिलाकर लगभग 68230 तथा निजी क्षेत्र में 35569 करोड़ रु० व्यय हुआ है। परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली प्रगति का मूल्यांकन निम्न तथ्यों से स्पष्ट होता है—

(1) राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि — किसी भी देश के आर्थिक विकास को मापने का माटा मापदंड राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि है। इस दृष्टि से देखने पर जहाँ 1950-51 में चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय 9330 करोड़ रु० थी वह 1960-61 में बढ़कर 13284 करोड़ रु० तथा 1977-78 में 73157 करोड़ रु० होने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय भी 1950-51 में चालू मूल्यों पर 266 रु० 5 पैसे थी वह 1960-61 में बढ़कर 306 रु० 10 पैसे तथा 1977-78 में बढ़कर 1163 रु० 10 पैसे हो गई है। इस प्रकार पिछले 27 वर्षों में राष्ट्रीय आय 150 प्रतिशत तथा प्रति व्यक्ति आय में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की धीमी गति का कारण जनसंख्या में प्रतिवर्ष 7.5 प्रतिशत की विस्फोटक वृद्धि वृद्धि होना है। अगर हम 1948-49 के मूल्यों पर गौर करें तो राष्ट्रीय आय में केवल 96 प्रतिशत तथा प्रति व्यक्ति आय में केवल 45 प्रतिशत ही वृद्धि हुई है। फिर भी हमारी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक विकास का परिचायक है। 1975-76 में राष्ट्रीय आय में 8.11 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि 1977-78 में राष्ट्रीय आय में लगभग 7.24 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान था।

2 विनियोग बचत एवं पूँजी निर्माण में वृद्धि—योजना बढ विकास के पिछले 27-28 वर्षों में सावजनिक एवं निजी क्षेत्रों में कुल मिलाकर लगभग 98000 करोड रु का पूँजी विनियोग हुआ। जहाँ 1950-51 में विनियोग की दर राष्ट्रीय आय का 5.8% थी वह 1965-66 में बढ़कर 14 से 15% हो गई। उसके बाद अर्थ-व्यवस्था पर प्राकृतिक प्रकोप, बंगला देश संकट, पाकिस्तान से युद्ध व मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण विनियोग दर 1968-69 में 11.3% तथा 1978-79 में 23% हो होने का अनुमान है। जहाँ 1950-51 में विनियोगों का वार्षिक औसत 500 करोड रु था वह 1955-56 में बढ़कर 2600 करोड रु वार्षिक तथा 1970-71 में 3000 करोड रु वार्षिक हो गया। चतुर्थ योजना के अन्त में विनियोगों का वार्षिक औसत 4412 करोड रु का अनुमान है। इसी प्रकार आन्तरिक बचतें 1950-51 में राष्ट्रीय आय का लगभग 4.5% भाग थी वह 1978-79 में बढ़कर राष्ट्रीय आय के 22% के बराबर हो गई। योजनावार विनियोग-भावा तालिका से स्पष्ट है—

### पंचवर्षीय योजनाओं में विनियोग

(करोड रुपये)

क्षेत्र	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना	तीन वार्षिक योजनाएँ	चतुर्थ योजना	कुल योग 1951-74	पाँचवी योजना अनुमान 1974-78
सावजनिक क्षेत्र	1560	3650	6300	5817	13665	30992	26000
निजी क्षेत्र	1800	3100	4100	3640	8980	21620	23000
कुल योग	3360	6750	10400	9457	22,645	52612	49000

3 कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र—योजनाबद्ध विकास के 27-28 वर्षों में जहाँ कृषि क्षेत्र में भी आश्चर्यजनक प्रगति हुई है वहाँ 1950-51 में कृषि विकास की दर 0.5% थी वह दर 1973-74 में बढ़कर 3.9% हो गई। खाद्यान्न उत्पादन जो 1950-51 में केवल 5.4 करोड टन था वह 1978-79 में 12.8 करोड टन होने का अनुमान है। इसी प्रकार व्यापारिक फसलों के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। कृषि में हरित क्रान्ति के कारण उर्वरकों के प्रयोग व उन्नत बीजों के प्रयोग में वृद्धि होने के साथ कृषि में परम्परागत दृष्टिकोण के स्थान पर व्यावसायिक दृष्टिकोण का सूत्रपात हुआ है। कृषि उत्पादन का सूचकांक, (1949=100) 1950-51 में 96.6 था वह 1960-61 में बढ़कर 139 तथा 1978-79 में बढ़कर 221 होने का अनुमान है। कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ अग्र तालिका से स्पष्ट हैं—

## कृषि क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियाँ

विवरण	इकाई	1950-51	1960-61	1970-71	1973-74	1978-79
(1) कृषि उत्पादन (सूचांक 100)	949=	95.6	139	182	198	221
(2) खाद्यान्न उत्पादन	करोड़ टन	5.5	8.2	10.8	10.47	12.8
(3) तिलहन	लाख टन	52	70	92	94	134
(4) गन्ना (गुड़ के रूप में)	" "	71	114	132	141	
(5) कपास	लाख गॉठें	29	53	46	66	72
(6) जूट	" "	35	41	49	65	70
(7) उर्वरकों का उपभोग	हजार टन	69	306	2180	2439	5000

Source—Compilation from Various plans

हरित क्रान्ति के अन्तर्गत उन्नत बीजों के प्रयोग में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है जहाँ 1969-70 में केवल 114 लाख हैक्टर में अधिक उपज देने वाली फसलें बोई गयीं वहीं 1978-79 में यह क्षेत्र बढ़कर 430 लाख हैक्टर होने का अनुमान था। 169 लाख हैक्टर में बहु फसल कार्यक्रम लागू किया गया है जबकि 1964-66 से पूर्व इनकी प्रगति नगण्य थी। जागीरदारी एवं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तो बहुत पहले ही किया जा चुका है। कृषि में यंत्रीकरण भी निरन्तर बढ़ रहा है। जहाँ 1956 में विद्युत संचालित पम्प सैंटो की संख्या 47 हजार थी जबकि 1970-71 में यह संख्या 166 लाख तथा 1978-79 में 35 लाख होने का अनुमान है। ट्रैक्टरों की माँग 1964-67 में 20 हजार थी वह 1970-71 में 40 हजार हो गई तथा अब यह माँग 2.5 लाख होने की सम्भावना है। कोटाबुनादाव दबाओ का उपभोग 1978-79 में 65 हजार टन होने का अनुमान है। जहाँ 1965-66 में केवल 16.6 लाख हैक्टर क्षेत्र में पौध संरक्षण कार्यक्रम लागू था अब लगभग 850 लाख हैक्टर क्षेत्र में पौध संरक्षण लागू है। रासायनिक खादों का प्रयोग 1974-75 में 27 लाख टन था जबकि 1978-79 में 50 लाख टन होने का अनुमान है।

4 सिंचाई एवं विद्युत शक्ति विकास—ये दोनों कृषि तथा औद्योगिक विकास के आधार-स्तम्भ हैं। पिछले 28 वर्षों में सिंचाई साधनों के विविधता पर लगभग 6500 करोड़ रु व्यय हो चुका है। फलस्वरूप जहाँ 1950-51 में सिंचित क्षेत्र 208 लाख हैक्टर था वह 1960-61 में बढ़कर 283 लाख हैक्टर व 1968-69 में 360 लाख हैक्टर हो गया तथा 1973-74 में सिंचित क्षेत्र 440 लाख हैक्टर हो गया था 1978-79 में सिंचित क्षेत्र 520 लाख हैक्टर था इस प्रकार सिंचित क्षेत्र दुगुने

से अधिक हो गया है। विशालकाय बहुउद्देशीय परियोजनाओं में भाकरा नामल, दामोदर घाटी, हीरा-मुण्ड, तुंगभद्रा, चम्बल नामाजून सागर, रिहन्द सेरावती, परियार व काशी योजनाओं का नाम उल्लेखनीय है।

विद्युत उत्पादन में पिछले 28 वर्षों में लगभग 12 गुना वृद्धि हुई है जहाँ 1950-51 में केवल 23 लाख Kw विद्युत उत्पादन क्षमता थी। 1960-61 में यह क्षमता 56 लाख Kw थी जबकि 1968-69 में क्षमता 145 लाख Kw हो गई। 1973-74 के अन्त तक विद्युत क्षमता 184.6 लाख Kw हो गई। 1978-79 में विद्युत क्षमता में 270 लाख किलोवाट होने का अनुमान है। विद्युतीकृत बस्तियों की संख्या 1950-51 में 3671 से बढ़कर 1973-74 में 140 लाख हो गई। 1978-79 तक विद्युतीकृत बस्तियों की संख्या 2.5 लाख होने का अनुमान है।

### पंचवर्षीय योजना में विद्युत शक्ति एवं सिंचाई क्षमता का विकास

विवरण	इकाई	1950-51	1960-61	1968-69	1973-73	1978-79
निर्दिष्ट क्षेत्र	लाख हेक्टर	208	283	360	440	520
विद्युत उत्पादन						
क्षमता	लाख कि वा	23	56	145	184	270
विद्युतीकृत	—					
— बस्तियाँ	संख्या	3671	25000	70,000	140 लाख	2.5 लाख

Source—Compilation from various plans

(5) उद्योग एवं खनिज विकास—यद्यपि प्रथम योजना में औद्योगिक विकास को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना मुख्यतः औद्योगीकरण की योजना थी तथा उसके बाद की सब योजनाओं में उद्योगों व खनिज विकास की प्राथमिकता में विशेष स्थान प्राप्त था। सावजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास पर पिछले 27-28 वर्षों में लगभग 15000 करोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र में 12000 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में लगभग 300% की वृद्धि हुई है। 1968-69 में औद्योगिक उत्पादन 1950-51 के उत्पादन से तिगुना था। 28 वर्षों में आधारभूत उद्योगों के उत्पादन में 300 से 600 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (1960=100) 1951 में 54.8 था वह 1961 में 110.6 पहुँच गया। 1970 में यह सूचकांक 180.8 था तथा 1978-79 तक यह सूचकांक 270 होने का अनुमान है। मशीनरी उत्पादन में लगभग 42 गुना वृद्धि हुई है। औद्योगिक संरचना में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ

हे जहाँ 1950-51 में औद्योगिक उत्पादन में उपभोग वस्तुओं, मध्यम वस्तुओं व पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन का अनुपात क्रमशः 68%, 23% तथा 8% था वह 1965-66 में बदलकर क्रमशः 34%, 43.3% तथा 22% हो गया। हमारे औद्योगिक उत्पादन में पूंजीगत वस्तुओं का बढ़ता अनुपात सुदृढ़ औद्योगिक आधार का द्योतक है। 1951 के मुकाबले औद्योगिक उत्पादन  $3\frac{1}{2}$  गुना हो गया है।

आधारभूत उद्योगों में रूरकेला, भिलाई दुर्गापुर व बोकारो के इस्पात कारखाने, बगलौर, रांची एवं पिन्जौर में मशीन टूल्स कारखाने, चितरजन व बारा-पसी में रेल इंजन कारखाने, हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के सात कारखाने, हिन्दुस्तान कंथल्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड, जिक स्मैल्टर, ताँबा-शोधक कारखाना, भोपाल हैवी इलेक्ट्रॉनिक कारखाना तथा बगलौर व कानपुर के हवाई जहाज निर्माण कारखाने योजनाबद्ध विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग 195 ऐसे औद्योगिक उपक्रम हैं जिनमें लगभग 13500 करोड़ रुपये की पूंजी नियोजित है। खनिजों का उत्पादन भी निरन्तर बढ़ रहा है जहाँ 1950-51 में खनिज उत्पादन का कुल मूल्य केवल 89 करोड़ रुपये था यह बढ़कर 1978-79 में 1400 करोड़ हो गया।

### पचवर्षीय योजनाओं में खनिज एवं औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियाँ

(लक्ष्य)

विवरण	इकाई	1950-	1960-	1968-	1973-	1978-
		51	61	69	74	79
लोहा अथस्क	लाख टन	32	120	260	357	560
कोयला	लाख टन	323	546	695	790	1240
पेट्रोलियम पदार्थ	लाख टन	2	58	161	197	270
तैयार इस्पात पिंड	लाख टन	10	22	46	48.9	88.0
मशीनरी	मूल्य लाख रु	30	700	2500	6730	13000
एल्यूमिनियम	हजार टन	4	18	120	148	310
सीमेन्ट	लाख टन	27	80	125	1467	208
विद्युत उत्पादन	लाख कि. वा.	23	56	145	1284	270
सूती वपडा	करोड़ मीटर	421	512	460	780	950
चीनी	लाख टन	11.3	30	35.6	39.5	54

मोटे रूप में यह कहा जा सकता है कि (1960=100) के आधार पर आधारभूत उद्योगों के सूचकांक 1961 में 112 से बढ़कर 1972 में 246, पूंजीगत उद्योगों में 118 से बढ़कर 227 तथा उपभोग उद्योगों में यह 106 से बढ़कर

175 जबकि सामान्य औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो 1951 में 54.8 था वह 1961 में 110.6 तथा 1977-78 में 270 होने का अनुमान है।

(6) परिवहन एवं संचार परिवहन एवं संचार व्यवस्था अर्थतन्त्र की वे रक्त धनियाँ हैं जो कृषि व उद्योगों के विकास का मार्ग प्रशस्त करती हैं। पिछले 27- 8 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास पर सार्वजनिक क्षेत्र में 13000 करोड़ रुपये व्यय किया जा चुका है। प्रथम योजना में वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अनेक राज्यों में सड़क परिवहन का भी राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। बंगलौर व कानपुर में वायुयान बनाने के कारखाने खोले गये हैं। समुद्रिक जहाज बनाने के सिपयाई विशालापट्टनम व कोचीन में कार्यरत हैं। चित्तूरजन और वाराणसी में रेल इंजन कारखाने, पेराम्बूर में रेल बेगन कारखाना रेल विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं। 35 राष्ट्रीय को भारत के वायुयान जाने हैं, 85 हवाई अड्डे हैं। 400 समुद्रिक जहाज हैं परिवहन व संचार क्षेत्र में प्रगति निम्न तालिका से स्पष्ट है —

### योजना में परिवहन एवं संचार व्यवस्था की प्रगति

विवरण	इकाई	1950-51	1968-69	19-73 74	1978-79
रेलो की लम्बाई	हजार कि.मी	54	60	61	61.5
रेलो की माल ढोने की क्षमता	करोड़ टन	9.3	20.3	21.5	26
जहाजरानी क्षमता	लाख GRT	3.9	21.4	3000	55
सतहद्वार सड़कों	लाख कि.मी	1.56	3.17	4.90	60
ढाकघर	हजार सख्या	36	102	117	130
सारघर	सख्या	8205	14000	17000	2000
टेलीफोन	लाख सख्या	N. A.	N. A.	16.4	25

भारत की जहाजरानी क्षमता पिछले 28 वर्षों में लगभग 13 गुना बढ़ गई है और जहा 1950-51 में भारतीय जहाजरानी हमारे विदेशी व्यापार का 8 प्रतिशत भाग होती थी अब यह बढ़कर 25 प्रतिशत हो गया है। सतहद्वार सड़कों की लम्बाई भी 3 1/2 गुनी हो गई है।

(7) सामाजिक सेवार्थ—भारत जैसे पिछड़े देश में निधन जनता के लिये सामाजिक सेवाओं का व्यापक कार्यक्रम भी अपर्याप्त ही रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार नियोजन, पेय जल, आवास व्यवस्था आदि पर पिछले 28 वर्षों में काफी राशि व्यय की जा चुकी है।

सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ 1950-51 में केवल 2.31 लाख शिक्षण संस्थायें थी और उसमें 235 लाख छात्र-छात्रा पढ़ते थे। 1968-69 में शिक्षण संस्थाओं की संख्या 6 लाख व छात्र-छात्राओं की संख्या 752 लाख हो गई थी। 1977-78 में छात्र-छात्राओं की संख्या 902 लाख होने का अनुमान है। यही नहीं इन्जीनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा में डिग्री एवं डिप्लोमा स्तर की प्रवेश क्षमता 1950-51 में क्रमशः 4 हजार तथा 5.9 हजार थी उसे बढ़ाकर 1968-69 में क्रमशः 25 हजार तथा 50 हजार कर दिया था। चौथी योजना में संस्थानों से प्रशिक्षितों के गुणात्मक विकास पर अधिक बल दिया गया। नयी क्षमता के विस्तार पर नियन्त्रण रहा। सब प्रयत्नों से भारत में साक्षरता का प्रतिशत 1951 में 18.5 से बढ़कर 1971 में 29.4% हो गया है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं में भी पिछले 28 वर्षों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जहाँ 1950-51 में रोगी शैयाओं की संख्या 1.13 लाख थी वहाँ 1968-69 में 2.6 लाख तथा 1973-74 में 2.81 लाख हो गई। डॉक्टरों की संख्या 56 हजार या वहाँ 1968-69 में 102 हजार तथा 1973-74 में 138 हजार होने का अनुमान है। परिवार नियोजन केन्द्रों का सारे देश में जाल बिछा दिया गया है। इस प्रकार स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं में सुधारों से मृत्यु दर 27.4 प्रतिशत हजार से घटकर अब 15 प्रति हजार हो गई है तथा प्रत्येक भारतीय की औसत आयु भी 32 वर्ष से बढ़कर अब 55 वर्ष होने का अनुमान है। अब देश में 12500 प्रवेश क्षमता के 99 मेडिकल कॉलेज हैं जबकि 1950-51 में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 30 और उनमें प्रवेश क्षमता 2500 ही थी। मलेरिया चेचक तथा अन्य कई छुआछूत की बीमारियों पर नियन्त्रण किया जा चुका है।

पिछले वर्षों के कल्याण एवं सामान्य कल्याण कार्यक्रमों पर योजनाबद्ध विकास के प्रथम 28 वर्षों में लगभग 800 करोड़ रु० व्यय किया। उनमें से 400 करोड़ रु० अनुमोचित जातियों के कल्याण कार्यक्रमों पर 300 करोड़ रु० आदिम जाति कल्याण व 100 करोड़ रु० अन्य पिछड़े वर्गों पर इस व्यय में 140 करोड़ रु० शिक्षा 110 करोड़ रु० आर्थिक विकास तथा 50 करोड़ रु० स्वास्थ्य, आवास अन्य योजनाओं पर व्यय हुआ है।

उन सबसे अतिरिक्त सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में आवास गृहों, जल-प्रदाय योजनाओं आदि पर ध्यान दिया गया है।

(7) रोजगार—मालव शक्ति मण्डलयोग के आन्वेषिक एवं समर्थक पट्टियों को ध्यान में रखते हुए पिछले 28 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 5 करोड़ अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है। पहली योजना में 75 लाख दूसरी योजना में 95 लाख, तृतीय योजना में 145 लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। चौथी योजना में लगभग 170 लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार प्रदान किये



जाने की सम्भावना थी। फिर भी देश में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि, विकास की घीमी गति व योजनाओं में मानव शक्ति नियोजन की दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण बेकारों की संख्या अब भी लगभग 4 करोड़ तक पहुँच गई है। इसमें शिक्षित बेकारों की संख्या 60 लाख है, 1980 तक देश में बेकारों की संख्या 5 से 6 करोड़ तक पहुँचने का भय है। इसी कारण छठी योजना में 49 करोड़ अतिरिक्त लोगों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य है।

(8) उपभोग एवं जीवन स्तर में सुधार—देश में विकास के फलस्वरूप आय, उत्पादन रोजगार व उपभोग में सुधार हुआ। लोगों के जीवन-स्तर में सुधार हुआ है। आज अधिकांश ग्रामीणों के पास साइकिलें, ट्रान्जिस्टर, घड़ियाँ, घरेलू सामान अच्छे कपड़े व उत्तम आवास व्यवस्था नजर आती है। स्वास्थ्य सेवाओं व शिक्षा में वृद्धि हुई है। उपभोग के प्रारम्भिक स्तर से तुलना करने पर बढ़ते जीवन स्तर व उपभोग स्तर का मोटा चित्र पामने आता है—

**प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुओं की उपलब्धता**

विवरण		1951	1978-7 (अनुमान)
खाद्यान्न	(प्रातिदिन-ग्राम में)	395	460
खाने का तेल	(प्रतिवर्ष-किलोग्राम)	27	34
चीनी	( " " )	30	75
सूती कपड़ा	( " मीटर )	11	148
विद्युत उपभोग	( " किलोवाट )	16	80

इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों की एक झलक से ही ज्ञात होता है कि पिछले 27-28 वर्षों के योजनावद्ध विकास के द्वारा मृतप्राय भारतीय अर्थव्यवस्था को प्राणवान एवं प्रगतिशील बनाया गया है। देश में औद्योगीकरण का सुदृढ़ आधार तैयार हुआ है। भारत का विदेशी व्यापार 1950-51 के मुकाबले में अब लगभग 10 गुना है। इपि में हरित क्रान्ति से कृषि उपज में तेजी से वृद्धि हुई है तथा किसानों में व्यावसायिक दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव हुआ है। परिवहन व संचार व्यवस्था में क्रान्तिकारी प्रगति हुई है पर योजनाओं में अनेक असफलताएँ भी रही हैं जिनके कारण आज जनसाधारण का जीवन संकटमय हो गया है। देश में 22 करोड़ जनसंख्या गरीबी के न्यूनतम स्तर पर है उन्हें 28 वर्षों की इस लम्बी अवधि में भी न्यूनतम जीवन स्तर की अनिवार्य वस्तुओं की पूर्ति भी सम्भव नहीं हुई। देश में बचारी द्रोपदी के चोर की भाँति बढ़ती जा रही है। आर्थिक विषमता व एकाधिकारी प्रवृत्तियों को बल मिला है। गरीब और अधिक गरीब तथा धनी अधिकाधिक धनी बनते जा रहे हैं। समाज-शास केवल एक धोया नारा प्रतीत होने लगा है। गरीबी हटाओ व आत्म-निर्भरता के सुखद स्वप्नों के काल्पनिक महल निराशा के ओकों से टह रहे हैं, जन असंतोष विभिन्न रूपों में विनाशकारी कृत्यों में रत है यह सत्ताधारी शासकों के निये व भारतीय नियोजकों के लिये एक ऐसी चुनौती है जिसका समय पर समाधान न होने

पर देश में खूनी क्रान्ति से प्रजातान्त्रिक समाजवाद, अधिनायकवाद या अराजकवाद में परिवर्तन का संकेत देती है। आपात स्थिति की घोषणा के बाद 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के लागू होने से कई नई आशाएँ बची थीं और नियोजन के क्षेत्र में एक नये दृष्टिकोण का सूत्रपात एवं युग प्रवर्तक मोड़ आया। जनता पार्टी के सत्ता में आने से तीव्रगामी आर्थिक परिवर्तनों की आशा है।

### योजनाओं की विफलताएँ (Failures of Plans)

भारतीय योजनाओं के कार्यान्वयन में अकुशलता व जनसहयोग के अभाव में अनेक विफलताएँ रही हैं और देश का आर्थिक विकास वांछित गति से नहीं हुआ। समाजवाद कोरा स्वप्न बनकर रह गया तथा गरीबी हटाओ की कल्पना बिल्कुल झूठी सिद्ध हुई। बेरोजगारी निरन्तर बढ़ती गई है। कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि से लोगों का जीवन स्तर नहीं बढ़ पाया। आर्थिक विपमताएँ बढ़ी। गरीब और अधिक गरीब और धनवान निरन्तर धनवान होते गये। जहाँ योजनाओं से जनता में जोश व विश्वास की भावना जागृत होनी चाहिये थी वहाँ निराशा व असन्तोष भडका। 2 करोड़ जनसंख्या अभी तक अपनी निर्धनता में अनिवार्य आवश्यकताएँ भी पूरी करने में असमर्थ है तो दूसरी ओर धनवानों में विलासितापूर्ण जीवन व राजशाही ठाट-बाट में गुलछर्रे उड़ाने की प्रवृत्ति प्रबल है। मुख्य विफलताएँ संक्षेप में इस प्रकार हैं—

(1) सख्यों व उपलब्धियों में गहरी खाई बढ़ी—जहाँ तीसरी योजना में तथा चौथी योजना में आर्थिक विकास की वार्षिक दर क्रमशः 5 व 5.5 प्रतिशत निर्धारित की गई थी वहाँ विकास की दर 1965 में 2.5 प्रतिशत ही थी तथा 1978-79 में विकास की दर 3.5 प्रतिशत रही। औद्योगिक उत्पादन में 8 से 10 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य था वहाँ वास्तविक वृद्धि केवल 8.0 प्रतिशत होने का अनुमान था। छाद्यान्त में आत्म-निर्भरता की कल्पना थी पर विदेशी आयातों पर निर्भरता बाद में भी बनी रही। गरीबी का भयंकर रूप सामने आया और असन्तोष के रूप में भभका।

(2) बेकारी की समस्या निरन्तर बढ़ती गई—योजनाबद्ध विकास के पिछले 27 वर्षों में बेकारी की समस्या के उन्मूलन की बात तो दूर रही, यह समस्या निरन्तर जटिल होती जा रही है। जहाँ बेकारों की संख्या 1950-51 में केवल 40 लाख थी वहाँ 1973-74 के अन्ततक बेकारों की संख्या 4 करोड़ होने का अनुमान था अब लगभग 60 लाख शिक्षित बेकार होंगे जिसमें 47.5 हजार इन्जीनियरों, डाक्टरों व तकनीकी प्रशिक्षितों के बेकार होने का अनुमान है। राष्ट्रपति श्री पी. वी. गिरि के अनुसार 1980 में बेकारों की संख्या 6.5 करोड़ होगी जबकि दीर्घकालीन योजना समिति ने भी 5 करोड़ लोगों के बेकार होने की सम्भावना व्यक्त की थी जहाँ इस ने अपनी पहली योजना के 5 वर्षों में ही बेकारी का उन्मूलन कर दिया वहाँ भारत में 28 वर्षों के योजनाबद्ध विकास में भी यह समस्या और अधिक जटिल व व्यापक होती गई। जनता पार्टी के सत्ता में आने पर अगले 10 वर्षों में बेकारी

को समाप्त करने की घोषणा उज्जवल भविष्य का द्योतक है। छठी योजना में 492 लाख अनिश्चित लोगों को रोजगार दिये जाने का लक्ष्य है।

(3) विदेशी सहायता व हीनार्थ प्रबन्ध पर अत्यधिक आश्रितता होने से देश में विदेशी विनिमय सबटो की समस्या उत्पन्न हुई तथा 1966 में रुपये का 36.5% अवमूल्यन करना पड़ा। हीनार्थ प्रबन्ध से प्रथम 18 वर्षों में 3262 करोड़ रुपये जुटाये गए। चतुर्थ योजना में इस श्रोत से केवल 857 करोड़ रुपये जुटाने का प्रावधान था पर योजना के अन्तर्गत हीनार्थ प्रबन्ध 2885 करोड़ से भी अधिक होने का अनुमान था।

(4) बढ़ते मूल्यों की समस्या व उपयुक्त मूल्य नीति का अभाव—पहली व दूसरी योजना में तो कोई निश्चित मूल्य नीति थी ही नहीं, तृतीय योजना में पहली बार मूल्य नियन्त्रण की एक ऐसी समितित घोषणा की गई जो उपभोक्ता तथा उत्पादकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए विकासोन्मुख हो पर इस नीति के कुशल कार्यान्वयन के अभाव, अनिवार्य वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि की धीमी गति तथा बड़े पैमाने पर हीनार्थ प्रबन्ध व अप्रत्यक्ष करों से मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। 1961=100 के आधार मूल्यों पर 1974 में घरेलू मूल्य सूचकांक 335 तक पहुँच गया। 1973-74 तथा 1974-75 में मूल्य वृद्धि की दर क्रमशः 15% तथा 21% रही है। परिणामस्वरूप चोर बाजारी, जमाबोरी, मुनाफाखोरी व भ्रष्टाचार बढ़ा। सामान्य जनता का जीवन दूँधर हो गया और सारी प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। आपात स्थिति के दौरान मूल्य स्तर में गिरावट आई किन्तु अप्रैल 1977 से अब तक मूल्यों में 12% से 15% वृद्धि का अनुमान है।

(5) आर्थिक विषमता व आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण में वृद्धि हुई है—यद्यपि पञ्चवर्षीय योजनाओं में आर्थिक समानता व आर्थिक सत्ता में विकेन्द्रीकरण का उद्देश्य था पर वास्तव में आर्थिक विषमता बढ़ी है, धनी अधिक धनी और गरीब अधिक गरीब हुए हैं। आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण कतिपय पूँजीपतियों व सत्ताधारियों के हाथ में हुआ है। पुराने जागीरदारों व जमींदारों के स्थान पर नये पूँजीवादी सामन्तों का उदय हुआ है। इसमें आर्थिक नियन्त्रण, घाटे की वित्त व्यवस्था व लाइसेंस पद्धति सहायक रही है। डॉ॰ के एन. राव के शब्दों में "आज आय व धन की असमानताएँ नियोजित विकास की अवधि के प्रारम्भ की तुलना में अधिक हो गई हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तत्त्व इसे समाजवाद की अपेक्षा पूँजीवादी प्रारूप के ही अधिक समीप ले जा रहे हैं।" डॉ॰ आर. के. हजारी, दत्त समिति व एकाधि-कारी आयोग आदि सबके प्रतिवेदन इस मन की पुष्टि करते हैं।

(6) समाजवाद व आत्म निर्भरता के लक्ष्य को ही बर्हना रहे—28 वर्षों के नियोजन के बावजूद भी भारत अपने खाद्यान्न की पूर्ति में आत्म-निर्भर नहीं हो पाया। प्रथम योजना में खाद्यान्न का आयात 595 करोड़ रुपये का था वह बढ़कर द्वितीय व तृतीय योजना में क्रमशः 850 करोड़ रु० व 1150 करोड़ रु० मूल्य का हो

गया। अब भी प्रतिवर्ष हमें 1200 करोड़ रु की मशीनरी, 305 करोड़ रु का लोहा-इस्पात व 1500 करोड़ रु पेट्रोलियम का आयात करना पड़ता है। समाजवाद की मुख्य कल्पना केवल सिद्धान्त बनकर रह गयी है। गरीबी का साम्राज्य व्याप्त है, आर्थिक विपत्ति व आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण हुआ है। देश की 22 करोड़ जनसंख्या निधनता का जीवन बिता रही है। कार्यशील जनसंख्या का लगभग 30% बेकारी का शिकार है। यह कौन सा समाजवाद है ?

(7) वृहद योजनाओं के चषकर में लघु योजनाओं की उपेक्षा—भारतीय नियोजकों ने बड़ी-बड़ी योजनाओं के निर्माण व कार्यान्वयन पर अधिक ध्यान दिया है तथा उनको क्रियान्वित करने में लघु योजनाओं की उपेक्षा की। वे यह भूल गये कि बड़ी तथा दीर्घावधि वाली योजनाओं में अधिक विनियोग करने में दीर्घकाल के लाभ मिलने से अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति उत्पन्न होगी तथा निश्चित क्षेत्र के लोगों को ही लाभ मिलने से क्षेत्रीय विपत्तियाँ बढ़ेंगी। परिणामस्वरूप छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं, लघु एवं कुटीर उद्योगों पर कम ध्यान दिया जाने से आद्यानुकूल लाभ न मिल सका। इसी प्रकार आधारभूत उद्योगों के विरास में उपभोग उद्योगों की उपेक्षा की गई। इसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि से लोगों के जीवन स्तर में सुधार सम्भव नहीं हुआ।

(8) आत्म निर्भरता का अभाव—योजनावद्ध विकास के 28 वर्षों की समाप्ति के बाद भी देश आत्म-निर्भर नहीं हो पाया। हमें अब तक विदेशों से खाद्यान्न का आयात करना पड़ता है। इसी प्रकार हमें औद्योगिक कच्चे माल, मशीनरी व खनिज तेल आदि के लिए विदेशी आयातों पर निर्भर करना पड़ता है। अब तेल सफ़ट बढ़ जाने के बाद भारत पर पाँचवी योजना के दौरान साधनों पर भार पड़ रहा है। जहाँ प्रथम योजना में खाद्यान्नों का कुल आयात मूल्य 595 करोड़ रु था वह द्वितीय योजना में बढ़कर 850 करोड़ रु तथा तृतीय योजना में 1150 करोड़ रु पहुँच गया। अब भी प्रतिवर्ष लगभग 305 करोड़ रु का लोहा इस्पात, 1.00 करोड़ रु की मशीनरी एवं परिवहन सामान तथा 1500 करोड़ रु का खनिज तेल, पेट्रोलियम आदि का आयात करना पड़ता है।

(9) क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि तथा असन्तुलित विकास—देश में बड़ी बड़ी योजनाओं पर अधिक धन, लाइसेंस नीति के कार्यान्वयन में व्याप्त भ्रष्टाचार, परियोजनाओं में राजनैतिक स्वार्थपरायणता, व अविवेकपूर्ण नीति से क्षेत्रीय विषमताएँ बढ़ीं। यही नहीं विकास चारों तरफ़ अधिकार लाभ बड़े भूमिामियों, राजनीतिज्ञों तथा पूँजीपतियों को मिला है। हरित-क्रान्ति का लाभ भी बड़े व समृद्ध किसानों को मिला है। इस प्रकार धनी अधिक धनी व गरीब अधिक गरीब हो गया है।

(10) केन्द्र तथा राज्य में सहयोग का अभाव—पिछले 11-12 वर्षों से राज्यों व केन्द्र के बीच मतभेद, भूमि-सुधार कार्यक्रमों को लागू करने, योजनाओं के लिए

अतिरिक्त वित्तीय साधन जुटाने, कुछ योजनाओं में पारस्परिक विवाद आदि के कारण योजनाओं के लक्ष्यों व उपलब्धियों में अन्तर रहा है। धीरे धीरे यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता विकास में बाधक बन रही है।

(11) विविध—इसके अतिरिक्त योजनाओं की विद्यता अन्य क्षेत्रों में दृष्टि-गोचर हुई है। सरकारी आन्दोलन के सख्यात्मक विकास में गुणात्मक प्रगति का अभाव रहा है। भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि को रोकने के लिये किये गये प्रयासों की सफलता नगण्य है क्योंकि अब तक केवल 350 लाख अतिरिक्त बच्चों के जन्म को रोका गया है जबकि इससे भी अधिक वृद्धि केवल एक साल में हो जाती है। आज देश में जनसंख्या में 2.5% की दर से वार्षिक वृद्धि हो रही है। वित्तीय व्यय पर अधिक ध्यान दिया है जबकि भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति का गौण स्थान रहा है।

निष्कर्ष—भारत के योजनाबद्ध विकास के 25 वर्षों में सफलताओं व विफलताओं का एक विविध संयोग रहा है जो योजना निर्माताओं को अधिक सतर्क रहने का संकेत दे रहे हैं कि थोथे नारों व राजनैतिक उद्देश्यों में लिप्त वार्षिक नीतियों से वार्षिक विकास सम्भव नहीं बरज योजनाओं का विवेकपूर्ण निर्माण, कुशल क्रियान्वयन तथा कर्मियों के अनुत्पत्ती ही परिश्रम व त्याग करने में वार्षिक विकास की सम्भावनाएँ निहित हैं। बेरोजगारी के निराकरण के लिये धन प्रधान योजनाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता थी। प्रदूषणनात्मक व्यय तथा अनुत्पादक व्ययों पर रोक लगा कर साधनों को विकास की ओर प्रवाहित करना था। भूमि सुधारों में तेजी, क्षेत्रीय विपरीतताओं में कमी, पिछड़े वर्गों के कल्याण कार्यों में वृद्धि व प्रशासन में कुशलता लाने की आवश्यकता है। विकास बढोतर श्रम, उच्च नैतिक स्तर, स्वार्थ रहित त्याग तथा सशय रहित राष्ट्र भक्ति में ही निहित है।

### भावी आयोजन के सुझाव

#### (Suggestions for Future Planned Development)

आयोजन समस्त वार्षिक रोगों की रामबाण औषधि तो है ही पर अगर औषधि का उपयोग सही ढंग से न हो तो संकट को बढा देती है। भारत के वार्षिक नियोजन की प्रक्रिया में भी उपयुक्त त्रुटियाँ रही। उसके कारण वार्षिक प्रगति मन्द रही और जनता के कष्टों में वृद्धि से निराशा का वातावरण बना। भावी नियोजन में निम्न सुझाव उपयुक्त लगते हैं—

(1) समाजवाद के लक्ष्य की सच्चे दिल से स्वीकृति—इस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिये वार्षिक नीतियों को इस प्रकार से क्रियान्वित किया जाय कि लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। यह थोथा नारा नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न कार्यक्रमों में परिलक्षित हो। बंकों का राष्ट्रीयकरण, भूमिहीनों को भूमि, शोषण से मुक्ति समाज के कमजोर वर्गों का विकास, उपयुक्त कर नीति तथा विदेशी व्यापार पर प्रभावी नियन्त्रण से समाजवाद की ओर अग्रसर होने की पूरी कोशिश की जाय।

(2) धम प्रधान शीघ्र फलदायी योजनाओं को विशेष महत्व—ये योजनाएँ बेकारी की समस्या का निराकरण करने तथा मूल्यों पर नियन्त्रण रखने में विशेष लाभदायक सिद्ध होंगी। इनसे देश में विदेशी सहायता पर भी निर्भरता कम होगी और राष्ट्र की आत्म-निर्भरता का मार्ग प्रशस्त होता। अब लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास किया जाना चाहिये। पाँचवी योजना में 160 लाख लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना का लक्ष्य था। छठी योजना में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर बल उपयुक्त है।

(3) कृषि विकास में तेजी एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण—कृषि क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि के लिये नवीन व्यूह रचना (हरित क्रान्ति) को सतर्कता एवं कुशलता से लागू किया जाय। भूमि सुधारों में तेजी लाई जाये और भूमिहीनों को भूमि का आवंटन करने, उपखंडन व उप विभाजन की समस्या के निराकरण के लिये चरदण्डी व सहकारी कृषि को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। बड़ी योजनाओं के बजाय लघु एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता दी जाय भूमि जल का उपयोग बढ़ाया जाय।

(4) आन्तरिक वित्तीय साधनों को गतिमान करना तथा विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना—भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिये विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विदेशी सहायता को कम किया जाय। चतुर्थ योजना में विदेशी साधनों को कम महत्व अच्छा समेत है। इसी प्रकार आन्तरिक साधनों में भी इस प्रकार समन्वय बँठाया जाय कि अधिग्राहक साधन कम भार तथा सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों की पूर्ति कर सकें। कृषि क्षेत्र में भी अधिक वित्तीय साधन जुटाये जायें।

(5) मूल्यों पर प्रभावी नियन्त्रण—देश में योजना की सफलता के लिये एक समन्वित मूल्य नीति आवश्यक है। मूल्य नीति, आपात नीति तथा उत्पादन नीति में परस्पर समन्वय बँठाना चाहिये। आवश्यकता इस बात की है कि स्थिरता के साथ विकास हो। चतुर्थ योजना में इस उद्देश्य को ध्यान में रखने के बावजूद भी मूल्यों पर प्रभावी नियन्त्रण नहीं हो पाया है। हीनार्थ प्रबन्ध की व्यवस्था में सतर्कता बरती जाने की आवश्यकता है।

(6) जनसंख्या नियन्त्रण—हमारी योजनाओं की असफलता का एक प्रमुख कारण जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि है। पिछले दो दशकों में जनसंख्या में तीव्र गति से (2.5 प्रतिशत वार्षिक) वृद्धि हुई है। वर्ष 1951 में जनसंख्या 36.5 करोड़ थी वह अब बढ़कर 63.5 करोड़ हो गई है। बढ़ती हुई जनसंख्या के रोजगार, खाना, वपश आवास सभी की व्यवस्था करनी पड़ी है। बढ़ती जनसंख्या की बाढ़ में योजना की प्रगति बह जाती है। अब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, उच्च जीवन स्तर, रोजगार की व्यवस्था के लिए जनसंख्या पर प्रभावी नियन्त्रण होना चाहिये।

(7) आर्थिक केन्द्रीयकरण व उत्कृष्ट उपभोग पर रोक—धन का असमान वितरण उत्कृष्ट उपभोग को बड़ावा देता है तथा साहस को हतोत्साहित करता है। आर्थिक केन्द्रीकरण से वर्ग संघर्ष की भावना प्रबल होती है। अतः इन पर रोक से समाजवाद का मार्ग प्रशस्त होगा तथा विदेशी विनिमय देश के आर्थिक विकास में सहायक होगा।

(8) निजी क्षेत्र की आर्थिक नीतियों के अन्तर्गत स्वतन्त्रता—भारतीय अर्थ-व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है और उसमें प्रजातान्त्रिक नियोजन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार छोटे रूप से आर्थिक नीतियों का निर्धारण कर उनके अन्तर्गत निजी साहसियों को स्वतन्त्र रूप से कार्य करने दे। राज्य का ध्यान प्रत्येक छोटी-छोटी बातों में न होकर केवल महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर ही रहे जिससे प्रशासनिक कुशलता बढे और दिन प्रतिदिन के हस्तक्षेप से व्याप्त भ्रष्टाचार का समापन हो।

(9) सामाजिक सेवाओं तथा उपभोग उद्योगों का विस्तार—यद्यपि विकास-शील राष्ट्रों में साधनों की स्वल्पता और अभावों की अधिकता है पर जन साधारण में आर्थिक नियोजन के प्रति निष्ठा एवं सहयोग की भावना जागने के लिये उनकी उपभोग वस्तुओं में वृद्धि तथा उनके लिये सामाजिक सेवाओं में वृद्धि की जाय। भारत में अब उपभोग उद्योगों का विकास भी साथ-साथ चलना चाहिये।

(10) प्रशासन में कुशलता की वृद्धि तथा भ्रष्टाचार पर रोक—आर्थिक योजनाओं की सफलता योजनाओं के नियाम्बन्धन की कुशलता पर निर्भर करती है। प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार से विकास कार्यक्रमों में अनावश्यक विलम्ब होता है। निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिये विकास की धलि दी जाती है। अतः इस दिशा में सुधार आवश्यक हैं।

इस प्रकार हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आर्थिक आयोजन से ही हम अपनी आर्थिक समृद्धि, राजनैतिक सुरक्षा और सामाजिक समानता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं पर नियोजन की सफलता के लिये कुशलता, समन्वय, सन्तुलन व साधनों के पूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। अतः अगर उपर्युक्त सुझावों पर अमल किया गया तो भारत में समाजवाद के स्वप्न की साकार किया जा सकता है।

### परीक्षोपयोगी प्रश्न

(1) भारतीय योजनाओं की सफलताओं एवं असफलताओं का मूल्यांकन कीजिये।

(Raj III yr B Com 1979)

संकेत—भारत में योजनावद्ध विकास की उपलब्धियों एवं विफलताओं को शीर्षकानुसार देना है।

□

## छठी पंचवर्षीय योजना (1978-83) का प्रारूप\* (DRAFT OF SIXTH FIVE YEAR PLAN 1978-83)

योजना आयोग ने उन जागतिकीय एवं आन्तरिकीय चुनौतियों का मूल्यांकन करने तथा देश में व्याप्त गरीबी, व्यापक बेरोजगारी तथा अल्पजनसंख्या आदि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निम्न पाँचवर्षीय योजना का एक वर्ष पहले ही परिष्कार कर जनता सरकार की आधिकारीय नीतियों के अनुसार छठी पंचवर्षीय योजना (1978-83) का प्रारूप राष्ट्रीय विराम परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस प्रारूप के अनुसार छठी पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय 1,16,240 करोड़ रुपये होने का प्रस्ताव है जिसमें मार्गदर्शक लेव का कुल परिव्यय 69380 करोड़ रु० तथा निचले क्षेत्र का कुल परिव्यय 46860 करोड़ रु० होने का अनुमान है। प्रारूप में 47 प्रतिशत निर्यात दर की परिचालना की गई है जो योजना के अन्त में बढ़कर 55 प्रतिशत होने की योजना है। इस योजना में अगले दस वर्षों में पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने, गरीबी को समाप्त करने तथा अधिक समानता प्राप्त समाज की स्थापना करने के लक्ष्यों की प्राप्ति पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है।

### छठी योजना के उद्देश्य एवं कार्यनीति (Objectives & Strategy of Sixth Plan)

इस योजना के प्रारूप में आधिकारिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य चार हैं जिनमें इस वर्ष की अग्रिम के भीतर—

- (i) राष्ट्रीय मोबाइल एवं बेरोजगारी तथा अल्पजनसंख्या का निराकरण,
- (ii) जनसंख्या के समग्र गरीब तबकों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार करना,
- (iii) इन क्षेत्रों में समग्र विकास के लिए राज्य द्वारा बुनियादी आवश्यकताओं जैसे पान तथा गन्ध पानी, शैक्षिक शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा प्रामाणिक मूल्य, आवास आदि की व्यवस्था करना, तथा
- (iv) अधिक समानता प्राप्त समाज की स्थापना करना।

इन प्राथमिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रारूप में सरकार की कार्यनीति (Strategy) की अग्रिम नीति उल्लेखनीय है—

\*छठी योजना का अन्तिम स्वरूप आगे के छत्र उपर अनुसार मिले।



(i) पिछले वर्षों की अपेक्षा अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर प्राप्त करना,

(ii) आय तथा सम्पत्ति की वर्तमान वियमताओं को पर्याप्त मात्रा में कम करने की दिशा में आगे बढ़ना, तथा

(iii) आत्म निर्भरता की दिशा में देश की सतत प्रगति सुनिश्चित करना।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजना प्रारूप में चार क्षेत्रों— (i) कृषि, (ii) लघु एवं कुटीर उद्योग, (iii) समन्वित ग्रामीण विकास के लिए क्षेत्रीय आयोजन तथा (iv) न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्था पर विशेष जोर दिया जाएगा।

### छठी योजना का परिचय एवं प्राथमिकताएँ

#### (Outlay & Priorities of Sixth Plan)

छठी पंचवर्षीय योजना (1978-83) का कुल प्रस्तावित परिचय 16240 करोड़ ₹ है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में 69380 करोड़ ₹ तथा निजी क्षेत्र में 46860 करोड़ ₹ व्यय का प्रावधान है। सार्वजनिक क्षेत्र का कुल परिचय 69380 करोड़ ₹ होगा जो कुल योजना परिचय का लगभग 59.7 प्रतिशत भाग है योजना प्रारूप को ग्रामोन्मुखी बनाया गया है। यही कारण है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास पर कुल योजना परिचय का लगभग 43.1 प्रतिशत भाग खर्च होगा जो पाँचवी योजना की निर्धारित राशि से लगभग दुगुनी होगी। अगले दस वर्षों में बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार के समापन के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों, यातायात, कृषि एवं सिंचाई विकास को प्राथमिकता के उच्च क्रम में रखा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र में प्रस्तावित परिचय निम्न तालिका से स्पष्ट है—

#### छठी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का परिचय (Outlay)

(1978-83)

(राशि करोड़ ₹)

क्षेत्र	परिचय	कुल परिचय का भाग
1 कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	8600	12.4%
2 सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	9650	33.9%
3 उद्योग एवं खनिज	10350	14.9%
4 शक्ति, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी	20800	30.0%
5 परिवहन एवं संचार	10625	15.2%
6 सामाजिक सेवाएँ	9355	13.5%
कुल योग	69380	100%

## छठी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र की वित्त व्यवस्था के स्रोत

(Financing of Public Sector outlay in Sixth Plan)

(करोड़ रुपये)

[A] घरेलू बजट साधन	
(i) 1977-78 की चामू दरो पर बजट अतिरेक	12889
(ii) सार्वजनिक उपधर्मो से प्राप्त शुद्ध बचत	10.96
(iii) अतिरिक्त करारोपण—केन्द्र 9000 } राज्य 4000 }	13000
(iv) बाजार ऋण	15986
(v) अल्प बचते	3150
(vi) राज्य भविष्य निधियाँ	2953
(vii) वित्तीय संस्थाओं के समयावधि ऋण	1296
(viii) विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	450
कुल बजट साधन	60020
[B] (i) विदेशी सहायता	5954
(ii) विदेशी विनिमय कोषों का प्रयोग	1180
[C] हीनार्थ प्रबन्ध (अपूर्ति अन्तर)	2226
कुल योग	69380

Source—Yojna—16 April, 1978 Page 7

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि योजना के लिये घरेलू बजट साधनों से कुल सार्वजनिक परिव्यय लगभग 85 प्रतिशत साधन जुटाये जायेंगे जबकि विदेशी सहायता से केवल 8.5 भाग प्राप्त होगा। अतिरिक्त करारोपण से लगभग 19 प्रतिशत भाग की व्यवस्था है जबकि हीनार्थ प्रबन्ध से केवल 2226 करोड़ रु० की व्यवस्था का प्रावधान भ्रमपूर्ण लगता है क्योंकि इस योजना के प्रथम वर्ष 1978-79 में ही 1950 करोड़ रुपये हीनार्थ प्रबन्ध की व्यवस्था है।

समूची छठी योजना में कुल परिव्यय 116240 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इसकी वित्त व्यवस्था भी योजना के प्रारूप में दी गयी है। अतः सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की सम्पूर्ण छठी योजना के लिये 116240 करोड़ रुपये की वित्त व्यवस्था निम्न प्रकार करने की व्यवस्था है—

(i) सार्वजनिक क्षेत्र से बचत 27444 करोड़ रुपये, (ii) वित्तीय संस्थाओं से बचत 1973 करोड़ रुपये, (iii) गैर सरकारी निगम क्षेत्र से बचत 9074 करोड़ रुपये, पारिवारिक बचत 62354 करोड़ रुपये होगी। इस प्रकार कुल आन्तरिक सहायता 100855 करोड़ रुपये होगी। विदेशी सहायता से 3955 करोड़ रुपये, विदेशी

विनिमय कोषों के धन का उपयोग 1180 करोड़ रुपये तथा चालू विकास परिव्यय के लिये बजट व्यवस्था से 10250 करोड़ रुपये जुटाये जायेंगे।

### छठी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य (1978-83)

#### (Main Targets of Sixth Five Year Plan)

छठी योजना में आधारभूत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं—

(1) राष्ट्रीय आय, बचत एवं विनियोग—योजना में 4.7% वार्षिक विकास दर की परिकल्पना की गई है जो योजना के अन्त तक बढ़कर 5.5% होने की आशा है। कृषि क्षेत्र में वार्षिक विकास दर 3.98% होगी जबकि औद्योगिक विकास दर 6.9% होने की आशा है। प्रति व्यक्ति खपत के स्तर में 1978-83 की अवधि में 2.11% की वृद्धि होगी। सकल घरेलू उत्पादन के रूप में बचतें राष्ट्रीय आय के 19.8% से बढ़कर 1982-83 में 23.4 प्रतिशत हो जायेंगी। पूंजी निर्माण की दर भी 1982-83 तक 25 प्रतिशत होने की आशा है।

(2) कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र—योजनाकाल में कृषि एवं ग्रामीण विकास पर कुल परिव्यय लगभग 43.1 प्रतिशत भाग व्यय किया जायगा। परिणामस्वरूप खाद्यान्न का उत्पादन 12.5 करोड़ टन से बढ़ाकर 14.05 करोड़ टन करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार अन्य फसलों के लक्ष्य भी ऊँचे निर्धारित किये गए हैं जो निम्न तालिका में स्पष्ट हैं—

#### कृषि उत्पादन के प्रमुख लक्ष्य (1978-83)

विवरण	इकाई	1977-78	1982-83
1. खाद्यान्न	करोड़ टन	12.5	14.05 से 14.45
2. गन्ना	" "	15.69	18.8
3. कपास	लाख गार्ड	64.3	81.5 से 92.5
4. तिलहन	लाख टन	92	112 से 115
5. रासायनिक खाद का उपयोग	" "	42	78

(3) सिंचाई विकास—योजनाकाल में सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण पर 9650 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान है जबकि पाँचवी योजना में केवल 4226 करोड़ रु० व्यय की ही व्यवस्था थी। पाँचवी योजना के चार वर्षों में 86 लाख हेक्टर सिंचाई क्षमता बढ़ी जबकि छठी योजना में 1.70 लाख हेक्टर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता बढ़ाने में

का लक्ष्य है। उसमें छोटी सिंचाई योजनाओं से 90 लाख हैक्टर तथा बड़ी एवं मध्यम योजनाओं से 80 लाख हैक्टर सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। इस प्रकार वर्तमान क्षमता 484 लाख हैक्टर से बढ़कर 654 लाख हैक्टर हो जायेगी।

(4) ऊर्जा विकास (Energy Development)—इसके अन्तर्गत विद्युत, पेट्रोलियम एवं कोयला उत्पादन के विकास का समावेश है। ऊर्जा विकास पर छठी योजना में 20150 करोड़ ₹० व्यय का प्रावधान है जिसमें विद्युत विकास पर 15750 करोड़ ₹०, पेट्रोलियम विकास पर 2550 करोड़ ₹० तथा कोयला विकास पर 1850 करोड़ ₹० व्यय की व्यवस्था है। परिणामस्वरूप योजना के अन्त तक देश में विद्युत की संस्थापित क्षमता 445 लाख किलोवाट हो जायेगी। 90 लाख पम्प सैंटो व एक लाख गांधी की विजली दी जायेगी। पेट्रोलियम का वार्षिक उत्पादन 125 लाख टन हो जाएगा। कोयले का उत्पादन 103 करोड़ टन से बढ़ाकर 1982-83 तक 149 करोड़ टन कर दिया जायेगा।

(5) उद्योग एवं खनिज विकास—छठी योजना में उद्योग एवं खनिज विकास पर 10350 करोड़ ₹० व्यय का प्रावधान है जिसके द्वारा वृहत उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ लघु एवं कुटीर उद्योगों का तेजी से विकास किया जायेगा। इस्पात उद्योग का उत्पादन 77 लाख टन से बढ़ाकर 118 लाख टन करने का लक्ष्य है। सीमेंट, उर्वरक, चीनी एवं अन्य प्रमुख उद्योगों के उत्पादन लक्ष्य निम्न तालिका से स्पष्ट है।

ग्रामोद्योगों एवं लघु उद्योगों के विकास पर 1410 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान है जबकि पाँचवी योजना में यह राशि केवल 387.8 करोड़ ₹० ही थी। इस क्षेत्र में भी उत्पादन के ऊँचे लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

#### छठी योजना में औद्योगिक उत्पादन के प्रमुख लक्ष्य (1982-83)

विवरण	इकाई	1977-78	1982-83 लक्ष्य
इस्पात (Steel)	लाख टन	77.3	118
सीमेंट	लाख टन	192	290-300
कोयला	लाख टन	1032	1490
कपड़ा-मिल क्षेत्र	करोड़ मीटर	420	460
विकेंद्रित क्षेत्र	" "	540	760
कागज एवं कागज-गत्ते	हजार टन	900	1250
एल्युमिनियम	" "	180	300
उर्वरक-नाइट्रोजन (N)	" "	2060	4100
फोस्फोरस ( $P_2O_5$ )	" "	660	1125

इस अवधि में औद्योगिक विकास की दर 6.9% होगी। खनिजों के उत्पादन में भी वृद्धि की जायेगी।

**सामाजिक सेवार्थ (Social Services)**—सामाजिक सेवाओं पर योजना काल में 9355 करोड़ रु० व्यय का प्रावधान है। शिक्षा के क्षेत्र में निरक्षरता दूर करने, शिक्षा को रोजगारोन्मुख एवं समाज के लिये सार्थक बनाने को प्राथमिकता दी जायेगी। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा। उस पर 1955 करोड़ रु० व्यय होगा।

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** पर 2095 करोड़ रु० व्यय किये जायेंगे जिससे गरीब ग्रामीण एवं शहरी जनता को चिकित्सा सुविधायें सुलभ होंगी। सक्तामक रोगों की रोकथाम, उन्मूलन एवं मलेरिया नियन्त्रण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

**रोजगार एवं बेकारी निवारण**—छठी योजना में 4.9 करोड़ अतिरिक्त मानव वर्ष रोजगार उपलब्ध करने का लक्ष्य है ताकि दस वर्षों में बेकारी एवं अर्द्ध बेकारी का समापन हो सके।

**न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम**—इस पर योजनाकाल में 4180 करोड़ रु० व्यय का प्रावधान है। जिसके फलस्वरूप योजना के अन्त तक 3.2 करोड़ बच्चों को प्राथमिक शिक्षा तथा 6.6 करोड़ प्रौढ़ों को साक्षर बनाना है। एक लाख गाँव में शुद्ध पेय जल की व्यवस्था की जायेगी। वर्तमान ग्रामण विद्युतीकरण प्रणाली को बढ़ाने के अतिरिक्त 1982-83 तक 40 हजार अतिरिक्त ग्रामों का विद्युतीकरण किया जायेगा। लगभग 80 लाख भूमिहीन मजदूरों को आवासीय भूखण्ड दिये जायेंगे। पोषाहार योजना के अन्तर्गत 26 लाख बच्चों तथा दोपहर का भोजन योजना के अन्तर्गत 40 लाख अतिरिक्त बच्चों को लाभ मिलने की आशा है।

### छठी योजना की आलोचनाएँ (Criticisms)

यद्यपि छठी पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था में तीव्र प्रगति, बेकारी का निराकरण एवं गरीबी उन्मूलन के लक्ष्यों से प्रेरित है फिर भी विद्वानों ने इसकी कई कारणों से आलोचना की है—

(1) **बहुत महत्वाकांक्षी योजना**—योजना में निर्धारित लक्ष्य बहुत ऊँचे हैं और योजना का कुल परिव्यय पाँचवी योजना के मुकाबले दुगुने से भी अधिक है जिसके लिये साधन जुटा पाना भी मुश्किल होगा।

(2) **बढ़ती बेकारी का उन्मूलन कठिन लगता है**—यद्यपि योजना के प्रारूप में अगले दस वर्षों में बेकारी तथा अर्द्ध-बेकारी का समापन करने का लक्ष्य है किन्तु मानव शक्ति नियोजन की कोई ठोस योजना के अभाव तथा रोजगार अवसरों के बढ़ाने की अपूर्ण योजना से लक्ष्य की प्राप्ति कठिन लगती है।

(3) **वित्तीय साधनों की कठिनाई**—इतनी विस्तृत योजना के लिये 13000 करोड़ रु० के अतिरिक्त कराधान की समस्या विकट होगी। बरों में चोरी की प्रवृत्ति, बढ़ते भूम्पों पर सरकार के अपव्यय के कारण जहाँ 1978-79 के पहले वर्ष में ही

1050 करोड़ रु० घाटे की वित्त व्यवस्था है वहा पूरे योजनाकाल में घाटे की वित्त व्यवस्था निर्धारित राशि 2226 करोड़ रुपये से कहीं अधिक बढ़ जाने की सम्भावना है।

(4) आय, वेतन एवं मूल्य की समन्वित नीति का अभाव—अन्य योजनाओं की भाँति इस योजना में भी आय, वेतन एवं मूल्यों की एक समन्वित नीति का अभाव है उसमें आर्थिक विषमता का निराकरण करना कठिन होगा। मूल्यों में वृद्धि के कारण योजना के बढ़ते व्यय में योजना का कार्यान्वयन कठिन हो जायेगा।

(5) आर्थिक समानता बरी कल्पना है—इस योजना में भी आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को रोकने, आर्थिक विषमता को कम करने तथा एकाधिकारी प्रवृत्तियों को रोकने की कोई ठोस योजना नहीं है यह 27 वर्षों के अनुभव से कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास को कम करने के लिये अधिक प्रभावी कार्यक्रम की आवश्यकता है।

(6) राजनैतिक मतभेदों में उत्पत्ती जनता सरकार—द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति सन्दिग्ध लगती है क्योंकि पारस्परिक मतभेदों और राजनैतिक दाव-पेचों में कुशल प्रशासन नहीं रहता और सफलता कठिन हो जाती है। कुर्सी हथियाने के हथकण्डे, दल बदल आदि भी दिव्य उत्पन्न करते हैं।

(7) योजना एवं आर्थिक उद्देश्यों की अपेक्षा राजनैतिक उद्देश्यों से भी प्रेरित है—यही कारण है कि अगले दस वर्षों में बेकारी का समापन, गरीबी का निराकरण एवं सामाजिक न्याय के उद्देश्य जनता को महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के भ्रमजाल में डालकर जनता पार्टी की सत्ता को सुदृढ़ करने का प्रयास है।

निष्कर्ष—यद्यपि योजना को बहुत महत्वाकांक्षी बताया जाता है फिर भी बेकारी, भुलमरी तथा आर्थिक विषमता को कम करने की दिशा में यह एक प्रगति-कारी कदम है। इससे न केवल बेकारी की विकट समस्या को निबटाने का बल मिलेगा वरन् अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से देश की 22 करोड़ गरीब जनता को राहत मिलेगी और उन्हें समृद्ध एवं विविधतापूर्ण जीवन यापन का सुअवसर मिलेगा। क्षेत्रीय विषमताएँ कम होंगी और आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके लिये जनता सरकार को आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर कुशल एवं स्वच्छ प्रशासन के द्वारा योजना के कार्यान्वयन में तत्परता बरतती पड़ेगी सभी लक्ष्यों की प्राप्ति सम्भव होगी और उद्देश्यों को मूर्त रूप दिया जा सकेगा।

## परिशिष्ट (APPENDIX)

आवर्ती योजना अथवा अनवरत योजना  
(ROLLING PLAN)

आवर्ती योजना की धारणा से भारतीय जनता में उत्सुकता स्वाभाविक है। स्थिर नियोजन पद्धति के कारण योजनाबद्ध विकास के पिछले वर्षों में भारतीय अर्थ-व्यवस्था एवं उसके विकास कार्यों में अनेक विकृतियाँ उत्पन्न हुई हैं। अमपूर्ण मान्यताओं एवं उनके अनिश्चितताओं पर आधारित पंचवर्षीय योजनाओं में बदलती परिस्थितियों के अनुरूप योजनाओं में परिवर्तन की उपेक्षा लक्ष्यों और वास्तविक उपलब्धियों में भारी अन्तराल के कारण जन साधारण की आशाओं और आकांक्षाओं पर पानी फिर गया। अतः आर्थिक नियोजन को अधिक व्यवहारिक, लोचशील एवं गत्यात्मक (Dynamic) बनाने के लिये जनता सरकार द्वारा पुनर्गठित योजना आयोग ने 10 सितम्बर 1977 को अपनी बैठक में भारतीय आयोजन प्रणाली में एक मौलिक परिवर्तन का फैसला कर यह घोषणा की 1 अप्रैल 1978 से छठी अनवरत योजना लागू होगी। इस निर्णय से पाँचवी योजना की अवधि चार वर्षों में ही 31 मार्च 1978 को समाप्त हो गई और पाँचवी योजना को अन्तिम वर्ष आवर्ती योजना (Rolling Plan) का पहला वर्ष हो गया।

## (आवर्ती या अनवरत योजना की धारणा)

## (Concept of Rolling Plan)

आवर्ती योजना अथवा अनवरत योजना का अभिप्राय आर्थिक नियोजन की उस तकनीक एवं विधि से है जिसके अन्तर्गत विकास लक्ष्य की समीक्षा वर्ष प्रतिवर्ष की उपलब्धियों और विकास के उपलब्ध साधनों के परिप्रेक्ष्य में की जाती है। वर्षानुवर्ष परिस्थितियों में हुए परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए योजना की प्राथमिकताओं, साधन आवृत्ति तथा लक्ष्यों में परिवर्तन एवं पंक्तिबद्ध किया जाता है जिससे नियोजन प्रक्रिया में निरन्तरता के साथ-साथ व्यावहारिकता, लोचशीलता एवं गतिमत्ता लाई जा सके।

आवर्ती योजना में आयोजन की निरन्तरता बनाये रखने के लिये नियोजन प्रक्षेप (Planning project) का सामवेश होता है। इसके लिये योजना के प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर पांच वर्षों की अवधि के बाद, प्रत्येक वर्ष के लिये वर्तमान प्रगति के आधार पर योजना की एक रूपरेखा तैयार की जाती है। इस प्रकार एक अनवरत योजना (Rolling Plan) के समाप्त होते-२ योजना निर्माताओं के पास एक प्रक्षिप्त योजना (Projected Plan) तैयार हो जाता है। जिससे नियोजन की प्रक्रिया में निरन्तरता बनी रहती है और क्रम भंग नहीं होता।

भारत में आवर्ती योजना का पहला वर्ष 1978-79 है। छठी योजना अनवरत योजना के रूप में 1978-83 की अवधि के लिये दीर्घवालीन दृष्टिकोण वाली पंच-वर्षीय योजना ही है 1978-79 की समाप्ति पर 1979-80 की वार्षिक योजना के साथ-साथ 1979-84 की पांच वर्ष की अवधि के लिये 1978-79 की समीक्षा एवं परिवर्तित परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित किये जायेंगे, इस प्रकार वष प्रतिवर्ष आगे की अवधि की वार्षिक एवं पाँच वर्षों की योजना क्रमशः 1981-85, 1982-86 1983-87 का भी प्रोजेक्शन कर लिया जायेगा। इस प्रकार छठी योजना की समाप्ति से पूर्व ही आगे 5 वर्षों के नियोजन प्रक्षेप तैयार हो जायेंगे।

प्रधानमन्त्री श्री मोरारजी देसाई ने राज्यों के मुख्यमन्त्रियों के नाम अपने प्रसारण में स्पष्ट कर दिया कि अनवरत योजना दीर्घवालीन दृष्टिकोण वाली पंच-वर्षीय योजना ही है। अतः अब पांच वर्षों की अनवरत योजना तैयार की जाती रहेगी जिसकी एक वर्ष की अवधि पूरी होने पर उसके अन्तिम वर्ष में आगे का एक वर्ष और जुड़ जायेगा। परिणामस्वरूप वर्षानुवर्ष उसकी अवधि बढ़ती चली जायेगी और हर वर्ष उसकी अवधि पांच वर्ष ही बनी रहेगी।

आवर्ती योजना की धारणा में चार आधारभूत तत्त्व हैं—(1) भूतकालीन उपलब्धियों का भावी नियोजन प्रयत्नों से एकीकरण, (2) कार्यों में समन्वय एवं दायित्व निर्धारण, (3) रोजगार अवसरों द्वारा प्रोत्साहन तथा (4) आर्थिक भविष्य तथा प्रगति मूल्यांकन के लिये कुशल सूचना व्यवस्था। इनके अभाव में आवर्ती योजना की धारणा निरर्थक सिद्ध होगी। आवर्ती योजना की धारणा बिल्कुल नयी नहीं है। इस धारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम प्रो० रेगनर प्रिन्स ने किया जिसके बाद में प्रो० गुनार मिर्डल ने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “एशियन ड्रामा” में लोकप्रिय बनाया। भारत में भी 1962 में चीनी आक्रमण के बाद प्रतिकार की पांच वर्षों की आवर्ती योजना (Five years Rolling Plan for Defence) लागू की गई थी। इसके बाद केन्द्र ने इस्पात उद्योग के विकास के लिये भी पांच वर्षों की रोलिंग प्लान लागू करने की घोषणा की थी। रक्षा योजना में यह काफी उपयोगी रही।



यह उल्लेखनीय है कि आवर्ती योजना पद्धति कई देशों में अपनाई गई है। जिसमें पोलैण्ड, रूमानिया, बल्गेरिया, चीन, जापान तथा फिलीपाईन्स प्रमुख हैं। भारत में भी वित्त वर्ष 1978-79 से यह तकनीक पूर्णतः अपनायी गयी है।

### अनवरत योजना की स्थिर योजना की तुलना में श्रेष्ठता अथवा

#### स्थिर योजना एवं अनवरत (आवर्ती) योजना में अन्तर

इन दो नियोजन पद्धतियों में काफी अन्तर है जिनमें निम्न उल्लेखनीय हैं—

(1) **तकनीकी अन्तर**—स्थिर योजना का प्रारूप तैयार करते समय विकास के लक्ष्य पांच वर्षों की निश्चित अवधि के लिये एक बारगी तय कर लिये जाते हैं और योजना के दौरान प्राप्त होने वाली उपलब्धियों का जायजा पांच साल की अवधि खत्म होने पर ही लिया जाता है।

जबकि आवर्ती योजना के लक्ष्य एक बार निर्धारित हो जाने के बाद के वर्ष प्रतिवर्ष की वास्तविक उपलब्धियों और विकास के उपलब्ध ससाधनों के परिप्रेय में प्रतिवर्ष परिवर्तनीय एवं परिवर्द्धनीय है। इससे लक्ष्यो एवं उपलब्धियों के विकास अन्तर की समीक्षा कर अगले वर्ष की नियोजन सम्बन्धी गणनाओं में महत्वपूर्ण स्थान देता है।

(2) **प्रकृति**—स्थिर नियोजन की कठोर प्रकृति है। परिस्थितियों में परिवर्तन होने तथा विकास अन्तर की उपेक्षा की जाती है अतः लक्ष्यो, प्राथमिकताओं आदि में कठोरता का रूप अपनाया जाता है।

अनवरत योजना लोचपूर्ण होती है लक्ष्यो एवं प्राथमिकताओं में समयानुकूल एवं परिस्थितियों के अनुकूल संशोधन की लोचता रहती है।

(3) **निरन्तरता**—स्थिर नियोजन में नियोजन प्रक्रिया की निरन्तरता का अभाव होता है जबकि अनवरत योजना में आये से आये नियोजन प्रक्षेप (Planning projections) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

(4) **सजगता**—स्थिर योजना में विकास की रणनीति पांच वर्षों के लिये स्थिर मान ली जाती है अतः प्राथमिकताओं, लक्ष्यो की वास्तविक उपलब्धियों व अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्प्रवाहों के प्रति सजगता का अभाव रहता है जबकि अनवरत योजना में वर्षानु-वर्ष प्राथमिकताओं, लक्ष्यो के मुकाबले उपलब्धियों तथा अर्थ-व्यवस्था के अन्तर प्रवाहों के प्रति जागरूकता रहती है।

(5) **व्यवहारिकता**—स्थिर योजना में सामान्यतः लक्ष्यो और उपलब्धियों में काफी अन्तर हो जाता है अतः नियोजन व्यावहारिक लगता है जबकि अनवरत योजना अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक एवं वास्तविकता के निम्न होता है।

(6) रणनीति—स्थिर योजना में पांच वर्षों के विकास की एक विशिष्ट रणनीति (Strategy) होती है जबकि अनवरत योजना की रणनीति आर्थिक परिस्थितियों एवं उद्देश्यों के अनुरूप ढाली जाती है अर्थात् अनवरत योजना की रणनीति देश की आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप आर्थिक विकास के बदलते दृष्टिकोणों (Rolling perspectives of Development) को भी स्वीकार करती है।

**अनवरत योजना (Rolling Plan) के लाभ/गुण**

अनवरत योजना की तकनीक के अनेक गुण एवं लाभ हैं जिनमें निम्न उल्लेखनीय हैं—

(1) परिवर्तनशीलता एवं लोचता—इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हर वर्ष योजना पर तात्कालिक आर्थिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में लक्ष्यो एवं वास्तविक उपलब्धियों की समीक्षा करने से विकास अन्तर (Development Gap) को पाटने के लिये योजना में आवश्यकतानुसार परिवर्तन एवं संशोधन किया जा सकता है। लक्ष्यो एवं वित्तीय संशोधनों में लोचशीलता बनी रहती है।

(2) निरन्तर प्रगति समीक्षा—अनवरत योजना में योजना के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में आकड़े लगातार एकत्रित किये जाते हैं अतः हर वर्ष योजना के लक्ष्यो एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन होता है।

(3) गत्यात्मक दृष्टिकोण—अनवरत योजना में गत्यात्मक दृष्टिकोण पाया जाता है क्योंकि योजना में समयानुकूल एवं परिस्थितियानुकूल तालमेल बैठाने की तत्परता रहती है।

(4) मूल उद्देश्यों के प्रति जागरूकता बनी रहती है—क्योंकि उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये ही तो सतत योजना कायशील रहती है। योजना को कार्यान्वित करने वाले उद्देश्यों से भटक नहीं सकते हैं।

(5) नियोजन की निरन्तरता—अनवरत योजना का यह भी लाभ है कि इसमें हर वर्ष से अन्त में अगले पांच वर्षों के योजना का लक्ष्य आदि तैयार निय जाते हैं अतः नियोजन प्रक्षेपो (Planning Projections) के कारण योजना की निरन्तरता की प्रक्रिया अविरल गति से चलती रहती है। उसमें कहीं योजना छुट्टी (Plan Holiday) की समस्या नहीं आती जैसी भारत में 1966-69 की अवधि में आई।

(6) व्यावहारिक नियोजन—अनवरत योजना में योजनायें वास्तविकता के निवृत्त और व्यावहारिक बनी रहती हैं क्योंकि लक्ष्यो और उपलब्धियों का सामन्वज्य रहता है। निरन्तर योजना की मभीक्षा होनी रहने से अनिश्चितता एवं अव्यवहारिकता को समाप्त कर दिया जाता है।

(7) नारी नियोजन में सुविधा तथा आर्थिक भविष्यवाणियों में सत्यता — अनवरत योजना में अव्यवस्था में योजना का निरन्तर मूल्यांकन होता रहता है। अतः विश्वमनीय आकड़े भावी निराजन तथा भविष्यवाणियों का सरल बना देते हैं।

## अनवरत योजना की आलोचनाएँ (Criticisms of Rolling Plan)

यद्यपि अनवरत योजना तकनीक नियोजन की बहुत ही उपयुक्त, व्यावहारिक गत्यात्मक एवं लोचपूर्ण विधि है फिर भी इस धारणा का भारत में कुछ विद्वानों ने विरोध किया है। प्रमुख आलोचनाएँ इस प्रकार हैं:—

(1) योजनावद्ध विकास की समाप्ति का प्रयास.—श्रीमति गांधी ने राज-नैतिक लाभ की दृष्टि से जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया कि आवर्ती योजना द्वारा योजनावद्ध विकास को समाप्त किया जा रहा है। उसके अनुसार रोलिंग प्लान से प्लानिंग को रोल-अप किया जा रहा है।

(2) योजना की विफलता को छिपाने का चतुराईपूर्ण प्रयत्न.—कुछ विद्वान यह आरोप लगाते हैं कि आवर्ती योजना सरकार का एक ऐसा चतुराई पूर्ण प्रयत्न है जिससे योजना आयोग पर योजना की असफलताओं का दोषागोपण नहीं किया जा सकेगा क्योंकि जो लक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे उन्हें पहले ही समायोजित कर लिया जायेगा।

(3) जनता की सहमति नहीं ली गई:—कुछ विद्वान कहते हैं कि भारत में प्रजातान्त्रिक नियोजन (Democratic Planning) की व्यवस्था है जिसमें जनता की सहमति के बिना योजना प्रणाली में परिवर्तन अनुचित है। इसी प्रकार राज्यों की भी सहमति न लेकर उनसे विश्वास प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया गया, यह अनुचित है।

(4) पंचवर्षीय योजना की प्रणाली अधिक वैज्ञानिक थी:—यदि उसमें सफलता-विक्रम का स्पष्ट संकेत होना है किन्तु अनवरत योजना में असफलता को छिपा कर समायोजित करने से भावी योजनाओं की सफलता की तुलना पिछली पंच-वर्षीय योजनाओं से सम्भव नहीं हो सकेगी।

(5) नेहरू जी के समाजवादी आर्थिक दर्शन की समाप्ति:—अनवरत योजना नेहरू जी द्वारा कार्यान्विष्ट योजना पद्धति का समापन उनके आर्थिक दर्शन की समाप्ति का संकेत है।

निष्कर्ष:—योजना आयोग के अनुसार आवर्ती योजना न तो किसी को गुमराह करने का प्रयास है और न नियोजन की समाप्ति ही वरन् आवर्ती योजना प्रणाली का उद्देश्य नियोजन को अधिक कुशल, लक्ष्यपूर्ण गत्यात्मक एवं व्यावहारिक बनाने का त्रिांनकारी कदम है जिसमें नियोजन प्रक्रिया की निरन्तरता और स्व-चालिता के तत्व विद्यमान हैं। योजना की प्रतिवर्षीय समीक्षा, उद्देश्य की पूर्ति हेतु समयानुसार परिवर्तन, तथा लक्ष्य एवं उपलब्धियों में व्यावहारिकता लाने के लिये यह प्रणाली बड़ी वैज्ञानिक है। योजना आयोग के प्रमुख सदस्य प्रो० राजकृष्ण ने बार-बार दोहराया है कि आवर्ती योजना में पंचवर्षीय परिकल्पना को पूर्णतः छोड़ा नहीं गया है और न विकास के लक्ष्यों के अनुरूप तरीकों एवं कार्य-प्रणाली में कोई आमूल-मूल या आधारभूत परिवर्तन है। आवर्ती योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मूल्यांकन सम्बन्धी

व्यवस्था कितनी कुशल एवं विश्वसनीय आकड़े उपलब्ध करना है तथा सर्राफ़ उन्हें कितनी तत्परता से मूर्तरूप देती है।

## II अन्त्योदय (Antyodaya) योजना

भारत में योजनाबद्ध विकास के पिछले 3 दशकों में देश तेजी से आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है किन्तु विकास का अधिकांश लाभ समाज के अपेक्षा कृत समृद्ध वर्ग तक ही सीमित हो जाने से देश का एक बड़ा तबका गरीबी का असह्य जीवन जीने को विवश हो रहा है। अब अन्त्योदय योजना ऐसे गरीबों के आर्थिक उत्थान की योजना है जो विकास के क्रम में सबसे अन्त में खड़े हैं। राजस्थान में अन्त्योदय योजना गरीबों के उत्थान की सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य राज्य को प्रत्येक गाँव के पाँच सर्वाधिक गरीब परिवारों का आर्थिक दृष्टि से विकास करना है।

राजस्थान की अन्त्योदय योजना में पहले वर्ष में 33000 गाँवों के लगभग 16 लाख ऐसे गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान की व्यवस्था की गई है जो विकास क्रम की पंक्ति में सबसे अन्त में खड़े हैं। प्रथम 16 लाख परिवारों के आर्थिक उत्थान के अनुभव के आधार पर अगले वर्ष फिर इसी प्रकार अन्य गरीब परिवारों को विवश हेतु लिया जायेगा और यह क्रम भविष्य में भी चलता रहेगा।

**अन्त्योदय योजना के परिवारों के चयन की विधि —**

अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत सहायता देने के लिये गरीब परिवारों के चयन में निम्न प्राथमिकताएँ निर्धारित की गई हैं।

(1) साधनहीन परिवार, अश्वनता, अपंगता अथवा वृद्धावस्था के जीवन यापन की असमर्थता वाले परिवार अथवा 15 से 59 वर्ष की आयु श्रेणी में कोई कमाने वाले व्यक्ति का न होना।

(2) साधन हीन किन्तु पाँच व्यक्तियों के ऐसे परिवार में वार्षिक आय 1200 ₹० से कम हो। साधारण तथा भूमिहीन मजदूर एवं दलक़ार ऐसी श्रेणी में आते हैं।

(3) द्वितीय श्रेणी में 1200 से 1800 ₹ की वार्षिक आय वाले परिवार।

(4) वे परिवार जिनके पास भूमि व सम्पत्ति तो हो किन्तु वे गरीबों रेखा (प्रति व्यक्ति 55 ₹० मासिक आय) से भी नीचे की स्थिति में हो।

### कार्य-क्रम का क्रियान्वयन

राज्य के 33000 गाँवों के 1.6 लाख परिवारों की अलग-अलग आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठ भूमि के कारण एक ही कार्यवाही से उनका उत्थान सम्भव नहीं हो सता अब गरीब परिवारों को दैनिक कार्यक्रमों के तहत सहायता दी जायेगी राज्य के सभी विभागत कार्यक्रम अन्त्योदय योजना का अंग माने जायेंगे और इन कार्यक्रमों के महत्त पहला काम अन्त्योदय परिवारों की मदद करना होगा। अन्त्योदय परिवारों को निम्न प्रकार से आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

(1) भूमि आवंटन—गाँवों में उपलब्ध भूमि अन्त्योदय परिवारों को ही दी जायेगी। रेगिस्तानी इलाकों में जहाँ कहीं भूमि आवंटन पर बाधन्दी है वहाँ भी

अन्त्योदय परिवारों को अपवाद स्वरूप भूमि आवंटन की जायेगी। इस वर्ष 40 हजार अन्त्योदय परिवारों को भूमि आवंटन का लक्ष्य है।

(2) कृषि उपकरण एवं बैल —भूमि आवंटन के साथ-साथ अन्त्योदय परिवारों को खेती करने के लिये बैल व कृषि उपकरण खरीदने के लिये सहायता दी जायेगी। सघु कृषक योजना और सूखा सम्भावित क्षेत्र का कार्यक्रम के तहत उनके खर्च की राशि का 33% अनुदान भी दिया जायेगा।

(3) पशु ऋण:—डेयरी निगम वाले क्षेत्रों में अन्त्योदय परिवारों को ग्नु खरीदने के ऋण दिये जायेंगे जिस पर 33% अनुदान की भी व्यवस्था है, दूध विपणन राज्य विपणन सघ द्वारा होगा।

(4) भेड़ व बकरी का रेवड —राज्य के जिन 10 जिलों में विशेष पशु पालन कार्यक्रम चल रहा है उनके अन्त्योदय परिवारों को 30 भेड़ों व एक भैंस की रेवड दिया जा सकेगा और इनके विपणन की व्यवस्था भी राज्य सहकारी भेड़ एवं ऊँट सघ से जोड़ दिया जायेगा।

(5) बकरी की इकाई, कुकुट पालन एवं शुकर विकास सहायता —अन्त्योदय परिवारों को उनकी आवश्यकतानुसार 10 बकरी की इकाई, शहरों के पाम वाले गावों के अन्त्योदय परिवारों को कुकुट पालन के लिये आर्थिक सहायता तथा भरतपुर एवं अलवर जिलों में शुकर विकास कार्यक्रम के तहत सहायता दी जायेगी।

(6) रोजगार एवं गृह-उद्योग विकास:—अन्त्योदय परिवारों को ढ़ी सहायता में छोटी माप करघा इकाईया स्थापित करवाने चरने एवं करघे वितरित करने सँग चालिन तेल धानिया लगवाने, चमड़ा कमाने व खाती गिरी के व्यवसाय व चूने के भट्टे लगवाकर सहायता की जायेगी। इनके खादी प्रामोद्योग निगम की सक्रिय सहायता रहेगी। 15 किलोमीटर की परिधि वाले बड़े उद्योगों में अन्त्योदय परिवारों को रोजगार की प्राथमिकता दी जायेगी।

(7) राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में:—अन्त्योदय परिवारों को कृषि योग्य भूमि आवंटन करने तथा हर प्रकार की सहायता दी जायेगी। रोजगार में भी प्रमुखता रहेगी।

(8) बुद्ध, असहाय एवं अपंगों को पेन्शन —बिना सम्पत्ति एवं बिना कमाने वालों के अभाव प्रसिद्ध आश्रितों को 40 रु० महावार पेन्शन दी जायेगी।

(9) खनिज एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों में रोजगार व व्यवसाय की प्राथमिकता —अन्त्योदय परिवारों को खनिज क्षेत्रों में उचित रोजगार व खनन पट्टों में प्राथमिकता दी जायेगी, इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग में रोजगार प्राथमिकता व चाहने पर काम उपलब्ध किया जायेगा।

### अन्त्योदय योजना की प्रगति की समीक्षा

(अप्रैल 1977 से जून 1979)

2 अक्टूबर 1977 से प्रारम्भ इस योजना के अगले पाँच वर्षों में लगभग 6 लाख निर्धन परिवारों का चयन किया जायेगा और इनमें से 29 लाख परिवारों को 105 करोड़ रु० के ऋण उपलब्ध किये जायेंगे और शेष 41 हजार परिवारों को वृद्धावस्था पेन्शन, 44 हजार परिवारों को भूमि आवंटन, 85 हजार परिवारों को खादी एवं प्रामोद्योग तथा 36 हजार परिवारों को प्रमोद्योग एवं कुटीर उद्योगों के तहत

(Source) पेम्फ्लिट राजस्थान में जनता सरकार के दो वर्ष जून 1979)

लाभान्वित करने का लक्ष्य है इसके लिये सरकार को 5 वर्षों में 50 करोड़ रु० व्यय की आवश्यकता होगी।

आज अन्त्योदय का नाम राजस्थान के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। राजस्थान के पद-चिन्हों का अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश, हिमालय प्रदेश, उड़ीसा तथा बिहार राज्यों ने भी अपने यहाँ इस कार्यक्रम को प्रारम्भ किया है इसके अन्तर्गत सारी सरकारी गति विधियाँ दरिद्र नारायण के सेवार्थ केन्द्रित की गई है अब तक विभिन्न रूपों में दी गई सुविधायें निम्न हैं।

### अन्त्योदय योजना से लाभान्वित परिवार

विवरण	प्रथम चरण में चयनित परिवार (हजार में)	द्वितीय चरण में चयनित परिवार (हजार में)	कुल सरपचा (हजार में)
भू-आवटन	43 8	13 5	57 3
श्रृण-स्वीकृति	57 8	32 9	89 7
रोजगार प्रदान	6 8	3 2	10 0
वृद्धावस्था पेंशन	24 1	20 4	44 5
आय लाभ	5 9	1 1	7 0
कुल योग	138 6	70 2	208 8
प्रतिशत उपलब्धि	89 6	62.3	78 1

अब तक 17 4 करोड़ रु० की राशि अन्त्योदय परिवारों को श्रृण के रूप में स्वीकृत की जा चुकी है। कर्ज से राहत देने के लिये 500 रु० तक के सरकारी श्रृणों को अपलिखित किया जा रहा है तथा 500 से 1000 तक के सरकारी श्रृणों वालों का ऋण अपलिखित किया जा रहा है।

स्पष्ट है कि अब तक 57 3 हजार परिवारों की कुल भूमि आवंटित की गई है और लगभग 89 4 हजार व्यक्तियों को अपना रोजगार प्रारम्भ करने के अपने पेटों पर खड़ा होने के लिये 17 4 करोड़ रु० के ऋण दिये जा चुके हैं। सर्वाधिक उपलब्धियाँ उदयपुर, जोधपुर, झुंझनेर एवं जालंधाड़ा जिलों में रहा है। 44 5 हजार परिवारों का वृद्धावस्था पेंशन देने से सामाजिक सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ है। कुल मिलाकर राज्य के 209 परिवारों को निधनता से ऊपर उठाने का प्रयास किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत चुने गये परिवारों में 95% अल्प सरपचा तथा पिछड़ी जाति के हैं।

यद्यपि अन्त्योदय परिवारों के चयन में विषम एवं पक्षपात के आरोप लाये गये हैं फिर भी अन्तर्गत पर पावन कार्यक्रम दरिद्र नारायण के अधिक उत्थान एवं सामाजिक सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगा। योजना आयोग ने भी इस कार्यक्रम की प्रशंसा की है तथा 2 करोड़ रु० योजना व्यय में स्वीकार किया है रिजर्व बैंक भी विशेष सुविधाएँ देने की पहल कर रहा है।

## भाग 2 (Part-Two)

### स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में आर्थिक विकास

(ECONOMIC DEVELOPMENT IN INDIA  
SINCE INDEPENDENCE)

- ✓ 1 स्वतन्त्रता प्राप्ति की पूर्व संध्या को भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा  
(State of Indian Economy on the eve of Independence)
- ✓ 2 कृषि नीति एवं विकास  
(Agricultural Policy & Development)
- 3 कृषि की नवीन द्यूह-रचना बनाम हरित क्रांति  
(New Agricultural Strategy & Green Revolution)
- ✓ 4 भारत में भूमि-सुधार (Land Reforms)
- 5 भारत में कृषि विपणन (Agricultural Marketing)
- ✓ 6 सामुदायिक विकास (Community Development)
- 7 औद्योगिक नीति (Industrial Policy)
- ✓ 8 औद्योगिक विकास की प्रवृत्तियाँ अथवा भारत में औद्योगीकरण  
(Industrialisation or Trends in Industrial Development)
- ✓ 9 उद्योगों में राज्य की भूमिका (Role of the State in industries)
10. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विकास (Growth of Public Sector)
- ✓ 11 पूँजी गहन बहत् उद्योग (Capital Intensive Industries)
- ✓ 12 श्रम-प्रधान सघु एवं कुटीर उद्योग  
(Labour Intensive Small Scale Industries)
- 13 भारत का विदेशी व्यापार व विदेशी व्यापार नीति की प्रवृत्तियाँ  
(Trends in Composition and Direction of Foreign Trade & Commercial Policy)
- ✓ 14 भुगतान सन्तुलन (Balance of Payments)
- 15 1957 से रेल यातायात का विकास (Growth of Rail Transport)
- ✓ 16 1947 से सड़क यातायात का विकास  
(Growth of Road Transport)
17. 1947 से वायु एवं यातायात का विकास  
(Growth of Air, Transport Shipping and Inland Water Transport)

# स्वतन्त्रता प्राप्ति की पूर्व संध्या को भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा

(The State of Indian Economy on the Eve of Independence)

भारतीय अर्थव्यवस्था जो अंग्रेजी शासन से पूर्वे घन धान्य पूर्ण, सम्पन्न तथा विश्व के अन्य देशों के मुकाबले काफी उन्नत थी अंग्रेजी शासन के शोषण व दोषपूर्ण नीतियों से 1947 की स्वतन्त्रता प्राप्ति तक लगभग निष्क्रिय हो गई थी। धी-बूझ की नदियाँ बहने लाले तथा सोने की चिड़िया कहलाने लाले देश मे स्वतन्त्रता प्राप्ति की पूर्वे संध्या को गरीबी, अशिक्षा, अन्धविश्वास, विषमता तथा शोषण का साम्राज्य व्याप्त था। डॉ० बी० बी० सिंह के अनुसार सत्रहवीं शताब्दी मे भारत ससार का अधिकतम धनी देश एशिया की कृषि जननी व सभ्यता का औद्योगिक निर्माण गृह था।" वही भारत अंग्रेजों की घातक एवं दोषपूर्ण वार्षिक नीतियों से स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्वे तक पूर्णतः मृतप्राय बन गया था। लघु उद्योगों का पूर्णतः पतन हो गया था। कृषि मे विकास की वार्षिक दर 0.5% तथा उद्योगों मे केवल 2.5% रह गई थी। दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था ने जागीरदारी व जमींदारी प्रथा को चरम सीमा पर पहुँचा दिया था। भोली भाली जनता निर्धनता, बेकारी व शोषण से त्रस्त थी। आर्थिक विषमता, अन्धविश्वास व अशिक्षा का बोलबाला था। गुलामी की जजीरो से जकड़े भारतीयों मे धीरे धीरे स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये विरोध की ज्वाला इतनी भनक चुकी थी कि अन्ततः अंग्रेजों को बाध्य होकर 15 अगस्त 1947 को भारतीय जनता को स्वतन्त्रता प्रदान करनी ही पड़ी। फिर भी जाते-जाते "फूट डालो व राज्य करो" की कूटनीति के अन्तिम दाव मे देश को भारत एवं पाकिस्तान मे विभाजित कर ही गये। स्वतन्त्रता प्राप्ति की पूर्वे संध्या को भारतीय अर्थ-व्यवस्था की हीन दशा की भ्रूण निम्न तथ्यों से मिलती है—

1 राष्ट्रीय आय—मोटे रूप मे किसी अर्थव्यवस्था का अन्दाज राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय से लगाया जा सकता है। इस सम्दर्भ मे देखने पर 1947 मे भारत की राष्ट्रीय आय 8650 करोड रु थी तथा प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 248 रु थी जो कि विश्व के विकसित देशों की तुलना मे नगण्य थी। यही नहीं राष्ट्रीय आय का 50% से भी अधिक भाग कृषि से प्राप्त होवा था। औद्योगिक उत्पादन का राष्ट्रीय आय मे केवल 10% से 12% भाग था। राष्ट्रीय आय में



वार्षिक वृद्धि की दर 1 से 1.5% थी। राष्ट्रीय आय के वितरण में घोर असमानता व्याप्त थी।

2 वृद्ध एव विनियोग—राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय का नीचा स्तर होने से वृद्ध, उपभोग व विनियोग का स्तर भी बहुत नीचा था। वृद्धों राष्ट्रीय आय के लगभग 4 से 5% थी तथा विनियोग की वार्षिक दर 6 से 7% थी जब कि ग़रब वृद्ध व विनियोग की दर क्रमशः 22% तथा 23.5% है।

3 कृषि की दयनीय दशा व दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था—स्वतन्त्रता प्राप्ति की पूर्व संध्या को कृषि की शोचनीय दशा थी। कृषि में वार्षिक विकास की औसत दर 0.5% थी। कुल क्षेत्रफल 55.8 करोड़ एकड़ में से केवल 24 करोड़ एकड़ (अर्थात् कुल भूमि के 43%) में खेती की जाती थी। उसमें से केवल 4.7 करोड़ एकड़ में सिंचाई होती थी अर्थात् कृषि योग्य भूमि के केवल 20% भाग में सिंचाई व्यवस्था थी और शेष 80% भाग मानसून पर निर्भर था। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश उद्योगों के बच्चे माल उत्पादन उपनिवेश बना दिया था। खाद्यान्न का उत्पादन 4.4 करोड़ टन, चाय का उत्पादन 55.7 करोड़ पौण्ड तथा मूँगफली का उत्पादन 31 लाख टन था। खाद्यान्न का निर्यात अभाव था और विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ती जा रही थी। जहाँ देश में सूई तथा पटसन की वार्षिक मांग क्रमशः 42 लाख व 70 लाख गांठें थी वहाँ उत्पादन क्रमशः 26 लाख गांठें तथा 17 लाख गांठें ही थी। विभाजन के कारण पटसन उद्योग भारत में तथा पटसन उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने से उद्योग को सफट का सामना करना पड़ रहा था।

अंग्रेजों की दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था से भारतीय कृषि में जमींदारी व जागीरदारी प्रथा के कारण कृषकों का श्रापण हो रहा था। भूमिहीनों की दशा तो और भी शोचनीय हो गई थी। जागीरदारों के जुल्मों व उनके विलासिता पूर्ण जीवन से कृषि की दशा दयनीय थी। भूमि पर उत्पत्ति का स्तर बहुत नीचा था।

4 औद्योगिक पिछड़ापन—स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय 1947 में देश औद्योगिक दृष्टि से भी काफी पिछड़ा था। आधारभूत और मूलभूत उद्योगों का तो निर्यात अभाव था ही पर उपभोग उद्योग भी अपनी पिछड़ी अवस्था में थे। आधुनिक उद्योगों का जो कुछ विकास 1940 के बाद हुआ था वह देश की विशालता व आवश्यकता को देखते हुए नगण्य था। औद्योगिक विकास की वार्षिक दर 1 से 1.5% ही थी और उद्योगों से राष्ट्रीय आय का लगभग 10-12% भाग प्राप्त होता था। लघु एव कुटीर उद्योगों का प्रायः पतन हो चुका था। बड़े पैमाने के उद्योगों में नियोजित श्रमिकों की संख्या लगभग 27 लाख थी। जखर तथा सीमेंट के अभाव के कारण उनके वितरण में राजन व्यवस्था लागू थी। वनस्पति प्रमुख उद्योगों का उत्पादन इस प्रकार था—

## 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय प्रमुख उद्योगों का उत्पादन

तेयार इस्पात	9 97 लाख टन	सूती वस्त्र	391 करोड़ गज
सीमेन्ट	15 00 " "	सूती धागा	136 7 करोड़ पौण्ड
शक्कर	9 000 " "	पटसन का माल	9 6 लाख टन

खनिजों का उत्पादन भी बहुत कम था और जो खनिज निकाले जाते थे उनमें भी अध्रक तथा मैंगनीज का क्रमशः 98% तथा 90% भाग निर्यात कर दिया जाता था। कच्चा सोहा भी निर्यात किया जाता था। विद्युत शक्ति क्षमता 13 96 लाख किलोवाट थी जिसमें  $\frac{2}{3}$  भाग कोयले तथा खनिज तेल से प्राप्त होती थी जबकि जल-विद्युत क्षमता 4 लाख किलोवाट थी।

5 परिवहन एवं संचार—ग्रंथव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण देश की परिवहन एवं संचार व्यवस्था भी अध्रकसित एवं अपर्याप्त थी। 1947 में रेलों की कुल लम्बाई 34159 मील थी जिनमें 15639 मील ग्राइनेज 14957 मील मीटर गेज तथा 3563 मील नेरी गेज रेल लाइनों थी और उनमें सरकार की 667 करोड़ की पूंजी लगी हुई थी। सड़कों की दशा भी दयनीय थी। दश में 1947 में सड़कों की कुल लम्बाई 2 39 लाख मील थी जिसमें 86 हजार मील सड़कें पक्की व 1 53 लाख मील लम्बी कच्ची सड़कें थीं। जहाँ इंग्लैंड व अमेरिका में प्रति 100 वर्ग मील में सड़कों की लम्बाई क्रमशः 200 व 100 मील थी वहाँ भारत में यह लम्बाई 19 मील ही थी।

जहाजरानी की कुल क्षमता 3 लाख जी आर टी थी। जहाज बनाने का एक कारखाना विशाखापट्टनम में था जिसमें 1946 तक केवल 3 जलयान बनाए गये थे। अधिकांश माल विदेशी जहाजों से लाया जाता था। वायु परिवहन भी नाम मात्र था। 10 वायु परिवहन कम्पनियाँ थी जिनके पास लगभग 170 छोटे-मोटे वायुयान थे। 1947 में भारत में 2 55 लाख यात्रियों को 93 6 लाख मील लम्बी वायु-सेवा उपलब्ध की गई थी।

संचार व्यवस्था भी अत्यन्त पिछड़ी थी।

6 मुद्रा एवं बैंकिंग—1947 में देश में केवल 558 बैंक थे। उनके कार्यालय की कुल शाखाएँ 5532 तथा उनकी कुल जमा 1012 करोड़ रुपये थी। बैंकिंग विकास तथा नियन्त्रण के लिये कोई विशेष विधान नहीं था। भारतीय कंपनी अधिनियम की बैंकिंग सम्बन्धी कुछ धाराएँ बैंकिंग प्रणाली के सुनिश्चित विकास व नियन्त्रण में अपर्याप्त थी। बैंकों के फैल होने की प्रवृत्ति से जनता में उनके प्रति विश्वास उठ गया था।

मुद्रा निर्गमन रिजर्व बैंक के हाथ में था और प्रानुपातिक कोष प्रणाली के

अन्तर्गत 40% कोष (उसमे 40 करोड रुपये का सोना) रखकर नोट प्रचलित किये जाते थे। उपर्युक्त मौद्रिक नीति का अभाव था। 1947 को 31 मार्च को रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित नोटों का मूल्य 1242 करोड रुपये था। द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल में मुद्रा-स्फीति का दुष्प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा था।

7 विदेशी व्यापार—भारत का विदेशी व्यापार 1947 में कुल विश्व व्यापार का लगभग 4% था। कुल विदेशी व्यापार 856 करोड रु था उसमें 446 करोड रु. के आयात तथा 408 करोड रु का निर्यात होने से विदेशी व्यापार का घाटा 38 करोड रु था जबकि 1946 में विदेशी व्यापार का घाटा केवल 11 करोड रु ही था। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व भारत का व्यापार शेष प्रायः हमेशा पक्ष में ही था। निर्यातों में औद्योगिक वस्त्रों माल, चाय, तिलहन, अन्न, मँगनीज, मसाले व तम्बाकू की प्रधानता थी। परम्परागत वस्तुओं का निर्यात में लगभग 75% भाग था जबकि आयातों में निर्मित माल, मशीनें, रसायन, बिजली व परिवहन के भारी सामान की प्रधानता तथा खाद्यान्नों का कुछ भाग होता था। भारत के विदेशी व्यापार में ब्रिटेन का मुख्य स्थान था। उसके बाद अमेरिका व पश्चिमी राष्ट्रों का स्थान था। रूस के साथ विदेशी व्यापार नगण्य था।

8 लोक वित्त—भारत सरकार को 1946-47 में करो से कुल आय लगभग 391 करोड रु थी जबकि कुल व्यय 444 करोड रु था। इस प्रकार राजस्व खाते में लगभग 45 करोड रु का घाटा था जबकि पूँजी खाते में लगभग 62 करोड रु का घाटा था। सरकार को कुल कर राजस्व का 22% सीमा शुल्क से, 11% केन्द्रीय भाववारी से, 23% भाग शाय कर तथा 19% निगम कर से प्राप्त होता था। अ-कर राजस्व नगण्य था। इसी प्रकार राजस्व का 62.4% भाग प्रतिरक्षा तथा 8.9% भाग नागरिक प्रशासन पर खर्च होता था जबकि विनाश व्यय नाम-मात्र का था। ब्रिटिश शासकों ने अपनी सत्ता को बनाये रखने के लिये सैनिक शक्ति पुलिस आदि पर ही ध्यान देकर भारतीय नागरिकों को दवान की अमफल चेष्टा की।

इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय तक भारतीय अर्थ-व्यवस्था प्रायः निष्क्रिय, गतिहीन व मृत्प्राय हो गई थी। शोषण, निर्धनता, आर्थिक असमानता, अक्षिा, अ-धविश्वास व व्यापक अभावों का साम्राज्य था।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की दुर्दशा,  
निष्क्रियता व गतिहीनता के कारण

(Causes of Stagnation & Downfall of Indian Economy  
During British Government)

जो भारतीय अर्थव्यवस्था सत्रहवीं शताब्दी तक आर्थिक दृष्टि से धन-पाय

पूर्ण, सम्पन्न एवं समृद्ध थी वह अंग्रेजी शासनकाल में उनके शोषण, साधनों के बाह्य बहाव तथा घातक एवं दोषपूर्ण आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप क्षिन्न-भित्त व निष्क्रिय हो गई। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का जो निर्मम शोषण किया उसका उदाहरण अन्यत्र मिलना कठिन है और इस शोषण को विश्व आर्थिक इतिहास का सबसे अधिक कालिमायम अध्याय कहा जाय तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था की इस दुर्दशा, निष्क्रियता व गतिहीनता के कारण अनेक वे जिनमें निम्न का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

1 ब्रिटिश सरकार की घातक नीतियाँ—ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन-काल से ही भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण की नीति सक्रिय हो गई थी। अंग्रेजी सरकार भारत को ब्रिटेन के निमित्त माल के लिए बाजार तथा कच्चे माल का उत्पादक बनाकर भारतीय उद्योगों के पतन की घातक नीति का अनुसरण करती रही। अनेक प्रकार से उन्होंने भारत के आर्थिक साधनों का बाह्य बहाव किया। दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था से जागीरदारी व जमींदारी प्रथा को विकसित किया जिससे अंग्रेज सरकार को अपने शासन की जड़ें मजबूत करने के लिए चाटुकार पिद्दू राजा-महाराजा उपलब्ध हो गये और वे 'फूट डालो व राज करो' की नीति में सफल रहे।

2 परतन्त्रता में विकास कार्यक्रमों की उपेक्षा—ब्रिटिश शासन भारतीय अर्थव्यवस्था में रुचि न लेकर अपने शासन की जड़ें मजबूत करके उसके शोषण में रुचि रखते थे अतः उन्होंने देश को आधुनिक औद्योगिकरण की ओर अप्रसर नहीं होने दिया यहाँ तक कि लघु एवं कुटीर उद्योगों के पतन की पुरजोर कोशिश की और श्रमिकों पर अमानुषिक अत्याचार किये गये। रक्षा पर व्यय कुल राजस्व का लगभग 3% भाग था जबकि विकास व्यय नगण्य था।

3 साधनों का बाह्य बहाव व पूँजी निर्माण का अभाव—अंग्रेजी शासन के अस्तंगत बड़े पैमाने पर भारतीय बचतों व साधनों का बाह्य-बहाव हुआ जो राष्ट्रीय आय का लगभग 2 से 3% था। यह अंग्रेजी ढकती व सूट-पाट ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा व्यापार के अत्यधिक लाभ अर्जन रेलवे निर्माण में ब्रिटिश पूँजीपतियों की गारण्टी पद्धति से लाभ पहुँचाने भारत पर धोपे गये होम चार्ज तथा युद्धों से सम्बन्धित व्यय को भारतीयों से वसूली आदि के रूप में 150 वर्षों तक निरन्तर चलती रही। प्रो सी एन वकील के मतानुसार 'भारत में अंग्रेजी शासनकाल में सरकारी खाते में ही बाह्य-बहाव की राशि 105 से 120 करोड़ पौण्ड थी। माण्टोगोमरी मार्टिन के अनुसार वार्षिक बाह्य-बहाव लगभग 30 लाख पौण्ड था। इतने बाह्य-बहाव की मात्रा ब्रिटेन जैसे देश को भी कगाल बना देती।' साधनों के बाह्य-बहाव से देश में पूँजी निर्माण न हो सका। जो समृद्ध वर्ग थोड़ी बहुत बचतें करते थे उह भी घातक नीतियों के वातावरण में पूँजी विनियोग का कोई प्रोत्साहन

न मिला। जमींदारों व जागीरदारों ने विलासिता का जीवन बिताने में बचतों का दुरुपयोग किया।

4 कृषि का पिछड़ापन व दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था—अंग्रेजों ने कृषि क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों की अवहेलना की। दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था ने ऐसे मध्यस्थों को जन्म दिया जो कृषकों का शोषण कर स्वयं विलासिता में डूब गये। उन्होंने शोषण का बहुत बड़ा भाग अंग्रेजी शासकों को उपलब्ध कर उन्हें सशक्त बनाया और उनके शासन की नींव मजबूत करने में देशभक्तों व क्रान्तिकारियों के दमन में कोई कसर न छोड़ी। कृषि भूमि का असमान वितरण व कतिपय लोगों के पास केन्द्रीयकरण ने भूमिहीनों की दशा और भी दयनीय बनाई। इस प्रकार कृषि के पिछड़ेपन में भी दासता की खेडियां हानिप्रद रही।

5 दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति व तकनीकी एवं प्राविधिक शिक्षा का अभाव—अंग्रेजों ने या तो शिक्षा के विकास के बहुत कम प्रयास किए और जो कुछ शिक्षा का स्वरूप मेकाले ने दिया उससे सफेद-पोश बाबुओं व क्लर्कों को तैयार करने की व्यवस्था थी। अंग्रेजी भाषा जानने वालों को नौकरी में प्राथमिकता से नई सभ्यता का उदय हुआ। भारतीय अपने देश में निमित्त वस्तुओं को हेय तथा घटिया समझने लगे तथा ब्रिटेन व विदेशों में निमित्त वस्तुओं के उपभोग में शान समझने लगे। परिणाम यह हुआ कि विदेशी माल भारत में घटाघट आने लगा। स्वदेशी माल के उपभोग की अवहेलना होने से स्वदेशी उद्योगों का पतन स्वाभाविक था।

देश में तकनीकी ज्ञान व प्राविधिक शिक्षा का अभाव होने से कृषि, उद्योग तथा परिवहन के आधुनिक ढंग का विकास न हो सका।

6 सामाजिक जड़ता—देश में शिक्षा के अभाव, धार्मिक रूढ़िवादिता व अंधविश्वास के कारण सामाजिक जड़ता उत्पन्न हो गई थी। देश में जानि प्रथा, बाल विवाह, पर्दा-प्रथा, छुआछूत, समुक्त परिवार प्रणाली तथा धार्मिक रूढ़िवादिता से भारतीय जनता की प्रगति के सब द्वार बन्द हो गये। देश में अंग्रेजों द्वारा विकसित पूँजीवादी प्रणाली में निर्धन वर्ग का शोषण हुआ। मध्यम वर्ग कुचल गया। सामाजिक गतिरोध व कुण्ठाओं ने समूची अर्थव्यवस्था को दीन-हीन बनाने में योग दिया।

7. घातक व्यापारिक नीति—ब्रिटिश सरकार भारत को ब्रिटेन का एक ऐसा उपनिवेश बनाना चाहती थी जो उसके निमित्त माल के लिए बाजार तथा प्रौद्योगिक वच्चे माल का पूर्तिकर्ता हो। अतः उन्होंने भारत में उद्योगों के विकास की बात तो दूर रही, रहे सहे उद्योगों के विनाश का पूरा-पूरा प्रयास किया। उन्होंने साम्राज्य परीयता (Imperial Preference) के अन्तर्गत रियायती तटकरों के आधार पर आयातों को प्रोत्साहन दिया तथा नीची बीमतों पर निर्यात किया गया। देश की तटकर नीति भी ब्रिटिश शासकों के शोषण के अनुकूल थी।

8. परिवहन व संचार विकास की अवहेलना—ब्रिटिश शासकों ने भारत के दातायात व संचार विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने केवल उन क्षेत्रों में

स्वतन्त्रता प्राप्ति की पूर्व सन्ध्या को भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा

परिवहन का विकास किया जो उनकी शासन सत्ता को मजबूत करने तथा आन्तरिक क्रान्तियों को दबाने के लिए जरूरी था। रेलों के विकास में भारतीय साधनों का बाहु-बहाव हुआ। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार ब्रिटेन की जहाजरानी द्वारा होता था। वायु-परिवहन में भी विदेशी हितों की कम्पनियाँ रत थीं।

9. असन्तुलित औद्योगिक विकास—भारत में आर्थिक निष्क्रियता का एक महत्वपूर्ण कारण देश में उद्योगों का असन्तुलित विकास होना है। देश में प्राधारभूत व मूलभूत उद्योगों के विकास पर ध्यान न देकर केवल परम्परागत उपभोग उद्योगों के विकास पर ही ध्यान दिया। लघु एवं बड़े उद्योगों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा से वे स्वयं उनके पतन का कारण बने। आधुनिकीकरण पर ध्यान नहीं दिया गया। देश में पूँजीगत व वित्तीय समस्याओं के अभाव में भी उद्योगों का सन्तुलित विकास न हो सका। अतः औद्योगिक पिछड़ापन बढ़ा।

10 प्रतिरक्षा व नागरिक प्रशासन पर अत्यधिक अपव्यय—जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि अंग्रेजी शासकों की हज़ि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में न होकर अपने शासन की जड़ें मजबूत करने की ही रही। अतः प्रतिरक्षा व नागरिक प्रशासन के लिए कुल राजस्व का क्रमशः 62.4% तथा 89% व्यय करते थे और विकास कार्यों व सामाजिक सेवामें की उपेक्षा करते थे। ऐसी परिस्थिति में विकास की कल्पना निरर्थक लगती है।

इस प्रकार इन कतिपय कारणों का विवेचन यह सिद्ध कर देता है कि अंग्रेजी शासकों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के कारण व विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो कुछ प्रगति हुई वह उनके प्रयासों का प्रतिफल न होकर परिस्थितियों की देन थी। भारतीय भाग्यवादी भीरु, अन्ध विश्वासी व धार्मिक रुढ़िवादी जनता ने भी समय व परिस्थितियों के साथ अपने को परिवर्तित नहीं किया। वे जुलूम सहते रहे, शोषण होता रहा और अंग्रेजी शासन 150 वर्षों तक चलता रहा जिसमें भारतीय अर्थ-व्यवस्था गतिहीन, निष्क्रिय, निर्धन व पिछड़ी रह गई।

### परीक्षोपयोगी प्रश्न मय सकेत

1 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा बताते हुए उसकी गतिहीनता के कारण दीजिये। अथवा

“अंग्रेजी शासन की दोषपूर्ण नीतियों व शोषण से स्वतन्त्रता प्राप्ति तक भारतीय अर्थव्यवस्था मृतप्राय, दरिद्र व निष्क्रिय हो गई थी।” इस कथन की पुष्टि कीजिये।

सकेत—अध्याय के अनुसार स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की हीन दशा बताते हुए कारणों का उल्लेख करना है तथा यह निष्कर्ष देना है कि वह दोषपूर्ण नीतियों व शोषण का परिणाम था।

## 2 ✓

# भारत में कृषि नीति एवं विकास

(Agricultural Policy & Development in India)

भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था है। देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। कृषि से राष्ट्रीय आय का 45 से 50 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। कृषि की हीन दशा और कृषकों का रुढ़िवादी दृष्टिकोण, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण हैं। कृषि व्यवसाय के रूप में नहीं होकर जीवन-यापन का साधन माना जाता है। डॉ० बलाउडस्टन के शब्दों में "भारत में हमारी पिछड़ी जातियाँ तो हैं ही, पिछड़े उद्योग भी हैं और दुर्भाग्य से इन उद्योगों में कृषि भी एक है।" कृषि की हीन दशा को देखकर ही स्वर्गीय पंडित नेहरू ने कहा था—“Every thing may wait but agriculture can not. There is nothing more important in India to-day than better agriculture”। कैसी विद्वम्बना है कि भारत में 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि में सलग्न है पर भारत अपने छाछानों के लिए दूसरे राष्ट्रो से भीख मागता है जबकि अमेरिका में कृषि में जनसंख्या का केवल 6 प्रतिशत भाग सलग्न है पर वह विश्व की एक तिहाई जनसंख्या के छाछानों की पूर्ति करने में सक्षम है।

भारतीय भूमि में निर्भरता के ताण्डव नृत्य के समापन, कृषि के सर्वांगीण विकास और भारतीय जन-जीवन की समृद्धि के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। चार पंचवर्षीय योजनाओं तथा तीन वार्षिक योजनाओं में कृषि विकास के लिए यथासम्भव प्रयत्न किये गये हैं और अब देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। हरितक्रान्ति से ग्रामीण जन-जीवन को विविधतापूर्ण बनाने तथा उसकी समृद्धि के लिए पृष्ठभूमि तैयार की गई है।

**भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्व**

(Importance of Agriculture in Indian Economy)

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला, 70% जनसंख्या के जीविको-

## भारत में कृषि नीति एवं विकास

पार्जन का साधन और विदेशी व्यापार का मूल स्रोत है। यह निम्न तथ्यों से स्पष्ट है :—

1 जीविकोपार्जन व रोजगार का आधार—कृषि भारत की 70% जनसंख्या के रोजगार तथा जीविकोपार्जन का मूल आधार है। 1971 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या 18.8 करोड़ थी उसमें से 9.95 करोड़ कृषक तथा 3.15 करोड़ खेतिहर मजदूर थे। इस प्रकार कृषि में कुल 13.1 करोड़ व्यक्ति नियोजित थे।

2 राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत—कृषि से राष्ट्रीय आय का 45 से 50 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। 1950-51 में यह 51.3% था, 1965-66 में यह घटकर 46% प्रतिशत रह गया पर अब भी यह राष्ट्रीय आय का 42 से 50 प्रतिशत भाग है।

3 औद्योगिक कच्चा माल—कृषि देश में कृषि पर आधारित उद्योगों (Agro-Industries) के लिए कच्चा माल उपलब्ध करती है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास, चीनी उद्योग के लिए गन्ना, वनस्पति उद्योग के लिए तिलहन तथा इसी प्रकार जूट, चाय, रबर, तम्बाकू और कागज उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति भी कृषि से होती है।

4 खाद्यान्न की पूर्ति—भारत की विशाल शाकाहारी जनसंख्या के लिए कृषि ही खाद्यान्नों की पूर्ति करती है। जहाँ 1950-51 में खाद्यान्नों का उत्पादन 5.49 करोड़ टन था वह 1978-79 में 12.8 करोड़ टन होने का अनुमान है। अब देश खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता की ओर अग्रसर है।

5 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विदेशी मुद्रा-अर्जन—भारत के निर्यातों में कृषि-जन्य पदार्थों का विशिष्ट महत्व है। 1955-56 में जूट एवं जूट निर्मित वस्तुएँ, कपास तथा सूती माल और चाय आदि का निर्यात में 43% भाग था। अब भी इन सबसे देश की विदेशी व्यापार से लगभग 2500 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।

6 राज्य सरकारों की आय का प्रमुख स्रोत—कृषि से राज्य सरकारों को भू-राजस्व, कृषि आय कर, सिंचाई वसूली तथा व्यापारिक फसलों से कर द्वारा लगभग 800-1000 करोड़ रुपये की वार्षिक आय होती है।

7 आर्थिक विकास में साधनों का आधार—भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कृषि विकास से सम्बद्ध है। कृषि विकास के बिना औद्योगीकरण और बेरोजगारी का समापन मुश्किल है। कृषि की समृद्धि में ही निर्धनता का समापन, बेकारी का उन्मूलन तथा जन-जीवन की खुशहाली निर्भर करती है।

8 यातायात, मूल्य स्थिरता, व्यापार और वित्त व्यवस्था—देश की यातायात व्यवस्था भी कृषि पर निर्भर करती है क्योंकि औद्योगीकरण तो अभी नाम मात्र का



हुआ है। निम्न जीवन-स्तर होने से उपभोग में कृषि वस्तुओं का महत्व है और मूल्य स्थिरता के लिए कृषि उत्पादन की स्थिरता आवश्यक है। देश का व्यापार और वैश्व आदि वित्तीय सस्याओं का कारोबार कृषि पर निर्भर करता है।

■ राजनैतिक एवं सामाजिक महत्व—कृषक भारतीय गणतन्त्र का बहु-सदस्य नागरिक है और प्रजातान्त्रिक प्रणाली में कृषक का महत्व रीढ़ की हड्डी के समान है।

### भारतीय कृषि की बाधाएँ एवं पिछड़ेपन के कारण

(Obstacles & Causes of Backwardness of Indian Agriculture)

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार स्तम्भ है और उसका अपना राजनैतिक तथा सामाजिक महत्व भी है पर इस महत्व के बावजूद भी इसकी हीन दशा है। कृषि की हीन दशा के कुछ प्राकृतिक कारण हैं तो कुछ आर्थिक एवं सामाजिक। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व राजनैतिक कारण भी महत्वपूर्ण थे पर अब यह कारण कृषि के पिछड़ेपन के लिए नहीं परन्तु उसके विकास के लिए प्रयत्नशील है। कृषि-विकास की मुख्य बाधाएँ तथा पिछड़ेपन के कारण संक्षेप में इस प्रकार हैं—

(अ) प्राकृतिक कारण—कृषि विकास में अनेक प्राकृतिक बाधाएँ हैं और यही मुख्य रूप से कृषि के पिछड़ेपन में योगदान करती हैं—(i) मानसूनी अर्थ-व्यवस्था होने से कृषि भी मानसून का जुझा है। 'अगर मानसून न आवे तो कृषि उद्योग में तालाब-दी' हो जाती है। 1965-66, 1966-67 तथा 1974-75 के मसूनपूर्व सूखों की इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। (ii) कीड़े-मकोड़े तथा पौधों की बीमारियों से कृषि उत्पादन में लगभग 10% क्षति होती है। (iii) भूमि में कटाव से उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है तथा कुछ समय बाद वह कृषि योग्य नहीं रहती लगभग 20 करोड़ एकड़ क्षेत्र भूमिभरणता (Soil Erosion) से ग्रस्त है। (iv) कृषि क्षेत्र सीमित है जबकि जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होने तथा उसके रोगाणु का अग्र विकल्प न होने से कृषि पर जन भार बढ़ाया जा रहा है। प्रति व्यक्ति 0.85 एकड़ से घटकर 0.75 एकड़ रह गया है।

(ब) आर्थिक बाधाएँ—कृषि में आर्थिक बाधाएँ भी अनेक हैं और इन बाधाओं से कृषि विकास की ओर अग्रसर नहीं हो पा रही है। इन कारणों में—

1 वित्तीय साधनों का अभाव—कृषि को प्रतिवर्ष 5000 करोड़ रुपये ऋण की आवश्यकता होती है पर इस ऋण के 55% की पूर्ति तो साहूकार करते हैं जबकि सरकार तथा बैंक का योगदान, क्रमशः 4.5% तथा 15% ही है। अतः वित्तीय साधनों के अभाव से कृषि में पूँजी विनियोग, यन्त्रीकरण, उत्तम बीज, रासायनिक खाद आदि का प्रयोग मुश्किल होता है।

2 वैज्ञानिक यन्त्रों एवं उपकरणों का अभाव—यह भी कृषि में कम उपज और अधिक लागत के लिए जिम्मेदार है।

3 रासायनिक खादों के उपयोग का अभाव—भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि तथा उसके स्थायित्व के लिए रासायनिक खादों का महत्व विवादों से परे है। भारत की तुलना में प्रति एकड़ रासायनिक खादों का उपयोग इंग्लैण्ड में 60 गुना, जापान में 90 गुना, पश्चिमी जर्मनी में 100 गुना, बेल्जियम में 150 गुना तथा नीदरलैण्ड में 170 गुना अधिक होता है। हम गोबर जैसी उत्तम खाद को जलाकर राख कर देते हैं। अतः प्रति एकड़ उपज बहुत कम है। देश में प्रतिवर्ष 50 लाख टन रासायनिक खाद का उपयोग हो रहा है पर देश में उत्पादन कम होने से आयात पर निर्भर करना पड़ता है। अब भी देश की कुल मांग की 60% की उत्पादन क्षमता ही है।

4 सिंचाई के साधनों का अभाव—भारत में लगभग 1,680 लाख हेक्टर कृषि योग्य भूमि है पर केवल 20 लाख हेक्टर भूमि पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है जबकि, 1160 लाख हेक्टर भूमि अब भी प्राकृतिक मानसून पर आश्रित है।

5 उत्तम बीजों तथा कीटनाशक औषधियों का अभाव—यद्यपि पहले 28 वर्षों में योजनाबद्ध विकास तथा 1965 से मुख्य रूप से इन कार्यों में सुधार हुआ है फिर भी अब तक उत्तम बीजों की उपलब्धि तथा पौध संरक्षण औषधियाँ सामान्य किसान की पहुँच से परे हैं।

(स) सगठनात्मक बाधाएँ व कारण—सगठनात्मक कार्यों से भी कृषि के विकास की गति धीमी रही है। प्रमुख सगठनात्मक बाधाएँ निम्न हैं—

1 खेतों का उपखण्डन एवं उप विभाजन—भूमि पर बहते जन-भार, दोषपूर्ण उत्तराधिकार नियमों तथा कृषकों की ऋण प्रवृत्ति आदि से देश में उप-खण्डन एवं उप-विभाजन समस्या इतनी जटिल है कि इससे मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन तथा पूँजी विनियोग को हतोत्साहन रहता है।

2 दोषपूर्ण भूमिस्वत्वस्था एवं भूमि सुधार की धीमी गति—अंग्रेजी शासन-काल में तो जागीरदारी एवं जमींदारी प्रथा भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी थे पर स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी भूमि-सुधार कार्यक्रमों की प्रगति इतनी धीमी रही है कि प्रगति में बाधक है।

3 कृषि विशेषज्ञों तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव—कृषि भी एक व्यवसाय है और इस उद्योग में अधिक उत्पादन के लिए अनुसंधान, प्रयोग आवश्यक है। भारत में कृषि विशेषज्ञों की आवश्यकता रुढ़ि एवं परम्परावादी किसान की मनोवृत्ति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्थापित करने के लिए भी आवश्यक है। अब यद्यपि इस दिशा में प्रगति हुई है परन्तु समूची अर्थव्यवस्था ऊँट के मुँह में जीरे के समान है।

4 आर्थिक जोत—कृषि जोत का आकार अनार्यक है अतः वैज्ञानिक कृषि सम्भव नहीं होती है और प्रति एकड़ कम उपज कृषकों के जोश को समाप्त कर देती है।

(२) सामाजिक एवं राजनैतिक बाधाएँ—कृषि विकास में प्राकृतिक, आर्थिक तथा सगठनात्मक बाधाओं के साथ-साथ सामाजिक एवं राजनैतिक बाधाएँ भी महत्वपूर्ण हैं।

1 जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और कृषि पर बढ़ता जन भार—जनसंख्या में प्रतिवर्ष 130 लाख की वृद्धि होती है और लगभग 65 लाख लोगो को रोजगार प्रदान करने की आवश्यकता सामने आती है पर रोजगार के लिए कोई विकल्प कृषि के अलावा दृष्टिगोचर नहीं होना। स्वाभाविक रूप से कृषि पर जन भार में तेजी से वृद्धि हो रही है। प्रो रबेल के अनुसार प्रति 100 एकड़ भूमि पर पौष्टिक में 31 व्यक्ति, ब्रिटेन में 6 जबकि भारत में 148 व्यक्ति आश्रित हैं।

2 अशिक्षित रुढ़िवादी एवं परम्परागत दृष्टिकोण—भारत में 70.7 प्रतिशत जनसंख्या अशिक्षित है जबकि केवल 29.3% जनसंख्या ही साक्षर है। शिक्षा के कारण ग्रामीण कृषक का भाव्यवादी एवं परम्परावादी दृष्टिकोण उच्च वैज्ञानिक तरीकों के अपनाने में बाधा पहुँचाना है। अब धीरे-धीरे उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हो रहा है परन्तु फिर भी कृषि के विकास के लिए पयाप्त प्रेरणा का अभाव है।

3 राजनैतिक कारण—भूमि सुधार अधिनियमों का प्रतिपादन तथा उनका क्रियान्वयन राज्य सरकारों के हाथ में है। इसके साथ-साथ आज़रल राजनैतिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में भूमि सुधार कार्रवाई ढग से सम्पन्न नहीं हुए हैं। अब इस दिशा में प्रगतिशील दृष्टिकोण ज्यों-ज्यों चुनाव का समय आ रहा है तेजी से कायरूप में परिणमन किये जाने की प्रवृत्ति है।

इस प्रकार कृषि विकास की अनेक बाधाओं का समापन भारतीय जनसंख्या की निधनता निवारण, औद्योगिक विकास और कृषि समृद्धि के लिए जरूरी है।

**स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि नीति**

( 1947 से 1979 )

( Agricultural Policy during Five Year Plans )

( From 1947 to 1979 )

राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ ही आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न सफ़ट योजनाएँ पच्चे माल का अभाव, दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था और कृषकों की हीन दशा से प्रभावित हो सरकार ने कृषि के सम्बन्ध में एक व्यावहारिक एवं सुनिश्चित नीति अपनाने का दृढ़ निश्चय किया। इस समय कृषि नीति का मूल उद्देश्य खाद्यान्न पदार्थों में आत्म निर्भरता तथा औद्योगिक पच्चे माल की उत्पत्ति में वृद्धि करना था। सन् 1949 में अधिकतर अन्न

उपजाओ आन्दोलन' प्रारम्भ किया गया। यह तत्कालीन खाद्यान्न संकट में मुक्ति पाने के लिए प्रारम्भिक प्रयास था।

1950 में योजना आयोग का निर्माण हुआ और योजना आयोग ने भी देश के भावी आर्थिक विकास में कृषि विकास को प्राथमिकता दी। यही कारण था कि प्रथम योजना के सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाले 1,960 करोड़ रु व्यय में से कृषि तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों और सिंचाई पर 601 करोड़ रु व्यय हुआ जो कि कुल योजना व्यय का 30.6% भाग था। प्रकृति की कृपा दृष्टि से कृषि उत्पादन में लक्ष्य से भी अधिक उत्पत्ति के आधार दृष्टिगोचर हुए। 1952 में ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाङ्गीण विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। 1953 में खाद्यान्न का पर्याप्त उत्पादन होने से 1954 तक खाद्यान्न से नियन्त्रण हटा लिया गया। पर इसके कारण कृषि उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों में 15 से 20% की कमी हुई यद्यपि 1955-56 से खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का दौर प्रारम्भ हो चुका था।

खाद्यान्न के आयात के सम्बन्ध में यह नीति अपनाई गई थी कि आयात केवल संकटकाल के लिये भण्डार (Buffer Stock) निर्मित करने के लिये ही किया जायगा। योजना आयोग ने कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये सस्यागत परिवर्तनों तथा प्रौद्योगिक (Technological) परिवर्तनों पर ही अधिक बल दिया। फलस्वरूप 1960-61 तक सम्पूर्ण देश 40% कृषि योग्य भूमि पर फैली हुई जागीरदारी तथा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया। भूमि घर में काश्तकारी व्यवस्था में सुधार के लिये लगान की अधिकतम सीमा, काश्तकारों को बेदखली के विरुद्ध सुरक्षा, भू-स्वामित्व अधिकार दिलाना तथा कृषि पुनर्संगठन में जोंत की सीमा निर्धारण, चक्रबन्दी, सहकारी कृषि, भूदान आन्दोलन तथा भूमिहीनों को भूमि वितरित करने की नीति रही ताकि सामाजिक न्याय के परिवेश में उत्पत्ति वृद्धि की प्रेरणा मिले। सस्यागत परिवर्तनों में वित्तीय सस्याओं का विकास कृषि विपणन व्यवस्था आदि महत्वपूर्ण रहे। 1956 में खाद्यान्न में राज्य व्यापार की व्यवस्था लागू हुई। 1957 में ही ग्रामीण मेहुता समिति ने खाद्यान्न स्थिरीकरण संगठन की स्थापना का सुझाव दिया था। 1959 के नागपुर अधिवेशन में कृषि भूमि सुधारों को गति प्रदान करने तथा सहकारी कृषि को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव पारित किया था। प्रौद्योगिक परिवर्तनों से सिंचाई साधनों का विकास, उत्तम बीज, रसायनिक खाद और कृषि के वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में विस्तार की नीति थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक योजना आयोग की कृषि नीति कुछ सीमा तक सस्यागत और प्रौद्योगिक उत्पादनों से परिवर्तन वृद्धि के उद्देश्य में तो सफल हो

सकी पर कृषि क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तनों का शीर्षण नहीं हो पाया। कृषि क्षेत्र में ऐसे तत्वों के अकुर नहीं पनपे जो कृषि उत्पादन में परम्पराओं के विरुद्ध नई पद्धतियों की धुम्रान से किसानों में नये जीवन का संचार कर उन्हें प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाने को अग्रसर कर सकें। बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं को अधिक महत्व देने से क्षेत्रीय विषमता में वृद्धि होने के साथ-साथ दीर्घकाल में लाभ मिलने से मुद्रा-स्फीति की स्थिति उत्पन्न हुई। अतः देश में कृषि विकास के लिये एक प्रभावी, व्यावहारिक, सुनिश्चित तथा सुदृढ़ नीति की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि ने नीति-निर्माणों को अधिक सजग होने का संकेत दिया।

### कृषि विकास की नई नीति का प्रादुर्भाव

(Evolution of New Strategy of Agriculture Development)

प्राथमिक समृद्धि की आकांक्षा में प्रगतिशील दृष्टिकोण पनपता है। भारतीय किसानों में प्राथमिक नियोजन के दस वर्षों में वांछित लाभ न मिलने से निराशा के साथ-साथ मनोबल की सुदृढ़ता व प्राथमिक समृद्धि की आकांक्षा से उचित मूल्यों, अधिक उपज देने वाली फसलों तथा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग की प्रवृत्ति बढ़ी। उनकी यह प्रवृत्ति उज्ज्वल भविष्य का सूचक थी। 1960-61 के बाद कृषि उत्पादन में अत्यधिक उतार चढ़ाव का दौर चला। 1964-65 में अच्छी उपज के साथ 1965-66 तथा 1966-67 के अभूतपूर्व सूखा, फिर 1967-68 में अच्छी फसल के बाद 1968-69 में स्थिरता, कृषि क्षेत्र में विकास की विफलता और सफलता का अस्वाभाविक मिश्रण है। इस वानावरण से जहाँ कृषकों में उचित मूल्यों, अधिक उत्पत्ति के लिये अग्रिम उपज देने वाले बीजों और रासायनिक खाद के प्रयोग को बढ़ावा मिला वहाँ साथ ही साथ कृषि के सम्बन्ध में परम्परागत निर्वाह दृष्टिकोण के स्थान पर व्यावसायिक दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ। सिंचाई की दृष्टि से उपयुक्त प्राथमिक उपजाऊ क्षेत्रों में अधिक उत्पादन करने की सुनिश्चित नीति का प्रादुर्भाव हुआ। इस नीति को कृषि विकास की नवीन व्यूह रचना की संज्ञा दी जाती है।

इस नवीन व्यूह रचना के प्रथम चरण में 1960-61 में चयनित 3 जिलों में सघन कृषि जिला कार्यक्रम (Intensive Agriculture District Programme) के नाम से फोर्ट पाउण्डेशन से प्राप्त प्राथमिक सहायता से चालू किया गया। इसे पैकेज प्रोग्राम (Package Programme) के नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि इनमें विभिन्न कृषि साधनों—उत्तम बीज, रासायनिक खाद, साख, फीजियर और सिंचाई सुविधाएँ—को एक साथ चुने क्षेत्रों में प्रयोग किया जाना है तथा

1. आवश्यक तकनीकी तथा आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। यह एक समन्वित एवं सघन प्रयास था जो बाद में 13 जिलों में फैला और अब 308 विकास खण्डों में चल रहा है।

1964-65 से अन्य क्षेत्रों से कम खर्च तथा कम साधनों से छोटे पैमाने पर सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (Intensive Agriculture Programme) चालू किया गया जिसमें विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट फसलों के उत्पादन पर ही ध्यान केन्द्रित किया गया।

इस तरह दोनों कार्यक्रम—सघन कृषि जिला कार्यक्रम और सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम प्रचलित किस्मों से ही अधिक गहन कृषि करने तक सीमित रहे। कृषि में अन्य पदार्थ (Inputs) को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया पर 1960 से ही अधिक उपज देने वाली फसलों को किस्मों का प्रयोग निरन्तर बढ़ने लगा। 1963 तक इनका बहुत उपयोग होना शुरू हुआ। 1966 की खरीफ की फसल की बुआई में अधिक उपज देने वाली फसलों की व्यापक वृद्धि हुई, यहाँ तक कि चतुर्थ योजना के प्रारम्भ में 8.5 मिलियन हेक्टर में अधिक उपज देने वाली फसलों का प्रयोग किया जा रहा था। चतुर्थ योजना के प्रारम्भ तक गेहूँ, धान, मक्का बाजरा और ज्वार की इन पाँच फसलों में ही अधिक उपज देने वाले बीजों का विस्तार हुआ। दूसरी पखुली के सम्बन्ध में प्रयोग एवं शोध बाध प्रगति पर है।

### पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कृषि नीति एवं कृषि विकास (1951-79) (Agriculture Policy & Development during 1951-79)

देश के योजनावद्ध विकास के प्रारम्भ से ही कृषि व सिंचाई विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया। प्रथम योजना में कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी ही गई किन्तु बाद की योजनाओं में भी कृषि विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। 1965-66 में कृषि विकास की नवीन गूँथ रचना अपनाई गई ताकि सीमित साधनों का चयनित सुरक्षित क्षेत्रों में प्रयोग कर छायाग्र व कृषि जन्य पदार्थों की उत्पत्ति में सीधे वृद्धि की जा सके और देश को छायाग्र में आत्म निर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त हो। चौथी योजना में ही 1970-71 तक छायाग्र में आत्म निर्भरता का लक्ष्य रखा गया था। योजनावद्ध विकास के पिछले 28 वर्षों (1951-79) में पाँच पंचवर्षीय योजनाएँ व चार वार्षिक योजनाएँ कार्यान्वित की जा चुकी हैं और इस अवधि में कृषि व सिंचाई विकास पर सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग 16500 करोड़ रु व्यय हुआ है जो सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाले समग्र योग का लगभग 20% भाग है। पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत व्यय का विवरण निम्न सारणी से स्पष्ट है—

तालिका 1. योजनाओं के अन्तर्गत कृषि एवं सिंचाई विकास पर सार्वजनिक क्षेत्र का व्यय (1951-77)

श्रवधि	सार्वजनिक क्षेत्र का कुल व्यय	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र पर व्यय	सिंचाई विकास पर व्यय	कुल योग 3+4	कृषि व सिंचाई पर व्यय का प्रतिशत
प्रथम योजना 1951-56	1960	291	310	601	30.6
द्वितीय योजना 1956-61	4600	530	340	870	21
तृतीय योजना 1961-66	8577	1089	580	1669	19
तीन वार्षिक योजनाएँ 1966-69	6756	1167	414	1581	23
चतुर्थ योजना 1969-74	16774	2566	900	3466	20.7
पाँचवी योजना के चार वर्ष 1974-78	29571	3400	2100	5500	
पिछले 27 वर्षों में कुल व्यय	68238	9043	4644	13687	20%

Source—Compilation from various plans

उपरोक्त तालिका पर दृष्टिपान करने से ज्ञात होगा है कि योजनावद्ध विभाग के 27 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र का कुल व्यय 68238 करोड़ रु. में लगभग रहा है। उसमें से कृषि एवं सिंचाई विकास पर लगभग 9043 करोड़ रु. तथा 4644 करोड़ रु. व्यय हुआ है अर्थात् दोनों पर कुल व्यय 13687 करोड़ रु. रहा है जो कुल सार्वजनिक क्षेत्र व्यय का लगभग 20% भाग है। यद्यपि इन 27 वर्षों में कृषि व सिंचाई के क्षेत्र में आवश्यकजनक प्रगति हुई है फिर भी भारतीय मानसून की अनिश्चितता व प्राकृतिक प्रभावों के कारण अन्न-भाजन खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। कृषि विकास की दर उध्या में कम रही है। योजनावद्ध विकास के 27-28 वर्षों में कृषि विकास की प्रगति का सक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है—

1 कृषि विकास दर में वृद्धि—पञ्चवर्षीय योजनाओं के मूल्यांकन में सन् 1900 से 1950 तक भारत में कृषि विकास की वार्षिक दर केवल 0.5% थी परन्तु पिछले 28 वर्षों में कृषि की वार्षिक दर बढ़कर लगभग 5% हो गई है। पिछले 28 वर्षों में कृषि उत्पादन में लगभग 100 से 121% प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जहाँ

1950-51 में कृषि उत्पादन का सूचकांक (आधार वर्ष 1949=100) 96 था। 1960-61 में बढ़कर 139, 1970-71 में 182 तथा 1978-79 में बढ़कर 221 होने का अनुमान है। 1969-70 से 1971-72 तक कृषि विकास की औसत वार्षिक दर 5% थी किन्तु चतुर्थ योजना में कृषि विकास की वार्षिक दर 3.9% हो रही जबकि लक्ष्य 5.5% का था। 1978-79 में कृषि विकास दर 2.7% होने का अनुमान है।

2. खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि— पिछले 27-28 वर्षों में खाद्यान्न के उत्पादन में भी लगभग दुगुनी वृद्धि हुई है। जहाँ 1950-51 में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन 5.49 करोड़ टन था वह प्रथम योजना में ही लक्ष्य 6.5 करोड़ टन को पार कर 6.9 करोड़ टन पहुँच गया। 1960-61 में खाद्यान्न का उत्पादन 8.2 करोड़ टन था किन्तु तीसरी योजना के 1964-65 में 8.9 करोड़ टन तक पहुँच कर 1965-66 में अकाल के कारण गिरकर 7.2 करोड़ टन हो रहा था। 1968-69 में खाद्यान्न का उत्पादन पुनः बढ़कर 9.5 करोड़ टन हो गया। चतुर्थ योजना में खाद्यान्न का उत्पादन 12.9 करोड़ टन करने का लक्ष्य था पर 1973-74 में खाद्यान्न का उत्पादन 10.47 करोड़ टन ही रहा। 1978-79 में खाद्यान्न का उत्पादन 12.8 करोड़ टन होने का अनुमान है।

3. व्यापारिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि—औद्योगिक व व्यापारिक फसलों के उत्पादन में भी तीव्र गति से वृद्धि हुई है। कपास, गन्ना तथा मूँगफली के उत्पादन में लगभग 4 से 4.5% की वार्षिक वृद्धि हुई है। सामान्य तौर पर कहा जा सकता है कि पिछले 28 वर्षों में व्यापारिक फसलों के उत्पादन में 100 से 105% की वृद्धि होने का अनुमान है। जहाँ 1950-51 में तिलहन का उत्पादन 52 लाख टन, गन्ने का उत्पादन 71 लाख टन, कपास का उत्पादन 29 लाख गॉठें तथा जूट का उत्पादन 35 लाख गॉठें थी वह बढ़ाकर 1973-74 में क्रमशः 94 लाख टन, 13.6 लाख टन, 60.5 लाख गॉठें कर दी गई हैं, योजना बार उत्पादन वृद्धि प्राप्ति तालिका 2 में स्पष्ट है। 1978-79 में तिलहन का उत्पादन 1.3 करोड़ टन, गन्ने का उत्पादन 1.75 करोड़ टन तथा कपास और जूट का उत्पादन क्रमशः 72 लाख तथा 70 लाख गॉठें होने का अनुमान है।


4. सिंचाई साधनों का विकास—योजनाबद्ध विकास के पिछले 25 वर्षों में सिंचाई सुविधाओं का तीव्र गति से विकास हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र में 3500 करोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र में भी लगभग इतनी राशि सिंचाई सुविधाओं के विकास पर व्यय किये जाने के परिणामस्वरूप जहाँ 1950-51 में सिंचित क्षेत्र 208 लाख हेक्टर था वह बढ़कर 1973-74 में 440 लाख हेक्टर हो गया। अब प्रत्येक लघु/पर मध्यम व बहु उद्देश्यीय योजनाओं के विकास के कारण सिंचाई के लिए उपलब्ध जल साधनों का प्रयोग 17% से बढ़कर 50% तक पहुँच गया है। मोटे अनुमानों के अनुसार भारत में 1978-79 तक 14.5 करोड़ हेक्टर भूमि पर खेती की जा



रही थी उसमें केवल 52 करोड़ हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी। 21 सूत्रीय कार्यक्रम के द्वारा 50 लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा की व्यवस्था थी। पांचवी योजना के अन्त में सिंचित क्षेत्र 484 करोड़ हेक्टर था।

5 भूमि सुधारों की प्रगति—प्रथम योजना से ही आन्तिमकारी भूमि सुधारों का प्रारम्भ हुआ जो अब तक चल रहा है। 1960-61 तक जागीरदारी एवं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। मध्यस्थों की समाप्ति से लगभग 2 करोड़ वास्तुकार सीधे सरकार के सम्पर्क में आ गये। उप-खण्डन एवं उप-विभाजन की समस्या के समाधान के लिए और अधिक छोटे खेतों पर प्रतिबन्ध तथा लगभग 5.2 करोड़ हेक्टर भूमि की चक्कण्डी की जा चुकी है। प्रायः सभी राज्यों में वास्तुकारों की भूमि से वेदस्वली वास्तु की सुरक्षा तथा उचित लगान वसूली सम्बन्धी अधिनियम पारित किये जा चुके हैं और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास जारी है। भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण सम्बन्धी अधिनियमों को बड़ी मुस्तैदी से लागू किया जा रहा है पर अधिनियमों में कानूनी खामियों का लाभ उठाकर बड़े भूस्वामी भूमिहीनों को वंचित करने में सतत प्रयत्नशील हैं। 20-सूत्रीय कार्यक्रम में भूमि सुधारों में तेजी लाई गई। अब जनता सरकार भी भूमि सुधारों को कार्यान्वित करने में प्रयत्नशील है।

6 उन्नत बीजों व रासायनिक खादों के प्रयोग की प्रगति—कृषि विकास में उन्नत बीजों व रासायनिक खादों का विशेष महत्व है। इसी कारण उन्नत बीजों व रासायनिक खादों के प्रयोग में निरन्तर वृद्धि हुई है। 1960-61 तक लगभग 4 हजार बीज गुणक फार्म स्थापित किये गये। 1963-64 में स्थापित राष्ट्रीय बीज निगम उन्नत बीजों के उत्पादन व वितरण में काफी सक्षम है। जहाँ 1950-51 में केवल 15 लाख हेक्टर भूमि में उन्नत बीजों की बुआई होती थी वहाँ 1968-69 में 80 लाख हेक्टर भूमि में उन्नत बीजों की बुआई हो रही थी। 1965-66 के बाद लगभग 140 लाख हेक्टर भूमि में बहुत फसल कार्यक्रम लागू किया जा चुका है। जहाँ 1950-51 में अधिक उपज देने वाली फसलों की बुआई नगण्य थी वहाँ बढाकर 1969-70 में 114 लाख हेक्टर तथा 1973-74 में 259 लाख हेक्टर कर दी गई है। 1978-79 में 430 लाख हेक्टर होने का अनुमान है।

 रासायनिक खादों के प्रयोग में पिछले 28 वर्षों में लगभग 55 से 60 गुना वृद्धि हुई है। दश में रासायनिक उर्वरकों की बढ़ी हुई मांग की पूर्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में ही पर्टीलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया के अन्तर्गत रात बाराहाने संचालित है। जहाँ 1950-51 में उर्वरकों का उपयोग 69 हजार टन था यहाँ 1960-61 में बढ़कर 36 लाख टन, 1970-71 में 218 लाख टन तथा 1973-74 में 197 लाख टन होने का अनुमान है। 1978-79 में उर्वरकों का उपयोग 50 लाख टन था जो कि छठी योजना के अन्त तक बढ़ाकर 78 लाख टन कर दिया जावेगा।

7. भूमि संरक्षण एवं पौध संरक्षण—भूमि का धीरे-धीरे कटाव व उपजाऊ मिट्टी का बहाव रेंगती हुई मीन के समान है अतः भूसंरक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया गया। 1953 में केन्द्रीय भूसंरक्षण मण्डल की स्थापना की गई। बढ़ते रेगिस्तान को रोकने के लिए जोधपुर में एक केन्द्र स्थापित किया गया है। पिछले 28 वर्षों में लगभग 25 लाख हेक्टर भूमि में भूसंरक्षण की व्यवस्था की जा चुकी है।

फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए पिछले दशक में कीटाणुनाशक औषधियों का प्रयोग तेजी से बढ़ा है। जहाँ 1960-61 में केवल 65 लाख हेक्टर क्षेत्र में पौध-संरक्षण किया गया था वहाँ 1968-69 में 540 लाख हेक्टर तथा 1978-79 तक लगभग 850 लाख हेक्टर पौध-संरक्षण की परिधि में आ चुका था। 1974-75 में कीटाणुनाशक दवाओं का कुल उपभोग 47.3 हजार टन था 1978-79 में यह बढ़कर 65 हजार टन होने का अनुमान है।

8. कृषि में यन्त्रीकरण को प्रोत्साहन—भारतीय कृषि विकास में यन्त्रीकरण की प्रगति भी आश्चर्यजनक कही जा सकती है। तृतीय योजना से ही वैज्ञानिक कृषि उपकरणों व यन्त्रों को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय कृषि यन्त्र एवं उपकरण मण्डल स्थापित किया गया। राज्यों में भी कृषि उपकरण मण्डलों की स्थापना की गई है। कृषि उपकरणों के निर्माण के लिए लगभग 55 वर्षाएँ स्थापित किये जा चुके हैं। विभिन्न राज्यों में कृषि उद्योग निगमों (Agro Industries Corporations) की स्थापना की गई है जो किराया रूप पद्धति (Hire Purchase System) पर कृषि यन्त्रों का विक्रय करते हैं, तकनीकी सेवा उपलब्ध करते हैं तथा कृषि व उद्योग में निकट सम्पर्क स्थापित करते हैं। देश में पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कृषि में द्रुत गति से यन्त्रीकरण की एक झलक इस बात से मिलती है कि जहाँ 1956 में विद्युत संचालित पम्प सेटों की संख्या 47 हजार थी वह बढ़कर 1970-71 में 169 लाख तथा 1978-79 में 35 लाख होने का अनुमान है। इसी प्रकार ट्रैक्टरों की कुल मांग 1966-67 में 20 हजार थी वह 1970-71 में बढ़कर 40 हजार तथा अब ट्रैक्टरों की मांग 25 लाख के लगभग है।

9. कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार—कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित उपज को उचित मूल्य दिलाने तथा उन्हें महाजनो की धोखा-पट्टी से बचाने के लिए कृषि विपणन व्यवस्था में अनेक सुधार किये गये हैं जिसके अन्तर्गत नियन्त्रित मण्डियों की स्थापना की गई है। 1950-51 में नियन्त्रित मण्डियों की संख्या केवल 265 थी अब वह संख्या लगभग 2500 है। वर्गीकरण एवं प्रमाणीकरण अधिनियम के अन्तर्गत लगभग 50 वस्तुओं का वर्गीकरण किया गया है। 1964 में राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ बनाया जिसके अन्तर्गत अभी 3500 कृषि विपणन सहकारी समितियाँ काम कर रही हैं। कृषि मूल्यों में स्थायित्व व उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए 1965 में कृषि मूल्य प्रायोग स्थापित किया गया। कृषि उपज के संग्रह के लिए गोदामों की

उचित व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है अतः 1956 में राष्ट्रीय सरकारी विकास एवं गोदाम अधिनियम के अन्तर्गत 1957 में केन्द्रीय गोदाम निगम तथा सभी राज्य में राज्य गोदाम निगम स्थापित किये गये। इनके सभी गोदामों की सग्रह क्षमता 1973-74 तक 131 लाख टन थी। देश में प्रचलित बाटों में एकरूपता लाने के लिए 1958 में मट्रिक तोल प्रणाली लागू की गई। रेडियो पर भावों का प्रसारण किया जाता है समाचार पत्रों में भी समीक्षा छापी जाती है। सरकार का विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय शोध व सर्वेक्षण कार्यों में रत है।

10 कृषि साख में वृद्धि—कृषकों को सुविधाजनक उचित शर्तों पर साख उपलब्ध कराने के लिए सस्यागत वित्त व्यवस्था के विकास पर ध्यान दिया गया है। 1955 से स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण व रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषि को दीर्घकालीन व मध्यम कालीन साख प्रदान करने के लिए क्रमशः कृषि साख (दीर्घकालीन कोष) तथा कृषि साख (स्थिरीकरण कोष) स्थापित किये हैं। प्रथम 23 वर्षों में सरकार तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा कृषि के लिए प्रथम योजना में 43 करोड़ रुपये, द्वितीय योजना में 240 करोड़ रुपये, तृतीय योजना में 492 करोड़ रु., तीन वार्षिक योजनाओं में 600 करोड़ रुपये तथा चतुर्थ योजना में लगभग 1200 करोड़ रुपये होने का अनुमान था। 14 वें वेंचर का जुलाई 1969 में राष्ट्रीयकरण करके कृषि क्षेत्र में ऋणों की मात्रा बढ़ाई गई है। अहा जून 1969 में इन बैंकों द्वारा कृषि के लिए दिया जाने वाला कुछ ऋण 162 करोड़ था वह 1978-79 तक 2000 करोड़ रुपये तक पहुँच गया।

11 विविध—कृषकों में आधुनिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए 1960-61 में पोड काउन्डेशन को आर्थिक अनुदान के साथ राज्यों में प्रारम्भ किया गया। सघन कृषि जिला कार्यक्रम 1965-66 में 308 विकास खण्डों में लागू कर दिया गया था। छोटे पैमाने पर तकनीकी जानकारी साख व उपकरण उपलब्ध करने के लिए सघन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम लागू किए।

कृषि शिक्षा व शोध कार्य में भी आश्चर्यजनक प्रगति हुई है। उदयपुर, लुधियाना, पतनगर व भुवनेश्वर, हरियाणा आदि में कृषि विश्वविद्यालय खोले गये हैं। 1929 में स्थापित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य करती है उसके अन्तर्गत 23 अनुसंधान संस्थायें कार्य कर रही हैं। इसके अन्तर्गत घाठ भूस्तरक्षण अनुसंधान, प्रदर्शन व प्रशिक्षण केन्द्र क्रमशः भागरा बेलारी देहरादून, कोटा, हैदराबाद, उटकमण्ड व चण्डीगढ़ में हैं।

इस प्रकार पचवर्षीय योजनाओं के पिछले 28 वर्षों में कृषि के सभी क्षेत्रों में प्रगति का माग प्रगस्त हुआ है।

पिछले 28 वर्षों के योजनावद्ध विकास के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में 100 से 121% की वृद्धि हुई है। खाद्यान्न का उत्पादन दुगुने से भी अधिक हो गया है।

# भारत में कृषि नीति एवं विकास

व्यापारिक फसलों के उत्पादन में भी 105% की वृद्धि हुई है। जहाँ 1950-51 से पूर्व कृषि विकास की औसत दर 0.5% वार्षिक थी वह 5% तक पहुँच गई थी। चतुर्थ योजना में कृषि विकास दर 3.9% हो गई थी। 1966-67 में लागू हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों व यन्त्रीकरण का काफी प्रयोग होने लगा है। देश खाद्यान्न उत्पादन में प्रायः आत्म निर्भरता के स्तर पर पहुँच चुका है। सिंचित क्षेत्र भी 2.08 करोड़ हेक्टर से बढ़कर अब 520 लाख हेक्टर हो गया है। कृषि अनुसंधान भी प्रगति पर है।

कृषि क्षेत्र में प्रगति की एक झलक निम्न तालिका से मिलती है—

तालिका—2 पञ्चवर्षीय योजनाओं में कृषि की प्रगति (1951-79)

विवरण	इकाई	1950-51	1960-61	1970-71	1973-74	1978-79 अनुमान
कृषि-उत्पादन सूचकांक (1949 = 100)		96	139	182	198	221
खाद्यान्न का उत्पादन	करोड़ टन	5.5	8.2	10.8	10.47	12.8
निलहन	लाख टन	52	70	92	94	134.4
गन्ना (गुड़ के रूप में)	" "	71	114	132	141	175.0
कपास	लाख गांठ	29	53	46	63	72.0
जूट	" "	35	41	49	65	70.0
उर्वरकों का उपभोग	हजार टन	69	306	2180	1970	5000
सिंचित क्षेत्र	करोड़ हेक्टर	2.08	2.83	4.2	4.30	520
अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग	क्षेत्र लाख हेक्टर	15	50	140	259	430
बहुफसल कार्यक्रम	" "	—	—	40	140	220
पौध संरक्षण	" "	—	65	560	630	850
विद्युत पम्प सेट	लाख संख्या	0.2	1	16.9	25	35

यद्यपि पञ्चवर्षीय योजनाओं में कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है फिर भी योजनाओं के क्रियान्वयन में अनेक चुटिया हैं—

1 खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता का अभाव—जम्बो अवधि के नियोजन के बावजूद भारत अब खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। जहाँ प्रथम योजना में 595 करोड़ रु० खाद्यान्न का आयात किया वहाँ तृतीय योजना में खाद्यान्न का आयात मूल्य 1150 करोड़ रु० रहा। 1973-74 में खाद्यान्न का आयात 200 करोड़ रु० तथा 1977-78 में 878 करोड़ रु० होने का अनुमान है। यद्यपि हमने 1970-71 तक ही खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा था परन्तु लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई है।

2 सिंचाई की अपर्याप्तता—भारत में कुल कृषि योग्य भूमि 16 80 करोड़ हेक्टर है उसमें से केवल 52 करोड़ हेक्टर में ही सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध हैं जबकि 11 60 करोड़ हेक्टर क्षेत्र अब भी प्राकृतिक मानसूनों की अनिश्चितता पर आश्रित है।

3 भूमि सुधारों की असतोषजनक प्रगति—भारत की स्वतन्त्रता के 28 वर्षों के बाद भी बड़े किसानों व भूस्वामियों द्वारा भूमिहीनों का शोषण होता है। भूमि सुधारों के अधिनियमों में विभिन्न धामियों के कारण वांछित लाभ नहीं मिल पाया है। 'भूमि हथियाओं' आन्दोलन भूमिहीनों की समस्या का परिचायक है।

4 कृषि वित्त की अपर्याप्तता—कृषि में वित्त व्यवस्था अब भी अपर्याप्त एवं असतोषजनक है। कृषकों का महाजनो द्वारा मयकर शोषण हो रहा है। ऋण-प्रस्तुता अब भी काफी है। ऊँची दरों से ब्याज शोषण का प्रमुख कारण है। वित्तीय-सुविधाओं का लाभ बड़े किसानों को ही मिला है।

5 छोटी सिंचाई योजनाओं की उपेक्षा—योजनाओं के अन्तर्गत बड़ी एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के विवास पर अत्यधिक जोर दिया जबकि छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं की उपेक्षा की गई। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि कुछ ही क्षेत्रों को इसका लाभ मिला और कुछ क्षेत्रों में असमानता बढ़ी है।

6 कृषि अनुसंधान पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है इसमें और काफी गुंजाइश है।

7 भूमिहीनों व छोटे किसानों की दयनीय दशा है—जहाँ एक ओर पुराने जमींदारों व जागीरदारों के स्थान पर नये संपेदपोष जागीरदारों का जन्म हुआ है और अधिकांश लाभ उन्हीं को मिला है, जबकि छोटे किसानों व भूमिहीनों की दशा में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है, उनमें अब भी भुखमरी, गरीबी व परम्परागत दृष्टिकोण व्याप्त है।

कृषि क्षेत्र में अनेक असफलताओं के आवरण में सफलताया को छुपाया नहीं

## भारत में कृषि नीति एवं विकास

जा सकता है। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोप व मानसून की अनिश्चितता ने हमें परेशानी में डाला है फिर भी कृषि विकास की दर 0.5 से बढ़कर 5% हो जाना, प्रति एकड़ उपज में 40% वृद्धि, रासायनिक खादों के उपभोग में 60 से 80 गुना वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में 120% वृद्धि सिंचित क्षेत्र का लगभग दुगुना हो जाना, जमींदारी प्रथा व मध्यस्थों का उन्मूलन आदि कृषि विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं। पिछले 28 वर्षों में कृषि उत्पादन में 100 से 121% की वृद्धि भावी भविष्य के लिए उचित संकेत है। कृषि उत्पादन वृद्धि से किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ी है। कृषकों में रुढ़िवादी तथा परम्परागत दृष्टिकोण के स्थान पर व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आतिर्भाव हुआ है। देश में कृषि को प्राकृतिक प्रकोपों से सुरक्षा मिली है और खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हरित क्रान्ति से कृषि के सर्वांगीण विकास व भारतीय कृषकों की आर्थिक समृद्धि से समाजवाद के स्वप्न को साकार करने में सहायता मिलने की आशा बढ़ी है।

### पाचवीं योजना में कृषि विकास के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

(Targets & Achievements of Agriculture in Fifth Plan)

पाचवीं योजना में कृषि विकास एवं सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए क्रमशः 4302 करोड़ रु० तथा 4226 करोड़ रु० परिष्यथ का प्रावधान था और इस विकास व्यय से कृषि विकास की दर को 3.9% से बढ़ाकर 4.67% करने का लक्ष्य था और खाद्यान्न का उत्पादन 12.5 करोड़ टन करने का लक्ष्य था। इसी प्रकार कृषि में रासायनिक खादों के प्रयोगों को बढ़ावा, पौध संरक्षण कार्यक्रमों में तेजी तथा कृषि में यन्त्रीकरण को प्रोत्साहन देना था। परिणामस्वरूप रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50 लाख टन करने तथा ट्रैक्टरों की पूर्ति 5 लाख करने की प्राप्ति अर्जित की गई थी। योजना के अन्त तक विद्युतीकृत पम्प सेटों की संख्या 40 लाख करनी थी।

योजना की मध्यावधि समाप्ति के चार वर्षों में खाद्यान्न का उत्पादन 12.5 करोड़ टन हुआ। उर्वरकों का प्रयोग 1977-78 में 42 लाख टन था। ट्रैक्टरों की संख्या भी काफी बढ़ी है और विद्युत संचालित पम्प सेटों की संख्या भी 34 लाख होने की आशा थी।

पाचवीं योजना में सिंचाई क्षमता में 131 लाख हेक्टर वृद्धि का लक्ष्य था किन्तु योजना के चार वर्षों में सिंचाई क्षमता 86 लाख हेक्टर बढ़ी। परिणामस्वरूप 1977-78 में सिंचित क्षेत्र 484 लाख हेक्टर हो गया जबकि लक्ष्य 584 लाख हेक्टर का था। प्रमुख क्षेत्रों में लक्ष्य एवं प्रगति निम्न तालिका से स्पष्ट है—

## पाचवीं योजना में कृषि विकास के प्रमुख लक्ष्य एवं उपलब्धियां

मद	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धिया
खाद्यान	करोड़ टन	12.5	12.5
निलहन	लाख टन	120	118
गन्ना	"	165	157
कपास	लाख गांठें	80	64.3
सिंचित क्षेत्र	लाख हेक्टर	584	484
विद्युत पम्प सेट	लाख सैट्स	40	34
उर्वरक का प्रयोग	लाख टन	50	42

## छठी योजना में कृषि एवं सिंचाई विकास (1978-83)

छठी योजना में कृषि एवं ग्रामीण विकास तथा सिंचाई साधनों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तदनुसार कृषि विकास पर 8600 करोड़ रु० तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण पर 9650 करोड़ रु० व्यय का प्रावधान है। परिणाम स्वरूप कृषि विकास की औसत दर 3.98% तक बढ़ने तथा खाद्यान का उत्पादन 14 करोड़ टन से 14.5 करोड़ टन करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार सिंचाई साधनों के विकास में योजना के अन्त तक सिंचाई क्षमता में 170 लाख हेक्टर की वृद्धि की जायेगी ताकि सिंचाई की वर्तमान क्षमता 484 लाख हेक्टर से बढ़कर योजना के अन्त तक 654 लाख हेक्टर हो जाये। छठी सिंचाई योजनाओं से 90 लाख हेक्टर तथा बड़ी एवं मध्यम योजनाओं से 80 लाख हेक्टर अनिश्चित भूमि में सिंचाई की व्यवस्था का प्रावधान है। प्रस्तावित लक्ष्य निम्न तालिका में स्पष्ट है —

## छठी योजना में कृषि एवं सिंचाई विकास के लक्ष्य (1978-83)

मद	इकाई	1977-78	1982-83 (लक्ष्य)
खाद्यान का उत्पादन	करोड़ टन	12.5	14 से 14.5
गन्ना	लाख टन	156.9	188
कपास	लाख गांठें	64.3	81.5 से 92.5
प्रमुख निलहन	लाख टन	92	112 से 115
सिंचाई क्षमता	लाख हेक्टर	484	654

इस योजना में कृषि में उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग हो सकेगा, उत्पादन में वृद्धि होगी और कृषि में व्यावसायिक दृष्टिकोण को बल मिलेगा। धारा है इसमें कृषि क्षेत्र में न केवल व्यापक राजस्व का अवसर बढ़ेगा बल्कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होकर गरीबी के निराकरण में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

# कृषि विकास की नवीन व्यूह-रचना बनाम हरित क्रांति

(New Agricultural Strategy or Green-Revolution)

तृतीय पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि कृषि उत्पादन कार्यों में पुनर्विचार की आवश्यकता है। अगर हम खाद्यान्न में आत्म-निर्भर होना चाहते हैं तो उत्पादन की आधुनिक विधियों का अधिकाधिक प्रयोग तथा माग और पूर्ति में सन्तुलन के लिए कृषि तथा विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली प्रगति का उपयोग करना होगा और अल्पकाल में परिणाम प्राप्त करने के लिए नई नीति अपनानी होगी।

प्रो. गाडगिल ने नवीन व्यूह रचना में संकेत प्रोग्राम, कम अवधि में तैयार होने वाली फसलों तथा अधिक उपज देने वाले बीजों के सहारे सिंचाई क्षेत्रों में अधिकाधिक उत्पादन करने पर जोर दिया है। प्रो० बी० के० आर० बी० राव ने भारतीय कृषि में तीव्र गति से प्रवेग (Dynamism) लाने पर दल दिया है। "नई व्यूह रचना भूमि, जन-शक्ति तथा अन्य आन्तरिक साधनों के विकासशील क्षेत्रों में समन्वित उपयोग से अधिकतम उत्पत्ति कम से कम समय में प्राप्त करने की अपेक्षा करती है। अतः इस नीति से सीमित साधनों का चयनित क्षेत्रों में उपयोग कर कम से कम समय में कृषि उत्पत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर वर्षा तथा प्रकृति के प्रकोपी से होने वाली अनिश्चितता को समाप्त करना है। इस तरह कृषि विकास की नवीन नीति में निम्न तत्व पाये जाते हैं—

**हरित क्रांति अथवा कृषि विकास की नवीन व्यूह रचना के मुख्य तत्व**  
(Main Features of New Strategy of Agriculture Development or Green Revolution)

नवीन व्यूह रचना में देश के सीमित साधनों में अनन्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादन की माग और पूर्ति के अन्तराल को पाटने में निम्न तत्वों की प्रधानता है—

1. कृषि विकास की प्राथमिकता के क्षेत्रों का चयन—कृषि उत्पादन में आयातनुकूल वृद्धि के लिए उन क्षेत्रों में कृषि विकास प्रयत्नों को बड़े पैमाने पर लागू



किया जायेगा, जहाँ कृषि विकास की आर्थिक सम्भावनाएँ हैं तथा जिन क्षेत्रों में सिंचाई साधनों की पर्याप्तता है और प्राकृतिक प्रकोपों के अभाव से सुरक्षित हैं। अधिक उपज देने वाली फसलों के उत्पादन में ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। उन्नत बीजों, रसायनिक खादों तथा पोष संरक्षण का वृहत्तर उपयोग (IADP) तथा (IAAP) क्षेत्रों में ही किया जाय, जहाँ सिंचाई की पर्याप्त सुविधा, कृषि कर्मचारी तथा निर्देशनकर्ता हैं।

■ उन्नत बीजों के प्रयोग पर चल (High Yield Variety Programme)—कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए अधिक उपज देने वाली फसल की बुआई के क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि करना। 1968 में 8.5 मिलियन हेक्टर क्षेत्र में अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग हो रहा था। चतुर्थ योजना के अन्तर्गत 15.6 मिलियन हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र में फैलाया गया। 1978-79 में 43 मिलियन हेक्टर क्षेत्र में इन बीजों का उपयोग होने का अनुमान है। इन आर्थिक उपज देने वाली फसलों में सिर्फ 5 फसलों में यह कार्यक्रम लागू है। गेहूँ, मेक्सिकन, 64-A, सोनारा-64 और सरमा रोजों की अधिक उपज लोकप्रिय हो रही है। इसी प्रकार धान की उपज में तार्डचुंग-नेटिव-1, तार्डचुंग 65, तनान-3, आई ग्रार ए भारत में विकसित ए. डी. टी-27, जय, पद्मा किस्में हैं। शकर मक्का तथा शकर ज्वार भी लोकप्रिय हो गई है।

3 रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में तीव्र गति से वृद्धि (Increased use of Fertilizers)—भूमि की उत्पत्ति क्षमता में वृद्धि से केवल प्रति एकड़ उपज में ही वृद्धि होती है बल्कि कम समय में तैयार होती है अतः नवीन नीति में खाद की बर्बादी को रोकने तथा रासायनिक खादों के प्रयोग पर अधिक ध्यान दिया गया है। देश में रासायनिक खाद की उत्पत्ति में वृद्धि के लिए पूर्व स्थापित इकाइयों की उत्पादन क्षमता में विस्तार, नई इकाइयों की स्थापना तथा आयात की नीति अपनाई गई है। जहाँ 1965-66 में नाइट्रोजन, फॉस्फेटिक तथा पोटेशिक खाद का उपभोग क्रमशः 5.50 लाख टन, 9.30 लाख टन तथा 80 हजार टन था वह 1968-69 के तीन वर्षों में ही बढ़कर क्रमशः 9.4 लाख टन, 4 लाख टन तथा 1.80 लाख टन होने का अनुमान है। चतुर्थ योजना के अन्त में इसके उपभोग का सद्यः क्रमशः 37 लाख टन, 18 लाख टन और 11 लाख टन रखा गया था अर्थात् नाइट्रोजन के उपभोग में 5 सालों में  $3\frac{1}{2}$  गुना से अधिक वृद्धि, पोस्फेटिक में  $4\frac{1}{2}$  गुना वृद्धि तथा पोटेशिक में 6 गुना वृद्धि करने का अनुमान था जबकि देश में नाइट्रोजन और फॉस्फेटिक का उपभोग 1978-79 में क्रमशः 50 लाख टन का ही था। चतुर्थ योजना के अन्त तक सार्वजनिक क्षेत्र में उर्वरक कारखानों की संख्या 13 करने का सद्यः था फिर भी हम अपनी माँग का केवल 60% भाग उत्पादन करते हैं। 40% विदेशों से आयात करते हैं।

4 सिंचाई साधनों के प्रति नया दृष्टिकोण—सिंचाई की व्यवस्था सिर्फ अनावृष्टि, अनियमित वर्षा तथा अल्प वृष्टि से सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि अब उसे कृषि उपज में महत्वपूर्ण घटक माना जाने लगा है। जहाँ पहले बड़ी सिंचाई योजनाओं को महत्व दिया गया अब छोटी सिंचाई योजनाओं को जो शीघ्र फलदायिनी हैं अधिक बल दिया गया है। वर्षा की अनिश्चितता की समाप्ति के लिये भूगर्भ जल योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। अमेरिकन सहायता के अन्तर्गत Spill over Tube well Projects शुरू किए गए हैं। सिंचाई की पर्याप्त सुविधा प्राप्त क्षेत्रों को ही प्राथमिकता दिये जाने से सिंचाई का महत्व अधिक उपज की दृष्टि से बहुत बढ़ गया है। जहाँ 1965-66 में लघु सिंचाई योजना से 170 लाख हेक्टर भूमि में सिंचाई होती थी वह 1968-69 में बढ़कर 190 लाख हेक्टर होने का अनुमान है तथा 1969-74 की चतुर्थ योजना के अंत में बढ़कर 202 लाख हेक्टर हो गई। 1974-78 की अवधि में सिंचाई क्षमता 86 लाख हेक्टर बढ़ी और 1978-79 में सिंचाई क्षमता 520 लाख हेक्टर थी।

5 बहु फसल कार्यक्रम (Multi-cropping Programme)—नवीन व्यूह रचना का उद्देश्य केवल अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों के प्रयोग के विस्तार ही नहीं बल्कि कम अवधि में तैयार होने वाली फसलों के उपभोग से अल्प काल में उत्पादन वृद्धि से भी है। इससे कम अवधि में फसल परिवर्तनों की नई पद्धति से बहु फसल कार्यक्रम को सफल बनाने में सफलता सम्भव है। 1967-68 में Multi-cropping Programme के अन्तर्गत 30 लाख हेक्टर भूमि आ चुकी थी। 1968-69 में यह 61 लाख हेक्टर हो गया तथा 1978-79 में इसे बढ़ाकर 220 लाख हेक्टर कर दिये जाने का अनुमान है जैसे पन्ना और जया जैसी धान की किस्में 90 दिन में तैयार हो जाती हैं इसी प्रकार मेक्सिकन गेहूँ कम समय में पक जाता है। शकर मक्का भी देशी बीज के मुकाबले शीघ्र तैयार होती है।

6 कीटाणुनाशक औषधियों का अधिकाधिक प्रयोग एवं पौध संरक्षण—कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए चयनित क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग, रासायनिक खाद की उत्तरोत्तर वृद्धि से फसलों में रोग तथा कीड़े मकोड़ों से होने वाली हानि में सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। अब नवीन नीति में पौध संरक्षण कार्यों के विस्तार पर बल दिया गया है। चतुर्थ योजना में कुल 8 करोड़ हेक्टर में पौध संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम जिन बीजोद्धार चून्नों पर नियन्त्रण, फसलों के रोगों पर नियन्त्रण अनावश्यक भ्रष्टाचारों पर नियन्त्रण तथा गहन उपचार शामिल हैं। इसके लिए निरन्तर शोध कार्य करना आवश्यक होगा। महामारी नियन्त्रण एवं कीड़े मकोड़ों के छिनटाव कार्य के लिए सरकार स्वयं व सामूहिक प्रयत्नों से साधन जुटायेगी। जहाँ 1965-66 में केवल 1.66 करोड़ हेक्टर में पौध संरक्षण तथा कीटाणुनाशक कार्यक्रम से लाभ पहुँचा वहाँ 1968-69 में यह बढ़कर 5.4 करोड़ हेक्टर तथा 1975-79 में 8.5 करोड़ हेक्टर हो गया है। कीटाणुनाशक औषधियों के उत्पादन

में वृद्धि तथा आयात में पर्याप्त पूर्ति के साथ साथ अनावश्यक उपकरणों की पूरी व्यवस्था का प्रावधान है। इसके अलावा तकनीकी सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था, आवश्यक अनुसंधान एवं शोध कार्य तथा लागत में कमी का पूरा प्रयत्न किया जायेगा। देश में एक पौध संरक्षण निदेशालय की स्थापना की गई है जिसके आधीन 17 केन्द्रीय पौध संरक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं। 1978-79 में दवाओं का उपयोग 65 हजार टन था।

7 सहायक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि पर बल—उत्तम स्वास्थ्य तथा शारीरिक स्वस्थता के लिए पोषक तत्वों से युक्त सन्तुलित आहार महत्वपूर्ण माना जाता है। अतः नवीन नीति में खाद्यान्न के अभाव की पूर्ति के साथ साथ पोषक तत्वों की वृद्धि के लिए सहायक खाद्यान्नों की उत्पादन वृद्धि पर बल दिया है। इसके अन्तर्गत आलू, शकरबन्द केले, अन्य फल, दूध, मछली, अण्डे और अन्य प्रोटीन-युक्त वस्तुओं की उत्पादन वृद्धि पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सम्बन्धित क्षेत्रों पर पर्याप्त ध्यान और परामर्श और सुविधाएँ उपलब्ध की जाती हैं।

8 कृषि विकास के लिए विभिन्न संस्थाओं की स्थापना—उन्नत बीजों की पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पांच कृषि फार्म जमश, सूरतगढ़, जेतसर, उडीसा, पंजाब और हरियाणा में स्थापित किये गए हैं। 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम (National Seed Corporation) की स्थापना की गई है। कृषि के कुशल विकास के लिये कृषि उपकरणों एवं मशीनों और गोदामी व्यवस्था के लिए 1965 से अब तक 13 राज्यों में कृषि उद्योग निगम (Agro Industries Corporations) की स्थापना की गई। कृषि साधन सुविधा की वृद्धि के लिए Agriculture Refinance Corporation की स्थापना 1963 में की गई। कृषि साधन में वृद्धि के लिए अभी 14 बड़े बैंक का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया है। फसल ऋण प्रणाली को बढाया दिने जाने की नीति है। इसके अलावा खाद्य निगम, उर्वरक, साख, गारम्टी निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, राष्ट्रीय सरकारी विकास निगम, कृषि मूल्य आयोग और केन्द्रीय उर्वरक वितरण निगम के नाम उल्लेखनीय हैं। आग भी आवश्यक संस्थाओं की स्थापना पर जोर दिया जायेगा। अब तक 4000 बीज गुणन फार्म-स्थापित किए जा चुके हैं तथा केंद्रीय सरकार और अधिक बीज गुणन फार्म स्थापित करने की प्रत्याज्ञा कर रही है। मशीनें किराये पर देन वाले केंद्रों की संख्या लगभग 300 है।

9 भूमि सुधार एवं भू-संरक्षण—भूमि सुधार के अन्तर्गत जमींदारी और जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन किया जा चुका है पर फिर भी 1970-71 तक सभी में यही एक विबोली को समाप्त करने की नीति है। अब तक लागू किए गए भूमि सुधारों के दोषों को निवारण करने के भी गवामम्भव प्रयत्न किये जाने का दृढ़ संकल्प है जिसमें कृषकों को सुरक्षा स्वामित्व और शोषण से मुक्ति दिलाई जा रहे। भू-संरक्षण के लिये आवश्यक सर्वेक्षण और भू-संरक्षण कार्यक्रमों को तेजी से विस्तार करने की नीति का अनुसरण किया गया है। 28-29 नवम्बर 1969 का

दिल्ली में होने वाले मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में नवीन व्यूह रचना के सन्दर्भ में भू-सुधार कार्यक्रमों में अधिक तेजी तथा कुशलता लाने का प्रस्ताव पारित किया है। इसको सरकारी कार्गो के बम्बई अधिवेशन तथा सण्टन कांग्रेस के ग्रहमदावाद अधिवेशन में भी अनुमोदित किया है। 21-सूचीय कार्यक्रम में भूमि सुधारों को शीघ्रता से लागू करने के प्रभावी कदमों का समावेश था। अब जनता सरकार भी सतर्क है।

10 कृषि में यन्त्रीकरण तथा उन्नत उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा—नवीन नीति में कृषि विकास के लिये उन्नत उपकरणों तथा यन्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रावधान है। इससे कृषि और उद्योगों में अधिक घनिष्ठता आयेगी। देश में 13 कृषि उद्योग निगम (Agro Industries Corporation) मशीनों और औजारों के निमाताओं तथा किसानों में सम्पर्क स्थापित कर औजारों तथा यन्त्रों की खरीद, मरम्मत आदि की व्यवस्था करेंगे। देश में इन यन्त्रों तथा उपकरणों की पूर्ति में वृद्धि का प्रयत्न भी सम्मिलित है। चौथी योजना के दौरान ट्रैक्टरों की पूर्ति में वृद्धि के लिए उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया है। 250 चुने हुए क्षेत्रों में कृषि औजार केन्द्र स्थापित किये हैं जिनमें उन्नत कृषि उपकरणों का उत्पादन, मरम्मत सर्विसिंग तथा किराये पर देने की व्यवस्था है। इससे कम से कम 20% कृषकों का उन्नत उपकरण औजार तथा यन्त्र देने का लक्ष्य है।

11 कृषकों को उचित मूल्य की गारन्टी—कृषकों की उत्पादन वृद्धि की प्रेरणा तथा मूल्यों में होने वाली गिरावट से सुरक्षा प्रदान करने के लिये नवीन उचित मूल्यों की गारन्टी दी गई है। कृषि मूल्य आयोग (Agriculture Price Commission) सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार कृषि उपज का वसूली व खरीद मूल्य निर्धारित करती है। केन्द्रीय साथ निगम और राज्य खाद्यान्न निगमों द्वारा सरकारी नीति को मूर्तत्व दिया जाने की चेष्टा की जाती है। मूल्य निर्धारण करते समय उपभोक्ताओं के हितों का भी पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। इस तरह अधिक उत्पादन की स्थिति में कृषि उपज की कम लोचदार भाग के कारण होने वाली क्षति से सुरक्षा प्रदान कर किसान को अधिक उत्पादन की प्रेरणा अधिक उपयोगी तथा व्यावहारिक लगती है। 1975-76 में किसानों की शीमों में गिरावट को रोकने के निम्न पाँच निगमों ने खरीद शुरू कर दी। कृषि मूल्य आयोग इन दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

12 ड्रमा कृषि (Dry Farming) का विकास—भारत में 1380 लाख हेक्टर कृषि योग्य भूमि में से केवल 484 लाख हेक्टर भूमि ही सिंचित है और बहु-प्रचारित हरित-क्रान्ति 360 लाख हेक्टर में ही लागू हुई है जबकि 1,120 लाख हेक्टर भूमि में हरित-क्रान्ति हो जाने पर भारत में केवल आत्म निर्भर ही नहीं निर्यातक बन सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार अगले 10 वर्षों में भी भूमिगत तथा

भूमि की ऊपरी सतह के जल साधनों का उपभोग होने पर भी सिंचित भूमि का विस्तार 820 लाख हेक्टर से अधिक नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति में आगामी दस वर्षों में भी 300 लाख हेक्टर भूमि का वर्षा के पानी पर ही निर्भर रहना होगा। इस कारण ऐसे क्षेत्रों में ऊष्मा कृषि (सूखी खेती) को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। अतः नवीन नीति में ऐसे क्षेत्रों में उहा सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ऐसी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जायगा जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती है। सप्ता कांग्रेस के 1969 के बम्बई अधिवेशन में भी ऊष्मा कृषि के विस्तार पर बल दिया गया था। वैज्ञानिकों को यह चुनौती स्वीकार करनी है कि अगर इजराइल जैसा छोटा सा देश अपने रेगिस्तानी क्षेत्र को लहलहाते क्षेत्रों में परिवर्तित कर सकता है, अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया में ऊष्मा कृषि के प्रयत्न सफल हो सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि धार के रेगिस्तान में अरबाल के साण्डव नृत्य का समापन न हो सके। इसके लिये शोध एवं अनुसन्धान प्रगति पर है तथा इसके बढ़ाने पर कारगर कदम उठाये जाने की नीति का अनुसरण किया जा रहा है। ऊष्मा कृषि के अनुकूल बीजों तथा आवश्यक साधनों का विस्तार किया जाना है।

**13 पशु पालन विकास—**पशु पालन विकास कृषि विकास का महत्वपूर्ण एवं अविभाज्य अंग है। इसलिए नवीन नीति में नस्ल-सुधार, रोगों की रोकथाम, उनके पर्याप्त चारे की व्यवस्था, मुर्गों पालन, सूअर पालन, मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग आदि को उत्तम एवं आधुनिकतम बनाने के प्रयत्नों का समावेश है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि नवीन कृषि नीति चुने हुए क्षेत्रों में जिनमें से सिंचाई की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं—चुने हुए फसलों के विस्तार, अलगावध फसलों के प्रचार (Short Duration Crops), अधिक उपज वाले बीजों तथा उत्तम बीजों के प्रयोग भूमि सुधार, पौध-सरक्षण कार्य-क्रमों तथा कीटाणु नाशक औषधियों के अधिक-अधिक प्रयोग, लघु सिंचाई योजना के विकास, कृषि श्रृंखला सुविधाओं के विस्तार तथा रासायनिक खाद के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि की नीति है। इसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि की प्रेरणा निहित है। उचित मूल्य नीति का समावेश है और वैज्ञानिक पद्धतियों तथा प्रौद्योगिक ज्ञान के उपयोग से कृषि उत्पादन में कम से कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन वृद्धि का लक्ष्य है, जिस पर देश की आर्थिक समृद्धि औद्योगिक विकास और कृषि प्रगति निर्भर करती है। इस प्रकार देश के सीमित साधनों के समुचित उपयोग से कृषि क्षेत्र के बहुमुखी विकास की यह वृहत् नीति अधिक व्यावहारिक तथा मोघ फल देने वाली नीति है जिससे पाचवीं योजना के अन्त तक स्वायत्तता में आत्म-निर्भरता, कृषि में व्यावसायिक दृष्टिकोण तथा औद्योगिक वर्चस्व माल को पर्याप्तता सम्भव हो सकेगी।

**नवीन व्यूह रचना के पक्ष में तर्क (हरित-क्रान्ति के पक्ष में तर्क)**

अनेक विद्वानों ने कृषि विकास की नवीन नीति की उचित, व्यापक तथा

व्यावहारिक बताया है और उनके अनुसार भारतीय कृषि का विशास अल्प काल में इसी नीति से सम्भव है। पक्ष में मुख्य तर्क निम्न हैं :—

1 सीमित साधनों का सर्वोत्तम उपयोग—इस नीति में अनुकूल क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई साधनों की पर्याप्त सुविधा है तथा जो दैवी प्रकोप से सुरक्षित है कृषि विकास कार्यों को वृहत् रूप में चलाने से अधिक उत्पत्ति कम से कम समय में सम्भव हो सकती है। दैवी प्रकोप का भय न होने से साधनों की क्षति की सम्भावना नहीं है।

2 अल्प काल में खाद्यान्नों में आत्म निर्भरता—उन्नत तथा अधिक उपज देने वाले बीजों तथा कम समय में तैयार होने वाली फसलों के विस्तार से अधिक उत्पत्ति कम समय में हो जायेगी। इससे 25 करोड़ टन प्रतिरिक्त खाद्यान्न की पूर्ति अल्पावधि में ही करना सम्भव हो सकेगा।

3 उर्वरकों के उपयोग से प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि—उर्वरकों के उपयोग से प्रति एकड़ उपज में वृद्धि होगी और साथ ही कुल उत्पादन में भी वृद्धि होगी। इससे कृषकों की आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा।

4 किसानों में कृषि के प्रति व्यावसायिक दृष्टिकोण—भारतीय किसान कृषि को व्यवसाय न मानकर जीवन-यापन का साधन मानता रहा है पर नवीन नीति उसके परम्परागत दृष्टिकोण को बदलने में सहायक होगी। वह कृषि में लगाये गये साधनों में अधिकारिक लाभोपार्जन करने की प्रेरित होगा।

5. विदेशी विनिमय की बचत—कृषि उत्पादन में वृद्धि से खाद्यान्न तथा कच्चे माल के उत्पादन में अल्प काल में ही तीव्र वृद्धि भारत में आत्मनिर्भरता नहीं लायेगी बल्कि निर्यात से विदेशी विनिमय प्राप्त होगा।

॥ व्यापक फैलाव प्रभाव—(Wide Spread Effect)—कृषि विकास कृषि पूरक कार्य-क्रमों के सम्भाव्य क्षेत्रों में लागू करने तथा उनके सफल सम्पादन से ये क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के लिये आदर्श उपस्थित करेंगे और दूसरे किसान उनकी सफलताओं से प्रेरित हो नई पद्धतियों की ओर आकर्षित होंगे। इस तरह से शनैः शनैः यह कार्य-क्रम दूसरे क्षेत्रों में भी फैल जायगा। सीमित क्षेत्रों में प्रयोग दूसरों का मार्ग-दर्शन करेंगे तथा अनुभव का लाभ उठाकर अवाञ्छनीय गतिविधियों का अन्त होगा।

7. कृषि में टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन का दौर—नवीन नीति में सस्यागत परिवर्तनों की अपेक्षा टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन को अधिक महत्व दिया गया है। इस से कृषि तथा विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति का उत्पादन वृद्धि में योगदान सम्भव होगा। उत्पादन के क्षेत्र में औद्योगिक परिवर्तनों को अपनाते को प्रोत्साहन मिलेगा।

8 औद्योगिक कच्चे माल की पर्याप्त पूर्ति—देश में औद्योगिक कच्चे माल की पर्याप्त पूर्ति औद्योगीकरण को बढ़ावा देगी। साथ ही उद्योगों और कृषि में घनिष्ठ सम्बन्धों की स्थापना दोनों के विकास में परस्पर सहायक होंगे।

इस तरह कृषि विकास की नवीन नीति में कृषि के उज्ज्वल भविष्य की

सम्भावनाएँ निहित हैं। देश में उत्पादन वृद्धि कृषि की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त कर देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी तथा निर्धनता के अन्धकार में समृद्धि की किरण प्रस्फुटित होगी।

### हरित-क्रान्ति अथवा नवीन कृषि नीति की आलोचना

कृषि विनास की इस नवीन-नीति की मिली-जुली प्रतिनिधियाँ सामने आई हैं। जहाँ एक ओर इस नीति से कृषि विकास का अल्पकाल में उज्ज्वल भविष्य का स्वप्न सजोया है वहाँ दूसरी ओर इस नीति की सफलता से सन्देह और क्षेत्रीय विषमताओं की वृद्धि की आशंका व्यक्त की गई है। ये आलोचनाएँ निम्न हैं—

1/ क्षेत्रीय विषमता में वृद्धि—नवीन नीति में अनुकूल क्षेत्रों की उत्पादन-क्षमता को बढ़ाने के लिये ही कृषि विकास कार्य जमीनों को वृहत् स्तर पर फैलाया जायगा। यह कार्य-क्रम मुख्यतया उन क्षेत्रों को ही लाभान्वित करेगा जहाँ सिंचाई की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं तथा फसलों की दैवी-प्रकोप से सुरक्षा है। ऐसे क्षेत्र भारत के 520 लाख हेक्टर में हैं जबकि बाकी 1,160 लाख हेक्टर कृषि योग्य भूमि या इसको लाभ न मिल पायगा। प्रो० बी० के आर० बी० राव का मत है कि इससे क्षेत्रीय विषमता में वृद्धि होगी और 6 करोड़ कृषक परिवारों में असम्भाव पैलेगा। सम्पन्न क्षेत्रों को अधिक सम्पन्न बनाने वाली यह नीति अविकसित क्षेत्रों की उपेक्षा करती है।

2. समाजवादी दिष्टारधारा के प्रतिकूल नीति—इस नीति से सम्पन्न क्षेत्रों में सम्पन्न कृषक परिवारों को अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो रहा है जिससे देशान्त में एक घनिष्ठ वर्ग बन रहा है। दूसरी ओर खेतिहर मजदूरों, छोटे कृषकों तथा परम्परागत पद्धति के पोषक वर्ग की आर्थिक स्थिति में स्थिरता है। इससे आर्थिक असमानता में वृद्धि हो रही है जो कि समाजवादी समाज की स्थापना के प्रतिकूल नीति है।

3/ उर्वरकों के उपयोग पर आवश्यक बल—श्री आर० एस० सावले (R S Savale) ने नवीन कृषि नीति की यह आलोचना की है कि इसमें उर्वरकों के प्रयोग पर सिंचाई से भी अधिक बल दिया गया है जबकि सिंचाई के अभाव में उर्वरकों का प्रयोग असफल ही रहेगा। अतः कृषि अर्थव्यवस्था में सिंचाई को ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त होना कृषि विकास की दृष्टि में आवश्यक है। यह आलोचना उनके द्वारा 5 में प्रकाश अध्ययनों के निष्कर्ष पर आधारित है।

4/ उर्वरकों की प्रस्तावित मात्रा त्रुटिपूर्ण—प्रो० मि० हास व थोनिवामन ने नवीन कृषि नीति का विश्लेषण करते हुए बताया है (याज्ञना जावरी 26, 1966 पेज 22) अगर 1970-71 में यह क्षेत्र के नियम निर्धारित नाइट्राजन केवल नई किस्मों तक सीमित रखा गया तो अतिरिक्त उत्पादन 3.18 मि टन होगा जबकि इसे नई व पुरानी किस्मों में वितरित करने पर अतिरिक्त उत्पादन 4.70 मिलियन टन (1.52 मिलियन टन अधिक) होगा अर्थात् उर्वरकों की प्रस्तावित मात्रा को नई

कृषि विकास की नवीन-व्यूह रचना बनाम हरित-क्रान्ति

किस्मों में ही उपयोग करने से उनको सर्वोत्तम लाभ प्राप्त नहीं होगा। प्रो पान्से ने भी प्रस्तावित उर्वरकों की मात्रा को अत्यधिक बताते हुए प्रति एकड़ 100 पौंड (N) के बजाय 50 पौंड (N) का उपयोग अधिक श्रेष्ठ बताया है।

✓5 टेक्नोलोजिकल दृष्टिकोण के पीछे संस्थागत परिवर्तनों की अपेक्षा—इस नीति में औद्योगिक परिवर्तनों को संस्थागत परिवर्तनों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है जबकि हम यह जानते हैं कि दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था, भू सुधारों के अभाव तथा भूमि-हीन किसानों के शोषण में कृषि विकास असम्भव सा लगता है। टेक्नोलोजिकल परिवर्तनों का लाभ प्राप्त करने के लिए संस्थागत परिवर्तनों को आधार बनाना आवश्यक है। अतः भूमि सुधारों पर अधिक ध्यान जरूरी है।

6. अनुभवों तथा विफलताओं की अवहेलना—1960-61 से चलाये गये सघन जिला कृषि कार्यक्रम (Intensive District Agricultural Programme) के रीपोर्ट्स, सेनी व शर्मा के अध्ययन से पता चलता है कि उत्पादन में वृद्धि आशा-मुक्त नहीं रही है। इसमें प्रशासनिक प्रकुशलता, विसम्ब तथा भ्रष्टाचार के कारण प्रगति लक्ष्यों से कम रही है। अतः इस नीति में पुन IDAP और IAAP क्षेत्रों में कृषि विकास कार्यक्रमों को चालू करने की नीति में अनुभवों की अवहेलना का संकेत है और इस नीति से लक्ष्यों की प्राप्ति में सन्देह है।

7. भारतीय परिस्थितियों में विदेशी किस्मों के बीजों के प्रयोग तथा अनुभव का अभाव—प्रो पान्से के अनुसार विदेशी किस्म के बीजों को भारत में प्रयोज्य अनुभव व प्रयोज्य प्रयोगों के आधार पर लागू करने में तथा आवश्यक वैज्ञानिक आंकड़ों के अभाव में उन बीजों की अधिकाधिक बुआई खतरे से खाली नहीं है। अतः आगे चलकर कठिनाई में फसने की अपेक्षा अभी अनुभवों से शिक्षा लेकर डग भरना उपयुक्त है।

✓8 कृषि पड़तो (Inputs) की पूर्ति तथा वितरण की समस्या—नवीन नीति में अधिक उपज देने वाले बीजों, कम समय में तैयार होने वाली फसलों, रासायनिक खाद, कीटाणुनाशक औषधियों, औजारों, साख तथा मिचाई के विस्तार पर बल दिया है पर उनकी पूर्ति बढ़ाये बिना कुशल एवं शीघ्र वितरण के बिना सफलता में सन्देह है। वर्तमान प्रशासनिक ढिलाई भ्रष्टाचार, विसम्ब, असमान वितरण, ऊँचे मूल्य तथा कृषि पड़तो की अपर्याप्त पूर्ति में इन साधनों की उपलब्धि होना एक चुनौती है। ऐसी स्थिति में नवीन नीति के सफल कार्यान्वयन में सन्देह स्वाभाविक है।

नवीन नीति की उपर्युक्त आलोचनाओं में कुछ सत्यता अवश्य है पर अगर हमें सीमित साधनों के उपयोग से कृषि विकास के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना है और कृषि में एक नई चेतना, प्रगतिशील दृष्टिकोण तथा परम्परावादी कृषि-पद्धति से छुटकारा दिलाना है तो यह नीति भारतीय कृषि को उन्नति की ओर अग्रसर करने का महत्वपूर्ण कदम है।



## हरित-क्रान्ति अथवा कृषि विकास की नवीन व्यूह रचना की सफलता का भूत्यांकन

अथवा

हरित क्रान्ति कहां तक हरी है ?

(How much Green is the Green Revolution)

तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र की अप्रत्याशित असफलता को दृष्टिगत रखते हुए कृषि विकास की नवीन नीति (व्यूह रचना) अपनाई गई जिसके अन्तर्गत सीमित साधनों के चयनित प्रयोग व उत्पादन में वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग में अल्पकाल में ही कृषि उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि पर जोर दिया गया। इस प्रकार हरित क्रान्ति की शुरुआत 1966-67 से हुई और कृषि क्षेत्र में 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अल्प अवधि में कृषि क्षेत्र में उन्नत व अधिक उपज देने वाली फसलों के विस्तार, रासायनिक उर्वरकों व कीटाणुनाशक दवाइयों के उपयोग में वृद्धि, मध्यम व लघु सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वयन से सिंचित क्षेत्र की अभिवृद्धि तथा कृषि के वैज्ञानिकीकरण व यन्त्रीकरण के द्वारा न केवल कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है बल्कि कृषकों में व्यावसायिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ है। कृषि क्षेत्र में हरित-क्रान्ति की सफलता निम्न तथ्यों से स्पष्ट है—

1 खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि—जहाँ 1965-66 में खाद्यान्न उत्पादन केवल 72 करोड़ टन था वह बढ़कर 1973-74 में 747 करोड़ टन तथा 1978-79 में ही 12.8 करोड़ टन होने का अनुमान है। केवल 12 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में 56 करोड़ टन की वृद्धि हुई है जबकि इतनी वृद्धि 1950-65 के 15 वर्षों में नहीं हो पाई थी। छठी योजना में खाद्यान्न का उत्पादन सक्षम 14 से 14.5 करोड़ टन रखा गया है। वैसे तो देश 1970-71 तक खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जाता पर अकाल, प्राकृतिक प्रकोपी व जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि के कारण अब भी विदेशी से खाद्यान्नो का आयात करना पड़ रहा है।

2 सिंचित क्षेत्र का विस्तार—पिछले 8 वर्षों में सिंचित क्षेत्र में भी काफी वृद्धि हुई है। 1965-66 में सिंचित क्षेत्र 322 करोड़ हेक्टर था वह बढ़कर अब 52 करोड़ हेक्टर हो गया है। छठी योजना में मध्यम व बड़ी सिंचाई योजनाओं के 80 लाख हेक्टर तथा लघु सिंचाई योजनाओं से 90 लाख हेक्टर अनिश्चित भूमि में सिंचाई होने से कुल सिंचित क्षेत्र 1982-83 तक 654 लाख हेक्टर हो जायेगा।

3 व्यापारिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि—देश में औद्योगिक कच्चे माल व निर्यात के लिए व्यापारिक फसलों के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। कपास, गन्ना, जूट तथा तिलहन की उत्पादन वृद्धि असाधारण तालिका 3 में स्पष्ट है।

4 यन्त्रीकरण—कृषि यन्त्रीकरण की बढ़ावा मिला है। जहाँ 1956 में देश में विद्युत पम्प सेटों की संख्या 47 हजार थी वह संख्या 1970-71 से बढ़कर 1691

लाख तथा 1978-79 में 35 लाख हो गई है। इसी प्रकार ट्रेक्टरों की कुल मांग 1966-67 में 20 हजार थी वह बढ़कर 1970-71 में 40 हजार तथा अब 4 लाख है। पाचवी पंचवर्षीय योजना में विद्युत पम्पसेटों की संख्या 40 लाख तथा ट्रेक्टरों की मांग 5 लाख तक बढ़ जाने का संक्षेप था। इसी प्रकार शक्ति संचालित हलों का प्रयोग 10 हजार से 1 लाख होने का अनुमान था।

5 रासायनिक उर्वरकों का उपयोग—पिछले 8 वर्षों में रासायनिक खादों के उपभोग में भी क्रान्तिकारी वृद्धि हुई है। 1965-66 में रासायनिक खादों का कुल उपयोग 7.6 लाख टन था वह बढ़कर 1970-71 में लगभग 21 लाख टन तथा 1974-75 तक 27 लाख टन तथा 1978-79 तक 50 लाख टन होने का अनुमान है। छठी योजना में उर्वरकों का उपयोग बढ़ाकर 78 लाख टन करने का संक्षेप है।

6 पौध संरक्षण एवं कीटाणुनाशक दवाइयों का प्रयोग—पौधों को कीटाणुनाश से नष्ट होने से बचाने के लिए पौध संरक्षण कार्यक्रम में तेजी आई है। जहाँ 1965-66 में 16.6 लाख हेक्टर में पौध-संरक्षण किया गया वहाँ चतुर्थ योजना के अन्त तक 650 लाख हेक्टर क्षेत्र में पौध-संरक्षण लागू था। सभी देश में लगभग 65 हजार टन कीटाणुनाशक दवाइयों का प्रयोग होता है तथा उसके अन्तर्गत 850 लाख हेक्टर क्षेत्र था।

7 उन्नत बीजों व अधिक उपज देने वाली फसलों का क्षेत्र विस्तार—कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए उन्नत बीजों व अधिक उपज देने वाली फसलों के क्षेत्र में वृद्धि की गई है। जहाँ 1965-66 में अधिक उपज देने वाली फसलों का क्षेत्र नगण्य था वह बढ़कर 1969-70 में 114 लाख हेक्टर तथा 1978-79 में 430 लाख हेक्टर हो गया है।

8 विविध—बहु-फसल कार्यक्रम के अन्तर्गत भी 1968-69 में 61 लाख हेक्टर था, वह 1978-79 में बढ़कर 220 लाख हेक्टर होने का अनुमान है। इसी प्रकार 52 करोड़ हेक्टर में चकबन्दी का कार्य पूरा हो चुका है। भूमि संरक्षण का लाभ अब 25 लाख हेक्टर क्षेत्र में हो रहा है। 1978-79 तक 25 लाख हेक्टर क्षेत्र को भूसंरक्षण का लाभ मिला है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पिछले 12 वर्षों में हरित-क्रान्ति से कृषि क्षेत्र में भारचर्यजनक प्रगति हुई है। एक दृष्टि में प्रगति व सफलता अग्र सारणी से स्पष्ट है—

## तालिका—3

## हरित क्रान्ति की सफलता और कृषि विकास (एक दृष्टि में)

विवरण	इकाई	1965-66	1968-69	1973-74	1978-79
कृषि उत्पादन का सूचकांक	(1949=100)	158	160	198	221
खाद्यान्न उत्पादन	करोड़ टन	72	9.4	10.47	12.8
तिलहन	लाख टन	63	8.5	94	134.4
गन्ना	लाख टन	131	120	140.8	175.0
कपास	लाख गॉर्डे	48	60	63	72
जूट एंव मेस्टा	लाख गॉर्डे	45	62	76	70
रासायनिक उर्वरकों का उपयोग	लाख टन	76	17.6	19.7	50
सिंचित क्षेत्र	करोड़ हेक्टर	3.22	3.6	4.30	5.2
पौध संरक्षण कार्य	लाख हेक्टर	166	400	630	850
अधिक उपज देने वाली फसलें	लाख हेक्टर	—	92	259	430

यद्यपि उपर्युक्त तालिका को देखने से ज्ञात होता है कि हरित क्रान्ति काफी सफल रही है इसके विपरीत इस नीति के आलोचकों का कहना है कि हरित क्रान्ति केवल गेहूँ, बाजरा तथा चावल आदि कतिपय वस्तुओं में ही सफल रही है बाकी फसलों में यह भिन्न रही है। कृषि-मूल्य आयोग ने भी आलोचना करते हुए लिखा है कि कृषि उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि अनुकूल मौसम, कृषि क्षेत्र के विस्तार तथा अन्य अनुकूल परिस्थितियों के कारण हुई है। हरित-क्रान्ति के कारण उत्पादन वृद्धि बहुत कम रही है।

यही नहीं हरित-क्रान्ति का लाभ अधिक समृद्ध वर्गों व कृषकों तक ही सीमित रहा है। गरीब कृषकों व भूमिहीनों की दशा में बिनाप मुश्किल नहीं हुआ है। क्षेत्रीय विपरीताओं में वृद्धि हुई है जो कि राजनैतिक एवं आर्थिक दोनों ही दृष्टियों में अवांछित है। अन्दाज से उर्वरकों के प्रयोग से कृषि योग्य भूमि बनार हुई है।

इन्हीं आलोचनाओं के बावजूद भी तथ्यों का नजरदाज नहीं किया जा सकता। पिछले आठ वर्षों में कृषि उत्पादन में जो तात्त्विक वृद्धि हुई है उससे कृषि क्षेत्र में एक नीरव क्रान्ति आई है। हरित क्रान्ति के कारण कृषकों में वैज्ञानिक व व्यावसायिक दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव हुआ है। देश खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। कृषि में यन्त्रीकरण का बालबाला है। समूचे प्रयत्नों का लाभ यह रहा है कि कृषकों की समृद्धि बढ़ी है।

## कृषि विकास की नवीन व्यूह रचना के सफल कार्यान्वयन की शर्तें एवं सुझाव

(Conditions & suggestions for Successful Implementation of the New Strategy of Agricultural Development)

कृषि विकास की नवीन नीति की असफलता उसके कार्यान्वयन में कुशलता, ईमानदारी, जन-सहयोग तथा सस्यागत परिवर्तनों की उपयुक्तता और समन्वय पर निर्भर करती है। हरित क्रान्ति की नीति की सफलता की मुख्य शर्तें एवं सुझाव निम्न हैं—

1. मिट्टी के पर्यवेक्षण के आधार पर बीजों का प्रयोग—भारत की विशालता में मिट्टी की विभिन्नता पाई जाती है। भिन्न-भिन्न मिट्टियों में उपज की भिन्नता के साथ अच्छे बीजों के समान रूप से सफलता की कल्पना करना वृद्धिपूर्ण है। अतः मिट्टी के पर्यवेक्षण के आधार पर ही उसके अनुकूल बीजों का उपयोग अनावश्यक क्षति से सुरक्षा प्रदान करेगा।

2. उर्वरकों की पूर्ति तथा उद्योग में उचित मार्ग-दर्शन—नई नीति के अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए उचित समय पर उचित उर्वरकों की पर्याप्त पूर्ति उचित मूल्यों पर हो जाना आवश्यक है। इसके लिए उर्वरकों का आवश्यक उत्पादन एवं आयात, मूल्यों की कमी वितरण में कुशलता तथा आवश्यक तकनीकी मार्ग-दर्शन मिलना जरूरी है।

3. विभिन्न विभागों में समन्वय एवं सहयोग—इस नीति की सफलता के लिए कृषि विकास से सम्बद्ध सभी विभागों में—सरकारी विभागों, पंचायतों, सहकारी संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं में समन्वय एवं सहयोग होना चाहिये जिससे अनावश्यक विलम्ब से छुटकारा तथा कुशलता में वृद्धि हो सके।

4. कृषि मूल्यों में स्थिरता तथा गारन्टी—नवीन कृषि नीति में अधिक जोखिम है। अतः इस नीति की सफलता के लिए कृषि मूल्यों में यथा सम्भव स्थिरता लाकर कृषकों को सम्भावित हानि से सुरक्षा का आश्वासन होना चाहिए।

5. कृषि वित्त तथा ऋण सुविधाओं का विस्तार—भारत के गरीब किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होने पर ही रासायनिक खाद, उन्नत बीज, कीटाणुनाशक औषधियों, कृषि उपकरणों का उत्तरोत्तर उपयोग सम्भव होगा। अतः कम ब्याज दर पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध किये जाने चाहिये।

6. पौध संरक्षण के प्रभावी प्रयत्न—उन्नत बीजों, रासायनिक खादों तथा तकनीकी मार्ग दर्शन में कृषि उत्पादन में तभी वृद्धि होगी जबकि फसलों को बीमारियों से बचाया जा सके तथा कीटाणुनाशक औषधियों से पौध संरक्षण सम्भव हो। अतः नवीन नीति की सफलता के लिए समय पर कीटाणुनाशक औषधियों उपलब्ध करना, पौध संरक्षण के सम्बन्ध में अनुसन्धान तथा किसानों को उन्हें अपनाते को प्रेरित

करना होगा। उचित मूल्यो पर कुशल वितरण भी होना आवश्यक है। इस दिशा में फसल बीमा योजना अपनाना उपयुक्त होगा।

7 भूमि सुधार कार्यक्रमो मे तेजी—यद्यपि देश को स्वतन्त्र हुए काफी लम्बी अवधि बीत चुकी है पर भूमि सुधार कार्यक्रमो मे अनेक कमियाँ रहने से अभी भी ऊँचे लगान, बेदखली, भूमिहीनो को शोषण, स्वामित्व अधिकारो का अभाव कृषि विकास मे बाधा उपस्थित करते हैं। अतः भूमि-सुधार कार्यक्रमो मे तेजी लाकर उनको कुशलता तथा सफलतापूर्वक कार्यान्वित करना चाहिये।

8 निर्धन किन्तु प्रगतिशील किसानो को प्रोत्साहन—समाजवादी समाज की स्थापना के लिए बहुसंख्यक, निर्धन किन्तु प्रगतिशील किसानो को सभी प्रकार की रियायतें तथा सुविधाएँ देकर नवीन नीति को क्रियान्वित करने मे प्रोत्साहन देना चाहिये। इससे सम्पन्न वर्गों के साथ निर्धन वर्ग के लोगो को भी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का अवसर मिलेगा। इससे सामाजिक समानता तथा वर्ग सहयोग बढ़ेगा।

9 प्रशासनिक कुशलता—नवीन नीति की सफलता के लिए प्रशासन के सभी स्तरों पर ढिलाई, भ्रष्टाचार और अनावश्यक विलम्ब को समाप्त कर कुशलता लानी चाहिए। इन कार्यों मे सलग्न अधिकारियों को प्रगति के विकास से सम्बद्ध करना चाहिए जिससे वे व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनावें।

10 अविकसित क्षेत्रो मे भी गंवासम्भव विकास कार्यों को प्रोत्साहन देना चाहिये तथा वहाँ जन-जागृति से नई चेतना उत्पन्न कर कृषि विकास मे प्रेरित करना चाहिये। निर्णय राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित न होकर आर्थिक दृष्टि से प्रेरित होने चाहिए। सिंचाई का ग्रन्थ क्षेत्रो मे विस्तार कर उनसे भी नई फसलो का प्रयोग करना चाहिये।

इस प्रकार कृषि विकास की नवीन व्यूह रचना हरित-क्रान्ति (Green Revolution) की सफलता के लिये एक महत्वाकांक्षी एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। सस्यामन परिवर्तनों, सिंचाई के साधनों के विकास एवं विस्तार, वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद रासायनिक खादो एवं उन्नत बीजों का उपयोग तथा टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन को अपनाने मे हमारा व्यवहार एवं क्रियान्वयन के प्रति दृष्टिकोण सैद्धांतिक व बेनोबदार न होकर प्रगतिशील, समाजवादी एवं व्यावहारिक होना चाहिए। नीति की सफलता जनसहयोग तथा सरकार द्वारा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर ही निर्भर करती है।

### परीक्षोपयोगी प्रश्न भय संकेत

1. भारतीय अर्थव्यवस्था मे कृषि का क्या महत्व है? और पंचवर्षीय योजनाओं मे कृषि विकास के लिये किये गये प्रयासों का मूल्यांकन कीजिये।  
(संकेत—भारत मे कृषि के महत्व को बताकर दूसरे भाग मे पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कृषि विकास का मूल्यांकन करना है)।

2. भारतीय कृषि के पिछड़े होने के क्या-क्या कारण हैं, योजनाबद्ध विकास के अन्तर्गत कृषि की प्रगति का मूल्यांकन कीजिये।

अथवा

भारत में कृषि विकास के मार्ग में मुख्य-मुख्य कठिनाइयाँ क्या-क्या हैं ? पच-वर्षीय योजनाओं में इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं और वे कहाँ तक सफल रहे हैं ?

(संकेत—कृषि विभाग की मुख्य बाधाओं का प्रथम भाग में विवेचन करके दूसरे भाग में योजनाओं के अन्तर्गत कृषि की प्रगति का मूल्यांकन देना है।)

3. कृषि विकास की नवीन व्यूह रचना से आप क्या समझते हैं ? यह नीति कृषि विकास में कहाँ तक सहायक सिद्ध हुई है ? 1980

अथवा

हरित-क्रान्ति से आप क्या समझते हैं ? हरित-क्रांति कहाँ तक दूरी है ?

(संकेत—कृषि की नवीन व्यूह-रचना (हरित-क्रान्ति) का अर्थ बताकर उसकी विशेषताएँ बताना है तथा दूसरे भाग में कृषि विकास का मूल्यांकन देना है कि 1965 के बाद प्रति एकड़ उत्पादन, कुल उत्पादन व स्वरूप में सीढ़ी गति से परिवर्तन आया है।)

- 4 “भारत में कृषि असफल रही है उसको सफल होना है” इस परिप्रेक्ष्य में कृषि के विकास का मूल्यांकन कीजिये।

(संकेत—विभिन्न योजनाओं में कृषि विकास पर भारी व्यय के बावजूद भी कृषि उत्पादन कम रहा है अतः सफलता के लिये प्रभावी प्रयासों का उल्लेख कीजिये तथा भावी सुधार के सुझाव दीजिये।)

1985

भारत में हरित-क्रान्ति से आप क्या समझते हैं ? इसकी सफलताओं एवं असफलताओं की विवेचना कीजिये। (Raj Iller B Com 1979)

(संकेत—हरित-क्रान्ति का अर्थ देकर उसकी विशेषताएँ संक्षेप में बताइये। फिर दूसरे भाग में उसकी उपलब्धियाँ “हरित-क्रान्ति कहाँ तक दूरी” शीर्षक की सामग्री देना है और तीसरे भाग में आलोचनाएँ देना है।)

# भारत में भूमि-सुधार

(Land Reforms In India)

(राजस्थान के विशेष सम्बन्ध में)

किसी भी कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था में कृषि उत्पादन व कृषकों की समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ भूमि-व्यवस्था (Land Tenure System) कैसी है, कृषकों व भू-स्वामियों में पारस्परिक सम्बन्ध अधिकार व उत्तरदायित्व क्या है ? लगान निर्धारण व वसूली का क्या ढंग है ? भू-सीमा क्या है ? जोतों की सुरक्षा कितनी है तथा कृषि का पुनर्संगठन कितना कुशल है ? जिस देश में समूची अर्थव्यवस्था की समृद्धि का आधार ही कृषि हो उनमें भूमि-सुधारों की आवश्यकता सर्वाधिक होता है ।

## भूमि सुधार का आशय

भूमि-सुधार शब्द अत्यन्त व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है जिसके अन्तर्गत वे सुधार आ जाते हैं जो भूमि-व्यवस्था (Land Tenure System), भूमि के स्वामित्व, अधिकार, दायित्व, जोतों के आकार, जोतों की सुरक्षा, लगान निर्धारण व वसूली की जाबत व्यवस्था, सहकारी कृषि, चक्रवर्दी, कृषि का पुनर्संगठन आदि से सम्बन्धित होते हैं । भूमि-व्यवस्था का अभिप्राय, भूमि पर स्वामित्व तथा भूमि पर वास्तविक छेती करने वाले के अधिकार व दायित्वों की व्याख्या करना होता है ।

## भूमि सुधार का उद्देश्य एवं महत्व

विद्वान मुन्नारा के शब्दों में 'जब ऐसी फलती-फूलती है तो उद्योग-धन्ये बनवने हैं और जब भूमि बजर छोड़ दी जाती है तो अन्य धन्ये भी अस्त हो जाते हैं ।' भारत के सम्बन्ध में यह कथन सत्य उतरता है । दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र की समृद्धि बहुत कुछ भूमि-व्यवस्था की उपयुक्त प्रणाली पर निर्भर करती है क्योंकि भूमि का स्वामित्व रेल की सोने में परिवर्तित कर देता है । कृषि कार्य में कुशलता आती है, उत्पादकता बढ़ती है तथा कृषि के विकास में समूची अर्थव्यवस्था के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है । डा० गांधीबहाल मुखर्जी का यह कथन "भारतीय कृषकों का जीवन-स्तर तब तक उन्नत नहीं किया जा सकता जब तक कि भूमि प्रणाली में ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाय जिससे कृषकों को अधिक कुशल कृषि करने का अवसर

मिले" युक्तिसंगत है। यही नहीं भूमि सुधारों का सामाजिक परिवर्तनों व सामाजिक न्याय से भी गहरा सम्बन्ध है। अतः भूमि सुधारों के उद्देश्य व महत्व को निम्न-शीर्षकों के अन्तर्गत रखा जा सकता है—

(i) कृषि विकास—भूमि-सुधारों में वास्तविक कृषकों को भू-स्वामित्व सौंपने में उत्पादन में वृद्धि, कुशलता व पर्याप्तता सम्भव है। "जमीन उसकी जो जमीन जोते" का नारा कार्यरूप में परिणत करने में ही भूमि, श्रम व पूँजी का आदर्श संयोग सम्भव होगा।

(ii) ग्राम तथा ग्रवसर की सामाजिक असमानता दूर करने से एक समाज-वादी अर्थव्यवस्था का केन्द्रीय उद्देश्य पूरा होता है।

(iii) कृषकों को शोषण से मुक्ति मिल जाती है क्योंकि जोत की सुरक्षा, लगान का उचित निर्धारण, व न्यायोचित बसूली, अनुपस्थित जमींदारों का उन्मूलन सभी सुधार इस दिशा में सहायक सिद्ध होते हैं।

(iv) भूमि का समान वितरण आर्थिक विषमता को कम करता है और यह सामाजिक समानता का मार्ग प्रशस्त करता है।

(v) भूमि-धारण व कास्तकारी अधिकारों से सम्बन्धित दोषों का निराकरण करना ताकि कृषि में कुशलता आ जावे।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सुधार के मुख्य उद्देश्य कृषि की संरचना के कारण पैदावार के मार्ग में आने वाली अड़चनों को दूर कर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करना जिससे कृषि उत्पादन व कुशलता दोनों बढ़ें और समाज में असमानता का उन्मूलन हो। इसलिये भूमि सुधारों के अन्तर्गत मध्यस्थों के उन्मूलन पट्टेदारी की सुरक्षा, लगान का नियन्त्रण, जोती की सीमा बन्दी, चक्रबन्दी तथा खेतों का पुनर्संगठन का प्रयास किया गया है।

### स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारत में प्रचलित भूमि-व्यवस्था

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंग्रेज शासकों ने भूमि-व्यवस्था की ऐसी दोषपूर्ण प्रणाली को सुदृढ़ बना दिया था कि जागीरदारी व जमींदारी प्रथा कृषकों के शोषण में सक्षम थी। किसान जमींदारों की कृपा के पात्र व साधनहीन बन गये थे। उनको कभी भी भूमि से वेदखल करना सम्भव था। पट्टे धारण की सुरक्षा नाममात्र की थी। ऊँचे लगान लेना सामान्य था। भू धारण की तीन प्रणालियाँ मुख्य रूप से कृषि, विकास की जड़ता के लिये उत्तरदायी थी। भूमि-व्यवस्था की मुख्य प्रणालियाँ निम्न थी—

1 रयतवाड़ी प्रथा (Ryotwari System)—यह प्रथा थॉमस मुनरो द्वारा सर्व प्रथम 1772 में मद्रास में लागू की गई। यह प्रथा धीरे-धीरे बम्बई, बरार, आसाम, मध्य प्रदेश आदि में प्रचलित हो गई थी। इस प्रथा के अन्तर्गत किसान और सरकार का सीधा सम्बन्ध था, किसान स्वयं खेतों का लगान सरकारी खजाने में



जमा करवाता और लगान न देने की स्थिति में वेदखन किया जा सकता था। पर धीरे-धीरे सरकार और किसान के बीच में मध्यस्थ पनपते गये और काश्तकार व उप-काश्तकार बन गये जिसमें शोषण होना स्वाभाविक था। 1947 में यह प्रथा मद्रास, गुजरात, महाराष्ट्र व मध्य-प्रदेश में प्रचलित थी।

**2 महलवाडी प्रथा (Mahalwari System)**—यह प्रथा 1833 में आगरा व प्रयाग में लागू की गयी पर बाद में पंजाब, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में प्रचलित हुई। इस प्रथा के अन्तर्गत सम्पूर्ण गांव को एक इकाई के रूप में मानकर उस गांव के किसानों का लगान निर्धारित किया जाता। वे सब संयुक्त व व्यक्तिगत रूप में एक मुखिया (महलदार) के माध्यम से मालगुजारी सरकारी कोष में जमा करवाते। भूमि पर सभी गांव वालों का संयुक्त स्वामित्व माना गया था। यद्यपि इस प्रथा में रयतवाडी के समान ही किसानों को अपनी भूमि हस्तान्तरण व उपयोग का अधिकार था पर इसमें भी बड़े बड़े किसानों ने भूमि पर खुद काश्त न कर उपकाश्तकारों को जन्म दिया।

**3 जमींदारी प्रथा (Zamindari System)**—इस प्रथा का श्री गणेश लार्ड कानॉनवालिस द्वारा 1793 में किया गया। इस प्रथा के अन्तर्गत एक निश्चित भू-राजस्व के बदले में जमींदारों का स्वामित्व अधिकार सौंप दिये गये। जमींदार भूमि-स्वामी के रूप में स्वयं भूमि को नहीं जोतता था पर लगान पर उठा देता था। इस प्रकार किसान और सरकार के बीच मध्यस्थ उत्पन्न हो गये। अंग्रेज शासकों ने जमींदारी प्रथा को इसलिये लागू किया था कि सरकारी प्राय में निश्चितता व स्थिरता आयेगी, भूमि में सुधार से कृषि का विकास होगा और एक ऐसे वर्ग का निर्माण होगा जो अंग्रेजों के स्वामिभक्त सेवक के रूप में उनके शासन की जड़े मजबूत बनायेगे। अंग्रेजों का अन्तिम उद्देश्य पूरा हुआ।

### जमींदारी प्रथा के दोष-दुष्प्रभाव

जमींदारी प्रथा में ऐसे अनेक दोष उत्पन्न हो गये कि भारतीय कृषि के विकास का मार्ग ही भ्रष्ट हो गया। जमींदारी व जागीरदारी प्रथा के निम्न दोष थे —

**1 कृषकों का शोषण**—जमींदारी प्रथा में जमींदार किसानों से मनमाना लगान वसूल करने लगे। चूंकि भूमि पर जमींदारों का स्वामित्व था अतः वे वेदखन करने में स्वतन्त्र थे और इस कारण कृषक उन जमींदारों की दया पर आश्रित थे। इस आश्रितता के कारण जमींदार बेगार लेते थे। कृषकों पर मनमाना ब्याज वसूल करते थे। अनेक प्रकार की लागतें व भेंट लेते थे। इस प्रकार जमींदार व उनके कर्मचारी सभी कृषकों का शोषण करने में व्यस्त थे।

**2 सरकार व जनता में प्रत्यक्ष सम्बन्ध विच्छेद** हो गया और दोनों के बीच एक खाई बढ़नी चली गई। जमींदार ही सर्वोच्च प्रतिनिधि था और वह सरकार को जनता के कष्टों से अवगत कराना तो दूर रहा अपने जुल्मों को बढ़ाता ही चला गया।

3. मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन—किसानों पर जमींदारों के भ्रष्टाचारों, बेदखली आदि के विरुद्ध झगड़ों में मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन मिला। इससे कृषकों में श्रद्धा प्रस्तुतता बढ़ती ही गई।

4 कृषि का पतन—कृषकों के शोषण, मुकदमेबाजी, बेदखली व भू-धारण की अनिश्चितता में कृषक भूमि विकास में कोई रुचि नहीं लेते थे और न कोई विनियोग ही करने में पहल करते थे। परिणामस्वरूप भूमि की उत्पादन-शक्ति निरन्तर गिरती ही गई।

5 आर्थिक जड़ता—जमींदारी प्रथा ने कृषि विकास का मार्ग ही अवरोध नहीं किया बल्कि समाज में ऐसे वर्गों को जन्म दिया जो परजीवी बन कर विलासिता के कारण नैतिक पतन की ओर अग्रसर हुआ। जो कुछ प्रायः ही उसे अनुत्पादक कार्यों में लगाते थे। विकास कार्यों में कोई रुचि नहीं थी। अतः अर्थव्यवस्था में स्थिरता आ गई।

6 सरकारी भ्रष्टाचार में स्थिरता—यद्यपि अंग्रेजों ने एक निश्चित भ्रष्टाचार के लिये जमींदारों को भू-स्वामित्व अधिकार दिए पर विकास व परिस्थितियों के अनुसार उसमें वृद्धि नहीं हुई। जमींदार किसानों से तो मनमाना लगान वसूल करते थे पर सरकारी खजाने में एक निश्चित राशि देते थे तथा बची रकम को वे विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत करने में लगाते थे। अतः सरकारी भ्रष्टाचार में स्थिरता आ गई।

7 मध्यस्थों की भरमार—जमींदारी प्रथा में बड़े जागीरदारों ने अपने अधिकारों को छोटे-छोटे जागीरदारों में हस्तान्तरित किया और बदले में कुछ लाभ लेने लगे। परिणामस्वरूप मध्यस्थों की एक श्रृंखला बढ़ती ही गयी यहाँ तक कि जमींदार व किसान के बीच 50 से अधिक विचौलिये बन गये इससे शोषण भी बढ़ता स्वाभाविक था।

8. असंतोष में वृद्धि—कृषकों के शोषण, जमींदारों के भ्रष्टाचारों, वेगारों व नैतिक पतन के कारण जमींदारों के विरुद्ध जनता का विरोध निरन्तर बढ़ रहा था। यही नहीं, जमींदार भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के सेनापतियों के विरुद्ध दमनकारी नीति अपनाकर उन्हें कुचलने में भरसक प्रयत्नशील थे। इससे भी जनता में इन देशद्रोहियों के प्रति रोष बढ़ता जा रहा था।

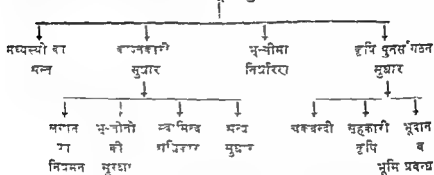
9 नैतिक पतन—जमींदारी प्रथा में जागीरदारों को परोपजीवी बनने का शोभाय्य मिला। वे कृषकों का मनमाना शोषण करते थे इससे बिना कमाई भ्राय से उनको विलासिता के जीवन-शराबखोरी, देशव्यवृत्ति आदि को बढ़ावा मिला इससे ग्रामीण जीवन सर्वथा नारकीय बनता गया।

### स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में भूमि सुधार

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश में भूमि-सुधारों का व्यापक कार्यक्रम अपनाया गया है जिससे न केवल दोषपूर्ण भूमि-व्यवस्था का समापन हुआ है बल्कि प्रगतिशील

हृषि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मध्यस्थों के अन्त में हृषिकों को शीघ्रता व धर्माचारों से मुक्ति मिली है। भारत में पञ्चवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत किए गए भूमि-सुधारों का अध्ययन की दृष्टि से निम्न तालिका के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और विवरण बाद में दिया जा रहा है—

### भारत में भूमि सुधार



#### 1 जमींदारी प्रथा का उन्मूलन व मध्यस्थों का अन्त

जमींदारी प्रथा के अनेक दोषों के कारण जतना का विरोध उनके प्रति बहुत पहले से पनप रहा था। 1928 में ही भागी कार्यस में प नेहरू ने जमींदारी प्रथा के समापन का प्रस्ताव दिया था। 1935 में पुनः मांग की गई पर अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को दबाने लगा। प्राजापति के बाद 1948 में हृषि सुधार समिति ने यह सिफारिश की कि भूमि पर स्वामित्व स्थानान्तरित होना चाहिये और जिन व्यक्तियों ने 6 वर्ष तक किसी नूतन पर खेती की है उन्हें उन भूमि का स्वामी मान लेना चाहिये तदनुसार मध्यस्थों के उन्मूलन का निर्णय लिया गया।

देश के लगभग 40 क्षेत्र में जमींदार, जमींदार, बंदाईदार व विचोलिए थे, अतः न केवल विभिन्न राज्यों में पारित अधिनियम से मध्यस्थों के उन्मूलन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। परिणामस्वरूप दो करोड़ से भी अधिक कारखाने भूमि के स्वयं मालिक बन गए तथा उनका सरकार से प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो गया है। मध्यस्थों की बहुत सारी परती भूमि भी सरकार के हाथ में आ गई। उनकी लगभग 57.7 लाख हेक्टर भूमि को एक करोड़ में अधिक भूमिहीन किसानों में बांट दिया गया है। जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों ने जो अधिनियम पारित कर भूमि अधिग्रहण की है उनके अन्तर्गत में 6.41 करोड़ रु मुद्रावका देना तथा हुआ है जिसमें 421 करोड़ रु भूमि का मुद्रावका, 92 करोड़ रु पुनर्वासन सहायता व 128 करोड़ रु व्याज के रूप में देना पड़ेगा। अब तक लगभग 350 करोड़ रु का मुद्रावका दिया जाने का अनुमान है।

यद्यपि कुछ राज्यों में भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी अध्यादेश रिहाई व कुशल कर्मचारियों के अभाव में मध्यस्थों के समापन में कठिनाई आई है। शक्तिपूर्ति का भी

सरकार पर भारी दबाव पड़ा है फिर भी इस दोषपूर्ण प्रथा के समापन से सरकार व किसान में सीधा सम्पर्क हो गया है। कानूनी छद्मचनो को सविधान म रणोधन करके भी दूर किया गया है।

## 2 काश्तकारी सुधार (Tenancy Reforms)

भारत के विभिन्न राज्यों में काश्तकारी कानूनों में भी सुधार किया गया है जिसके परिणामस्वरूप लगान की कमी, किसानों को भूमि का मालिकाना हक देने व स्थायी सुधारों के लिए मुआवजे की व्यवस्था की गई है। किसानों की बेदखली पर रोक लगाकर भू-धारण की सुरक्षा प्रदान की गई है। काश्तकारी सुधारों के अन्तर्गत निम्न विवरण युक्तिसंगत है—

(1) लगान का नियम (Regulation of Rents)—कृषि विकास के लिए लगान का न्यायोचित निर्माण व सरल रूप में वसूली आवश्यक है। जमींदारी प्रथा में साधारणतः आधी से अधिक उपज लगान के रूप में किसान से ले ली जाती है इससे किसान के पास उपज का बहुत ही कम भाग रह जाता था। प्रथम योजना में योजना आयोग ने लगान कृषि उपज के  $\frac{1}{3}$  से  $\frac{1}{2}$  भाग पर ही निर्धारित करने की सिफारिश की। द्वितीय व तृतीय योजनाओं में भी इसी पर विशेष बल दिया गया। परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में अधिनियम पारित कर लगान में कमी कर दी गई है तथा लगान की दरें निवारित कर दी गई हैं।

उन दरों से अधिक लगान वसूल करना अवैधानिक है। सभी राज्यों में लगान की दरें समान नहीं हैं जहाँ राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र में लगान दर उपज का  $\frac{1}{3}$  है, दिल्ली में  $\frac{1}{4}$  भाग, उड़ीसा में  $\frac{1}{5}$  भाग तथा आन्ध्रप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी बंगाल व जम्मू काश्मीर में  $\frac{1}{5}$  से  $\frac{1}{3}$  भाग है अब भी कुछ राज्यों में लगान की दरें ऊँची हैं उन्हें नियमित करना आवश्यक है।

(ii) भूमि धारण की सुरक्षा (Security of Tenure)—भूमि धारण की सुरक्षा का अभिप्राय काश्तकारों को स्थायी भूमि सुधार मिलने से है ताकि उन्हें बेदखल नहीं किया जा सके। इस सुरक्षा में दोहरा लाभ मिलता है। पहला उत्पादन में वृद्धि व दूसरा सामाजिक न्याय। योजना आयोग के अनुसार भी लगान व प्रभावी नियमन तभी सम्भव है जबकि काश्तकारों को पट्टेदारी की सुरक्षा प्राप्त हो। अतः सभी राज्यों में भू-जोती की सुरक्षा सम्बन्धी अधिनियम पारित किये जा चुके हैं। परिणामस्वरूप कृषि योग्य 9% भूमि में भू-धारण की पूरी सुरक्षा मिल चुकी है। 59% क्षेत्र में आंशिक सुरक्षा, 19% क्षेत्र में अस्थायी सुरक्षा हो पाई है पर 12% क्षेत्र में अभी भी पट्टेदारी सुरक्षा का अभाव है।

इन अधिनियमों के बावजूद भी बेदखली होती है इस पर रोक के लिए प्रभावी व व्यावहारिक कानूनों की आवश्यकता है।

(iii) काश्तकारी का पुनर्ग्रहण (Resumption of Tenancies)—काश्तकारों को भू-स्वामियों को भू-स्वामियों द्वारा वेदखली से सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में पुनर्ग्रहण अधिकार को यथासम्भव सीमित करने का प्रयास किया है। उत्तरप्रदेश, बंगाल व दिल्ली में भू-स्वामियों को भूमि के पुनर्ग्रहण की इजाजत नहीं है। बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, मणौपुर व हिमालय-प्रदेश में भू-स्वामियों द्वारा काश्तकारी व पुनर्ग्रहण की यह शर्त है कि यह खुदकाश के लिए हो तथा कृषक के पास भी भूमि की न्यूनतम जोत छोड़ना आवश्यक है। पंजाब व आसाम में पुनर्ग्रहण का अधिकार काश्तकार को अन्यत्र भूमि देने पर ही सम्भव है जबकि आन्ध्र-प्रदेश व तामिलनाडू में भू-स्वामी काश्तकारी का पुनर्ग्रहण निर्धारित सीमा तक ही कर सकते हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि काश्तकार से भूमि अधिग्रहण का अधिकार खुदकाश के लिए भी तब हो जबकि काश्तकार को अन्यत्र जमीन की व्यवस्था कर दी जाय।

(iv) काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार (Ownership Rights for Tenants)—आर्थिक दृष्टि का यह कथन “निजी सम्पत्ति का जाबू रेत को भी सोना बना देता है। किसी व्यक्ति को कालो चट्टान का अधिकार दे दीजिए वह उसे उपवन में बदल देगा और अगर नौ वर्ष के ठेके पर उपवन दे दिया जाय तो मरुस्थल में बदल देगा।” इस बात की पुष्टि करती है कि जब तक जमीन जोतने वालों की नहीं होगी तब तक तीव्र विकास की कल्पना बेकार लगती है। अतः उन क्षेत्रों में जिनका पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकता, काश्तकारों को मालिकाना हक दिया जाना उपयुक्त है। भारत के विभिन्न राज्यों में काश्तकारों को भूमि का मालिकाना हक सौंपने के लिए अधिनियम पारित हुए हैं। काश्तकारों को भू-स्वामी बनाने के लिए तीन प्रकार की व्यवस्था की गई है—(i) मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र में काश्तकारों को भूमि का स्वामी घोषित कर उनके स्वामियों को उचित मुआवजा उपयुक्त किशो में चुकाने का प्रावधान किया गया, (ii) दिल्ली तथा कुछ राज्यों में सरकार ने स्वयं भू-स्वामियों को मुआवजा चुकाकर काश्तकारों को भू-स्वामित्व अधिकार उचित विस्तार के बदले में सौंपा है। (iii) केरल तथा उत्तर-प्रदेश में सरकार ने भू-स्वामियों से भूमि के अधिकार प्राप्त कर काश्तकारों को निर्धारित मुआवजा चुकाकर स्वामी बनने की छूट दे दी है।

इन प्रयत्नों के फलस्वरूप 30 लाख काश्तकारों, उपकाश्तकारों या बटाईदारों को 28 लाख हेक्टर भूमि में मालिकाना हक मिल चुका है जिसमें राजस्थान में 1.7 लाख आसानी से भूमि के मालिक बन चुके हैं। गुजरात में 4.62 लाख काश्तकारों को 14 लाख एकड़ में, महाराष्ट्र में 6.2 लाख काश्तकारों को 17 लाख एकड़ तथा उत्तर-प्रदेश में 15 लाख आसामियों को 20 लाख एकड़ में स्वामित्व अधिकार दिए जा चुके हैं।

(१) स्थायी सुधारों के लिए मुआवजे—काश्तकारों को भू-स्वामियों की बेदखली से सुरक्षा के रूप में स्थायी सुधारों—जैसे नालियाँ बनाने, कुआँ बनाने, खाद देने, पेड़ लगाने या मेड़ लगाने आदि के लिए मुआवजा चुकाने पर ही बेदखली सम्भव है ।

(२) ग्रन्थ सुधारों के अन्तर्गत काश्तकारों से ली जाने वाली वेगार अवैधानिक है । प्राकृतिक सड़कों के समय—बाढ़, सूखा, अकाल आदि काश्तकारों को लगान में छूट की व्यवस्था है । यदि लगान देने में काश्तकार असमर्थ रहे तो उसके हल, बँल, वर्तमान फसल व कृषि यन्त्र नीलाम नहीं किये जा सकते हैं ।

### 3 जोतों की सीमा निर्धारण (Ceiling on Holdings)

आर्थिक जोतों के निर्माण तथा भूमि के वितरण में समानता लाने की दृष्टि से जोतों की सीमा निर्धारण आवश्यक है । सीमा निर्धारण के अन्तर्गत न्यूनतम सीमा निर्धारण उप-खण्डन व उप-विभाजन को रोकने के लिए आवश्यक है जबकि उच्चतम सीमा निर्धारण का उद्देश्य किसी भी भू-स्वामी के पास आवश्यकता से अधिक भूमि लेकर भूमिहीनों में बांटने से भूमि के सदुपयोग की व्यवस्था सम्भव है ।

उच्चतम सीमा निर्धारण के उद्देश्य—सीमा निर्धारण के अनेक उद्देश्य हैं जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं—

- (i) सब किसानों के लिए भूमि का समान वितरण करना ।
- (ii) सीमा निर्धारण से खेतों को आर्थिक जोतों के रूप में परिवर्तित करना ।
- (iii) बड़े आकार के खेतों को उचित आकार में परिवर्तित करना ताकि उनकी प्रवृद्ध कुशलता बड़े ।
- (iv) उच्चतम सीमा से अधिक भूमि को लेकर उसे भूमिहीनों में बांटना तथा अधिक लोगों के लिए रोजगार व्यवस्था करना ।

उच्चतम सीमा निर्धारण के दो पहलू हैं—पहला वर्तमान जोतों पर सीमा निर्धारण तथा दूसरा भावी जोतों पर सीमा निर्धारण करना जिससे भविष्य में कोई किसान कितनी अधिकतम भूमि रख सकेगा उसका निर्धारण हो जाता है ।

वर्तमान जोतों की सीमा निर्धारण का कार्य उच्चतम सीमा से अधिक भूमि कानून पास कर सरकार द्वारा ले ली गई है और अतिरिक्त प्राप्त भूमि को भूमिहीन किसानों में बांटने की व्यवस्था की गई है । विभिन्न राज्यों से नवीनतम अधिनियम पास कर वर्तमान जोतों का आकार निश्चित कर दिया गया है जैसा अग्र तालिका से स्पष्ट है—

## भूमि सीमा निर्धारण

(हेक्टर में)

राज्य	जोत की सीमा	राज्य	जोत की सीमा
आन्ध्र प्रदेश	4 05 से 21 85	गुजरात	4 05 से 21 85
आसाम	6 71	कर्नाटक	4 86 से 21 85
बिहार	6 07 से 18 21	पंजाब	7 00 से 21 80
मध्य-प्रदेश	4 05 से 21 85	उड़ीसा	4 05 से 18 21
राजस्थान	7 25 से 21 85	तामिलनाडू	4 86 से 24 28
हरियाणा	7 25 से 21 85	त्रिपुरा	2 00 से 7 20
पश्चिमी बंगाल	5 00 से 7 00	हिमाचल-प्रदेश	4 05 से 12 14
महाराष्ट्र	7 25 से 21 85	जम्मू काश्मीर	3 86 से 7 77
केरल	4 86 से 6 07		
उत्तर-प्रदेश	7 25 से 18 21		

उच्चतम सीमा निर्धारण का आधार—भूमि की उर्वरा शक्ति में भिन्नता, प्रकृति में भिन्नता स्थान की भिन्नता आदि के कारण एक ही सीमा निर्धारित करना असम्भव है। 1971 में केन्द्रीय भूमि सुधार समिति ने सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में कुछ सामान्य सिफारिश की थी जिसमें (i) सीमा निर्धारण को परिवार आधार पर लागू किया जाय जिसमें पति-पत्नी व नाबालिग बच्चे सम्मिलित हों। (ii) पाँच से अधिक सदस्यों के परिवार में प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य के लिए अतिरिक्त भूमि की छूट हो पर एक परिवार के पास सीमा के दुगुने क्षेत्रफल से अधिक भूमि न हो। (iii) पाँच सदस्यों के परिवार के लिए सम्मानजनक जीवन बिताने के लिए उच्चतम सीमा 10 से 18 एकड़ उपजाऊ व सिंचित भूमि की व्यवस्था होनी चाहिए। भूमि की भिन्नता के कारण ही भिन्न-भिन्न भूमि की वर्तमान व भावी जोतों की सीमा में अन्तर पाया जाता है।

सीमा निर्धारण के लाभ—जोतों की उच्चतम सीमा निर्धारण के अनेक लाभ हैं। (i) भूमि के वितरण में समानता लाने में मदद मिलेगी जिससे समाजवाद का मार्ग प्रशस्त होगा। (ii) सीमा से अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन किसानों में बाँटने से

भूमिहीनो को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। (iii) भूमि की उचित व आर्थिक जोतों के निर्माण से प्रबन्ध कुशलता बढ़ेगी। (iv) आर्थिक विपमता को कम करने में सहायता मिलेगी। (v) भूमि के समान वितरण से चक्रवर्ती व सहकारी कृषि का कार्य सरल हो जायगा और दोनों को प्रोत्साहन मिलेगा।

सीमा निर्धारण के दोष—(i) जोतों की सीमा निर्धारण से बड़े पैमाने की कृषि का हतोत्साहन होता है अतः यन्त्रीकरण सम्भव नहीं हो पाता। (ii) अतिरिक्त भूमि का हस्तान्तरण अगर साधनहीनो के पास होगा तो उत्पादकता घटेगी और प्रबन्ध कुशलता गिरेगी। (iii) सीमा निर्धारण से प्राप्त कुल भूमि इतनी कम है कि भूमिहीनो की समस्या का समाधान सम्भव नहीं लगता। (iv) छोटे खेतों के कारण बाजार में विक्रय वाली उपज की मात्रा प्रायः घटती है। (v) सीमा निर्धारण के बाद अतिरिक्त भूमि को हस्तगत करने के लिए क्षति-पूर्ति का भार सरकार को उठाने की समस्या उत्पन्न हुई है। (vi) सीमा निर्धारण में बड़े-बड़े भूस्वामियों से भूमि लेने में वर्ग संघर्ष की भावना जागृत हुई है।

फिर भी सीमा निर्धारण के लाभ सम्भावित खतरो के मुकाबले काफी अधिक हैं। कुछ क्षेत्रों में सीमा निर्धारण की छूट देकर दोषों को दूर करने का प्रयास किया गया है। चाय, कच्चा, रबड़ व इलायची के बागानों में सीमा निर्धारण से छूट की व्यवस्था है। सरकारी फार्म व चीनी मिलों के गन्ने के फार्मों में सीमा निर्धारण की छूट दी गई है। विशेष तौर पर जिनमें पशुपालन, भेड़ पालन व दुग्ध शालाओं को उच्चतम सीमा निर्धारण में छूट है।

यह उल्लेखनीय है कि सीमा निर्धारण के कारण अब तक 11.5 लाख हेक्टर, अधिक अतिरिक्त भूमि प्राप्त हुई है जिसमें 6.3 लाख हेक्टर भूमि भूमिहीनो में वितरित की गयी है। सबसे ज्यादा अतिरिक्त पश्चिमी बंगाल में 3.2 लाख हेक्टर, जम्मू काश्मीर में 1.8 लाख हेक्टर, उत्तरप्रदेश में 0.5 लाख हेक्टर भूमि प्राप्त हुई है।

#### 4. कृषि पुनर्संगठन

(Reorganisation of Agriculture)

भूमि सुधारों के अन्तर्गत कृषि का पुनर्संगठन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् कृषि पुनर्संगठन कार्यक्रमों में चक्रवर्ती, भूदान आन्दोलन सहकारी कृषि एवं भूमि प्रबन्ध सुधार आदि आते हैं।

(i) चक्रवर्ती—जब भूमि के छोटे-छोटे बिल्खरे टुकड़ों को मिलाकर स्वेच्छा या कानूनी दबाव से बड़े चक्रों में परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसे चक्रवर्ती कहते हैं। भारत में चक्रवर्ती का कार्य काफी प्रगति पर रहा है। प्रथम योजना के अन्त तक 33 लाख हेक्टर में चक्रवर्ती की जा चुकी है। द्वितीय योजना के अन्त तक चक्रवर्ती के अन्तर्गत 1.21 लाख हेक्टर क्षेत्र आ गया। तृतीय योजना के अन्त तक 2.41 लाख हेक्टर की चक्रवर्ती की जा चुकी थी, तीन वार्षिक योजनाओं में लगभग



— 55 लाख हेक्टर की चक्कन्दी की गई। परिणामस्वरूप 1968-69 तक कुल मिला कर 296 लाख हेक्टर भूमि में चक्कन्दी हो चुकी थी, चतुर्थ योजना में चक्कन्दी के लिए 28.4 करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था की गई थी तथा कुल मिलाकर चक्कन्दी के अन्तर्गत 390 लाख हेक्टर क्षेत्र करने का लक्ष्य रखा गया था पर वास्तव में 320 लाख हेक्टर क्षेत्र की चक्कन्दी हो पाई है। 1978-79 तक 520 लाख हेक्टर की चक्कन्दी हो चुकी थी।

राज्यों के अनुसार पञ्जाब व हरियाणा में चक्कन्दी का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। उत्तरप्रदेश में भी 95 लाख हेक्टर में चक्कन्दी की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में देश के प्रायः सभी राज्यों में अधिनियम पारित हो चुके हैं।

(ii) सहकारी कृषि—पहली व द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण सर्वव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए सहकारी कृषि पर विशेष बल दिया गया। तृतीय योजना में 318 पायलट परियोजनाओं में प्रत्येक में 10-15 सहकारी कृषि समितियों के संगठन की व्यवस्था की गई। परिणामस्वरूप 30 जून 1974 तक समुक्त सहकारी कृषि समितियों की संख्या 4985 तथा उनकी सदस्य संख्या 1.22 लाख थी जबकि सामूहिक कृषि समितियों की संख्या 4740 तथा उनकी सदस्य संख्या 1.48 लाख थी। उनके पास क्रमशः 3.2 लाख, 3.1 लाख हेक्टर भूमि थी।

दण्डारण्य क्षेत्र में सामुदायिक विकास केन्द्रों में सहकारी कृषि समितियों का संगठन किया गया है जिनमें स्थिरापिता की बसाने का कार्य किया गया है। मैसूर के तुंगभद्रा व आन्ध्रप्रदेश के गादावरी व कृष्णा नदियों की मिट्टाई परियोजना क्षेत्र में सहकारी कृषि समितियों के विकास के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है।

सहकारी कृषि समितियों के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सहकारी कृषि सत्राङ्गण चोर्ट तथा राज्यों में सहकारी कृषि बोर्डें गठित की गई हैं।

(iii) भूमिहीनों को बसाना व भूदान आन्दोलन—भूदान आन्दोलन का गुरुदास आचार्य जिनावा गाँव में 1951 में तेलंगाना क्षेत्र में किया जिसके अन्तर्गत भूमि का 1/4 भाग दान के रूप में लिया जाता है। न्याय व समानता के आधार पर भूमि पर सबका अधिकार है। इसके लिए जिना सघर्ष के भूमिहीनों को भूमि का हिस्सा देने का कार्यक्रम है।

धार्मिक अर्थ में भूदान आन्दोलन का अर्थ भूमिहीनों को बसाने के लिए भूमिदाताओं में उनकी भूमि का छटा भाग स्वेच्छा से दान करने का अनुरोध है। अतः यह आन्दोलन सम्पत्तिदान, बुद्धिदान, जीवदान व धर्मदान आन्दोलन में बदल गया है। इसके अन्तर्गत 2 करोड़ हेक्टर भूमि प्राप्त करने का लक्ष्य है।

इसके लिए सभी राज्यों में भूमि के हस्तान्तरण व वितरण के लिए कानून पास किये जा चुके हैं।

अन्तिम रूप से उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार भूदान आन्दोलन के अन्तर्गत

43 लाख एकड़ भूमि तथा 40 हजार ग्राम दान में मिल चुके हैं उसमें से 10 लाख एकड़ भूमि भूमिहीनों में वितरित कर दी गई है। इसमें भू स्वामियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। पर जो भूमि प्राप्त हुई है उसमें से अधिकांश भूमि बजर, सिंचाई रहित व भगड़े की है अतः विशेष लाभ की आशा नहीं है।

(iv) भूमि प्रबन्ध में सुधार—देश में योजनाबद्ध विकास के साथ ही भूमि प्रबन्ध में भी सुधार के प्रयास किये गये हैं जिसके फलस्वरूप बजर भूमि के उपयोग, उत्तम बीजों व अधिक उपज देने वाली फसलों का प्रयोग बढ़ा है, हरित-क्रान्ति इसका परिचायक है। कीटाणुनाशक दवाइयाँ भी प्रयुक्त की जाने लगी हैं। उर्वरकों की पूर्ति व प्रयोग भी बढ़ रहे हैं। यन्त्रीकरण भी बहुत बढ़ा है। वैको के द्वारा वित्तीय व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है।

### भूमि सुधारों की आलोचनात्मक समीक्षा

यद्यपि भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भूमि सुधार कार्यक्रमों को बहुत ही जोश के वातावरण में लागू किया गया है पर उसमें अनेक कमियों के कारण कार्यान्वयन बढ़ा ही असम्पोजनक रहा है इस कारण भूमि सुधारों की अनेक आलोचनाएँ की गई हैं।

(i) भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में एकरूपता का अभाव—भूमि सुधार कार्यों का दायित्व राज्य सरकारों पर होने से भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों ने जो अधिनियम पारित किये हैं उनमें एकरूपता का अभाव है।

(ii) कानूनी खामियों के कारण अनावश्यक विलम्ब—विभिन्न अधिनियमों में एकरूपता का अभाव तो है ही बल्कि साथ-साथ उन अधिनियमों में कानूनी खामियाँ भी रही हैं जिसका निहित स्वार्थों ने छिद्रान्वेषण कर कानूनी दुर्बलताओं का लाभ उठाया है।

(iii) काश्तकारों को सुरक्षा, शोषण से मुक्ति व स्वामित्व कोरी कल्पना बनी हुई है। अब भी देश में काश्तकारों को बेदखल किया जाता है। उनसे अवैधानिक ढंग के ऊँचे लगान वसूल किये जाते हैं। भू स्वामित्व अधिकार भी बहुत ही कम काश्तकारों को मिल पाया है। पुनर्संगठन कार्य भी असम्पोजनक रहा है।

(iv) सीमा निर्धारण को लागू करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है जिसके कारण बड़े-बड़े भू-स्वामी भूमि का हस्तान्तरण अपने निकटतम सम्बन्धियों आदि को करके कानून के चंगुल से बच गये हैं। इसका दुष्प्रभाव यह हुआ है कि 1971 तक केवल 10 लाख हेक्टर भूमि ही 'अतिरिक्त' (Surplus) घोषित हुई है जो कुल कृषि क्षेत्र का 0.8% भाग है।

(v) प्रशासनिक अकुशलता एवं अष्टाचार के कारण भी भूमि सुधार के लक्ष्यों व प्राप्ति में काफी अन्तर है। भूमि सुधारों को जिस गति से कार्यान्वित किया जाना चाहिये वह सम्भव नहीं हो पाता।

(vi) समन्वय का अभाव—विभिन्न राज्यों में जो भूमि सुधार लागू किये गये हैं उनमें परस्पर समन्वय का अभाव पाया गया है अतः प्रशासनिक कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं और विभिन्न कार्यों में तालमेल भी नहीं बैठ पाता ।

(vii) जन सहयोग का अभाव व भूमि सुधारों से बचने के प्रयास—भूमि सुधार के क्रान्तिकारी कार्यक्रमों को लागू करने में निहित स्वार्थी-वर्ग ने सुधारों से बचने के लिए सभी प्रकार के हथकण्ड अपनाये हैं । जब सरकारी प्रवक्ता किसी सुधार की घोषणा करते हैं तब डरावने व वास्तविक कानून बनाने के बीच लम्बी अवधि में सभी प्रकार के बचने के उपाय अपना लिये जाते हैं । इसके अतिरिक्त अधिकांश कृषकों में अनिश्चय है कि वे न तो कानून को समझते हैं और न घोषण से बचने के लिए कानून की शरण लेते हैं जैसे ऊँची लगान व बेदखली के विरुद्ध शरण लेने से काश्तकार कतराते हैं ।

(viii) भूमि विवरण में अभी भी असमानता है । बड़े बड़े भू-स्वामियों के कब्जे में अब भी काफी भूमि है जबकि भूमिहीनों की संख्या अब भी बहुत बड़ी है । काश्तकारों की भरमार है ।

उपर्युक्त विवरण व आलोचनाओं से स्पष्ट होता है कि भूमि सुधारों की प्रगति आशानुसार व उसाहवर्धक नहीं रही जा सकती क्योंकि मध्यस्थों का अन्त करने के बाद भी सब किसान स्वयं भूमि का मालिक नहीं हैं, अनेक छोटे-छोटे मध्यस्थ काश्तकारों से ऊँची लगान वसूल करते हैं । बेदखली का भय हमेशा बना रहता है । फिर भी यह मानना ही पड़ेगा कि जमींदारी व जागीरदारी प्रथा के समापन से शोषक वर्ग का उन्मूलन हुआ है । अनेक कृषक स्वयं भूमि के स्वामी बन गये हैं । भूमि को अधिकतम सीमा निर्धारण से समाजवाद का मार्ग प्रशस्त हो रहा है । क्रान्तिकारी भूमि सुधार अगर सच्चे दिल से लागू किये जायें तो अनेक समस्याएँ स्वयं समाप्त हो जायेंगी । जमींदारी प्रथा का पूर्ण उन्मूलन हो चुका है । 30 लाख काश्तकारों को 70 लाख एकड़ का स्वामित्व प्रदान कर दिया गया है । सभी राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है ।

### भूमि सुधारों की सफलता के सुझाव

भूमि सुधारों की पर्याप्त सफलता के लिये यह आवश्यक है कि (i) भूमि सुधार अधिनियमों की कानूनी सामियों को दूर कर उन्हें प्रभावी रूप से लागू किया जाय ताकि बचन की सम्भावनाएँ सीमित हो जायें (ii) प्रशासनिक कुशलता बड़ाई जाय व भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण रखा जाय ताकि भूमि सुधारों को मुश्किलों से लागू करना सम्भव हो सके । (iii) भूमि सुधारों को लागू करने में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि विलम्ब होने में बहुत से स्वार्थी लोग कानून के छिद्रान्वेषण द्वारा कानून के चंगुल से बच जाते हैं । (iv) भूमि का स्वामित्व उच्च प्राँश को ही सीधेना चाहिये जो वास्तव में स्वयं कृषि करता है । वर्तमान कानून जो कि नताओं, मालगुजारी

व व्यावसायिक व्यक्तियों को अधिकांश भूमि खुदकाफ्त के अन्तर्गत रखने की अनुमति देता है समाप्त कर देना चाहिये तथा वास्तविक कृषक का ही भूमि का स्वामी बनाना उपयुक्त होगा। (v) किसानों से मनमाने ढंग से लगान वसूल करने व बेदखली के विरुद्ध सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किया जाना चाहिये। (vi) भूमिहीनों को पड़त भूमि का आवंटन करने में शीघ्रता बरती जाना परम आवश्यक है पर देखा यह गया है कि वास्तविक भूमिहीनों को भूमि न मिलकर राजनताओं, सरकारी अफसरों, कमचारियों को भूमि का आवंटन हुआ है क्योंकि वे भी वर्तमान अर्थ में भूमिहीन ही हैं अतः ऐसे कानून में संशोधन करना जरूरी है। (vii) सीमा बन्दी से प्राप्त भूमि को शीघ्र भूमिहीनों को आवंटित की जानी चाहिये। (viii) भूमि के गैर-कृषकों के पास हस्तान्तरण पर रोक लगा दी जानी चाहिये।

### राजस्थान में भूमि सुधार

राजस्थान के गठन के समय 1949 में राज्य के कुल 34648 गाँवों में से 16780 गाँवों में (60%) में जागीरदारी प्रथा, 4780 गाँवों (20%) क्षन में जमींदारी व विश्वेदारी प्रथा प्रचलित थी केवल 20% क्षेत्र ही रयतवाड़ी प्रथा के अन्तर्गत आता था जिसका सरकार से सीधा सम्बन्ध था। जमींदारी व जागीरदारी प्रथा में कृषकों का शोषण होता था, बेमार ली जाती थी। मनमाने ढंग से लगान वसूली व वदवनी का भय हमेशा व्याप्त रहता था, किसान पूर्णतः जागीरदारों व जमींदारों की दया पर आश्रित थे।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश के अन्य भागों में भूमि सुधारों के साथ-साथ राजस्थान में भी क्रान्तिकारी भूमि सुधारों का सूत्रपात हुआ।

1 बेदखली से रक्षा—सर्व प्रथम सन् 1949 में जब जमींदारों ने किसानों से अन्धाधुन्ध बेदखली करना प्रारम्भ किया तो किसानों की बेदखली से रक्षा करने के लिए राजस्थान (काश्तकार संरक्षण) अध्यादेश, 1949 (Rajasthan (Protection of Tenants) Ordinance 1949) जारी किया गया। इसके लागू होने से अवधानिक ढंग से बेदखल किये गये काश्तकारों को पुनः मिल्कियत अधिकार दिए गए।

2 लगान नियन्त्रण—मनमाने ढंग से ऊँचे लगान वसूल करने पर नियन्त्रण करने तथा सभी क्षेत्रों में लगान में समानता लाने के लिए सन् 1951 में राजस्थान उपज लगान नियमन अधिनियम (Rajasthan Produce Rent Regulating Act 1951) जारी किया गया जिसमें काश्तकारों से वसूल किया जाने वाला लगान कुल उपज के  $\frac{1}{3}$  से ज्यादा नहीं हो सकता था। इसको अधिक प्रभावी बनाने के लिए 1952 में कृषि लगान नियन्त्रण अधिनियम 1952 (Agricultural Rents Control Act) पारित किया गया। इसे बाद में रद्द कर दिया गया और 1954 में नया अधिनियम राजस्थान कृषि लगान नियन्त्रण अधिनियम (Rajasthan Agricultural Rents Control Act 1954) पारित हुआ जिसके अन्तर्गत मध्यमों का

मालगुजारी के द्रुगुने से अधिक लगान वमूली पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। फिर इसके बाद राजस्थान शासककारी अधिनियम 1955 पाम किया जिसमें कृषकों को लगान की वमूली में शोषण से मुक्त करने की व्यवस्था है।

3 जागीरदारों प्रथा का अन्त—राजस्थान के लगभग 17 हजार गाँवों में राज्य के 60% क्षेत्र में जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए 1952 में राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम (The Rajasthan Land Reforms & Resumption of Jagirs Act 1952) पास किया गया जिसको बाद में कुछ जागीरदारों ने न्यायालय व “स्वयंशासन आदेशों” से लागू करने में बाधा लड़ी करदी पर पण्डित महारू की मध्यस्थता से जागीरदारों को सुझावजा व पुनर्वाप्त अनुदान देने की दूर निर्धारित की गई। 1954-58 की अवधि में 259 लाख जागीरा का पुनर्ग्रहण किया गया। 1 नवम्बर 1959 से पांच हजार रुपये से अधिक आय वाली जागीरों तथा 1 अगस्त 1960 से एक हजार से अधिक आय वाली जागीरों को पुनर्ग्रहण का कार्य प्रारम्भ हुआ। निम्न श्रेणी की जागीरों के पुनर्ग्रहण का कार्य 1963 से प्रारम्भ हुआ। अब तक लगभग 2.9 लाख जागीरा का पुनर्ग्रहण किया जा चुका है जिसमें धार्मिक और गैरधार्मिक सभी जागीरा का समावेश है। नेहरू भवाङ 1954 के अनुसार जागीरदारों का खुदकाशन के लिए भूमि तथा जागीरों के पुनर्ग्रहण का सुझावजा उनके भू राजस्व व 7 गुने के बराबर रखा गया जिसे 15 वार्षिक किस्ता में भुगतान की व्यवस्था की गई।

पुनर्ग्रहण की प्रत्यक्ष लागत 1971 तक 513 करोड़ रु० आई है जिसमें सुझावजा, पुनर्वास अनुदान, व्याज व वार्षिक किस्ता का भुगतान भी शामिल है।

4 जमींदारी व विशेषदारी प्रथा का अन्त—राजस्थान से लगभग 5 हजार गाँव (मरतपुर, झलवर, अजमेर, जयपुर, भीनवाड़ा, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा व सीकर जिला) के राज्य व 20% क्षेत्र में यह प्रथा प्रचलित थी जिसमें शासककारी का शोषण होता था। अतः 1 नवम्बर से इस प्रथा का अन्त कर दिया गया जिसमें शासककारी व सरकार में सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया है।

1964 में राजस्थान भूमि सुधार एवं भूस्वामी सम्पत्ति पुनर्ग्रहण अधिनियम 1963 (The Rajasthan Land Reforms & Acquisition Land Owner's Estate Act, 1963) व द्वारा राजस्थान में विलीन होन वाले सभी राज्यों में शासककारी की भू-सम्पत्ति तन की व्यवस्था से मध्यस्थ वर्ग का समापन करने के अन्तिम कदम उठाये गये हैं।

5. शासककारी कानून 1955—राजस्थान में शासककारी भूमि सुधारों के लिए एक व्यापक अधिनियम 1955 में राजस्थान शासककारी अधिनियम (Rajasthan Tenancy Act, 1955) में पारित किया गया जिसमें शासककारी को भूमि के अधिकार देने, लगान का नियन्त्रण करने, रिमाणा को नू चारण की सुरक्षा प्रदान करने, जोतों के हस्तान्तरण करने आदि की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम से

राज्य के सभी भागों में काश्तकारी कानूनों में समानता लाकर काश्तकारी को भूमि अधिकार प्रदान किये हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत आसामियों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है—

(i) खातेदार—जो काश्तकार 195॥ में भूमि जोत रहे थे उन्हें उस भूमि के खातेदार अधिकार प्रदान कर दिये गये।

(ii) मालिक काश्तकार—रैयतवादी क्षेत्रों में काश्तकारों को भूमि का स्वामी बनाकर फसलों की बटाई को मान्यता दे दी।

(iii) खुद काश्त आसामियों को बटाई का अधिकार नहीं दिया गया।

(iv) गैर खातेदार आसामी—इनको भूमि पर कोई स्वत्व अधिकार नहीं दिये गये हैं। इनके भू धारण की सुरक्षा पूर्ण नियमों के अन्तर्गत की गई। इस अधिनियम में समय समय पर संशोधन किये गये हैं।

राज्य में काश्तकारों को 15 6 से 125 एकड़ तक पट्टेदारी की पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है। पुनर्ग्रहण न किये जाने वाले क्षेत्रों में मालिकाना हक देकर हस्तान्तरण की व्यवस्था की गई। लगान उपज के छठे भाग से अधिक नहीं हो सकता। 1 37 लाख काश्तकारों को लगभग 8 लाख एकड़ पर खातेदारी अधिकार दिये जा चुके हैं।

6 भू जोतों की सीमा निर्धारण—राजस्थान भूमि सुधारों की दृष्टि में अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक क्रान्तिकारी रहा है। भू जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में जांच करने के लिए 1953 में एक समिति बनाई जिसने 1958 में अपना प्रतिवेदन दिया जिसे प्रवर समिति को सौंपा गया और 1960 में राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम पारित कर दिया गया। तत्सम्बन्धी सीमा निर्धारण के नियम 1963 में प्रकाशित किये गए पर वास्तविक क्रियान्वयन 1966 में लागू किया गया है। इस प्रकार सीमा निर्धारण में काफी विलम्ब हुआ है।

राजस्थान में सीमा निर्धारण की अधिकतम सीमा 7 5 हेक्टर रखी गई है। सीमा से अतिरिक्त भूमि पर राज्य मुद्रावजा देकर अधिकार कर सकता है। मुद्रावजे की दर प्रथम 40 एकड़ पर भू राजस्व का 30 गुना, दूसरे 25 एकड़ पर 25 गुना तथा शेष पर भू-राजस्व का 20 गुना रखा गया है। राजस्थान में वर्तमान भूमि की अधिकतम सीमा 7 5 से 21 85 हेक्टर रखी गई है। कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों में यह सीमा 70 82 हेक्टर भी है।

7 कृषि पुनर्संरचना—कृषि पुनर्संरचना के अन्तर्गत राजस्थान में आवश्यक अधिनियम समय समय पर पारित किये गये हैं। चकबन्दी का कार्य भी प्रगति पर है। अब तक लगभग 50 लाख एकड़ की चकबन्दी की जा चुकी है। सहकारी कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया है पर कृषकों में सहकारी कृषि के प्रति उत्साह नहीं होने से विशेष प्रगति सम्भव नहीं हुई है। भूमिहीनों को सरकारी भूमि आवंटित करने में

काफी दिलचस्पी दिखाई गई है। भूदान आन्दोलन भी कुछ सीमा तक सफल कहा जा सकता है।

राजस्थान भूमि सुधारों को कार्यान्वित करने वाले प्रदेशों में अग्रणी है। 21-सूचीय आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा के पूर्व 8 22 लाख एकड़ भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये जा चुके हैं। 9 48 लाख भूमिहीन किसानों को 61 15 लाख एकड़ भूमि निशुल्क वितरित की गई जिसमें 25 लाख अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को दी गई है। इसके अतिरिक्त सिचाई परियोजना के अन्तर्गत आने वाली 5 लाख एकड़ सिंचित भूमि साधारण दरों पर किसानों पर भूमिहीनों में आवंटित की गई है।

नरोरा शिविर तथा राज्य स्तरीय रावतभाटा शिविर में लिए गये निर्णयों के अनुपालनाय मार्च 1975 से राजस्व एवं भूमि सुधार अभियान के फलस्वरूप 1 25 लाख भूमिहीन किसानों को 4 34 लाख एकड़ कृषि भूमि का निशुल्क आवंटन किया गया। अब तक लगभग छह लाख एकड़ भूमि पर ढाई लाख अतिरिक्तों को हटा कर वह भूमि भूमिहीनों में वितरित कर दी गई है। सीलिंग के अन्तर्गत 3 52 लाख एकड़ भूमि के अधिग्रहण पर प्रदेश जारी किये गये तदा लगभग दो लाख एकड़ भूमि पर कब्जा लेकर 50 हजार एकड़ भूमि को साठे छ हजार भूमिहीनों में वितरित कर दी गई है। सीलिंग कानून कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए राजस्थान राजस्व कानून (संशोधन) अध्यादेश 1975 जारी किये गये।

भूमि सम्बन्धी अभिलेख पूर्ण करने की दिशा में अब तक 2625 ग्रामों के तबरे 3 42 लाख नामान्तरकरण तथा 22 5 लाख पास बुकें वास्तुकारों को वितरित की गयी।

### राजस्थान में भूमि सुधारों की आलोचनात्मक समीक्षा

राजस्थान में भूमि सुधार के जो क्रान्तिकारी कदम उठाये गये हैं उनमें जागीरदारी व जमींदारी प्रथा का पूर्णतः उन्मूलन हो चुका है। कृषकों की शोषण में मुक्ति मिली है। भूधारण की सुरक्षा व लगान दसूनी में नियन्त्रण रहा है फिर भी कुछ झुटियां रहा हैं जिसके कारण आलोचना स्वाभाविक है।

1 अधिनियमों में पूर्णता रही है जिसका स्वार्थ तत्काल अनुचित लाभ उठाया है और कानून से बचने के सभी हथकण्डे अपनाये गये हैं।

2 आवश्यक विलम्ब रहा है। जहाँ भूमि सीमा निर्धारण अधिनियम 1953 में लागू होना चाहिए था वह 1966 में लागू किया गया। जागीरों का पुनर्ग्रहण भी 19 वर्षों तक चलता रहा।

3 प्रशासनिक अकुशलता व भ्रष्टाचार के कारण भू-सुधारों का जिस जोश से लागू किया गया उसका वांछित तान नही मिल सका।

4 भूमि-सुधार अधिनियम जटिल, त्रुटिपूर्ण व कठिन है अतः सर्वे साधारण की समझ से बाहर होने के कारण किसान लाभ नहीं उठा पाये हैं।

5 ढाँचा अवैज्ञानिक है—योजना आयोग की शोध कार्य समिति का मन है कि राजस्थान में भूमि कर तथा भू-राजस्व का ढाँचा अवैज्ञानिक है तथा भूमि कानून जटिल व भ्रमात्मक है।

6 मुआयजा चुकाने के कारण तथा खुदकास्त के लिए भूमि की छूट में जागीरदारों व जमींदारों ने बहुत से भूमि पर कब्जा रख लिया है। अतः अतिरिक्त भूमि से कारनकार वञ्चित रह रहे हैं।

7 भू-स्वामित्व सम्बन्धी रिकार्ड अपूर्ण व अप्रयाप्त हैं अतः भूमि सुधारों को लागू करने में कठिनाई आती है।

8 अन्न की वेदखली व अधिक लगान वसूली की जाती है।

फिर भी उपर्युक्त प्रगति का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि राजस्थान में जागीरदारी और जमींदारी प्रथा का पूरा उन्मूलन हो जाने में काश्तदार सीधे सरकार के सम्पर्क में आ गये हैं। 50 लाख एकड़ में खेजबन्दी का कार्य पूरा हो चुका है, लगान की अधिकतम सीमा उपज के छठे भाग के बराबर निर्धारण करके मनमानी लगान वसूली पर नियन्त्रण लगाया है। वगैरह प्रथा समाप्त हुई है। भूमि की अधिकतम वर्तमान व भावी सीमा 22 एकड़ 336 एकड़ निर्धारित कर अनिवारित भूमि को भूमिहीनों में बाँटने का वाय सम्राजवाद की ओर कदम है।

अतः भूमि सुधार कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए (i) भूमि सुधार अधिनियमों की जटिलता व त्रुटियों को दूर करना चाहिए। (ii) भूमि से वेदखली व भूमि के पुनः जमींदारों के पास हस्तान्तरण पर नियन्त्रण रखा जाना चाहिए। (iii) भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी अधिनियम की उपक्षा को रोकना जरूरी है। (iv) सहकारी ऋषि को प्रोत्साहन देना चाहिए। (v) काश्तकारी भूमि सम्बन्धी रिकार्ड को पूर्णता प्रदान कर काश्तकारों की सुरक्षा की जानी चाहिए। (vi) भूमिहीनों को भूमि अधिग्रहण में प्राथमिकता व पूर्णतः ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। (vii) प्रशासनिक अकुशलता, भ्रष्टाचार व अनावश्यक विलम्ब पर रोक लगाकर कुशलता लाने का भरसक प्रयत्न जरूरी है।

अन्त में यही कहना पर्याप्त है कि भूमि सुधार कार्यों को जिस जोश से लागू करना चाहिए या वह नहीं किया गया और वास्तविक लाभ नीति के मुकाबल बहुत कम रहा है। प्रा. दातवर्मा के शब्दों में 'भूमि सुधार के कदम रणोपजनक हैं किन्तु उचित रूप में लागू करने के अभाव में इनका परिणाम सन्तोषजनक नहीं हो पाया है।

### परीक्षोपयोगी-प्रश्न मय सकेत

- 1 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में भूमि सुधारों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये।



अथवा

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत भूमि-सुधार के क्या कदम उठाये गये हैं और वे कहा तक सफल रहे हैं ?

अथवा

भारत में भूमि-सुधार सम्बन्धी सरकारी प्रयासों का उल्लेख कीजिये तथा उनकी प्रमुख आलोचनाओं की समीक्षा कीजिये ।

(संकेत — देश में भूमि सुधार के लिए उठाये गये कदमों का विवरण दूसरे भाग में आलोचनाएँ देनी हैं तथा अन्त में मूल्यांकन देना है ।)

2 राजस्थान में भूमि सुधार की प्रगति से आप कहाँ तक सन्तुष्ट हैं ? कमियों को दूर करने के लिए सुझाव दीजिये ।

(संकेत — प्रथम भाग में राजस्थान में भूमि सुधारों का वर्णन देकर दूसरे भाग में आलोचना व तीसरे भाग में सुझाव देना है ।)

3 भूमि सीमा निर्धारण (Ceiling on Holdings) से आप क्या समझते हैं ? इसके पक्ष-विपक्ष (नाभ हानि) देकर उसकी प्रगति का मूल्यांकन कीजिये ।

(संकेत — भूमि सीमा निर्धारण का अर्थ उद्देश्य बनाकर पक्ष-विपक्ष में तर्क देने हैं तथा अन्त में उसकी प्रगति का मूल्यांकन करना है ।)

4 कृषि अर्थव्यवस्था में भूमि सुधार का क्या महत्व है ? भारत में भूमि सुधार कहाँ तक अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाये हैं ?

(संकेत — भूमि सुधारों का महत्व बनाकर दूसरे भाग में भारत में किये गये भूमि सुधारों का विवरण देना है । तीसरे भाग में उनके असन्तोषजनक क्रिया-न्ययन पर दोष बनाकर मूल्यांकन देना है ।)



## भारत में कृषि विपणन अथवा कृषि उपज का विक्रय (Agricultural Marketing in India)

भारतीय कृषि की समृद्धि केवल अधिकाधिक उत्पादन में ही निहित नहीं होकर उत्पादित उपज को उचित मूल्यों में बेचने में भी निहित है अतः कृषक को एक कुशल उत्पादक होने पर भी उचित मूल्य न मिलने पर न तो उसकी आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होगी और न उसे अधिक उत्पादन की प्रेरणा ही मिलेगी। इसी कारण प्रायः विद्वान यह मत व्यक्त करते हैं कि किसान के दोनो हाथ हल पर और दोनो आँखें बाजार पर होनी चाहियें। उसे बाजार की भाँव के अनुरूप ही उत्पादन करने में लाभ रहता है।

**कृषि विपणन के अर्थ**—कृषि का कार्य केवल कृषि-उपज उत्पन्न करना ही नहीं बल्कि उसका कार्य बाजार की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित रह कर मांग के अनुरूप उत्पादन करना तथा उस उपज को उचित समय पर उचित मूल्यों पर बेचकर अधिकतम लाभ अर्जन करना है अतः कृषक की उत्पादन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उस उत्पादित वस्तु को अन्तिम उपभोक्ता तक पहुँचाने अथवा कृषि उपज के क्रेताओं से निकट व्यवहार की प्रक्रिया ही कृषि विपणन की क्रिया है। इस प्रकार कृषि उपज के विपणन में निम्न क्रियाओं का समावेश होता है—(i) कृषि उपज का एकत्रीकरण (ii) सवारना (Procession) (iii) श्रेणीकरण व वर्गीकरण (Grading and Classification) (iv) गोदामों में सुरक्षित रखना (Storage) (v) वित्त-व्यवस्था करना (Financing) (vi) मंडी व विक्रय स्थान पर ले जाना, (vii) विपणन करना तथा (viii) जोखिम उठाना।

**आर्थिक विकास में कृषि उपज के विपणन की आवश्यकता एवं महत्व**

आज के विशिष्टीकरण के युग में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जा रही है। जब आवश्यकताएँ सीमित थीं और आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति प्रबल थी उस समय विपणन की समस्या नहीं थी। पर आज जब सर्वत्र अम विभाजन, बड़े पैमाने की उदात्ति, व्यावसायिक दृष्टिकोण और विशिष्टीकरण का बोलबोला है तो सभी क्षेत्रों में उत्पादन के विक्रय की समस्या जटिल हो गई है। कृषि क्षेत्र में विपणन की समस्या और भी जटिल है क्योंकि कृषि उपज में भिन्नता, कृषकों की अज्ञानता,

निर्माण द्वारा आर्थिक विकास मार्ग प्रशस्त किया है। रूस में तो सामूहिक कामों से कृषि पदार्थों की निर्यात वसूली से साधन एकत्रित किये गये।

6 कृषकों की समृद्धि व उच्च जीवन स्तर भी अन्ततः कृषि के विपणन योग्य आधिक्य पर निर्भर है। उन्हें अधिक आय प्राप्त होने पर ही वे अधिक उपभोग कर सकेंगे। बचत को विनियोग कर सकेंगे। वैज्ञानिक व आधुनिक कृषि का अनुसरण कर कृषि का तीव्र विकास कर सकेंगे।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि देश में कृषि उत्पादन की वृद्धि के साथ-साथ उसके विपणन योग्य आधिक्य से औद्योगिक कच्चा भात, श्रमिकों के लिए साक्षरता की पूर्ति, विदेशी मुद्रा अर्जन, आयातों का भुगतान, औद्योगिक वस्तुओं के लिए बाजार, पूंजी निर्माण का स्रोत तथा कृषि समृद्धि व उच्च जीवन-स्तर का आधार तैयार होता है।

### भारत में कृषि उपज के विपणन का संगठन

#### (Organisation of Agricultural Marketing in India)

भारत में अपनी कृषि उपज का विपणन संगठन बहुत ही कमजोर व ढीला है। ग्रामीण-स्तर पर कृषक अपनी उपज को या तो स्वयं सीधे उपभोक्ताओं को बेचते हैं अथवा ग्रामीण महाजन, व्यापारी या कमीशन एजेंट आड़तियों या दलाल के माध्यम से बेचते हैं। गांव में ही फसल बेचने के प्रमुख कारण हैं कि (i) किसान को अपनी उपज घर बैठे अपने ही गांव में बेचने में सुविधा रहती है। (ii) भावों में होने वाले उतार-चढ़ाव व बाजार की धोखा-धड़ी की जोखिम से मुक्ति मिल जाती है। (iii) दानायात व्यय नहीं करना पड़ता। परन्तु इस पद्धति में किसान को न तो अपनी उपज का उचित मूल्य मिल पाता है और न उसे बाजार में प्रचलित भावों का ज्ञान होता है। व्यापारी की धोखा धड़ी की जोखिम अधिक होती है। उसके विपरीत शहरो व नरुबो में (i) हाट तथा शन्दियों (ii) मण्डियों तथा (iii) कृषि सहकारी विपणन संस्थाओं के माध्यम से कृषि उपज को बेचा जाता है। आजकल खाद्यान्न में गेहूँ के व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर देने से सरकारी कर्मचारी अथवा खाद्यान्न निगम के कर्मचारी खाद्यान्न का क्रय करते हैं।

हाटें ऐसा बाजार हैं जहाँ सप्ताह में एक या दो बार पदार्थों का क्रय-विक्रय होता है जबकि शन्दियाँ लम्बी अवधि वाली हाटें होती हैं जो विशेष अवसरों पर लगती हैं। भारत में लगभग 25 हजार हाटों व शन्दियों में कृषि उपज का क्रय-विक्रय होता है जिनमें लगभग 4 लाख विपणन कृषि उपज बेची जाने का अनुमान है।

मण्डियों में कृषि उपज का बड़े पैमाने पर क्रय-विक्रय होता है जिसमें व्यापारी, उद्योगपति आदि दलालों आड़तियों के माध्यम से कृषि उपज खरीदते हैं और फिर थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को थोड़ी-थोड़ी मात्रा आवश्यकतानुसार बेचते रहते हैं। मण्डियाँ संगठित या असंगठित हो सकती हैं। संगठित मण्डियाँ वे हैं जो

नियन्त्रण में कार्य करती हैं और उनमें घोसायली अनियमितता व अनुचित व्यवहार का अभाव होता है जबकि असंगठित मण्डियों में नियन्त्रण में कार्य न करने, अनियमितताओं और घोसायली का बाहुल्य होता है। भारत में संगठित मण्डियाँ कम होने से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता।

### भारत में कृषि विपणन के दोष (Defects of Agricultural Marketing in India)

भारत में कृषि उपज के विपणन में अनेक दोष हैं उन सबका सामूहिक प्रभाव यह होता है कि किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। मध्यस्थों की एक लम्बी कतार अपना अपना लाभ बमावर अन्तिम उपभोक्ताओं तक कम मूल्य और बिनय मूल्य में काफी अन्तर डाल देते हैं। मुख्य दोष ये हैं—

1 किसान का स्वभाव भारतीय किसानों में अधिकांश अनिश्चित, छाँटवादी और अविश्वासी है अतः अपनी उपज को संगठित बाजारों में बेचने की प्रेरणा अपने ही गांव के महाजनों को बेच देते हैं जो उन्हें ठगने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उन्हें बाजार मूल्य का भाव ज्ञात न होने से ग्रामीण बाजार में मूल्य भी कम ही चुकाया जाता है।

2 निधनता व ऋणग्रस्तता—भारत में कृषि व्यवसाय के रूप में नहीं बरन् जीवनयापन के साधन के रूप में है अतः अधिकांश किसान गरीब हैं और गरीबी में ऋणग्रस्तता का बोलबोला है अतः ऋणों को शीघ्र चुवाने के लिये उपज को ऋणदाता महाजन ही हड़प जाते हैं। उह ऋणों को चुकाने के लिये शीघ्र बिक्री के लिए बाध्य होना पड़ता है अतः उचित मूल्य नहीं मिल पाता।

3 कम उपज व घटिया किस्म—कृषि क्षेत्र में जनसंख्या के अत्यधिक भार, छोटे छोटे बिल्वरे खेत और साधनों के अभाव में परम्परागत कृषि से प्रति किसान कृषि उपज बहुत कम ही नहीं होती वरन् वह किस्म में भी घटिया होती है। छोटी-छोटी उपज को बाजार में ले जाकर बेचना अतिथ्यपिप्ता पूर्ण है। यही नहीं कभी-कभी फसल काटने व सम्भालने में असावधानी से कृषि पदार्थों में घूल मिट्टी, ककड़ मिल जाते हैं नमी धा जाती है यन्ना तक कि रंग बदल जाता है। अतः कम उपज और घटिया किस्म दानों के कारण से अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता।

4 कृषि उपज के अधोनीकरण व प्रमाणीकरण का अभाव—कृषक अपनी थोड़ी थोड़ी उपज को मिलाते हैं अतः उपज का अधोनीकरण व प्रमाणीकरण के अभाव में बढ़िया किस्म का घटिया किस्म से अन्तर हो पाने में कम मूल्य मिलता है। यद्यपि अब हमारे देश में भी कृषक सहकारी विपणन समितियों व स्वयं के संगठनों द्वारा कृषि उपज के वर्गीकरण को महत्त्व देने लगे हैं फिर भी उपज की दृष्टि से यह नगण्य है।

5 गोदामों व भण्डार गृहों का अभाव—कृषिजन्य वस्तुओं को उत्पादन से बिक्री होने तक की लम्बी अवधि में संग्रह करने की समस्या भी जटिल है। कृषक निर्धन हैं उनके स्वयं के रहने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं तो उपज के संग्रह की व्यवस्था और भी कठिन है। जो कुछ संग्रह की व्यवस्था है भी तो वह अर्बन्धानिक व अपूर्ण है अतः कृषक को अपनी उपज की शीघ्र बिक्री के लिये बाध्य होना पड़ता है। यद्यपि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इस दिशा में काफी प्रयास हुआ है पर देश की आवश्यकता की तुलना में यह अपर्याप्त है।

6 शीघ्र बिक्री के लिये बाध्य होना—किसानों को प्रायः अपनी उपज को निर्वन्धता, श्रृण-श्रुतता व गोदामों में संग्रह व्यवस्था के अभाव के कारण शीघ्र बिक्री के लिए बाध्य होना पड़ता है परिणामस्वरूप दरबस कुसमय पर कृषि उपज की बिक्री के कारण न तो उसे बिक्री की उपयुक्त शर्तें ही मिल पाती हैं और न उपयुक्त मूल्य ही। शीघ्र बिक्री की बाध्यता में कृषक का शोषण होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में गेहूँ की 80% तिलहन की 75% तथा रुई की 40% उपज प्रतिशीघ्र ही ग्रामीण बाजारों में ही बेच दी जाती है। बिहार में भी 90% गेहूँ व जूट तथा 85% जूट की उपज फसल के तुरन्त बाद बेच दी जाती है। अब धीरे-धीरे इसमें सुधार हो रहा है।

7 कृषकों के विक्रय संगठनों का अभाव—जहाँ विश्व के विकसित देशों में कृषकों के सुदृढ़ विक्रय संगठन हैं वहाँ भारतीय किसानों में प्रशिक्षण, सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ापन, व्यापारी वर्ग की कूटनीति तथा कृषकों की स्वाभाविक उपेक्षा से शक्तिशाली विक्रय संगठनों का विकास नहीं हो पाया है। यद्यपि अब धीरे-धीरे सहकारी विपणन समितियों व कृषक सघों के विकास की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है।

8 मध्यस्थों का बाहुल्य—भारत में कृषक व कृषि उपज के अन्तिम उपभोक्ताओं के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, इन दोनों के बीच मध्यस्थों की एक लम्बी कतार है जैसे गांव का महाजन, नगर के थोक व्यापारियों के प्रतिनिधि दलाल, आड़तिये थोक व्यापारी, फटकर व्यापारी, उपभोक्ता भंडार, घूमते फिरते विक्रेता, उद्योगपति या निर्यातक आदि हैं। इससे उपभोक्ता और कृषक की उपज के दिये व लिये जाने वाले मूल्य में काफी अन्तर हो जाता है। सर्वशेषों से ज्ञात होता है कि चावल उत्पादक किसान की उपभोक्ता द्वारा प्रदत्त मूल्य का 52% तथा गेहूँ उत्पादक को केवल 61% मिलता है अर्थात् मध्यस्था का लाभ-सामंत क्रमशः 48% तथा 40% है। यही नहीं दलाल व आड़तिये केना और विक्रेता दोनों से कमीशन खा जाते हैं।

९ परिवहन साधनों का अभाव—भारत गाँवों का देश है और बहुत से गाँवों में अभी भी उपयुक्त व सस्ती परिवहन व्यवस्था का अभाव है। अच्छी सड़कों व यातायात साधनों के अभाव में वर्षा ऋतु में तो बहुत से गांव मण्डियों से कट जाते हैं। अतः कृषि उपज विपणन में शीघ्रता होना स्वाभाविक है।

10 बाजार मूल्यों व अन्य सूचनाओं की जानकारी का अभाव—देश में संचार साधनों के अर्द्ध-विवसित होने तथा कृषकों में अज्ञानता, अशिक्षा व सतर्कता की कमी के कारण किसानों को न बाजार भावों की जानकारी होती है और न अन्य उपयोगी सूचनाएँ ही मिल पाती हैं। परिणामस्वरूप किसान की अनभिज्ञता का व्यापारी वर्ग अनुचित लाभ उठाते हैं। यद्यपि अब तो रेडियो पर बाजार भाव प्रसारित किये जाते हैं तथा अखबारों में भी सूचना प्रकाशित होती है पर देश के अधिकांश अशिक्षित किसान उसका लाभ नहीं उठा पाते।

11. बाजारों में अवांछित परम्पराएँ व घोखाधड़ी—भारतीय कृषि विपणन में सबसे बड़ा दोष बाजारों में अवांछित परम्पराओं व घोखाधड़ी की क्रियाओं से किसान का शोषण करने की प्रवृत्ति है। देश में संगठित मण्डियों को इन दोषों से मुक्त करने के लिए कठोर नियंत्रण की नीति लागू की गई है फिर भी असंगठित मण्डियों व गाँवों में बित्री में ये दोष विद्यमान हैं। ये अवांछित क्रियाएँ हैं (i) कड़वा अथवा काटा काटना—अधिकांश व्यापारी कृषकों से उनकी उपज क्रय करते समय धूल, ककड़ व माल में मिलावट के नाम पर प्रति क्विंटल 2 से 5 किलो की कटौती कर देते हैं इसके कारण कृषकों को एच विटल के वस्तु केवल 98 से 95 किलो का ही मूल्य मिल पाता है। (ii) अनेक शुल्क व कटौतियाँ—कृषकों का माल बिक्र जाने के बाद उससे तुल्य ईलासी आइस फलेहारी, चुगो आदि शुल्क वसूल कर लिये जाते हैं। यही नहीं व्यापारी उपज व विषय मूल्य में से धर्मादा, प्याऊ, ब्यूतरखाना धर्मशाला, गौशाला पाठशाला, मन्दिर आदि की कटौतियाँ काट लेता है तथा मौना मिला तो अपने अधीनस्थ बर्मचारियों मुनीम व चौकीदार शुल्क भी वसूल करने में नहीं चूकता। (iii) नमूने में उपज का भाग थोड़ा-थोड़ा सब व्यापारी लेते हैं जिससे भी नमूने में दी गई उपज का मूल्य नहीं मिल पाता (iv) नाप-तौल में घोखाधड़ी से अधिक तोल लेना, रिमान की नासमझी से गलत मूल्य की गणना करना आदि से भी कृषकों को काफी हानि उठानी पड़ती है (v) गुप्त सौदा पद्धति में दलाल या आइतिये व्यापारी वर्ग के पक्ष में शर्तें तय करवाने में अधिक रुचि रखते हैं तथा उनसे गुप्त मोदे करके कृषकों का माल कीड़ियों में बिस्वावर स्वयं साम धर्जन की चेष्टा करते हैं। (vi) सभी कृषकों के द्वारा एक साथ बाजार में माल लाकर बेचने की प्रवृत्ति से फसल आने के बाद मण्डियाँ व कृषिजन्य पदार्थों की पूर्ति बढ़ जाती है अतः मूल्य ठीक-ठीक नहीं मिल पाते।

12. वित्तीय साधनों का अभाव—किसानों की निर्धनता व अल्पसंख्या के कारण तथा नयी फसल के लिये नये आदान क्रय के लिये किसानों को वित्त साधनों की तत्काल आवश्यकता होती है पर वित्त साधनों के अभाव में कृषि उपज को शीघ्र बेचने में उनको उचित मूल्य नहीं मिलता।

## कृषि विपणन सम्बन्धी सरकारी नीति व दोषों को दूर करने के लिए किये गये उपाय

(Govt Policy towards Agricultural Marketing & Measures Adopted for Removal of Defects)

कृषि उपज के विपणन में भी अन्य क्षेत्रों की भाँति सरकार की यह नीति रही है कि कृषक को अपनी उपज का उचित मूल्य मिले ताकि उसे अधिक उत्पादन की प्रेरणा मिले और उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्यों पर वस्तु उपलब्ध हो जाय और जन असन्तोष उत्पन्न न हो। वैसे तो प्रथम विश्वयुद्ध के बाद से ब्रिटिश सरकार ने परोक्ष व प्रत्यक्ष तरीकों से व्यापारिक फसलों—चाय, कपास, जूट, तम्बाकू, तिलहन आदि व खाद्यान्न वस्तुओं के विपणन में सुधार के प्रयास किये पर स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पञ्चवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सरकार ने प्रभावी कदम उठाये हैं। द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में सरकार की नीति का संकेत इस कथन में भलकता है कि “किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा उपभोक्ताओं को भी कृषि पदार्थ उचित मूल्यों पर दिलाने के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कृषि पदार्थों के त्रय-विक्रय सम्बन्धी दोष दूर करने होंगे कृषि उत्पादन क्षेत्रों के अतिरिक्त माल उपभोक्ता क्षेत्रों में भेजने की व्यवस्था करनी होगी और अधिकतम सम्भव सीमा तक सहकारी त्रय-विक्रय का प्रवर्धन करना होगा।” इस नीति की कार्यान्विति व प्रगति का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है—

### 1 नियन्त्रित मण्डियों का विस्तार (Expansion of Regulated Markets)

—कृषि उपज विपणन में अवांछित परम्पराओं व घोखाघड़ी की प्रवृत्तियों को रोकने के लिये नियन्त्रित मण्डियों की स्थापना व विस्तार को महत्व दिया गया। अब सम्पूर्ण देश में नियन्त्रित बाजार व्यवस्था लागू हो चुकी है। समस्त भारत में लगभग 3300 बड़ी मण्डियाँ हैं उनमें से प्रथम योजना तक केवल 255 नियन्त्रित मण्डियाँ थी। दूसरी योजना के अन्त तक नियन्त्रित मण्डियों की संख्या 725, तृतीय योजना के अन्त तक 1600, (1968-69) तक 1880 तथा जून 1975 तक देश की सभी 3300 बड़ी मण्डियाँ नियन्त्रित मण्डियों की श्रेणी में आ जाने का अनुमान है।

नियन्त्रित मण्डियों में कृषक तथा व्यापारियों की एक प्रतिनिधि “मण्डी समिति” का कृषि उपज के त्रय-विक्रय पर प्रभावी नियन्त्रण रहता है, वह मूल्य सम्बन्धी सूचना देती है। नाप-तोल पर निगरानी रखी जाती है, केवल अधिकृत कटौतियाँ व शुल्क ही वसूल किये जाते हैं। दलाल व व्यापारी लाइसेंस शुदा होते हैं और मण्डी के नियमों का उल्लंघन करने पर दण्ड व्यवस्था होती है।

### 2 कृषि उपज श्रेणीकरण व चिन्हांकन (Grading & Marking)—

कृषि उपज का श्रेणीकरण व चिन्हांकन भारत सरकार के कृषि उपज (श्रेणीकरण व चिन्हांकन) अधिनियम 1937 (Agricultural Product Grading and Marking Act, 1937) के अन्तर्गत किया जाता है। निर्यात की जाने वाली कृषि

उपज का श्रेणीकरण अनिवार्य है जैसे तम्बाकू इलायची उज, पशुधो के बाल आदि सरकार द्वारा अब तक लगभग 45 वस्तुधो की 200 किस्मो के वर्ग निर्धारित किये जा चुके है जिनमे कई प्रकार के फल, चावल गेहू, गन्ना, रुई, आलू, धी, मक्खन, तेल आदि प्रमुख हैं। इन प्रमाणित वस्तुधो पर एगमार्क (Agmark) की सील लगा दी जाती है। चौथी योजना के अन्त तक सभी महत्वपूर्ण पदार्थों के एगमार्क प्रमाणीकरण का लक्ष्य रखा गया था। लगभग 600 ग्रैडिंग इकाइया स्थापित की जा चुकी है।

3. प्रयोग एषा अनुसंधान शालाओ की स्थापना—श्रेणीकरण व प्रमाणीकरण के लिए तृतीय योजना काल मे ही एक केन्द्रीय प्रयोगशाला नागपुर मे स्थापित की गई तथा दूसरी योजना मे स्थापित चार प्रयोगशालाओ—कोचीन बम्बई, राजकोट व कानपुर की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओ मे परिवर्तित किया गया और चार नई प्रयोगशालाए गुदूर मद्रास बलकत्ता व अमृतसर मे स्थापित हुई। 1968 मे दो और क्षेत्रीय प्रयोगशालाए स्थापित की गई। अब देश मे लगभग एक हजार श्रेणीकरण इकाइया कार्यरत तथा 17 प्रयोगशालाए है।

4. प्रमाणित माप तोल की उचित व्यवस्था—स्वतन्त्रता के पूर्व तथा बाद मे अप्रैल 1958 से पूर्व देश मे विभिन्न प्रकार के बाट तोल प्रचलित रहे जिसमे 20 सेर से लेकर 100 मेर तक मन होता था और उसमे बहुत अधिक् धोखाधड़ी होती थी। इस दोष के निराकरण के लिये 1 अप्रैल 1958 से नाप तोल की समूचे देश मे एक ही मीट्रिक ताल (विलोग्राम, किलो) प्रणाली चालू कर दी गई। मूल्य की गणना को भी सरल बनाने के लिये दशमलव मुद्रा प्रणाली (Decimal Coinage System) चालू किया गया। इसके बावजूद भी लोग ठगने मे नही चूकते।

5. बाजार सम्बन्धी शोध एवं सर्वेक्षण—देश मे कृषि उपज विपणन सम्बन्धी समस्याओ का अध्ययन करने तथा महत्वपूर्ण कृषि पदार्थों के बाजारो का सर्वेक्षण व अन्वेषण करने का काम भारत सरकार का विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (Directorate of Marketing & Inspection) करता है। 1937 के बाद इस निदेशालय ने 80 वस्तुधो से सम्बन्धित 130 प्रतिवेदन प्रकाशित किये है। वह 'कृषि विपणन' नामक एक त्रैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित करता है।

1937 मे गवर्नरमेन्ट केन्द्र सरकार ने एक कृषि विपणन सलाहकार तथा कई विपणन अधिकारी व निरीक्षक नियुक्त किये जो प्रायः तब कृषि मन्त्रालय के अन्तर्गत कार्यरत है और उनका विस्तार हुआ है। राज्यों मे भी केन्द्र की भांति कृषि विपणन विभाग खोले गये हैं। इन सबका काम बाजार सम्बन्धी सूचना एकत्रित करना, जाच पड़ताल करना अथवा कृषि पदार्थों के श्रेणीकरण की व्यवस्था करना है।

6. परिवहन व यातायात का विकास—योजनाबद्ध विकास के पिछले 28 वर्षों मे यातायात साधनो का तीव्र गति से विकास हुआ है। बोर्ड भी गांव अब पक्की सड़क से 8-10 मील से दूर नही है। रेलो की लम्बाई 1950-51 मे 54 हजार



किलोमीटर थी जो अब बढ़कर 61.5 हजार किलोमीटर तथा रेलों की माल ढोने की क्षमता 8.3 करोड़ टन से बढ़कर 26.5 करोड़ टन हो गई है। सतहदार सड़कों की लम्बाई 1.56 लाख किलोमीटर से बढ़कर 8 लाख किलोमीटर हो गई है। डाक, तार टेलीफोन आदि में तीव्र विकास हुआ है।

7 मालगोदामों की व्यवस्था—कृषकों की बिक्री योग्य उपज को मालगोदामों में सुरक्षित रखने तथा उन्हें उचित समय में बाजार में बेचने के लिए देश की सरकार ने शुरू से ही रुचि ली है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण की सिफारिश पर 1954 में ही केन्द्र सरकार ने एक राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं गोदाम मण्डल की स्थापना की। 1957 में एक केन्द्रीय गोदाम निगम बनाया गया तथा राज्यों में भी राज्य गोदाम निगमों की स्थापना हुई। इन निगमों ने क्रमशः केन्द्रीय स्तर पर तथा राज्य स्तर पर गोदाम निर्मित करवाये। मार्च 1971 तक देश की सभी सरकारी संस्थाओं के माल गोदामों की सम्ग्रह क्षमता 109 लाख टन थी। चतुर्थ योजना काल में गोदामों के विकास पर लगभग 18 करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था थी तथा उससे 10 लाख प्रतिरिक्त क्षमता की व्यवस्था का प्रावधान था। 20 लाख टन क्षमता के गोदाम सहकारी क्षेत्र में बढ़ाने का लक्ष्य था। अब भण्डारण क्षमता लगभग 180 लाख टन है।

8 बाजार एवं मूल्य सम्बन्धी सूचनाओं का प्रसारण—कृषि उपज की प्रमुख वस्तुओं के मूल्यों का प्रसारण रेडियो पर किया जाता है। दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रमुख मण्डियों में प्रचलित भावों को छापा जाता है। साप्ताहिक समीक्षा दी जाती है। 'Agricultural Situation in India' नामक पत्रिका भी प्रकाशित होती है। यही नहीं सिनेमा स्लाइडो, वृत्त चित्रों आदि से भी सहारा लिया जाता है।

9 कृषि मूल्य आयोग की स्थापना—भारत में कृषकों को भावों में होने वाले उतार-चढ़ावों से सुरक्षा व प्रेरणा प्रदान करने, उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्यों पर कृषि पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्यों से कृषि मूल्य आयोग (Agriculture Price Commission) द्वारा न्यूनतम गारन्टी मूल्यों की घोषणा की जाती है। वर्ष 1975-76 में कृषिजन्य पदार्थों के मूल्यों की गिरावट को रोकने के लिए सरकारी खरीद में मूल्य सहायता नीति (Price Support Policy) का सहारा लिया जा रहा है।

10 कृषि विपणन प्रशिक्षण—कृषि विपणन में लगे अधिकारियों व अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद उचित व्यवस्था पर पूरा-पूरा ध्यान दिया गया है। प्रशिक्षण के तीन पाठ्यक्रम चालू हैं जिनमें पहला नागपुर में, राजकीय विपणन उच्च अधिकारियों के प्रशिक्षण का एक वर्षीय कोर्स है। दूसरा पाच माह के लिए सागली तथा हैदराबाद में ऊप-विक्रय सचिवों व अजीशकों के प्रशिक्षण के प्रशिक्षण का कोर्स होता है तथा तीसरा वर्गीकरण निरीक्षकों के लिए

प्रैमासिक प्रशिक्षण कोम है। सहकारी विपणन समितियों के अधिकारियों के प्रशिक्षण की अनग व्यवस्था है। अब तक लगभग 6 हजार कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

11 सहकारी कृषि विपणन व्यवस्था को बड़ाया—कृषि विपणन के अधिकांश दोषों का निराकरण करने में सहकारी कृषि विपणन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कृषकों को मगठिन होकर साल व विपणन की एक एकीकृत योजना को मूर्त रूप देने का मौका मिलता है। 30 जून 1975 तक देश में सहकारी कृषि विपणन समितियों की संख्या 3300 थी और जहाँ 1960-61 में 175 करोड़ रुपये मूल्य की कृषि वस्तुओं का विपणन किया था वहीं 1970-71 में यह राशि बढ़कर 650 करोड़ रुपये हो गई। 1950-51 में तो केवल 47 करोड़ रुपये मूल्य की बिक्री की थी। 1974-75 में सहकारी विपणन समितियों द्वारा 1215 करोड़ रुपये मूल्य की कृषि उपज विपणन की गई। 1978-79 तक यह 1900 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

12 विविध—कृषि उपज विपणन के दोषों के निराकरण के लिए शिक्षा का तेजी में प्रसार किया है। अतः जहाँ 1951 में साक्षरता का प्रतिशत 16.6 था वह 1961 में बढ़कर 24.3 तथा 1971 में 29.35 हो गया है। अब यह 32% होने का अनुमान है। सरकार ने गृह के व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर लिया है। कृषकों को वित्तीय सहायता दी जाती है। बैंकों के द्वारा भी कृषकों को बड़ी मात्रा में ऋण दिया जाने लगा है।

### कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार के सुझाव

यद्यपि भारत में कृषि विपणन के क्षेत्र में काफी सुधार लाने का प्रयास किया है पर इन प्रयासों की उपलब्धियाँ देश की कुल भाग को देखते हुए नगण्य हैं। यद्यपि अब देश में नियन्त्रित मण्डियाँ हैं फिर भी जब किसान अपनी उपज को गांव के महाजनों के हाथ सस्ते मूल्यों में बेच देता है तो यह दोष किमका? कृषकों की अज्ञानता व उनकी छोटी-छोटी उपजा की शीघ्र भेजन की बाधिता। अतः शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए। कृषकों के माल को सुरक्षित गोदामों में रखकर सहकारी विपणन व्यवस्था के आधार पर उनका वित्तीय साधना व कृषि की आवश्यक पदार्थों की पूर्ति करने में "कृषि वित्त व विपणन" की एक एकीकृत योजना लागू की जाना श्रेष्ठ है। सस्त यातायात साधनों व शीघ्र नाशवान वस्तुओं के लिए शीत भण्डारण (Cold Storage) की व्यवस्था की जानी चाहिये। गोदामों की क्षमता बढ़ानी चाहिये और यथासम्भव उन्द् प्राधुनिकनम बनाया जाना चाहिये। बाजार सम्बन्धी सर्वेक्षणों व अन्वेषण कार्यों को प्रोत्साहन देना चाहिये।

निष्कर्ष—भारत में कृषि उपज के विपणन की समस्या समूची ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है। अतः कृषकों की समृद्धि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि आवश्यक है बल्कि उन प्रतिकूलताओं के निवारण की आवश्यकता है जिनके अन्तर्गत कृषकों को अपनी उपज बहुत ही कम

कीमतों पर बेचने को बाध्य होना पड़ता है। शक्तिशाली व चालाक व्यापारियों द्वारा कृषकों का शोषण समाप्त करने की आवश्यकता है। इसके लिए कृषकों में शिक्षा का प्रसार, सहकारी कृषि विपणन को बढ़ावा, मण्डियों पर नियन्त्रण, बाजार भावों की जानकारी तथा कृषि उपज के सरकारी व्यापार को प्रेरित किया जा सकता है। गेहूँ के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण एक असफल प्रयत्न होते हुए भी कटु अनुभव रहा।

### परीक्षोपयोगी प्रश्न मय संकेत

1. भारत में कृषि विपणन के क्या-क्या दोष हैं और इन दोषों के निराकरण के लिए क्या-क्या प्रयास किये गये हैं ?

अथवा

“भारतीय कृषक की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि उसे प्रतिकूल स्थान पर प्रतिकूल समय में तथा प्रतिकूल शर्तों के अन्तर्गत अपनी उपज बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इस कथन की विवेचना कीजिये।

(संकेत :—दोनों प्रश्नों के उत्तर में थोड़ी बहुत भाषा में हेर-फेर कर कृषि विपणन के दोषों को बताकर उसके निराकरण के लिए किये गये प्रयत्नों की समीक्षा करनी है।)

2. भारत में कृषि उपज के विपणन की समस्याओं पर प्रकाश डालिये तथा उन्हें दूर करने के उपाय बताइये।

(संकेत :—कृषि विपणन के दोषों को बताकर उनके दूर करने के सरकारी प्रयत्नों का उल्लेख करते हुए साथ-साथ सुझाव दे देना है।)

3. भारत सरकार ने कृषकों को उनकी उपज का मूल्य दिलाने के लिए क्या-क्या प्रयत्न किये हैं ?

(संकेत :—इसके अन्तर्गत कृषि विपणन सम्बन्धी सरकारी नीति व कृषि विपणन के दोषों के निराकरण के उपचारों का उल्लेख करना है।)

## सामुदायिक विकास (Community Development)

भारत के 56 लाख गावों में बसी 82% निधन व दुखी ग्रामीण जनसंख्या को सर्वांगीण विकास तथा उन्हें विविधतापूर्ण एवं समृद्ध जीवन उपलब्ध करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" के प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक सिद्धान्त को मूर्त रूप प्रदान करने का एक संगठित एवं आयोजित प्रयत्न है। यह सामूहिक कल्याण को प्राप्त करने का ऐसा सामूहिक प्रयास है जिसमें ग्राम-वासियों के स्वयं के प्रयत्नों व नेतृत्व को आधार माना गया है और उनमें पारस्परिक सहयोग, आत्म-निर्भरता व परिश्रम की प्रेरणा दी जाती है ताकि उनके व्यक्तिगत एवं सामूहिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सके। वैसे तो ग्रामीण जनता के पुनर्स्थान व विकास के लिए रवीन्द्रनाथ टैगोर ने आन्ति निकेतन में, महात्मा गांधी ने मेवाड़ में स्पेन्सर हेच ने मार्तण्डम तथा बापन ने पंजाब के गुडगाव में कुछ प्रयास किये थे पर सरकारी स्तर पर ग्रामीण विकास की दिशा में सुनियोजित कार्यक्रम स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद राजकोषीय आयोग (Fiscal Commission) 1949 की सिफारिश पर "अधिक शक्ति उपजाओ आन्दोलन" के रूप में चालू हुआ। अधिक शक्ति उपजाओ जाच समिति ने जून 1952 में अपने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की कि (i) ग्राम विकास योजनाओं के अनुकूल ग्राम, जिला तथा राज्य स्तर पर सरकारी व गैर-सरकारी सङ्गठन बनाये जायें, (ii) राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम लागू किया जाय तथा (iii) इस कार्यक्रम के लिए केन्द्र द्वारा आर्थिक सहायता दी जाय।

भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारम्भ—अधिक शक्ति उपजाओ जाच समिति की सिफारिशों को योजना आयोग तथा सरकार ने स्वीकार कर 2 अक्टूबर 1952 को महात्मा गांधी की जन्म तिथि के अवसर पर सम्पूर्ण देश के 55 केन्द्रों के 500 वर्ग मील क्षेत्र की लगभग 2 लाख जनसंख्या पर यह ग्राम-विकास का ऐतिहासिक कार्यक्रम लागू किया गया यद्यपि प्रारम्भ में 1960 तक देश की सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या को इस कार्यक्रम की परिधि में लाने का लक्ष्य था पर यह लक्ष्य 1963 में ही पूरा हो सका।

सामुदायिक विकास का अर्थ—सामुदायिक विकास का अभिप्राय उस स्थापक एवं सुनियोजित कार्यक्रम से है जिसने द्वारा ग्रामीण जनता का सर्वांगीण एवं

सर्वतोन्मुखी विकास किया जाता है ताकि उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक उत्थान हो और उन्हें अपने ही प्रयत्नों व प्रेरणाओं से आर्थिक दृष्टि से समृद्ध, विविधतापूर्ण एवं सुखी जीवनयापन का अवसर उपलब्ध हो सके। यह सामूहिक कल्याण का एक ऐसा गहन विकास कार्यक्रम है जिसके कार्यान्वयन में पिछड़ी व निर्धन ग्रामीण जनता की आर्थिक समृद्धि, सामाजिक सबलता व राजनैतिक सुदृढता का स्वप्न सजोया गया है। इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास के समस्त पहलुओं का समावेश होता है और इसी कारण पण्डित नेहरू ने ठीक ही कहा है, "सामुदायिक विकास परियोजनाएँ सम्पूर्ण भारत में वे खमकीली, जीवन से परिपूर्ण एवं प्रावैगिक चिन्तारियाँ हैं जिनसे शक्ति, आशा एवं उत्साह की किरणें प्रस्फुटित होती हैं। ये विकास के ऐसे ज्योति स्तम्भ हैं जो घने अन्धकार में तम तक प्रकाश फैलाते रहेंगे जब तक कि समस्त भारतीय अर्थव्यवस्था आलोकित न हो उठे।"

सामुदायिक विकास की विशेषताएँ—(i) यह सरकारी तथा स्थानीय जनता दोनों का संयुक्त प्रयास है। (ii) स्वेच्छा के आधार पर स्थानीय साहस, प्रयत्नों व प्रेरणाओं को महत्व दिया जाता है। (iii) यह ग्रामीण विकास का एक ऐसा व्यापक व संनियोजित कार्यक्रम है जिसमें ग्रामीण विकास का एवं ऐसा व्यापक व सुनिश्चित कार्यक्रम है जिसमें ग्रामीण विकास के समस्त पहलुओं का समन्वित समावेश होता है। (iv) कार्यक्रम के संगठन व संचालन में जनतान्त्रिक आधार पर ग्रामवासियों का सक्रिय सहयोग लिया जाता है। (v) इस कार्यक्रम में तीन महत्वपूर्ण सत्यायें हैं—पचायतें सहकारी समितियाँ तथा पाठशालाएँ जिसमें पचायतें ग्राम स्तर पर विकास कार्यों का संचालन व देख रेख करती हैं, सहकारी संस्थाएँ आर्थिक पहलुओं के विकास की आधारशिला हैं जबकि गाँव का स्कूल शिक्षा व सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र होता है। (vi) यह ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास से सम्बन्धित है। (vii) 1958 तक यह कार्यक्रम तीन चरणों में पूरा किया जाता था जब केवल दो ही चरणों में पूरा किया जाता है। (viii) अब सम्पूर्ण भारतीय ग्रामीण जनता इस कार्यक्रम की परिधि में आ चुकी है।

### सामुदायिक विकास के उद्देश्य (Objectives)

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आधारभूत उद्देश्य समस्त ग्रामीण जनता का सर्वांगीण एवं सर्वतोन्मुखी विकास करना है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के भूतपूर्व प्रमुख सहाकार डा. डगलस एन्सिमन्जर के मतानुसार सामुदायिक विकास के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं<sup>1</sup>—

1 प्रगतिशील व व्यापक दृष्टिकोण उत्पन्न करना—इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की भाग्यवादी, रुढ़िवादी एवं अशिक्षित जनसंख्या में प्रगतिशील एवं

ध्यापक दृष्टिकोण उत्पन्न करना है ताकि वे राष्ट्र के सबल, सर्वगुण एवं सजग प्रहरी बन सकें।

2 प्रभावशाली नेतृत्व व स्थानीय साहस को प्रोत्साहन—सामुदायिक विकास का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य स्थानीय साहस तथा नेतृत्व को उनको अपने ही विकास कार्यक्रमों के संचालन के लिये प्रेरित करना है ताकि वे अन्ततः राष्ट्र निर्माण कार्यों में सजग एवं प्रभावी नेतृत्व प्रदान करने में समर्थ हो सकें। इसके लिए युवक सघ, महिला मण्डल, कृषक संगठन, मनोरजन क्लब, सहकारी समितियाँ आदि का विस्तार व विकास करना है।

3 जन सहयोग—किसी भी देश के विकास कार्यक्रमों की सफलता जन-सहयोग पर निर्भर करती है। अतः ग्रामीण जनता में योजनाओं के प्रति उत्साह व विकास के प्रति आत्म विश्वास जागृत कर उनमें सक्रिय सहयोग का वातावरण उत्पन्न करना है।

4 उत्पादन व आय में वृद्धि—ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का यथा-सम्भव विकास कर उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि करना ताकि ग्रामीण जनता की आय, रोजगार व उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो। कृषि में उत्पादन की नवीनतम वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों, उन्नत बीजों व कीटाणुनाशक दवाओं का उपयोग, सिंचाई साधनों का विकास, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास आदि इसके उद्देश्य हैं।

5 प्राथमिक वस्तुओं में आत्म-निर्भरता—सामुदायिक विकास का पाँचवा महत्वपूर्ण उद्देश्य समस्त गावों को प्राथमिक वस्तुओं—भोजन, कपड़ा, आवास की दृष्टि से आत्म-निर्भर बनाना है।

6 युवकों को प्रशिक्षण तथा रोजगार में वृद्धि—आर्थिक विकास कार्यों में ग्रामीण युवकों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना ताकि वे भावी विकास में सक्रिय योगदान दे सकें। यही नहीं लोगो को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध करने के श्रम-प्रधान कार्यों का संचालन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है।

7 स्वास्थ्य सुधार मनोरजन साधनों की वृद्धि तथा उच्च जीवन स्तर प्रदान करना—ग्रामीण जनता को अधिकधिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराना तथा स्वास्थ्य सुधार करना। ग्रामीण क्षेत्र में मनोरजन सुविधाएँ बढ़ाना तथा ग्रामीणों को विकास व उत्पादन वृद्धि से उच्च जीवन-स्तर के अवसर प्रदान करना है।

इस प्रकार सामुदायिक विकास एक बहुउद्देशीय कार्यक्रम है जो ग्रामीणों के सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक उत्थान में उनके सर्वांगीण विकास के लक्ष्य से प्रेरित है।

**सामुदायिक विकास के अन्तर्गत कार्यक्रम**

सामुदायिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण जीवन के

सभी पहलुओं का समावेश करते हुए एक अष्ट-सूत्रीय कार्यक्रम अपनाया गया है जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

1 कृषि सम्बन्धी कार्य-क्रम—भारत की कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था में कृषि विकास कार्यक्रम को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसके अन्तर्गत कृषि क्षेत्र का विस्तार, उत्पादन की नई विधियों व तकनीक का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों, उन्नत बीजों तथा सुधरे उपकरणों का प्रयोग, कृषि विपणन एवं वित्त व्यवस्था में सुधार, भूमि कटाव की रोकथाम, सहकारिता का विकास, पशु-पालन में वैज्ञानिक प्रयोग आदि का समावेश है।

2 सिंचाई सुविधाओं के विकास व विस्तार के लिए लघु सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता देना तथा ऐसी व्यवस्था करना कि कृषि योग्य भूमि के लगभग 50% क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध हो जायें।

3 शिक्षा प्रसार—ग्रामीण जनता के दृष्टिकोण में प्रगतिशील व आत्म-निर्भरता की प्रवृत्ति शिक्षा के व्यापक प्रसार में निहित है अतः सामान्य व तकनीकी शिक्षा सुविधाओं की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था करना, वयस्कों के लिए प्रौढ शिक्षा आदि प्रमुख कार्य हैं।

4 ग्रामीण एवं लघु उद्योगों का विकास करना ताकि गावों में व्याप्त बेरोजगारी तथा अर्द्ध-बेरोजगारी का निराकरण कर उपयोगी रोजगार उपलब्ध किया जा सके। इसके लिए कारीगरों व शिल्पकारों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

5 यातायात एवं संचार साधनों का विकास करने के लिए यथासम्भव ग्रामीणों के ऐच्छिक श्रम, सार्वजनिक सस्थाओं तथा सरकारी विभागों को प्रोत्साहित करना ताकि कोई भी गाव मुख्य सड़क से आधे मील से अधिक दूर न हो।

6 स्वास्थ्य एवं ग्राम सफाई कार्य-क्रम—इसके अन्तर्गत गावों में जन-चिकित्सा केन्द्र, पशु-चिकित्सालय तथा चल-चिकित्सालयों की व्यवस्था, छुप्राछून की बीमारियों—हैजा, मलेरिया, तपेदिक, टी बी आदि पर नियन्त्रण तथा गावों में सफाई के कार्यक्रमों का समावेश है।

7 आवास, प्रशिक्षण व सामाजिक कल्याण कार्य-क्रम—इसके अन्तर्गत ग्रामीण जनता की सुविधाजनक आवास व्यवस्था के कार्यक्रम लागू करना ग्रामीण युवकों को कार्य, खेलकूद व योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना तथा सामाजिक कल्याण कार्यों को संचालित करना है।

8 महिला विकास कार्य-क्रम—ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की दयनीय दशा को सुधारने के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों को विशेष महत्व दिया गया है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की सफलता के आदर्श आवश्यक तत्व

सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिए चार आदर्श तत्वों का

हाना आवश्यक समझा गया है। (1) प्रजातन्त्र के आधारभूत सिद्धांतों पर ग्राम पंचायतों का विकास करना जो बिना किसी भेदभाव के स्वयं स्फूर्त एवं त्रियाशील संस्थाओं के रूप में सामुदायिक विकास कार्य क्रमों को मूल रूप देने में अधिकारियों को योग दे। (2) ग्रामीण जनता के आर्थिक विकास के सम्पूर्ण पहलुओं के कार्य क्रमों का त्रियन्वयन सहकारी समितियों की लोकप्रियता में निहित है। (3) ग्राम विद्यालयों व ग्राम्यापकोटी महत्वपूर्ण भूमिका है जो सम्पूर्ण गांव में सांस्कृतिक केन्द्र व शिक्षा निवारण के प्रमुख स्तंभ हैं। (4) ग्रामीण जनता का सहयोग योजनाओं की सफलता का आधार स्तम्भ है अतः उनके सक्रिय सहयोग का उचित वातावरण बनाना सफलता की कुंजी है।

### सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संगठन व प्रबन्ध

सामुदायिक विकास कार्य कम लागू होने के बाद आज तक प्रयोगात्मक स्तर से गुजर रही है अतः समयानुबन्ध व परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तनों की प्रवृत्ति रही है। संगठन का वर्तमान स्वरूप निम्नांकित है—

1. केन्द्र स्तर पर देश का सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मन्त्रालय है जो सामुदायिक विकास संबंधी सभी नीतियों का निर्धारण व संचालन करता है। यह मन्त्रालय नीति निर्धारण व संचालन में योजना आयोग, साधारण व कृषि मन्त्रालय आदि से भी परामर्श करता है। सामुदायिक विकास कार्य क्रमों की प्रगति का मूल्यांकन योजना आयोग के कार्य क्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किया जाता है।

2. राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य में राज्य विकास परिषदों की स्थापना की गई है। इस परिषद् का अध्यक्ष राज्य का मुख्य मंत्री सदस्य विकास मंत्री व सचिव राज्य का विकास आयुक्त होता है। राज्य सरकार इस परिषद् के निर्देशानुसार सामुदायिक विकास कार्यों का संचालन करता है। विकास आयुक्त (Development Commissioner) सामुदायिक विकास के मुख्य अधिकारी के रूप में जिलाधीनो (विकास अधिकारियों) के कार्यों की देखभाल करता है।

3. जिला स्तर पर जिला परिषदें होती हैं। जिलाधीन उत्तका पदेन मुख्य अधिकारी होता है। खण्ड स्तर पर पंचायत समितियाँ होती हैं जिनमें मुख्य अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी (Block Development Officers) होते हैं। प्रायः एक विधान परिषद् के अन्तर्गत तीन खण्ड होते हैं और औसतन प्रत्येक खण्ड में 100 गांव होते हैं।

4. ग्रामीण स्तर पर ग्राम विकास पंचायतें होती हैं। अगर गांव छोटे-छोटे होते हैं तो दो-तीन छोटे गांवों को बड़ गांव की पंचायत में सम्मिलित कर लिया जाता है। इस स्तर पर मुख्य वायकता ग्राम सेवक होता है।

यह यह उल्लेखनीय है कि जिन राज्यों में प्रजातांत्रिक विरेद्रीकरण नहीं हुआ है उनमें खण्ड विकास समितियाँ (Block Development Committees)



होती है जिनमें मसद व विधान सभा के सदस्य कुछ प्रगतिशील किमान, सामाजिक कार्यकर्ता, युवक-युवनियाँ, सहकारिता व पचायत राज के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के आयोजन व क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

सामुदायिक विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने में सलग्न प्रमुख कार्यकर्ता (1) ग्राम सेवक, (2) कृषि विस्तार अधिकारी तथा (3) खण्ड विकास अधिकारी हैं। ग्राम सेवक सम्बन्धित विकास पचायत की देख-रेख करता है, प्रगति एवं कार्यक्रमों का सम्पूर्ण लेखा-जोखा रखता है और गाँवों की समस्याओं को हल करने में मदद करता है। कृषि विस्तार अधिकारी खण्ड स्तर पर कृषि सम्बन्धी समस्याओं का विशेषज्ञ होता है तथा उनके हल करने में मदद करता है। खण्ड-विकास अधिकारी खण्ड स्तर पर पचायत समितियों के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है तथा खण्ड से सम्बद्ध पचायतों सहकारी समितियों व विकास कार्यक्रमों में तासमेल बँटाता है।

### सामुदायिक विकास योजना के विभिन्न चरण

भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संचालन प्रायः चार चरणों में रहा है—(1) पूर्व विस्तार अवस्था—प्रथम चरण में जिस क्षेत्र में सामुदायिक विकास खण्ड स्थापित करना होता है उसमें प्रायः एक वर्ष की अवधि में खण्ड स्थापना के लिए आवश्यक आधार तैयार किया जाता है। उस क्षेत्र का गहन अध्ययन व सर्वेक्षण किया जाता है व आवश्यक दस्तावेजों की नियुक्ति की जाती है। (2) प्रथम अवस्था वाले खण्ड—द्वितीय चरण में पूर्व विस्तार अवस्था वाला क्षेत्र इस क्षेत्री में आ जाता है जिसमें पाँच वर्ष की अवधि में 14 लाख रुपये व्यय करने की व्यवस्था होती है और इस धन राशि का प्रयोग कृषि विकास कार्यों, लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास खण्ड कार्यालय व सामाजिक सेवाओं के लिए होता है। इन कार्यों का सामयिक मूल्यांकन करने के लिए मासिक निवेदन दिये जाते हैं। (3) द्वितीय अवस्था वाले खण्ड—तीसरे चरण में प्रथम अवस्था की समाप्ति पर द्वितीय अवस्था प्रारम्भ होती है जिसमें अगले पाँच वर्षों में 5 लाख रुपये व्यय से अधिक विकास कार्यक्रमों को और सृष्ट किया जाता है। (4) अन्तिम अवस्था—द्वितीय अवस्था की समाप्ति पर प्रत्येक विकास खण्ड में आदिन योजनाओं का निश्चित ढंग स्वयं स्कूल रूप में चानू हो जाता है। अगले पिछले पाँच वर्षों में विकास पर्याप्त न हो तो उस क्षेत्र के विकास को बाह्य स्तर पर लाने के लिए अगले एक या दो वर्ष तक 1 लाख रुपये की विशेष राशि व्यय की जाती है।

सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा में अन्तर

सामान्यतः सामुदायिक विकास (Community Development) तथा राष्ट्रीय विस्तारसेवा (National Extension Service) में कोई अन्तर नहीं समझा

जाता पर दोनों में अन्तर है। (i) सामुदायिक विकास ग्रामीण विकास की एक पद्धति (System) है जबकि राष्ट्रीय विस्तार सेवा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने का साधन (means) है। (ii) सामुदायिक विकास का क्षेत्र विस्तृत तथा लक्ष्य व्यापक गहन एवं महत्वाकांक्षी होता है जबकि राष्ट्रीय विस्तार सेवा का क्षेत्र एवं उद्देश्य सीमित है। (iii) सामुदायिक विकास पर काफी राशि व्यय की जाती है जबकि राष्ट्रीय विस्तार सेवा पर तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम व्यय किया जाता है। (iv) सामुदायिक विकास ग्रामीण जनसंख्या के सर्वांगीण विकास से सम्बन्धित योजना है जबकि राष्ट्रीय विस्तार सेवा कृषि के विकास से उन्हे उच्च जीवन स्तर प्रदान करने तक सीमित है।

### सामुदायिक विकास की पंचवर्षीय योजनाओं में प्रगति

**प्रथम योजना:** भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का श्रीगणेश 2 अक्टूबर 1952 को 55 चुने हुए केन्द्रों पर लागू हुआ। प्रथम योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर 40.98 करोड़ रुपये खर्च हुए और योजना की समाप्ति तक 988 विकास खण्डों के अन्तर्गत 1.40 लाख गाँवों की 7.75 करोड़ जनसंख्या इस कार्यक्रम की परिधि में आ गई। इस योजना के अन्तर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रगति पर था।

**द्वितीय पंचवर्षीय योजना—** इस योजना में भी सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के विस्तार पर जोर दिया गया और साथ ही 1956 में सामुदायिक विकास आन्दोलन की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए अन्तराल में महत्ता की अध्यक्षा में एक समिति नियुक्त की गई जिसने 1957 में प्रकाशित प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण सिफारिशों की जिनमें मुख्य थी—(i) सत्ता का प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण (Democratic Decentralisation) कर स्थानीय जन प्रतिनिधियों को सत्ता का हस्तांतरण करना। (ii) सामुदायिक विकास के मसूचे कायम की सृष्टि करने के लिए उचित प्रशासन की स्थापना। (iii) सामुदायिक विकास कार्यक्रम की तृतीय योजना तक बढ़ाना और (iv) सामुदायिक विकास कार्यक्रमों व राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अन्तर का समापन करना। ये सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई और राजस्थान में 2 अक्टूबर, 1959 को भारत में सर्वप्रथम प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का सूत्रपात स्वर्णय पश्चिम मेहरारू द्वारा नागौर में किया गया।

द्वितीय योजना का म सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर कुल 187.12 करोड़ रुपये व्यय किया गया। परिणामस्वरूप 3100 विकास खण्डों के 3.7 लाख गाँवों की 20 करोड़ जनसंख्या इस कार्यक्रम की परिधि में आ गई।

**तृतीय पंचवर्षीय योजना—** इस योजना में सामुदायिक विकास पर 294 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान था पर वास्तविक व्यय 269.12 करोड़ रु. ही रहा। योजना के अन्त तक यह कार्यक्रम 5200 विकास खण्डों में प्रगति पर था और देश का अधिकांश भाग इसकी परिधि में आ चुका था।

तीन वार्षिक योजनाएँ (1966-69)--इन तीन वार्षिक योजनाओं की अवधि में सामुदायिक विकास पर लगभग 92 करोड़ रु० व्यय किया गया। 1968-69 के अन्त में सम्पूर्ण देश में 5265 विकास खण्ड थे।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74)--इस योजना में सामुदायिक विकास को कृषि विकास का एक अविभाज्य अंग मानकर उस पर 1152 करोड़ रु० व्यय का प्रावधान था। चतुर्थ योजना काल में अनेक राज्यों में सामुदायिक विकास खण्डों के पुनर्गठन के कारण विकास खण्डों की संख्या 5123 हो गई है जबकि योजना के प्रारम्भ में विकास खण्डों की संख्या 5265 थी। यह योजना भारत के प्रायः सभी क्षेत्रों में लागू हो चुकी है और समस्त भारतीय ग्रामीण जनसंख्या सामुदायिक विकास कार्यक्रम की परिधि में आ चुकी है।

पाँचवीं योजना--इस योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर 275 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान था ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन एवं रोजगार व्यवसरो में वृद्धि की जा सके और सम्पूर्ण गाँव को एक इकाई मानकर समूचे समाज को समन्वित करना था।

वर्तमान स्थिति एवं छठी योजना--इस समय देश में लगभग 5123 विकास खण्ड हैं जिनके अन्तर्गत 22 लाख ग्रामपंचायतें, 3863 पंचायत समितियाँ तथा 301 जिला परिषद् कार्यरत हैं। यह योजना देश के 544 लाख गाँवों की लगभग 407 करोड़ जनसंख्या को लाभान्वित कर रही है और 90% ग्रामीण जनसंख्या इसकी परिधि में आ चुकी है। छठी योजना में भी इस कार्यक्रम पर विशेष बल दिया जायगा और सभी ग्रामीण संस्थाएँ इसकी परिधि में आ जायेंगी।

पंचायत राज--पंचायत राज भारत के मेमालय व नागालैण्ड को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में लागू हो गया है जिससे लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का स्वप्न साकार हुआ है। देश के 544 लाख गाँवों की 4068 करोड़ जनसंख्या इसकी परिधि में आ चुकी है।

प्रशिक्षण--सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को दर्शन व नीति सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक सामुदायिक विकास राष्ट्रीय संस्थान-हैदराबाद के अतिरिक्त ग्राम सेवकों के लिए 98 केन्द्र सहकारी विस्तार अधिकारियों के लिए 13 केन्द्र, पंचायत सचिवों के प्रशिक्षण के लिए 80 केन्द्र और पंचायत समिति के पदाधिकारियों के लिए 26 प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत हैं। कुल 200 प्रशिक्षण केन्द्र सन्त्रिय हैं।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा, आलोचनाएँ व कठिनाइयाँ

यद्यपि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में वार्यान्वयन के ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है, ग्रामीण जनता में नई आवश्यकताओं, आशाओं और आकांक्षाओं का प्रादुर्भाव हुआ है। रूढ़ियों के दृष्टिकोण में नान्तिकारी परिवर्तन हुआ है उनमें अधिकारों के प्रति जागरूकता, नवीन आधुनिक उत्पादन विधियों के प्रति रुचि और

ग्रामीण नेतृत्व के साथ साथ आर्थिक विकास की भावना प्रबल हुई है। पिछले 24-25 वर्षों में कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है—शिक्षा विविधता, स्वास्थ्य सेवाओं तथा परिवहन साधनों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है फिर भी कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के प्रतिवेदनो से इसकी प्रगति के साथ इसकी दुर्बलताओं व असफलताओं की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है। भ्रष्ट आलोचनाएँ असफलताएँ, व कठिनाइयाँ ये हैं

1 सामुदायिक विकास एक खोखला कार्यक्रम है जिससे पैसे का दुरुपयोग कर मनगढ़न्त आकड़ों से कागजी घोड़े दोड़ाये जाते हैं और विकास के ऐसे हवा-महल बनाये जाते हैं जो आंच करते ही ढह जाते हैं इसमें व्यावहारिकता की अवहेलना व औपचारिकता व नींकरशाही को आवश्यक महत्व दिया गया है। न तो इसमें भूमिहीन किसानों की दशा सुधारने का कोई कार्यक्रम है और न कार्यक्रमों में मनियोजित पाषाणिकताएँ ही हैं। लाल फीनाशाही व नींकरशाही के बोलबाले में सरकारी पैसे का अव्यय्य प्रयोग है। वमचारियों के आवश्यक प्रशिक्षण के अभाव में योजना के निशान्वयन के लिये कुशल कर्मचारियों का अभाव है। यह कार्यक्रम तो पूँजीवादी अमेरिका की एक औपनिवेशिक विस्तार नीति का पहला कदम है।

2 गन्दी राजनीति का अखाड़ा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के केन्द्र बिन्दु ग्राम विकास पंचायत सहकारी समितियाँ पंचायत समितियाँ व जिला परिषदें ग्रामीणों के भर्खाड़ीय विकास के लिये स्थापित किये गये पर वे अब गन्दी राजनीति के शिकार हैं। घिनौने व घृणित राजनैतिक हरकतों के कारण विकास के केन्द्र दिनाशकारी सिद्ध हो गये हैं। जिस क्षेत्रों में गन्ताधारी दल पंचायत पर अधिकार जमा लेता है उनमें विराभी गडचनें उत्पन्न करते हैं और जिन क्षेत्रों में सरकारी विरोधी दल पंचायत सत्ता प्राप्त कर लेता है सरकार उनके सब विकास कार्यों में जान बूझकर गडचनें डालती है। राजस्थान में ग्रामपंचायतों के लम्बी अवधि से चुनाव न करना इस घिनौनी राजनीति का एक छोटा सा उदाहरण है। सहयोग के स्थान पर दलबं व घनपी है।

3 अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों में मतभेद—सामुदायिक विकास स्थानीय लोगों तथा सरकार का एक समुक्त प्रयास है। एक तरफ चुनाव द्वारा मनोनीत सरपंच प्रधान व जिला प्रमुख होना है तो दूसरी तरफ ग्राम सेवक, गटवारी कृषि निम्नार अधिकारी सण्ड विकास अधिकारी। इनमें परस्पर मतभेद हो जाने पर विकास का कहीं रह जाना है व अपनी शक्तियों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा देते हैं विकास ठण हो जाता है घृणा लड़ाई भगडे व असहयोग बनपता है।

4 कृषि ग्रामोद्योग व सहकारिता की बहुत घीमी प्रगति—पिछले 24-25 वर्षों के प्रयासों के बावजूद अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, ग्रामोद्योग व सहकारिता

का बहुत ही कम विकास हो पाया है। अधिकांश कृषकों में प्रगतिशील दृष्टिकोण का अभाव है, चक्कन्दो, भूमि संरक्षण, सिंचाई, वैज्ञानिक उपकरणों व कृषि की उन्नत विधियों का निर्यात-अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों व सहकारिता का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। लक्ष्य व उपलब्धियों में काफी अन्तर रहा है।

5. सरकारी सहायता में अपर्याप्तता व विलम्ब—सरकारी कार्यालयों में व्याप्त शासकीयतावादी नीतिरक्षाहीन व ढील ग्राहक विकास खण्डों, पचायतों व सहकारी समितियों में भी परिलक्षित होती है। अतः विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आर्थिक सहायता समय पर न मिलने से वांछित लाभ नहीं मिल पाता और विकास अवरुद्ध हो जाता है। अभावस्थिति की घोषणा के बाद कुछ सुधार हुआ है।

6. सामुदायिक भावना व जन सहयोग का अभाव—भारत में दूषित राजनीति का अभाव ग्रामीण जनता पर भी पड़ा है। प्रजातान्त्रिक विकेंद्रीकरण ने गांवों में धिनीनी व घृणित राजनीति से दलबन्दी, परस्पर मतभेद व संघर्षों को जन्म दिया है। चरित्र व छीटाकशी, भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के हथकण्डों आदि के कारण सेवा भावी, ईमानदार व योग्य व्यक्ति इनके नेतृत्व से दूर रहना चाहते हैं जबकि भ्रष्ट, चोर, बेईमान तथा गुण्डे अपने स्वार्थी हितों के कारण इन समस्याओं पर प्रभुत्व जमाने में प्रयास करते हैं। नि स्वार्थ भोले भाले लोग इनका तमाशा देखने में लग जाते हैं। इस प्रकार के वातावरण में सामुदायिक भावना व जन सहयोग की वरूपना निरर्थक नहीं तो भी कठिन अवश्य है।

### सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए सुझाव

यद्यपि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को वांछित सफलता नहीं मिली है और यह कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफी असफल रहा है फिर भी इसे सफल होना है। भारत की 82% जनता का सर्वाङ्गीण विकास हुए बिना भारत का भविष्य अन्धकारमय है अतः इस कार्यक्रम की सफलता के लिये निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं।

1. शिक्षा का तेजी से प्रसार—ग्रामीण जनसंख्या में शिक्षा का अभाव ही उनकी रुढ़िवादिता, अज्ञानता, अश्विश्वास व सकीर्ण दृष्टिकोण का प्रमुख कारण है। यद्यपि पिछले 20-25 वर्षों में शिक्षा के विकास पर काफी ध्यान दिया गया है पर इसका अधिकाधिक लाभ शहरी जनता को ही मिला है। ग्रामीण जनता उसके पूरे-पूरे लाभ से वंचित रही है। सुविधा उपलब्ध करना ही पर्याप्त नहीं उन्हें उस सुविधा के प्रयोग की अभिरुचि व प्रेरणा जागृत करना भी जरूरी है।

2. भूमि सुधारों व कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देना आवश्यक है। भूमि सुधारों का कार्यान्वयन सच्चे मन से होना चाहिये। क्षामियों से परिपूर्ण कानूनों व उन्हें ऊपरी मन से लागू करने का परिणाम हमारे सामने है। 20-25 वर्षों के बाद भी गांवों में व्याप्त निधनता, बड़े मूस्वामियों द्वारा शोषण, भूमि आवंटन में भ्रष्टाचार, भूमिहीनों की दुर्दशा ये सब इस दिशा में प्रभावी कदम का आह्वान कर

रहे हैं अन्यथा शिक्षा का वातावरण और अधिक तेज हो सकता है। हरित प्रान्ति की प्रगतिशीलता का प्रान्ति में बदन सकती है।

3. प्राथमिक सहायता उद्योगों का विकास एवं विस्तार—सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में जाता है नाम के विद्ये आयोजनों का लक्ष्य एवं गुटीर उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन व प्राथमिक सहायता प्रदान करना चाहिये। इससे एक और बेरोजगार या अर्द्ध-बेरोजगार व्यक्तियों को काम मिलेगा तथा दूसरी ओर आय, उत्पादन व उपभोग बढ़ने से जीवन-स्तर में सुधार होगा।

4. गन्दी राजनीति से छुटकारा—प्रजातन्त्र की सफलता सजग एवं वक्तव्य-निष्ठ राजनीति से ही पर निर्भर करती है। अतः पचायतों की गन्दी राजनीति से दूर रहने के लिये सभी स्तरों द्वारा एक निश्चित आधार-सहिता का पालन करना चाहिये। विकास कार्यो में दखल मतभेदों को परे रखना चाहिये। इसमें पहले प्रगर सत्ता-प्राप्ति का नरे तो अर्थ है।

5. प्रशासनिक कुशलता—सामुदायिक विकास कार्यो के कार्यक्रमों में प्रत्येक प्रारम्भ व प्ररण पर कुशल, ईमानदार, वक्तव्यनिष्ठ व प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की नियुक्ति करना चाहिये तथा उन्हें समय व परिस्थितियों के अनुकूल योजनाओं में समायोजन व समन्वय बैठाने की सीमित स्वतन्त्रता देनी चाहिये। उन्हें सुरक्षा व सुविधाएँ प्रदान करने के साथ साथ योजनाओं के नियन्त्रण की एक निश्चित जिम्मेदारी भी होनी चाहिये व एक निश्चित मापदण्ड से काम प्रगति के कारणों के प्रवर्तन के बाद सीधी अधिकारियों के उठेर दण्ड की व्यवस्था जरूरी है। वर्तमान पद्धति में पंचायतों के पंचों व राष्ट्रीय गुस्सहार तथा वक्तव्यनिष्ठ व ईमानदार व्यक्तियों को उनकी कुशलता की सजा की परम्परा को तोड़ना होगा।

6. मतभेदों का समापन व उचित समन्वय—विकास गण्डा, विकास पचायतों आदि में जन प्रतिनिधियों व सरकारी अधिकारियों के बीच मतभेद विकास का मार्ग अवरुद्ध कर देता है। अतः दोनों के कार्यो व अधिकारों में इस प्रकार का समन्वय बैठाना जाना चाहिये कि वास्तविक मतभेद उत्पन्न होने के लिये न्यूनतम हो जायें और इन मतभेदों का निपटारा अधिकतर रिया जाता चाहिये। सरपंचों, पंचों, प्रगणों व प्रमुखों को भी नगरपालिकों व अधिकारियों की भांति आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

7. जनसहयोग की प्रोत्साहन—सामुदायिक विकास की जनता व सरकार का संयुक्त प्रयास सभी सफल हो सकता है। जबकि जाता अपना पूरा-पूरा सहयोग दे। इससे लिये प्रचार केन्द्रों, निम्नो तथा प्राथमिक भाषा में आयोजित कार्यक्रमों व प्रतियोगिताओं की महत्त्वता भी जा सकती है। जन-सम्पर्क विभाग जो अपना बहुत सारा समय सदस्यों के प्रप्रभावी निम्नो दिगाने, निनिस्टरो के साथ पीछे पुमने फिरने, जिन्ना अधिकारियों व मन्त्रियों का गुणगात्र करने में व्यस्त रहते हैं, प्राथमिक स्तरों के लोगों में विकास कार्यक्रमों में सहयोग की भावना भर सकते हैं। यद्यपि

आज के राजनैतिक प्रोपेगण्डा के वातावरण में भोले-भाले ग्रामीण उनके प्रचार को सन्देह की दृष्टि से देखेंगे पर धीरे-धीरे आत्मविश्वास जम जायेगा।

**निष्कर्ष**—उपर्युक्त विवरण व विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सामुदायिक विकास ग्रामीण जनता के सर्वाङ्गीण एवं सर्वतोन्मुखी विकास का गहन एवं विस्तृत कार्यक्रम है जिसकी सफलता में ही भारत की प्राथित समृद्धि व सम्पन्नता निहित है। यद्यपि देश की भाग्यवादी, धन्यविश्वासी, श्रमानी एवं निर्धन, भूखी ग्रामीण जनसंख्या को एकदम चमत्कारी ढंग से बदलना एक कठिन कार्य है फिर भी एक सुनियोजित ढंग से कार्यान्वित विकास कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीणों में उत्साह, विकास के प्रति अभिरुचि, उच्च जीवन-स्तर की लालसा तथा सर्वाङ्गीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। इसके लिए गंदी राजनीति से मुक्ति, परस्पर मतभेदों का समापन, उचित प्राथमिकताओं का निर्धारण, कार्यक्रमों के कुशल आयोजन व क्रियान्वयन के साथ साथ ग्रामीणों में परस्पर सहयोग की भावना स्थापित है। अतः स्वर्गीय पूज्य बापू व स्वर्गीय पंडित मेहरू को सच्ची श्रद्धाजलि यही होगी कि हम सामुदायिक विकास योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर ग्रामीण जनता को समृद्ध, सबल व गुणोत्कृष्ट नागरिक बना सकें और उनका सर्वाङ्गीण विकास हो सके।

### परीक्षोपयोगी प्रश्न भण्ड संकेत

1 भारत में सामुदायिक विकास योजनाओं के उद्देश्यों व उपलब्धियों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये। अथवा

सामुदायिक विकास योजनाएँ ग्रामीणों में उत्पादकता व जीवन स्तर बढ़ाने में कहाँ तक सफल हुई हैं? अथवा

भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये।  
(संकेत—प्रथम भाग में सामुदायिक विकास का अर्थ, उद्देश्य व सफलता बताकर आलोचना करनी है।)

2 “सामुदायिक विकास भारतीय ग्रामीण जनता के सर्वाङ्गीण विकास का कार्यक्रम है” इस कथन की समीक्षा (विवेचना) कीजिये।

(संकेत—सामुदायिक विकास का अर्थ, उद्देश्य बताना है तथा पञ्चवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत प्रगति की समीक्षा कीजिये।)

3 सामुदायिक विकास की कठिनाइयों व आलोचनाओं का विवेचन कीजिये तथा इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सुझाव दीजिए।

(संकेत—सामुदायिक विकास योजनाओं की आलोचनाओं व कठिनाइयों का विवरण देकर अध्याय में दिए गए दीर्घांशानुसार विवरण देना है।)

# भारत में औद्योगिक नीति एवं लाइसेन्स नीति

(Industrial Policy & Licencing Policy In India)

मानव सभ्यता के विकास की प्रारम्भिक अवस्था में राज्य आर्थिक क्षेत्र में निर्बाधता की नीति (Policy of laissez faire) अपनाते थे किन्तु विश्व व्यापी आर्थिक मंदी ने मुक्त व्यापार एवं राज्य की आर्थिक निरपेक्षता की नीतियों की अव्यावहारिकता जाहिर कर दी। आर्थिक निर्बाधता की नीति के प्रतिपादक एवं बहुर समर्थक पूँजीवादी राष्ट्र स्वयं मंदी के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिये राज्य हस्तक्षेप की दुहाई देने लगे। अब विश्व के सभी राष्ट्र चाहे वे पूँजीवादी हो अथवा समाजवादी, आर्थिक क्षेत्र में राज्य के प्रभावी हस्तक्षेप को आवश्यक मानते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में देश के तीव्र औद्योगीकरण एवं आर्थिक विकास के लिये सुनिश्चित, सुनियोजित एवं प्रगतिशील औद्योगिक नीति का प्रतिपादन एवं क्रियान्वयन भी राज्य की नीतियों का महत्वपूर्ण अंग है। राज्य औद्योगीकरण की स्वस्थ परम्पराओं कायम करता है, मार्गदर्शन देता है तथा औद्योगिक निषादों का नियमन एवं नियन्त्रण करता है ताकि देश का तीव्र सुनिश्चित एवं सन्तुलित औद्योगीकरण का मार्ग प्रशस्त हो सके।

## औद्योगिक नीति के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व (Objectives Need and Importance of Industrial Policy)

निसी भी दश में औद्योगिक नीति की आवश्यकता उनके उद्देश्यों से प्रेरित होती है जिनमें निम्न उल्लेखनीय हैं —

1. औद्योगिक उत्पादन में तीव्र प्रगति—यह औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्देश्य होता है मगर नीति मफन रहती है तो केवल औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ता है वरन् देश के तीव्र आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है।

2. उत्पादन की आधुनिकतम पद्धतियों को प्रोत्साहन—औद्योगिक नीति का महत्व औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन की आधुनिकतम एवं नवीनतम वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रोत्साहन देने में निहित है क्योंकि इससे कम लागत पर अधिक उत्पादन होता है।

3. सन्तुलित विकास—औद्योगिक नीति का महत्व कृषि एवं उद्योगों के सन्तुलित विकास को गति देने तथा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सन्तुलित विकास करना होता है।



4. आधारभूत उद्योगों एवं उपभोग उद्योगों में सामन्जस्य स्थापित करना तथा उनमें पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना ताकि दोनों क्षेत्रों में सन्तुलन रह सके।

5. पूँजी एवं श्रम में मधुर सम्बन्धों को बढ़ावा देना ताकि दोनों में सघर्षों को रोका जा सके और सौहार्दपूर्ण सहयोग से औद्योगीकरण की गति तेज हो।

6. वृहत् एवं लघु उद्योगों में समन्वय एवं सहयोग—औद्योगिक नीति बड़ा एवं छोटे उद्योगों में समन्वय एवं सहयोग स्थापित करती है जिससे रोजगार में वृद्धि, उत्पादन का उच्च स्तर एवं उत्पादन लागत में कमी की जा सके। प्रतिस्पर्धा न हो।

7. निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारण करना ताकि दोनों क्षेत्रों को अपने-अपने क्षेत्रों में अबाध गति से आगे बढ़ने का सुप्रबसर मिल सके।

8. विदेशी पूँजी एवं साहस का राष्ट्रहित में सदुपयोग करना—विकासशील राष्ट्रों के पास पूँजी एवं साहस दोनों की कमी होती है अतः औद्योगिक नीति से इन दोनों के लिये विदेशी साहसियों को आकर्षित किया जा सकता है।

9. सन्तुलित क्षेत्रीय विकास—औद्योगिक नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था के प्रायः सभी क्षेत्रों का सन्तुलित, औद्योगिक एवं आर्थिक विकास किया जा सकता है।

### भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व औद्योगिक नीति

#### (Industrial Policy before Independence)

ब्रिटिश शासन काल में उपर्युक्त औद्योगिक नीति का अभाव रहा। यद्यपि ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने प्रारम्भ से उद्योगों को प्रोत्साहन दिया ताकि उनके उत्पादन के निर्यात से लाभ कमाया जा सके। किन्तु ब्रिटिश उद्योगपतियों ने भारत में औद्योगीकरण का विरोध किया और ब्रिटिश सरकार ने भारत में मुक्त व्यापार (Free trade) की नीति एवं निर्बाध व्यापार नीति (Laissez-Faire Policy) का अनुसरण किया जिससे भारत को कच्चे माल का उत्पादक एवं निर्मित औद्योगिक माल का बाजार बनाया जा सके। इसका भारतीय उद्योगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन हुआ। डॉ० बेराएनस्टे ने स्वयं स्वीकार किया है कि "1858 से पूर्व ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकारियों की दमनपूर्ण नीति ने भारत के परम्परागत उद्योग नष्ट हो गये।"

यद्यपि 1858 से 19 वीं शताब्दी के अन्त तक मुक्त व्यापार नीति से भारतीय उद्योगों की प्रगति का अवसर न मिल सका। किन्तु 1904 में स्वदेशी आन्दोलन के जोर पकड़ने से 1905 में लार्ड कर्जन ने "केन्द्रीय व्यापार एवं उद्योग विभाग" स्थापित किया तथा 1906 में मद्रास में एक प्रांतीय उद्योग विभाग भी खोला गया पर यह दोहरी एवं बेमन से लागू नीति भारत के औद्योगीकरण में सहायक न बन सकी।

प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कुछ विशिष्ट वस्तुओं की उत्पादन वृद्धि के लिए मुक्त व्यापार नीति का परित्याग कर राजकीय प्रोत्साहन की नीति अपनाई। भारत में औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं की जांच के लिये एव 'औद्योगिक आयोग' (Industrial Commission) 1916 में स्थापित किया गया तथा 1917 में मिनट्री एव नागरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इण्डियन ऐम्प्लूनीशन बोर्ड स्थापित किया गया। 1918 में औद्योगिक आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दी किन्तु युद्धोत्तर मंदी के संकट व विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण आयोग की सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया गया।

स्वदेशी आन्दोलन एव भारतीय उद्योगों के सामने मंदी के संकट के कारण 1921 में सरकार का बाध्य होकर प्रशुल्क आयोग (Fiscal Commission) की स्थापना करनी पड़ी और इसी आयोग की सिफारिशों पर ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उद्योगों के लिए विभेदात्मक संरक्षक नीति (Policy of Discriminating Protection) की घोषणा की तदनुसार 1923 में प्रथम तटकर बोर्ड (Tariff Board) बनाया गया और 1924 में लोहा इस्पात उद्योग को, 1925 में कागज के उद्योग को 1926 में सूती वस्त्र उद्योग को तथा 1932 में चीनी उद्योग को संरक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त दियासलाई, भारी रासायनिक उद्योग तथा अन्य कई छोटे उद्योगों को भी संरक्षण दिया गया।

1930 की विश्व व्यापी मंदी ने भारत के उद्योगों को भी मंदी के संकट में डाल दिया। संरक्षण की नीति अपर्याप्त एव अवरोधक होने के कारण औद्योगिकरण बाधित गति से न हो सका। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यातायात एव आधारभूत उद्योगों के राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया। अन्ततः 1939 में उद्योग मन्त्रियों के सम्मेलन में औद्योगिक विकास के लिए एक राष्ट्रीय आयोजन समिति गठित की गई।

1939 में द्वितीय विश्व-युद्ध की चिंगारी भभक उठी। अतः युद्ध सामग्री उत्पादन के लिए ब्रिटीश मिशन तथा अन्य कई समितियाँ उद्योग विकास के लिए बनीं। युद्धकाल में भारतीय उद्योगों को तेजी से विकसित होने का मौका मिला। युद्धोत्तर-कालीन पुनर्निर्माण के लिए 1943 में सरकार ने अनेक औद्योगिक समितियों की नियुक्ति की तथा 1944 में एक योजना एव विकास विभाग (Planning and Development Deptt.) खोला गया। 1946 में एक योजना सचिवालय बोर्ड भी बनाया गया। ये सब छुट पुट प्रयास थे।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में मुनिश्वर एव प्रगतिशील औद्योगिक नीति का सर्वथा अभाव था। यदा-कदा परिस्थितियों वगैरह सरकार को औद्योगिक विकास के लिए छुट-पुट निर्णयों के लिए बाध्य होना पड़ा परन्तु ब्रिटिश सरकार ने कभी उन निर्णयों का भारत के औद्योगिक हितों का रक्षा

एवं संरक्षण के लिए स्वेच्छा से लागू नहीं किया। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में जो कुछ औद्योगिक विकास सम्भव हुआ वह सब ब्रिटिश सरकार की नीति का प्रतिफल न होकर भारतीय उद्योगपतियों के साहस, विदेशी पूँजीपतियों के सहयोग तथा अनुकूल परिस्थितियों की देन थी।

### भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद औद्योगिक नीति (Industrial Policy in India Since Independence)

15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश दासता से मुक्त होकर अपनी भाग्य डोर सम्माली। औद्योगिक विकास के प्रति ब्रिटिश सरकार की उदासीन एवं अकर्मण्यता पूर्ण नीति का परित्याग देकर देश के नेताओं ने भारत के तीव्र औद्योगिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि के प्रयास शुरू किए। 1947 के औद्योगिक सम्मेलन में उद्योगों की प्रगति, औद्योगिक शक्ति तथा धन के केन्द्रीकरण पर रोक आदि मुद्दों पर विचार हुआ। इस सम्मेलन के प्रस्तावों को मूर्त-रूप देने के उद्देश्य से ॥ अप्रैल; 1948 को तत्कालीन उद्योग मन्त्री स्वर्गीय श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने स्वतन्त्र भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की।

### स्वतन्त्र भारत की पहली औद्योगिक नीति (1948)

देश में तीव्र औद्योगिक विकास एवं आधारभूत उद्योगों को सुदृढ़ आधार तैयार करने के उद्देश्य से 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग मन्त्री स्वर्गीय श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) पर आधारित स्वतन्त्र भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की जिसकी मुख्य विशेषताएँ संक्षेप में निम्नानुसार हैं—

1 उद्देश्य—यह नीति मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित प्रजातान्त्रिक नियोजन द्वारा देश में औद्योगिक उत्पादन के सुदृढ़ आधार से आर्थिक समानता और समृद्धि के साथ-साथ रोजगार एवं जीवन-स्तर में सुधार के लिए राष्ट्रीय साधनों का समुचित उपयोग करना था।

2 उद्योगों का चार भागों में वर्गीकरण—इस नीति में वृहत् उद्योगों को चार भागों में वर्गीकृत किया गया—

(i) राज्य अधिभूत क्षेत्र—इसके अन्तर्गत अस्त्र-शस्त्र निर्माण, अणु-शक्ति उत्पादन एवं नियन्त्रण तथा रेल यातायात, इन तीनों के विस्तार, विकास एवं नये निर्माण का सरकारी क्षेत्र का एकाधिकार रहेगा।

(ii) राज्य नियन्त्रित उद्योग—इसमें 6 आधारभूत उद्योग—कोयला, लोहा-इस्पात, टेलीफोन, तार-बेतार, खनिज तेल, वायुयान एवं जलयान निर्माण का समावेश था। नये निर्माण को पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रखा तथा निजी उद्योगों को राष्ट्र-हित के आवश्यक होने पर राष्ट्रीयकरण की भी व्यवस्था थी।

(iii) मिश्रित उद्योग—इस श्रेणी में राष्ट्रीय महत्व के 20 उद्योगों को रखा

जिनकी स्थापना, संचालन एवं विकास पर सरकारी प्रभावी नियन्त्रण एवं नियमन में रहना।

(iv) पूर्णतः निजी क्षेत्र—इस क्षेत्र में बारी शेष उद्योगों को जो निजी क्षेत्र में रहेंगे तथा उन पर सरकार का सामान्य नियन्त्रण रहेगा।

3 सधु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए बृहत् उद्योगों के साथ तालमेल बंठाया गया ताकि दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी न होकर सहयोगी एवं पूरक रहे।

4 मधुर औद्योगिक सम्बन्धों के लिए औद्योगिक नीति में औद्योगिक विवादों को निपटाने की उपयुक्त मशीनरी, श्रम-कल्याण कार्यो तथा उचित मजदूरी भुगतान की व्यवस्था की गई थी।

5 प्रशुल्क एवं कर नीति—औद्योगिक नीति में उत्पादन वृद्धि एवं विनियोग वृद्धि के हेतु उपयुक्त कर-नीति तथा विदेशी प्रतिस्पर्द्धा से देश के उद्योगों को बचाने के लिए समुचित प्रशुल्क नीति की व्यवस्था थी।

6 विदेशी पूँजी एवं साहस की मान्यता—इस नीति में विदेशी पूँजी को भारतीय पूँजी के समकक्ष स्थान प्रदान करने तथा राष्ट्रहित में राष्ट्रीयकरण के साथ साथ ऐसी सस्थाओं या बहुमत-स्वामित्व भारतीयों के हाथ में रखने तथा भारतीय विशेषज्ञों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी।

7 विशिष्ट संगठनों का निर्माण एवं उत्पादन वृद्धि को प्राथमिकता दी गई थी। वितरण की समस्या भविष्य पर छोड़ दी गई थी।

### 1948 की औद्योगिक नीति की समीक्षा

इस औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के कलेवर में तीव्र औद्योगीकरण की व्यवस्था थी। पहली बार औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व स्वीकार किया गया था और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के पारस्परिक सहयोग की व्यवस्था थी। आधारभूत एवं सार्वजनिक महत्व के उद्योगों के विकास का दायित्व राज्य पर डाला गया था। विदेशी पूँजी एवं साहस को भी भारत के औद्योगीकरण में पर्याप्त भूमिका का अवसर दिया गया था। कुछ विद्वानों ने इसे भारत के औद्योगिक विकास के लिए क्रान्तिकारी कदम तथा लोचन की आधार शिला की सजा दी। जहाँ प्रो. रंग ने इस नीति को गांधीवादी समाजवाद की विजय बताया वहीं मोनू मसानो ने अनुसार 'इस नीति द्वारा प्रजातान्त्रिक समाजवाद को नोंक डालो गई।'।

मुख्य आलोचनाएँ—जहाँ एक ओर 1948 की औद्योगिक नीति की काफी सराहना हुई वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने इस पूँजीपति विरोधी नीति भी बनाया। इसका कारण विदेशी एवं देश के पूँजीपतियों में राष्ट्रीयकरण का भय व्याप्त हो गया तथा नियन्त्रण एवं नियमन के कारण वे विनियोग के प्रति उदासीन होन लगे।

कुल मालोचनाएँ इस प्रकार थी — (i) मिश्रित अर्थव्यवस्था में तीव्र औद्योगीकरण सम्भव नहीं होता । (ii) यह नीति अस्पष्ट एवं अनिश्चित थी क्योंकि इसमें वामपक्षी एवं दक्षिण-पक्षी दोनों प्रवृत्तियों के समावेश से अनिश्चितता का वातावरण हो गया । (iii) विदेशी पूँजीपतियों में अविश्वास जागा । (iv) इस नीति में उत्पादन वृद्धि को महत्व दिया किन्तु वितरण के महत्व की उपेक्षा की । (v) औद्योगिक विकास की सुनिश्चित योजनाओं का अभाव था । (vi) सन्तुलित क्षेत्रीय विकास पर ध्यान नहीं दिया गया ।

### 1948 की औद्योगिक नीति का क्रियान्वयन

इस नीति के कार्यान्वयन के लिए औद्योगिक केन्द्रीय सलाहकार समिति की नियुक्ति की गई तथा फिर 1950 में औद्योगिक विकास समिति बनाई गई जिसका कार्य श्रमिकों की कार्य-क्षमता में वृद्धि करना, उत्पादन व्यय को घटाना, प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा उद्योग विशेष की समस्याओं को हल करना था ।

1 अप्रैल 1951 से देश में योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया पहली पंचवर्षीय योजना से शुरू हुई । 1948 की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1951 (Industrial Development & Regulation) Act 1951 पारित किया गया जिसमें 36 उद्योगों के पंजीकरण की व्यवस्था थी और नये उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार के लिए सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक था । 1952 में यह अधिनियम लागू हो गया । उद्योगों के विकास के लिए सरकार को उचित सलाह देने के लिए 1952 में केन्द्रीय सलाहकार परिषद् (Central Advisory Council) बनाई गई जिसमें श्रमिकों, उद्योगपतियों तथा सरकार के प्रतिनिधि होते हैं । विशिष्ट उद्योगों की समस्याओं के अध्ययन एवं विकास में सरकार को सहयोग देने के लिए अनेक उद्योग विकास परिषदें (Development Councils) भी बनाई गईं । नये उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु एक लाइसेन्स समिति (Licence Committee) भी बनायी गई ।

1951 के औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम में संशोधन किया गया जिससे यह अधिनियम 1953 में 45 उद्योगों तथा 1955 में 89 उद्योगों पर लागू था । लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए अनेक विशिष्ट संगठन बनाये गये जिनमें खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, दस्तकारी बोर्ड, हाथ करघा बोर्ड, अखिल भारतीय कुटीर उद्योग बोर्ड आदि उल्लेखनीय हैं ।

### 1948 की औद्योगिक नीति का मूल्यांकन

देश की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 साठ वर्ष तक कार्यशील रही इस नीति के क्रियान्वयन में अनेक कमियों के बावजूद पहली योजना में औद्योगिक उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई । सार्वजनिक क्षेत्र में 55 करोड़ रु० तथा निजी क्षेत्र में 233

करोड़ रुपये का विनियोग हुआ इस नीति के क्रियान्वयन में पक्षपात, अनावश्यक विलम्ब एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा क्योंकि सरकारी हस्तक्षेप की नीति ने पुलिस मनोवृत्ति का परिचय दिया। बढ़ते सरकारी नियन्त्रण से भी उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार में विलम्ब हुआ। कुछ स्वतन्त्रता प्रेमी पूँजीपति एवं निरकुश विदेशी पूँजीपति राष्ट्रीयकरण के भय से आतंकित रहे। श्रम और पूँजी सम्बन्धों में भी विशेष सुधार नहीं हुआ।

इन आलोचनाओं के बावजूद यह कहना न्यायसंगत है कि औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1951 के कारण सरकार का उद्योगों के विनास एवं विस्तार पर भी प्रभावी नियन्त्रण रहा। सावजनिक क्षेत्र में आधारभूत उद्योगों की प्रगति ने भावी विकास का मार्ग प्रशस्त किया। निजी क्षेत्र को तही दिशा में बढ़ने का मार्ग-दर्शन मिला। यह एक सुनिश्चित एवं सुनियोजित औद्योगिक नीति थी जिसमें उन सब पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया था जिनसे औद्योगिक उत्पादन बढ़े, पूँजी एवं श्रम में मधुर सम्बन्ध बढे तथा औद्योगीकरण का मार्ग प्रशस्त होने की पूरी व्यवस्था थी।

### भारत में 1956 की औद्योगिक नीति

(Industrial Policy of 1956)

भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगीकरण तथा आधारभूत उद्योगों के सुदृढ़ आधार हेतु सरकार ने 1948 की औद्योगिक नीति में सामयिक परिवर्तन कर 1956 की औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस नीति की आवश्यकता अनेक कारणों से महसूस हुई जिनमें निम्न प्रमुख थे—

(i) भारतीय संविधान में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापक विस्तार एवं उत्पादन के समान वितरण को महत्वपूर्ण स्थान देना था।

(ii) समाजवादी समाज की स्थापना के लिये औद्योगिक नीति सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापक विस्तार व निजी क्षेत्र पर प्रभावी नियन्त्रणों की आवश्यकता बढ गई थी।

(iii) समुचित क्षेत्रीय विकास की जो उपेक्षा 1948 की नीति में थी उसे दूर करने के लिए 1956 की औद्योगिक नीति जरूरी हो गई।

(iv) द्रुत औद्योगीकरण—द्वितीय योजना में औद्योगीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दिये जाने से हुई औद्योगिक नीति जरूरी हुई।

(v) भय एवं शक्तियों का निवारण करने के लिए 1956 की सुनिश्चिन्त नीति आवश्यक हुई।

(vi) औद्योगीकरण की बाधाओं का निराकरण करने के लिए भी 1956 की नीति की आवश्यकता महसूस हुई।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बदरी परिस्थितियों के लिये समायोजन तथा

तीव्र औद्योगीकरण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ही 30 अप्रैल 1956 को तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वतन्त्र भारत की दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की।

### 1956 की औद्योगिक नीति की विशेषताएँ

( Salient Features of Industrial Policy of 1956 )

1956 की औद्योगिक नीति समाजवादी, प्रगतिशील, स्पष्ट एवं सुनिश्चित थी। इस नीति के उद्देश्य बड़े व्यापक थे। इसमें न केवल सार्वजनिक क्षेत्र के तीव्र विस्तार की व्यवस्था थी बल्कि निजी क्षेत्र पर प्रभावी नियन्त्रण के साथ-साथ द्रुत गति से औद्योगीकरण का मार्ग प्रशस्त करने का लक्ष्य था। इस नीति में 1948 की नीति के मुकाबले कई विशेषताएँ थी —

1 उद्देश्य—इस नीति के उद्देश्य बड़े व्यापक थे जिसमें (i) सार्वजनिक क्षेत्र के तीव्र विकास एवं विस्तार, (ii) आधारभूत एवं भारी उद्योगों का सुदृढ़ आधार तैयार करना, (iii) एकाधिकारी एवं केन्द्रीयकरण की प्रवृत्तियों पर रोक, (iv) विकासोन्मुखी सहकारी क्षेत्र का उत्तरोत्तर विकास करना, (v) आय तथा सम्पत्ति के वितरण में असमानता को कम करना तथा (vi) द्रुत औद्योगीकरण द्वारा समाजवादी समाज की स्थापना करना आदि उल्लेखनीय हैं।

2 उद्योगों का तीन श्रेणियों में वर्गीकरण—1956 की नीति में वृहत् उद्योगों को तीन लोचपूण श्रेणियों में विभाजित किया गया—

(i) अनुसूची "अ" (Schedule A)—इस अनुसूची में सामरिक महत्व, सार्वजनिक उपयोगिता, आधारभूत परिवहन क्षेत्र तथा खनिज उद्योगों में से 17 उद्योगों का समावेश था जिनके विकास व नई इकाइयों की स्थापना पूर्ण रूपेण सरकार का दायित्व रहा गया। इसमें अस्त्र-शस्त्र, अणु शक्ति, लोह इस्पात उद्योग, भारी मशीनें व बिजली के यन्त्र, कोयला, खनिज तेल, सोना, मैंगनीज, लोहा, हीरे, आदि खनिज, रेल, जहाज एवं वायु परिवहन, अणु-शक्ति के खनिज, टेलीफोन, तार, बेतार का सामान आदि का समावेश था।

(ii) अनुसूची "ब" (Schedule B)—इस अनुसूची में 12 उद्योगों का समावेश था जिनको अन्ततः केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के नियन्त्रण में लेने की व्यवस्था थी। नई इकाइयों की स्थापना का अधिकार सरकार के पास होते हुए भी निजी साहसियों को भी समानान्तर कार्य करते रहने का अवसर था। इस अनुसूची में मशीन टूल्स, साद, कृत्रिम रबर, रासायनिक उद्योगों की आधारभूत सामग्री, रासायनिक घोल, समुद्री एवं सड़क यातायात, एल्यूमिनियम एवं अलौह-धातुएँ आदि का समावेश था।

(iii) अन्य उद्योग—शेष सभी उद्योग तृतीय श्रेणी में रखे गये जिनके विकास एवं विस्तार का दायित्व निजी क्षेत्र पर डाला गया। इनके सहयोग के लिए राज-कोषीय एवं वित्तीय नीतियों में उदारता की व्यवस्था थी।

सरकार द्वारा उद्योगों का यह श्रेणीकरण कठोर न होकर बड़ा व्यावहारिक एवं लाक्षणिक था। अलग अलग मूचियाँ होने पर भी विभिन्न उद्योगों की परस्पर निर्भरता के कारण सावजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों में गहरे सम्बन्ध का प्रावधान था।

3 क्षेत्रीय असमानता में कमी एवं सन्तुलित विकास को बढ़ावा—इस नीति में ग्राम्यव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र—कृषि, उद्योग परिवहन एवं व्यापार के सन्तुलित विकास के साथ साथ क्षेत्रीय असमानता में कमी की व्यवस्था नीति की मुख्य विशेषता थी।

4 सद्भाव एवं सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध—इसके लिए नीति में श्रमिकों को लाभ में सहभागिता, श्रम सन्तुष्टि में सुधार श्रमिकों को औद्योगिक मंचालन में हाथ बढ़ाने तथा औद्योगिक विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से निपटाने की पर्याप्त व्यवस्था थी।

5 कुटीर एवं लघु उद्योगों की बढ़ती भूमिका को स्वीकार किया गया ताकि उत्पादन एवं रोजगार में तेजी से वृद्धि हो और राष्ट्रीय औद्योगिक शक्ति को केन्द्रीकरण पर रोक लगे। लघु उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक वस्तियों का निर्माण, लघु एवं कुटीर उद्योगों का मस्ती बिजली, मुद्रिघाटन एवं उद्पादन विधियों में सुधार तथा बरो में रियायतों की व्यवस्था थी। प्रतिस्पर्धा से बचाव हेतु बड़े उद्योगों से तालमेल करना था।

6 प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध कुशलता—इस नीति में औद्योगीकरण की सफलता के लिए प्राविधिक शिक्षा, कुशल प्रबन्ध एवं पर्याप्त प्रशिक्षण पर जोर दिया गया तथा तदनुसार विश्वविद्यालयों एवं विशिष्ट संस्थानों में प्रशिक्षण की सुविधाएँ बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। सरकारी उद्योगों की व्यापारिक सिद्धान्तों पर संचालित करने तथा अधिकारों के विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था की गई।

7 विदेशी पूँजी एवं साहस के भय का निवारण करने के लिए पंडित नेहरू की 1949 की घोषणा को आधार बनाया गया कि विदेशी पूँजी एवं स्वदेशी पूँजी में कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। इन विशेषताओं के प्रयत्नों से स्पष्ट होता है कि इस नीति में तीव्र औद्योगीकरण हेतु सावजनिक एवं निजी क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग एवं निर्भरता पर जोर दिया गया। क्षेत्रीय विषमताओं के समाधान लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास श्रम तथा पूँजी में सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध तथा राष्ट्र हित की दृष्टि से निजी क्षेत्र के औद्योगिक कारखानों के नियमन एवं नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था सामयिक थी। कुछ विद्वानों ने इस नीति में भी कमियों की धार सकेत दिया है।

1956 की औद्योगिक नीति की सफलताएँ एवं उपलब्धियाँ  
(Success & Achievements of Industrial Policy of 1956)

1956 की औद्योगिक नीति काफी सीमा तक अपने उद्देश्यों में सफल रही।



इस नीति के क्रियान्वयन से सन्तुलित एवं द्रुत औद्योगीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ तथा भावी विकास के लिए आधारभूत उद्योगों का सुदृढ़ आधार तैयार हुआ। एकाधिकारी प्रवृत्तियों के समापन एवं औद्योगिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर जोर रहा। लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास में तेजी आई तथा बहुत कुछ सीमा तक श्रम एवं पूँजी में सद्भाव बनाया गया। इस नीति की उपादेयता उसकी निम्न सफलताओं में परिलक्षित होती है—

1 औद्योगिक विकास में तेजी—1956 की औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन से औद्योगिक उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई। 1956 के आधार वर्ष पर औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक 100 से बढ़कर 1965-66 में 181 तथा 1977 तक 260 तक पहुँच जाने की आशा है। जहाँ 1955-56 में औद्योगिक विकास की दर 4% थी वह 1976-77 में 10.4% पहुँच गई। 1977-78 में औद्योगिक उत्पादन 5-6% बढ़ा है।

2 औद्योगिक विनियोग में निरन्तर वृद्धि—इस नीति के कारण सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में विनियोग निरन्तर बढ़ता ही गया। जहाँ प्रथम योजना में विनियोग 288 करोड़ रुपये था वहाँ पाँचवी योजना में विनियोग 16,660 करोड़ रुपये का प्रावधान था जैसा निम्न तालिका 1 में स्पष्ट है।

3 सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से विस्तार—समाजवाद के स्वप्न को साकार करने के लिए इस नीति के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से विस्तार किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र पर औद्योगिक विकास का अधिक दायित्व होने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग काफी बढ़ा जैसा निम्न तालिका में स्पष्ट है—

उद्योगों में विनियोग

क्षेत्र	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना	चतुर्थ योजना	पाँचवी योजना
सार्वजनिक क्षेत्र	55	938	1520	3729	9600
निजी क्षेत्र	233	850	1050	2000	7000

4 सार्वजनिक उपक्रमों में वृद्धि—सार्वजनिक उपक्रमों (Public Enterprises) में जहाँ 1950-51 में सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या 5 थी और उनमें कुल 29 करोड़ रुपये पूँजी विनियोग था वहाँ 1960-61 में उनकी संख्या 48 तथा 1978-79 में 155 पहुँच गई तथा उनमें पूँजी विनियोग भी क्रमशः 2415 करोड़ रुपये तथा 13500 करोड़ रुपये हो गया। स्पष्ट है कि सार्वजनिक उपक्रमों की बढ़ती संख्या से समाजवाद का आधारशिला मजबूत हुई है।

5 आधारभूत एवं मूलभूत उद्योगों का सुदृढ़ आधार—1956 की नीति के क्रियान्वयन से देश में आधारभूत उद्योगों का सुदृढ़ आधार तैयार हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र में 3000 करोड़ पूँजी विनियोग से पाँच लोह इस्पात कारखाने खोले गये। भोपाल में हैवी इलेक्ट्रॉनिक कारखाना, टोम्बे तथा रावत भाटा ग्रुप मट्टिया,

उदयपुर का जिंक स्मेल्टर, भेतडी का तांबा शोधक कारखाना, राची, पिर्गौर व बंगलौर के मशीन टूल्स कारखाने, चितरजन तथा चारानसी के रेल इंजिन कारखाने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हैं। पिछले 22 वर्षों में आधारभूत उद्योगों के उत्पादन में 200 से 600 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जहाँ 1950-51 में लोह-इस्पात का उत्पादन 10.4 लाख टन था वह 1977-78 में 77.3 लाख टन हो गया। सीमेंट का उत्पादन भी 27 लाख टन से बढ़कर अब 190 लाख टन है। पेट्रोलियम का उत्पादन 2 लाख टन से बढ़कर 230 लाख टन हो गया है। ये 1956 की नीति की सफलता के चोटक ही हैं।

6 आर्थिक विवेकीकरण एवं एकाधिकार पर रोक—इस नीति से औद्योगिक साम्राज्यों की शक्ति घटी। जहाँ 1951 में ACC का सीमेंट उत्पादन में 64% भाग था वह अब घटकर लगभग 15% रह गया है। इसी प्रकार Wimco का माचिस उत्पादन में एकाधिकार था वहाँ अब उसका कुल उत्पादन में लगभग 20% भाग ही है। यद्यपि दल समिति एवं डा. ग्रार क. हजारी ने औद्योगिक सत्ता के कन्द्रीकरण की प्रवृत्ति में वृद्धि के लिए इस नीति को उत्तरदायी ठहराया है किन्तु वास्तव में कर्मचारियों ने व्याप्त अष्टाचार एवं प्रशासनिक अकुशलता के कारण ही औद्योगिक सत्ता के कन्द्रीकरण को बन मिला है।

7 लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर दल दिया गया तदनुसार द्वितीय योजना में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर सार्वजनिक क्षेत्र में 180 करोड़ रु. व्यय किये गये। तृतीय एवं चतुर्थ योजनाओं में भी इनके विकास पर सरकार द्वारा क्रमशः 241 करोड़ रु. तथा 293 करोड़ रु. व्यय किये गये। पाचवीं योजना में भी 388 करोड़ रु. व्यय का अनुमान है। 21-सूत्री कार्यक्रम में 16 लाख लघु उद्योग स्थापित करने का लक्ष्य था। लघु उद्योगों के विकास के लिए सुविधाजनक ऋण, करों में रियायतें व उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा उदार न्य नीति का अनुसरण किया गया है।

8 अनुसंधान एवं प्राविधिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया गया। श्रमिकों के प्रशिक्षणार्थ पोलिटेक्नीक बालेज खोले गये। एपरेन्टिसों की भर्ती व डिप्लोमा कोर्स की भी व्यवस्था की गई है।

9 क्षेत्रीय विषमताओं में कमी के लिए हर प्रयास किया गया। लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापना के लाइसेन्सों में प्राथमिकता दी गई। विशेष ग्यावनें सरकारी अनुदान भी दिया गया। यही कारण है कि राजस्थान एवं उड़ीसा जैसे औद्योगिक पिछड़े क्षेत्र अब काफी विकसित हो गये हैं।

10 नये साहसियों एवं नव प्रागन्तुकों की प्रोत्साहना—इस नीति के अन्तर्गत साहसेन्य देने में नये साहसियों की प्राथमिकता दी गई। इससे जहाँ एक ओर नये

साहसियों को मोका मिला वह दूसरी ओर एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण एवं औद्योगिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण को प्रोत्साहन मिला।

11. विदेशी पूँजी एवं साहस को प्रोत्साहन मिला—जहाँ 1948 में भारत में विदेशी पूँजी विनियोग केवल 265 करोड़ रु के लगभग था वह 1965 में बढ़ कर 936 करोड़ रु हो गया। अब यह लगभग 300 करोड़ रु के लगभग है। विदेशी पूँजीपतियों के साथ सहयोग में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई।

### 1956 की औद्योगिक नीति की आलोचनात्मक समीक्षा (Critical Analysis of Industrial Policy 1956)

यद्यपि 1956 की औद्योगिक नीति के नियाम्बन्धन से भारत में तीव्र औद्योगीकरण हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र में निरन्तर विनियोग बढ़ा, क्षेत्रीय विपन्नताओं में भी कमी आई और भावी औद्योगीकरण हेतु आधारभूत उद्योगों का सुदृढ़ आधार भी तैयार हुआ किन्तु इस नीति में अनेक कमियों का भी भान होता है जिनके कारण वांछित सफलता न मिल सकी और अन्ततः 23 दिसम्बर, 1977 को जनता सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। 1956 की नीति की प्रमुख आलोचनाएँ इस प्रकार थी—

1 निजी क्षेत्र को अत्यधिक संकुचित कर दिया गया—सार्वजनिक क्षेत्र को अत्यधिक व्यापक बनाये जाने के कारण निजी उद्योगपतियों का क्षेत्र बहुत संकुचित कर दिया गया था। यह आलोचना व्यापक नहीं है क्योंकि सरकार ने निजी क्षेत्र को राष्ट्रहित में कार्य करते रहने के लिए प्रेरित किया था तब कि पाँचवी योजना में निजी क्षेत्र का विनियोग 6000 करोड़ रु रहने का अनुमान है जबकि पहली योजना में यह 233 करोड़ रु ही था।

2 राष्ट्रीयकरण का अप्रत्यक्ष भय बना रहा—इस नीति में यद्यपि सरकार ने राष्ट्रीयकरण का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं किया था पर औद्योगिक नीति में यह वाक्य “सरकार का किसी औद्योगिक उपक्रम को हस्तगत करने का अधिकार सदा बना रहेगा।” परीक्षक रूप से राष्ट्रीयकरण की धमकी दी थी इससे निरंकुश प्रेमी निजी उद्योगपतियों व विदेशी साहसियों में भय व्याप्त रहा और वांछित गति से विनियोग न हो सका। वैसे यह भय अनावश्यक था क्योंकि किसी सम्पत्ति को हस्तगत करने का अधिकार संविधान में भी है।

3 विदेशी पूँजी एवं साहसियों में भ्रान्ति व्याप्त रही क्योंकि इस नीति में विदेशी पूँजी के सन्दर्भ में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। यह आलोचना भी बेमानी है क्योंकि 1949 की पण्डित नेहरू की विदेशी पूँजी के सन्दर्भ में घोषणा स्पष्ट थी जिसमें स्वदेशी एवं विदेशी पूँजी में कोई भेद न करने की बात कही गई थी।

4 राजकीय पूँजीवाद को बढ़ावा—सार्वजनिक क्षेत्र के अत्यधिक विस्तार पर बल देने के कारण कुछ आलोचकों ने इसे राजकीय पूँजीवाद की नीति कहा है

किन्तु समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य से प्रेरित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की बढ़ती भूमिका अवश्यम्भावी होती है अतः भारत में भी यह हुआ।

5 एकाधिकारी प्रवृत्तियों में वृद्धि एवं औद्योगिक सत्ता का केन्द्रीकरण बढ़ा जबकि नीति का उद्देश्य औद्योगिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण तथा एकाधिकारी प्रवृत्तियों में कमी करना था। इस आलोचना की सत्यता दत्त समिति व डा. भार के हजारों के प्रतिवेदनों से सिद्ध हो गई है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी यही आलोचना की थी।

6 कठोरता का रख रहा जबकि उद्योगों का विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण सोचपूर्ण रखा जाना था। समाजवाद की धारणा में राष्ट्रहित की सर्वोच्चता भारतीय नेताओं में भी हावी रही अतः निजी क्षेत्र के प्रति कठोर रुख रहा।

इस नीति में समय-समय पर आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक सशोधन भी किये। 1970-1973 तथा 1975 में लाइसेन्स नीतियों में परिवर्तन एवं सशोधन किया गया। 1970 की लाइसेन्स नीति में समुक्त क्षेत्र को माय्यता दी गई। एक करोड़ रु. से कम पूंजी वाले उद्योगों को लाइसेन्स से मुक्त कर दिया। अनुसूची 'अ' के अतिरिक्त अनिवार्य क्षेत्रों में निजी उद्योगपतियों के प्रवेश की अनुमति दे दी गई। आयात नियंत्रण एवं प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन दिया गया। 1973 में बड़े औद्योगिक घरानों (Big Business Houses) की परिभाषा की गई। लघु उद्योगों के आरक्षण की व्यवस्था की गई। 25 अक्टूबर 1975 को 21-सूत्रीय कार्यक्रम की सफल कार्यान्विति के लिए पांचवी योजना में 16 लाख नये लघु उद्योगों की स्थापना, एपरेटिंसों की मर्तों एवं उद्योगों में धर्मिकों की सहभागिता पर जोर दिया गया।

### जनता सरकार की नई औद्योगिक नीति-1977 (New Industrial Policy-1977 of Janata Govt.)

देश में रोजगार प्रदान लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास को अपेक्षाकृत अधिक महत्व देने तथा देश में सन्तुलित एवं विवेचिन्त औद्योगीकरण की दृष्टि से जनता सरकार के केन्द्रीय उद्योग मन्त्री जार्ज फर्नाण्डीज ने 23 दिसम्बर 1977 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। यह नीति मौजूदा औद्योगिक ढांचे में व्याप्त विवृत्तियों एवं व्यावहारिक खामियों को सुधारते हुए लघु उद्योगों की भूमिका निर्धारण करती है। जहां इसमें एक ओर लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास का दृढ़ संकल्प है वहां दूसरी ओर बड़े उद्योगों को अतिरिक्त सम्बल को अनिवार्य मानते हुए उन्हें स्वावलम्बी बनाने की परिकल्पना की गई है। बड़े उद्योगों का नियमन एवं नियंत्रण इस प्रकार किया जायेगा कि बड़े उद्योग छोटे उद्योगों के प्रति प्रतिस्पर्धा व अवरोध की दीवारें नहीं बन सकें।

### नयी औद्योगिक नीति-1977 की आवश्यकता क्यों ?

यद्यपि भारत में 1956 की औद्योगिक नीति के त्रिशत्ययन से देश में तीव्र

औद्योगीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, भावी औद्योगीकरण के लिए आधारभूत उद्योगों का मुण्ड आधार भी बना है किंतु भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अकुशलता तथा नीति का क्रियान्वयन घोषित उद्देश्यों के अनुरूप न होने से बड़े उद्योगों व नयी तकनीक पर अधिक काम हुआ। पूँजी प्रधान एवं आयातित विदेशी तकनीक को अपेक्षाकृत अधिक महत्व मिला, फलतः श्रम प्रधान ग्रामीण लघु एवं घरेलू उद्योगों की उपेक्षा हुई। बड़े उद्योगों के विकास का लाभ चन्द पूँजीपतियों एवं सम्पन्न वर्ग को मिला तथा ऐसी वस्तुओं का ही अधिक उत्पादन बढ़ा जो समाज के विशिष्ट एवं सम्पन्न वर्ग द्वारा उपभोग की जाती थी। संक्षेप में इन कारणों को निम्न प्रकार से पंक्तिबद्ध किया जा सकता है —

1 1956 की नीति का क्रियान्वयन घोषित उद्देश्यों के अनुरूप नहीं रहा—पिछले 10 वर्षों में औसतन औद्योगिक विकास दर 4% ही रही है। प्रति व्यक्ति आय भी 1.5% की वार्षिक दर से बढ़ी है। लघु उद्योगों की उपेक्षा, बेरोजगारी में वृद्धि, विकास का लाभ सम्पन्न वर्ग को मिला। ये ऐसी विकृतियाँ हैं जिनके कारण नई औद्योगिक नीति की आवश्यकता बढ़ी।

2 औद्योगिक विकेंद्रीकरण बोरी कल्पना रही—बड़े औद्योगिक घरानों ने आर्थिक सत्ता पर केन्द्रीकरण एवं एकाधिकारी प्रवृत्तियों को बल दिया।

3 लघु एवं कुटीर उद्योगों की उपेक्षा की गई। यद्यपि 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में लघु एवं कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन की बात थी पर क्रियान्वयन में पूँजी प्रधान एवं आयातित विदेशी तकनीक को अधिक महत्व दिया गया। अतः जनता सरकार ने नई नीति आवश्यक समझी।

4 एकाधिकार एवं औद्योगिक केन्द्रीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति—1956 की नीति में औद्योगिक विकास का लाभ बड़े पूँजीपतियों ने ही अधिक उठाया। बड़े औद्योगिक घराने कई गुना विस्तृत हो गये। यही नहीं उत्पादन पर एकाधिकारी प्रवृत्ति बढ़ी। अतः जनता सरकार ने इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण के लिये नई औद्योगिक नीति की तीव्र आवश्यकता समझी।

5 उत्पादन वृद्धि—देश में 1956 की औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन से पिछले 10 वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में केवल 4% वार्षिक वृद्धि हुई है जबकि जनता सरकार जनता की आकांक्षाओं और आशाओं को मूलरूप देने के लिये 8 से 10% औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य रखती है अतः वर्तमान नीति में परिवर्तन आवश्यक हो गया।

■ कृत्रिम अभाव को समाप्त कर उचित वितरण की व्यवस्था हेतु नई नीति की आवश्यकता हुई। पहले एकाधिकारी शक्तियों द्वारा कम उत्पादन करके अधिक मुनाफा कमाने और कृत्रिम अभाव पैदा करने के हथकण्डे अपनाये जाते थे। इन विवृत्तियों को दूर करना आवश्यक हो गया।

7 लागतों एवं मूल्यों के विकृत ढाँचे को सुधारने के लिये नयी नीति जरूरी हुई ।

इस प्रकार जनता सरकार ने अगले दस वर्षों में सबको रोजगार देने का जो वायदा किया है उसकी पूर्ति बड़े उद्योगों से संभव न होकर श्रम प्रधान ग्रामीण, लघु एवं कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार एवं विकास में निहित है । इसी प्रकार भारत में आयातित विदेशी पूँजी तथा तकनीक पर आधारित बड़े उद्योगों का विकास देश की भौतिक परिस्थितियों एवं निवासियों की रुचि रुझान के अनुकूल भी नहीं है । इस परिप्रेक्ष्य में तीव्र उत्पादन वृद्धि, औद्योगिक विकेन्द्रीकरण एवं रोजगार अवसरों की वृद्धि के संकल्प के अनुरूप नई औद्योगिक नीति आवश्यक थी ।

### जनता सरकार की औद्योगिक नीति की विशेषतायें (Salient Features of New Industrial Policy of Janata Govt.)

जनता सरकार की नई औद्योगिक नीति ग्रामीण, लघु एवं कुटीर उद्योगों के तीव्र विकास, विकेन्द्रीकरण तथा रोजगार अवसरों में वृद्धि के दृढ़ संकल्प से प्रेरित होने के कारण 1956 की नीति की विकृतियों व व्यावहारिक खामियों को दूर करने के लिये बनाई गई है उसमें निम्न मुख्य विशेषतायें हैं—

1 उद्देश्य—नई औद्योगिक नीति के उद्देश्य बड़े व्यापक एवं समयानुबल हैं । इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं—

- (i) देश के गानवीय एवं भौतिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग ।
- (ii) आवश्यक उपभोक्ता माल के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि ।
- (iii) रोजगार प्रधान लघु एवं कुटीर, ग्रामीण एवं कृषि उद्योगों का तीव्र गति से विकास एवं विस्तार ।
- (iv) आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण एवं एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक ।
- (v) औद्योगीकरण के मौजूदा ढाँचे में व्यावहारिक विकृतियों एवं खामियों का निराकरण करते हुए तीव्र गति से औद्योगिक विकास ।
- (vi) उद्योगों की सामाजिक आशाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप ढालना ।
- (vii) अनुसंधान एवं विकास में आधुनिक तकनीक का राष्ट्रहित में उपयोग ।

2 आरक्षित उद्यम—लघु एवं कुटीर उद्योगों को बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिये आरक्षित उद्यमों की संख्या 180 से बढ़ाकर अब नई नीति में 805 कर दी गई है । इन उद्यमों पर कम लागत पर स्वीकार्य प्रतिमान का उत्पादन का दायित्व रहेगा । इस प्रकार आरक्षित उद्यमों की संख्या में 625 की वृद्धि उल्लाह-वर्द्धक है । इस सूची में निरन्तर समीक्षा करते रहने की भी व्यवस्था की गई है ।

3 बहुत छोटे उद्यमों (Tiny Sector) को विशेष सुविधायें प्रदान करने हेतु लघु उद्योग की विद्यमान परिभाषा तो बनी रहेगी । इसके अन्तर्गत बहुत छोटे क्षेत्र जिनमें मशीनों व उपकरणों का विनियोजन एवं साख रु तक है और जो 1971 की जनगणना के अनुसार 50 हजार से कम जनसंख्या वाले नगरो या गावों में

स्थापित किये गये हैं उन्हें विशेष सुविधायें—वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन आदि विशेष सहायता दी जायेगी।

4. कुटीर एवं घरेलू उद्योगों के संरक्षण एवं नये उद्योगपतियों को प्रोत्साहन—नई नीति में सरकार द्वारा कुटीर एवं घरेलू उद्योगों के हितों की रक्षा एवं संरक्षण के लिये विशेष विधान बनाने की व्यवस्था है क्योंकि अब तक लघु उद्योगों की ही संरक्षण व्यवस्था थी। कुटीर एवं घरेलू उद्योगों को कोई विशेष संरक्षण नहीं दिया गया था। इसी प्रकार इस नीति में उद्योगपतियों को कारोबार खोलने के लिये प्रोत्साहन हेतु एक विधेयक पारित किया जायगा।

5. जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना—लघु तथा ग्रामोद्योगों की सभी आवश्यकताओं के बारे में कार्यवाही एवं सहयोग देने के लिये प्रत्येक जिले में एक उद्योग केन्द्र स्थापित किया जायगा। ये केन्द्र जिले में उपलब्ध कच्चे माल तथा अन्य साधनों का अधिक अन्वेषण, मशीनों एवं उपकरणों की आपूर्ति, कच्चे माल की व्यवस्था, उधार देने की व्यवस्था करना, प्रभावी विपणन व्यवस्था, किस्म नियंत्रण, अनुसंधान एवं विस्तार के लिये एक प्रकोष्ठ की स्थापना करना आदि सभी कार्य करेंगे। लघु उद्योगों से भिन्न कुटीर एवं घरेलू उद्योगों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जिला केन्द्र में एक अलग विंग होगा। ये जिला केन्द्र एक और विकास खण्डों से सम्पर्क रखेंगे तथा दूसरी ओर विशिष्ट मस्थानों—जैसे लघु उद्योग सेवा मस्थान से भी सम्बद्ध रहेगा। इस वर्ष जनता सरकार ने 180 जिला केन्द्र स्थापित करने का निश्चय किया है और 1979 के अन्त तक 460 जिला उद्योग केन्द्र स्थापित हो जायेंगे। जनता सरकार द्वारा अगले चार वर्षों में सभी जिलों में ऐसे केन्द्र स्थापित हो जायेंगे अर्थात् राज्य सरकारों को समुचित वित्तीय एवं सगठनात्मक सहायता उपलब्ध करने की व्यवस्था की जायेगी।

6. विकास बैंक खण्ड—लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकासार्थ प्रभावी वित्तीय सहायता उपलब्ध करने के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank of India) में एक अलग खण्ड (wing) खोलने की व्यवस्था कर ली गई है। यह खण्ड सभी प्रकार के वित्तीय सुविधाओं के समन्वय में मार्गदर्शन, समन्वय एवं व्यवस्था का काम करेंगे। राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे लघु, कुटीर एवं घरेलू उद्योगों को निश्चित अनुपात में ऋण मुहैया करेंगे।

7. खादी-ग्रामोद्योग की बढ़ती भूमिका—इस नीति में खादी ग्रामोद्योग की भूमिका को समुचित महत्व दिया गया है। कलहाल में खादी-ग्रामोद्योग आयोग के क्षेत्र में 22 उद्योग ही होते थे पर अब यह आयोग ग्रामोद्योगों के विकास के लिये आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने तथा आधुनिक प्रबन्ध व्यवस्था विकसित करने के लिये योजनाएँ बनायेगा जिनमें साबुन एवं जूतों के उद्योग विशेष रहेगे। नयी खादी के उत्पादन में पोलिस्टर धागे का उपयोग सम्बन्धी प्रयोग किया जायेगा।

जनता की कपड़े की आवश्यकता की पूर्ति हैण्डलूम क्षेत्र में बढ़ायी जायेगी। मिल क्षेत्र एवं शक्ति संचालित कर्षों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जायेगी।

8 बड़े उद्योगों के सम्बन्ध में व्यावहारिक दृष्टिकोण—नई औद्योगिक नीति में संगठित बड़े उद्योगों के बारे में पूर्णतः व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। वे अब प्रदर्शनात्मक दृष्टि से बहुत बड़े तथा अनावश्यक विदेशी तकनीकी से अभिभूत नहीं होंगे। उन्हें छोटे एवं कुटीर उद्योगों के लिये बाधक नहीं बनने दिया जायेगा। अब इस नीति में बड़े उद्योगों का कार्यक्षेत्र फिर से परिभाषित किया गया है—

(i) बुनियादी उद्योग (Basic Industries)—ये वे उद्योग हैं जो अर्थव्यवस्था के लिये आवश्यक संरचना (Infrastructure) निर्माण करते हैं तथा लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को विकास करने के लिये जरूरी हैं जैसे इस्पात, असोह धातुएं, सीमेंट, तेल शोधक कारखाने आदि।

(ii) पूंजीगत सामान उद्योग (Capital Goods Industries)—जो बुनियादी एवं छोटे उद्योगों के लिये मशीनें बनाते हैं।

(iii) उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योग (High Technology Industries)—जिनमें बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकता होती है तथा जो कृषि तथा लघु स्तर के औद्योगिक विकास जैसे खाद, कीटनाशक दवाइयों तथा पेट्रोरसायन आदि से सम्बन्धित हैं।

(iv) अन्य उद्योग जो लघु क्षेत्र उद्योगों की आरक्षित भूमि से बाहर हैं और जिन्हें अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिये जरूरी समझा जाता है जैसे मशीनरी, औजार, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन उद्योग।

9 बड़े औद्योगिक घरानों पर प्रभावी नियन्त्रण—1956 की नीति से बड़े औद्योगिक गृहों की अनुपात से अधिक वृद्धि पर नियन्त्रण में बाधित सफलता नहीं मिली। बड़े उद्योग समूहों का विकास उनके आन्तरिक साधनों से नहीं बल्कि उनके द्वारा बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के ऋणों पर आधारित रहा। अब उस प्रक्रिया को बदलने के लिये नई औद्योगिक नीति में अर्थव्यवस्था के लिये बड़े औद्योगिक गृहों (Large Industrial Houses) का विस्तार निम्न मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जायेगा—

(i) मौजूदा उपक्रमों का विस्तार एवं नये उपक्रमों की स्थापना दोनों एकाधिकार तथा प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हो सकेगा।

(ii) जो उद्योग इस समय समता की स्वन वृद्धि करने योग्य हैं उनके अभाव में विद्यमान उपक्रमों द्वारा नयी वस्तुओं का उत्पादन करने तथा बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा नये उपक्रमों की स्थापना करने के लिये सरकार के विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता होगी।



(iii) बड़े औद्योगिक गृहों को अपनी नई या विस्तार सम्बन्धी परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था के लिये अपने स्वयं के साधनों पर ही निर्भर करना होगा। पूँजी प्रधान कुछ उद्योगों जैसे उर्वरकों, कागज, सीमेंट, जहाजरानी तथा पेट्रो रसायन आदि के मामले में उपयुक्त ऋण इक्विटी के लिये अनुमति दी जायेगी बशर्तें सार्वजनिक वित्त सस्याओं पर उनकी निर्भरता कम हो।

बड़े औद्योगिक घरानों के कार्य-कलापों को देश के आर्थिक-सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप लाने के लिये सरकार अपनी लाइसेंस नीति को विनियमित करेगी।

(iv) लघु उद्योगों के क्षेत्र के लिये प्रारक्षित।

10 सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका—नयी औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र पर काफी दायित्व डाला गया है अतः उसे अर्थव्यवस्था में बढ़ती भूमिका निभानी होगी। इस क्षेत्र में न केवल बुनियादी किस्म का महत्वपूर्ण उत्पादन होगा वरन् जन साधारण के लिये आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति बनाये रखने के लिए भी उनका प्रयोग एक स्थायी शक्ति के रूप में कारगर ढंग से किया जायेगा। यह क्षेत्र विविध सहायक उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन तबनीक एवं प्रबन्ध व्यवस्था भी उपलब्ध करेगा। यह क्षेत्र अब एक सफेद हाथी के रूप में न रह कर कार्यकुशल, लागत में कमी तथा उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र से लोहा ले सकने की स्थिति में होगा। सरकारी क्षेत्र में प्रबन्धकों का एक व्यावसायिक सवर्ग बनाने को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

11 स्वदेशी एवं विदेशी प्रौद्योगिकी (Technology)—भविष्य में भारतीय उद्योगों का विकास यथासम्भव देशी प्रौद्योगिकी (technology) पर निर्भर करेगा क्योंकि अन्ततः स्वदेशी तकनीक ही सस्ती एवं कारगर साबित होती है। फिर भी विशिष्ट क्षेत्रों में विदेशी प्रौद्योगिकी (foreign technology) का रास्ता खुला रहेगा और देश की आवश्यकता के अनुरूप ऐसी प्रौद्योगिकी को अनुकूलित किया जायेगा। जिन भारतीय कम्पनियों को विदेशी प्रौद्योगिकी आयात करने की अनुमति दी जाती है उन पर पर्याप्त अनुसन्धान एवं विकास सुविधायें स्थापित करने का दायित्व रहेगा ताकि आयातित प्रौद्योगिकी को अनुकूलित अथवा आत्मसात किया जा सके।

12 विदेशी विनियोजन एवं सहभागिता—नई औद्योगिक नीति में विदेशी निवेश तथा विदेशी कम्पनियों की सहभागिता को राष्ट्रीय हितों के अनुरूप बनाया जायेगा। विद्यमान विदेशी कम्पनियों पर विदेशी मुद्रा विनिमय कानून को सख्ती से लागू किया जायेगा और विदेशी इक्विटी को कम करने की प्रक्रिया पूरी होने पर 40% से अधिक प्रत्यक्ष अथवा वासी निवेश न रखने वाली कम्पनियों को भारतीय कम्पनियों के समकक्ष विस्तार की अनुमति होगी। पूर्ण स्वामित्व रखने की इच्छुक विदेशी कम्पनियों को अब भारत में कोई स्थान नहीं है जैसे कोका-कोला एवं आई. बी. एम.।

**13. औद्योगिक आत्मनिर्भरता—**औद्योगिक एवं आर्थिक नीति का सर्वोच्च उद्देश्य आत्मनिर्भरता की प्राप्ति है इसलिए नयी नीति में सुदृढ़ एवं विविधापूर्ण औद्योगिक आधार तैयार करने की व्यवस्था है। इसके लिए सरकार भारतीय उद्योगों को अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति एवं प्रौद्योगिकी में सुधार के लिए सभी सहायता प्रदान करेगी।

**14 सन्तुलित क्षेत्रीय विकास को महत्वपूर्ण माना गया है** घट विभिन्न क्षेत्रों के बीच विकास स्तर की असमानताओं को तेजी से कम किया जायेगा। इसके लिए 1971 की जनगणनानुसार दस लाख से अधिक आबादी वाले महानगरीय क्षेत्रों को निश्चित सीमाओं तथा 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में नये औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये अनुमति नहीं दी जायेगी और जिन उद्योगों में लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं उन्हें राज्य तथा वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता न देने पर जोर दिया जायेगा जबकि घनी आबादी वाले महानगरीय व शहरों से पिछड़े क्षेत्रों को स्थानान्तरित होने वाले बड़े उद्योगों की आर्थिक सहायता पर विचार किया जायेगा।

**15 कर्मचारियों की सहभागिता—**देश में उपलब्ध मानवीय शक्ति के सदुपयोग का पूरा प्रयास रहेगा। औद्योगिक इकाइयों की अगली पीढ़ी में सहभागिता और कर्मशाला स्तर से संचालन स्तर तक निर्णय करने में कारीगरों को सम्बद्ध होना कार्यकुशलता एवं उत्पादन वृद्धि में प्रयुक्त किया जायेगा।

**16. सकटग्रस्त बीमार मिलें—**औद्योगिक क्षेत्र में सकटग्रस्तता की बढ़ती प्रवृत्ति का देखते हुए नई औद्योगिक नीति में यह प्रावधान किया गया है कि काफी जाब पड़ताल के बाद ही सकटग्रस्त इकाइयों को सरकार अपने हाथ में लेगी। सरकार यह भी सोच रही है कि जो प्रबन्धक या मालिक, कुप्रबन्ध के लिए जिम्मेदार पाये जाते हैं उन्हें दूसरी मिलों के प्रबन्ध में कोई भूमिका निभाने से वंचित किया जा सके।

इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि जनता सरकार की नई औद्योगिक नीति यही मामूली एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण पर आधारित है। देश में उत्पादन वृद्धि विकेंद्रीकरण एवं रोजगार अवसरों में पर्याप्त वृद्धि हेतु लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास एवं विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है। बड़े उद्योगों में स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर जोर दिया गया है तथा बड़े औद्योगिक घरानों के प्रभावी नियन्त्रण की व्यवस्था है। सार्वजनिक क्षेत्र पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का दायित्व है।

### नयी औद्योगिक नीति की आलोचनाएँ एवं शिकायतें (Criticisms of New Industrial Policy)

यद्यपि जनता सरकार की नई औद्योगिक नीति के अनेक दम वषों में सत्रह। रोजगार गृह्या करन के उद्देश्य से लघु एवं कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों के

## भारत में औद्योगिक नीति एवं लाइसेन्स नीति

विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है फिर भी इस नीति की कई कमियाँ, शिकायतें एवं आलोचनाएँ हैं जो संक्षेप में इस प्रकार हैं—

1 लघु उद्योगों की व्याख्या अस्पष्ट—औद्योगिक नीति में वर्णित लघु उद्योगों के लिए आरक्षण, वित्तीय सहायता, करों में रियायतें तथा अन्य सुविधाओं का सही इस्तेमाल किये जाने के लिए यह व्याख्या जरूरी है कि लघु उद्योगों में किन-किन को सम्मिलित किया जायगा। लघु उद्योगों के द्वारा फिलहाल लगभग 2400 वस्तुओं का निर्माण होता है। उनमें से केवल 805 वस्तुओं के लिए ही आरक्षण के पीछे कौन-सा तर्क है।

2 लघु उद्योगों की व्यावहारिक कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया गया है—आजकल उत्पादन, विक्रय तथा आय पर इतने अधिक नियम, उपनियम तथा कानून लागू होते हैं कि उन्हें लागू करने में सामान्यतः नये उद्यमियों का लगभग 22 निरीक्षकों एवं अधिकारियों से पाला पड़ना है जो आमतौर पर उद्योगों के विकास में उत्सुक न होकर कथिन अनियमितताओं को पकड़ने में रुचि रखते हैं। भारतीय लघु उद्योग संघ के उपाध्यक्ष नरेन्द्र शास्त्री के अनुसार यह एक प्रकार का नया पटवारी वर्ग है जिसका वेतन कम पर आय अधिक है। लघु उद्यमी सामान्यतः अनुभवहीन, नियमों उपनियमों से अनभिज्ञ तथा अर्द्ध शिक्षित होता है और वह नियमों के शिकंजे में निरन्तर फँसता ही जाता है अतः लघु-उद्योगों के सामने इन व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने की व निषेधो-उपनियमों को सरल बनाने की आवश्यकता है।

3 लघु उद्योग श्रम नीति में परिवर्तन का औद्योगिक नीति में कोई प्रावधान नहीं है। चूँकि लघु उद्योगों के श्रम मालिक सम्बन्ध अधिक मानवीय एवं धनिक होते हैं कि जटिल श्रम नियमों की आवश्यकता ही नहीं रहती और न उनके पालन की क्षमता ही होती है।

4 बड़े उद्योग और आधुनिक ढंग के उद्योगों की उपेक्षा—कुछ आलोचकों ने देश में स्वदेशी तकनीक के प्रयोग पर जनता सरकार के जोर व विदेशी प्रौद्योगिकी पर नियन्त्रण की नीति से देश आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से वंचित रह जायेगा।

■ विदेशी विनियोजकों एवं कम्पनियों को धक्का लगा है। वे अब भारत में अधिक पूँजी विनिवेश के लिये प्रेरणास्पद नहीं होगी। ये आलोचनाएँ अधिक वजनी नहीं हैं क्योंकि सरकार स्वयं उनके प्रति जागरूक है।

नई औद्योगिक नीति बड़ी व्यापक, सामयिक एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण पर आधारित है। इस नीति में औद्योगिक विकास की गति को तेज करने, उत्पादन एवं कारीगरों की आय में वृद्धि तथा रोजगार में वृद्धि के जो उद्देश्य हैं उनके लिये लघु, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया है। उन्हें विकास के लिए पर्याप्त अवसर एवं सुविधाएँ दी जायेंगी। बड़े उद्योगों को छोटे उद्योगों व

विकास में बाधाये खड़ी करने का अवसर नहीं दिया जायेगा। विदेशी पूँजी एवं अयाधिन प्रौद्योगिकी को हतोत्साहित कर देश में आत्म निर्भरता को धोर प्रयास किया जायेगा।

### औद्योगिक लाइसेन्सिंग नीति (Industrial Licencing Policy)

निजी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना, विस्तार एवं विकास का नियमन एवं नियंत्रण करने के लिये औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1951 पारित हुआ था। उसमें 1952 में संशोधन कर इसे व्यापक बनाया। इस अधिनियम में यह व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार से लाइसेन्स प्राप्त किये बिना कोई नई औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं की जा सकती अथवा प्वालू प्लांट का काफी विस्तार नहीं किया जा सकता। इस अधिनियम में लाइसेन्स समिति (Licencing Committee) की भी व्यवस्था है। भारत की औद्योगिक लाइसेन्स नीति में समय समय पर संशोधन होते रहे हैं जिनमें 1970, 1973, 1975, और 1978 के संशोधन उल्लेखनीय हैं। भारत में औद्योगिक लाइसेन्स नीति में मुख्य विशेषणाएँ निम्न हैं —

1. लाइसेन्सिंग हेतु उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है (i) अनिवार्य क्षेत्र में निजी उद्योगपतियों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी (ii) मध्यम क्षेत्र में 3 करोड़ से 5 करोड़ रु० पूँजी विनियोग वाले उद्योग गिने जायेंगे तथा (iii) लाइसेंस मुक्त क्षेत्र अब तीन करोड़ रु० से कम पूँजी वाले उद्योगों को लाइसेन्स से मुक्त कर दिया गया है।

2. संयुक्त क्षेत्र की मान्यता—सरकार ने संयुक्त क्षेत्र को सैद्धान्तिक मान्यता दे दी है जिसके अनुसार सरकार वित्तीय संगठनों द्वारा बड़ी परियोजनाओं की अधिक मात्रा में वित्तीय व्यवस्था करने की अवस्था में इन परियोजनाओं की साख नीति एवं प्रबंध में हिस्सा तथा ऋणों को अग्र पूँजी में बदलने का अधिकार होगा।

3. देश के औद्योगिक उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु आयात नियंत्रण की नीति अपनाई जायेगी। नई आयात-निर्यात नीति में देश में आयात प्रतिस्थापन को ध्यान में रखते हुए उदारता रखी गई है कि देश के उद्योगों की पूरी क्षमता के उपयोग हो जाने के बाद आवश्यक हुआ तो उपभोक्ताओं के हितों के लिये आयात किया जा सकेगा।

4. एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर कठोर नियंत्रण—सरकार आर्थिक सत्ता के विवेन्द्रीकरण हेतु नई लाइसेन्स नीति में “बड़े औद्योगिक गृहों” की पुनः परिभाषा में अब 20 करोड़ रु० से अधिक परिसम्पत्ति वाले व्यवसायिक गृहों को भी शामिल कर लिया है जबकि 1970 की लाइसेन्स नीति में यह सीमा 35 करोड़ रु० थी। अब उन्हें अपने विस्तार, लाइसेन्स मुक्त क्षेत्र में भी इकाइयाँ स्थापित करने पर लाइसेन्स लेना होगा।

5. लघु उद्योगों के आरक्षण की व्यवस्था को विस्तृत किया गया है अब 504 वस्तुओं के उत्पादन में छोटे एवं लघु एवं कुटीर उद्योगों को आरक्षण मिल सकेगा। किन्तु जनता सरकार ने आवश्यकानुसार आयात की उदारता का हल अपनाया है।

6. विदेशी बड़ी तथा MRTP कंपनियों को 5 करोड़ रु की समस्त पूँजी विनियोग की व्यवस्था के कानून का पालन करना होगा जबकि दूसरे उद्योगों के लिये इसे हटा दिया गया है। अब बड़े औद्योगिक गृहों को भी पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने में उदारता का हल अपनाया जा सकेगा।

अब नई लाइसेंस नीति में औद्योगीकरण की गति तेज करने तथा विदेशी विनियोगों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त उदारता एवं सरलता प्रदान की गई है। अब आशयपत्र, विदेशी सहयोग एवं पूँजीगत सामान सम्बन्धी आदेशनों को 90 दिन में निपटाने की व्यवस्था अपनाई जायेगी। पूँजीगत सामान प्राप्ति के लिए सरलीकरण किया गया है। बड़े औद्योगिक गृहों को भविष्य में केवल प्रमुख क्षेत्रों में ही औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने की अनुमति दी जा सकेगी।

इस प्रकार नई औद्योगिक एवं लाइसेंस नीतियों में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, विनियोगों को प्रोत्साहन छोटे उद्योगपतियों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर बड़े औद्योगिक गृहों पर कठोर नियन्त्रण, निर्यात सम्बंधन एवं आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को रोकने के प्रयास हैं। इससे देश में औद्योगीकरण की गति तेज होगी व विदेशी पूँजी को नया आकर्षण रहेगा।

# भारत में औद्योगीकरण एवं औद्योगिक विकास की मुख्य प्रवृत्तियाँ

(Industrialisation & Main Trends in Industrial Growth of India)

प्राज विश्व के सभी विकासशील राष्ट्रों में औद्योगीकरण की-होड़ सी लगी है और वे अपने आर्थिक विकास का दीर्घकालीन उद्देश्य औद्योगीकरण मान कर अपने अन्तिम लक्ष्य 'आर्थिक सम्पन्नता' की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भारत भी उनमें से एक है। भारत के लघु एवं कुटीर उद्योगों का प्राचीन बड़ा गौरवपूर्ण रहा है और यहाँ तक कहा जाता है कि "जब आधुनिक सभ्यता का जन्म स्थान पश्चिमी यूरोप जंगली कबीलों का निवास स्थान था भारत अपने शासकों की सम्पत्ति तथा पारोगरों की कला-कौशल के लिए विख्यात था।" इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति तथा भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की घातक नीति से भारत की औद्योगिक व्यवस्था धीरे-धीरे नष्ट होने लगी। ब्रिटिश शासनकाल में 18वीं शताब्दी के अन्त तक जो उद्योग अन्तिम सास ले रहे थे वे उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक अपना गौरव पूर्णतया खो बैठे। 1840 से परिस्थितियों के दबाव में आकर अंग्रेज शासकों ने औद्योगीकरण के यदा-कदा कुछ प्रयत्न किये पर आधुनिक ढंग के उद्योगों की स्थापना की सही शुरुआत 1890 के बाद ही हुई। राष्ट्रीय आन्दोलन तथा स्वदेशी की भावना ने भारत में उद्योगों के विकास का मिलसिना पुनः प्रारम्भ किया। 1914 में प्रथम विश्व-युद्ध ने विकास के लिए बाधाकरण तैयार किया, पर युद्ध के तुरन्त बाद उद्योगों की विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 1921-22 में विभेदात्मक सरक्षण की नीति का अनुसरण किया गया। 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी ने समूची अर्थ-व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया। 1930 के बाद चीनी उद्योग को भी सरक्षण दिया गया। 1939 तक स्थिति ढावाडोल हो चल रही थी। फिर द्वितीय विश्व-युद्ध को बिनगारी मड़न उठी। इस युद्धकाल में भारत का औद्योगीकरण बड़ी तेजी से हुआ। उद्योगपतियों ने अब खूब लाभ कमाया तथा तेजी से विस्तार किया। इस प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में थोड़ा बहुत औद्योगिक विकास सरकार की मुनिश्चिन औद्योगिक विकास की नीति से नहीं—बल्कि परिस्थितियों, भारतीय राष्ट्रवादियों तथा राष्ट्रीय भाव से सम्भव हो पाया था। अंग्रेजों ने तो अपने शासन

काल में भारत को कमाल बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। भारत में आधारभूत एवं मूलभूत उद्योगों की स्थापना नाम मात्र की थी।

### स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद औद्योगिक नीति एवं विकास

1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ-साथ देश का विभाजन हुआ। उनका औद्योगीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। भारत सरकार ने अपनी राजनैतिक स्वतन्त्रता के साथ-साथ भारतीय जनता को आर्थिक स्वतन्त्रता, सम्पन्नता तथा विविधता पूर्ण जीवनयापन का सुअवसर प्रदान करने के लिए औद्योगीकरण की आवश्यकता महसूस की। तदनुसार 1948 में स्वतन्त्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गयी। इस नीति में मिश्रित धर्मव्यवस्था को आधार बनाकर औद्योगीकरण के लिए सरकार के सक्रिय योगदान की आवश्यकता जाहिर की। इस नीति को सुचारु रूप से कार्यान्वित करने के लिए 1951 में एक (औद्योगिक विकास एवं नियमन) अधिनियम-[Industrial (Development & Regulation Act)] पारित किया गया।

प्रथम योजना एक कृषि प्रधान योजना थी और इसमें कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। भारत के नियोजित विकास का यह प्रथम प्रभावी प्रयास था। परन्तु इस योजना में औद्योगिक विकास को यथोचित स्थान नहीं दिया गया। औद्योगिक नीति में औद्योगिक विकास का मुहूर्त आधार तैयार करने के लिए लोहा, इस्पात, सीमेंट, खाद, भारी रसायन व बिजली का सामान, मशीनी औजार तथा अल्युमिनियम जैसे आधारभूत एवं बुनियादी उद्योगों की स्थापना की ओर अधिक ध्यान देने का उद्देश्य था।

आर्थिक परिस्थितियों और उद्देश्यों में परिवर्तनों के अनुकूल नीतियों में परिवर्तन एक प्रगतिशील नियोजन का लक्षण है। 1948 की औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद 1950 में भारतीय संविधान में नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकारों की घोषणा और सरकारी विषयक नीति निर्देशों प्रथम योजना में सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों की आश्चर्यजनक प्रगति, 1945 में संसद द्वारा "समाजवादी समाज की स्थापना" का प्रस्ताव पारित किये जाने तथा द्वितीय योजना में उद्योगों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के कारण एक अधिक स्पष्ट, सुनिश्चित और प्रगतिशील औद्योगिक नीति की आवश्यकता हुई। इसलिए 30 अप्रैल 1956 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने संसद में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस नीति में सावजनिक क्षेत्र का बहुत विस्तार कर उसके उत्तरदायित्व में वृद्धि कर दी। इसमें समाजवाद की स्थापना, तीव्रगति से औद्योगीकरण, आधारभूत एवं मूलभूत उद्योगों के विकास से देश के भावी विकास का मुहूर्त आधार तैयार करने तथा एकाधिकार व केन्द्रीयकरण प्रवृत्तियों पर रोक लगाने के उद्देश्य निहित थे। द्वितीय योजना में औद्योगिक विकास की गति तब हुई पर विदेशी विनिमय संकट ने मार्ग में बाधा उपस्थित की। फिर भी द्वितीय योजनाकाल में उद्योगों का खूब विकास हुआ।

समय-समय पर नीति निर्देश दिये गये तथा वित्तीय व्यवस्था की गई। तृतीय योजना में भी औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इसमें भी 1962 में बवंरता पूर्ण चीनी आन्वेषण तथा 1965 में पाकिस्तानी आक्रमण के बावजूद उद्योगों में विकास की वार्षिक दर 7 से 8% तक रही।

1966 तथा 1967 में उद्योगों में शिथिलता (Recession) आ गई। खासतौर से इन्जीनियरिंग उद्योगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सरकार ने उद्योगों के विकास तथा नियन्त्रण के यथासम्भव सब प्रयत्न किये। 1968-69 तक उद्योगों में पुनः चेतना उत्पन्न हुई। शिथिलता का वातावरण समाप्त होने से विकास और विस्तार का दौर शुरू हुआ। जहाँ 1966 में औद्योगिक विकास की दर 1% थी, 1967 में यह और भी कम थी। 1968 में यह पुनः बढ़ कर 6.4% हो गई। 1969 में विकास दर 7.1% थी पर 1970 में घटकर केवल 4.5% ही होने का अनुमान है। 1974-75 में विकास दर 2 से 3% थी जबकि अब 5% से 6% का अनुमान है।

चतुर्थ योजना (1969-74) में भी देश ने निर्यात को बढ़ाने, आयात को कम करने तथा अव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उद्योगों के विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। चतुर्थ योजना में अब उद्योगों के विकास पर सार्वजनिक क्षेत्रों में 3739 करोड़ रुपये व्यय हुआ। पाँचवी योजना में लगभग 13528 करोड़ रुपये लघु व कुटीर, समूहित उद्योग एवं खनिज विकास पर व्यय होने का प्रावधान था।

योजना आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, दत्त समिति तथा डा. भार के हजारी की सिफारिशों के अनुसार उद्योगों के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के तेजी से विस्तार करने, आर्थिक केन्द्रीकरण और उद्योगों में एकाधिकार प्रवृत्तियों पर अकुशल लगाने तथा समाजवाद की स्थापना का स्वप्न साकार करने के लिए 18 फरवरी 1970 को भारत सरकार ने नई औद्योगिक लाइसेंस नीति की घोषणा की है और 2 फरवरी 1973 तथा 25 अक्टूबर 1974 को उसमें और महत्वपूर्ण घोषणायें की हैं। इस प्रकार भारत सरकार देश के औद्योगीकरण के लिये कृतसंकल्प है।

(1948, 1956 तथा 1977 की औद्योगिक नीतियों और नई लाइसेंस नीति के विस्तृत विवरण के लिए "भारत में औद्योगिक नीति" का अध्याय 7 देखिये।

उपयुक्त सजिप्त भूमिका से हम यह देखते हैं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश में औद्योगिक विकास का सुदृढ़ आधार तैयार करने के लिए भारत सरकार पिछले 24-25 वर्षों से कृतसंकल्प है और आवश्यकतानुसार सुनिश्चित, स्पष्ट तथा प्रगतिशील नीतियों का अनुसरण किया है। इन प्रयत्नों से भारत के औद्योगिक विकास में कई प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं जिनका विस्तृत विवरण प्रस्तुतित तथ्यों से स्पष्ट होता है—



## स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में औद्योगिक विकास की मुख्य प्रवृत्तियाँ

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् 1948 की औद्योगिक नीति, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास कार्यक्रमों 1956 की नवीन औद्योगिक नीति तथा निजी क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान से औद्योगिक विकास में निम्न प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं—

1 पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर व्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि— प्रथम योजना में कृषि विभाग पर अधिक ध्यान दिया गया। इस योजना में उद्योगों के विकास पर सार्वजनिक क्षेत्र में केवल 117 करोड़ रुपये ही व्यय हुआ। द्वितीय योजना में उद्योगों और खासतौर पर नाधारभूत और सूत्रभूत उद्योगों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दिये जाने से सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों के विकास पर 1,125 करोड़ रुपये व्यय किया गया। तृतीय योजना में भी विकास का यह क्रम जारी रहा तथा इस योजना में स्वयं-स्फूर्ति ग्रहणबन्धन के लिए उद्योगों के विकास पर सार्वजनिक क्षेत्र में 1,967 करोड़ रुपये व्यय किया गया। तीन वार्षिक योजनाओं में 1,719 करोड़ रुपये तथा चतुर्थ योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों के विकास पर 3,729 करोड़ रुपये व्यय हुआ। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगीकरण के लिए विकास व्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई है। निजी क्षेत्र में भी प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय योजना में क्रमशः 233 करोड़ रुपये 850 करोड़ रुपये तथा 1,050 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय का विस्तृत विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट है—

पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों पर व्यय

(करोड़ रुपये)

विवरण	प्रथम योजना 1951-56	द्वितीय योजना 1956-61	तृतीय योजना 1961-66	तीन वार्षिक योजनाएँ 1966-69	चतुर्थ योजना 1969-74	पाँचवी योजना 1974-78
ग्राम एवं लघु उद्योग	43	187	241	144	293	388
संगठित उद्योग एवं खनिज विकास	74	938	172	1375	3435	7432
उद्योगों पर कुल व्यय	117	1125	1967	1719	3729	7820
सार्वजनिक क्षेत्र के कुल व्यय का प्रतिशत	4%	24%	23%	25.4%	22.7%	26.5%
सार्वजनिक क्षेत्र में कुल व्यय	1960	4600	8577	6757	16774	29571

2 औद्योगिक विनियोग में निरन्तर वृद्धि का स्वरूप—भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद औद्योगिक विकास की दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति, विनियोगों में निरन्तर वृद्धि है। सार्वजनिक क्षेत्र में प्रथम योजना में उद्योगों में विनियोग 55 करोड़ रुपये था वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 938 करोड़ रुपये तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 1520 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। तीन वार्षिक योजनाओं में विनियोग कुछ कम रहा है परन्तु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष 1969 में 1968 के मुकाबले दुगुने लाइसेन्सों की मजूरियाँ दी गईं। निजी क्षेत्र में निवेशों में तेजी से वृद्धि हुई है। पहली तीन योजनाओं में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में कुल औद्योगिक विनियोग 4 646 करोड़ रुपये हुआ। संगठित उद्योग व खनिज विकास में योजनावार निक्षेप निम्न तालिका से स्पष्ट है—

पंचवर्षीय योजनाओं में संगठित उद्योगों व खनिज उद्योगों में विनियोग  
(करोड़ रुपये)

क्षेत्र	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना	1966-69	चतुर्थ योजना	पाँचवीं योजना
सार्वजनिक क्षेत्र	55	938	1520	1520	3729	7820
निजी क्षेत्र	233	850	1060	480	000	6000
कुल-योग	288	1788	2580	2100	5729	13820

चतुर्थ योजना में कुल मिलाकर उद्योगों में 5729 करोड़ रुपये विनियोग हुआ जबकि पाँचवीं योजना में 13820 करोड़ रुपये विनियोग की आशा थी। इस तरह विनियोग में बढ़ावा देने की नीति से विदेशी पूँजी का विनियोग भी बढ़ा है। छठी योजना में 200 अरब रुपये विनियोग की आशा है।

3 औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि (Increase in Industrial Production)—पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत उद्योगों के विकास पर भारी व्यय तथा बड़ी मात्रा में विनियोग से औद्योगिक उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले 28 वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में 270 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1950-51 के मुकाबले 1968-69 में औद्योगिक उत्पादन तिगुना हो गया है। 1960-100 के आधार पर औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक 1950-51 में 49 था वह 1965-66 में बढ़कर 154 तथा 1977-78 में बढ़कर 270 तक पहुँचने का अनुमान है। जहाँ 1950-51 में औद्योगिक विकास की दर 2.5% थी वह 1976-77 में 10.4% पहुँच गई। 1978-79 में यह दर 7 से 8% रहने का अनुमान है।

4 आधारभूत एवं मूलभूत उद्योगों का सुदृढ़ आधार—1948 की नीति में ही स्पष्ट कर दिया गया था कि देश के औद्योगीकरण के लिए देश आधारभूत एवं बुनियादी उद्योगों का सुदृढ़ आधार आवश्यक है। घन 1956 से लागू होने वाली द्वितीय योजना में आधारभूत उद्योगों के विकास को सर्वोच्च स्थान दिया। जोहा इस्पात की तीन नई इकाइयाँ—झरनेना भिवाई व दुर्गापुर में जोरासल में हैवी इलेक्ट्रॉनिक कारखाना अल्युमिनियम, सीमेंट मशीन और प्रोत्तार निर्माण, रासायनिक उद्योगों का निर्माण तन्त्री से शुरू हुआ। तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी विकास तथा सुगमता की दृष्टि में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में प्रगति का सक्षिप्त दिग्दर्शन घाते दी गई ताजिस्त से होता है—

## योजनाओं में आधारभूत उद्योगों का विकास

क्र० सं० उद्योग	इकाई	1950-51	1960-61	1965-66	1968-69	1973-74	1977-78	1979-80	छठी योजना का लक्ष्य 1982-83
(1) लोह इस्पात	लाख टन	10.4	23.0	45.1	46.0	48.9	77.3	88	118
(2) सीमेंट	लाख टन	27.3	80	108.2	125.0	146.7	190	208	290
(3) मशीनें	लाख रु०	30	700	2900	2500	6500	12000	13000	20000
(4) मल्यूमिनियम	हजार टन	4	18	62	120	147.9	180	310	300
(5) पेट्रोलियम पदार्थ	लाख टन	2	60	97	161	197	220	270	350
(6) नाइट्रोजन उर्वरक	हजार टन	9	—	232	450	1058	2060	3670	4100
(7) विद्युत क्षति	लाख कि. वाट	23	56	102	145	184.56	250	265	430
(8) कोयला	लाख टन	328	557	677	695	790	1032	1240	1490

Source . Compilation from Five Year Plans.

Draft Sixth Plan

इस तरह रासायनिक उद्योगों के उत्पादन में लगभग 10 गुना, मशीन औजार उत्पादन में लगभग 430 गुना, सीमेंट उत्पादन में 8 गुना और पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन में 120 गुना वृद्धि हुई है। ये देश में औद्योगिक विकास के लिए सुदृढ़ आधार बन पाये हैं। उत्पादन उद्योग में विकास उपभोग उद्योग की अपेक्षाकृत तीव्र रहा है। तीन इस्पात कारखाने—एक आन्ध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम्, दूसरा मंसूर के हास्पेट तथा तीसरा तामिलनाडू के सेलम जिले में लगाये जाने हैं।

5. उपभोग उद्योगों में भी तेजी से विकास हुआ है—उत्पादन उपभोग उद्योगों में विकास की गति तेज करते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में आधार-भूत उद्योगों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के साथ-साथ निजी क्षेत्र को उपभोग उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रोत्साहन दिया गया। उपभोक्ता उद्योगों में उत्पादन की वृद्धि इस प्रकार है—

### प्रमुख उपभोग उद्योगों का विकास

उद्योग	इकाई	1950-51	1970-71	1973-74	1978-79 (संक्ष)
सूती वस्त्र	करोड़ मीटर	421.9	780	795	950
चीनी	लाख टन	11	37.6	39.5	45
रेडियो रिसेवर्स	हजार से	54	1830	3250	5000
कागज उद्योग	हजार टन	116	756	776	1050
जूट उद्योग	लाख टन	8.37	10.5	10.7	12.8
साइकिलें	हजार संख्या	99	2084	2575	3000
बिजली के पखे	लाख	1.99	17.2	21.2	25

कपड़े के उत्पादन में दुगुनी चीनी के उत्पादन में लगभग त्रिगुनी, साइकिलों के उत्पादन में लगभग 19 गुनी, बिजली के पखों में लगभग साठे सात गुनी वृद्धि पिछले 28 वर्षों में सन्तोषप्रद स्थिति का संकेत करती है।

भारत में पिछले 28 वर्षों में ही औद्योगिक क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है। इससे भारत का सुदृढ़ औद्योगिक आधार तैयार हो गया है। यह निम्न सूचकांक को देखने से स्पष्ट है। सामान्यतः 1960=100 के आधार पर 1971 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 186 हो गया जबकि 1975 के घन में सूचकांक 210 तक बढ़ जाने का अनुमान है। 1978-79 में सूचकांक 273 होने का अनुमान है।

**औद्योगिक विकास सूचकांक (1960=100)**

वर्ष	आधारभूत उद्योग	पूँजीगत उद्योग	मध्यवर्ती उद्योग	उपभोग उद्योग	सामान्य (General) सूचकांक
1961	112.7	118	105.8	106.6	109.2
1965	164.3	244.2	140.1	127.5	153.8
1970	220.8	234.1	158.6	154.4	180.3
1978-79 (अनुमान)	300	320	280	270	270

**■ औद्योगिक ढाँचे में परिवर्तन (Change in Industrial Structure)—**

भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् औद्योगिक क्षेत्र में सम्पादित विकास कार्यक्रमों में औद्योगिक ढाँचे का आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिलता है। भारत के परम्परागत उद्योगों—सूती वस्त्र, जूट, चीनी, चमड़ा में विकास अपेक्षाकृत धीमी गति से हुआ है जबकि उत्पादन व मध्यवर्ती उद्योगों की अग्रभूमि प्रगति से औद्योगिक ढाँचे का कायापलट सा हो गया है। जहाँ 1950-51 में कुल औद्योगिक उत्पादन में पूँजीगत उद्योगों का भाग केवल 8 प्रतिशत था, वह 1965-66 में बढ़कर 22% हो गया। इसी प्रकार उपभोग उद्योगों का भाग कुल औद्योगिक उत्पादन में 68% से घटकर 34 प्रतिशत रह गया। इसी प्रकार भारतीय औद्योगिक ढाँचे में यह आमूल-मूल परिवर्तन औद्योगीकरण के उज्ज्वल भविष्य का संकेत देता है। औद्योगिक ढाँचे में तेजी से परिवर्तन का अर्थ द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं को जाता है। निम्न सारणी औद्योगिक ढाँचे में परिवर्तन प्रदर्शित करती है।

**भारत में औद्योगिक ढाँचे में परिवर्तन**  
**(Structural Changes in Indian Industries)**  
**(कुल औद्योगिक उत्पादन में प्रतिशत भाग)**

उद्योग	1950-51	1960-61	1965-66	1978-79 (अनुमान)
उपभोग उद्योग	67.9	45.7	34	26
मध्यवर्ती उद्योग	23.3	37.3	43.0	48
पूँजीगत उद्योग	8.0	16.0	22.0	25
अन्य	0.8	0.8	0.7	1
	100.00	100.00	100.00	100

7 उद्योगों में विविधीकरण तथा संगठित उद्योगों का अपेक्षाकृत अधिक विकास (Diversification in Industries and Speedy Expansion of Large Scale Industries)—देश में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद औद्योगिक विकास कार्यक्रमों में न केवल औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि तथा ढाँचे में परिवर्तन हुआ है बल्कि उद्योगों में विविधता आई है। जो भारत पहले आलपिन तक के लिए विदेशों पर आश्रित था अब अनेक प्रकार का इंजीनियरिंग, रासायनिक, उपभोक्ता माल का उत्पादन करने लगा है। देश में टेलीफोन, घड़ियां, रेडियो, टेलीविजन सेट, चीनी-सीमेंट व कागज, कपड़ा उद्योग की मशीनें, मिश्रित प्लास्टिक, सामुद्रिक-जहाज, हवाई जहाज, विभिन्न प्रकार की दवाइयां, सिलाई की मशीनें, पक्षे आदि कतिपय उदाहरण हैं। ये अब विदेशों को बड़ी मात्रा में भेजे जाने लगे हैं।

औद्योगिक विकास की एक विशेषता यह रही है कि संगठित उद्योगों का विकास अधिक तीव्र गति से हुआ है। जहां 1948-49 में कुल औद्योगिक उत्पादन का 60 प्रतिशत छोटे उद्योगों से तथा 40% बड़े पैमाने के उद्योगों से प्राप्त होता था वहां 1966-67 में लघु उद्योगों का कुल औद्योगिक उत्पादन में भाग 30 प्रतिशत ही रह गया जबकि बड़े पैमाने के उद्योगों का भाग 40% से बढ़कर 70 प्रतिशत हो गया। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूँजी की गहनता औद्योगिक प्रगति का सूचक है।

8 उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र का तीव्र विस्तार—उद्योगों में एकाधिकार एवं केन्द्रीकरण को रोकने तथा समाजवादी लक्ष्य की पूर्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का तजी से विस्तार हुआ है। विनियोग की तालिका से स्पष्ट होता है कि जहाँ प्रथम योजना में सार्वजनिक उद्योगों में विनियोग 55 करोड़ रुपये था वह बढ़कर तृतीय योजना में 1520 करोड़ रुपये हो गया। तीन पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक उद्योगों पर 2513 करोड़ रुपये विनियोग हुआ। जहाँ 1950-51 में सार्वजनिक उद्योगों की संख्या 5 थी और उनमें 29 करोड़ रुपये की पूँजी विनियोजित थी, 1965-66 में सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या 74 और विनियोजित पूँजी 2415 करोड़ रुपये हो गई। 1978 के मार्च में उपक्रमों की संख्या 155 तथा विनियोजित पूँजी 13500 करोड़ रुपये थी। भारत की सम्पूर्ण उत्पादन सम्पदा में लोक क्षेत्र का भाग 1950-51 में केवल 15% था वह अब बढ़कर 46% हो गया।

इसके अलावा जहाँ 1951 में संगठित उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र का भाग 3% था वहाँ वह बढ़कर 1966 में 30% हो गया। छठी योजना के अन्त तक सार्वजनिक क्षेत्र का भाग 60% हो जाने का अनुमान है। सार्वजनिक क्षेत्र में रुखेला, भिलाई तथा दुर्गापुर में लोह-इस्पात कारखाने, भोपाल में बिजली की भारी मशीनें बनाने का कारखाना, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, चित्तूरजन व वाराणसी के रेल इंजन कारखाने, बगलोर में जहाज बनाने का कारखाना, आदि-आदि कतिपय उदाहरण हैं। विस्तृत विवरण के लिए “सार्वजनिक उद्योग एवं समस्याएँ” अध्याय पढ़िये।

सार्वजनिक क्षेत्र में यह विस्तार देश के भावी औद्योगीकरण के उद्देश्य से प्रेरित है ।

9. उद्योगों में विदेशी विनियोग एवं विदेशी सहयोग में वृद्धि (Increase in Foreign Investments and Foreign Collaboration in Industries)—  
मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाने तथा 1949 में स्वर्गीय प० नेहरू द्वारा विदेशी विनियोजकों को आश्वासन देने से देश में औद्योगिक विकास के लिए विदेशी पूँजी विनियोग तथा विदेशी सहयोग में वृद्धि हुई है । रिजर्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार जहाँ 1948 में भारत में निजी क्षेत्र में विदेशी विनियोग का शेष (Outstanding Foreign Investments) 264.6 करोड़ रुपये था वह बढ़कर 1960 में 634 करोड़ रुपये तथा 1965 में 936 करोड़ रुपये हो गया । तीन पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में निजी क्षेत्र में विदेशी पूँजी का विनियोग 671.2 करोड़ रुपये था । इस विनियोग का 177.8 करोड़ रुपये प्रथम योजना, 192.3 करोड़ रुपये द्वितीय योजना तथा 301 करोड़ रुपये तृतीय योजना काल में प्राप्त हुआ । विदेशी पूँजी विनियोग की दृष्टि से ब्रिटेन का पहला स्थान है उसके बाद दूसरा स्थान अमेरिका का है ।

भारत की अर्थव्यवस्था के विदोहन में लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से अब विदेशी पूँजीपति भारतीय औद्योगिक साहसियों के साथ मिलकर उद्योग खोलते हैं । विदेशी उद्योगपति भारत सरकार के साथ भी औद्योगिक उपक्रमों में भागीदार बने हैं । 1957 से 1968 की अवधि में विदेशी सहयोगों की संख्या 2950 थी । Economic Times के अनुसार 194 बम्पनियों की 206 करोड़ रुपये की पूँजी में से विदेशी पूँजी का भाग लगभग 49 करोड़ रुपये था जो उनके कुल विनियोग का लगभग 24% भाग था । इन इकाइयों में पूँजी के अतिरिक्त प्राविधिक सहयोग भी मिल रहा है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ।

10. लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास—भारत जैसी अर्थव्यवस्था में जहाँ पूँजी का अभाव है तथा अतुल जन-शक्ति वैचार है लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास का महत्व बढ़ जाना है । इन उद्योगों का विकास प्राथमिक, सामाजिक तथा राजनैतिक दृष्टि के साथ मानवीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है । इनके विकास से अधिक लोगों को पूर्ण रोजगार, अनेक लोगों को नये रोजगार, उत्पादन में अल्पकाल में वृद्धि विकेन्द्रीकरण तथा समाजवाद का आधार बनता है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रथम योजना में लघु उद्योगों के विकास के लिए 43 करोड़ रुपये, द्वितीय योजना में 187 करोड़ रुपये, तृतीय योजना में 241 करोड़ रुपये व्यय किये गये । तीन वार्षिक योजनाओं में इन उद्योगों के विकास पर 144 करोड़ रुपये व्यय हुआ जबकि चतुर्थ योजना में इनके विकास पर 293 करोड़ रुपये व्यय हुआ । विशिष्ट उद्योगों के लिए निगमों की स्थापना जैसे हस्तकला बोर्ड, हाथकढ़ाई बोर्ड, कोपर बोर्ड, लघु उद्योग विकास निगम, आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों में राज्य

वित्त निगम आदि के साथ प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए उत्पादन सीमा तथा भिन्नता का सिद्धान्त अपनाया गया है। 1965 में लघु उद्योगों (लघु एंव कुटीर) में उद्योगों की कुल पूंजी का केवल 11.3% भाग था पर फिर भी वे कुल औद्योगिक उत्पादन का 32.2% भाग उत्पादन कर रहे थे जब 4% भाग है। फिर भी यह सत्य है कि बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास लघु एंव कुटीर उद्योगों की अपेक्षाकृत तेजी से हुआ है। पांचवी योजना में लघु एंव कुटीर उद्योगों की अपेक्षाकृत तेजी से हुआ है। पांचवी योजना में लघु एंव कुटीर उद्योगों के विकास पर सार्वजनिक क्षेत्र में 388 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। छठी योजना में 1410 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान है।

11 औद्योगिक क्षेत्र में एकाधिकार एवं केन्द्रीयकरण की बढ़ावा—1956 की औद्योगिक नीति का उद्देश्य एकाधिकारी प्रवृत्तियों का रोकना तथा नये साहसियों को प्रोत्साहन देना था पर औद्योगिक लाइसेन्स नीति के दोषपूर्ण कार्यान्वयन, प्रशासनिक भ्रष्टाचार तथा उद्योगपतियों की स्वार्थपरायणता से विपरीत परिस्थिति देखने में आई। यद्यपि कुछ क्षेत्रों—दियासलाई में WIMCO व सीमेन्ट में ACC की एकाधिकारी प्रवृत्तियों का हास हुआ है पर साथ ही कुछ बड़े उद्योगपतियों के हाथ में औद्योगिक इकाइयों का केन्द्रीयकरण हुआ है। डॉ० आर० के० हजारी तथा दत्त समिति ने इसके बारे में विस्तृत विवरण दिया है। एकाधिकार आयोग (Monopoly Commission) के प्रतिवेदन से भी पता चला कि 100 वस्तुओं में 65 वस्तुएँ ऐसी हैं जिनका उत्पादन कुछ ही उद्योगपतियों के हाथ में केन्द्रित है और वे अपनी एकाधिकारमय प्रवृत्ति से कृत्रिम अभाव से अनुचित मुनाफाखोरी को बढ़ाते हैं। भारत के कुछ बड़े व्यावसायिक समूहों—जैसे बिड़ला, टाटा, डालमिया आदि का अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव है। इन समाजवाद के नये नारे के रूप में 23 दिसम्बर 1977 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है उससे अब सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार होगा आर्थिक एकाधिकार का यह टूटगा। नये-नये सहयोगियों को औद्योगिक इकाइया स्थापित करने में प्रोत्साहन तथा लाइसेन्स से उदारता बरती जायेगी। लघु उद्योगों की विकास की पर्याप्त सुविधा होगी तथा बड़े उद्योगपतियों को नियन्त्रण के साथ अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जायगा। (इस नीति का विवरण “औद्योगिक नीति” अध्याय में देखिये)

12 अन्य प्रवृत्तियाँ—(1) उद्योगों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विशिष्ट वित्तीय संस्थान स्थापित किये गये हैं—जैसे औद्योगिक वित्त निगम, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, औद्योगिक विकास बैंक, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, राज्य वित्त निगम, औद्योगिक सार्वजनिक एवं विनियोग निगम आदि। इसके अलावा 19 जुलाई 1969 को लघु उद्योगों को ऋण देने के लिए तथा वित्तीय सहायता पर बड़े उद्योगों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर नियन्त्रण रखने के लिए 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया है।



(ii) किसी भी देश में क्षेत्रीय विषमता सन्तुलित विकास में बाधक है और इसलिए भारत सरकार ने औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों तथा क्षेत्रों के विकास की ओर भी ध्यान दिया है। लाइसेंस देने में पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाने का उद्देश्य था पर व्यवहार में ऐसा कम हुआ। 1969 में सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए साहसियों को विनियोग का 15% अनुदान सहायता (केवल 50 लाख रुपए के विनियोग तक) देने की घोषणा की। राज्य सरकारें भी रियायती दरों पर भूमि, विजली की व्यवस्था करने में सतत् प्रयत्नशील हैं। औद्योगिक बस्तियों का निर्माण किया गया है। करो में भी रियायतें दी जाती हैं। यह उद्योगों के विकेन्द्रीकरण तक पिछड़े क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

(iii) औद्योगिक नीति में सामयिक संशोधन की प्रवृत्ति हमेशा दृष्टिगोचर हुई है। 1948 के बाद 1956 की औद्योगिक नीति इसकी परिचायक है। 1966 से 1968 तक उद्योगों में शिथिलता (Recession) को रोकने के लिए नई इकाइयों की स्थापना व पुरानी इकाइयों में विस्तार की भुक्ति प्रदान की। अभी हाल में ही 18 फरवरी 1970 को नई औद्योगिक लाइसेंस नीति की घोषणा तथा 14 मार्च को उसमें कुछ ढिलाई की घोषणा तथा 25 अक्टूबर 1975 को लाइसेंसिंग नीति में परिवर्तन नीतियों की लोचता तथा व्यावहारिकता को प्रदर्शित करती है। समय-समय पर इन नीतियों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने तथा आवश्यक सुधार के सुझाव देने के लिए समितियाँ नियुक्त की गई हैं। इसमें डॉ० हजारी, दत्त समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग तथा एकाधिकार आयोग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब जनता सरकार ने 23 दिसम्बर 1977 को नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की है।

(iv) पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने की लाइसेंस नीति में इस प्रकार की व्यवस्था पर विचार हुआ कि बड़े व्यावसायिक समूहों को लाइसेंस देने में उदारता बरती जायगी।

इसके अलावा कृषि-जन्य उद्योगों में अब सहकारिता का बोलबाला है। भारत जो दूसरों की सहायता से उद्योग स्थापित करता है, स्वयं दूसरे देशों में औद्योगिक सहयोग कर रहा है। भारतीय उद्योगपति अफ्रीका, नेपाल, लेटिन अमेरिका में उद्योग स्थापित कर रहे हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में औद्योगिक विकास की गति तेज ही नहीं हुई वरन् अभी औद्योगीकरण का मुहड़ आज़ार तैयार हो गया है। उत्पादन में विविधता आई है। औद्योगिक संरचना में पूर्वीगत व आधारभूत उद्योगों का आधार मजबूत बना है। समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य से प्रेरित होने का कारण उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र का काफी

विम्बार हुआ है। औद्योगिक केन्द्रीयकरण को रोकने के प्रयास किये हैं और तदनुसार लाइसेंस नीति का मगाधित किया गया है तथा नये उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

### परोक्षोपयोगी प्रश्न मय संकेत

- 1 मन्तव्यता प्राप्ति के बाद औद्योगिक विकास की मुख्य प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिये।

अथवा

पञ्चवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत औद्योगिक विकास की मुख्य प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए।

(संकेत — यात्राओं के अन्तर्गत औद्योगिक विकास की प्रवृत्तियों का उल्लेख अध्याय के शीर्षकानुसार करना है।)

- 2 भारत में यात्राकाण्ड में औद्योगिक विकास पर एक सुक्षिप्त लेख (टिप्पणी) लिखिए।

अथवा

“पञ्चवर्षीय योजनाओं में भारत का औद्योगिक आधार मजबूत व सरचना में महम्बूना परिवर्तन हुए हैं” इस कथन की पुष्टि कीजिए।

(संकेत — दाना प्रश्न के उत्तर में औद्योगिक विकास की प्रवृत्तियों का आलोचनार्थक विवेचन देना है और कथन की पुष्टि करनी है।)

— — —

# उद्योगों में राज्य अथवा सरकार की भूमिका

(Role of the State in Industry)

वे दिन हवा हुए जब उद्योग तथा व्यवसाय में राज्य सरकार के हस्तक्षेप की प्रवाधित माना जाता था तथा यह धारणा थी कि राज्य द्वारा आर्थिक क्षेत्र में यथासम्भव न्यूनतम हस्तक्षेप ही समाज के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी है। परिस्थितियों ने पलटा लाया, निजी हित सार्वजनिक हित पर हावी होने लगा और व्यापार चक्रों ने पूँजीवादी स्वतन्त्र व्यापार नीति के खोखलेपन को जाहिर कर दिया तो अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप के समर्थकों की तीव्र वृद्धि हुई। प्रो. खेरा के शब्दों में "आज राज्य पहले की भाँति आर्थिक-प्रक्रिया का भूक पर्यवेक्षक मात्र नहीं बरन् वह अब सक्रिय भागीदार के रूप में सामने आया है। उसने उद्यमी, नियन्त्रक, संरक्षक व रक्षक की भूमिका ग्रहण करती है।" आज अर्थव्यवस्था में कदम-कदम पर राज्य का हस्तक्षेप, नियन्त्रण एवं नियमन है। राज्य आर्थिक क्रियाओं का संचालक, नियन्त्रक व पर्य-प्रदर्शक है। इस प्रकार सरकार आजकल उद्योगों की स्थापना, संचालन तथा समापन आदि सभी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

## उद्योग में राज्य सरकार के हस्तक्षेप के उद्देश्य अथवा कारण (Objectives or Reasons for State Interference in Industry)

औद्योगिक क्षेत्र में राज्य सरकार के हस्तक्षेप के अनेक उद्देश्य अथवा कारण हो सकते हैं, उनमें प्रमुख अधोलिखित हैं—

1. राष्ट्रीय सुरक्षा—राष्ट्रीय महत्व के सुरक्षा उद्योगों पर देश की अखण्डता, स्वतन्त्रता व राजनैतिक सार्वभौमिकता बहुत कुछ निर्भर करती है अतः संशय सामग्री व सुरक्षा उद्योगों पर राज्य का प्रभावी स्वामित्व एवं नियन्त्रण आवश्यक है। यही नहीं राजनैतिक स्वतन्त्रता को विदेशी शक्तियों से बचाने के लिए भी सुरक्षा उद्योगों पर राज्य का प्रभावी नियन्त्रण होना जरूरी है। सुरक्षा उद्योगों को निजी क्षेत्र में छोड़ना खेतरे एवं जोखिम से परिपूर्ण होता है।

2. आधारभूत एवं मूलभूत उद्योगों का सुदृढ़ आधार तैयार करने के लिए

भी सरकार ऐसे उद्योगों की स्थापना, विकास, विस्तार एवं नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से लोह-इस्पात उद्योग, खनिज तेल उद्योग विद्युत उत्पादन उद्योग, रसायन उद्योग, सीमेंट एवं महत्वपूर्ण उद्योगों का समावेश होता है।

3 अधिक जोखिम वाले उद्योगों की स्थापना—जिन उद्योगों में जोखिम अधिक होता है उनमें निजी व्यक्ति पूँजी लगाने का साहस नहीं करते अतः ऐसे उद्योगों की स्थापना सरकार द्वारा की जाती है। रेल, जहाजरानी वायु यातायात आदि।

4 सार्वजनिक उपयोगी उद्योग (Public Utility Services)—जिनके अन्तर्गत पानी, बिजली, यातायात और संचार सेवाओं का समावेश होता है उनमें पूँजी अधिक लगती है और उनके विकास से सार्वजनिक लाभ मिलता है। ऐसे उद्योगों की स्थापना, विकास व नियंत्रण जनहित में किया जाता है।

5 औद्योगिक क्षेत्र में स्थायित्व एवं विकास—सरकारी उद्योगों में व्याप्त तेजी-मंदी के दुष्प्रभावों को दूर करने तथा उनके सन्तुलित विकास के उद्देश्य से राज्य हस्तक्षेप करता है क्योंकि अगर उद्योगों में मंदी आती है तो बेकारी, भुखमरी व निर्धनता फैलती है और अगर तेजी आती है तो उपभोक्ताओं को क्षति होती है अतः उद्योगों में स्थायित्व के साथ विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है।

6 सार्वजनिक कल्याण—समाज के अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए उद्योगों का विकास विस्तार एवं प्रगति नियंत्रण किया जाता है क्योंकि सभी आर्थिक क्रियाओं का अन्तिम उद्देश्य ही अधिकतम कल्याण करना है।

7 एकाधिकार पर नियंत्रण—उद्योगों पर निजी एकाधिकार उपभोक्ताओं और श्रमिकों के शोषण को प्रेरित करता है अतः उद्योगों में निजी व्यक्तियों के एकाधिकार को रोकने व उसका समापन करने के उद्देश्य से सरकार हस्तक्षेप करती है।

8 बड़े पैमाने की उत्पत्ति की लाभ प्राप्ति व दोहरे व्यय की रोक के लिए भी कभी कभी सरकार हस्तक्षेप करती है। अनेक छोटी छोटी इकाइयों की एक ही सार्वजनिक मस्या के नियंत्रण में रखने से मितव्ययता को प्रोत्साहन मिलता है। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें सार्वजनिक एकाधिकार अपव्यय को बचाता है और अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को समाप्त करके सामाजिक कल्याण में वृद्धि करता है जैसे अगर विद्युत आपूर्ति, पाइप लाइन, टेलीफोन लाइनें, रेल-लाइनें आदि की बिछाने का काम अनेक निजी प्रतिस्पर्द्धा firmों को करने दिया गया तो सामाजिक पूँजी का दोहरा अपव्यय होता है।

9 हानिप्रद उद्योगों पर नियंत्रण—जो उद्योग सार्वजनिक दृष्टि से हानिप्रद व नैतिक पान के कारण हाने हैं उन पर प्रगति नियंत्रण जनहित में

आवश्यक हो जाता है जैसे शराब उत्पादन करने वाले उद्योगों पर नियन्त्रण करना जरूरी होता है।

10 सन्तुलित औद्योगिक विकास व आर्थिक लाभ सरकार सभी प्रकार के उद्योगों के सन्तुलित विकास के उद्देश्य से भी हस्तक्षेप करती है और कभी-कभी हस्तक्षेप का उद्देश्य इन उद्योगों में प्राप्त होने वाले अत्यधिक लाभ का सार्वजनिक हित कार्यों में मोड़ना होता है। देश में तीव्र आर्थिक विकास के लिए औद्योगीकरण करना पड़ता है।

11 सीमित साधनों का आदातम उपयोग—देश में उपलब्ध भौतिक एवं वित्तीय साधनों के आदातम उपयोग के उद्देश्य से भी सरकार को औद्योगिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना पड़ता है।

### उद्योग में राज्य की भूमिका के विभिन्न स्वरूप

सरकार उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये औद्योगिक क्षेत्र में अनेक प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारी भूमिका (i) उद्योगों को प्रत्यक्ष सहायता देने, (ii) अप्रत्यक्ष सहायता देने, (iii) सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना करने; (iv) औद्योगिक विकास के लिए सुदृढ़ अन्तःसरचना तैयार करने, (v) उद्योगों के विकास का नियन्त्रण व नियमन करने तथा (vi) उद्योगों पर सार्वजनिक स्वामित्व एवं नियन्त्रण कायम करने आदि अनेक रूपों में हो सकता है। इनका संक्षिप्त विवरण भारतीय उद्योगों के संदर्भ में सदाय में इस प्रकार है—

1 राज्य द्वारा उद्योगों की प्रत्यक्ष सहायता—देश के औद्योगीकरण में सरकार प्रत्यक्ष योगदान करती है और वह विभिन्न रूपों में हो सकता है जैसे —

(i) विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण (Protection)—सरकार देश के उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान कर सकती है ताकि वे कानामर में विकसित हो सकें। भारत में इस दिशा में सबसे पहला कदम 1921 में विवेकात्मक संरक्षण नीति (Policy of Discriminating Protection) के अंगीकार के बाद स्वतन्त्र भारत में उद्योगों के संरक्षण के लिये व्यापक, व्यावहारिक व उपयोगी नीति अपनाई गई जिसके अंगगण (A) प्रतिरक्षा सम्बन्धी सभी उद्योगों के हरे कीमत पर संरक्षण प्रदान करने, (B) भारी एवं बुनियादी उद्योगों को अनहित में तथा सम्भव संरक्षण देने तथा (C) अन्य उद्योगों की उनकी प्रयोजनीयता के आधार पर संरक्षण की व्यवस्था है।

(ii) वित्त व्यवस्था (Industrial Finance)—भारत सरकार ने देश में उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त सामाजिक वित्त व्यवस्था के उद्देश्य से अनेक विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की है जो उद्योगों की वित्त व्यवस्था करते हैं। इनमें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation of India) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, रिजर्व बैंक, जीवन बीमा निगम, लघु उद्योगों की वित्त व्यवस्था में राज्य वित्त निगमों (State Finance Corporations)

श्रीछोगीकरण या उद्योगों में सरकार राज्य की भूमिका के रूप				
↓	↓	↓	↓	↓
(1) प्रत्यक्ष सहायता	अप्रत्यक्ष सहायता	सांख्यिक	औद्योगिक विकास	उद्योगों पर
य सुविधाएँ	य सुविधाएँ	उद्योगों की	की गुदुद	प्रभावो
(i) विदेशी प्रतिस्पर्धा	(i) श्रम अधिनियम	स्थापना	अन्तर्संचना	नियंत्रण एवं
से सरक्षण	(ii) स्थापना संगठन	स्वयं उद्योगों	का निर्माण	नियमन
(ii) वित्त व्यवस्था	य संचालन सम्बन्धी	की स्थापना	उद्योगों के विकास	इसके अन्तर्गत
(iii) तकनीकी परामर्श	अधिनियम	बला	के लिये आवश्यक	उद्योगों में
(iv) अनुसंधान सुविधा	(iii) ट्रेड मार्क		सुविधाएँ, पूँजी,	सन्तुलित विकास
(v) औद्योगिक शिक्षा	(iv) विनय व वितरण		बच्चा माल, पेयजन	शोषण से मुक्ति
एवं प्रशिक्षण	सम्बन्धी		शक्ति, तकनीकी	एकाधिकार पर
(vi) सरकार की	अधिनियम		ज्ञान, श्रमिकों	रोक, श्रम
नयनीति	(v) प्रसविदा, कम्पनी		भादि की	सुविधाओं का
(vii) यातायात-संचार	य साभेदारी		व्यवस्था	विस्तार व
साधनों का विकास	अधिनियम			उत्पादन व
(viii) वरारोपण म				वितरण पर
दूट व रियायतें				नियन्त्रण

की स्थापना उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंक भी उद्योगों को वित्त प्रदान करते हैं। सरकार स्वयं भी उद्योगों को ऋण, अनुदान व आर्थिक सहायता देकर उद्योगों को वित्त व्यवस्था करती है।

(iii) तकनीकी ज्ञान व अनुसंधान—देश में औद्योगिक विकास के लिये सरकार अनेक विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध करती है। अनेक अनुसंधान कार्यों का संचालन करती है तथा निजी अनुसंधान कार्यों में सहायता व प्रोत्साहन दिया जाता है। भारत में इस प्रकार की अनेक अनुसंधान शालाएँ कार्यरत हैं।

(iv) औद्योगिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में ही कुल श्रमिकों की पूर्ति निहित है। भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद औद्योगिक शिक्षा व प्रशिक्षण की सुविधाओं में तीव्र गति से विकास हुआ है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् इसमें सहायक है।

(v) सरकार की कृप्य नीति—सरकार अपनी कृप्य नीति से उद्योगों को प्रोत्साहन देती है जैसे लघु एवं कुटीर उद्योगों के सामान को सरकारी कृप्य में प्राथमिकता दी जाती है। जिन उद्योगों को प्रोत्साहन देना हो उनके उत्पादित माल का बड़ा भाग सरकार द्वारा उचित मूल्यों पर खरीदने की प्रक्रिया उद्योग के विकास में सहायक है।

(vi) करारोपण में छूट व रियायतें—जब सरकार किसी उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहती है तो उन्हें करो से मुक्ति प्रदान करती है या रियायतें देती है। भारत में अनेक उद्योगों की स्थापना में लाभ कर में छूट, विकास, रियायत आदि की व्यवस्था है। प्रारम्भिक हानि का समायोजन अगले वर्षों की आय में कर करारोपण में छूट के ऐसे अनेक उदाहरण हैं। किसी पिछड़े क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने में न केवल करो में रियायतें व छूट दी जाती है बल्कि उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाती है।

अप्रत्यक्ष सहायता एवं सुविधाएँ—सरकार उद्योगों को अप्रत्यक्ष रूप से भी अनेक सुविधाएँ प्रदान कर उनके विकास का मार्ग प्रशस्त करती है जिनमें श्रम सम्बन्धी अधिनियम, साझेदारी अधिनियम, कम्पनी अधिनियम, प्रसविदा, अधिनियम, वस्तु विक्रय अधिनियम, फैक्टरी अधिनियम, ट्रेड मार्क अधिनियम आदि महत्वपूर्ण हैं।

स्वयं सरकार द्वारा उद्योगों की स्थापना—जब किसी क्षेत्र विशेष में उद्योग स्थापना में निजी साहसी आगे नहीं आते, या निजी साहसियों के पास औद्योगिक इकाइयों के लिये पर्याप्त पूँजी नहीं होती अथवा वे लम्बे समय तक जोखिम उठाने की क्षमता नहीं रखते तो स्वयं सरकार ऐसे उद्योगों की स्थापना करती है। देश में आधारभूत एवं मूलभूत उद्योगों की स्थापना में राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे भारत में लोह-इस्पात उद्योग की चार इकाइयाँ दुर्गापुर, भिलाई, खरकेसा व बोकारो में स्थापित की गई है। इसी प्रकार भोपाल हेवी इलेक्ट्रॉनिक कारखाना, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, चित्तूरजन सोकोमोटिव वर्क्स

विशालापट्टम का जलयान निर्माण कारखाना, वानपुर व बगलौर के वायुयान कारखाने, हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर कारपोरेशन के अन्तर्गत 9 इकाइयाँ सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित कतिपय इकाइयाँ हैं। यही नहीं भारत में अनेक प्रतिरक्षा उद्योगों की स्थापना भी सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत हुई है।

ई औद्योगिक विकास के लिए सुदृढ़ अन्तर्संरचना (Infrastructure) का निर्माण—सरकार देश में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक वातावरण व अन्तर्संरचना का निर्माण करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अन्तर्संरचना के अन्तर्गत क्षेत्र विशेष में परिवहन संचार एवं विद्युत शक्ति का विकास वित्त व पूँजी की व्यवस्था, कच्चे माल की पूर्ति, पेयजल व आवास की व्यवस्था, कुशल व तकनीकी श्रमिकों की व्यवस्था आवश्यक बाजार का सर्वेक्षण आदि कार्य सरकार करती है। राजस्थान जैसे पिछड़े क्षेत्र में सरकार ने औद्योगीकरण के लिये आवश्यक अन्तर्संरचना तैयार की है। परिणामस्वरूप अब कोटा, जयपुर, भरतपुर, चित्तौड़, उदयपुर, भजमेर, भोलवाडा आदि उद्योगों के प्रमुख केन्द्र बन गये हैं।

ई सरकार द्वारा उद्योगों का नियन्त्रण एवं नियमन (Control and Regulation)—सरकार एक सुनिश्चित उपयुक्त औद्योगिक नीति द्वारा उद्योग के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। योजनावद्ध विकास के अन्तर्गत सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों के उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। इस नियन्त्रण में उत्पादन पूँजी विनियोग, विदेशी पूँजी आयात आदि का समावेश होता है। भारत में औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम, श्रम संधि अधिनियम, फॅक्टरी अधिनियम, विदेशी विनिमय नियन्त्रण अधिनियम, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, पूँजी विनियोग अधिनियम औद्योगिक लाइसेंस नीति आदि आदि के द्वारा औद्योगिक विकास विस्तार व अनुशरण पर नियन्त्रण रखा जाता है। नियमनों का उद्देश्य देश के सीमित साधनों के प्रयोग से अधिकतम वांछित उत्पादन करना व अवांछित उत्पादन को रोकना श्रमिकों की शोषण में बचाना, तथा औद्योगिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोकना व अत्यधिक सामाजिक कल्याण के अनुरूप उत्पादन का नियमन करना है।

ई उद्योगों का राष्ट्रीयकरण—जब अनिश्चित में उद्योगों पर प्रभावी नियन्त्रण नहीं हो पाता तो सरकार अन्तिम हथियार के रूप में निजी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर लेती है। राष्ट्रीयकरण का अभिप्राय उद्योग पर सरकार का स्वामित्व, संचालन अधिकार प्रभावी नियन्त्रण स्थापित करना है। कभी कभी सरकार निजी उद्योग का राष्ट्रीयकरण इसलिए भी कर लेती है कि उद्योग या तो वांछित प्रगति नहीं कर पा रहा है अथवा प्रगति धीमी है अथवा तात्कालिक परिस्थितियों के उद्घाटन को निजी हाथों में छाड़ना अनिश्चित में नहीं है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में तो प्रायः सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है। भारत की मिथित अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीयकरण की गति धीमी है।



भारत में प्रतिरक्षा सम्बन्धी सब उद्योग राष्ट्रीयकृत (Nationalised) — हैं। इसके अनतिरिक्त जनोपयोगी सेवाओं में रेल डाक तार विद्युत उत्पादन एवं वितरण, पेयजल, वायु यातायात का पूर्णतः राष्ट्रीयकरण कर लिया है। मोटर यातायात का राष्ट्रीयकरण तेजी से प्रगति कर रहा है। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1956 से हो चुका है, सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण 1972 में किया गया है। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की बात जोरों पर है।

### उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष व विपक्ष में तर्क<sup>1</sup>

उद्योगों के राष्ट्रीयकरण द्वारा सरकार उनका स्वामित्व संचालन एवं नियन्त्रण अपने हाथ में ले लेती है। राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में लोगों में काफी मतभेद हैं किन्तु समाजवाद की बढ़ती प्रवृत्ति पूँजीवाद के षोखलेपन में राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति को बढावा दिया है। जहाँ एक ओर राष्ट्रीयकरण के पक्ष में सन्तुलित औद्योगिक विकास, लाभ का सार्वजनिक हित में उपयोग, उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा, श्रमिकों की दशा में सुधार, बड़े पैमाने की उत्पत्ति के लाभ, औद्योगिक स्वामित्व, पूँजी निर्माण में सुविधा व साधनों के अद्वैत उपयोग से समाजवाद व सामाजिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। निजी एकाधिकारी प्रवृत्तियों का समापन होता है वहाँ दूसरी ओर राष्ट्रीयकरण से सरकार का एकाधिकार होने से सरकार की मनमानी, अकुशल संचालन, उद्योगों में नीकरशाही व लाल फीताशाही से घाटा, राजनीतिज्ञों का प्रभाव निजी क्षेत्र का मकुचन व औद्योगिक अस्थिरता आती है।

अतः पक्ष व विपक्ष के तर्कों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जब तक उद्योग निजी क्षेत्र में वांछित सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के सहायक हैं और केवल नियन्त्रण व नियमन से ही काम चल आता है उसका राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिये पर प्रतिरक्षा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण अनिवार्य है। जनोपयोगी सेवा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण अनहित में आवश्यक है। जो निजी उद्योग लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति नहीं कर पा रहे हैं अथवा उनका लाभ कमपैय पूँजीपतियों को लाभान्वित कर रहा है अथवा जन कल्याण की भावना कम हो, उनका राष्ट्रीयकरण वांछित है।

1. नोट — राष्ट्रीयकरण के पक्ष विपक्ष में तर्कों का विस्तृत विवरण अगले अध्याय में 'सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के पक्ष व विपक्ष के तर्क' शीर्षक के अन्तर्गत दिया जा रहा है। ये दोनों लगभग एक ही हैं केवल शब्दों का भ्रम-जाल है क्योंकि राष्ट्रीयकरण के बाद उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाता है।

# सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विकास

(Growth of Public Sector Industries)

आधुनिक युग राज्य के बढ़ते हुए हस्तक्षेप व नियन्त्रण का युग है। अर्थतन्त्र में राज्य की निरपेक्षता अब तेज़ व बढ़ रही है। 1917 की रूसी क्रांति, 1930 की विश्व व्यापी आर्थिक मंदी और दो विश्व-युद्धों में आर्थिक संकटों के बटु अनुभवों के बाद समूचे विश्व के अर्थतन्त्र में राज्य के हस्तक्षेप में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था के अग्र क्षेत्रों की भांति उद्योगों में भी सरकार का हस्तक्षेप अब नियन्त्रण इतना बढ़ गया है कि वह केवल सहायता, सुविधा व मार्गदर्शन ही नहीं देनी बल्कि स्वयं उद्योगों की स्थापना, संचालन एवं प्रबन्ध व्यवस्था करती है। समाजवाद के लक्ष्यों में प्रेरित सभी अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक क्षेत्र का तीव्र गति में विकास हो रहा है। भारत भी उनमें से एक है।

सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों का प्रतिपक्ष एवं अर्थ—सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों से प्रतिपक्ष उन सब उद्योगों व व्यवसायों से है जिनका स्वामित्व, संचालन एवं प्रबन्ध व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है। सरकार शब्द का यहाँ व्यापक अर्थ में प्रयोग है जिसमें हम केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों व स्थानीय सार्वजनिक संस्थाओं (Local Public Authorities) सभी का समावेश करते हैं। इन सार्वजनिक औद्योगिक संस्थाओं में उद्योगों अथवा उद्योगों पर केन्द्र, राज्य सरकारें या स्थानीय सार्वजनिक संस्थाओं का स्वामित्व होता है। ये केन्द्र, राज्य सरकारें या दोनों के द्वारा संचालित एवं संचालित हैं। उनके लाभ-हानि की भारी जिम्मेदारी सरकार की होती है। हिन्दुस्तान स्टील लि., हिन्दुस्तान मशीन टूल, चित्तूरजन लोकोमोटिव वर्क, हिन्दुस्तान टिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का लोहा शोधन करखाना, भारत सरकार के रेल, डाक-तार विभाग आदि इसके कनिष्ठ उदाहरण हैं। जब किसी निजी उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है तो वह भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की श्रेणी में आ जाता है।

**सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों का महत्व, आवश्यकता**

**अथवा उनके पक्ष में तर्क**

आधुनिक कल्याणकारी राज्य में सार्वजनिक उद्योगों का अत्यधिक महत्व है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार में समाजवादी समाज की स्थापना, सन्तुलित

औद्योगिक विकास एवं आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। शोषण से मुक्ति मिलती है, साधनों का आदर्श उपयोग करने का अवसर मिलता है तथा देश को बाह्य-आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करने में योग्य मिलता है। इसी कारण सार्वजनिक क्षेत्र के समर्थक उसके गुणों का बखाना करते हैं। संक्षेप में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के पक्ष में निम्न तथ्य प्रस्तुत किये जाते हैं

1. तीव्र गति से आर्थिक विकास—प्रो० एच० हेन्सन के शब्दों में 'आर्थिक दृष्टि से उन्नति करने के इच्छुक देशों के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों का बृहत्-स्तर पर विस्तार करने के अतिरिक्त दूसरा विकल्प नहीं है।' क्योंकि जब निजी साहसी उद्योग स्थापित करने में तत्पर न हो तो सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की पहल करना ही होगा।

2. सन्तुलित औद्योगिक विकास—निजी साहसी केवल उा उद्योगों की स्थापना में रुचि लेते हैं जिनमें लाभ की मात्रा अधिक, विनियोग की मात्रा कम तथा अति अल्पकाल में ही लाभ अर्जन होने लगे। परिणाम यह होता है कि केवल उपभोग उद्योगों से देश का एकाकी विकास होता है अतः सरकार को देश में पूँजीगत एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना करना आवश्यक हो जाता है ताकि देश में सन्तुलित औद्योगिक विकास हो सके।

3. क्षेत्रीय विषमताओं का समापन—निजी साहसी प्रायः विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में ही उत्तरोत्तर औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करते हैं जिससे पिछड़े क्षेत्र पिछड़े ही रह जाते हैं और विकसित क्षेत्र विकसित हो जाते हैं इसमें देश में क्षेत्रीय विषमता उत्पन्न हो जाती है। जबकि सरकार उपेक्षित क्षेत्रों में सार्वजनिक औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करके देश में व्याप्त औद्योगिक क्षेत्रीय विषमता को समाप्त कर सकती है। सरकार की पहल से निजी साहसी भी आकर्षित हो सकते हैं।

4. आधारभूत एवं जनोपयोगी उद्योगों की स्थापना—इन उद्योगों में बड़ी मात्रा में पूँजी, तकनीकी ज्ञान एवं जोखिम उठाने की क्षमता की आवश्यकता होती है। इनकी गर्भावधि (Gestation period) भी काफी लम्बी होती है अतः लोह-इस्पात, भारी रसायन, भारी इन्जीनियरिंग एवं भारी विद्युत सामान, पेय जल व्यवस्था, विद्युत उत्पादन आदि उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में ही सम्भव होती है उससे दोहरा लाभ मिलता है। एक ओर भावी औद्योगीकरण के लिये सुदृढ़ आधार तैयार हो जाता है और दूसरी ओर जनोपयोगी सेवाओं पर सरकार का एकाधिकार मितव्ययतापूर्ण, कल्याणकारी एवं उपयोगी होता है।

5. श्रमिकों के शोषण का समापन—सरकार का उद्देश्य शोषण से लाभ कमाना न होकर श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक देना तथा उनका कल्याण करना होता है। अतः सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार से श्रमिकों को निजी उद्योगपतियों के शोषण से बचाया जा सकता है।

॥ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा—लाभ को अधिकतम करने के लक्ष्य से प्रेरित निजी साहसी घटिया विस्म की वस्तुओं का उत्पादन, ऊँची कीमतें, मिलावट तथा कृत्रिम अभाव द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण करने का प्रयास करते हैं जबकि सरकार का उद्देश्य अधिकतम लाभ नहीं बरन् सामाजिक सेवा होती है अतः सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा अच्छी किस्म का माल, उचित कीमतें तथा उचित वितरण व्यवस्था में निहित रहती है।

7 साधनों का सर्वोत्तम उपयोग—निजी क्षेत्र में साधनों का सर्वोत्तम उपयोग प्रायः नहीं हो पाता जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में साधनों का उपयोग पूर्ण सुनियोजित योजना के अनुसार दूरदर्शिता, मितव्ययिता व विवेकपूर्ण ढंग से होता है अतः देश के वित्तीय एवं भौतिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग सम्भव होता है।

8 बड़े पैमाने की उत्पत्ति के लाभ—सरकार के पास विपुल पूँजी, पर्याप्त तकनीकी ज्ञान एवं विशाल साधन होते हैं अतः सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना से बड़े पैमाने की उत्पत्ति की बाह्य एवं आन्तरिक बचतों से लाभ प्राप्त होता है। पूँजी भी प्राप्त सस्ती दर पर सुलभ होती है, तकनीकी एवं कुशल श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं सरकार ही बड़े उद्योगों का संचालन करने में सक्षम होती है। लागत में मितव्ययिता आती है।

9 प्रतिरक्षा एवं सैन्य सुदृढता—प्रतिरक्षा उद्योगों के विकास को निजी क्षेत्र में छोड़ना खतरा से खाली नहीं है अतः देश की प्रतिरक्षा एवं सैन्य सुदृढता के लिये ऐसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित करना राजनैतिक स्वतन्त्रता एवं सार्वभौमिकता के लिये उपयुक्त रहता है।

10 धन व आर्थिक सत्ता का विफेन्दीकरण—सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग का विकास निजी एकाधिकारी प्रवृत्ति पर रोक है अतः देश में सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों का लाभ किसी निजी व्यक्ति का लाभ न होकर सम्पूर्ण समाज का लाभ है। इसी प्रकार सार्वजनिक स्वामित्व व प्रबन्ध भी समाज के सामूहिक स्वामित्व व प्रबन्ध का परिचायक है। अतः सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार से धन व आर्थिक सत्ता का सकेन्द्रण नहीं हो पाता।

11 मितव्ययिता—सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों का संचालन मितव्ययितापूर्ण होता है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े पैमाने की उत्पत्ति के लाभ तो मिलते ही हैं पर साथ साथ गंभीर प्रतिस्पर्धा, विज्ञापन व्यय आदि से भी छुटकारा मिलता है। मितव्ययिता के कारण उपभोक्ता वगैरे को लाभ मिलता है।

12 समाजवाद की स्थापना—पूँजीवाद का समापन व समाजवाद की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार व विनाश में निहित है। सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों के विकास से आर्थिक विषमता का समापन व्यापार चक्रों से मुक्ति, जन कल्याण, लाभ का सार्वजनिक प्रयोग एवं सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होता है।

**13 तीव्र औद्योगीकरण एवं औद्योगिक स्थिरता**—देश में तीव्र औद्योगीकरण तथा औद्योगिक स्थायित्व के लिये भी सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों का विकास आवश्यक है क्योंकि निजी उद्योगपति शीघ्र लाभ की दृष्टि से अति उत्पादन व कम उत्पादन के दोषों से प्रभावित होते हैं जिससे व्यापार चक्रों का प्रादुर्भाव होता है इसी प्रकार उनके पास पर्याप्त पूँजी व तकनीकी ज्ञान भी नहीं होता है। आधारभूत उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में करके तीव्र औद्योगीकरण का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। आवश्यक अस्तमरचना का निर्माण किया जा सकता है।

**14 सार्वजनिक कल्याण में वृद्धि**—सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार से अधिको व उपभोक्ताओं को शोषण से मुक्ति मिलती है। लाभ का प्रयोग सामाजिक कल्याण में प्रयुक्त होता है विपरीतता का समापन होता है। सन्तुलित विकास से अधिक विकास और सार्वजनिक कल्याण में वृद्धि होती है।

### सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों के दोष अवगुण अथवा विपक्ष में तर्क

यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों का विस्तार एवं विकास समाजवाद एवं जनकल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है पर फिर भी यह एक अमिश्रित वरदान नहीं है। इसके अन्तर्गत भी लालफीताशाही नौकरशाही प्रबन्ध में प्रकुशलता, सरकारी एकाधिकार से उत्पादकों, अधिको व उपभोक्ताओं की स्वतन्त्रता का हनन तथा राजनैतिक प्रभाव आदि दोषों का प्रादुर्भाव होता है जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार की सुझ कल्पना धूमिल हो जाती है। प्रमुख दोष अधोलिखित हैं—

**1 सरकारी एकाधिकार के दोष**—जब सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों में एकाधिकारी प्रवृत्ति बढ़ती है तो सरकार एक मात्र उत्पादक, वितरक व नियोजक होने पर जनता के हितों की उपेक्षा करने में भी नहीं चूकती। कहावत है कि, “शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। (Power corrupts & Absolute Power corrupts absolutely) अगर यह कहावत चरितार्थ हो जाय तो प्रतिस्पर्धा के अभाव में सरकार मामानी कीमतें मात्रा व पक्षपात वरत कर जनहितों की उपेक्षा कर सकती है, उनका दमन कर सकती है। जैसे रूस में अधिक उद्योगों में गुलाम की भाँति होता है।

**2 औद्योगिक प्रकुशलता**—सार्वजनिक उद्योगों का संचालन एवं प्रबन्ध बेतन्मोगी कर्मचारियों व अधिकारियों के हाथ में होता है जिनका उनके लाभ से कोई सरोकार नहीं होता है। वे लापरवाही एवं बेमन से काम करते हैं। परिणामस्वरूप कार्यक्षमता में हास होता है उन्हें अधिक कुशलता के लिए कोई उत्प्रेरणा नहीं होती। नियुक्तियाँ भी राजनैतिक प्रभाव, भाई भतीजावाद आदि के कारण होने से स्थिर हो जाती है।

**3 मितव्ययिता का अभाव एवं फिजूलखर्ची**—सार्वजनिक उद्योगों में प्रकुशलता पनपती है। खरीद बिनी में घोटाने होते हैं। प्रतिस्पर्धा के अभाव में

उद्योगों में शिथिलता आती है। उनकी प्रगति का मापदण्ड दूसरा निजी उद्योग न होने से तुलना करना सम्भव नहीं होता। औपचारिकता में समय बर्बाद होता है। परिणामस्वरूप सार्वजनिक उद्योगों में धन व साधनों का बड़ी मात्रा में अपव्यय होता है। सबकी सम्पत्ति किसी की सम्पत्ति न होने की भावना से सार्वजनिक सम्पत्ति में काफी नुकसान की भी कोई परवाह नहीं होती।

4 नौकरशाही एवं सार्वजनिक सेवा—सार्वजनिक उद्योगों का प्रबन्ध एवं संचालन बेतनभोगी प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में होता है जिन्हें प्रायः औद्योगिक इकाइयों के संचालन की अनभिज्ञता व आवश्यकता का अनुभव नहीं होता। इसके अतिरिक्त अन्य सरकारी कार्यालयों की भाँति उनमें भी नौकरशाही, भ्रष्टाचार एवं सार्वजनिक सेवा पनपती है जो अन्ततः उद्योग की दृष्टि से अनुपयुक्त है।

5 औद्योगिक विकास में अस्थिरता—आधुनिक प्रजातांत्रिक सरकारें अस्थायी सरकारें होती हैं। सत्ताधारियों में परिवर्तन होता रहता है और उद्योगों की विकास सम्बन्धी नीति भी उनकी मनमर्जी से जुड़ी रहती है और उनमें भी सत्ताधारियों के साथ साथ हेर फेर होता रहता है। अतः अस्थिरता के वातावरण में कोई ठोस कार्य नहीं हो पाता। यही नहीं, निर्वाचित सत्ताधारियों में आवश्यक तकनीकी एवं व्यावसायिक योग्यता का भी प्रायः अभाव रहता है अतः उनके द्वारा उचित नीतियों का निर्धारण होना भी प्रायः कठिन होता है।

6 उत्पादक, उपभोक्ताओं व श्रमिकों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हनन—सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार एवं एकाधिकार के कारण निजी साहसी उस क्षेत्र विशेष में दखल होने के बावजूद भी उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। इसी प्रकार उपभोक्ता भी अपनी व्यक्तिगत रुचि के अनुरूप उत्पादन के लिये बाध्य नहीं कर सकता और श्रमिक भी एकाधिकारी उद्योग में सरकार के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। सर्वप्रसङ्ग सार्वजनिक क्षेत्र होने पर एक मात्र नियोजक सरकार ही रह जाती है अतः वह अपनी एकाधिकारी प्रवृत्ति का दुरुपयोग कर सकती है।

7 राजनैतिक दुष्प्रभाव—सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों में निर्णय पूर्णतः आर्थिक दृष्टि से प्रेरित न होकर सत्ताधारी पार्टी के राजनैतिक हितों के आधार पर किया जाते हैं। परिणाम यह होता है कि साधनों का आदर्शतम उपयोग सम्भव नहीं हो पाता। इसके अनेक उदाहरण भारत में विद्यमान हैं और ऐसे उदाहरण चुनावों के समय प्रायः बड़ी मात्रा में देखने में आते हैं।

8 व्यक्तिगत प्रेरणा, उत्साह एवं आवश्यक लोच का अभाव—सार्वजनिक उद्योगों में बेतनभोगी कर्मचारियों के उद्योग के विकास में प्रति न ही कोई रुचि होती है और न उत्साह एवं प्रेरणा ही। परिणाम यह होता है कि सुधार व विकास की सम्भावनाएं सीमित हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक उद्योगों में कोई

परिवर्तन करने या निर्णय लेने में अनेक अनौपचारिकताओं से गुजरना पड़ता है अतः लोच का अभाव होता है।

9. अनुसंधान एवम् अन्वेषणों का अभाव—सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग में प्रतिस्पर्धा न होने तथा सरकार की एकाधिकारी प्रवृत्ति के कारण उद्योग में अनुसंधान एवम् अन्वेषणों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी उत्पादक देते हैं। यह कथन भाषिक रूप से पिछड़े राष्ट्रों में सत्य है। विकसित राष्ट्रों में विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण अनुसंधानों व आविष्कारों को पर्याप्त प्रोत्साहन दी जाती है।

10. राजकीय अधिनायकवाद—सार्वजनिक क्षेत्र का उत्तरोत्तर विस्तार औद्योगिक व आर्थिक क्षेत्र में सरकार के एकाधिकार द्वारा राज्य की तानाशाही को जन्म देता है। आज रूस में सर्वत्र सार्वजनिक क्षेत्र के विकास से तानाशाही समाजवाद स्थापित हो गया है जिसमें अधिक व उपभोक्ता सब सरकार की दया पर आश्रित हैं।

**फिर भी सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग का विकास अछूट क्यों ?**

यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र के विकास में अनेक दोष हैं और सरकार उनकी स्वतन्त्रता का हनन कर राजकीय अधिनायकवाद स्थापित कर सकती है और फिर भी सार्वजनिक क्षेत्र का विकास अगर कुशलता, विवेक एवम् दूरदर्शिता के आधार पर किया जाय तो देश में तीव्र आर्थिक विकास, उच्च जीवनस्तर, शोषण से मुक्ति, सार्वजनिक कल्याण, सामाजिक सुदृढ़ता एवं राजनैतिक स्थिरता का मार्ग प्रशस्त होता है धन प्रतिरक्षा उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखना सुरक्षा व सार्वभौमिकता के लिए अनिवार्य है। आधारभूत एवं जनोपयोगी सेवा उद्योगों का सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत विकास एवं विस्तार आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण की दृष्टि से आवश्यक है। जो उद्योग निजी क्षेत्र में वांछित गति से विकास नहीं कर पाते और जो साधनों के अभाव में पिछड़े रहते हैं उनकी सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत लेना वांछित है। इसी प्रकार क्षेत्रीय असमानता के समापन, धन व आर्थिक सत्ता के सकेन्द्रण पर रोक सम्बुलित औद्योगिक विकास एवं अधिकतम उत्पादन क्षमता के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार आधुनिक युग का आधार स्तम्भ व युग-धर्म बन गया है।

**विकास में सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों का विकास**

**(Growth or Development of Public Sector Industries in India)**

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों की परम्परा अति प्राचीन काल से रही है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में हमें इस परम्परा के संकेत मिलते हैं उसके बाद मगधो शासन काल में भी सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों का यत्र तत्र विकास हुआ पर स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। अध्ययन की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों के अधिक विकास का सक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है—

(A) स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विकास—अतीत काल से ही सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना, संचालन एवं प्रबन्ध का दायित्व सम्भाला है जिसका चित्रण कौटिल्य अर्थशास्त्र व अन्य ग्रन्थों में मिलता है। ब्रिटिश शासन काल में 1766 में लार्ड क्लाइव ने पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ सेवाओं को प्रथम राजकीय उपक्रम के रूप में संगठित किया। 1834 में ब्राडिनेन्स फैक्टरी स्थापित की गई। 1914 में रेलवे पर और 1932 में प्रसारण सेवा (Broad Casting) पर सरकार ने स्वामित्व एवं नियन्त्रण जमा लिया। इसी प्रकार प्रतिरक्षा उद्योगों पर सरकारी स्वामित्व एवं नियन्त्रण रहा है। इस प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों में रेल रेलवे वर्कशॉप, अस्त्र-शस्त्र निर्माण कारखाने प्रसारण सेवा डाक सार वर्कशॉप तथा सिंकाई व विद्युत उत्पादन इत्यादि थीं जिनमें अधिकांश विभागीय संगठन के रूप में कार्य करते थे।

(B) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों का विकास—जैसा कि पहले बताया जा चुका है स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व केवल प्रतिरक्षा उद्योगों एवं जनोपयोगी सेवा उद्योगों तथा प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से ही कतिपय उद्योगों में सार्वजनिक स्वामित्व एवं नियन्त्रण था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अबिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (A I C C) द्वारा नियुक्त आर्थिक आयोग समिति ने 1948 के अपने प्रतिवेदन में सुरक्षा सम्बन्धी सभी उपक्रमों, प्रमुख उद्योगों तथा एकाधिकारी उद्योगों को सरकारी स्वामित्व एवं नियन्त्रण में लेने की सिफारिश की। देश में औद्योगिक विनाश को गति प्रदान करने के लिए स्वतन्त्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में घोषित की गई जिसमें प्रथम बार उद्योगों को—सार्वजनिक उद्योग एवं निजी उद्योग दो अलग अलग वर्गों में विभाजित किया। इन दोनों की कार्य सीमाओं का भी निर्धारण कर दिया गया।

इस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व स्पष्ट करते हुए लिखा उद्योगों के विकास में राज्य को उत्तरोत्तर सक्रिय भाग लेना चाहिये। अस्त्र-शस्त्र, अणु शक्ति एवं रेल यातायात जो केन्द्रीय सरकार के एकाधिकार में रहेंगे, के अतिरिक्त द्वा प्रत्येक आधारभूत उद्योगों में नये कारखाने खोलने का सम्पूर्ण दायित्व भी सरकार के ऊपर रहेगा। कबल कुछ दशाओं में यदि आवश्यक समझा गया तो राज्य राष्ट्र हित में निजी क्षेत्र का सहयोग प्राप्त कर सकेगा। अन्य समस्त उद्योग निजी क्षेत्र के लिए सुरक्षित रहेंगे यद्यपि इनमें भी राज्य की सक्रिय भाग लेने का अधिकार होगा।”

भारतीय संविधान में भी राज्य नीति के निर्देशन सिद्धान्तों में सार्वजनिक क्षेत्र के निये व्यापक प्राधार रखा गया है जैसे राज्य अपनी नीति का इस प्रकार निर्देशन करेगा जिससे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में जनता के हितों के विपरीत सम्पत्ति एवं उत्पादन के साधनों का केन्द्रीयकरण न हो।



1954 में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया और उससे प्रेरित होकर सरकार ने 1956 की नई औद्योगिक नीति से सार्वजनिक उत्तरोत्तर विस्तार एवं तीव्रगति से विस्तार को बढ़ावा दिया। इस नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में कहा गया कि राष्ट्र में समाजवादी समाज की स्थापना का उद्देश्य अपना लेने तथा तीव्र विकास के लिए नियोजन की आवश्यकता के कारण यह जरूरी है कि समस्त आधारभूत उद्योगों, सैनिक महत्व के उद्योगों तथा जनोपयोगी उद्योगों (Public utility Industries) को सार्वजनिक क्षेत्र में संचालित किया जाय। अतः उद्योगों के व्यापक क्षेत्र के विकास का प्रत्यक्ष दायित्व अब सरकार को अपने ऊपर लेना है।”

इस प्रकार तीव्र औद्योगीकरण, उत्पादन एवं वितरण के प्रमुख साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व एवं नियन्त्रण तथा सम्पत्ति व साधनों के केन्द्रीयकरण पर नियंत्रण के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इन घोषणाओं व नीति को कार्यान्वित कर उन्हें भूत रूप प्रदान करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में सक्रिय कदम उठाये गये हैं जिनका संक्षिप्त विवरण योजनावार इस प्रकार है—

(i) प्रथम योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विकास—यद्यपि प्रथम योजना कृषि प्रधान योजना थी फिर भी सार्वजनिक क्षेत्र में वृहत् उद्योगों पर 73 करोड़ रुपये तथा लघु उद्योगों पर 43 करोड़ रु० व्यय हुआ। कुल पूंजी विनियोग 55 करोड़ रु० था। इस अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र में सिन्दरी खाद कारखाना, चित्तूरजन रेल इंजिन कारखाना, बगलौर में मशीन टूल्स कारखाना, पिम्परी में पेंसिलित कारखाना, पेराम्बूर में रेल डिब्बों का कारखाना, बगलौर में हवाई जहाज कारखाना, हिन्दुस्तान शिप यार्ड, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, मध्यप्रदेश में नेपा न्यूप्रिन्ट कारखाना आदि की स्थापना महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं। यही नहीं, प्रथम योजना काल में कायु यातायात व इम्पीरियल बैंक का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था।

प्रथम योजना के प्रारम्भ में सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या (केन्द्रीय व राज्य सरकार के विभागीय प्रतिष्ठानों को छोड़कर) केवल 5 थी और उनमें 29 करोड़ रु० की पूंजी लगी हुई थी। प्रथम योजना की अवधि में 16 नये उपक्रम स्थापित किये जाने से योजना के अन्त में उपक्रमों की कुल संख्या 21 तथा विनियोजित पूंजी 81 करोड़ रु० थी।

(ii) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक उद्योगों का विकास द्वितीय योजना में औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। समाजवादी समाज की स्थापना से प्रेरित हो 1956 की नवीन औद्योगिक नीति में सार्वजनिक उद्योगों का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक बना दिया गया। अतः आधारभूत उद्योगों के अन्तर्गत लोह-इस्पात के तीन कारखाने—हुरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर की स्थापना की गई। 1956 में जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण किया गया। भोपाल में

हेवी इलेक्ट्रॉनिक कारखाना, खनिज व तेल विकास के लिए ऑयल इण्डिया लि, खाद निगम, कोयला विकास निगम नेशनल इन्स्ट्रुमेन्टेशन, राची में हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन इण्डियन रिफाइनरीज लि आदि मिलाकर 27 नये सार्वजनिक उपक्रम स्थापित किये। परिणामस्वरूप योजना के अन्त तक सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या 21 से बढ़कर 48 तथा विनियोजित पूँजी 18 करोड़ से बढ़कर 953 करोड़ रु हो गई। इस योजना काल में सार्वजनिक क्षेत्र का पूँजी विनियोग 938 करोड़ रुपये था।

(iii) तृतीय पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक उद्योगों का विकास—इस योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था को स्वयं स्फूर्त बनाने के लिए कृषि एवं औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। तृतीय योजनावधि में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों पर कुल विनियोग 1520 करोड़ रु था। इस योजना काल में चीनी तथा पाकिस्तानी आक्रमणों के संकटों का सामना करना पड़ा अतः अर्थव्यवस्था को सुरक्षा एवं विकास की ओर उन्मुख करने व लिए आधारभूत पूँजीगत एवं उत्पादक उद्योगों के तीव्र विकास की नीति अपनाई गई। झरूरे कार्यों को पूरा करने, पूर्व स्थापित उद्योगों की उत्पादन क्षमता का विस्तार करना तथा नई इकाइयाँ स्थापित करने पर जोर दिया गया। इस योजना में उद्योगों में मिग विमान बनाने का कारखाना, आवाड़ी में टैंक निर्माण कारखाना तथा अस्पयन सैनिक वाहनो, स्वचालित राइफिलो आदि व कारखाने स्थापित किये गये। बोयली में तेल शोधक कारखाना, निवेली, टांम्बे व गोरखपुर में खाद कारखाने, बगलोर में जापान की सहायता से घड़ी बनाने का कारखाना, दुर्गापुर में माइनिंग मशीन निर्माण कारखाना, कोटा में प्रंसीजन इन्स्ट्रुमण्ट फैक्ट्री होशंगाबाद में सिक्कुरिटी पेपर मिल आदि की स्थापना तृतीय योजना की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं।

1960-61 में जहाँ सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या 48 तथा उनमें विनियोजित पूँजी 953 करोड़ रु थी वह 1965-66 में बढ़कर क्रमशः 74 तथा 2415 करोड़ रुपये हो गई।

(iv) तौन आर्थिक योजनाओं (1966-69) में सार्वजनिक उद्योगों का विकास—इस अवधि में उद्योगों को आर्थिक शिथिलता के दौर से गुजरना पड़ा। फिर भी 1969 में सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या 74 से बढ़कर 86 हो गई तथा उनमें विनियोजित पूँजी भी 2415 करोड़ रुपये से बढ़कर 3500 करोड़ रुपये हो गई।

(v) चतुर्थ योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विकास (1969-74)—इस योजना में स्थायित्व के साथ विकास (Growth with Stability) की नीति अपनाकर आत्मनिर्भरता की व्यूह रचना की गई। अतः सार्वजनिक क्षेत्र का व्यय का

अधिकांश भाग चालू योजनाओं को पूरा करने, उपलब्ध समताओं का पूरा-पूरा उपयोग करने तथा उच्च प्राथमिकता प्राप्त करने के लिए नये कारखाने स्थापित करने का कार्यक्रम रखा गया। विभिन्न कार्यक्रमों के फलस्वरूप सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या 122 तथा विनियोजित पूँजी की मात्रा 6237 करोड़ होने का अनुमान है। चतुर्थ योजना काल में ही सामान्य जीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी योजना की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि योजनाबद्ध विकास के पिछले 27-28 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का तेजी से विकास हुआ है। जहाँ 1950-51 में (केन्द्रीय व राज्य सरकारों के विभागीय उपक्रमों को छोड़कर) केन्द्र सरकार के उपक्रमों की संख्या 5 थी और उनमें 29 करोड़ रु की पूँजी विनियोजित थी वहाँ 1960-61 में उपक्रमों की संख्या 48 तथा पूँजी विनियोग 953 करोड़ रुपये हो गया।

1968-69 के अन्त में सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या 86 तथा कुल पूँजी विनियोग 3902 करोड़ रु था। चतुर्थ योजना के अन्त में सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या 122 तथा उनमें पूँजी विनियोग 6237 करोड़ रुपये होने का अनुमान था जबकि 1977-78 के अन्त में सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या 155 तथा पूँजी विनियोग 13500 करोड़ रुपये था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रगति का अवलोकन एक दृष्टि में निम्न तालिका से किया जा सकता है—

तालिका-1

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सार्वजनिक उपक्रमों का विकास  
(1950-51 से 1977-78 तक)

विवरण	सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या	पूँजी विनियोग (करोड़ रुपये)
प्रथम योजना के प्रारम्भ में (1950-51)	5	29
प्रथम योजना के अन्त में (1955-56)	21	81
द्वितीय योजना के अन्त में (1960-61)	48	953
तृतीय योजना के अन्त में (1965-66)	74	2415
तीन वार्षिक योजनाओं के अन्त में (1966-69)	86	3902
चतुर्थ योजना के अन्त में (1973-74)	122	6237
(1975-76)	129	8973
(1976-77)	145	11097
(1977-78)	155	13500

जहाँ 1950-51 में सार्वजनिक क्षेत्र का कुल उत्पादन देश के समूचित

उद्योगों के कुल उत्पादन का केवल 3% भाग था वह बढ़कर अब 35 से 45% होने का अनुमान है।

### क्षेत्रवार सार्वजनिक उपक्रमों में पूँजी निवेश की संरचना

केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत कार्यशील 14 सार्वजनिक उपक्रमों में अप्रैल 1977 को कुल 11097 करोड़ रुपये का पूँजी विनियोग था जिसका लगभग 26% लोह-इस्पात उद्योग, 18.7% रसायन उद्योग तथा 11.1% कायला उद्योग में ही विनियोजित था। प्रमुख क्षेत्रों में विनियोग निम्न तालिका से स्पष्ट है —

तालिका-2

उद्योग क्षेत्र	कुल पूँजी निवेश (करोड़ रु.)	कुल का प्रतिशत
1 लोह इस्पात उद्योग	2864	25.8
2 रसायन उद्योग	2076	18.7
3 कायला उद्योग	1277	11.5
4 इन्जीनियरिंग उद्योग	1019	9.3
5 खनिज एवं धातु उद्योग	704	6.4
5 पेट्रोलिएम उद्योग	690	6.2
7 सेवा-उपक्रम	1943	19.5
(i) व्यापारिक एवं विपणन सेवा	528	4.8
(ii) परिवहन सेवाएँ	933	8.4
(iii) वित्तीय सेवाएँ	371	3.3
(iv) विविध	111	1.0
अन्य सहित कुल योग	11097	100

Source—Eastern Economist March 10, 1978, Page 449

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 31 मार्च 1977 तक कुल पूँजी विनियोग का लगभग 6264 करोड़ रु. (56.3% भाग) तो केवल 10 बड़े उपक्रमों में ही लगा था। सर्वोच्च स्थान कोकारो स्टील लि० का है जिसमें 1341 करोड़ रु. (कुल का 12%) हिन्दुस्तान स्टील लि० में 129 करोड़ रु. (10.9%) भारतीय खाद्य निगम में 1110 करोड़ रु. (10%), जहाज रानी निगम में 503 करोड़ रुपये (4.5%) भारतीय खाद्य निगम में 429 करोड़ रुपये (3.9%) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में 421 करोड़ रु. (3.8%), केन्द्रीय कायला क्षेत्र लि० में 403 करोड़ रु. (3.6%), हेवी इन्जीनियरिंग निगम में 307 करोड़ रु. (2.8%), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि० में 297 करोड़ रु. (2.7%) तथा भारत कोकिंग कोल लि० में 244 करोड़ रु. लगे थे।

सार्वजनिक उपक्रमों में अब तक कुल पूँजी विनियोग में 5413 करोड़ रु. की हिस्सा पूँजी तथा 5684 करोड़ रुपये ऋण से प्राप्त हुए हैं जिसमें केन्द्र

सरकार के 9569 करोड़ रु., राज्य सरकारों में 15 करोड़ रु., भारतीय निजी उद्यमियों के 908 करोड़ रु तथा विदेशियों के 605 करोड़ रु लगे हैं।

### सार्वजनिक उपक्रमों की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ 1951-77

पिछले 26 वर्षों में सार्वजनिक उपक्रमों का तेजी से विकास हुआ है और उनकी भूमिका निरन्तर बढ़ती जा रही है। जहाँ 1950-51 में केवल 5 सार्वजनिक उपक्रम थे और उनमें 29 करोड़ रु की पूँजी लगी हुई थी वहाँ 1 अप्रैल, 1977 को भारत में 145 सार्वजनिक उपक्रमों में 11097 करोड़ रु पूँजी लगी हुई थी। उद्योगवार पूँजी निवेश उपर्युक्त तालिका-2 में दिया गया है। देश के 10 बड़े सार्वजनिक उपक्रमों में कुल पूँजी निवेश 6264 करोड़ रु (कुल का 56.5%) है। इन सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा उत्पादित मानव सेवाओं का वित्तीय मूल्य 1972-73 में 5299 करोड़ रु था वह 5 वर्षों में बढ़कर 1976-77 में 14542 करोड़ रु हो गया है। इसी अवधि में रोजगार भी 9.32 लाख से बढ़कर 15.75 लाख हो गया है। प्रारम्भिक वर्षों में बहुत से सार्वजनिक उपक्रमों में घाटे की समस्या विकट थी किन्तु 1972-73 में शुद्ध लाभ 18 करोड़ रु से बढ़कर 1976-77 में 240 करोड़ रु हो गया है। फिर भी लगभग 26 उपक्रमों में घाटा चल रहा है जिनमें भारतीय खाद निगम, कोयला कम्पनियाँ तथा इण्डियन ग्रामरन एण्ड स्टीन कम्पनी प्रमुख हैं।

जहाँ चतुर्धा योजना काल में सार्वजनिक उपक्रमों से केन्द्र सरकार को 3120 करोड़ रु. का साधन प्राप्त हुआ वहीं पञ्चवी योजना के केवल तीन वर्षों में ही 4100 करोड़ रु के साधन प्राप्त हुए। जहाँ 1974-75 में सार्वजनिक उपक्रमों ने 1113 करोड़ रु की विदेशी मुद्रा अर्जन की वहाँ 1976-77 में यह राशि 2248 करोड़ रु (लगभग दुगुनी) हो गई। पिछले पाँच वर्षों में हुई प्रगति निम्न तालिका से स्पष्ट है।

### तालिका-3 सार्वजनिक उपक्रमों की प्रगति की झलक

विवरण	1972-73	1974-75	1976-77
(1) सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या	110	129	145
(2) पूँजी विनियोग (करोड़ रु.)	5571	7261	11097
(3) वित्तीय मूल्य (करोड़ रु.)	5299	11688	14542
(4) सकल लाभ (करोड़ रु.)	245	599	1054
(5) शुद्ध लाभ (करोड़ रु.)	18	184	240
(6) कार्यशील पूँजी पर रिटर्न	5%	8.4%	9.7%
(7) रोजगार (लाख सरवा)	9.3	14	15.75
(8) कर्मचारियों पर व्यय (करोड़ रु.)	582	1133	1503
(9) विदेशी मुद्रा अर्जन (नरोड़ रु.)	300	1113	2248
(10) सरकार को प्राप्त साधन	717	1130	1597

इन उपक्रमों के अतिरिक्त भी केन्द्र सरकार के विभागीय प्रतिष्ठानों में भी बड़ी मात्रा में पूँजी विनियोग हुआ है। एक मोटे अनुमान के अनुसार रेलों में कुल विनियोग 5000 करोड़ रु., डाक तार में 500 करोड़ रु., बिजली व सिंचाई परियोजनाओं में 10000 करोड़ रु., बन्दरगाहों में 300 करोड़ रु. तथा सड़क परिवहन में ५०० करोड़ रु. पूँजी विनियोग होने का अनुमान है।

### सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के विभिन्न रूप अथवा वर्गीकरण

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का वर्गीकरण मुख्य रूप से उनके कार्य, संगठन तथा स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है—

(A) कार्यात्मक वर्गीकरण (Functional Classification)—कार्य की दृष्टि से सार्वजनिक उपक्रमों के प्रायः निम्न 9 रूप हैं—

- 1 उत्पादन उपक्रम (Manufacturing Enterprises)
- 2 खनन उपक्रम (Mining Enterprises)
- 3 निर्माण उपक्रम (Construction Enterprises)
- 4 परिवहन उपक्रम (Transportation Enterprises)
- 5 व्यापार उपक्रम (Trade Enterprises)
- 6 बिजली एवं बहु उद्देशीय परियोजनाएँ
- 7 वैज्ञानिक वित्त एवं बीमा उपक्रम
- 8 प्रवर्तन एवं विकास उपक्रम (Promotional & Developmental Enterprises)
- 9 सेवा एवं विविध उपक्रम

भारत में अधिकांश उपक्रम प्रथम श्रेणी में आते हैं।

(B) स्वामित्व एवं विनियोग के आधार पर वर्गीकरण—इस दृष्टि से सार्वजनिक उपक्रमों को मुख्य रूप से 6 वर्गों में बांटा जा सकता है—

1 केन्द्रीय सरकार के उपक्रम—जिनमें केन्द्र सरकार द्वारा पूँजी विनियोग किया गया है तथा उन पर केन्द्र सरकार का ही स्वामित्व एवं नियन्त्रण है।

2 केन्द्र तथा राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम जिनका स्वामित्व एवं नियन्त्रण केन्द्र सरकार व राज्य सरकार दोनों का समुक्त रूप से होता है।

3 केन्द्र राज्य तथा निजी क्षेत्र के संयुक्त उपक्रम में इन तीनों का समुक्त स्वामित्व व नियन्त्रण होता है। निजी साहमियों का भाग नगण्य होता है।

4 केन्द्र तथा निजी क्षेत्र के स्वामित्व वाले उपक्रम जिनमें केन्द्र तथा निजी साहमियों का संयुक्त स्वामित्व व नियन्त्रण होता है पर केन्द्र सरकार के पास 51% से अधिक स्वामित्व व नियन्त्रण होता है।

5 पूर्णतः राज्य सरकार उपक्रम—इनमें किसी एक राज्य अथवा दो या दो से अधिक राज्यों का संयुक्त स्वामित्व एवं नियन्त्रण रहता है।

## सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विकास

6 राज्य एवं निजी साहस के संयुक्त उपक्रम—इनमें राज्य तथा निजी साहसी मिलकर उपक्रम में पूँजी लगाते हैं व दोनों का संयुक्त स्वामित्व एवं नियन्त्रण रहता है।

यह उल्लेखनीय है कि इन सभी उपक्रमों में पूँजी विनियोग की मात्रा ही स्वामित्व एवं नियन्त्रण का आधार है।

(C) संगठनात्मक वर्गीकरण—(Organisational Classification)  
सार्वजनिक उपक्रमों का संगठन मुख्यतः चार प्रकार से होता है—

1. विभागीय उपक्रम, 2 सार्वजनिक निगम, 3 सरकारी कम्पनियाँ तथा नियन्त्रण बोर्ड व कमेटियाँ। इनका विवरण मूल शीर्षक के अनुसार इस प्रकार है—

### भारत में सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों की संगठनात्मक संरचना (Organisational Structure of Public Sector Industries in India)

उद्योगों का संगठन उद्योग की प्रकृति एवं उसके स्वामित्व के अनुसार मूल-मूल हो सकता है इसी कारण भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों की संगठन व्यवस्था में भिन्नता स्वाभाविक है। सार्वजनिक उपक्रमों की संगठन एवं प्रबंध की मुख्य चार पद्धतियाँ भारत में प्रचलित हैं जैसे—

1 विभागीय उपक्रम एवं प्रतिष्ठान (Departmental Undertaking)—यह सरकारी उपक्रमों के संगठन की सबसे प्राचीन एवं रुढ़िवादी पद्धति है। यह पद्धति मुख्यतः प्रतिरक्षा, सार्वजनिक सेवा उद्योगों तथा ग्राम की दृष्टि से लाभप्रद उद्योगों में प्रचलित है जैसे—प्रतिरक्षा उद्योग, रेल, डाक-तार तथा औषध विभाग आदि।

इस प्रकार के विभागीय उपक्रम—नीमच, गाजीपुर तथा मन्दसौर में अफीम कारखाने, कोलार की स्वर्ण खानें, सिल्वर रिफायनरी परियोजना कलकत्ता वित्त मंत्रालय के अधीन हैं। ओवरसीज कम्प्यूनीकेशन सर्विस बम्बई संचार विभाग के अन्तर्गत है। दिल्ली दुग्ध परियोजना, कोल्ड स्टोरेज एवं फ्राइस फैक्टरी बम्बई, रिजर्व फूल ऑफ फर्टीलाइजर्स लाघ तथा कृषि मंत्रालय के अधीन हैं। मेडिकल स्टोर्स डिपो तथा बीकारो मिनरल वाटर फैक्टरी रांची स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत हैं जबकि इन्दोप्रल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर—डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, चित्तूरजन का रेल इंजन का कारखाना, भरतपुर का रेल वेगन कारखाना व अनेक वर्कशॉप रेल मंत्रालय के अधीन हैं। डाक-तार विभाग भी महत्वपूर्ण विभागीय उपक्रम है।

रेल उपक्रम में सरकार की लगभग 5 हजार करोड़ रु की पूँजी विनियोजित है जबकि डाक-तार विभाग में 500 करोड़ रु की पूँजी लगी हुई है। अन्य विभागीय उपक्रमों में भी लगभग तीन हजार करोड़ रु की पूँजी लगी हुई है।

इस प्रकार की संगठन व्यवस्था के मुख्य लाभ—गोपनीयता, सार्वजनिक हिसाब देयता, पूर्ण राजकीय नियन्त्रण, प्रारम्भिक उद्योगों का विकास तथा राजनैतिक

स्थिरता में सहायता के साथ-साथ आय प्राप्ति की दृष्टि से उपयोगी है। पर इन उपक्रमों में लाभफीताशाही व नौकरशाही का बोलबाला रहता है। योग्य कुशल एवं तकनीकी विशेषज्ञों का अभाव रहता है, अधिकारों का सरकार के हाथ में केन्द्रीकरण हो जाता है। अनुभवहीनता, ससदीय हस्तक्षेप राजनैतिक प्रभाव के कारण मित-व्ययता का अभाव रहता है।

2 सवैधानिक सार्वजनिक निगम (Statutory Public Corporation)—इन्हें स्वशासित निगम (Autonomous Corporations) भी कहा जाता है। ये राजकीय विभाग से भिन्न ऐसी पृथक् अस्तित्व रखने वाली संस्था है जिनकी स्थापना लोक सभा या विधान सभामें द्वारा पारित विशेष अधिनियमों द्वारा होती है और वे एक स्वतन्त्र उपक्रम के रूप में अपनी प्रबन्ध व वित्त व्यवस्था स्वयं करते हैं। प्रक्षेपण व बजट नियमों से मुक्त होते हैं। ये स्वशासित निगम अग्र पूँजी सहित या अग्र पूँजी रहित दोनों प्रकार के हो सकते हैं जैसे जीवन बीमा निगम तथा इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन अग्र रहित निगम है जबकि रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, खाद्य निगम आदि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संयुक्त पूँजी सहित निगम हैं।

स्वतन्त्रता से पूर्व केवल तीन सार्वजनिक निगम—1 बोम्बे पोर्ट ट्रस्ट, 2 कलकत्ता पोर्ट कमिशन तथा 3 मद्रास पोर्ट ट्रस्ट ही थे किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अनेक निगम व स्वशासित संस्थान स्थापित किए गये हैं जिनमें कुछ के नाम उल्लेखनीय हैं। 1948 में दामोदर बेली कारपोरेशन, औद्योगिक वित्त निगम, पुनर्वास वित्त निगम रिजर्व बैंक कर्मचारी राज्य बीमा निगम, 1953 में एयर इण्डिया इन्टरनेशनल, एयर लाइन्स कारपोरेशन, 1955 में स्टेट बैंक, 1956 में जीवन बीमा निगम केन्द्रीय गोदाम निगम 1959 में तेल एवं प्राकृतिक गैस प्रायोग, 1965 में खाद्य निगम तथा इसी प्रकार के अनेक निगम कार्यरत हैं।

सार्वजनिक निगम आधुनिक संगठन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आविष्कार है। प्रो. डब्लु. मोरिसन के शब्दों में सार्वजनिक निगम की ध्येयता का कारण उनमें सार्वजनिक हित की दृष्टि से राजकीय स्वामित्व, राजकीय दायित्व एवं व्यावहारिक प्रगति नीति का मिश्रण होता है जबकि प्रो. एम. फ्रेन्साइ के अनुसार सार्वजनिक निगम का उपयोग आन्तरिक संगठन अन्तर्गत सीमा तक लोच की अनुमति देता है। यह राजनैतिक प्रशासनिक वित्तीय एवं प्रबन्ध सम्बन्धी स्वतन्त्रता प्रदान कर विभिन्न मात्रा में सार्वभौमिकता सम्भव बनाता है। इसमें नौकरशाही की कठोरता तथा बार-बार राजनैतिक हस्तक्षेप का भय नहीं रहता।

इसके गुणों के साथ अस्वगुणों का भी मिश्रण है। इनसे एकाधिकारी प्रवृत्ति पनपती है, सरकारी नीति व निगम नीति में विरोधाभास बठिनाई उत्पन्न करता है। हानि का भार जनता पर पड़ता है। संचालन में व्यक्तिगत हित न होने से विचलन खर्चों व प्रमितभयिना पाई जाती है। इनमें भा. सरकारी विभागों की भांति लाभ



## सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विकास

फीनाशाही पनपती है अकेलण सम्बन्धी कठिनाइयाँ हैं क्योंकि ये नियम नियमों का उल्लंघन करते रहते हैं।

3 सरकारी संयुक्त पूँजी कम्पनी प्रबन्ध (Govt Joint Stock Company) सार्वजनिक उपक्रमों के संगठन की व्यवस्था को सरकारी संयुक्त स्वरूप प्रमण्डल भी कहा जाता है। सरकारी कम्पनी से अभिप्राय एव ऐसी कम्पनी से है जिसकी प्रदत्त हिस्सा पूँजी (Paid-up Share Capital) का कम से कम 51% भाग केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारी या अथवा केन्द्रीय और एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के पास हो। सरकारी कम्पनी में वह कम्पनी भी शामिल करली जाती है जो किसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी (Subsidiary Company) होती है। इस प्रकार सरकार उस उपक्रम में प्रमुख अग्रगण्य होती है। अथ राष्ट्रपति के नाम आवंटित होते हैं और सम्पूर्ण मन्त्रालय अथवा राज्य के विभागीय प्रमुख अग्रगण्य के समान सरकार के अधिकारों का प्रयोग करत है। इनके हिस्सा-विताव का अकेलण भारत के आर्टीटर जनरल की सलाह से नियुक्त अकेलक द्वारा होता है और वार्षिक प्रतिवेदन ससद में प्रस्तुत करना होता है।

इस प्रकार की प्रबन्ध व संगठनात्मक प्रणाली के कतिपय उदाहरण (i) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, (ii) हिन्दुस्तान केबल्स लि, (iii) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि, (iv) नाहन फाउन्ड्री लि, (v) सिन्दरी फर्टीलाइजर एण्ड कैमिक्स, (vi) हिन्दुस्तान मैग्नीट टूल्स, (vii) भारतीय टेलीफोन उद्योग लि (viii) हिन्दुस्तान फोटो फ्लिम्स मैग्नू कम्पनी लि, (ix) हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड तथा (x) इण्डियन ग्रायल कम्पनी आदि हैं।

पहली योजना के समय सरकारी कम्पनियों की संख्या 36 थी। वह संख्या 1967-68 तक बढ़कर 241 तथा अब इनकी संख्या 300 से अधिक है। 1955-56 में इनमें 66 करोड़ की पूँजी थी वह बढ़कर 1967-68 में 1559 करोड़ हो गई। अब इनमें लगभग 3000 करोड़ की पूँजी होने का अनुमान है।

इस प्रकार की संगठन व्यवस्था के अनेक लाभ हैं। हमें कोई विशेष विधान की जरूरत नहीं पड़ती, लाभ अर्जन के विस्तृत ध्यान हात है। पर्याप्त स्वतन्त्रता एवं लोच रहती है। इनका संचालन व्यावसायिक आधार पर होता है। राजकीय हस्तक्षेप कम होता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा व निजी एवं सरकारी उत्साह प्रेरणा एवं अनुभव का लाभ मिलता है पर इसके विपरीत कुछ दोष भी हैं। संचालन में असहयोग, गोपनीयता का अभाव, सरकारी प्रतिनिधियों में आवश्यक तकनीकी, व्यावसायिक एवं प्रबन्ध सम्बन्धी ज्ञान का अभाव रहना है मत कार्य में शिथिलता रहती है।

4. बोर्डों द्वारा प्रतिबन्धित सार्वजनिक उपक्रम (Public Enterprises managed by Boards or Committees)—जब सरकारी उपक्रम का प्रबन्ध किसी "कमेटी" या "बोर्ड" अथवा "मण्डल" के हाथ में होता है तो उसे बोर्डों द्वारा प्रबन्धित सार्वजनिक उपक्रम कहते हैं। यह संगठन की एक नवीन, मिश्रित एवं डीजी-टाली

व्यवस्था है जिसमें हारे हुए सत्ताधारी पार्टी के राजनीतिज्ञों व रिटायर्ड अधिकारियों को भी आश्रय मिलता है। इन संगठनों की प्रबन्ध व्यवस्था नियन्त्रण मण्डलों (Control Boards) में होती है जिनके स्वरूप, अस्तित्व, प्रशासकीय संरचना तथा वित्तीय व्यवस्था में एकरूपता का अभाव पाया जाता है। इन नियन्त्रण मण्डलों में केन्द्रीय सरकार एवं सम्बन्धित राज्य सरकारों व अन्य प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार की संगठन व्यवस्था सिचाई व विद्युत परियोजनाओं में अधिक प्रचलित है।

इस प्रकार के संगठन के कतिपय उदाहरण भाखरा कन्ट्रोल बोर्ड, चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड, कोसी कन्ट्रोल बोर्ड, कोयना, हीराकुण्ड, रिहन्द, नागार्जुन सागर आदि के कन्ट्रोल बोर्ड, राष्ट्रीय सहकारी एवं गोदाम बोर्ड हस्तकला बोर्ड, प्रखिल भारतीय हस्त वस्त्र बोर्ड चाय बोर्ड आदि हैं।

### सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ

1 हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड—100 करोड़ रु प्रारम्भिक पूँजी से 1953 में स्थापित यह प्रतिष्ठान झरकेला भिलाई तथा दुर्गापुर स्थित लोह इस्पात कारखाने का संचालन करता है। पूँजी निवेश की दृष्टि से यह सार्वजनिक उपक्रमों में दूसरे स्थान पर है। इसमें 31 मार्च 1977 को 1209 करोड़ रु की पूँजी लगी हुई थी। प्रथम स्थान बोकारो स्टील लि का है जिसमें 1341 करोड़ रु की पूँजी लगी हुई थी। इन दोनों प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कुल पूँजी का लगभग 21% भाग विनियोजित है।

2 भारतीय खाद निगम—यह निगम रासायनिक खाद उत्पादन करने के लिए 1961 में स्थापित किया गया। अब इस निगम के अन्तर्गत सात खाद इकाइयाँ क्रमशः सिन्धरी (बिहार), नागल (पंजाब), ट्राम्बे (महाराष्ट्र), नामहण (म्यासाम), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) कोरबा (मध्य प्रदेश) तथा दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) हैं। पूँजी 1977 में 1110 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।

3 हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (H M T)—यह 1953 में बंगलौर में स्थापित किया गया। इसकी दो इकाइयाँ बंगलौर तीसरी इकाई (पंजाब), चौथी इकाई वसमसेरी (केरल) तथा पाचवीं हैदराबाद में स्थापित की गई है। इन पाँचों इकाइयों में छोटी बड़ी मशीन व घड़ियाँ बनाई जाती हैं।

4 राष्ट्रीय कोयला विकास निगम—यह प्रतिष्ठान कम्पनी एक्ट के अन्तर् 1956 में रांची के कोयला खानों के विकास व्यवस्था के लिए स्थापित किया गया। इस निगम के अन्तर्गत 24 कोयला खाने हैं और 15 परियोजनाएँ निर्माण प्रगति पर हैं। यह कारगली सवाग गिडो तथा कठारा में कोयला खानों की इकाइयों का संचालन करता है।

5 राष्ट्रीय विकास सन्निध निगम—1958 में यह स्थापित निगम खेती

तावा योजना, किरी-बुरी लोहा परियोजना, बेलाडिला लोहा योजना, पना-हीरा खान परियोजना आदि का संचालन करता है।

6 हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि—1941 में स्थापित इस कम्पनी ने 1952 में सिन्धिया स्टीम नेवीशेन कम्पनी को अपने हाथ में ले लिया। विशालाष्टनम में हिन्दुस्तान शिपयार्ड जहाज बनाने व उनकी मरम्मत का कार्य करता है। 1941 से 1971 की अवधि में इस कम्पनी ने 5 लाख टन क्षमता के लगभग 50 जहाजों का निर्माण किया तथा 1971-72 में दो जहाज बनाये। 1977 में इसकी पूँजी 503 करोड़ रु थी।

7. हेवी इलेक्ट्रीकल्स लि—50 करोड़ रु की अधिकृत पूँजी से 1956 में यह प्रतिष्ठान भोपाल में स्थापित किया गया जिसके अन्तर्गत तीन इकाइयाँ क्रमशः रानीपुर (U P) रामचन्द्रपुरम (मा प्र) तथा तिरुवेराम्बूर (मद्रास) में हैं। इसमें मार्च 1977 में 297 करोड़ रु की पूँजी लगी हुई थी।

8 हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि—पेनिसिलीन स्ट्रैप्टोमाइसिन तथा अन्य एन्टीबायोटिक दवाइयाँ निर्मित करने के लिए 1954 में पिम्परी (पूना) में स्थापित किया गया। चतुर्थ योजना में इस कम्पनी ने विटामिन “सी”, नियोमाइसिन सल्फेट तथा थ्रॉरियोफेगिन का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है।

9 हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लि—1940 में मैथूर सरकार द्वारा प्राइवेट फर्म के सहयोग से स्थापित किया तथा इसने 1942 में भारत सरकार ने खरीद लिया। 1951 में इसकी एक शाखा बेंकपुर (प बंगाल) में खोली गई जिसमें वायुयान निर्माण व मरम्मत की जाती है।

10 चित्तरजन लोकोमोटिव वर्क्स—रेल मन्त्रालय के अन्तर्गत चित्तरजन में रेल इंजन कारखाना खोला गया। इसी प्रकार वाराणसी में डीजल इंजिन तथा विद्युत रेल इंजिन बनाने का कारखाना खोला गया है। इसी प्रकार पेराम्बूर में इन्ट्रोल कोच फैक्टरी खोली गयी है।

11 इण्डियन रिफाइनरीज—59 करोड़ रु की अधिकृत पूँजी से 1958 में इस कम्पनी की स्थापना हुई। इसके अन्तर्गत बरोनी तथा मोहरी की तेल शोध-शालयें तथा (मोहाटी) सिलीगुडी व बरोनी हव्दिवा एव कानपुर वाइप साइनों का निर्माण एवं प्रबन्ध सम्मिलित है। 1964 में इसे इण्डियन ऑयल कम्पनी के साथ मिलाकर इसका नाम इण्डियन ऑयल कारपोरेशन कर दिया गया। बर्मा शेल को भी सरकार ने ले लिया है।

12 एयर इण्डिया एव इण्डियन एयर लाइन्स—एयर इण्डिया की स्थापना 1953 में हुई व एयर इण्डिया इन्टरनेशनल लि का कार्यभार सम्भाला। इस कम्पनी में सरकार की लगभग 80 करोड़ रु की पूँजी लगी हुई है और यह भारत से इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, जापान, आस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी अरब

राष्ट्रो को अन्तर्राष्ट्रीय उड्डयन सेवाएँ उपलब्ध करता है जबकि इण्डियन एयर लाइन्स राष्ट्रीय हवाई यातायात में सलग्न है।

13 नेपा मिल्स—1947 में स्थापित इस मिल को 1949 में मध्य-प्रदेश सरकार ने सम्भाल लिया। 1958 में भारत सरकार ने इसके अधिकांश हिस्से खरीद लिए। देश में अस्खरी कागज की 20% भाग की पूर्ति यह मिल करती है। इसकी उत्पादन क्षमता 30 हजार टन से बढ़ाकर 70 हजार टन करने का कार्य प्रगति पर है।

### राजस्थान में सार्वजनिक उपक्रम

राजस्थान के कृषि प्रधान पिछड़े राज्य की प्रगति हेतु सार्वजनिक उपक्रमों का विकास किया गया है। कुछ उपक्रम केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किये गये हैं और कुछ उपक्रम राज्य सरकार ने ही स्थापित किये हैं।

(A) केन्द्र सरकार के उपक्रमों में लगी पूँजी एवं स्वाभिव्यक्ता तथा प्रमुख सब केन्द्र सरकार के हाथ में है। इनमें हैं—

- 1 जावर माइन्स व डेयरी में जिक स्मेल्टर,
- 2 कोटा में प्रेगिमन इस्ट्रुमेन्ट्स प्लांट,
- 3 जेनडी में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अन्तर्गत तांबा शोधन कारखाना,
- 4 मौंभर की नमक खाने,
- 5 अजमेर में HMT का घाटिंग मशीन दल कारखाना,
- 6 भरतपुर में रेनवे बेगन कारखाना (रेल विभाग)।

(B) राज्य सरकार द्वारा संचालित उपक्रम—इनमें विनियोजित पूँजी सरकार की है तथा उनका स्वामित्व प्रबन्ध एवं नियंत्रण भी राजस्थान राज्य सरकार के हाथ में है—1 गंगापुर गुंजर भिच, 2 हाई टक खास फौजगी, धौलपुर, 3 राजस्थान लघु उद्योग निगम, 4 राजस्थान राज्य विद्युत-मण्डल, जयपुर, 5 राज्य गोशाला निगम 6 राज्य वित्त निगम जयपुर, 7 राजस्थान एगो इण्डस्ट्रीज लि, 8 राजस्थान स्टेट होटल्स जयपुर, 9 राजस्थान शीशीमिश एव खनिज विकास निगम, 10 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम प्रमुख हैं।

### सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों व उपक्रमों की समस्याएँ व समाधान के सुझाव

यद्यपि भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का तेजी से विकास एवं विस्तार हुआ पर उनके मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ व समस्याएँ हैं अतः उनकी उपस्थितियाँ आकर्षण नहीं कही जा सकती।

1. प्रमुख की समस्या—सार्वजनिक उपक्रमों के संचालन के कठोर नियमों का अक्षरार्थ पालन करने में तात्पर्य अभाव रहता है। यंत्रनिर्माणकारियों में व्यावसायिक कुशलता व तकनीकी ज्ञान का अभाव होने से गहन निरीक्षण, अनावश्यक

विलम्ब, नौकरशाही एवं लालफीताशाही का बोलबाला होता है। परिणाम यह होता है कि फिजूलखर्ची एवं प्रशासनिक अकुशलता उद्योग की सशक्तता में बाधक बनती है।

1. इस समस्या के समाधान के लिए योग्य, तकनीकी एवं व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों को ही प्रबन्ध का भार सौंपना चाहिये तथा प्रबन्ध के उत्तरदायी व्यक्तियों को सीमित स्वतन्त्रता देनी चाहिये ताकि वे अपनी तर्कशक्ति, निर्णय चातुर्य व उत्पादन प्रेरणा का यथासम्भव प्रयोग कर प्रशासन में कुशलता ला सकें। समय-समय पर प्रशिक्षण व रिफ्रेशर कोर्स भी चालू किये जाने चाहियें।

2. संगठन की समस्याएँ—सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों को संचालित करने के लिए अलग-अलग संगठन व्यवस्था है अतः कोई एक विशिष्ट एवं एकरूप नीति अपनाने में कठिनाई रहती है। सभी एक ही प्रकार की इकाइयों में प्रतिस्पर्धा का अभाव रहने से उनकी तुलनात्मक क्षमता का पता लगाना कठिन है।

अतः इस समस्या के समाधान के लिए संगठन में एकरूपता का प्रयास करना चाहिए। मनुभाई शाह के अनुसार “एक इकाई एक कम्पनी” संगठन का सर्वोष्ठ स्वरूप है। इससे प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। प्रबन्ध में परिस्परिण व समयानुकूल परिवर्तन सम्भव होता है। 1951 में गोरवाला समिति ने सार्वजनिक उद्योगों के संचालन में मन्त्रियों व सदस्य सदस्यों को शामिल न करने की सिफारिश की थी। सभी प्रकार के योग्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व उपयुक्त रहता है।

3. उत्पादन क्षमता के पूर्ण उपयोग की समस्या—भारत में एक ओर उत्पादन वृद्धि के लिए वैसे ही कुल क्षमता कम है और दूसरी ओर उपलब्ध क्षमता का भी पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो पाता। 1965-66 में राबी हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट की क्षमता का केवल 15% का प्रयोग हो पाया। 1969 में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की केवल 45-48% क्षमता का, हिन्दुस्तान स्टील की 60% क्षमता का, भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स की केवल 29% क्षमता, हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स क्षमता के 67% भाग का ही उपयोग हो पा रहा था जबकि शेष क्षमता अग्रयुक्त थी। आपात स्थिति की घोषणा के बाद पूरी क्षमता का प्रयोग किया जा रहा है।

इस समस्या का समाधान करने के लिए पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग जरूरी है। आवश्यक कच्चे मान, कल-पुर्जों आदि के अभाव से कारखाने के बन्द होने की नौबत से बचने के लिए योजनाबद्ध ढंग से उत्पादन किया जाना चाहिए।

4. संसद, केंद्र तथा राज्य सरकारों के हस्तक्षेप की समस्या भी बड़ी जटिल है क्योंकि व्यावसायिक निर्णयों पर राजनैतिक एवं निजी स्वार्थी हितों का प्रभाव पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए स्वायत्त शासन निगमों की स्थापना को प्राथमिकता देनी चाहिए तथा उनका संचालन उन योग्य, कुशल व ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों को सौंपना चाहिए जो राजनैतिक हितों को आवश्यक मान्यता न दें।

5. उचित मूल्यों के निर्धारण की समस्या—उन सार्वजनिक उपक्रमों में जो जनोपयोगी सेवाओं में सलग्न हैं अथवा जनहित की महत्वपूर्ण वस्तुओं का उत्पादन करते हैं अतः उनकी एकाधिकारी प्रवृत्ति के कारण उचित मूल्य निर्धारण की समस्या आती है ताकि उपभोक्ताओं को उचित लाभ पर वस्तु मिले तथा सरकार को भी घाटा न उठाना पड़े।

इस समस्या के समाधान के लिए सार्वजनिक उपक्रमों में लागत लेखा तथा प्रबन्ध लेखा पद्धति का यथोचित प्रयोग होना चाहिए। इससे अपव्यय का भी पता लगेगा और उचित मूल्य व उचित लाभ पर वस्तुएँ उपलब्ध की जा सकेंगी।

6. घाटे की समस्या—जब सार्वजनिक उपक्रमों में विपुल धन-राशि विनियोजित करने के बाद लाभ की बात तो दूर रही—घाटा उठाना पड़ता है तो वह समस्या अति कष्टदायक है। हिन्दुस्तान स्टील लि० भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है उसमें लगभग 1400 करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई है पर अब तक उसमें लगभग 200 करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है। 31 मार्च 1972 को सार्वजनिक क्षेत्र में 99 उपक्रमों में से 54 इकाइयों ने घाटा दिखाया। उनमें 17 इकाइयाँ तो ऐसी थीं जो लगातार पिछले तीन वर्षों से घाटे में चल रही थी। इन तीन वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों का घाटा 65.9 करोड़ रुपये था। 1971-72 के बाद स्थिति में कुछ सुधार आया है। 1973-74 में इनका कुल लाभ 272 करोड़ रुपये तथा शुद्ध लाभ 64 करोड़ रुपये था जबकि 1976-77 में कुल लाभ 1054 करोड़ रुपये तथा शुद्ध लाभ 240 करोड़ रुपये था।

इस समस्या का समाधान योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति, कुशल संचालन, उपयुक्त मूल्य नीति, अप्रयुक्त क्षमता का पूरा-पूरा प्रयोग तथा अतिरिक्त श्रम शक्ति के आधिक्य को हटाने में निहित है।

7. श्रम आधिक्य व श्रम असन्तुष्टि की समस्या—सार्वजनिक उपक्रमों में आवश्यकता से अधिक श्रमिक नियुक्त करने की सामान्य प्रवृत्ति है। उपयुक्त श्रम नियोजन नीति के अभाव व भाई-भतीजावाद, राजनैतिक प्रभाव आदि के कारण सार्वजनिक उपक्रमों में आवश्यकता से अधिक श्रमिक नियुक्त कर लिये जाते हैं। पाकिस्तान नियम के अनुसार बिना काम बढ़े ही स्टाफ में वृद्धि हो जाती है। यूरो ऑफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज के एक अनुमान के अनुसार 1967 में अकेले हिन्दुस्तान स्टील लि० में 9200 अतिरिक्त श्रमिक थे जबकि सभी सार्वजनिक उद्योगों में 15 हजार का श्रम-आधिक्य था। यही नहीं, इन श्रमिकों को छुट्टी करने, वेतन बढ़ाई भत्ता, काम की सुरक्षा व दयाएँ सुधारने आदि को लेकर हड़तालें तालाबन्दी करते हैं। राजनैतिक दल उस आग को और अधिक भड़का कर अनुचित लाभ उठाते हैं। इन सबका सार्वजनिक उपक्रमों की उत्पादन क्षमता, लाभ की मात्रा, जिम्मेदारी का प्रभावित करता है। इण्डियन एयर लाइन्स में चली सम्बन्धी हड़ताल व तालाबन्दी इसका उदाहरण था। अभी इन उपक्रमों में 15.75 लाख लोग रोजगार में हैं।

इस समस्या का समाधान विवेकपूर्ण नियोजन नीति पर निर्भर है अतः नियुक्तियों में सतर्कता बरतनी चाहिये। अधिको व प्रबन्ध में सौहार्दपूर्ण वातावरण, उच्च मांगों की पूर्ति, सुविधाओं की व्यवस्था तथा अपव्यय पर नियन्त्रण लगाना चाहिए।

8 उत्पादक नीति का बाजार मांग के अनुसार समन्वय—निजी उत्पादकों की भांति सार्वजनिक उपक्रमों में भी उत्पादन की मात्रा बाजार की मांग से अधिक हो जाती है। इससे "उत्पादन-अधिक्य" (Over-production) की समस्या उत्पन्न हो जाती है। 1968-69 में जिन्क स्मेल्टर में उत्पादन एक महीने बन्द कर दिया था।

इस समस्या का समाधान बाजार के सर्वेक्षणों के आधार पर उत्पादन नीति का निर्धारण करने में निहित है। यही नहीं, कम उत्पादन होने पर उत्पादन वृद्धि का प्रयास भी जरूरी है।

9 कर्मचारियों व अधिकारियों में व्यावसायिक कुशलता का अभाव तथा उत्तरदायित्व हीनता की समस्या—सार्वजनिक उपक्रमों के संचालन का उत्तरदायित्व प्रायः प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में सौंपा जाता है जिनमें व्यावसायिक व तकनीकी ज्ञान का नितान्त अभाव होता है। यही नहीं, उनका जन्दी-जन्दी एक-उद्योग से दूसरे उद्योग में स्थानान्तरण होता रहता है। कोई जिम्मेदारी निश्चित नहीं होती। परिणामस्वरूप अपव्यय एवं गैर जिम्मेदारिता का प्रसार होता है। नौकरी की सुरक्षा व व्यवसाय में कोई उत्प्रेरणा न होने से भी उत्तरदायित्व हीनता पैदा होती है।

इस समस्या का समाधान करने के लिए ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों को नियुक्त करना चाहिये जो उस उद्योग विशेष की संचालन विधियों, तकनीकी मामलों की बीमारियों व समस्याओं से अवगत हों। उन पर एक निश्चित उत्तरदायित्व डाला जाना चाहिये तथा लापरवाही, अकुशलता व गैर-जिम्मेदारी के लिए कठोर दण्ड व सफलता पर पुरस्कार, पदोन्नति व उत्प्रेरणाओं की व्यवस्था होनी चाहिये। जल्दी-जल्दी हस्तान्तरण को हतोत्साहित करना चाहिए।

### परीक्षोपयोगी प्रश्न मय संकेत

1 सार्वजनिक उद्योग से व्यापक क्या अभिप्राय है? इनके विकास के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दीजिये।  
अथवा

सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग के महत्व एवं दोषों (कमियों) का उल्लेख कीजिये।

(संकेत —प्रथम भाग में सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों का अर्थ बनाकर द्वितीय भाग में उसके लाभ, गुण अथवा पक्ष में तर्क देना है तथा तीसरे भाग में अथवा दोषों या विपक्ष के तर्क देकर समीक्षा करनी है।)

2. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र, उपक्रमों अथवा उद्योगों के विकास पर प्रकाश डालिये तथा उनकी स्थापना के उद्देश्य बताइये।

अथवा

भारत में सार्वजनिक उद्योगों के उद्देश्यों व उनके विकास पर प्रकाश डालिये।

(सकेत — प्रथम भाग में सार्वजनिक उपक्रम का अर्थ, दूसरे भाग में उसके उद्देश्य (पक्ष में तर्क) देकर विकास पर प्रकाश डालना है।)

3. 'सार्वजनिक उपक्रमों के संगठन के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिये तथा उनमें कौनसी व्यवस्था उपयुक्त है, बताइये।

(सकेत — सार्वजनिक उपक्रमों के संगठन के चार रूपों का भारतीय संदर्भ में विवरण देकर उनके श्रेष्ठत्व पर प्रकाश डालना है तथा अन्त में निगम व्यवस्था को उपयुक्त बताना है।)

4. सार्वजनिक उपक्रमों के विकास व समस्याओं को समझाइये तथा समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव दीजिये।

(सकेत — सार्वजनिक उपक्रमों के विकास का विवरण योजनावार या संक्षेप में एक साथ देकर उनकी समस्याओं को ध्यायानुसार समझाना है तथा साथ-साथ सुझाव देना है।)

5. भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक उपक्रम के विकास का आलोचनात्मक विवरण दीजिये।

(सकेत — पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों के विकास का विवरण व तालिका देना है, फिर समस्याएँ व आलोचनाएँ देनी हैं।)

6. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण इकाइयों का विवरण दीजिये।

(सकेत — इसमें ध्यायानुसार महत्वपूर्ण इकाइयों का विवरण देना है।)

7. 'भारत में सार्वजनिक क्षेत्र इतना सफल नहीं रहा जितना निजी क्षेत्र' विवेचना कीजिये। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की व्यावसायिक इकाइयों की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख भी कीजिये। (Raj III Yr B Com 1979)

(सकेत — सार्वजनिक क्षेत्र की उपलब्धियाँ देकर विवेचना देनी है तथा फिर उसकी समस्याएँ बताना है।)



# भारत में पूँजी गहन अथवा बृहत्-उद्योग

(Capital Intensive or Large Scale Industries in India)

भारत में आधुनिक बड़े बड़े पैमाने के उद्योगों का सूत्रपात 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अनुकूल परिस्थितियों के कारण हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के कारण इन उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिला। 1921 में देश में उद्योगों को विभेदारमक संरक्षण (Discriminating Protection) दिया जाने से उन्हें विदेशी प्रतिस्पर्धा व मन्दिकाल के सकट से राहत मिली। जैसे तैसे द्वितीय महायुद्ध के पूर्व देश में पूँजी गहन उद्योगों का ठीक-सा आधार तैयार हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद उद्योगों के योजनाबद्ध तीव्र विकास की आवश्यकता को देखते हुए पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास का एक सुदृढ़ आधार तैयार किया गया और उनकी द्रुत गति से प्रगति हुई। आज भारत बड़े उद्योगों की दृष्टि से विश्व के औद्योगिक देशों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पूँजी विनियोग, उत्पादन मात्रा एवं रोजगार की दृष्टि से कतिपय महत्वपूर्ण उद्योगों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है

## 1. सूती वस्त्र उद्योग (Cotton Textile Industry)

यह भारत का सबसे बड़ा एवं प्राचीनतम उद्योग है। भारत की ढाका की मलमल व सूती वस्त्रों की लोकप्रियता व प्रसिद्धि सम्पूर्ण सप्ताह में थी पर ब्रिटिश सरकार की दोषपूर्ण नीति से इन लघु स्तर पर चलने वाले सूती वस्त्र उद्योगों का पतन हुआ। प्रथम सूती मिल 1818 में कलकत्ता में लगायी। 1851 में श्री डार्वर ने कटाई व बुनाई मिल में उत्पादन प्रारम्भ किया। 1854 के बाद बम्बई, अहमदाबाद, कानपुर, मद्रास व नागपुर में इस उद्योग का तेजी से विकास हुआ। 1860 में देश में केवल 3 मिलें थी जबकि 1900 तक देश में सूती मिलों की संख्या 190 थी और 40 हजार करघे एवं 1 56 लाख श्रमिक कार्यरत थे। उनमें 82 मिलें अकेले बम्बई में थी।

1905 में स्वदेशी आन्दोलन तथा 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के कारण उद्योग में चमत्कारी प्रगति हुई। अतः जहाँ 1907 में सूती मिलों की संख्या 224 थी वह 1914 में बढ़कर 271 हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के उपरान्त भारतीय सूती वस्त्र

उद्योग को जापान में कठोर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। जापान से आयात 1918-19 में 24 करोड़ गज था वह 1928-29 तक 59 करोड़ गज तक पहुँच गया। 1930 की विश्व-व्यापी आर्थिक मंदी ने तो इसकी कमर ही तोड़ दी किन्तु सरकार ने इस उद्योग को राहत प्रदान की। 1939 में पुनः द्वितीय विश्व युद्ध ने उद्योग को सहारा दिया। जहाँ 1922 में सूती कपड़े का उत्पादन 173 करोड़ गज था वह बढ़कर 1945 में 485 करोड़ गज हो गया तथा सूती मिलों की संख्या भी 421 हो गई।

**स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पञ्चवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत**

**सूती वस्त्र उद्योग की प्रगति**

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय 1947 में विभाजन के बाद 380 मिलें भारत में रही किन्तु कपास उत्पादन करने वाले 40% महत्वपूर्ण क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने से 'कपास संकट' ने उद्योग की प्रगति में बाधा उत्पन्न की।

**प्रथम योजना**—योजना के प्रारम्भ में सूती मिलों की संख्या 378 थी और उनके द्वारा 340 करोड़ मीटर कपड़ा तथा 53.4 करोड़ किलोग्राम सूत का उत्पादन किया जाता था। योजना काल में उद्योग के विस्तार व उत्पादन क्षमता में वृद्धि के फलस्वरूप 1955-56 में सूती मिलों की संख्या 412 हो गई तथा उनमें 466.5 करोड़ मीटर कपड़ा तथा 74.4 करोड़ किलोग्राम सूत उत्पादित किया गया था।

**द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना**—द्वितीय योजनाकाल में वार्षिक उत्पादन 800 करोड़ मीटर करने का लक्ष्य था। उसमें से संगठित मिलों के लिए 465 करोड़ मीटर निर्धारित किया गया। 1960-61 तक सूती मिलों की संख्या 479 हो गई पर कपड़ा की संख्या 203 हजार से घटकर 199 हजार कर दी। उत्पादन-क्रम में कमी की गई व आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। योजना के अन्त में मिलों द्वारा निर्मित कपड़ का उत्पादन 465 करोड़ मीटर तथा सूत का उत्पादन 80 करोड़ किलोग्राम था। प्रति व्यक्ति कपड़ की खपत 14.7 मीटर से बढ़कर 15 मीटर तक पहुँच गई।

**तृतीय पञ्चवर्षीय योजना**—इस योजना में 870 करोड़ मीटर कपड़ा उत्पादन का लक्ष्य था जिसमें संगठित मिलों के लिए 540 करोड़ मीटर का लक्ष्य था। 105 करोड़ रु. आधुनिकीकरण पर व्यय किया गया। विकास के फलस्वरूप मिलों की संख्या 479 से बढ़कर 575 हो गई पर उत्पादन लक्ष्य से कम रहा। मिलों द्वारा 440 करोड़ मीटर कपड़े का उत्पादन किया गया। प्रति व्यक्ति खपत 15 मीटर से बढ़कर 18.3 मीटर हो गई।

**तीन वार्षिक योजनाएँ—(1966-69)—**1965-66 तथा 1966-67 में अभूतपूर्व अवकाल, कपास की कम उत्पत्ति व बाजार माग में शिथिलता से उद्योग को भारी धक्का लगा। 1968-69 में मिल क्षेत्र का उत्पादन 430 करोड़ मीटर हो रहा। 1968 में सूती वस्त्र निगम की स्थापना की गई जिसका प्रमुख कार्य नयी

-भारत में सूती गहन अथवा बृहत्-उद्योग

मिलों की स्थापना करना, कमजोर मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने इत्यादि आधुनिकीकरण के लिए ऋण देना है। अब तक इस निगम ने 28 कमजोर मिलों को अपने हाथ में ले लिया है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना—इस योजना में सूती वस्त्र का कुल उत्पादन 935 करोड़ मीटर करने का लक्ष्य रखा गया जिसमें मिलों द्वारा 510 करोड़ मीटर कपड़ा उत्पादन होना था। 25 नयी सूती मिलें सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित की जानी थी। योजना के अन्त में देश में सूती मिलों की संख्या 680 थी। सूती मिलों के विस्तार पर 134 करोड़ रुपये तथा पुनर्स्थापन तथा आधुनिकीकरण पर 132.5 करोड़ रु. व्यय होने का अनुमान है।

पाचवी पंचवर्षीय योजना में सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन लक्ष्य 950 करोड़ मीटर रखा गया था जिसमें 480 करोड़ मीटर मिल क्षेत्र में तथा 470 करोड़ मीटर बिकेन्द्रित क्षेत्र में उत्पादित करना था किन्तु योजना के चार वर्षों में ही 1977-78 में उत्पादन 960 करोड़ मीटर हुआ जो लक्ष्य से भी अधिक था।

इस प्रकार पिछले 28 वर्षों के योजनाबद्ध विकास के अन्तर्गत सूती वस्त्र उद्योग की काफी प्रगति हुई है जिसकी झलक निम्न सारणी से लगती है—

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सूती-वस्त्र उद्योग की प्रगति (1951-79)

वर्ष	मिलों की संख्या	मिलों द्वारा उत्पादित कपड़ा (करोड़ मी.)	हाथ करघों तथा शक्ति करघों द्वारा उत्पादित कपड़ा (करोड़ मीटर)	कुल उत्पादन (करोड़ मी.)	प्रति व्यक्ति वस्त्र उपलब्धता (मीटर)
1951	378	373	101	474	10.99
1956	412	486	166	652	14.7
1961	479	470	237	707	14.74
1966	575	424	310	734	13.8
1973-74	680	400	380	780	13.5
1974-75	700	430	400	830	13.3
1975-76	702	402	410	812	13.1
1977-78	702	416	410	826	13.0
1978-79	704	480	470	950	14.8

जहाँ 1950-51 में सूत व सूती वस्त्र निर्यात मूल्य 138.4 करोड़ रुपये था वह घटकर 1965-66 में 90 करोड़ रु. ही रह गया। पर निर्यात प्रोत्साहन के कारण 1973-74 में निर्यात 371 करोड़ रु. का था। 1977-78 में निर्यात केवल 457 करोड़ रु. होने का अनुमान है।

**वर्तमान स्थिति**—अब भारत में लगभग 704 सूती मिलें हैं और उनमें 2.5 लाख रुपये तथा 260 लाख तकिए लगे हुए हैं। उनमें लगभग 550 करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई है तथा उनके द्वारा प्रतिवर्ष 1300 से 1400 करोड़ रु. मूल्य का उत्पादन किया जाता है। देश की श्रम शक्ति का लगभग 20% इस उद्योग में लगा हुआ है। इस उद्योग में 12 लाख श्रमिक लगे हुए हैं तथा 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। भारत सरकार को भी उत्पादन करो से प्रतिवर्ष लगभग 50 करोड़ रु. की आय होती है।

छठी पंचवर्षीय योजना में सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन लक्ष्य 1220 करोड़ मीटर रखा गया है जिसमें 460 करोड़ मीटर मित्र क्षेत्र तथा 760 करोड़ मीटर विदेशित क्षेत्र में होगा। 1978-79 में मित्र क्षेत्र में उत्पादन 480 करोड़ मीटर तथा विकेंद्रित क्षेत्र में उत्पादन 470 करोड़ मीटर रहा।

### सूती वस्त्र उद्योगों की समस्याएँ एवं समाधान के सुझाव

पिछले 10-15 वर्षों से इस उद्योग को भारी सबट का सामना करना पड़ रहा है यहाँ तक कि लगभग 100 मिल बन्द हो चुकी हैं। इनमें से अधिकांश बीमार मिल दक्षिण भारत में हैं। उनकी वित्तीय स्थिति शोचनीय है। बच्चे माल का प्रभाव विदेशों में प्रतिस्पर्धा तथा अभिनवीकरण की समस्या है। मुख्य समस्याएँ व उनके समाधान के सुझाव इस प्रकार हैं—

1. **अभिनवीकरण की समस्या (Problem of Modernisation)**—भारत की अधिकांश मिलों में मशीन 100 वर्ष पुरानी हैं। लगभग 25% मशीनें बिल्कुल बेकार हो गई हैं जबकि आधुनिक स्वचालित मशीनों का अभाव है। इन पुरानी मशीनों के अभिनवीकरण पर 1000 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मजदूरी भी अभिनवीकरण के मार्ग में अड़बट पैदा करती है। पिछले वर्षों में केवल 20% मशीनों का ही अभिनवीकरण किया जा सका है। शेष 80% अभी भी पुरानी ही हैं।

अभिनवीकरण के लिए प्रयासों को भूत रूप देने के लिए वित्तीय सहायता द्वारा पर्याप्त ऋण व सरकार द्वारा अनुदानों की व्यवस्था करनी चाहिए। श्रमिकों के विरोध को कम करने के लिए अभिनवीकरण का कार्य इस प्रकार कार्यान्वित किया जाना चाहिए कि बगैर श्रमिकों की छुट्टी किए ही काम हो जाय।

2. **बच्चे माल की बमी**—1947 के विभाजन के बाद से ही भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का बच्चे माल की बमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि लम्बी रेशे की रूई के उत्पादन में वृद्धि हुई है फिर भी विदेशों के मायास/पर

भारत में पूँजी गहन अथवा वृहत्-उद्योग

निर्भर करना पड़ता है। गत दो वर्षों में भी कच्चे माल की विकट समस्या उत्पन्न हुई है।

बढ़िया किस्म के कपड़े का उत्पादन करने के लिये लम्बे रेशे की रूई के उत्पादन व बोये गये क्षेत्र में वृद्धि करना आवश्यक है।

3 विदेशी प्रतिस्पर्धा तथा निर्यात—भारत को विदेशी बाजारों में कपड़ा निर्यात करने में जापान, चीन, हांगकांग तथा पाकिस्तान की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। चूँकि भारत में कीमती ऊँची हैं, उत्पादन लागत अधिक है तथा उत्पादन मशीनें पुरानी हैं। भारत का निर्यात जो 1950-51 में 138.4 करोड़ रु मूल्य का था वह 1965-66 में घटकर 90 करोड़ रु हो रहा गया। अब निर्यात प्रयत्नों के फलस्वरूप निर्यात 1975-76 में 406.7 करोड़ रु हो गया है। इसमें और कमी आने की सम्भावना है। इस समस्या का समाधान करने के लिए उत्पादन लागत में कमी, कच्चे माल की पूर्ति में वृद्धि मिलो में अभिनवीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौते के द्वारा निर्यात वृद्धि करने की आवश्यकता है। निर्यातक मिलों को प्रोत्साहन देना चाहिये तथा उन्हें करो से मुक्ति या रियायतें आदि का प्रलोभन देना होगा।

4 संगठित मिलों तथा विकेन्द्रित हाथ करघों व शक्ति चालित करघों के उत्पादन में सामंजस्य की समस्या रोजगार अभिवृद्धि के उद्देश्य से प्रेरित हो। सरकार द्वारा मिल क्षेत्र पर मनमाने ढंग से नियन्त्रण लगाये जाते हैं। उत्पादन को सीमित किया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय उद्योग के दो अलग अलग भागों में पक्षपात बरता जाता है।

सरकार को संगठित सूती मिलों के सम्बन्ध में निश्चित नीति अपनानी चाहिये और संगठित व विकेन्द्रित क्षेत्रों में परस्पर उचित समन्वय बैठाना चाहिये।

5 कृत्रिम रेशा वस्त्र-उद्योग से प्रतिस्पर्धा—प्राजबल टेरेलिन, नॉयलान आदि कृत्रिम रेशों से उत्पादन कपड़ों का प्रचलन बढ़ रहा है। इनका प्रयोग 12 वर्षों में लगभग तिगुना हो गया है। विदेशी बाजारों में भी कृत्रिम रेशे के कपड़ों की वृद्धि बढ़ जाने से सूती वस्त्रों की मांग घट रही है। क्लीफोर्ड हार्डिन के शब्दों में "कपास का रेशा जिसका मुकाबला कोई अन्य प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रेशा नहीं कर सकता, अनुसंधान, प्रवर्तन और बिजली की दृष्टि से कृत्रिम रेशों द्वारा पछाड़ दिया गया है।"

इस समस्या का समाधान करने के लिये सूती-वस्त्र की उत्पादन लागत को कम करने, अनुसंधान से उसकी किस्म में सुधार करने का प्रयास करना चाहिये।

6 अलाभकारी एवं अकुशल मिलों की समस्या—अनेक मिलों में मशीनें इतनी पुरानी एवं घिसी हुई हैं कि उन्हें नए यन्त्रों से प्रतिस्थापित किये बिना कुशल उत्पादन व्यवस्था सम्भव नहीं होती। उनके पास वित्त साधनों का अभाव है। इन रुग्ण सूती मिलों की लगभग आधी दक्षिणी भारत में हैं। राष्ट्रीय कपड़ा निगम के पास 103 बीमार मिलें हैं जिनमें 16 लाख अधिक कार्यरत हैं।

7 बढ़ती हुई लागतों की समस्या—पिछले दशक से सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं। मजदूरी दरों में 80 से 120% वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप सूती वस्त्रों की कीमतें लगभग दुगुनी हो गई हैं। बढ़ती लागतों के कारण निर्यात में वृद्धि नहीं हो पाती। जनता कपड़े के उत्पादन की अनिवार्यता के कारण अनेक मिलों की प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रु. का घाटा उठाना पड़ता है।

इस समस्या का समाधान उचित कीमत नीति अपनाने, अपव्यय को रोकने तथा स्वपालित मशीनों के प्रयोग में निहित है।

8. सरकार की दोषपूर्ण नीति व क्षमता का पूर्ण उपयोग न होना—सरकार सूती मिलों के कपड़े की उत्पत्ति को सीमित करने की नीति अपनाती रही है परिणामस्वरूप सूती मिलों की पूरी-पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है। मोट रूप में कुल क्षमता के 70% का ही प्रयोग होता है। इस समस्या का समाधान करने के लिये सरकार ने अब पूरी-पूरी उत्पादन क्षमता के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया है। ऊँचे करो के स्थान पर करो में छूट कर दी गई।

9 क्षम उत्पादकता का नीचा स्तर—भारत में श्रमिकों की उत्पादकता विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। जहाँ अमेरिका में 2 श्रमिक लगभग एक हजार तकुओं की देखभाल करते हैं जबकि भारत में एक हजार तकुओं की देखभाल करने के लिये 10 श्रमिकों की आवश्यकता होती है।

इस समस्या का समाधान श्रमिकों की नियुक्ति में सतर्कता, उचित प्रशिक्षण, प्राधुनिकतम मशीनों का प्रयोग आदि के द्वारा सम्भव है।

### जनता सरकार की नई कपड़ा नीति

भारत सरकार ने सूती कपड़ों सम्बन्धी नीति की घोषणा 7 अगस्त 1978 को कर दी जिसके अनुसार सूती मिलों के लिये कन्ट्रोल का कपड़ा बनाने की अनिवार्यता 8 दिसम्बर 1978 से समाप्त करने का फैसला किया है। कन्ट्रोल के कपड़े का उत्पादन धीरे-धीरे मिलों से हटाकर हाथ-करघा उद्योग को सौंपा जायगा। कमजोर वर्ग को सस्ता कपड़ा मुहैया करने का काम तथा हाथ-करघा उद्योग का विकास दोनों एक साथ करने के उद्देश्य से हाथ-करघा उद्योग में बने कपड़े पर सरकार सबसिडी भी समय-समय पर निर्धारित करेगी। अब मिलों में कन्ट्रोल का कपड़ा 40 करोड़ वर्ग मीटर ही तैयार किया जायगा जो राष्ट्रीय कपड़ा नियम के निर्धारित कोटा व शेष निजी मिलों का दायित्व होगा। नई जाति के अनुसार न तो पावर-लूम क्षमता में वृद्धि की जायगी और न मिलों को नूतन उत्पादन की क्षमता बढ़ाने की इजाजत दी जायगी। पावर-लूम की अनधिकृत इकाइयों को भारी जुर्माने के साथ नियामक कर पजीबड किया जायगा।

सरकार की यह कपड़ा नीति हाथ-करघा एवं खादी जैसे विकेंद्रित क्षेत्र के विकास एवं गरीब वर्ग को सस्ता कपड़ा मुहैया करने के साथ-साथ रोजगार अवसरों में वृद्धि की नीति है।

## 2 लोहा-इस्पात उद्योग

(Iron & Steel Industry)

यह उद्योग आधुनिक युग में औद्योगीकरण, कृषि विकास, परिवहन विकास सभी का प्रमुख आधार है क्योंकि लोहा एवं इस्पात मशीनों, कारखानों, औजारों, पुलों, भवनों सभी में काम आता है। भारत में इस उद्योग के अति प्राचीन काल के अवशेष दिल्ली में “अशोक का स्तम्भ” अब भी विश्व वैज्ञानिकों के लिये आश्चर्य का विषय बना हुआ है कि जो स्तम्भ ईसा से पूर्व प्रथम शताब्दी में निर्मित किया गया उस पर आज तक जग नहीं लगा है। आधुनिक ढंग का कारखाना, सर्व प्रथम 1830 में मद्रास में श्री हीथ (Heath) द्वारा स्थापित किया गया पर असफल रहा। उसके बाद 1857 में आसनसोल बंगाल आयर्न कम्पनी, 1875 में बंगाल आयर्न एण्ड स्टील कम्पनी बनाई गई पर ये कम्पनियाँ इस्पात बनाने में सफल न हो सकी।

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व लोहा-इस्पात उद्योग का विकास—भारतीय लोहा-इस्पात उद्योगों में प्रथम महत्वपूर्ण एवं चिरस्मरणीय प्रयास भारतीय उद्योगपति श्री जमशेदजी नशरवानी टाटा द्वारा 1907 में सिंहभूमि जिले में टाटा आयर्न एण्ड स्टील कम्पनी की स्थापना का था जिसने 1911 में कच्चे लोहे तथा 1913 में इस्पात का उत्पादन प्रारम्भ किया। प्रथम विश्व-युद्ध में इस उद्योग को काफी प्रोत्साहन व सफलता मिली अतः 1918 में हीरापुर इण्डियन आयर्न एण्ड स्टील कम्पनी तथा 1923 में मैसूर राज्य सरकार ने भद्रावली में मैसूर आयर्न वर्क्स की स्थापना की। 1915 में लोहे का उत्पादन 1.62 लाख टन था वह बढ़कर 1916-17 में 2.32 लाख टन हो गया व इस्पात का उत्पादन 0.99 लाख टन था।

1921-22 में लोहा-इस्पात की कीमतें गिरने से उद्योग में संरक्षण की मांग की जाने लगी। 1924 में उद्योग को 3 साल के लिये संरक्षण दिया गया तथा इस अवधि में 2.4 करोड़ रु. की आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। 1930 की विश्वव्यापी मंदी में उद्योगों को भारी संकट का सामना करना पड़ा जबकि 1927 में ही संरक्षण की अवधि 7 साल और बढ़ा दी गई थी वह 1947 तक चलता रहा। 1939 में इण्डियन आयर्न एण्ड स्टील कम्पनी का विस्तार किया गया तथा आसनसोल में स्टील कारपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। उस समय कच्चे लोहे का उत्पादन 18 लाख टन तथा इस्पात का उत्पादन 8 लाख टन था।

द्वितीय विश्व-युद्ध में लोहा-इस्पात की मांग में अचानक वृद्धि हो जाने से उसकी कीमतें बढ़ी और उद्योग ने आश्चर्यजनक प्रगति की।

**स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् लोहा-इस्पात उद्योग का विकास**

युद्धोत्तर काल में उद्योग की मांग कम हो जाने, मशीनों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता, पूँजी के अभाव व अथम समस्या आदि ने उद्योग को पुनः संकट में डाल दिया। 1947 में जब भारत स्वतन्त्र हुआ तो देश में लोहा-इस्पात का उत्पादन

9 लाख टन था और लोह-इस्पात उद्योग के तीन बड़े कारखाने—(1) टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (Tisco) (2) इण्डियन आयरन एंड स्टील कंपनी (Iisco) तथा (3) मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स (Misco) कार्यरत थे। 1948 की प्रथम औद्योगिक नीति में इस उद्योग के भावी विकास का उत्तरदायित्व पूर्णरूपेण सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। 1950 तक भी इस्पात का उत्पादन 10 लाख टन से कम ही था।

**प्रथम पंचवर्षीय योजना**—इस योजना में सभी चालू कारखानों के आधुनिकीकरण व विस्तार की योजनाओं को कार्यान्वित करने पर 63 करोड़ रु व्यय हुआ जिसमें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी पर 34 करोड़ रु, इण्डियन आयरन पर 15 करोड़ रु तथा मैसूर स्टील कंपनी पर 14 करोड़ रु व्यय किया गया। परिणामस्वरूप जहाँ 1950-51 में बच्चे ताड़े का उत्पादन 14 लाख टन तथा इस्पात का उत्पादन 10 लाख टन था वह बढ़कर 1955-56 में क्रमशः 19.15 लाख टन तथा 12.86 लाख टन हो गया। 1953 में हिन्दुस्तान स्टील कंपनी लि की स्थापना की गई जिसने दुर्गापुर भित्ताई व रुर्केला में सार्वजनिक क्षेत्र के लोह-इस्पात कारखाने स्थापित करने के लिये विदेशी कंपनियों से समझौते किए।

**द्वितीय पंचवर्षीय योजना**—इस योजना में औद्योगीकरण एवं आधारभूत उद्योगों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। 1956 की नीति में भी लोह-इस्पात उद्योग के विकास व सरकारी दायित्व को पुन दोहराया गया। अतः लोह-इस्पात उद्योग की नई एक इकाई स्थापित करने एवं पुरानी इकाइयों का विस्तार व आधुनिकीकरण पर ज़ोर दिया गया। योजना काल में 431 करोड़ रु व्यय से सार्वजनिक क्षेत्र में तीन बड़े लोह-इस्पात कारखाने दुर्गापुर (प. बंगाल), भित्ताई (मध्य प्रदेश) तथा रुर्केला (उड़ीसा) में क्रमशः ब्रिटेन, रूस तथा जर्मनी की सहायता से स्थापित किए जिनमें प्रत्येक की उत्पादन क्षमता 10 लाख टन थी पर 1960-61 तक ये तीनों इकाइयाँ केवल 6 लाख टन इस्पात का ही उत्पादन कर रही थी। तीनों पुराने कारखानों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण की योजनाओं को कार्यान्वित कर उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि की गई। योजना के अन्त में बच्चे लोह का उत्पादन 19 लाख टन से बढ़ाकर 35 लाख टन तथा इस्पात का उत्पादन 12.86 लाख टन से बढ़ाकर 23 लाख टन कर दिया जबकि उत्पादन कुल क्षमता 50 लाख टन इस्पात तैयार करने की थी।

**तृतीय पंचवर्षीय योजना**—लोहा इस्पात की बढ़ती मांग को देखते हुए इस योजना में इस्पात पिण्डों का उत्पादन 92 लाख टन तथा इस्पात का उत्पादन 68 लाख टन करने का लक्ष्य था। तीनों सरकारी कारखानों की क्षमता दुगुनी करने का लक्ष्य रखा गया। सार्वजनिक क्षेत्र के एक नया लोह-इस्पात कारखाना बोकारो में स्थापित करने का प्रावधान था। योजनाकाल में इस उद्योग के विकास पर 425 करोड़ रु व्यय करने की व्यवस्था थी। 1962 में चीनी आक्रमण तथा 1965 में



भारत में पूँजी गहन ग्रन्थवा वृहत-उद्योग

पाकिस्तानी आक्रमणों के कारण उद्योग के विकास को घटका पहुँचा। योजना के अन्त तक इस्पात पिण्डों का उत्पादन 65 लाख टन तथा तैयार इस्पात का उत्पादन 45 लाख टन ही हो पाया। बोकारो कारखाने की स्थापना भी सम्भव न हो सकी।

तीन वार्षिक योजनाएँ—(1966-69)—इस अवधि में उद्योग के विकास की कोई नयी योजना चालू न कर केवल चालू बाधों को पूरा करने का लक्ष्य रखा। बोकारो कारखाने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। 1966-67 तथा 1967-68 में विभिन्न कारखानों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया फिर भी उत्पादन प्रायः स्थिर रहा। 1968-69 में इस्पात पिण्डों का उत्पादन 65- लाख टन तथा तैयार इस्पात का उत्पादन 46 लाख टन रहा।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना—इस योजना में लोह इस्पात की बढ़ती मांग को देखते हुए इस्पात पिण्डों का उत्पादन 117 लाख टन तथा तैयार इस्पात का उत्पादन 18 लाख टन करने का लक्ष्य था। बोकारो व मिलाई इस्पात कारखानों की क्षमता क्रमशः 1 करोड़ टन तथा 70 लाख टन तक बढ़ाने का प्रावधान था। तीन नए कारखाने स्थापित करने की योजना को मूर्तरूप देने के लिए तामिलनाडु के सलेम, मैसूर के हास्पेट तथा आन्ध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के तीनों कारखानों का निर्माण कार्य 1971 में हाथ में लिया गया। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में सभी में उत्पादन वृद्धि हुई पर वास्तविक उत्पादन लक्ष्यों से काफी नीचा रहा। तैयार इस्पात का उत्पादन योजना के अन्त में 46 लाख टन ही था जबकि लक्ष्य 81 लाख टन का था। कई इकाइयाँ अपनी कुल उत्पादन क्षमता का 50 से 60% भाग का ही उपयोग कर पा रही थी। 1972 में इण्डियन स्टील एण्ड स्टील कम्पनी को भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया।

पाँचवीं योजना—इस योजना के वर्ष 1978-79 तक देश में इस्पात की भ्रान्तरिक मांग 100 लाख टन होने का अनुमान था। अन्त देश के कारखानों में 88 लाख टन तैयार इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया और 2237 करोड़ रुपये व्यय के प्रावधान से (i) भिलाई कारखाने की क्षमता 40 लाख टन करने, (ii) बोकारो की क्षमता बढ़ाकर 47.5 लाख करने, (iii) विजयनगर एवं विशाखापट्टनम स्टील परियोजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित करने (iv) एलोय स्टील व विशेष इस्पात के लिये सलेम स्टील कारखाने की स्थापना, (v) दुर्गापुर स्टील प्लांट की उत्पादन क्षमता का पूरा पूरा उपयोग करने व मैसूर स्टील प्लांट में अधिकतम उत्पादन के लिये अतिरिक्त सुविधाएँ देने के साथ साथ निजी क्षेत्र के विस्तार की व्यवस्था की। योजनाकाल में किये गये प्रयासों में 1977-78 में इस्पात का उत्पादन 77.3 लाख टन पहुँच गया।

पिछले 28 वर्षों में लोह इस्पात उद्योग की प्रगति की भल्लक ग्रन्थ तालिका से मिलती है—

## योजनाओं के अन्तर्गत लोह-इस्पात उद्योग की प्रगति (1961-79)

(लाख टन)

वर्ष	इस्पात पिण्ड तैयार	इस्पात	वर्ष	इस्पात पिण्ड	तैयार इस्पात
1950-51	14	10 40	1973-74	63 2	48 9
1955-56	19 2	12 86	1975-76	76 5	54 9
1960-61	34 2	23 00	1977-78	108 0	77 3
			लक्ष्य		
1965-66	65 0	45 00	1978-79	113 2	88 0
			1982-83	150	118
			1987-88	200	154

वर्तमान स्थिति एवं छठी योजना के लक्ष्य—इस प्रकार योजनाबद्ध विकास के पिछले 27 वर्षों में लोह-इस्पात उद्योग की प्रगति काफी सन्तोषप्रद है। इस समय देश में (1) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, (टिस्को) (Tisco), (2) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (IISCO) (इस्को), (3) मंसूर आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (मिस्को) (Misco) के अतिरिक्त हिन्दुस्तान स्टील क के अन्तर्गत, (4) दुर्गापुर लोह-इस्पात कारखाना, (5) भिनाई इस्पात कारखाना तथा (6) कुरुकेला इस्पात कारखाना और अलग अस्तित्व वाला, (7) बोकारो स्टील कारखाना है। पहला कारखाना निजी क्षेत्र में शेष सभी सार्वजनिक क्षेत्र में है। सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखानों में लगभग 2500 करोड़ रु की पूंजी लगी हुई है और देश में 1977-78 में इस्पात का उत्पादन 77.3 लाख टन था जो छठी योजना के अन्त तक 1982-83 में 118 लाख टन तक बढ़ाने का लक्ष्य है। छठी योजना के अन्त में एवं नये इस्पात संयंत्र पर काम शुरू करने की संभावना है। लोह इस्पात उद्योग पर छठी योजना में 2491 करोड़ रु व्यय होगा।

### भारतीय लोह इस्पात उद्योग की समस्याएँ व सुझाव

भारत में लोह-इस्पात उद्योग की प्रगति में अनेक घड़बड़ें हैं उनके कारण ऊँचे लक्ष्य निर्धारित किये जाने के बावजूद भी वास्तविक उत्पादन काफी नीचे रहा है।

1 **अच्छे कोयले का अभाव**—लोह-इस्पात उद्योग में अच्छे किस्म के कोकिंग कोल की आवश्यकता होती है जिसका उत्पादन मांग के मुकाबले काफी कम है। अतः उत्तम कोटि के कोयले के उत्पादन के लिये प्रयास किये जाने चाहिये। कोयले की शुद्धाई करके उसे अच्छे किस्म का बनाना चाहिये।

2 **उत्पादन की निम्न स्तर की तकनीक एवं प्रशिक्षण कर्मचारियों का अभाव**—इस उद्योग में उत्पादन तकनीक व प्राविधिक ज्ञान में इतनी धीमी गति से प्रगति हो रही है कि हम नवीन पद्धतियों से काफी दूर हैं, प्रशिक्षित कर्मचारियों का भी अभाव है अतः उद्योग में हम तकनीकी विशेषज्ञता को भी विदेशों से आमंत्रित करना पड़ता है। यद्यपि भारत में अब इस दिशा में काफी सुधार हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेजों व ट्रेनिंग स्कूलों की स्थापना की गई है। विदेशों में भारतीय प्रशिक्षण प्राप्त

करके लौटते हैं फिर भी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती। अतः और अधिक सुविधाओं का विस्तार करना चाहिये।

3 परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयाँ—भारत में लोहा इस्पात उद्योग में कच्चा खनिज लोहा, मैंगनीज, कोयला तथा निर्मित माल को बाजारों में भेजने आदि के लिए सस्ते, पर्याप्त व शीघ्रगामी परिवहन साधनों का अभाव है। इस समस्या का समाधान परिवहन के सभी प्रकार के साधनों को विकसित करने में निहित है।

4 ऊँची कीमतों व लागतों की समस्या—इस्पात उद्योग की सबसे बड़ी समस्या बढ़ती हुई लागतों व बढ़ते हुये मूल्यों की है। 1958 से 1966 की अवधि में लोहे का मूल्य 60% तथा कोयले का मूल्य 82% बढ़ा है। मजदूरी दरों में अमिको की उत्पादकता की अपेक्षा तीव्र गति से वृद्धि हुई है। भारत में मुद्रा-स्फीति के कारण लोहा इस्पात लागतों व उनके उत्पादन मूल्यों में पिछले दस वर्षों में 150% की वृद्धि हुई है। इसके लिये मितव्ययिता मजदूरी दरों की अपेक्षा उत्पादकता में वृद्धि आदि का प्रयास करना चाहिये।

5 क्षमता के अपूर्ण उपयोग की समस्या—सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उद्योगों में उनकी पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है। 1970-71 में इण्डियन आयरन की 62%, स्लैक्का की 56% क्षमता तथा दुर्गापुर की 43% क्षमता का ही उपयोग हो रहा था जबकि देश में पूर्ति मांग के मुकाबले काफी कम थी। इन कारखानों में पूरी-पूरी क्षमता के उपयोग न होने में मुख्य बाधाएँ—कल पुर्जों के आयात की कठिनाई, मशीनों की देखभाल व मरम्मत की समस्या, श्रमिक विवाद तथा कच्चे माल की समय पर पूर्ति न होना था। अब पूरा उपयोग होने के प्रयास हैं।

अतः सरकार को इन कारखानों की पूरी-पूरी उत्पादन क्षमता के प्रयोग के लिये प्रभावी कदम उठाना चाहिये। इसके लिये कच्चे माल की समय पर व्यवस्था, आवश्यक कल पुर्जों के आयात की व्यवस्था, श्रम विवादों का समय पर निपटारा आदि करना है।

6. इस्पात उद्योग में घाटे की समस्या—निजी क्षेत्र में टाटा आयरन मुनाफा कमा रही है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की हिन्दुस्तान स्टील कंपनी जिसमें लगभग 3000 करोड़ रु की पूँजी लगी हुई है, अपनी स्थापना के बाद से अब तक 200 करोड़ रु. से भी अधिक घाटा उठा चुकी है। पहली बार 1973-74 में 22 करोड़ का लाभ हुआ। अब निरन्तर लाभ हो रहा है।

7. भारत का लोह-इस्पात उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय तुलना में काफी पीछे है—भारत के लोह-इस्पात का उत्पादन की दृष्टि से तेरहवा स्थान है। जापान का प्रथम स्थान, रूस का (12 करोड़ टन) द्वितीय स्थान, अमेरिका का (10-9 करोड़ टन) तृतीय स्थान, इंग्लैंड का (8-9 करोड़ टन) चौथा स्थान तथा पाचवा स्थान पश्चिमी जर्मनी का (4 करोड़ टन) व सातवा स्थान चीन का (2 करोड़ टन) है। भारत का इस्पात उत्पादन विश्व उत्पादन का 1-2% है। प्रति व्यक्ति उपभोग की दृष्टि

से भी भारत का काफी पिछड़ा व छत्तीसवा स्थान है। जहाँ भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात उपयोग 11 किलोग्राम है वहाँ अमेरिका में 685 किलोग्राम, जापान में 490 किलोग्राम पश्चिमी जर्मनी में 488 किलोग्राम, रूस में 428 किलोग्राम और इंग्लैंड में 422 किलोग्राम है।

### भारत में लोह इस्पात उद्योग का भविष्य व सरकारी नीति

जैसा कि पहले कहा जा चुका है लोह इस्पात उद्योग के विकास व विस्तार का उत्तरदायित्व पूर्णरूपेण सरकार ने अपने ऊपर से लिया है अतः सार्वजनिक क्षेत्र में नयी इकाइयाँ स्थापित करने तथा उनकी उत्पादन क्षमता में विस्तार करने की नीति कार्यान्वित की गई है। यहाँ तक कि 1972 में इण्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी का राष्ट्रीयकरण किया गया है। उत्पादन वृद्धि के लिये विशालापट्टनम, सलेम व हास्पेट में नये इस्पात कारखाने निर्माणाधीन हैं। आधुनिकतम मशीनों के आयात के साथ-साथ देश में आवश्यक मशीनों व कलपुजों के उत्पादन वृद्धि का प्रयास है। एलोय स्टील उत्पादन पर काफी जोर दिया जाने लगा है। यही कारण है कि पाचवी योजना में इस उद्योग के विकास, आधुनिकीकरण, विस्तार व अन्य योजनाओं पर 22374 करोड़ रु. व्यय किया जाना था। नये कारखानों के निर्माण तथा पुराने कारखानों के विस्तार की योजनाओं को तीन चरणों में पूरा किया जायगा। प्रथम चरण में कच्चा लोहा, द्वितीय चरण में इस्पात पिण्ड गलाने तथा तृतीय चरण में इस्पात तैयार करने की व्यवस्था की जायेगी। प्रथम चरण के पूरा न होने तक दूसरे चरण शुरु नहीं किये जायेंगे।

माग की दृष्टि से भारतीय लोह-इस्पात उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है क्योंकि देश में पर्याप्त बाजार व बढ़ती हुई माग, कच्चे माल के पर्याप्त भण्डार, सस्ती श्रम शक्ति तथा आवश्यक अनुभव है। धीरे-धीरे तकनीकी एवं प्राविधिकी कर्मचारियों की संख्या भी बड़ रही है। यही क्रम चलता रहा तो भारत के लोह-इस्पात उद्योग का विश्व के इस्पात उत्पादक राष्ट्रों में महत्वपूर्ण स्थान हो जायेगा। एक पच्चीस वर्षीय योजना से सन् 2000 तक विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन 75 मिलियन टन करने का लक्ष्य है।

### 3 जूट या पटसन उद्योग

(Jute Industry)

जूट उद्योग भारत का सगठित एवं विदेशी मुद्रा अर्जन करने वाला प्रमुख उद्योग है। उत्पादन की दृष्टि से भारतीय जूट उद्योग का विश्व में प्रथम स्थान है तथा निर्यात व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें लगभग 250 करोड़ रु. की पूँजी लगी हुई है तथा 30 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त है। जहाँ 1972-73 में जूट उत्पादनों के निर्यात से 250 करोड़ रु. की मुद्रा अर्जित हुई जबकि 1975-76 में

यह घटकर 248 करोड़ रु ही रह गई। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय 1947 के विभाजन के पूर्व भारतीय जूट उद्योग को एकाधिकार प्राप्त था पर विभाजन के बाद यह उद्योग दो देशों में बँट गया। कच्चा जूट उत्पादन करने वालों का 72% क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया किन्तु जूट उद्योग की प्रायः सभी मिलें भारत में ही रही। जूट उद्योग में जूट के बोरे, कालीन दरिया, रंग-बिरंगे पर्दे, सोफों के कवर, वाटर प्रूफ कवर, रंग बिरंग फर्श तथा मिश्रित वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है।

### जूट उद्योग का प्रारम्भिक दिग्गज

जूट उद्योग के रूप में चलने वाले इस उद्योग में ग्रायुनिङ टंग का कारखाना 1855 में जार्ज आफ्लेण्ड के द्वारा पश्चिम बंगाल के रिश्वारा नामक स्थान पर स्थापित हुआ जिसकी उत्पादन क्षमता 8 टन प्रतिदिन थी। यह कारखाना 1858 में बन्द हो गया पर 1859 में जार्ज हैण्डर्सन द्वारा जूट का कपड़ा बनाने का नया शक्ति संचालित कारखाना स्थापित किया गया तदुपरान्त 1862 में तीन कारखाने और स्थापित किये गये। 1868 से 1873 की अवधि में इस उद्योग में खूब लाभ कमाया। 1884 में इण्डियन जूट मिल्स एसोसियेशन लो स्थापित किया गया उस समय 21 जूट मिलें थी जबकि उनकी संख्या 1904 में 38 तक पहुँच गई थी।

1900 से 1913 तक इस उद्योग की तीव्र प्रगति हुई क्योंकि निर्यात में निर्मित माल का प्रतिशत बढ़ा और कच्चे जूट का निर्यात कम हुआ। विश्व युद्ध के दौरान भी उद्योग ने काफी लाभ कमाया क्योंकि मित्र राष्ट्रों की सेना के लिए निम्न बोरे जूट के कपड़े व सूतकी की बिक्री की गई। इस समय जूट के कारखानों की संख्या 60 हो गई थी। युद्ध के बाद उद्योग का सक्रिय प्रारम्भ हुआ। भाग घटने लगी। विश्व व्यापी आर्थिक मंदी के कारण 1929-33 तक जूट उद्योग को भारी सकट से गुजरना पड़ा। 1937 तक ये समस्याएँ प्रायः समाप्त हो चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग घटने से पुनः उद्योग को प्रोत्साहन मिला। जहाँ 1938-39 में जूट मिलों की संख्या 107 थी और उनमें 68 हजार कर्चे तथा 13.5 लाख तकुए थे वहाँ 1945-46 तक मिलों की संख्या 111, तकुओं की संख्या 14.35 लाख तथा कर्चों की संख्या 69 हजार हो गई।

### स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद व पंचवर्षीय योजना में

#### जूट उद्योग का विकास

1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के विभाजन का जूट उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा क्योंकि जूट पैदा करने वाला 72% क्षेत्र तो पाकिस्तान में चला गया और तब मिलें भारत में रह गईं। कच्चे जूट की कमी तथा पाकिस्तान द्वारा बहुत ऊँचे मूल्य लिये जाने से तथा 1949 में भारतीय रुपये का अस्थिरता किये जाने से पाकिस्तानी जूट भारत को लगभग 50% महंगा पड़ा। यही नहीं, कच्चे माल के अभाव में बहुत सी मिलें बन्द हो गईं। 1947-48 में पाकिस्तान से लगभग 540 लाख गार्डें आयात की गईं जोकि कुल आवश्यकता का 80% भाग था। पाकिस्तान पर निर्भरता

बम करने के लिए भारत में कच्चा जूट उत्पादन करने के प्रयास किये गये, एक साल में ही निर्भरता 80% से घटकर 52% रह गई।

**प्रथम पंचवर्षीय योजना**—इस योजना में जूट उद्योग के विस्तार, नवीनीकरण और कच्चे माल की कमी को दूर करने के लिए कच्चे जूट का उत्पादन लक्ष्य 54 लाख गांठे करना था। जूट सामान का उत्पादन 12 लाख टन तथा निर्यात लक्ष्य 10 लाख टन रखा गया। भारत में ही जूट मशीनरी निर्माण पर ध्यान दिया गया। परिणामस्वरूप जहाँ 1950-51 में कच्चे जूट का उत्पादन 33 लाख गांठे, जूट के सामान का उत्पादन 8.37 लाख टन तथा निर्यात 6.5 लाख टन था वह बढ़कर क्रमशः 43 लाख गांठे, 10.6 लाख टन तथा 8.75 लाख टन था जो लक्ष्य से कम था। 1953 में जूट उद्योग के सम्बन्ध में एक आयोग ने उद्योग की क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने, नवीनीकरण करने, कच्ची जूट का निर्यात बन्द करने, कच्चे जूट के उत्पादन की वृद्धि के लिये गहन कृषि व न्यूनतम मूल्य, किस्म में सुधार आदि की सिफारिश की।

**द्वितीय पंचवर्षीय योजना**—इस योजना में जूट सामान का उत्पादन 12 लाख टन करने तथा कच्चे माल की दृष्टि से देश को आत्म निर्भर बनाने के लिए कच्चे जूट का उत्पादन 65 लाख गांठे करने का लक्ष्य था। 1957 की जूट आच समिति की सिफारिशों पर उत्पादन लागत कम करने, विद्यमान क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने मशीनों के नवीनीकरण व निर्यात वृद्धि पर जोर दिया गया। इन सब प्रयत्नों के फलस्वरूप भी प्रगति आशानुकूल नहीं रही। योजना के अन्तिम वर्ष 1960-61 में जूट का निर्यात मात्र 10.97 लाख टन तथा कच्चे जूट की 43 लाख टन गांठें ही उत्पादिता हुई।

इस योजना के अन्त में भारतीय जूट उद्योग को भारी पाकिस्तानी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। कई मिलें बन्द हो गईं। निर्यात भी 9 लाख टन लक्ष्य की तुलना में 7.6 लाख टन ही रहा।

**तृतीय पंचवर्षीय योजना**—इस योजना के अन्त तक कच्चे जूट का उत्पादन 75 लाख गांठें तथा जूट के सामान का उत्पादन 13 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया पर वास्तविक उत्पादन क्रमशः 58 लाख गांठे तथा 13 लाख टन ही रहा। निर्यात 9.3 लाख टन रहा।

**तीन वार्षिक योजनाय (1966-69)** अकालों के कारण इस उद्योग में कच्चे माल का सर्रास घाटा। ऊँची कीमतें तथा बढ़ती प्रतिस्पर्धा से उद्योग की स्थिति में गिरावट आयी। 1968-69 में जूट के तैयार माल का उत्पादन 9.98 लाख टन तथा जूट का उत्पादन केवल 30.5 लाख टन रहा जो 1950-51 के बाद सबसे कम था तथा 1965-66 के मुकाबले घाटा ही रह गया था। निर्यात भी 6.5 लाख टन ही रहा।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना—चतुर्थ योजना में निर्यात वृद्धि के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए कच्चे जूट के उत्पादन की 74 लाख गांठें तथा निर्मित माल का उत्पादन 15 लाख टन करने का लक्ष्य रखा पर अनेक बाधाओं के कारण कच्चे जूट का उत्पादन 1973-74 में 56 लाख गांठें रहा जबकि जूट के सामान का उत्पादन 10 74 लाख टन था। भारतीय जूट उद्योग में अभिनवीकरण व विकास के लिए अप्रैल 1971 में भारतीय जूट निगम की स्थापना की गई। चतुर्थ योजना में प्रगति सन्तोषजनक न रह सकी क्योंकि वास्तविक उत्पादन लक्ष्य से काफी कम रहा।

इस प्रकार पिछले 27 वर्षों में भारत का जूट उद्योग उत्पादन के उतार-चढ़ाव व अनिश्चितता के बातावरण में भटक रहा है। बांग्ला देश की बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा तथा मुद्रा स्फोति के कारण बढ़ती लागतों व मूल्यों की समस्या उद्योग के भविष्य को चुनौती है। इस उद्योग की पंचवर्षीय योजना की भलक एक दृष्टि में निम्न सारणी से स्पष्ट है—

**पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत जूट उद्योग का विकास**  
**1950-51 से 1978-79**

वर्ष	कच्चे माल का उत्पादन (लाख गांठें)	जूट का निर्मित सामान (लाख टन)	निर्यात (लाख टन)
प्रथम योजना के प्रारम्भ में 1950-51	33	8 37	6 5
प्रथम योजना 1955-56	43	10 71	8 75
द्वितीय योजना 1960-61	43	10 97	7 6
तृतीय योजना 1965-66	58	13 02	9 3
तीन वार्षिक योजनायें 1968-69	30 5	9 98	5 8
चतुर्थ योजना 1973-74	56 0	10 74	5 6
1977-78	68	12 0	5 2
पाचवीं योजना 1978-79	70 0	12 5	5 5

पाचवीं योजना—इस योजना के अन्तर्गत जूट उद्योग के आधुनिकीकरण तथा वर्तमान उत्पादन क्षमता के पूरे-पूरे उपयोग पर ध्यान दिया गया। योजना के अन्तिम वर्ष 1977-78 में जूट का उत्पादन 70 लाख गांठें तथा निर्मित माल 12 5 लाख टन रहा जबकि लक्ष्य क्रमशः 77 लाख गांठें तथा 13 8 लाख टन था।

## जूट उद्योग की वर्तमान स्थिति एवं छठी योजना

भारत में अभी जूट के 112 कारखाने हैं जिनमें 101 कारखाने पश्चिमी बंगाल, 4 आन्ध्र प्रदेश 3 बिहार, 3 उत्तर प्रदेश तथा एक मध्य प्रदेश में हैं। उद्योग में लगभग 300 करोड़ रु० की पूँजी लगी है और लगभग 3 लाख श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार तथा 40 लाख श्रमिकों को जूट उत्पादन में रोजगार मिला हुआ है। सन्नी कारखानों की उत्पादन क्षमता 14 से 15 लाख टन है। जूट का निमित्त माल विदेशी विनिमय का प्रमुख स्रोत है। जहाँ 1950-51 में जूट निमित्त माल के निर्यात से 114 करोड़ रु० मिलते थे 1975-76 में निर्यात 288 करोड़ रु० का अब तक का रिकार्ड है। 1977-78 में जूट तथा जूट के निमित्त माल का निर्यात मूल्य 245 करोड़ रु० रहा।

**छठी योजना—**इस योजना में भी वर्तमान क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने तथा उद्योग के आधुनिकीकरण पर जोर दिया जायगा। लागत में कमी का प्रयास करना मुख्य लक्ष्य है। 1982-83 तक जूट के निमित्त माल का उत्पादन 14 लाख टन करने का लक्ष्य है।

### जूट या पटसन उद्योग की समस्याएँ व समाधान के सुझाव

1 **कच्चे माल का अभाव—**विमाजन के बाद से भारतीय जूट उद्योग में कच्चे माल का अभाव सदा से बना हुआ है। यद्यपि बिहार आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश के उपयुक्त इलाकों में इसका क्षेत्र बढ़ाया गया है फिर भी कुल उत्पादन 56 लाख टन है जबकि भारतीय जूट मिलों को अपनी पूरी-पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रतिवर्ष 75 लाख टन कच्चे जूट की आवश्यकता है। अतः जूट उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि करके वैज्ञानिक दृष्टि से अधिनाशित उत्पादन करने का प्रयास करना चाहिए।

2 **अभिनवीकरण की समस्या—**भारत में अधिकांश मिलें पुरानी हैं तथा उनकी मशीनें या तो घिस चुकी हैं या वे इतनी पुरानी हैं कि आधुनिकतम मशीनों के मुकाबले अलानकारी हैं। बांग्ला देश जिसमें अधिकांश मिलें नई हैं उनकी प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए नयी मशीनों की आवश्यकता है और उनके लिए करोड़ रुपये की जरूरत है। 1952 से ही देश में इस उद्योग के आधुनिकीकरण का कार्य हाथ में लिया गया। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने भी इसके लिए लगभग 72 करोड़ रुपये का भ्रण दिया है। अब तक आधुनिकीकरण पर 50-60 करोड़ रुपये व्यय किया जा चुका है। सरकार को अभिनवीकरण को और अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए। मशीनों के आयात लाइसेंस में उदारता बरतनी चाहिए।

3. **बढ़ती प्रतिस्पर्धा—**भारतीय जूट उद्योग एक निम्न प्रधान उद्योग है नन्से पहले पाकिस्तान तथा अब बांग्ला देश से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है जहाँ 1964-65 में निम्न में भारत पाकिस्तान (अब बांग्ला देश) के निम्नानों का अनुपात 80 : 20 था अब भारत का भाग घटकर 53% तथा बांग्ला देश का भाग 47% हो गया है। नदिय में यह प्रतिस्पर्धा और अधिक बढ़ेगी क्योंकि आईलैंड, पाना, नाइजीरिया तथा इन्डोनेशिया में यह उद्योग तेजी से पनप रहा है।



भारत में पूंजी गहन अथवा बृहत-उद्योग

यही नहीं, जूट के सामान की प्रतिस्थापन वस्तुओं के कारण यह प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी।

अतः उत्पादन लागत में कमी, उत्पादन की किस्म में सुधार, उत्पादन में विविधता व विदेशों में विज्ञापन, प्रदर्शनियों व व्यापारिक समझौतों पर बल देना चाहिये।

4 स्थानापन्न वस्तुओं का भय—अब विश्व बाजारों में जूट की निर्मित वस्तुओं के स्थान पर प्लास्टिक, पोलीथिन, कृत्रिम रेशो आदि की वस्तुओं का प्रयोग बढ़ रहा है। अमेरिका आदि देशों में प्लास्टिक थैलों का प्रयोग होने लगा है। अगर इन प्रतिस्थापन वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता ही गया तो उद्योग का भविष्य खतरे में पड़ जायगा। अतः जूट की उत्पादन लागतों व मूल्यों में कमी करनी चाहिये, उत्पादन में उपभोक्ताओं की रुचि के अनुरूप विविधता लाना चाहिये। अनुसंधानों को प्रोत्साहन देना चाहिये।

5 विविध—जूट उद्योग की सबसे बड़ी समस्या मुद्रा-स्फीति के कारण बढ़ती लागतों व बढ़ते मूल्यों की समस्या है। आये दिन हड़तालें व तालाबंदी होती हैं। अभिनवीकरण में भी श्रमिकों के विरोध की समस्या आती है। जूट उद्योग का केन्द्रीकरण पश्चिमी बंगाल में ही होने से परिवहन की समस्या भी है। जूट उद्योग का भविष्य अनुसंधानों में ही निहित है बल्कि उसके लिए आवश्यक सुविधा तथा साधनों का अभाव है। अभी केवल जूट उद्योग शोधशाला कलकत्ता ही अनुसंधान कार्य में रत है। अतः इन समस्याओं का समाधान करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाना चाहिए।

#### 4. चीनी (शक्कर) उद्योग (Sugar Industry)

भारत में संगठित बड़े उद्योगों में चीनी उद्योग का विशिष्ट स्थान है। बिना चीनी के भारत में कोई भोज फीका और अधूरा ही माना जाता है। इस उद्योग का महत्व इस दृष्टि से भी है कि गन्ना उत्पादन कर कृषक काफी आय अर्जित करते हैं। लगभग 30 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त है। 20 लाख गन्ना उत्पादकों की समृद्धि इस उद्योग की समृद्धि से जुड़ी हुई है। विदेशी मुद्रा अर्जन होती है तथा सरकार को भी कर के रूप में काफी आय प्राप्त होती है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व उद्योग का विकास

यह भारत का अति प्राचीन उद्योग है। पहले यह घरेलू उद्योग के रूप में चलाया जाता था तथा यहाँ के छोटे उद्योगों से खाद्य यूरोप के देशों को निर्यात की जाती है पर आधुनिक ढंग का कारखाना सर्वप्रथम 1903 में बिहार में खोला गया तत्पश्चात् बिहार व उत्तर प्रदेश में कई कारखाने स्थापित किये गये। 1930 तक उद्योग की प्रगति धीमी रही।

1930 को विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का इस उद्योग पर भी बहुत दुष्प्रभाव पड़ा। अतः 1932 में चीनी उद्योग को 15 वर्षों के लिए संरक्षण दिया गया। उस समय देश में चीनी उद्योग मिलों की संख्या 32 तथा उत्पादन 16 लाख टन था। औसतन प्रतिवर्ष भारत में 67 लाख टन चीनी का आयात किया जाता था। संरक्षण से उद्योग का तेजी से विकास हुआ। 1938-39 में ही चीनी मिलों की संख्या 132 तथा उत्पादन 6 लाख टन हो गया तथा आयात भी घटकर 22 हजार टन रह गया। 1939 तक तो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि चीनी उद्योग में 145 कारखानों में उत्पादन आधिराज्य की समस्या उत्पन्न हो गई और सरकार को चीनी उत्पादन पर नियन्त्रण लगाना पड़ा तथा चीनी के वितरण को नियन्त्रित करने के लिए बिहार तथा उत्तर-प्रदेश चीनी मिलों द्वारा शुगर सिन्डीकेट बनाया गया।

द्वितीय विश्वयुद्ध के समय चीनी उद्योग की स्थिति में सुधार आया। चीनी के बढ़ते मूल्यों को नियन्त्रित करने के लिये सरकार को 1942 में नियन्त्रण व राशनिंग लागू करना पड़ा। 1945-46 में चीनी मिलों की संख्या 158 और उत्पादन 9 लाख टन था।

### स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत चीनी उद्योग की प्रगति

1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद विभाजन का चीनी उद्योग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि चीनी मिलें व शर्करा उत्पादन क्षेत्र भारत में ही रहे। महात्मा गांधी के प्रयत्नों से 1948 में चीनी पर से नियन्त्रण हटा लिया पर मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण पुनः 1949 में नियन्त्रण लगाया तथा उसके वितरण व मूल्य निर्धारण की जिम्मेदारी सरकार ने स्वयं सम्भाल ली। प्रथम योजना के शुरू होने से पूर्व 1950-51 में देश में 138 चीनी मिलें थी तथा चीनी का उत्पादन 11 लाख टन था। पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत प्रगति योजनावार इस प्रकार थी

प्रथम पंचवर्षीय योजना—इस योजना में चीनी उद्योग के विकास पर 15 करोड़ रु. व्यय किये गए। 1952 में चीनी पर से नियन्त्रण हटा दिया गया। परिणामस्वरूप चीनी की मांग में तीव्र वृद्धि हुई। अतः 1954 में 83 नयी चीनी मिलों की स्थापना तथा 41 पुरानी मिलों के विस्तार की अनुमति दी। पूर्ण निर्धारित 15 लाख टन उत्पादन लक्ष्य को बढ़ाकर 18 लाख टन कर दिया। योजना के अन्त तक चीनी मिलों की संख्या 143 तथा चीनी का उत्पादन 18 1/2 लाख टन था।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना—इस योजना में चीनी उद्योग के विकास पर 51 करोड़ रुपये व्यय कर सहकारिता क्षेत्र में 35 नयी मिलें स्थापित करने तथा उत्पादन 22 1/2 लाख टन करने का लक्ष्य था। पुरानी मिलों के विस्तार, नवीनीकरण व विकास पर जोर दिया। योजनाकाल में चीनी उद्योग के विकास व विस्तार पर 56

भारत में पूँजी गहन अथवा बृहत्-उद्योग

करोड़ ६० व्यय किये। परिणामस्वरूप चीनी मिलों की संख्या 175 तथा चीनी का उत्पादन 30.3 लाख टन हो गया। 1958 में ही चीनी के निर्यात को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई गई। 1960-61 तक सहकारी चीनी मिलों की संख्या 38 हो चुकी थी।

**तृतीय पंचवर्षीय योजना**—इस योजना में 25 नयी चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित करने तथा उत्पादन 33 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया। विकास के प्रयत्नों के फलस्वरूप चीनी मिलों की संख्या 200 हो गई तथा उत्पादन 35.1 लाख टन था।

**तीन वार्षिक योजनाएँ (1966-69)**—पहले दो वर्षों में भ्रूकाल के कारण चीनी का उत्पादन घटकर लगभग 23 लाख टन ही रह गया था। चीनी वितरण पर 1967 में आंशिक नियन्त्रण हटाकर 60% भाग नियन्त्रित दर पर तथा शेष 40% खुले बाजार में बिकने की व्यवस्था की। 1968-69 में उत्पादन पुन बढकर 35.1 लाख टन हो गया।

**चतुर्थ पंचवर्षीय योजना**—इस योजना में भी चीनी उद्योग उतार-चढ़ाव के दौर से गुजरा है। योजनाकाल में 70 नये कारखाने खोलने तथा चीनी का उत्पादन 47 लाख टन करने का लक्ष्य था पर योजना के अन्त तक 1973-74 में चीनी का उत्पादन 39 लाख टन ही रहा। चीनी मिलों की संख्या भी बढकर 228 हो गई है जिनमें से 75 सहकारी क्षेत्र में थीं। 1974-75 में चीनी का उत्पादन 48 लाख टन हुआ।

**पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत चीनी उद्योगों की प्रगति (1950-79)**

योजना के अन्तिम वर्ष		चीनी मिलों की संख्या	उत्पादन (लाख टन)	निर्यात (करोड़ रु.)
	1950-51	138	11.0	0.50
प्रथम	1955-56	143	18.9	0.96
द्वितीय	1960-61	175	30.3	3.28
तृतीय	1965-66	200	35.1	11.34
वार्षिक	1968-69	215	35.6	10.19
चतुर्थ	1973-74	220	39	42.9
पाचवी	1977-78	293	64.3	5
छठी	1982-83	300	62	

**पाचवी योजना**—इस योजना में चीनी का उत्पादन 50 लाख टन करने का लक्ष्य था किन्तु योजना के अन्तिम वर्ष 1977-78 में उत्पादन 64.6 लाख टन रहा जो अब तक का रिकार्ड उत्पादन है।

## चीनी उद्योग की वर्तमान स्थिति एवं छठी योजना

पिछले 28 वर्षों में चीनी उद्योग ने आश्चर्यजनक प्रगति की है। इस समय देश में 293 चीनी मिलें हैं और 58 का निर्माण चल रहा है। उत्पादन क्षमता 65 लाख टन से अधिक है। चीनी उद्योग में 131 मिले सहकारी क्षेत्र में हैं और कुल उत्पादन का लगभग 50% भाग उत्पादन करती है। देश की कुल 293 चीनी मिलों में से लगभग 100 उत्तर प्रदेश में, 80 महाराष्ट्र में, 30 बिहार में तथा 3 राजस्थान में हैं। 1977-78 में चीनी का रिकार्ड उत्पादन 64.6 लाख टन रहा जबकि 1979-80 में उत्पादन 58 लाख टन होने का अनुमान है। कुल श्रमिक 3.5 लाख लगे हैं।

छठी योजना में कोई नया कारखाना नहीं खोला जायगा किन्तु रोजगार बढ़ाने के लिये खण्डसारी उद्योग को बढ़ावा दिया जायगा। 1982-83 तक चीनी का उत्पादन 62 लाख टन करने का लक्ष्य है।

### चीनी उद्योग की प्रमुख समस्याएं व समाधान के सुझाव

1. गन्ने की कम उपज व उसमें चीनी की मात्रा कम—भारत में गन्ने की प्रति एकड़ उपज केवल 15 टन की है जबकि जावा हवाई द्वीपों में प्रति एकड़ लगभग 56 टन तथा 52 टन प्रति एकड़ है जो भारत की उपज की लगभग चौगुनी है। यही नहीं, भारत का गन्ना नीची किस्म का है उसमें चीनी का प्रतिशत लगभग 9 से 10% होता है जबकि अन्य चीनी उत्पादक देशों—जावा, सुमात्रा, क्यूबा, मारीशस आदि में चीनी का प्रतिशत 13 से 14% होता है।

अतः सरकार को गन्ने की प्रति एकड़ में उपज की वृद्धि के लिये वैज्ञानिक पद्धतियों व सुधरी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। अनुसंधान बागों द्वारा उत्पादन वृद्धि पर भी जोर देना चाहिये।

2. गुड़ तथा खण्डसारी उद्योग से प्रतियोगिता—देश में उपलब्ध गन्ने का प्रयोग चीनी उद्योग तथा गुड़ खण्डसारी उद्योग में होता है। अतः दोनों में कच्चे माल गन्ने की प्राप्ति में प्रतिस्पर्धा होती है अतः उद्योगों को पर्याप्त कच्चा माल नहीं मिल पाता। अतः इनमें परस्पर समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये।

3. अनार्यिक आहार व अभिनवीकरण की समस्या—भारतीय चीनी उद्योग में अनेक आर्थिक छोटी छोटी इनाइयाँ हैं तथा उनमें आधुनिक मशीनों का अभाव है। एक मोटे अनुमान के अनुसार अभिनवीकरण के लिये 90 करोड़ रु. की आवश्यकता है। जहाँ एक ओर वित्तीय संकट है तो दूसरी तरफ मजदूरों का विरोध भी।

इन समस्याओं का समाधान करने के लिये छोटी छोटी इनाइयों को मिलाकर उन्हें बड़ी इनाइयों में बदलना चाहिये ताकि उनकी गन्ना पैरने की दैनिक क्षमता 700-800 टन से बढ़ाकर 300 टन कर दी जाये। अभिनवीकरण की योजना को धीरे-धीरे कार्यान्वित करना चाहिये। अब भारत ने भी चीनी मशीनों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करली है यह एक अच्छा संकेत है।

4. अवशेषों से उप-उत्पादनों तथा उत्पादन लागतों में वृद्धि की समस्या—चीनी उद्योगों में मिलों में अवशेष के रूप में खोई (Bagasses) तथा शीरा (Molasses), प्रेसमड तथा केन्द्रैस आदि उप-उत्पाद (By-Product) प्राप्त होते हैं। प्रतिवर्ष चीनी मिलों में तीन चार लाख टन शीरा निकलता है जिससे 20-25 मिलियन गैलन अल्कोहल तैयार की जा सकती है। गन्ने के छिन्को (छोड़) से कागज, कार्ड-बोर्ड आदि तैयार किया जा सकता है। यही नहीं, उत्पादन की पुरातन मशीनें, उप-उत्पादनों का समन्वित प्रयोग का अनाज आदि के कारण लागतों में वृद्धि हो जाती है अतः इन सब अवशेषों के आर्थिक उपयोग पर जोर देना चाहिये।

5. विविध—इस प्रकार चीनी उद्योग के सागने परिवहन की समस्या, तकनीकी एवं प्रौद्योगिक ज्ञान, अनुसन्धान नियंत्रण आदि की समस्या है। अब रासायनिक तत्वों का भी चीनी के स्थान पर प्रयोग होने लगा है जिसमें सैल्फीन एवं सल्फुरिन प्रमुख हैं।

चीनी पर कंट्रोल हटा—16 अगस्त 1978 से भारत सरकार ने चीनी का कंट्रोल हटा दिया है। अब खुले बजार में अपना पूरा उत्पादन बेचने की छूट मिल गई है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार चीनी के भाव को 2.75 रु प्रति किलोग्राम बनाये रखने का हर सम्भव प्रयास करेगी।

### परिलोपयोगी प्रश्न

1. भारत में लोह इस्पात उद्योग के विकास एवं समस्याओं का वर्णन कीजिये।  
(Raj, IIIyr. B. Com. 1979)

## श्रम-प्रधान लघु एवं कुटीर उद्योग

(Labour Intensive Industries)

किसी भी देश की औद्योगिक संरचना में कुटीर एवं लघु उद्योगों का विशेष स्थान होता है। भारतीय जनसंख्या में पूर्ण रोजगार का अभाव, श्रम की अत्यधिक पूर्ति तथा तकनीकी ज्ञान का अभाव आदि के कारण इन उद्योगों का अत्यधिक महत्व है। इन उद्योगों का अतीत बहुत ही गौरवपूर्ण था पर अंग्रेजी शासनकाल में इन उद्योगों का इतना पतन हुआ कि भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग प्रायः समाप्त हो गये। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इनके विकास के लिए काफी प्रयास किये गये हैं फिर भी समुचित विकास नहीं हो पाया है।

**पर्यटन व परिरक्षा—**कुटीर उद्योगों का प्राग्जन्म इन उद्योग वर्गों से है जो एक ही परिवार के सदस्य द्वारा एक ही छत के नीचे परंपरा या आशिक रूप से संचालित किये जाते हैं। राजकीय अर्थोपयोग के दृष्टिकोण से कुटीर उद्योग वह है जो पूर्णतया या मुख्यतः परिवार के सदस्यों की मजदूरी से पूर्ण या आंशिक व्यवसाय के रूप में चलाये जाते हैं।” उत्पादन की पद्धति परम्परागत होती है।

लघु-उद्योगों के अर्थ में समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन हुआ। राजकीय अर्थोपयोग के अनुसार लघु-उद्योग के उद्योग हैं जो मुख्यतः 10 से 15 श्रमिकों की मजदूरी से चलाये जाते हैं। इसमें वे सब इकाइयाँ व संस्थान सम्मिलित होत हैं जिनमें पाँच लाख रुपये से कम पूँजी लगी हुई होनी है। वर्तमान में श्रमिकों की संख्या पर ध्यान न देकर विनिर्माण पूर्ण पर ध्यान दिया जाता है जब 75 लाख रुपये से कम विनियोग वाले उद्योगों को लघु उद्योगों की श्रेणी में गिना जाता है।

**लघु व कुटीर उद्योगों में अन्तर**

यद्यपि दोनों का समान स्तर पर सम्बन्ध आता है पर दोनों में पर्याप्त अन्तर है—

## श्रम-प्रधान लघु एवं कुटीर उद्योग

1 संचालन—कुटीर उद्योगों का संचालन एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा अपने ही घर में परम्परागत ढंग से किया जाता है जबकि लघु उद्योगों का संचालन वेतनभोगी श्रमिकों द्वारा किया जाता है। श्रम व पूँजी में पृथक्ता होती है।

2 यन्त्रों का प्रयोग—कुटीर उद्योगों में यन्त्रों का प्रयोग सीमित होता है, श्रम की प्रधानता होती है जबकि लघु-उद्योगों में पूँजी व यन्त्रों का प्रयोग बहुत बढ़ गया है।

3 पूँजी—कुटीर उद्योगों में पूँजी परिवार द्वारा लगाई जाती है। बाह्य पूँजी का प्रयोग न के बराबर होता है जबकि लघु-उद्योगों में बाह्य-पूँजी का प्रयोग बढ़ जाता है।

4 बाजार—कुटीर उद्योग का बाजार सीमित होता है जबकि लघु-उद्योगों का बाजार विस्तृत है।

## कुटीर व लघु उद्योगों का वर्गीकरण

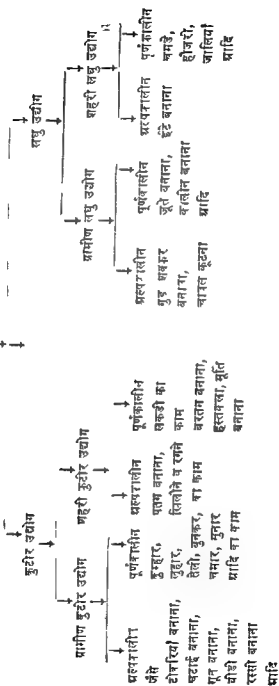
राजकोषीय आयोग ने कुटीर व लघु उद्योगों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है—

### भारत में कुटीर एवं लघु उद्योगों का गौरवपूर्ण अतीत व पतन के कारण

भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों का अतीत बड़ा ही गौरवपूर्ण रहा है। एक विद्वान् के अनुसार भारत के कुटीर उद्योग बुद्धिमान मस्तिष्क, विलक्षण योग्यता तथा अद्भुत प्रतिभा की उपज थे तथा 17वीं शताब्दी तक विश्व में भारत के उद्योगों का अद्वितीय स्थान था। ये उद्योग पश्चिम के उद्योगों से कहीं अधिक उत्तम थे। 1918 के भारतीय औद्योगिक आयोग के शब्दों में 'जब औद्योगिक विकास में अपनी यूरोप में असम्य जातियाँ निवास करती थीं तब भारत अपने शासकों के वैभव व कारीगरों की श्रेष्ठ कला के लिये विश्व प्रसिद्ध था।'

पर अंग्रेज शासकों ने अपनी स्वार्थ नीति के कारण भारत के लघु एवं कुटीर उद्योगों के पतन की नीति अपनाई। ब्रिटिश सरकार को पक्षपातपूर्ण विरोधी नीति, ईस्ट इण्डिया कम्पनी की घातक नीति, प्राचीन नवाबों व राजाओं के संरक्षण का अन्त, पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव मशीनों द्वारा निर्मित माल की कट्टर प्रतियोगिता, यान्त्रिकता के साधनों के विकास व भारतीय कारीगरों में तकनीकी परिवर्तन की लोच-हीनता के कारण भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन हुआ। प्रो. आर. सी. दत्त के शब्दों में अठारहवीं शताब्दी में भारत एक बहुत बड़ा खेतिहर और औद्योगिक देश था उसे अंग्रेजों ने अपनी घोर स्वार्थपरायणता की नीति के कारण सट्टियामेढ कर दिया।

## कुटीर एवं तधु उद्योग





## भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्व व आवश्यकता

भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों की अत्यधिक आवश्यकता और विशेष महत्व है। महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कहा है कि भारत का उद्धार कुटीर उद्योग धंधों के द्वारा ही सम्भव है। इसी प्रकार के विचार पंडित नेहरू ने व्यक्त किये थे। उनके अनुसार 'भारत अभी एक औद्योगिक राष्ट्र होगा जबकि यहाँ पर लाखों की संख्या में छोटे-छोटे उद्योग हों।' योजना आयोग ने लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास की आवश्यकता रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आय व रहन-सहन का ऊँचा स्तर तथा सन्तुलित अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए महसूस की है। लघु उद्योगों की आवश्यकता व महत्व निम्न तथ्यों से स्पष्ट हो जाती है—

1 रोजगार—लघु व कुटीर उद्योग रोजगार के प्रमुख स्रोत हैं। इनके विकास से अर्द्ध बेरोजगारी व पूर्ण बेकारी का निराकरण सम्भव होता है। जहाँ 1931 में कुटीर उद्योगों में 61.4 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त था अब लगभग 2 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है।

2 कम पूँजी व अधिक उत्पादन—भारत में पूँजी का अभाव है, ऐसी परिस्थिति में लघु एवं कुटीर उद्योगों में नितम धन की प्रधानता होती है और कम पूँजी से ही काम चल जाता है। अतः लघु एवं कुटीर उद्योगों में थोड़ी पूँजी लगाकर ही आय, उत्पादन व रोजगार में वृद्धि सम्भव है।

3 आय व सम्पत्ति का न्यायोचित वितरण—बड़े पैमाने के उद्योगों का संचालन व स्वामित्व कतिपय बड़े-बड़े उद्योगपतियों के हाथों में होता है। अतः सारे लाभों का वे ही हूबप जाते हैं। इसके कारण आय व सम्पत्ति देश की विपन्नता बढ़ती है जबकि छोटे-छोटे उद्योगों का स्वामित्व अनेक व्यक्तियों में बँटा होता है, धन की प्रधानता होती है अतः आय व सम्पत्ति के समान वितरण की सम्भावनाएँ बढ़ती हैं जो समाजवाद के सिद्धान्तों के अनुकूल हैं।

4 अर्थव्यवस्था का सन्तुलित एवं सर्वांगीण विकास—भारत में कृषि की प्रधानता के कारण भूमि पर भार अधिक हो गया है तथा अर्थव्यवस्था का सन्तुलित विकास नहीं हो पाया है जबकि लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास से अर्थव्यवस्था का सन्तुलित विकास सम्भव है।

5 विकेंद्रित अर्थव्यवस्था—बड़े उद्योगों के केंद्रीयकरण से आदाम, नीति व पतन, दूषित वातावरण व क्षेत्रीय विपन्नता की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं जबकि लघु एवं कुटीर उद्योगों को देश के विभिन्न भागों में विव्नेन्द्रित कर विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है।

6 संचालन की सरलता—लघु एवं कुटीर उद्योगों की कार्य-प्रणाली सरल होती है। उसमें विविष्ट तकनीकी ज्ञान व औद्योगिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। जब भारत में तकनीकी व औद्योगिक ज्ञान का अभाव है तो स्वाभाविक रूप से ऐसे उद्योगों का महत्व बढ़ जाता है।

7. औद्योगिक शान्ति व सघर्षों से मुक्ति—बड़े पैमाने के उद्योगों में पूँजी व श्रम से सघर्ष के कारण घेराव, हड़तालें, तालाबन्दी आदि बढ़ती हैं और औद्योगिक शान्ति भंग हो जाती है जबकि लघु एवं कुटीर उद्योगों में श्रमिकों की सख्या सीमित होती है, पूँजी व श्रम में परस्पर सद्भावना रहती है अतः सघर्षों की सम्भावना कम होती है और औद्योगिक शान्ति का मार्ग प्रशस्त होता है।

8. युद्ध में सुरक्षा—राजनीति व सुरक्षा के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों का विशेष महत्व है। ऐसे उद्योगों की अनेक छोटी-छोटी इकाइयाँ देश के सभी भागों में वितरित होती हैं। अतः युद्ध में बमबारी द्वारा उन्हें नष्ट करना असम्भव होता है जबकि बड़े उद्योगों का नष्ट करना सरल होता है।

9. कलात्मक व श्रेष्ठ वस्तुओं का उत्पादन—लघु एवं कुटीर उद्योगों की आवश्यकता व महत्व इस कारण भी है कि विभिन्न उपभोक्ताओं की रुचि के अनुकूल कलात्मक वस्तुएँ उत्पादन की जाती हैं और उत्पादन भी ऊँचे स्तर का होता है।

10. देश की सम्यक्ता व संस्कृति के अनुरूप—कुटीर व लघु उद्योगों में परस्पर सद्भावना, सहकारिता, समानता व भ्रातृत्व की भावना पनपती है जबकि बड़े उद्योगों में शोषण, प्रतिस्पर्धा, वर्ग सघर्ष व स्वार्थ बढ़ता है अतः भारतीय सम्यक्ता व संस्कृति की रक्षा लघु व कुटीर उद्योगों के विकास में निहित है।

11. व्यापार चक्रों से मुक्ति व सामाजिक कल्याण—बड़े पैमाने की उत्पत्ति में उत्पादन आधिक्य की सम्भावनाएँ सदा बनी रहती हैं जबकि लघु एवं कुटीर उद्योगों में उत्पादन का पैमाना छोटा व माय के अनुरूप उत्पत्ति की जाती है। अतः व्यापार चक्रों से उत्पन्न बेकारी का उद्भव नहीं होता। इसके अतिरिक्त लघु उद्योगों में रोजगार व आय में वृद्धि, शोषण से मुक्ति व समान वितरण के कारण सामाजिक कल्याण में अभिवृद्धि होती है।

12. शीघ्र उत्पादन वृद्धि तथा मूल्यों पर नियन्त्रण में सुविधा—लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना में कम समय लगता है अतः औद्योगिक उत्पादन शीघ्रता से बढ़ाया जा सकता है और उत्पादन वृद्धि में मूल्यों पर नियन्त्रण में भी सुविधा रहती है।

13. राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि—लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास से अधिकाधिक लोगों को पूर्ण रोजगार तथा अर्द्ध बेरोजगारों को सहायक रोजगार प्रदान कर राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है और इससे प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि की जा सकती है। भारत में किसानों को साल में 4 महीने काम मिलता है अतः बाकी समय में लघु एवं कुटीर उद्योगों के कारण सहायक रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि देश का विकास, घातक निर्भर रोजगार की वृद्धि, मूल्यों पर नियन्त्रण, कम पूँजी में अधिक उत्पादन आदि के लिए लघु एवं

कुटीर उद्योग की विशेष आवश्यकता है। वे हमारी परम्पराओं के अनुरूप तथा समाजवाद के अनुकूल हैं।

### लघु एवं कुटीर उद्योगों की समस्याएँ व कठिनाइयाँ

यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एव कुटीर उद्योगों का अत्यधिक महत्त्व है परन्तु उनके सामने अनेक कठिनाइयाँ व समस्याएँ होने से समुचित विकास नहीं हो पाया है। मुख्य समस्याएँ इस प्रकार हैं—

1 कच्चे माल की समस्या—लघु एव कुटीर उद्योगों को अच्छा व पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाता क्योंकि एक तो उनके साधन सीमित हैं अतः क्रय कम होता है और दूसरे बड़े उद्योगों के क्रय की प्रतिस्पर्धा में छोटे उद्योग नहीं टिक पाते। अतः कारीगरों की क्रय की दक्षता में कमी के कारण अच्छी किस्म का कच्चा माल उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं होता।

2 वित्त सम्बन्धी कठिनाइयाँ—लघु एव कुटीर उद्योगों में कच्चे माल की खरीद, मशीनों, औजारों, कारखानों, गोदामों आदि के लिए वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है। माल का उत्पादन करके बिच्री में पूर्व मजदूरी का भुगतान भी करना पड़ता है अतः आवश्यक वित्तीय साधनों की समस्या आती है। यद्यपि अब वित्त व्यवस्था के काफी प्रयास किये गये हैं फिर भी आवश्यकता के मुकाबले वित्त साधन अपर्याप्त हैं।

3 उत्पादन की पुरानी पद्धतियाँ व ऊँची लागत—भारत में लघु एव कुटीर उद्योगों में उत्पादन की अटिवादी पद्धतियाँ हैं। नवीन वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग बहुत सीमित है अतः उत्पादन का नीचा स्तर और लागत ऊँची बैठती है। उत्पादन वृद्धि के लिए उचित प्रशिक्षण व अनुसंधान सुविधाओं का अभाव होने से शिल्पकारों व कारीगरों की हीन दशा है।

4. विपणन की समस्या—उत्पादन का नीचा स्तर, ऊँची लागत, कारीगरों की ऋणग्रस्तता व मध्यस्थों के शोष के कारण कारीगरों को उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। मध्यस्थ उत्पादन मूल्य का लगभग 40% भाग हड़प जाते हैं। समय पर उत्पादित माल बिक्री न होने से उत्पादन का क्रय ही रुक जाता है।

5. बड़े उद्योगों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा—देश में तेज़ी से बढ़ते बड़े उद्योगों में आन्तरिक एव बाह्य वचन प्राप्त होती हैं। अतः उनकी उत्पादन लागत कुटीर व लघु उद्योगों के मुकाबले कम बैठती है अतः बड़े उद्योगों का बड़ी मात्रा में उपलब्ध सस्ता माल लघु उद्योगों के उत्पादित महँगे माल को प्रतिस्पर्धा में पीछे धकेल देता है। अतः लघु कुटीर उद्योगों की कठिनाई आती है। भारत में लघु एव कुटीर उद्योगों के पतन का एक प्रमुख कारण बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा रही है।

6. उपभोक्ताओं की अदक्षि व संरक्षण का अभाव—भारत में बढ़ती महंगाई की स्थिति में उपभोक्ता सस्ता व अच्छा माल खरीदते हैं। लघु एव कुटीर उद्योगों में निर्मित माल महंगा पड़ता है तथा मशीनों के माल की अपेक्षा खटिया भी रहता है।

प्रभावी कदम उठाये हैं। सरकार के प्रयत्नों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

## 1. लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए समितियों की नियुक्ति

भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास व उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार की सुझाव देने के उद्देश्य से समय-समय पर समितियों की नियुक्ति की है और उनकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने का प्रयास किया है।

(i) अन्तर्राष्ट्रीय योजना दल (1954)—फोर्ड फाउन्डेशन के विशेषज्ञों के एक दल ने लघु उद्योगों की स्थिति का अध्ययन कर उत्पादन की नवीन पद्धतियों के अपनाने की सलाह दी। उत्पादन के तरीकों के अध्ययन व्यावहारिक शोध तथा नवीन उत्पादन पद्धतियों के प्रचार के लिए चार बहुदेशीय औद्योगिक स्थान स्थापित करने की सिफारिश की। इसके अतिरिक्त दल ने राष्ट्रीय डिजाइन शाखा, उद्योगों से सम्बन्धित विशेष सगठनों की स्थापना, लघु उद्योगों के विकास हेतु लघु उद्योग निगम की स्थापना के साथ-साथ व्यापारिक बैंक से वित्तीय व्यवस्था का सुझाव दिया।

भारत सरकार ने इस दल की सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम व अन्य विशिष्ट सगठनों की स्थापना की।

(ii) ग्रामीण व लघु उद्योग (कर्वे) समिति—1955 में डॉ० कर्वे की अध्यक्षता में सरकार ने इस समिति की नियुक्ति की। अक्टूबर 1955 में कर्वे समिति ने महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत की (A) स्टेट बैंक व रिजर्व बैंक द्वारा लघु उद्योगों की वित्त व्यवस्था, (B) लघु उद्योगों को राज्य वित्त निगमों से दीर्घकालीन ऋण व्यवस्था, (C) लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण व लघु उद्योग मन्त्रालय की स्थापना, (D) बड़े उद्योगों के उत्पादन की सीमा निर्धारण, (E) बड़े पैमाने के उद्योगों के उत्पादन पर उपकर लगाकर उस रकम को लघु उद्योगों की सहायता के लिए, (F) लघु उद्योगों की स्थापना में सहकारिता को प्रोत्साहन आदि का समावेश था।

इसकी सिफारिशों को द्वितीय योजना में प्रमुख स्थान दिया गया तथा लघु कुटीर उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल कदम उठाये।

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय दीर्घकालीन आयोजना दल (1963) लघु उद्योगों की प्रगति की समीक्षा करने तथा भावी विकास के सुझाव देने के लिये फोर्ड फाउन्डेशन के विशेषज्ञों का दूसरा दल 1963 में महत्वपूर्ण सिफारिशें कर गया जिसमें लघु उद्योगों के कच्चे भाग, कल पुर्जों व साज सामान के सम्बन्ध में प्राथमिकता व समस्त वस्तुओं के लिए एक कर व्यवस्था अपनाने का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त लघु उद्योगों को कृषि पर मशीनरी व साज सामान देने तथा विदेशी विनिमय व कच्चे भाग के अभाव की स्थिति में रियायती व्याज दरों पर ऋण की व्यवस्था पर जोर दिया।

### ■ विभिन्न विशिष्ट संगठनों की स्थापना

देश में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए अलग-अलग उद्योगों के विकास के लिए विशिष्ट संगठनों की स्थापना की गई है —

(i) कुटीर उद्योग बोर्ड 1948 (Cottage Industries Board)—इस बोर्ड की स्थापना 1948 में की गई तथा इसका पुनर्संगठन 1950 में किया गया। इस बोर्ड का कार्य केन्द्र सरकार को लघु कुटीर एवं उद्योगों के विकास व संगठन के बारे में सुझाव देना, बड़े तथा छोटे उद्योगों में परस्पर समन्वय स्थापना का सुझाव देना तथा राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं में सामंजस्य लाना था।

(ii) केन्द्रीय स्लिक बोर्ड 1949 की स्थापना रेशम लघु उद्योग की देख-भाल व विकास के लिए की गयी थी।

(iii) अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड 1952—दस्तकारी के उत्पादन व विपणन में सुधार लाने को इस बोर्ड की स्थापना की गई। यह बिन्नी केन्द्रों की व्यवस्था करता है। यह बोर्ड अभी 19 पायलट केन्द्रों को संचालित कर रहा है जिनमें उत्पादन अनुसंधान, प्रशिक्षण व परीक्षण व माध्य-साध्य विशेषज्ञता की सहायता से उत्पादन वृद्धि के लिए सुझाव देता है। इनके कारण अब देश में लगभग 100 करोड़ रु० मूल्य की वार्षिक उत्पत्ति होती है।

(iv) अखिल भारतीय हाथ-करघा बोर्ड 1952—यह बोर्ड हाथ करघा उद्योग के विकास उत्पादन वृद्धि व विपणन में सुधार की ओर ध्यान देता है। उनकी वस्तुओं का प्रचार करना है तथा उनकी समस्याओं में सरकार को अवगत कराकर समस्या के समाधान के सुझाव देता है।

(v) अखिल भारतीय खादी प्रामोद्योग आयोग 1953—इस आयोग का कार्य गांधी, तन माधुन दिमासलाई, नाड गूड, मधुमक्खी पालन की विकास योजनाएँ बनाना व विकास के प्रयास करना है। राज्य स्तर पर खादी-प्रामोद्योग मण्डल विक व कार्य में रत है।

(vi) नान्यतल जडा बोर्ड 1954—इस बोर्ड का कार्य नान्यतल जडा से निर्मित वस्तुओं का प्रचार करना व इस उद्योग के विकास का कार्य करना आदि है। इस बोर्ड ने केरल में एक अनुसंधान संस्थान स्थापित किया है।

(vii) भारतीय दस्तकारी विकास निगम—इस निगम की स्थापना 1958 में दस्तकारी उद्योग के उत्पादन को व्यापारिक आधार पर संगठित करने, उत्पादन के विपणन की व्यवस्था करना व रोगरो को आधुनिक औजारों के प्रयोग के लिए प्रेरित करने तथा दस्तकारी उद्योग के विकास के लिए की गई है।

### 3 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (National Small Industries Corporation)

1955 में 10 लाख रुपये की पूँजी से इस निगम की स्थापना की गयी। यह निगम (i) लघु उद्योगों की वित्त व्यवस्था करता है, (ii) शिल्पिक व प्राथिक

सहायता देता है, (iii) बड़े तथा छोटे उद्योगों में समन्वय स्थापित करता है ताकि वे एक दूसरे के पूरक के रूप में काम कर सकें, (iv) केन्द्र व राज्य सरकारों से माल का आर्डर प्राप्त करना व समुचित हिस्सा दिखाना तथा (v) अन्य सस्याओं द्वारा दिये गये ऋणों की गारंटी करना आदि कार्य करता है।

#### 4. लघु उद्योग बोर्ड (Small Industries Board)

इस बोर्ड की स्थापना 1954 में की गई। यह लघु उद्योगों के विकास की योजनाएँ बनाकर उन्हें कार्यान्वित करता है तथा लघु उद्योगों को प्रावधिक व वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

#### 5. लघु उद्योगों की तकनीकी सहायता के क्षेत्र में प्रयास

लघु एव कुटीर उद्योगों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई है जैसा कि निम्न तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं—

(i) केन्द्रीय लघु उद्योग सस्यान की स्थापना की गई है जो सेवा सस्यानों व प्रसार केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षित व्यक्तियों की व्यवस्था करता है।

(ii) लघु उद्योग सेवा सस्याएँ—अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन दल 1954 की सिफारिश पर दिल्ली, मद्रास, बम्बई व कलकत्ता में चार लघु उद्योग सेवा सस्याएँ स्थापित की गई हैं। ये सस्याएँ लघु उद्योगों की उत्पादन विधियों, कच्चे माल, मशीनों की सरीददारी, विप्री व प्रबन्ध में सुधार तथा पूँजी प्राप्त करने में सहायता देती हैं। इस समय लगभग 19 लघु उद्योग सेवा सस्याएँ हैं।

(iii) औद्योगिक विस्तार सेवा (Industrial Extension Service)—लघु उद्योगों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए उपर्युक्त सेवा सस्याओं के अतिरिक्त 16 बड़ी विस्तार सेवा सस्याएँ, 6 शाखा सस्याएँ तथा 65 विस्तार, उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(iv) क्षेत्रीय तकनीकी सस्यान—देश में लघु उद्योगों को तकनीकी एव प्रबन्ध सम्बन्धी सुधार के बारे में सुझाव के लिए चार क्षेत्रीय तकनीकी सस्यान भी खोले गये हैं।

(v) ग्रामीण अनुसंधान सस्यान की स्थापना लघु उद्योगों व ग्रामीण उद्योगों में तकनीकी अनुसंधान करने के लिए की गई है।

(vi) आदिष्कार प्रोत्साहन मण्डल—श्रमिकों व कारीगरों को लघु व ग्रामीण उद्योगों में नये नये तकनीकी आविष्कार में प्रोत्साहन देने के लिए यह मण्डल इनाम व आर्थिक सहायता देता है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा लघु उद्योग बोर्ड भी तकनीकी एव प्राविधिकी सहयोग प्रदान करने को तत्पर रहते हैं।

#### 6 जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना

(Establishment of District Industrial Centres)

1977 की नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत लघु एव कुटीर उद्योगों को सभी

प्रकार की सहायता, वित्तीय, तकनीकी, कच्चा माल, विपणन आदि एक ही स्थान पर जिला स्तर पर ही प्रदान करने के लिए 1979-80 तक देश में 460 जिला औद्योगिक केन्द्र खोलने की व्यवस्था की गई। प्रथम वर्ष में केवल 160 औद्योगिक केन्द्र स्थापित करने का विचार था किन्तु अधिक उत्साह के कारण 346 औद्योगिक केन्द्र स्थापित कर दिये गये हैं और इन्होंने कई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1979-80 तक देश में 460 औद्योगिक केन्द्र खोलने में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास को काफी बल मिलेगा।

1979-80 में ये 91 हजार नई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करेंगे।

## 7. लघु एवं कुटीर उद्योगों को वित्तीय सहायता

लघु एवं कुटीर उद्योगों को उत्पादन तथा विकास के लिए आसान शर्तों पर यथासम्भव अधिकाधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रयास किया गया है जिनमें निम्न उल्लेखनीय हैं —

(i) सरकारी सहायता—सरकार लघु एवं कुटीर उद्योगों को राजकीय सहायता अधिनियम के अन्तर्गत ऋण एवं अनुदान देती है। द्वितीय एवं तृतीय योजना के अन्तर्गत सरकार ने क्रमशः 13 करोड़ ₹० तथा 17 करोड़ ₹० की वित्तीय सहायता दी। अब यह राशि बढ़कर 50 से 60 करोड़ ₹० वार्षिक हो गई है।

(ii) राज्य वित्त निगमों द्वारा सहायता—लघु एवं कुटीर उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण देने के लिए 19 राज्य वित्त निगमों की स्थापना की गई है। जहाँ 1966-67 में वित्त निगमों ने लघु एवं कुटीर उद्योगों को 25.3 करोड़ ₹० के ऋण दिये वहाँ 1977-78 में यह राशि 166 करोड़ हो गई। जून 1978 तक इन निगमों ने कुल 954 करोड़ ₹० के ऋण स्वीकृत किये हैं और उसमें से 622 करोड़ ₹० के ऋण शेष थे।

(iii) स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय सहायता—स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया भी लघु एवं कुटीर उद्योगों को वित्तीय सहायता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 31 दिसम्बर 1978 तक स्टेट बैंक तथा उसके सहायक बैंकों द्वारा 1.9 लाख इकाइयों को 591 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है तथा 1.4 लाख कारीगरों को 16.2 करोड़ ₹० सहायता दी है।

(iv) रिजर्व बैंक द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों को अप्रत्यक्ष सहायता दी जाती है। रिजर्व बैंक साक्ष गारन्टी योजना के तहत लघु उद्योगों को दी जाने वाली ऋण राशि के पुनर्भुगतान की गारन्टी देता है। जून 1978 तक रिजर्व बैंक ने 2711 इकाइयों के लगभग 333 करोड़ ₹० के बकाया मुग्तानों को चुकाया है।

(v) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम—लघु उद्योगों को विश्वों पर मशीनें एवं कच्चा माल खरीदने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ऋण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(vi) औद्योगिक विकास बैंक का विशेष प्रकोष्ठ—लघु एव कुटीर उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए औद्योगिक विकास बैंक का एक विशेष प्रकोष्ठ (CELL) स्थापित किया गया है।

(vii) व्यापारिक बैंक—14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के पीछे एक उद्देश्य यह रहा है कि लघु एव कुटीर उद्योगों को पर्याप्त ऋण मिल सक। राष्ट्रीयकरण के बाद व्यापारिक बैंक का ऋण भी तेजी से बढ़ रहा है। जहाँ 1960 में व्यापारिक बैंकों का ऋण शेष 28 करोड़ था वह बढ़कर 1966 में 91 करोड़ रु० तथा 1977 में बढ़कर 1222 करोड़ रु० हो गया है। 1978 में 53 लाख इकाइयों को 1830 करोड़ रु० का ऋण दिया।

(viii) औद्योगिक सहकारी समितियाँ भी आसान शर्तों पर कारीगरों को ऋण उधार देती हैं।

## 8. विपणन व्यवस्था में सुधार

लघु एव कुटीर उद्योगों के निमित्त माल के विक्रय की उचित व्यवस्था के लिए भी सरकार ने कदम उठाये हैं। 1949 से ही केन्द्र सरकार में केन्द्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम की स्थापना की गई जो देश विदेश में विपणन में सहायता देता है। इस समय देश में 255 प्रदर्शन व बिक्री केन्द्र कार्य कर रहे हैं। विश्व के प्रमुख नगरों में भी प्रदर्शन गृह स्थापित किये गये हैं। निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया है। 1953 में एक केन्द्रीय बिक्री संस्था (Central Marketing Organisation) की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त सरकार लघु उद्योगों के उत्पादनों को सरकारी खरीद में प्राथमिकता देती है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों से आर्डर प्राप्त कर उन्हें लघु उद्योगों का माल बेचता है।

## 9 लघु उद्योगों के उत्पादन क्षेत्रों का आरक्षण (Reservation)

लघु एव कुटीर उद्योगों को बड़े एव सगठित उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिये सरकार ने समय-समय पर कुछ वस्तुओं के उत्पादन को पूर्णतः लघु एव कुटीर उद्योगों के लिये आरक्षित कर दिया है अतः उन वस्तुओं का उत्पादन बड़े एव सगठित उद्योग नहीं कर सकते। जहाँ 1967-68 में आरक्षित उद्यमों की संख्या 46 थी वह बढ़कर 1976-77 में 180 पहुँच गई। नई औद्योगिक नीति की घोषणा के समय 324 नये उद्यमों को आरक्षण प्रदान करने से जनवरी 1977 में आरक्षित उद्यमों की संख्या 504 हो गई। उसके बाद में और वृद्धि करने से अब यह संख्या 805 से भी अधिक है।

## 10. बड़े उद्योगों पर विशेष कर (CESS) लगाया गया है

लघु एव कुटीर उद्योगों को बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिये बड़े उद्योगों के कुछ उत्पादनों पर विशेष कर (CESS) लगाया गया है। इस कर



राशि का प्रयोग लघु एवं कुटीर उद्योगों को अनुदान देने या उनके विकास पर व्यय किया जाता है।

### 11. औद्योगिक बस्तियों की स्थापना

लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास हेतु सरकार ने औद्योगिक बस्तियों की स्थापना की है। योजनावद्ध विकास के पिछले 28 वर्षों में लगभग 670 औद्योगिक बस्तियाँ स्थापित की गई हैं जिनमें 580 में उत्पादन कार्य चालू है तथा 90 निर्माणाधीन हैं। इन औद्योगिक बस्तियों के निर्माण पर सरकार ने लगभग 80 करोड़ ₹ व्यय किया है जिससे 580 औद्योगिक बस्तियों के 16500 कारखानों में लगभग 2.5 लाख श्रमिकों को रोजगार मिला है और उनमें 500 करोड़ ₹ से अधिक मूल्य का वार्षिक उत्पादन होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास हेतु अनेक कदम उठाये गये हैं। जनता सरकार ने तो देश में रोजगार वृद्धि एवं विकेंद्रित औद्योगीकरण के लिये लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अतः लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास तेज हुआ है।

### पंचवर्षीय योजनाओं में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास (Development of Small & Cottage Industries During the Plans)

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास को विशेष महत्व दिया गया है। योजनावद्ध प्रावधान व व्यय इस प्रकार हैं—

**प्रथम पंचवर्षीय योजना—**प्रथम पंचवर्षीय योजना में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिये 43 करोड़ ₹ व्यय का प्रावधान था पर वास्तविक व्यय 42 करोड़ ₹ हो हुआ है। प्रथम योजनाकाल में उद्योगों के विकास हेतु विशिष्ट संस्थाएँ स्थापित की गईं। कर्षे समिति की नियुक्ति की गई जिसमें माछी विकास के सुझाव दिये गये। इस योजनाकाल में लघु उद्योगों की वित्तीय व्यवस्था पर ध्यान दिया गया। बड़ उद्योगों में प्रतिस्पर्धा में लघु उद्योगों का संरक्षण देने के लिये व्यवस्था की गई।

**द्वितीय पंचवर्षीय योजना—**इस योजना में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए 200 करोड़ ₹ व्यय का प्रावधान किया पर वास्तविक व्यय 180 करोड़ ₹ हुआ। इस अवधि में कर्षे समिति के सुझाव का कार्यान्वित किया गया। तकनीकी व औद्योगिक महत्त्व के लिए औद्योगिक सेवा संस्थानों व उद्योग विस्तार सेवा योजनाओं को बढ़ाया गया। 66 औद्योगिक बस्तियों का निर्माण किया। 1961 तक देश में 3.8 लाख अग्रर चलें अतिरिक्त किये। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई तथा चार सहायक निगम बनाये गये। 1960-61 में सरकार द्वारा लघु उद्योगों से 9.5 करोड़ ₹ का मास परीदा था।

## धन-प्रधान लघु एव कुटीर उद्योग

तृतीय पंचवर्षीय योजना में लघु एव कुटीर उद्योगों के विकास कार्यक्रम पर 241 करोड़ रु व्यय किया गया। इस अवधि में बड़े और छोटे उद्योगों के परस्पर मिले जुले उत्पादन कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया। राज्य वित्त निगमों की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ने गारन्टी योजना प्रारम्भ की। इस योजना में 300 नयी औद्योगिक वस्तियाँ स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया।

तीन वार्षिक योजनाओं में लघु एव कुटीर उद्योगों के विकास पर 144 करोड़ रु व्यय किया गया जिससे सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भी लघु एव कुटीर उद्योगों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस योजना में इनके विकास व्यय पर 293 करोड़ रु व्यय करने का प्रावधान था। इस विकास व्यय से सभी प्रकार के लघु एव कुटीर उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन दिया गया। 18 15 करोड़ रु व्यय से 147 औद्योगिक वस्तियों की स्थापना की गई। ग्रामीण उद्योगों के विकास कार्यक्रमों पर 51 करोड़ रु तथा शक्ति संचालित करघों के विकास पर 43 करोड़ रु व्यय किये जाने थे।

— पाँचवीं योजना—इस योजना में भी गरीबी हटाने तथा आर्थिक विषमता कम करने के उद्देश्य से लघु एव कुटीर उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र में उनके विकास पर 535 करोड़ रु का प्रावधान था। किन्तु इसकी मध्यावधि समाप्ति के समय 1977-78 तक 387.8 करोड़ रु व्यय किये जा चुके हैं। 21-सूचीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.60 लाख लघु उद्योग खोले जाने थे जिनमें से 1.23 लाख लघु उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने थे।

## भारत में लघु उद्योगों की वर्तमान स्थिति<sup>1</sup> एवं छठी योजना

अभी हाल ही में लघु उद्योग विकास समूहों के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में इस समय पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों की संख्या लगभग 5 लाख है जिनमें लगभग 1850 करोड़ रु की पूँजी लगी हुई है। 1978 में इनके उत्पादन का कुल मूल्य 7200 करोड़ रु है जबकि 1972 में लघु उद्योगों में विनियोजित पूँजी 1054 करोड़ रु थी और उत्पादन का मूल्य 2900 करोड़ रु था। औद्योगिक उत्पादन में लघु उद्योगों का लगभग 40% भाग है। इन लघु उद्योगों में संगठित उद्योगों के मुकाबले कहीं अधिक रोजगार क्षमता है। फैक्टरी में 20 लाख लोग रोजगार में हैं जबकि फैक्टरी क्षेत्र में 155 लाख लोग काम पर लगे हुए हैं। पिछले वर्षों में सरकारी प्रयासों से नये साहसी वर्ग का विकास हुआ है और 2 लाख नई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हुई हैं।

निर्यात प्रयासों में भी लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जहाँ 1971-72 में लघु-उद्योग क्षेत्र का निर्यात 155 करोड़ रु था वह 1977-78

1. Source—Financial Express Feb 20, 1977 Page 1, Col 6-7.

में बढ़कर 800 करोड़ रु हो गया है जो कि कुल निर्यात मूल्य का लगभग 15% भाग है।

हाथ करघो, शक्ति संचालित करघो व खादी आदि का सम्मिलित सूती कपड़े का उत्पादन 1968-69 के 358 करोड़ मीटर से बढ़कर 1978-79 में 410 करोड़ मीटर तथा कच्चे रेशम का उत्पादन 23 लाख किलोग्राम से बढ़कर 33 लाख किलोग्राम हो गया है। ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं में उत्पादित वस्तुओं का उत्पादन 1968-69 में 22 करोड़ रु से बढ़कर अब 100 करोड़ रु से भी अधिक होने का अनुमान है।

**छठी पंचवर्षीय योजना**—सुनियोजित रूप में रोजगार प्रदान करने के लिये इस क्षेत्र को बहुत उंची प्राथमिकता दी जायेगी। इसके लिये विभिन्न मोर्चों पर काम होगा जिनमें नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत प्रारक्षण 504 उद्योगों के लिये कर दिया गया है। अब यह संख्या 807 है। उत्पादन शुल्क में भी राहत दी जायेगी। योजना के अन्त तक सभी जिलों में औद्योगिक केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। पर्याप्त एवं प्रभावी ऋण व्यवस्था की जायेगी। तकनीकी सहायता, विपणन व्यवस्था एवं ग्रन्थ सुविधायें उपलब्ध करने तथा विकास हेतु योजनाकाल में 1410 करोड़ रु व्यय का प्रावधान है जो पाचवी योजना के व्यय के मुकाबले 3 गुना है।

### लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के सुझाव

यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं फिर भी अनेक कमियाँ हैं जिन उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये निम्न सुझाव हैं—

1 **बड़े व छोटे उद्योगों में सहयोग**—दोनों में प्रतिस्पर्धा समाप्त करने के लिये दोनों के उत्पादन क्षेत्र निर्धारित कर एक दूसरे के पूरक बनाने से समस्या हल हो सकती है।

2 **तकनीकी सुधार**—लघु एवं कुटीर उद्योगों में नवीनतम आधुनिक मशीनों को प्रोत्साहन देना चाहिये इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण व्यवस्था की जानी चाहिए।

3 **प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार**—तकनीकी सुधार के लिए प्रशिक्षण की विस्तृत सुविधायें होनी चाहिये। यद्यपि पोलिटेक्निक कालेज खोले गये हैं पर आधुनिक विधियों की जानकारी के लिए और अधिक सुविधाएँ दी जा सकती हैं।

4 **कच्चे माल की पूर्ति करने के लिये सरकार के उद्योग विभाग को सहायता करनी चाहिए तथा आयातिन कच्चे माल में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।** महकारी समितियों के निर्माण से भी कच्चे माल की पूर्ति को सुविधाजनक बनाया जा सकता है।

5. **वित्त सम्बन्धी सुविधायें**—यद्यपि पिछले 27-28 वर्षों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की वित्त व्यवस्था में काफी प्रयास हुए हैं पर उनकी कुल आवश्यकता को

देखते हुए ऋण अर्पणार्थ हैं। उन्हें महाजनो के चंगुल में फसना पड़ता है मत. सह-कारिता व व्यापारिक बैंको के मार्फत अधिक साख उपलब्ध की जानी चाहिये।

6. अनुसंधान व सर्वेक्षण के द्वारा भावी विकास का मार्ग निश्चित किया जा सकता है। समस्याओं के मूल कारणों का पता लगाया जाकर आवश्यक सुधार किये जा सकते हैं।

7. मशीनों व औजारों की पूर्ण विज्ञान खरीद पद्धति द्वारा की जानी चाहिये। देश में कारीगरों को आधुनिक मशीनों की खरीद के लिए अनुदान व भासान शर्तों पर ऋण दिये जाने चाहिये ताकि वे रुढ़िवादी पद्धतियों के स्थान पर आधुनिक मशीनों के द्वारा उत्पादन में प्रेरित हो।

8. सुसंगठित बिक्री व्यवस्था—कारिगरो को अपने उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने तथा बिक्री बढ़ाने के लिए देश विदेश में जनता की रुचि बढ़ाने के लिए बिक्री केन्द्र खोले जाने चाहिये। सहकारी बिक्री समितियाँ संगठित की जानी चाहिये तथा सरकार को खरीद में पहल करनी चाहिये।

9. अन्य सुझाव (i) इसके पतिरिक्त लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए उत्पादन क्षेत्र सुरक्षित कर उन्हें बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सकता है। (ii) नई-नई डिजाइनों को प्रोत्साहन देना चाहिये। (iii) लघु एवं कुटीर उद्योगों के उत्पादन को स्थानीय करों व अन्य करों से मुक्ति प्रदान की जानी चाहिये। (iv) सहकारी औद्योगिक उत्पादन समितियों के गठन को प्रोत्साहन देना चाहिये।

इस प्रकार अगर लघु एवं कुटीर उद्योगों की कठिनाइयों का निराकरण किया गया तो उनका तेजी से विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा, समाजवाद का मार्ग प्रशस्त होगा और विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के निर्माण में सहायता मिलेगी। देश में उत्पादन अभाव व बढ़ते मूल्यों की समस्या का समाधान सम्भव होगा।

### परीक्षोपयोगी प्रश्न मय संकेत

1. भारत के लघु एवं कुटीर उद्योगों के महत्व को स्पष्ट कीजिये तथा उनके विकास के प्रयत्नों की विवेचना कीजिये।  
(संकेत :—प्रथम भाग में अर्थ बताकर महत्व देना है और दूसरे भाग में विकास के प्रयत्नों की विवेचना करना है।)
2. पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिये किये गये प्रयत्न कहाँ तक पर्याप्त हैं? अपनी धोर से भी सुझाव दीजिये।  
(संकेत :—पंचवर्षीय योजनाओं में किये गये प्रयत्नों को शीर्षकानुसार दीजिए तथा अन्त में सुझाव देना है।)
3. भारत के लघु एवं कुटीर उद्योगों की क्या-क्या समस्याएँ हैं और उन्हें दूर करने के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद किये गये प्रयत्नों का आलोचनात्मक विवरण दीजिये।

(संकेत :—मुद्रा समस्याओं का वहीन देवर सरकार द्वारा समस्याओं के निराकरण के लिए किये गये प्रयत्नों का विवेचन देना है ।)

4. भारत के लघु एवं कुटीर उद्योगों के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिये तथा उनका पुनर्गठन के प्रयत्नों का विवेचन कीजिये ।

(संकेत :—ब्रिटिश शासन-काल में लघु एवं कुटीर उद्योगों के पतन के कारण बताकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उनके विकास के लिए किये गये प्रयत्नों का उल्लेख कीजिये ।)



# भारतीय विदेशी व्यापार की संरचना एवं दिशा तथा व्यापारिक नीति की प्रवृत्तियाँ

(Trends in the Composition & Direction of Foreign Trade & Commercial Policy)

दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच व्यापार क्रिया को विदेशी व्यापार कहा जाता है और यह प्रक्रिया देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। आज एक देश सभी वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता रखते हुए भी तुलनात्मक लागत लाभ उठाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार से लाभान्वित होने के लिए विदेशी व्यापार का सहारा लेता है। विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक समृद्धि के लिए विदेशी व्यापार में वृद्धि तथा नियन्त्रण की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है ताकि उन्हें विदेशी मुग्तान सकट का सामना कम करना पड़े।

विदेशी व्यापार में भारत का अतीत गौरवपूर्ण रहा। भारत शताब्दियों तक अपनी कलापूर्ण वस्तुओं, कारीगरों की उच्च किस्म तथा नमूनों की वस्तुओं के निर्यात से भारतीय जनता की समृद्धि और भौतिक कल्याण में वृद्धि करता रहा। पर अठारहवीं शताब्दी में पश्चिमी राष्ट्रों में औद्योगिक क्रांति, भारत में ब्रिटिश शासन का उदय और उसकी दृढ़तापूर्ण कठोर नीति हमारे उद्योगों के पतन के लिए निर्याती में बाधा बनी। द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारम्भ में 1940-41 में भारत से 187 करोड़ रुपये का निर्यात तथा भारत में 157 करोड़ रुपये का आयात होता था। पर स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश का विभाजन होने, खाद्यान्न के अभाव तथा विकास कार्यों के लिए पूँजीगत सामान के आयात से व्यापार संतुलन जो पहले प्रायः पक्ष में रहता था, विपक्ष में रहने लगा। यहाँ तक कि 1949 तथा 1966 में मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ा। 1957 में देश के सामने भारी विदेशी विनिमय सकट उत्पन्न हो गया। अब भी विदेशी व्यापार में घाटा अधिक है। भारत के विदेशी व्यापार की प्रवृत्ति एवं समस्याओं के अध्ययन के लिए उसकी विशेषताओं की जानकारी आवश्यक है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएँ  
(Salient Features of Foreign Trade of India Since Independence)  
15 अगस्त, 1947 को भारत विदेशी परतन्त्रता से मुक्त हो अपने भाग्य का

निर्माता बना। देश में योजना-बद्ध विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। अतः देश के विदेशी व्यापार में मात्रा, प्रकृति, बनावट, दिशा आदि में अनेक नई प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है। ये विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

1 विदेशी व्यापार मात्रा में वृद्धि—स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत के विदेशी व्यापार में मात्रा व मूल्यों दोनों की दृष्टि से तेजी से वृद्धि हुई है। 1940-41 में भारत का कुल विदेशी व्यापार 344 करोड़ रुपये था वह बढ़कर 1965-66 में 2,254 करोड़ रुपये तथा 1970-71 में 3,158 करोड़ रु तथा 1973-74 में 5450 करोड़ रु होने का अनुमान है जबकि 1978-79 में विदेशी व्यापार 12322 करोड़ रु होने का अनुमान है। निम्न तालिका विदेशी व्यापार में निरन्तर वृद्धि का स्पष्टीकरण करती है—

### भारत का विदेशी व्यापार (1950-79)

(करोड़ रुपये)

वर्ष	आयात	निर्यात	कुल विदेशी व्यापार	व्यापार शेष
1950-51	650 4	600 7	1251 0	- 49 8
1960-61	1122 5	642 1	1764 6	- 480 4
1970-71	1634 20	1535 2	3169 4	- 99 0
1975-76	5265 0	4043 0	9308 0	-1222 0
1976-77	5074 0	5143 0	10217-0	+ 69 0
1977-78	6066 0	5373 0	11439 0	- 693 0
1978-79	6703 9	5618 0	12322 1	-1085 7

2 आयात निर्यात दोनों में वृद्धि—भारत के निर्यातों एवं आयातों का मूल्यों निरन्तर बढ़ा है। देश में तीव्र औद्योगीकरण के कारण बड़ी मात्रा में पूंजीगत सामान का आयात किया जाने से व खाद्यान्नों का भी आयात करने की अनिवार्यता आयातों में निर्यातों से प्रायः अधिकता का रूप रहा। अब निर्यातों में तेजी से वृद्धि व आयातों में कमी की प्रवृत्ति है। जहाँ 1950-51 में आयात 650 करोड़ रु, 1973-74 में 2925 करोड़ रु था वह 1978-79 में 5618 करोड़ रु हो गया। इसी प्रकार

निर्यातों का मूल्य 1950-51 में 601 करोड़ रु. बढ़कर 1973-74 में 2523 करोड़ रु. तथा 1978-79 में 6704 करोड़ रु. हो गया है।

3. व्यापार संतुलन प्रतिकूलता में वृद्धि—द्वितीय विश्व-युद्ध तक भारत का व्यापार शेष भारत के पक्ष में रहता था। 1940-41 में 30 करोड़ रु. पक्ष में था। पर स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद व्यापार संतुलन विपक्ष में रहने लगा और तीव्र गति से वृद्धि के कारण विदेशी विनिमय को सकटों का सामना करना पड़ रहा है। 1950-51 में व्यापार का घाटा केवल 49.8 करोड़ रु. था वह 1957-58 में बढ़कर 640 करोड़ रु. हो गया। 1966-67 में यह घाटा अपनी शरम सीमा 922 करोड़ तक पहुंच गया। अब घटने का रुख है। 1968-69 में व्यापार शेष 552.4 करोड़ रु. विपक्ष में था। 1969-70 में केवल 154.0 करोड़ रु. रहा है। 1970-71 में केवल 98.97 करोड़ रु. विपक्ष में रहा। 1973-74 में पुनः बढ़कर 402 करोड़ रु., तथा 1975-76 में 1222 करोड़ रु. था, अब 1978-79 में पुनः घाटा 1086 करोड़ रु. हो गया है।

4. व्यापार की संरचना या बनावट (Composition) में परिवर्तन—ब्रिटिश शासन काल में आयात में निर्मित माल का 84% होता था तथा निर्यात में कच्चा माल तथा खाद्यान्न आदि परम्परागत वस्तुओं का 70% भाग था। अब उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। आयात में खाद्यान्न, मशीनरी तथा अन्य पूंजीगत माल का बाहुल्य होता है। निर्यात में यद्यपि अब भी परम्परागत वस्तुओं का भाग 40% है पर लोह-इस्पात, इन्जीनियरिंग सामान, सूखे मेवे तथा चमड़े का निर्मित माल, बिजली के पंखे, सिलाई की मशीन, रेल के इंजन आदि के निर्यात में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है। यह भाग स्पष्ट किया जायगा। पहले भारत खाद्यान्न का निर्यातक था पर अब आयातक है और खाद्यान्न का आयात प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय योजना काल में क्रमशः 595 करोड़ रु., 850 करोड़ रु. तथा 1,150 रुपये रहा। चतुर्थ योजना में भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो जाता पर अकाल के कारण 1973-74 में 170 करोड़ रु. के खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। निर्यात में विविधता आई है। जहाँ 1950-51 में केवल 100 प्रकार की वस्तुएँ निर्यात की जाती थीं अब लगभग 3 हजार प्रकार की वस्तुएँ निर्यात की जाती हैं। प्रमुख आयात-निर्यात मर्चे भागे दी गई हैं।

5. व्यापार की दिशा (Direction) में परिवर्तन—स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व हमारे विदेशी व्यापार से इंग्लैंड को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अब अमेरिका का स्थान ऊँचा हो गया है। अब हमारा विदेशी व्यापार पश्चिमी यूरोपीय देशों व साम्राज्यवादी देशों से भी तेजी से बढ़ रहा है। जहाँ द्वितीय विश्व-युद्ध से पूर्व अमेरिका का हमारे आयात-निर्यात में क्रमशः 6 और 9 प्रतिशत भाग था वह बढ़ कर 1971-72 में क्रमशः 35% तथा 18% हो गया। रूस का भाग 1948-49 में नगण्य था वह 1971-72 में क्रमशः 6 और 11 प्रतिशत हो गया। अब हमारे विदेशी



## भारत के विदेशी व्यापार की दिशा (Direction of Foreign Trade of India)

देश	आयातों का प्रतिशत वितरण (Percentage Distribution)					निर्यातों का प्रतिशत वितरण (Percentage Distribution)				
	1938-39	1951-52	1960-61	1970-71	1976-77	1938-39	1951-52	1960-61	1970-71	1976-77
ब्रिटेन	29.9	17.6	19.0	7.8	5.2	34.3	25.9	26.1	11.1	10.2
अमेरिका	16.3	30.4	28.7	27.7	24.6	8.4	18.1	15.5	13.5	12.9
रुस	0.8	2.0	1.8	7.2	4.4	1.3	2.2	2.7	2.1	1.0
फ्रांस	0.8	1.2	1.9	1.3	3.5	3.8	1.6	1.3	1.2	2.2
यू जर्मनी	10.9	3.0	10.7	6.6	6.7	5.1	1.3	3.0	2.1	3.2
इटली	0.1	0.1	1.4	6.5	5.7	—	0.9	4.4	13.6	10.5
जापान	9.0	2.6	5.3	5.1	6.9	8.7	2.0	5.3	13.3	10.8
सांगाना देश	—	—	—	—	0.8	—	—	—	0.1	1.2
अन्य सहित कुल योग	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Source Eastern Economist Page 1383 & 1392 Dec 28, 1973, & 1975-76 from  
Journal of Industry & Trade, Jan 1977 pp 80-83

व्यापार में अमेरिका, ब्रिटेन तथा रूस को क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त है जैसा कि चार्ट 190 पर दी गई तात्तिका से स्पष्ट है—

इस प्रकार हम देखते हैं कि अब हमारे विदेशी व्यापार में ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी व फ्रांस आदि का महत्व घटा है जबकि रूस, जापान व अमेरिका का महत्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है। अमेरिका से बांग्लादेश के स्वतन्त्रता संग्राम के समय हमारे सम्बन्ध बिगड़ने से विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा।

6 विदेशी व्यापार नीतियों में नये मोड़—भारत में आयात निर्यात नीतियों को देश की विकास नीतियों के अनुकूल बनाने की चेष्टा की गई है। विदेशी विनिमय संकट से छुटकारा पाने के लिए आयात को कम करने के लिए नियन्त्रणों में वृद्धि तथा निर्यात में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन की नीतियाँ अपनाई गई हैं। 1970-71 व 1971-72 की आयात नीतियों को उत्पादन निर्यात-मुख (Production Cum Export-Oriented) बनाया गया है। यद्यपि विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण तो नहीं किया गया पर उसके सरकारीकरण का सिलसिला 1969-70 से लागू हो गया है, क्योंकि 1969-70 में राज्य व्यापार संस्थाओं को 22 वस्तुओं के आयात का एकाधिकार प्रदान किया गया था। 1970-71 में 38 वस्तुओं के और समावेश से 60 वस्तुओं के आयात का एकाधिकार प्राप्त हो गया। सरकार द्वारा राज्य व्यापार-निगम के अन्तर्गत एक अलग केन्द्र की स्थापना राज्य अभिकरणों के बढ़ते प्रभाव का घौंक है। नई आयात नीतियों में कुछ और वस्तुओं का सरकारी सूचो में समावेश हो जाने से अब 210 वस्तुओं के आयात में सरकार को एकाधिकार प्राप्त हो गया है। 1977-78 की आयात नीति के अनुसार जो उपक्रम अपने उत्पादन का 20% निर्यात करते थे उन्हें अपने लिए आयातों तथा वित्तीय सहायता में बरीयता दी जायेगी। लोह-हस्तात के निर्यात को छूट दी गई है।

7 निर्यात सम्बर्द्धन प्रयत्नों में वृद्धि—विकास कार्य-क्रमों के लिए विदेशी विनिमय साधन जुटाने तथा विदेशी विनिमय संकट की समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्यात वृद्धि के लिए ऋरो में रियायतें भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन, निर्यात संस्थाओं की स्थापना, तथा आवश्यक सुविधाओं की समय समय पर घोषणा की गई है। निर्यात सम्बर्द्धन के लिए किये गये प्रयत्नों का उल्लेख आगे विस्तार से दिया गया है। 1978-79 की आयात नीति में निर्यात सम्बन्धी अनेक सुविधाओं का विस्तार किया है। 1979-80 में और सुविधाएँ दी हैं।

8 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के माग में कमी—विश्व के विदेशी व्यापार में 1950-60 की अवधि में द्रुगुनी वृद्धि हुई है। भारत का 1950-51 में विदेशी व्यापार में 2.1% भाग था वह घटकर 1960 में केवल 1.1% ही रह गया। अब यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत का हिस्सा विश्व व्यापार में केवल 0.6% ही रह गया है। भारत के विदेशी व्यापार में वृद्धि तो हुई है पर विश्व व्यापार में इससे कहीं अधिक वृद्धि हुई है। 1978-79 में विश्व का कुल निर्यात 1300 अरब

डालर था उसमें भारत का निर्यात 8 अरब डालर ही था जो विश्व निर्यात का केवल 6% भाग ही है। भारत का स्थान 28 वां है।

9 विदेशी व्यापार में भारतीयकरण—भारत में विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग विदेशी आयात-निर्यात फर्मों, जहाजी कंपनियों, बीमा कंपनियों तथा विदेशी विनिमय बैंकों के हाथ में है। अतः लाभ उन्हें ही प्राप्त होता है। अब यद्यपि भारतीयकरण करने का कार्य प्रगति पर है पर गति धीमी होने से लाभोपार्जन विदेशियों को हो रहा है।

10 विदेशी व्यापार का केन्द्रीयकरण—भारत के विदेशी व्यापार का लगभग 68% भाग सामुद्रिक मार्ग से होना है। अतः विदेशी व्यापार मुख्यतः बम्बई, कलकत्ता, मद्रास बन्दरगाहों में केन्द्रित है। इन बन्दरगाहों पर भीड़ कम करने के लिए विनालापट्टनम्, कोचीन और बान्दला बन्दरगाहों को विकसित किया जा रहा है।

### भारत के मुख्य आयात (Principal Imports of India)

भारत के आयातों में पहले निर्मित माल की प्रमुखता थी। अब हमारे मुख्य आयात मशीनों, पूँजीगत सामान लोहा-इस्पात, यातायात उपकरण, रासायनिक पदार्थ तथा घालीह घातुरें एवं खाद्यान्न हैं। आयात की वस्तुओं तथा आयातित देशों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—1978-79 में पिछले वर्ष के मुकाबले 15% की वृद्धि हुई है।

1 मशीनें बिजली का सामान तथा परिवहन उपकरण—हमारे आयातों में इस मद का प्रथम स्थान है क्योंकि देश में औद्योगीकरण की योजनाओं का इनके आयात के बिना त्रिगन्धित करना मुश्किल है। 1950-51 में इनका आयात 91 करोड़ रुपये का था पर 1965-66 में बढ़कर 802 करोड़ रु का हो गया। 1969-70 में इनका आयात 395 करोड़ रु रहा जबकि 1973-74 में आयात 781.6 करोड़ रुपये रहा है। 1977-78 में बढ़कर 1158 करोड़ रु हो गया है। इन वस्तुओं का आयात ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, जापान, कनाडा से होता है। अब भारत में चीनी, सीमेन्ट, बिजली की मशीनें, यातायात उपकरण के उत्पादन में वृद्धि से भविष्य में इनके आयात में कमी आयेगी।

2 लोहा-इस्पात—देश में लोहा-इस्पात की अधिक मांग है। यद्यपि तीन लोहा-इस्पात कारखानों से पूर्ति में वृद्धि हुई है फिर भी आयात करना पड़ता है पर अब कमी का रुख है। 1960-61 में खाद्यान्न का आयात 163 करोड़ रु था वह 1965-66 में 154 करोड़ रु तथा 1969-70 में घटकर 81 करोड़ रुपये ही रह गया है पर 1973-74 में आयात 249.3 करोड़ रुपये रहा है जबकि 1977-78 में बढ़कर 350 करोड़ रु हो गया है। भारत में लोहा-इस्पात मुख्यतः इंग्लैण्ड, अमेरिका तथा पश्चिमी जर्मनी से मगवाया जाता है।

3 खाद्यान्न एवं खाद्यान्न का सामान—देश में बढ़ती जनसंख्या और मान्यून

## भारतीय विदेशी-व्यापार की संरचना तथा व्यापारिक नीति

के प्रकोपो के कारण भारत जो विभाजन से पूर्व खाद्यान्न का निर्यातक देश था अब आयातक हो गया है। जहाँ 1950-51 में खाद्यान्न का आयात केवल 99 करोड़ रुपये था वह बढ़कर 1965-66 में 507 करोड़ रुपये हो गया। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में क्रमशः 595 करोड़, 850 करोड़ तथा 1,150 करोड़ रुपये के मूल्य का खाद्यान्न आयात किया गया। 1969-70 में भी लगभग 261 करोड़ रुपये के खाद्यान्न का आयात हुआ और 1971-72 में आयात केवल 197 करोड़ रु रहा। 1975-76 में खाद्यान्न का आयात मुख्य 342.8 करोड़ रु रहा जबकि 1977-78 में घटकर 122 करोड़ रुपये रह गया है। अमेरिका से गेहूँ एवं चावल, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा अर्जेंटीना से गहूँ और बर्मा तथा थाइलैंड से चावल आयात करते हैं।

4 खनिज, ईंधन एवं अन्य चिकने पदार्थ—इस मद के अन्तर्गत आशिक साफ या कूड़ पेट्रोल व मिट्टी का तेल एवं चिकने पदार्थों का समावेश करते हैं। इसका आयात 1950-51 में केवल 55 करोड़ रुपये था पर 1965-66 में आयात का मूल्य 107.5 करोड़ रुपये था। अब भारत में ही खनिज तेल साधनों के विदोहन में प्रगति से आयात में कमी होनी थी पर माँग बढ़ जाने के कारण आयात में वृद्धि हुई है। 1969-70 में 96 करोड़ रुपये व पेट्रोल तथा 41 करोड़ रुपये के अन्य सामान आयात हुए। 1973-74 में इसका कुल आयात मूल्य 560.64 करोड़ रुपये रहा। 1977-78 में आयात 1556.4 करोड़ रुपये का रहा। पेट्रोल बर्मा, रूस, ईरान व अमेरिका से आयात किया जाता है।

5 रासायनिक तत्व एवं घोल—देश में कृषि एवं औद्योगिक विकास के कारण रासायनिक तत्व एवं घोल का महत्व बहुत बढ़ गया है। इसके अन्तर्गत रंगों का सामान, दवाइयाँ, उर्वरकों का सामान तथा रासायनिक तत्व एवं घोल आते हैं। 1965-66 में उर्वरकों का आयात मूल्य 81 करोड़ रुपये था वह 1968-69 में 150 करोड़ रुपये हो गया तथा रासायनिक तत्वों एवं घोल का आयात क्रमशः 56.5 करोड़ से बढ़कर 82 करोड़ रुपये हो गया। 1977-78 में रासायनिक उर्वरकों तथा रासायनिक तत्वों एवं घोल का आयात क्रमशः 338 करोड़ रुपये तथा 194.4 करोड़ रुपया रहा। इन वस्तुओं का आयात ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी तथा जापान से होता है। भारत में रासायनिक खाद का उत्पादन बढ़ाने से जहाँ 1968-69 में आयात 150 करोड़ रुपये मूल्य का था वह 1976-77 में घटकर 197.7 करोड़ रु हो गया जबकि 1977-78 में 338 करोड़ रु का था।

6 कपास व कच्चा जूट—विभाजन से पूर्व भारत जूट के कच्चे माल का एकमात्र उत्पादक तथा कपास का निर्यातक था पर ये क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने से आयात करना पड़ता है। पंचवर्षीय योजनाओं में भारत में उत्पादन में वृद्धि से आयात पर निर्भरता कम होती जा रही है। जहाँ 1950-51 में कपास व जूट का आयात क्रमशः 101 करोड़ तथा 17.5 करोड़ रुपये था वह 1968-69 में घट कर

क्रमशः 90 करोड़ तथा 9 करोड़ रुपये रह गया है। 1977-78 में आयात मूल्य क्रमशः 199 करोड़ रुपये तथा 4 करोड़ रुपये ही होने का अनुमान है। कपास का आयात मिस्र अमेरिका, सूडान व पाकिस्तान से तथा जूट का आयात पाकिस्तान से होता है। वैसे हम छोटे देशों की घटिया किस्म की रुई का निर्यात करते हैं पर बढ़िया किस्म की लम्बे रेशे की रुई का आयात करते हैं।

7 अन्य आयात—इसके अलावा भारत अलौह वस्तुएँ (तावा, सीसा, टिन, रागा, निकल) पशुओं की चर्बी, रबर पेपर बोर्ड, कच्चा ऊन और हीरे-मोतियों का आयात भी करता है। अलौह धातुओं का आयात 1960-61 में 74.5 करोड़ रु था वह बढ़कर 1965-66 में 108 करोड़ रु हो गया। 1977-78 में आयात 100 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसी प्रकार 1969-70 में रबर का आयात 9.7 करोड़ रुपये था वह घटकर 1977-78 में 7 करोड़ रुपये रहा। धागज, अलवारी कागज व कागज का निमित्त माल 62 करोड़ रुपये तथा वनस्पति तेल का आयात 712 करोड़ रुपये रहा क्योंकि देश में बढ़ते भावों के नियन्त्रण के लिये अधिक आयात हुआ।

### भारत के प्रमुख आयात (Imports 1950-78)

(मूल्य करोड़ रुपये में)

वर्ग	1950-51	1960-61	1970-71	1973-74	1977-78
1 पूर्वागत सामान मशीनें, बिजली का सामान, परिवहन सामान इत्यादि	91.4	560.5	409	781.6	1158
2. लौह इस्पात	20	193	147	249.3	350
3 लौह अथवा लौह सामग्री	99.5	285.7	213	352.5	122
4 पेट्रोलियम व अन्य चिकन पदार्थ	55.0	109.0	136	560.64	1556
5 कपास	100.8	128.8	98.8	52.05	199
6 जूट	27.5	12.0	1.1	1.2	4
7 उबरक एव उबरक सामग्री	12.4	23.4	61.0	162.8	338
8. अलौह धातुएँ	28.3	74.5	119.6	140.2	100
9 रासायनिक तत्व एव घोल	9.4	61.9	68.0	109.6	194
अन्य सहित कुल योग	650.3	1795.0	1625.2	2955.7	6066.0

## भारत के प्रमुख निर्यात (Principal Exports of India)

जिस प्रकार भारत के आयात में कुछ ही वस्तुओं की प्रधानता है ठीक उसी प्रकार हमारे निर्यात व्यापार में भी परम्परागत वस्तुओं की प्रधानता है। चाय, सूती कपड़ा तथा जूट में निमित्त माल का हमारे निर्यात में अब भी लगभग 40 से 43 प्रतिशत भाग है। अब इन्जीनियरिंग सामान, लोहा, इस्पात, रसायन व मछली आदि वस्तुओं के निर्यात में तीव्र गति से वृद्धि हुई है और विविधता दृष्टिगोचर हुई है पर जूट के निमित्त माल में चाय तथा काजू हीरे-मोती व तिलहनो के निर्यात में कमी का दृष्टि है। हमारे निर्यातों में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है परिणामस्वरूप निर्यात में वृद्धि हो रही है। 1978-79 में निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 6.5% बढ़े।

1 जूट से निमित्त माल—इनके अन्तर्गत टाट, घटाइया, बोरे, गलीचे व घुलसी आदि हैं। 1948-49 में विश्व व्यापार में जूट के निमित्त माल के निर्यात में भारत का हिस्सा 97% था पर अब प्रतिस्पर्धा वस्तुएं काम में देशों की प्रतिस्पर्धा से हमारे निर्यात कम हो रहे हैं। जहाँ 1950-51 में जूट के निमित्त माल का मूल्य 113.8 करोड़ रुपये था वह 1965-66 के उच्चतम बिन्दु 288 करोड़ रुपये पहुँच गया। 1970-71 में केवल 190.4 करोड़ रु. ही रहा जबकि 1976-77 में निर्यात बढ़कर 200.8 करोड़ रुपये हो गया है। जूट के निमित्त माल के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने निर्यात शुल्क जो 750 रुपये प्रति टन था घटा कर अब 200 रुपये प्रति टन कर दिया है तथा अभिनवीकरण में सहायता दे रही है। हमारे मुख्य ग्राहक संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, कनाडा, चीन, पीकू, क्यूबा, थाईलैंड आदि हैं। 1977-78 में निर्यात 245 करोड़ रुपये से अधिक थे।

2 चाय व काफी—चाय हमारे निर्यात की दूसरी सबसे बड़ी भंड है। भारत का विश्व व्यापार में चाय में पहले 50% भाग था अब घट कर 40% ही रह गया है। अब हमारे प्रतिद्वंद्वी के रूप में तुर्की, अफ्रीका, इण्डोनेशिया आदि हैं। चाय का निर्यात अब देश में ही खपत बढ़ने से घट रहा है। जहाँ 1950-51 में निर्यात 80.4 करोड़ रुपये था वह अपने रिकार्ड बिन्दु पर (1962-63 में) 203 करोड़ रु. पहुँच गया तब से निरन्तर घट रहा है। 1967-68 में निर्यात मूल्य 180 करोड़ रुपये था वह घट कर 1969-70 में 124.5 करोड़ रुपये ही रह गया था पर 1973-74 और 1977-78 में यह बढ़कर क्रमशः 146 तथा 555 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। कॉफी का निर्यात बढ़ा है। 1968-69 में निर्यात 18 करोड़ रुपये था जबकि 1977-78 में निर्यात 191 करोड़ रुपये से कुछ अधिक है। हमारी चाय के बड़े राष्ट्र—ब्रिटेन, अमेरिका, मिश्र, कनाडा, आयरलैंड, सूडान, आस्ट्रेलिया,

पश्चिमी जर्मनी तथा नीदरलैंड आदि हैं। ब्रिटेन हमारे कुल निर्यात का लगभग  $\frac{1}{3}$  भाग चाय खरीदता है।

3 सूत एवं सूती वस्त्र—इस भद का हमारे निर्यात व्यापार में तीसरा स्थान है। कुछ वर्षों में निर्यात के गिरने की प्रवृत्ति रही पर 1969-70 में फिर वृद्धि हुई है। देश में खपत बढ़ने तथा सुपरफाइन व बढिया किस्म के कपड़े के उत्पादन की कमी से तो निर्यात कम हुए हैं पर साथ-साथ विदेशी बाजारों में जापान, पाकिस्तान, हांगकांग, पुर्तगाल व स्पेन की प्रतिस्पर्धा भी महत्वपूर्ण घटक रही है। 1950-51 में हमारे सूत तथा सूती वस्त्रों का निर्यात 138.4 करोड़ रुपये था वह घटकर 1965-66 में 90 करोड़ रुपये हो रह गया। विभिन्न निर्यात प्रयत्नों के फलस्वरूप 1973-74 में निर्यात बढ़कर लगभग 265.6 करोड़ रुपये रहा जबकि 1977-78 में निर्यात 457 करोड़ रुपये रहा है।

भारत के कपड़ों व सूत के सामान के मुख्य ग्राहक ब्रिटेन, लका, बर्मा, आस्ट्रेलिया, मलाया, अदन, इण्डोनेशिया, सूडान, इथोपिया, नाइजेरिया तथा न्यूजीलैंड आदि हैं। निर्यात वृद्धि के लिए निर्यात परिपक्व भी प्रयत्नशील है तथा ठहरने के लिए लागत में कमी तथा हैण्डलूम वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

4 कच्चा लोहा—भारत में उच्चकोटि के लोहे के भण्डार हैं पर देश में आन्तरिक मांग कम है। यद्यपि अब नये कारखानों की स्थापना से मांग में वृद्धि हो रही है। भारत से कच्चा लोहा जापान को निर्यात किया जाता है। 1960-61 में निर्यात मूल्य 34 करोड़ रुपये था वह 1970-71 में बढ़कर 127.3 करोड़ रुपये हो गया है पर 1973-74 में पुन बढ़कर 132.8 करोड़ रुपये होगा जबकि 1977-78 में निर्यात 241 करोड़ रुपये रहा।

5 इजीनियरिंग सामान—देश में औद्योगीकरण से अब इजीनियरिंग सामान की उत्पत्ति में वृद्धि हुई है और भारत जो पहले इजीनियरिंग सामान का बड़ी मात्रा में आयात करता था अब निर्यात करने लगा है। यहाँ से मशीनरी औजार, साइकिलें, स्टील कर्मीचर मशीन टूल्स सिनार्ड की मशीनें पम्पे, डीजन इंजन रेलवे वॉगन, सीमेंट, मशीनरी तथा ट्रांसमिटर मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी अफ्रीका के विकासशील देशों यूरोप के कुछ देशों तथा रूस को निर्यात किया जाता है। जहाँ 1965-66 में केवल 29 करोड़ रुपये मूल्य के इजीनियरिंग सामान का निर्यात होता था वह 1970-71 में निर्यात मूल्य बढ़कर 116.5 करोड़ रु० हो गया है। 1965-66 के मुकाबले इसने निर्यात में लगभग 300% की वृद्धि हुई है। केवल एक साल में ही पिछले वर्ष के मुकाबले 30% की वृद्धि उज्ज्वल भविष्य का संकेत है। 1973-74 में इजीनियरिंग सामान का निर्यात मूल्य बढ़कर 201.7 करोड़ रु० हो गया है। 1977-78 में यह बढ़कर 617 करोड़ रु० होना अनुमान है।

6. काजू व मसाले—इन वस्तुओं की आंशिक विदेशों में मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत मौजम्बिक तथा टांगानिका से कच्चे काजू आयात करता है और उन्हें तैयार कर अमेरिका, रूस, पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जापान, लेबनान तथा नीदरलैंड आदि देशों को निर्यात करता है। 1960-61 में काजू का निर्यात केवल 29.8 करोड़ रु० का था वह बढ़कर 1968-69 में 61 करोड़ रु० मूल्य का हो गया पर 1977-78 में यह 149.5 करोड़ रु० होने का अनुमान है। मसालों का निर्यात भी मुख्यतः उपर्युक्त देशों को होता है। 1965-66 में निर्यात 36.4 करोड़ रुपये था वह 1968-69 में घटकर केवल 25 करोड़ रुपये रह गया पर 1973-74 में निर्यात 54.9 करोड़ रु० था जबकि 1977-78 में निर्यात बढ़कर 137 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

7. लोहा-इस्पात—भारत में लोहा-इस्पात उद्योग के विकास में भारत निर्यात करने में सक्षम हुआ है। हमारे यहां से लोहा इस्पात का निर्यात विकासशील राष्ट्रों को होता है वैसे हम आयातक और निर्यातक दोनों हैं। 1965-66 में लोहा इस्पात का निर्यात 19.5 करोड़ रुपये था वह 1969-70 में बढ़ कर 87.2 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। 1965-66 की तुलना में 1969-70 में लोहा इस्पात के निर्यात में  $3\frac{1}{2}$  गुनी वृद्धि हुई है। 1977-78 में निर्यात मूल्य 186 करोड़ रुपये था।

8. घनस्फटिक तेल व खली—भारत में औद्योगीकरण का प्रभाव तिलहन के निर्यात में कमी पर तेज और खली के निर्यात में वृद्धि का कारण बना। अब भारत से मूंगफली, सरण्डी और अलसी का तेल व खली ब्रिटेन, बर्मा, इटली, फ्रांस, बेल्जियम आदि राष्ट्रों को भेजी जाती है। तेल तथा खली का निर्यात 1960-61 में क्रमशः 8.5 करोड़ रुपये तथा 14.3 करोड़ रुपये था, अब 1969-70 में बढ़कर क्रमशः 11.7 करोड़ रु० तथा 42 करोड़ रु० पहुंच गया है। 1977-78 में तेलों का मूल्य घटकर 2 करोड़ रु० तथा खली का मूल्य 133 करोड़ रु० रह गया।

9. विविध—इनके अलावा भारत से 93 करोड़ रु० मूल्य तम्बाकू के उत्पादन का निर्यात इंग्लैंड, जापान, स्वीडन तथा नीदरलैंड को किया जाता है। इसी प्रकार घटिया किस्म की कपास ब्रिटेन तथा जापान को निर्यात की जाती है। मैंगनीज और भस्त्रक का भी निर्यात 1977-78 में क्रमशः 15 तथा 12 करोड़ रु० था। मछली तथा मछली की वस्तुओं का निर्यात 1965-66 में केवल 10.5 करोड़ रु० था वह 1977-78 में बढ़कर 174 करोड़ रु० हो गया है अर्थात् 12 वर्षों में इसके निर्यात में 18 गुनी वृद्धि हुई है। हीरा-पत्तों का निर्यात मूल्य अब 242 करोड़ रु० है।

रासायनिक तत्वों (Chemicals) के निर्यात में भी हमारा कदम सराहनीय है जहां 1965-66 में रासायनिक पदार्थों का निर्यात लगभग 18 करोड़ रुपये था वह 1977-78 में बढ़कर 117 करोड़ रुपये हो गया है। चीनी का निर्यात भी 1968-69 में 10.2 करोड़ रुपये से बढ़कर 1975-76 में 72.5 करोड़ रु० हो



गया था। सरकार द्वारा देश में उपयोग हेतु निर्यात 1977-78 में घटाने से 173 करोड़ ₹० मूल्य की चीनी बाहर भेजी।

इस प्रकार भारत के निर्यात में विविधता आई है और परम्परागत वस्तुओं के स्थान पर नये उत्पादों से निर्यात में क्रान्तिवारी परिवर्तन हो रहे हैं। निर्यातों का स्वरूप विकासोन्मुख है।

### भारत के प्रमुख निर्यात (Exports)

(करोड़ रुपये में)

वस्तु	1950-51	1965-66	1970-71	1977-78
1 जूट का सामान	113.8	182.1	190.4	245
2 चाय (Tea)	80.4	144.4	148.2	555
3 सूत सूती वस्त्र आदि	138.4	90.0	115.0	457
4 चमड़ा चमड़े की वस्तुएँ	26.0	28.5	72.2	248
5 इंजीनियरिंग सामान	—	80.0	116.5	617
6 रसायन एवं रसायन पदार्थ	—	14.4	29.4	117
7 चीनी	0.4	3.2	27.6	17
8 बाजू	8.6	23.0	52.0	150
9 खली इत्यादि	0.03	34.3	55.4	133
10 फल आदि	—	—	12.9	40
11 तम्बाकू	—	19.0	51.4	117
अन्य सहित कुल योग	600.7	805.6	1535.2	5373.0

## भारत में विदेशी व्यापार की मुख्य समस्याएँ (Main Problems of Foreign Trade in India)

भारत के विदेशी व्यापार में अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं। जहाँ एक ओर निर्यातों की अपेक्षा आयातों में तीव्र वृद्धि से व्यापार असंतुलन एवं विदेशी विनिमय संकट उत्पन्न हो गया है वहाँ दूसरी ओर निर्यातों में वृद्धि की समस्या है। देश में वस्तुओं की आन्तरिक मांग में वृद्धि, ऊँची उत्पादन लागतें, बढ़ती विदेशी प्रतिस्पर्धा और सभी राष्ट्रों में बढ़ती राष्ट्रीयता की कट्टर भावना से सरक्षण नीतियों का अनुसरण नई समस्याओं को जन्म दे रहा है। यही नहीं, नये नये आविष्कारों से प्रतिस्थापन वस्तुओं का निमाण और विकसित देशों में परस्पर व्यापारिक गठबंधनों के कारण भी विदेशी व्यापार की समस्याएँ बढ़ रही हैं। भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख समस्याएँ इस प्रकार हैं—

1 आन्तरिक माँग में वृद्धि—योजना-वद्ध विकास से देश में जनसाधारण की नवशक्ति में वृद्धि होने तथा जीवन-स्तर में वृद्धि की सालसा प्रबल होने से देश में वस्तुओं की मांग तीव्रता से बढ़ी है। इससे निर्यातों के लिए उपलब्ध माल में कमी हो जाना स्वाभाविक है। क्योंकि जब निर्यातकों को देश में ही ऊँचे मूल्य प्राप्त हो जायें तो निर्यात का जोखिम क्यों उठाने लगे। यही कारण है कि भारत में चाय, चीनी, सूती कपड़ा, जूते, तम्बाकू तथा वनस्पति का निर्यात घटा है या कम गति से बढ़ा है।

इसके साथ-साथ आन्तरिक माँग में वृद्धि से आयातों में भी वृद्धि होती है क्योंकि विकासशील राष्ट्रों में उच्चवर्ग में उत्कृष्ट उपभोग (Conspicuous Consumption) की प्रवृत्ति प्रबल होती है। सरकार के द्वारा ऐसे माल के आयात पर नियन्त्रण होने पर भी तस्करी से माल आता है अतः आन्तरिक माँग में वृद्धि दुहरी समस्या है। निर्यात को हतोत्साहित करती है तथा आयात को प्रोत्साहित, जो कि विदेशी विनिमय संकट एवं व्यापार असंतुलन को जन्म देती है।

2 निर्यात की कट्टर प्रतिस्पर्धा—विश्व व्यापार में हमारी परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में नये विकासशील राष्ट्र हमारी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जैसे चाय में लका, पूर्वी अफ्रीका तथा चीनी कट्टर प्रतिद्वन्द्वी हैं। जूट में पाकिस्तान, सूती कपड़े में जापान, चीन, पाकिस्तान, मैंगनीज में ब्राजील, अफ्रीका व रुम हैं। इस प्रतिस्पर्धा में भारत तभी टिक सकता है जबकि उसकी निर्मित वस्तुओं की विराम ऊँची, मूल्य कम तथा माँग लोचदार हो।

3 भारत में उच्च मूल्य स्तर—योजनाबद्ध विकास में होनायें प्रबल का अत्यधिक सहारा लेने तथा मूल्य स्थायित्व के अभाव में मूल्य-स्तर बहुत ऊँचा है। इससे हमारे विदेशी व्यापार पर मुख्य तीन प्रभाव पड़े हैं, ऊँचे मूल्य से आयात को बढ़ावा, निर्यात को हतोत्साहित तथा ऊँची उत्पादन लागत से विदेशी प्रतिस्पर्धा में टिक पाने की शक्ति में कमी। अतः विदेशी व्यापार की समस्या विकट हुई है।

4 विकसित राष्ट्रों में उदार दृष्टिकोण का अभाव—विकासशील राष्ट्रों के सामने यह समस्या अधिक भयावह है क्योंकि जब तक विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों में आयातों पर प्रतिबन्ध लगायेंगे या उनसे प्रतिस्पर्द्धा करेंगे तो उनके निर्यात की सम्भावनाएँ सीमित होगी। विकसित राष्ट्रों की प्रतिबन्धात्मक नीतियाँ भारत के विदेशी व्यापार में बाधा हैं। दिल्ली में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सच के व्यापार-विकास सम्मेलन में विशेष प्रयत्नों के बावजूद भी आधारभूत निर्णय न हो सके।

5 औद्योगीकरण के लिये आयातों की अनिवार्यता—भारत ने देश में तीव्र-गति से औद्योगीकरण के लिये सुदृढ़ आधार तैयार करने का लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिये भारी मशीनों, विजली का सामान तथा परिवहन उपकरणों का आयात अनिवार्य है जब तक कि देश इन वस्तुओं के निर्माण में आत्मनिर्भर न हो जाय।

6 कच्चे माल व आधुनिकीकरण की समस्या—देश में जहाँ एक ओर निर्यात उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कल पुर्जों व कच्चे माल की आवश्यकता होती है वह दूसरी ओर फैशन, रबि परिवर्तन के साथ-साथ भारतीय उद्योगों में उत्पादन की किस्म, डिजाइन व ताल-मेल नहीं बैठता जाता। अतः निर्यात वृद्धि के लिए लम्बे रेशो की रस्, काजू, ममालो के उत्पादन व वृद्धि करने की आवश्यकता है तथा उद्योगों में विवेकीकरण, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना आवश्यक है।

7 राष्ट्रीय भावना तथा संरक्षण नीति—सभी नवोदित एवं विकासशील राष्ट्रों में अनेक अधिक विकास के लिए आयात पर प्रतिबन्ध आन्तरिक उद्योगों को संरक्षण देने की भावना अति प्रबल है। जिस प्रकार हम अधिक निर्यात तथा कम आयात को चष्टा करन है, सभी देशों में यही प्रवृत्ति प्रबल है। विकासशील राष्ट्र ही नहीं विकसित राष्ट्र भी आयातों पर प्रतिबन्ध की नीति का अनुसरण करते हैं।

8 व्यापार में घाटा तथा व्यापार असन्तुलन—हमारे विदेशी व्यापार की सबसे बड़ी समस्या व्यापार में घाटा है। देश में आयातों की अनिवार्यता तथा उनमें निरन्तर तीव्र गति व वृद्धि तथा दूसरी ओर आन्तरिक मांग में वृद्धि से निर्यात में कम गति से वृद्धि होने से व्यापार असन्तुलन हमारे विपक्ष में बढ़ा है। जहाँ 1950-51 में व्यापार का घाटा केवल 49.77 करोड़ रुपया था वह बढ़ कर 1957-58 में 640 करोड़ रुपया तथा 1967-68 में 921.6 करोड़ रुपया हो गया। अब निर्यातों में वृद्धि अधिक होने तथा आयात प्रविस्थापन में प्रगति से आयात में कमी होने से व्यापार व बढ़ती कीमतों का घाटा 1970-71 में 98.7 करोड़ रुपये ही रहा पर साधारण के अभाव व घटती कीमतों से 1973-74 में घाटा बढ़कर 402 करोड़ रुपया था जबकि 1975-76 में घाटा बढ़कर 1216 करोड़ रुपया होने का अनुमान है। किन्तु 1976-77 में घाटा 69.0 करोड़ रुपया बचत में बदल गया किन्तु 1978-79 में पुनः घाटा 1086 करोड़ रु हो गया।

9 विदेशी विनिमय संकट तथा सम्बर्द्धन समस्याएँ—विदेशी व्यापार में बढ़ना हुआ असन्तुलन, विदेशी सहायता एवं ऋणों की अनिश्चितता से भुगतान असन्तुलन होना स्वाभाविक है और इससे विदेशी विनिमय संकट का हमको सामना करना पड़ता है। इस संकट का मुकाबला करने के लिए हमारे सामने निर्णयों में वृद्धि के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। ऐसी परिस्थिति में निर्माण सम्बर्द्धन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

10 यूरोपीय साभा बाजार व ब्रिटेन (E C M & Brit.)—हमारे विदेशी व्यापार में ब्रिटेन की महत्वपूर्ण भूमिका है। वह हमारी चाय का दो तिहाई भाग आयात करता है और साम्राज्य अधिमान से भी भारत को इंग्लैंड में निर्यात लाभप्रद रहते हैं। इसके अलावा भी अमेरिका के बाद वह हमारे माल का सबसे बड़ा ग्राहक है। परन्तु जब से ब्रिटेन ने यूरोपीय साभा-बाजार में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा है तब से हमें चिन्ता हो गई है क्योंकि ब्रिटेन साभा-बाजार में सम्मिलित होने से वह भी उसके अन्य सदस्यों के अनुकूल हमारे निर्यातों पर प्रतिबन्ध नियन्त्रण की नीति अपना हमारे निर्यातों को घटाना पड़ेंगे।

11 विविधता का अभाव—हमारे विदेशी व्यापार में निर्यातों में कुछ ही वस्तुओं—जूट का माल सूत एवं सूनी वस्त्र तथा चाय की प्रधानता है। अगर इनकी फसल मानसून के प्रकोप के कारण खराब हो जाय तो स्वाभाविक रूप से निर्यात की कमी हो जाती है। इसके अलावा इन वस्तुओं की माग कम लोचदार है। अतः अन्य विदेशी राष्ट्रों द्वारा प्रतिस्पर्धा होने पर मूल्य में कमी हो जाने से व्यापार का घाटा बढ़ जाता है। जब प्रतिस्थापन वस्तुओं का अभाव बढ़ रहा है, चाय के मूल्यों में उतार-चढ़ाव होते रहे हैं तथा प्रतिस्पर्धा में हमारा टिकना मुश्किल हो रहा है तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम निर्यातों में विविधता लायें। अतः परम्परागत वस्तुओं के स्थान पर दूसरी वस्तुओं के निर्यातों में वृद्धि की प्रवृत्ति उज्ज्वल भविष्य का द्योतक है।

इस प्रकार ॥ समस्याएँ हमारे विदेशी व्यापार में व्यावहारिक एवं विवेकीय मार्ग अपनाने को प्रेरित करती हैं जिनमें व्यापार का घाटा कम हो, निर्यात बढ़ें तथा औद्योगीकरण के माग में बाधा उपस्थित न करते हुए आयातों को आन्तरिक उत्पादन से प्रतिस्थापित करें व आयातों को कम करें।

### भारत में निर्यात सम्बर्द्धन के सरकारी उपाय (Government Measures for Export Promotion)

यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में निर्यात नियन्त्रण की नीति अपनाई गई थी पर स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद योजनाबद्ध विकास की सफलता एवं विदेशी भुगतान असन्तुलन से छुटकारा पाने के लिये निर्यात सम्बर्द्धन की आवश्यकता बढ़ी। प्रथम योजना में तो आयातों की मात्रा प्रायः स्थिर रहने से विशेष प्रयास न करने पड़े पर ज्योंही देश में औद्योगीकरण की द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना का शुभारम्भ

इन्जीनियरिंग सम्बर्द्धन परिषदों ने उत्त्प्रेमनीय काम किया है। ये परिषदें सम्बन्धित वस्तु विशेष के निर्यात वृद्धि के लिए बाजारों का अध्ययन, मेलों व प्रदर्शनियों का आयोजन, शिष्टमण्डल भेजने, किस्म-नियन्त्रण पर ध्यान देना आदि कार्य सम्पादित करती हैं।

(v) निर्यात निरीक्षण परिषद्—निर्यात अधिनियम 1962 के अन्तर्गत विदेशी क्रेताओं को भारतीय माल की किस्म की पूरी गारन्टी के लिए, किस्म नियन्त्रण, लदानों से पूर्व निरीक्षण तथा निरीक्षण के लिये आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए निरीक्षण परिषद् की स्थापना की गई।

(vi) निर्यात सात एव गारन्टी निगम—यह निगम निर्यातकों की वित्त व्यवस्था करता है। माल की सामुद्रिक एवं मूल्यों में उतार-चढ़ाव की जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। प्रत्येक निर्यात सम्बर्द्धन समूहों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है।

(vii) व्यापार मण्डल (Trade Board)—व्यापार एवं वाणिज्य के सभी पहलुओं पर विचार करने, उनके सम्बन्ध में सरकार को सलह देना तथा निर्यात सम्बर्द्धन में योग देने के लिए इस समिति की स्थापना 1962 में की गई। इस मण्डल ने सरकार की उत्पादन व्यय में कमी, सात सुविधा के विस्तार, जहाज तथा भाड़े की समस्या तथा विदेशों में व्यापारिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति पर महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र होना है और अध्ययन के लिए दस समितियाँ बनाई हैं।

इन समस्याओं के अलावा महत्वपूर्ण समस्याएँ हैं—

(अ) खनिज व धातु व्यापार निगम—खनिजों व धातुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए।

(ब) भारतीय प्रमाणीकरण संस्थान—किस्म नियन्त्रण के लिए।

(स) वस्तुकारी व हाथकरघा निर्यात निगम—वस्तुकारी तथा हाथ करघा सामान के निर्यात वृद्धि के लिए।

(द) इन्डियन कौन्सिल ऑफ आर्बिट्रेशन—अपसी भगड़े निपटाने के लिए।

(ध) प्रदर्शनी निदेशालय—विदेशों में भारतीय माल की प्रदर्शनी करने हेतु विभिन्न राज्यों में भी निर्यात सम्बर्द्धन सलाहकार बोर्ड बनाये गये हैं। इस प्रकार निर्यात सम्बर्द्धन के लिए समूहों का ऐसा जाल बिछ गया है कि उनके कार्यों का विभाजन मुश्किल है और एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप (Over-lapping) तथा समन्वय की समस्या उठ खड़ी हुई है।

3. वित्तीय सुविधाओं का विस्तार—निर्यात सम्बर्द्धन के लिये निर्यातकों को सस्ती एवं सुविधाजनक वित्तीय सहायता के लिए जहाँ एन और निर्यात सात एव गारन्टी निगम तत्पर हैं वहाँ दूसरी ओर रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक प्रत्येक तथा मध्यमक तीन ऋण प्रदान करते हैं। विपणन विकास निधि 1963 के अन्तर्गत भी निर्यात-कर्ताओं

व उत्पादका का विदेशी बाजार, विकास याजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

4 कर्तों में छूट व रियायत—सरकार ने नियान का प्राप्ताह देने के लिए अनेक वस्तुओं पर नियान कर समाप्त कर दिया है। इसी प्रकार नियान की जाने वाला वस्तुओं का उत्पादन कर से मुक्ति तथा नियान वस्तुओं के निमाण में काम आने वाले वस्तुओं पर चुकाया गया तटकर बापिस लोगन की नाति अपनाई गई है। जूट पर नियान कर 750 रुपये प्रति टन से घटा कर 200 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। प्राप्ति होने वाले लाभों का आय कर से मुक्ति चाय पर दर 44 पैसे प्रति किलोग्राम से घटा कर 20 पैसे इन्क कतिपय उदाहरण हैं।

5 निर्यात प्रोत्साहन योजनाएँ—सरकार द्वारा नियान सम्बन्धन के लिए निर्यातका का अपने निर्यात में मान से प्राप्त विदेशी मुद्रा का उपयोग विशिष्ट कार्यों में करने मानीता व पुर्तों के अध्ययन में सुविधा देने भांड में रियायत व परिवहन में प्राथमिकता देने का नीति अपनाई गई है जिन—(i) अग्रिम लाइसेंस—विशिष्ट शर्तों का पूर्ति पर निर्यात किया जाने वाले मान के लिए कच्चा मान आयात करने में लाइसेंस प्रदान किया जाता है (ii) मनीता के आयात में प्राथमिकता उन उद्योगों का दी जाता है—(iii) निर्यात में मन्त है (iv) आयातित कच्चा माल व पुर्तों को निर्यात उद्योगों का उपयोग करना (v) निर्यात उद्योगों का अपने द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा का कुछ भाग कच्चा मान व खराद व हल-पुर्तों के आयात की सुविधा देने (vi) निर्यात के लिए रत न डे व सानुचित भांड में रियायत तथा परिवहन में प्राथमिकता प्रदान करने (vii) निर्यात सदन—निर्यात व्यापार में वित्तीयिकरण तथा उनके स्तर को उँचा करने के लिए प्रसिद्ध व्यापारिक फर्मों का मान्यता देकर सुविधायें देता (viii) निर्यात सदन का स्थापना विदेशी बाजारों का अध्ययन व निर्यात वृद्धि के लिए योजनाओं के लिए विदेशी विनमय में प्राथमिकता दी जावेगी।

ii व्यापारिक समन्वयन एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सहयोग—व्यापारिक समन्वयन द्वारा विदेशी व्यापार में वृद्धि करने की प्रवृत्ति बामबो सनादी की प्रमुख विशेषता है। भारत सरकार द्वारा अनेक द्विपक्षीय तथा बहु पक्षीय समन्वयन किए हैं। भारत अन्तर्गन्तीय व्यापार संगठन G A T T का सदस्य है। 1932 का छोटावा समन्वयन भारत के विदेशी व्यापार का आधार है। अनेक नारत पंचोकादा साम्यवादी तथा गुट निरपेक्ष सभा से व्यापार समन्वयन कर अपने निर्यातों में वृद्धि करने के सभी प्रयत्न कर रहा है।

7 मुद्रा अवमूल्यन (Devaluation)—भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद निर्यातों में वृद्धि करने तथा व्यापार समन्वयन का ठाँव करने के लिए दो बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया है। पहला बार अवमूल्यन 1949 में किया जबकि भारतीय मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के रूप में 30.5% कम कर दिया गया। दूसरा बार अवमूल्यन 1966 में किया गया। तब भारतीय मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के रूप में

36.5% कम कर दिया। इसका योगदान दुर्भाग्यवश निर्यात सम्बर्द्धन में उत्साहजनक नहीं रहा।

8 विदेशी ग्राहकों में विश्वास सृजन—भारतीय माल की विदेशी ग्राहकों में पैठ जमाने तथा उनकी विश्वास की पूरी गारन्टी करने के लिए निर्यात अधिनियम 1963 के अन्तर्गत माल सदन से पूर्व उसका निर्यात परीक्षण परिषद् परीक्षण की सुविधा उपलब्ध करती है। भारतीय प्रमाणीकरण सत्यान (I S I) भी योगदान करता है। व्यापार-मण्डल ने भी अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना में सहयोग दिया है। आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए भारतीय समझौता-परिषद् है। इस प्रकार विदेशी ग्राहकों को सन्तुष्ट रखने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

9 नेशनल ट्रांकी ऑफ एक्सपोर्ट्स—भारत में निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिये निर्यात में कीनिमान स्थापित करने वालों को पहली बार 28 नवम्बर, 1959 में 9 ऐवाई तथा 25 मेरिट सर्टिफिकेट दिये गये और आगे भी चालू रखे जा रहे हैं।

10 विकासोन्मुख आयात-निर्यात नीति (1978-79 एवं 1979-80)—देश के आयातों-निर्यातों के सम्बन्ध में जनता सरकार ने “नियंत्रणों” की अपेक्षा विकासोन्मुख एवं प्रोत्साहन मूलक आयात निर्यात नीति 1979-1980 की घोषणा की है जो उदारता, सरलता और विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्तियों पर जोर देता है। लघु उद्योगों की प्रारक्षित वस्तुओं के आयातों पर प्रतिबन्ध लगाता है। विकास के लिए नयी सुविधाओं का समावेश करता है। निर्यातों को प्रोत्साहन दिया गया है।

### विदेशी व्यापार नीति (Foreign Trade Policy)

किसी भी देश के विकास में उसकी आयात और निर्यात नीतियों का विशेष स्थान होता है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत के विदेशी व्यापार की नीति स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् विकासोन्मुख बनाई गई है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से आयात और निर्यात नीतियों में समय-समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। प्रारम्भ में आयात नीति उदार रखी गई पर 1949 में उसे प्रतिबन्धात्मक बनाया गया। 1955-56 में आयात नीति का उद्देश्य औद्योगीकरण के लिए आवश्यक मशीनरी व भारी सामान के आयात को प्रोत्साहन देना था पर 1957-58 में विदेशी व्यापार में भारी असन्तुलन के कारण आयातों पर प्रतिबन्ध लगा। विदेशी विनिमय संकट निवारण के लिए निर्यात प्रोत्साहन देने की नीति का अनुसरण किया। वर्तमान आयात और निर्यात नीतियों का प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता और विविधता की दशाओं को बढ़ाना है ताकि आयात नियन्त्रण औद्योगिक विकास का साधन, विनिमय संकट में रक्षक तथा निर्यात सम्बर्द्धन के माध्यम के रूप में कार्य करें। 1961 में ही भारत की विदेशी व्यापार नीति को मुदाजियर समिति की सिफारिशों के अनुकूल

1 लघु कुटीर एवं छोटे उद्योग क्षेत्र की आरक्षित वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध—लघु छोटे एवं कुटीर उद्योगों द्वारा जिन वस्तुओं के उत्पादन को सरकार द्वारा आरक्षित कर दिया गया है अब उन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध रहेगा।

2 छोटे उद्योगों की स्थापना व विकास की सुविधाएँ—नयी नीति के अधीन छोटे पैमाने के उद्योग लगाने वालों को तीन लाख रुपये तक के लाइसेंस प्राप्त करने में मिल सकेंगे।

3 वास्तविक उपभोक्ताओं का दर्जा अब सभी अस्पताल, शोध तथा उच्च शिक्षा केन्द्र, कृषक सेवा केन्द्र, छात्रों की एन.ए.ए.ए. का भी द दिया गया है। देश में उपलब्ध न होने वाली वस्तुओं का आयात से मगाने के लिये अब लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वतन्त्र रूप से वैज्ञानिक एवं शोध कार्य में सलग्न व्यक्ति को भी 10 हजार रु० तक का सामान वैज्ञानिक मगाने की सुविधा दी गई है।

4 आपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत पूँजीगत माल की सूची में बिना लाइसेंस मंगाई जा सकने वाली चीजों की संख्या 203 कर दी गई है।

5. 14 बुनियादी उद्योगों के लिए मशीनों खरीदने के वास्ते अन्तर्राष्ट्रीय डेण्डर मॉगने की सुविधा दी गई। यह सुविधा उर्वरक, वागज, आधारभूत दवाइयों, बिजली उत्पादन, खनिज तेल की खोज, कीटाणुनाशक औषधियों के लिए बुनियादी कच्चा माल आयात करने के लिए भी है।

6 विदेशों से खरीदने वाले भारतीयों को देश में उद्योग लगाने की सुविधा दी जाने की व्यवस्था है। ये अपनी निछली बचतों एवं जमा पूँजी के बल वृत्ते पर पूँजीगत माल एवं साल भर के लिए कच्चा माल सरकार से बिना अनुमति मगा सकेंगे।

7 लाइसेन्सिंग व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। अभी तक जो काम दिल्ली, बम्बई एवं कलकत्ता के लाइसेंस देने वाले कार्यालयों में होता था अब वह धनरसला, चण्डीगढ़, इंदूर, गौहाटी, जयपुर एवं पटना के नये कार्यालयों में भी होने लगेगा।

8 निर्यात प्रोत्साहन एवं सम्बर्द्धन की दृष्टि से फैसला किया गया है जिनमें औद्योगिक इकाइयों ने पिछले दस अपने उत्पादन का दस से कम आयात हिस्सा निर्यात किया है उन्हें अपने लाइसेन्स की रकम के साधे से बराबर माल आयात करने की सुविधा अपने आप मिल जायेगी। लघु एवं कुटीर उद्योगों के भाग का निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यातक अपने निर्यात के आधार पर अतिरिक्त राशि के लाइसेन्स ले सकेंगे।

9 पिछड़े क्षेत्रों में पिछड़ी जाति एवं जनजाति अथवा तत्कालीन दृष्टि से योग्य व्यक्तियों द्वारा नये उपक्रमों की स्थापना हेतु ५ लाख रुपये तक आयात का लाइसेन्स मिल सकेगा।



10 लाइसेन्स व्यवस्था को सरल बना दिया गया है ताकि विकास में बाधा उत्पन्न न हो।

### नई आयात-निर्यात नीति (1979-80)

(New Import & Export Policy of 1979-80)

4 मई 1979 की नई आयात-निर्यात नीति 1979-80 पिछले वर्ष की नीति का ही विस्तार मात्र है जिसमें आयातों में उदारता तथा अर्थव्यवस्था में स्थायित्व के साथ अब व्यापार में बढ़ने पाटे को कम करने के उद्देश्य से निर्यात सम्बर्द्धन की प्रेरणा का समावेश किया गया है। इस नीति की मुख्य विशेषताएँ निम्न हैं—

(1) आयातों में आधिक उदारता—पूर्वत निषेध आयात मदों की सख्यागत वर्ष की 96 से घटाकर 65 निषेध मदों की सख्या 751 से घटाकर 658 तथा प्रतिबन्धित (Restricted) मदों की सख्या 498 से घटाकर 362 कर दी गई है।

(2) भारतीय गैर शहरीको जो भारत में विनियोगों को बढ़ावा देने के लिए प्रति व्यक्ति 25 लाख रु के मूल्य की मशीनों में आयात में छूट दी जायगी।

(3) वैज्ञानिक एवं भाषक यन्त्रों के आयातों पर रोक लगा दी है ताकि इनके कारण स्वदेशी उद्योगों को क्षति न हो।

(4) प्रत्येक निर्यात गृहों को अब 2 लाख रु मूल्य तक के स्पेयर पार्ट्स आयात करने का अतिरिक्त लाइसेन्स दिया जा सकेगा।

(5) प्रत्येक आयातित ट्रैक्टर या वाहन के स्पेयर पार्ट्स 2500 रु तक बिना लाइसेन्स आयात किये जा सकेंगे।

(6) सेम्पल्स आयात में 'रयायत—पञ्जीकृत निर्यातकों को REP के लाइसेन्स के अन्तर्गत पहले 10 हजार रु मूल्य के स्थान पर 50 हजार रु मूल्य के सेम्पल्स आयात करने की छूट दी गई है तथा बिना लाइसेन्स आयात में छूट 500 रु से बढ़ाकर 5000 रु कर दी है अगर सेम्पल्स डाक या हवाई जहाज से भेजा जाय।

(7) अधिकृत दवाइयों, व्यापारिक नमूनों मुफ्त प्रान्त पशु इजेक्शनो को OGL के अन्तर्गत सूची में ले लिया है।

(8) प्रथम बार फोटो फिक् स्टूडियो को आधुनिक कैमरा भेजने की अर्हता सहित छूट दी है जिसमें 2000 रु मूल्य के कैमरों का आयात हो सकेगा।

(9) बिजली तथा स्टॉक के लिए (OGL) सूची न ज्ञास स्त्रो, जिक स्त्रो, घड़ियों के लिए लूब्रिकेटिंग तेल तथा जीवनदायक यन्त्रों का शामिल कर लिया गया है।

(10) लघु एवं कुटीर उद्योगों के विभाग के लिए बच्चे माल के आयात तथा स्पेयर पार्ट्स के आयात में छूट की व्यवस्था की गई है।

(11) एल्यूमिनियम, प्राकृतिक रबर तथा सीमेंट का आयात अब सार्वजनिक सस्याएँ ही कर सकेंगी ।

(12) REP के अन्तर्गत पूंजीगत आयात की विधि का सरलीकरण कर दिया गया है ।

(13) 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक नगर में निर्यात सम्बद्ध न कार्यालय खोला जायेगा ।

### भारत के विदेशी व्यापार का भविष्य (Future of India's Foreign Trade)

भारत में आयात प्रतिस्थापन निर्यात सम्बद्ध न तथा अर्थव्यवस्था में स्थायित्व के साथ विकास की नीति में भारत के उज्ज्वल भविष्य का संकेत मिलता है । निर्यातों में वृद्धि की प्रवृत्ति में विदेशी व्यापार का उज्ज्वल भविष्य दृष्टिगोचर होता है किन्तु साथ ही बढ़ते व्यापार घाटे में खतरे की सूचना भी है । जहाँ 1978-79 में विदेशी व्यापार शेष 69 करोड़ रु पक्ष में था वहीं 1978-79 में विदेशी व्यापार शेष 1086 करोड़ रु प्रतिकूल (Deficit) रहने की सम्भावना है । छठी योजना की प्रवृद्धि में आयात निर्यात का अनुमान भी बढ़ते आयातों और निर्यातों के साथ-साथ व्यापार के घाटे की वृद्धि का संकेत देते हैं ।

### भारत में विदेशी व्यापार (1982-83) तक के अनुमान (करोड़ रुपये)

वर्ष	आयात	निर्यात	कुल	व्यापार शेष
1976-77	5074	5143	10217	+69
1978-79	6074	568	12322	- 1086
1978-83 (औसत)	8565	6800	15365	- 1765
1982-83	10500	7750	18250	- 2750

Source-Sixth Five Year Plan (Draft)

उपरोक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि यद्यपि निर्यातों में निरन्तर वृद्धि होगी किन्तु साथ-साथ आयात भी अधिक बढ़ते जायेंगे जिससे व्यापार का घाटा निरन्तर बढ़ता ही जायेगा । 1982-83 तक आयातों में 4426 करोड़ रु की वृद्धि तथा निर्यातों में 2148 करोड़ रु की ही वृद्धि निराशाजनक लगती है ।

अतः भारत में भविष्य में निर्यातों में तीव्र वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन की संकल्पना हेतु आन्तरिक मांग पर अनुश्रुति रखना जरूरी है । विदेशी बाजारों में

भारत के माल की प्रतिष्ठा एवं रुचि जागृत करने के लिए उनकी उत्तमता में सुधार, लागत में कमी तथा निर्यात सम्बर्द्धन प्रयासों में वृद्धि करना चाहिये। सरकार भी उपयुक्त आयात-निर्यात नीति द्वारा देश में आन्तरिक उत्पादन को बढ़ावा देकर निर्यात बढ़ा सकती है।

यह निर्विवाद सत्य है कि भारत के विदेशी व्यापार में आयात प्रतिस्थापन और निर्यात सम्बर्द्धन से देश में औद्योगीकरण को बल मिला है। विदेशी तकनीकी सुधारों का भारतीय उद्योगों को लाभ मिला है। औद्योगिक कच्चे माल एवं मशीनों के आयात से देश के औद्योगीकरण का मुहृद आधार तैयार हुआ है। परम्परागत माल के स्थान पर इन्जीनियरिंग एवं निमित्त माल के निर्यातकों को प्रेरणा मिली है। लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास का मार्ग खुला है और ये सब उज्ज्वल भविष्य के सूचक हैं। केवल व्यापार घाटे को कम करने के लिए निर्यातों में वृद्धि एवं आयातों में कमी के लिए सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

### विदेशी व्यापार नीति का मूल्यांकन

उपर्युक्त संक्षिप्त विवरण से स्पष्ट है कि जहाँ भारत की आयात नीति प्रतिक्रियात्मक होने के साथ-साथ औद्योगिक विकास, विविधता तथा आत्मनिर्भरता की दृष्टि से प्रगतिशील और सार्वजनिक समस्याओं के प्रसार से समाजवाद के अनुकूल है इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में आयात-प्रतिस्थापन की अन्ननिहित प्रवृत्ति (Built in Tendency) औद्योगिक उत्पादन में विविधता और आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त हुआ है वहाँ दूसरी ओर निर्यात नीति देश में व्यापार असंतुलन को कम करने निर्यातों में अभिवृद्धि करने तथा विदेशों में भारतीय माल की खपत बढ़ाने में काफी सफल रही है। नई आयात-निर्यात नीतियाँ सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार व उनकी भूमिका को प्रधानता देती हैं तथा निर्यात सम्बर्द्धन के लिए कच्चे माल, मशीनरी व उपकरणों के आयात से आधुनिकीकरण द्वारा भारतीय उद्योगों में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, प्रगतिशील उत्पादन, कुशलता का सृजन करना चाहती हैं। सरकार इसके लिए तकनीकी, वित्तीय तथा विदेशी मुद्रा की आवश्यक सहायता देने में सदा तत्पर है।

### परीक्षोपयोगी प्रश्न मय संकेत

- 1 भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? विदेशी व्यापार की मुख्य समस्याओं का उल्लेख करते हुए इनके समाधान के लिए किये गये प्रयत्नों का विवेचन कीजिये।  
(संकेत - प्रथम भाग में विदेशी व्यापार की मुख्य-मुख्य विशेषताएँ बताना है तथा दूसरे भाग में समस्याओं का शीर्षकानुसार वर्णन देकर तीसरे भाग में इन समस्याओं के समाधान के प्रयत्नों का उल्लेख करना है।)
- 2 भारत के आयात-निर्यात की प्रमुख वस्तुओं का वर्णन दीजिए तथा निर्यात सम्बर्द्धन के लिए किये गये प्रयत्नों का उल्लेख कीजिए।

(संकेत—आयात की मुख्य मदों तथा निर्यात की मुख्य मदों का विवेचन देकर दूसरे भाग में निर्यात बढ़ाने के प्रयत्नों का क्रमबद्ध विवेचन कीजिये।)

3 भारत के विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिये। पिछले वर्षों में सरकार ने आयात व निर्यात की किन-किन नीतियों का अनुसरण किया है ?

(संकेत—विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियों का क्रमबद्ध विवेचन दीजिये कि आयात व निर्यात में वृद्धि व्यापार क्षेत्र में अन्तराल, निर्यात वृद्धि व आयात नियन्त्रण, व्यापार स्वरूप, व्यापार की दिशा सभी का विवेचन देना है तथा निर्यात व आयात सम्बन्धी सरकारी नीति का मूल्यांकन देना है।)

4 भारत सरकार की आयात व निर्यात नीति की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये।

(संकेत—भारत सरकार की आयात नियन्त्रण व निर्यात सम्बर्द्धन की वर्तमान नीतियों की आलोचनात्मक समीक्षा देना है।)

5 भारत सरकार की “निर्यात सम्बर्द्धन” तथा “आयात प्रतिस्थापन” नीति पर टिप्पणी कीजिये तथा विदेशी व्यापार के भविष्य पर प्रकाश डालिये।

(संकेत—दोनों नीतियों का मूल्यांकन देना है तथा अन्त में भविष्य को उज्ज्वल बनाना है।)

6 भारत सरकार की वाणिज्यिक नीति की विवेचना दीजिये।

(Raj B Com, III yr 1979)

# भारत का भुगतान सन्तुलन

## अथवा भुगतान-शेष

(Balance of Payments of India)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान सन्तुलन की समस्या एक प्रकार से अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं, देश की बदलती परिस्थितियों तथा विनिमय दरों में होने वाले उतार-चढ़ावों का विश्लेषण करती है तथा उनके समाधान का मार्ग-दर्शन देती है।

भुगतान सन्तुलन का अर्थ—विदेशी व्यापार शब्दावली में 'भुगतान सन्तुलन' शब्द के कई अर्थ प्रचलित हैं। पहले अर्थ में इसका अर्थ 'किसी देश-विदेश में उसने द्वारा खरीदी व बेची गई विदेशी मुद्रा के अन्तर' से है। दूसरे अर्थ में विदेशों से प्राप्त भुगतान व विदेशों में गिरा गया भुगतानों का अन्तर बताता है। तीसरे अर्थ में 'राजस्व खाते में भुगतानों का सन्तुलन प्रदर्शित करता है तथा चौथे अर्थ में अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों व सन्तुलन को स्पष्ट करता है। सबसे अधिक प्रचलित अर्थ भुगतान सन्तुलन का अभिप्राय विदेशों पर हमें की सम्पूर्ण मांग तथा सम्पूर्ण सम्पत्ति परिस्थिति में है। प्रो. एल्सवर्थ के शब्दों में, 'भुगतान सन्तुलन विर के नियामियों और शेष विश्व के मध्य हुए सीढ़ों का संक्षिप्त विवरण है।' , अधिक स्पष्ट करते हुए प्रो. जेम्स इंग्राम (James Ingram) ने लिखा है, "भुगतान सन्तुलन उन सभी आर्थिक लेन देनों का अभिलेख (लेखा जोला) है जो कि एव निवासियों (व्यक्तियों, कर्गों, सरकार तथा अन्य संस्थाओं) एवं शेष संसार के किसी निश्चित समय में होता है।"

इस प्रकार स्पष्ट है कि भुगतान सन्तुलन एक विवरण है जिसमें देश द्वारा एव अदृश्य आयातों व निर्यातों को (जो शेष संसार के विभिन्न देशों में हो रहे हैं) बताया जाता है। दूसरे शब्दों में, देशों के विदेशी मुद्रा का सम्पूर्ण एव पूंति की परिस्थितियों का समावेश होता है।

### व्यापार सन्तुलन तथा भुगतान सन्तुलन में अन्तर

(Difference Between Balance of Trade & Balance of Payments)

व्यापार सन्तुलन (Balance of Trade) का अभिप्राय किसी देश के